



भारतीय राष्ट्रवाद  
की  
सामाजिक पृष्ठभूमि

दि मकमिलन कपनी आफ इडिया लिमिटेड

नई दिल्ली ववई कलकत्ता मद्रास

समस्त विश्व म सहयोगी कपनिया

भारतीय इतिहास अनुसधान परिषद  
अनुवाद प्रयागदत्त त्रिपाठी

प्रथम हिंदी संस्करण 1976

मूल्य 36 00

भारतीय इतिहास अनुसधान परिषद द्वारा प्रयतित

एस० जी० वमानी द्वारा दि मकमिलन कपनी आफ इडिया लिमिटेड  
के लिए प्रकाशित तथा प्रगति प्रिंटम, दिल्ली 110032 में मुद्रित।

A R Desai Bhartiya Rashtrawad Ka Samajik Prishthabhumi

## अनुसंधान परिषद की ओर से

भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के अनेक उद्देश्यों में एक है भाषा की उपलब्धियों को उस पाठक वगैरे तक पहुंचाना जो हमसे यह अपेक्षा रखता है कि हम भारतीय भाषाओं में इतिहास संबंधी रचनाएँ तैयार तथा प्रकाशित करें। अंग्रेजी भाषा के माध्यम से भारतीय इतिहासविद अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पहुंच सकते हैं नाम और प्रतिष्ठा अर्जित कर सकते हैं, किंतु भारतीय पाठकों का एक छोटा जश ही इससे लाभ उठा पाता है। शिक्षण और अनुसंधान के माध्यम के रूप में हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के प्रयोग की प्रवृत्ति बल पकड़ रही है। ऐसी स्थिति में इतिहास की स्तरीय पुस्तकों की कमी गंभीर रूप से अनुभव की जा रही है। सबसे पहले हम भारतीय इतिहास की ओर ध्यान देना है। अतः भा० इ० अ० प० ने कुछ गौरवग्रथी (क्लासिक्स) तथा इतिहास विषयक शोध की निर्दोष पद्धतियों पर आदृत और इतिहास की समकालीन प्रवृत्तियों को प्रतिबिंबित करने वाली कुछ अन्य पुस्तकों का अनुवाद कराने का निश्चय किया है।

प्रस्तुत पुस्तक में, सामाजिक दृष्टिकोण से, रजनी पामदत्त की 'आज का भारत' की विचारधारा का अनुसरण किया गया है। इसमें भारतीय राष्ट्रवाद के उद्भव को खोजा गया है तथा यह बताया गया है कि औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था ने किस प्रकार अंतर्विरोधों से आक्रांत सामाजिक व्यवस्था को जन्म दिया। लेखक ने भारत में ब्रिटिश शासन के प्रभाव का विश्लेषण किया है तथा भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में सामाजिक शक्तियों तथा सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन की भूमिका का मूल्यांकन किया है। पुस्तक के विषय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के वगैरे की विवेचना पहली बार हमें यही प्राप्त होती है।

पुस्तक का प्रकाशन पटना यूनिट के प्रयासों का परिणाम है जिसके लिए अनुवादक प्रयागदत्त त्रिपाठी, श्री० नगेंद्र प्रसाद वर्मा तथा अन्य सभी सहयोगियों के प्रति हम धन्यवाद ज्ञापन करते हैं।

नई दिल्ली

28 फरवरी 1976

रामशरण शर्मा

अध्यक्ष

भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद



कठोर एव हास्यप्रिय मनस्वी जिसने दारुण नियति  
की निमग्न मार को बरसो सहा एव बुद्धि और  
तक की गरिमा मानवतावाद के ऐश्वर्य तथा  
जीवन के आनदातिरेक से मुझे परिचित कराया—  
ऐसे पितामह की पुण्य स्मृति की ।



## चतुर्थ सस्करण की भूमिका

'भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि' के चतुर्थ सस्करण की भूमिका लिखत हुए लेखक को बड़ी प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। जैसा कि पुस्तक के प्रथम सस्करण की भूमिका में बताया जा चुका है, 'भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि' में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय की जटिल और बहुरंगी प्रक्रिया और उसके विभिन्न रूपों का सम्मिश्रित शब्द चित्र प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। इस अव्येपण का काल क्षेत्र अंग्रेजों के भारत आगमन से द्वितीय महायुद्ध की शुरुआत तक सीमित है। युद्ध और युद्धोत्तरकाल के भारतीय राष्ट्रवाद पर लेखक का अध्ययन उसके संपूरक ग्रंथ 'रीसट ट्रेंड्स इन इंडियन नेशनलिज्म' में उपलब्ध है। ये दो ग्रंथ इस रोचक विषय की अविच्छिन्न गाथा प्रस्तुत करते हैं। इन ग्रंथों से यह भी सिद्ध है कि कम से कम लेखक के लिए, पिछली दो शताब्दियाँ में भारतीय समाज में जो परिवर्तन हुए हैं, उनका ऐतिहासिक भौतिकवाद की पद्धति से बड़ा सफल साध्य अध्ययन हो सकता है। यह सचमुच उत्साहवर्द्धक है कि 'भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि' अभी भी दुनिया के विभिन्न भागों में समादृत है और इसके चतुर्थ सस्करण की आवश्यकता है।

मैं पुनः डॉ॰ जी॰ एस॰ घुर्गे के प्रति अपने गहरा कृतज्ञता बोध को स्वीकार करता हूँ। उन्होंने ही मुझे इस अध्ययन की प्रेरणा दी और इस जटिल विषय के अव्येपण में बहुमूल्य वास्तव्यपूर्ण भाग दर्शन किया। मैं बावे युनिवर्सिटी का भी आभारी हूँ, जिसने अपने समाजशास्त्र सिरीज में इस पुस्तक का प्रथम सस्करण प्रकाशित किया।

मैं हृदय से अपने युवा दोस्त श्री उदय मेहता, रिसर्च असिस्टेंट, को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस पुस्तक के प्रकाशन में मदद की और इसकी अनुक्रमणिका तैयार की।

श्री रामदास भटवल और पापुलर प्रकाशन के उनके सहयोगियों का भी आभारी हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा सस्करण निकाला है। मुझे विश्वास है कि इस ग्रंथ और इसके संपूरक पर वाद विवाद और विचार विमर्श हाते रहेंगे।





## तृतीय सस्करण की भूमिका

'भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि' के तीसरे सस्करण की भूमिका लिखते हुए मुझे खुशी हो रही है।

जैसा कि द्वितीय सस्करण की भूमिका में कहा जा चुका है, द्वितीय विश्व युद्ध और युद्धोत्तर वर्ष भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास में महत्वपूर्ण और निर्णायक थे। वस्तुतः, सारे विश्व पर इस काल का वातचक्र का सा प्रभाव पडा। इन वर्षों में इतिहास तूफानी तेजी से आगे बढ़ा है, यद्यपि इसकी प्रगति मनमानी या मनमौजी नहीं रही है।

मेरे प्रकाशकों ने भारतीय राष्ट्रवाद की युद्धकालीन और युद्धोत्तरकालीन प्रवृत्तियों पर अलग से एक अध्याय लिखने का अनुरोध किया। मैंने छोटा सा पुनश्च लिखने का प्रयास किया। लेकिन सामग्री की जटिलता और सपनता के कारण इस अध्याय ने एक अलग पुस्तक का रूप ले लिया और यह ग्रथ इसी के साथ अलग से 'रीसट ट्रेडस इन इंडियन नेशनलिज्म' नाम से छप रहा है।

यह जानकर मुझे बडा सतोष है कि दुनिया के विभिन्न भागों में इस ग्रथ का स्वागत हुआ है।

मैं फिर डा० जी० एस० घुर्थे के प्रति अपना गहरा आभार प्रकट करता हू। प्रस्तुत अध्ययन उनके बहुमूल्य अनुरागपूर्ण मागदशन में सपन हुआ है।

मैं बावे युनिवर्सिटी का आभारी हू जिसने अपने सोशियलजी सिरीज में इस ग्रथ का पहला सस्करण प्रकाशित किया।

डिपार्टमेंट आफ सोशियलजी  
युनिवर्सिटी आफ बावे  
बवई, अक्टूबर 1959

ए० आर० देसाई



## द्वितीय सस्करण की भूमिका

'भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि' का पहला सस्करण वाशिंगटन युनिवर्सिटी की सोशियलजी सिरीज में 1948 में प्रकाशित हुआ। डा० जी० एस० घुर्थे प्रोफेसर एच हंड, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियलजी, इस सिरीज के सामान्य संपादक थे। विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक विचारधाराओं को माननेवाले कई समीक्षकों ने इसकी काफी प्रशंसा की। राष्ट्रवाद आधुनिक भारत के विकास का अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है और यह ग्रंथ भारत में इसके उदय का सागोपाग और बहुपक्षीय विवरण है।

इस ग्रंथ पर जब काम शुरू हुआ था उसके बाद दस से अधिक साल गुजर गए हैं। भारत और विश्व में इस अवधि में अनेक महत्वपूर्ण और तूफानी घटनाएँ घटी हैं। दुनिया इस बीच बहुत बेतुह बढ़ली है। कई अतर्निहित तथ्य सुनिश्चित और सुस्पष्ट हो चुके हैं। विश्व के मानव समाज की रूपावृत्ति तेजी से और गुणात्मक तौर पर बदली है। भारत में भी देशी और अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के प्रभाव के फलस्वरूप अनेक दूरगामी परिवर्तन हुए हैं। कई दशकों का परिवर्तन प्रक्रिया कुछ ही बरसों की अवधि में मिमटी आ रही है।

इस ग्रंथ का मूल अभिप्राय भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि का अभिचित्रित करना है। इसलिए पिछले दशक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर द्वितीय सस्करण के अंत में महज एक अध्याय जोड़ देना काफी नहीं हाता। मुझे लगा कि हाल की घटनाओं पर वर्तमान पुस्तक की उत्तरकथा के रूप में स्वतंत्र, अलग गद्य की रचना आवश्यक है।

इसीलिए गवेषणा का क्षेत्र प्रथम सस्करण के काल क्षेत्र से आगे नहीं बढ़ाया गया है। मैं अद्य ग्रंथ में पिछले दशक के भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि का अलग से अध्ययन करने की आशा करता हूँ।

लेकिन इस द्वितीय सस्करण में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं—

- 1 प्रथम सस्करण में आ गई पुनरुक्तियों को हटा दिया गया है।
- 2 प्रथम सस्करण की पाठ्यलिपी तैयार करने के समय भारत में अभी अंग्रेजी शासन था ही, इसलिए रचना में जो काल संबंधी अमंगलिया आ गई थी, उनका भी निराकरण कर दिया गया है।

3 पिछले मस्करण में जो विचार कुछ अस्पष्ट रह गए थे, उन्हें स्पष्ट कर दिया गया है।

4 ग्रथ के अध्ययन में सहायता हेतु उप शीपक दे दिए गए हैं।

वर्तमान अध्ययन डॉ० जी० एस० घुर्ये के बहुमूल्य एवं वात्सल्यपूर्ण मार्ग-दर्शन में सम्पन्न हुआ और मैं फिर एक बार उनके प्रति अपने अगाध कृतज्ञता बोध का ज्ञापन करता हूँ।

अपने सांशिक्षालजी सिरीज में इस ग्रथ का प्रथम मस्करण की प्रकाशित करने के लिए मैं वावे युनिवर्सिटी का भी आभारी हूँ।

डिपार्टमेंट आफ सोशियलजी  
युनिवर्सिटी आफ वावे  
वर्ग, जगस्त 1954

ए० आर० देसाई

# प्रथम सूक्ष्मकरण की भूमिका

समाजशास्त्र के अन्तर्गत  
यस्य माहान धरारह्ये।

पिछले डेढ़ सौ बरसों में भारतीय समाज का मध्ययुग से आधुनिक आघार पर जो रूपांतरण हुआ है और उसके फलस्वरूप राष्ट्रवाद और सामाजिक, धार्मिक, जायिक, राजनीतिक एव सांस्कृतिक आदि अपन विभिन्न रूपों में राष्ट्रीय आंदोलन का जो उदय हुआ है, वह भारतीय इतिहास और समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत रोचक विषय है। मानव जाति के लगभग पाचवें भाग का यह सशक्त आंदोलन महान और नाटकीय तो है ही, यह मानवता के भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। इस रोचक विषय की ओर आकृष्ट होना स्वाभाविक ही था।

फिर, छात्र, मजदूर, किसान और राजनीतिक राष्ट्रीय आंदोलन से विद्यार्थी जीवन के अपने सीमित संपर्क के समय में इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इन आंदोलनों की सही समझदारी और उनमें साथक सहयोग के लिए यह आवश्यक है कि ब्रिटिश शासनकाल में हुए भारतीय समाज के मरचनात्मक परिवर्तन नई सामाजिक शक्तियों के उत्थन और उनकी भूमिका और राष्ट्रीय आंदोलन एव भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के सामाजिक कारणों को ठीक और सम्यक रूप में समझा जाए। नई सामाजिक शक्तियों की प्रवृत्ति और भारतीय समाज के विकास के निम्न को समझने की आवश्यकता है। इसलिए इस विषय के विशेष अध्ययन की मेरी इच्छा और तीव्र हुई।

जहां तक मुझे मालूम है, अभी तक कोई एक ऐसी अक्ली पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, जिसमें भारतीय राष्ट्रवाद के जन्म का ऐतिहासिक, सांश्लेषिक और क्रमबद्ध विवरण हो, या जिन विविध नई सामाजिक ऐतिहासिक शक्तियों से राष्ट्रीय चेतना का जन्म हुआ, उनके विशिष्ट भार और पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया का चित्रण एव मूल्यांकन हो। प्रस्तुत ग्रंथ, जो बाबे यूनिवर्सिटी की पी एच० डी० की उपाधि के लिए लिखे गए मेरे शाधप्रबन्ध से जन्मा है उपयुक्त आवश्यकता की पूर्ति की दिशा में किया गया प्रयास है। मैंने इस विषय के अध्ययन के लिए, जिन विभिन्न सामाजिक शक्तियों से भारतीय राष्ट्रवाद के उदय और विकास की सामाजिक पृष्ठभूमि का निर्माण हुआ था उनके विशिष्ट भार के

अवस्थापन और मूल्यांकन के लिए ऐतिहासिक भौतिकवाद की पद्धति का उपयोग करने का प्रयास किया है।

मैं डा० जी० एस० घुर्ये, प्राफेसर एव अध्यक्ष, सोशियलजी डिपार्टमेंट, वाशिंग्टन यूनिवर्सिटी का अनुग्रहित हूँ जिन्होंने शोध प्रबंध की रचना में मेरा वात्सल्यपूर्ण और बहुमूल्य मार्गदर्शन किया।

यह अध्ययन भारतीय राष्ट्रवाद के उदय की जटिल और बहुमुखी प्रक्रिया और उसके विभिन्न रूपों का अभिचित्रित करने का प्रयास है। लेखक को स्वयं इस ग्रंथ की अनेक त्रुटियों का अहसास है। फिर भी, अगर इस ग्रंथ के कारण इस विषय में लोगों की रुचि बढ़ती है और अधिक मूल्य तथ्यों के आधार पर अधिक ठोस और सही निष्कर्ष निकालने वाली पुस्तकें लिखी जाती हैं तो लेखक अपना श्रम साधक मानेगा।

अप्रैल 1946

ए० आर० देसाई

## प्राक्कथन

1

० राष्ट्रवाद ऐतिहासिक तथ्य, ई० एच० कार द्वारा दी गई राष्ट्र की परिभाषा, विभिन्न देशों में राष्ट्रवाद का विकास, आधुनिक युग में राष्ट्रवादी भावा की प्रधानता, शोध का विशिष्ट क्षेत्र राष्ट्रवाद, भारतीय राष्ट्रवाद के उदभव और विकास का अध्ययन।

## प्राक् ब्रिटिश भारत की अर्थव्यवस्था और संस्कृति

6

आत्मनिर्भर ग्राम समुदाय, भारतीय और यूरोपीय सामतवाद, प्राक् ब्रिटिश भारत का ग्रामीण अर्थतन्त्र, प्राक् ब्रिटिश भारत में नागरिक अर्थव्यवस्था प्राक् ब्रिटिश भारत में ग्राम संस्कृति का रूप, प्राक् ब्रिटिश भारत में नागरिक संस्कृति का रूप, भारतीय संस्कृति की धार्मिक वैचारिक एकता, राष्ट्रीय भावना का अभाव।

## ब्रिटेन की भारत विजय

25

भारतीय समाज का रूपांतरण अंग्रेजों की भारत विजय का परिणाम, अंग्रेजों की भारत विजय के कारण, अंग्रेजों की भारत विजय के विशिष्ट लक्षण, भारत की आर्थिक मरचना पर प्रभाव, ऐतिहासिक दृष्टि से प्रगतिशील महत्व।

## ब्रिटिश शासन काल में भारतीय कृषि का रूपांतरण

31

भारतीय सामतवाद के मूलभूत तत्व, भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व का प्रारंभ, नई भूराजस्व व्यवस्था, कृषि का वाणिज्यीकरण, परंपरागत भारतीय गांव का विघटन।

## भारतीय कृषि के रूपांतरण के सामाजिक परिणाम

43

राष्ट्रीय कृषि का उदभव जमीन उपविभाजन और विलयन, विलुद्धीकरण के परिणाम, नई भूराजस्व व्यवस्था कृषि का वाणिज्यीकरण, किसानों की बढ़ती हुई दरिद्रता, किसानों की बढ़ती हुई ऋणग्रस्तता भूमि का हस्तांतरण काश्तकार से गैर काश्तकार मालिकों को, कृषि दासता का उदभव, कृषि क्षेत्र में वर्गों का वृद्धि हुआ ध्रुवीकरण, खेतिहर



सबहाग वग का उत्पन्न, परजीवी जमीन मालिका के नए वग का उदभव, भारतीय कृषि का औपनिवेशिक चरित्र, कृषि के पुनगठन की आवश्यक शर्तें ।

### नागरिक हस्तशिल्प का अपकथ

66

नागरिक हस्तशिल्प पर अंग्रेजी शासन का प्रभाव, देशी रजवाडा अर्थात् नागरिक हस्तशिल्प के सरक्षकों का लोप, नागरिक हस्तशिल्प पर विदेशी शासन का अनधिकारी प्रभाव, भारतीय हस्तशिल्प की घर्बादी के कारण, भारत के हस्तशिल्प के ह्रास की विशिष्टता, हस्तशिल्प के ह्रास का ऐतिहासिक महत्व ।

### ग्रामीण शिल्प उद्योग का ह्रास

77

प्राक् ब्रिटिश ग्रामीण शिल्प उद्योग, ग्रामीण शिल्पकार उद्योग के ह्रास के कारण, ग्रामीण हस्तशिल्प उद्योग के ह्रास की विषम प्रक्रिया, बच्चे खूब कारीगर और उनकी परिवर्तित स्थिति, भारतीय हस्तशिल्प के नवनिर्माण के असफल प्रयास ग्रामीण उद्योग के ह्रास के परिणाम ।

### भारत में आधुनिक उद्योगों का उदभव और विकास

86

भारत में आधुनिक उद्योगों के विकास का विकास, भारत में आधुनिक उद्योगों के विकास का संक्षिप्त इतिहास, व्यापार सभा और व्यावसायिक एकाधिकार का आविर्भाव, वित्तीय पूजा का प्रारम्भ, भारतीय अर्थतंत्र पर ब्रिटिश पूजा की घानक जगड, भारतीय उद्योग के एकांगी विकास के कारण, भारतीय इजारेदारी के विशिष्ट लक्षण स्वस्थ औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक शर्तें बाव प्लान और उसकी कमजोरिया, भारतीय औद्योगिक विकास का सामाजिक महत्व ।

### आवागमन के आधुनिक साधन और भारतीय राष्ट्रवाद का उदभव

107

प्राक् ब्रिटिश भारत में आवागमन आवागमन के आधुनिक साधनों का उदभव आवागमन के आधुनिक साधनों का एकांगी विकास, रेलवे की प्रगतिशील भूमिका ।

### भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में आधुनिक शिक्षा का योगदान

114

शिक्षा का सामाजिक महत्व, प्राक् ब्रिटिश भारतीय संस्कृति के वार में दो गलत धारणाएँ प्राक् ब्रिटिश भारत में शिक्षा, आधुनिक शिक्षा का जन्म आधुनिक शिक्षा के प्रति अस्वस्थ प्रतिक्रिया आधुनिक शिक्षा का विकास 1854 तक, वुडम डिस्पच स लाड बज्रन के युनिवर्सिटी ऐक्ट

तक, आधुनिक शिक्षा के विकास का तीसरा चरण, 1921 तक, चौथा चरण 1921-1939, भारत में आधुनिक शिक्षा की आलोचना के मूल तत्व, आधुनिक शिक्षा के प्रगतिशील तत्व, भारतीय राष्ट्रवाद आधुनिक शिक्षा का परिणाम नहीं, आधुनिक शिक्षा के लाभ, आधुनिक शिक्षा की उन्नति की आवश्यक शर्तें।

### ब्रिटिश शासनकाल में भारत का राजनीतिक और प्रशासनिक एकीकरण

141

प्राक ब्रिटिश भारत में आधारभूत राजनीतिक और प्रशासनिक वक्रता का अभाव, न्यायिक एकता, प्रशासनिक एकता, समरूप मुद्रा व्यवस्था एकीकरण की दृष्टियाँ।

### भारत में नए सामाजिक वर्गों का उदय

147

नए सामाजिक वर्गों का असमान उदय, नए सामाजिक वर्ग, नए वर्गों के उदय के कारण, उत्तरजीवी पुराने वर्ग और उनकी परिवर्तित स्थिति, जमींदार वर्ग के हित और संगठन, पट्टदारों के हित और संगठन, किसान मालिकों के विभिन्न उपभाग हित और संगठन, भारतीय किसानों के प्रमुख आंदोलन, किसानों के विशिष्ट मानसिक और चारित्रिक लक्षण, आधुनिक बुद्धिवादी वर्ग का उदय, आधुनिक भारतीय बुर्जुआजी के हित, संगठन और आंदोलन, भारत में आधुनिक सवहारा वर्ग का उदय, आधुनिक सवहारा, इसकी चरित्रगत विशिष्टताएँ, मजदूर आंदोलनों का विकास, नए सामाजिक वर्ग उनका राष्ट्रीय चरित्र, सम्मिलित स्वार्थों की चेतना, विभिन्न वर्गों की चेतना का विपरीत विकास संपत्तिशील वर्गों में बढ़ती हुई प्रक्रियावादी प्रवृत्तियाँ, भारत में दो प्रकार के आंदोलन।

### आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास में समाचारपत्रों की भूमिका

185

समाचारपत्रों का निर्णायक सामाजिक महत्त्व प्राक ब्रिटिश भारत में समाचारपत्रों का अभाव, भारतीय पत्रकारिता का विकास 1900 ईस्वी तक, भारतीय पत्रकारिता का विकास, 1900 के बाद, भारतीय समाचारपत्रों की मूलभूत राजनीतिक प्रवृत्तियाँ समाचारपत्रों के मध्य एवं स्वल्प विकास के कारण, समाचार पत्रों के विरुद्ध दमनात्मक काय-चाइयाँ का इतिहास, 1910 के प्रेस एक्ट पर सर जेम्स के विचार, 1931 और 32 के प्रेस ऐक्ट का महत्त्व, तीन समाचार एजेंसियाँ, भारतीय प्रेस की प्रगतिशील भूमिका प्रेस के विकास की आवश्यक शर्तें।



सुधार आंदोलन राष्ट्रीय जागरण के प्रतीक, सुधार आंदोलन में जनतांत्रिक भाव ।

### जाति प्रथा के विरुद्ध धमयुद्ध

202

जाति प्रथा हिंदू धर्म का लोह ढांचा, जाति वनाम वग, जाति व्यवस्था के प्रमुख लक्षण नए संपत्ति मवधा का प्रभाव, आधुनिक शहरों का प्रभाव, नए यायतंत्र का प्रभाव, नए सामाजिक वर्गों के उदय का प्रभाव, वग मधुपर्षों का प्रभाव आधुनिक शिक्षा का प्रभाव, राजनीतिक आंदोलन का प्रभाव, जाति प्रथा का प्रतिश्रियावादी रूप, जाति प्रथा के विरुद्ध आंदोलन, जाति प्रथा के ममथक आंदोलन, निम्न जातियों के आंदोलनों का द्वैत रूप, भावी प्रवृत्तियाँ ।

### अस्पृश्यता के विरुद्ध धमयुद्ध

219

अस्पृश्यता हिंदू समाज का जमानुषिक विधान, पददलित वर्गों की शक्ति, जहूतों की हालत में सुधार के आंदोलन, ब्रिटेन की तटस्थता की नीति और उसकी आलोचना, नई आर्थिक शक्तियों का प्रभाव आधुनिक शिक्षा का प्रभाव राष्ट्रीय आंदोलन के प्रभाव, अस्पृश्यता निवारण के लिए आवश्यक शर्तें ।

### स्त्री स्वातंत्र्य का आंदोलन

228

प्राक त्रिटिश भारत में नारी की स्थिति नारी की स्थिति पर नई आर्थिक शक्तियों का प्रभाव, स्त्रियाँ की स्थिति में सुधार के लिए किए गए आंदोलन, शिक्षा के अधिकार के लिए सघष, राजनीति में स्त्रियों का सहयोग, वग सघष में स्त्रियों का सहयोग ।

### हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म सुधार आंदोलन

235

धर्म सुधार आंदोलन राष्ट्रीय जागरण की ही अभिव्यक्ति, अतीत का आग्रह इसका विंगिष्ट तात्पर्य, मध्ययुगीनता वनाम उदारवादी दृष्टि कोण धर्म सुधार आंदोलनों का व्यापक प्रभाव, यूरोप में जैसे ही आंदोलन, ब्रह्म समाज आंदोलन, प्रायना समाज आय समाज, राम कृष्ण मिशन आंदोलन, थियासफी (ब्रह्मवाद), समाज सुधार की दिशा में प्रमुख राजनीतिक नताआ के काय भारत में भौतिकवादी दशन का अभाव, प्रारंभिक धर्म सुधार आंदोलनों की प्रगतिशील भूमिका, बुद्धिवाद और भौतिकवाद का विकास, मुसलमानों में राष्ट्रीय जागरण उनमें राष्ट्रीय भावना के अक्षिप्र विकास के कारण, अहमदिया

आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, सर मुहम्मद इकबाल, अय मुस्लिम सुधार आंदोलन, परवर्नी बाल म धम सुधार आंदोलनो की प्रति क्रियावादी भूमिका ।

## भारतीय राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति के रूप में राजनीतिक आंदोलनो का उद्भव

258

राजनीतिक राष्ट्रवाद, विदेशी शासन परिणाम, राजनीतिक आंदोलन के प्रथम अङ्कुर, 1857 के विद्रोह के कारण, विद्रोह का स्वरूप और उसका महत्व, ब्रिटिश शासन की युद्ध नीति, ब्रिटिश शासन की नई नीति के परिणाम, 1857 और 1885 के बीच की प्रमुख घटनाएँ, अनथकारी दुर्भिक्ष और किमान विद्रोह, इलवट विल, बढ़ता हुआ असतोष और नया नतुत्व, सुरक्षा कपाट (बचाव के रास्ते) की आवश्यकता के बारे में ह्यूम के विचार, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, उदारवादी नेतृत्व की विचार पद्धति और काय प्रणाली, उदारवादी नेतृत्व की प्रगतिशील भूमिका, मार्गें जो पूरी नहीं हुईं, बढ़ता हुआ मोहभंग, लडाकू राष्ट्रवादी नतुत्व का उद्भव, स्वदेशी और बहिष्कार, लडाकू राष्ट्रवाद के बारे में जवाहरलाल नेहरू के विचार, लडाकू राष्ट्रवादियों के प्रमुख काय, कांग्रेस में फूट, 1907, मार्लि मिंटो रिफार्म स और उसके बाद, आतंकवादी और श्रांतिकारी आंदोलन का उदय, मौटेग्यु-चेम्स फोड रिफार्म स, जालियावाला बाग की दुःखद घटना, गांधी और गांधीवाद का दौर, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन का वापस लेना और इसके परिणाम, स्वराज पार्टी की स्थापना, सांप्रदायिक तनाव में वृद्धि, समाजवादी और साम्यवादी विचारों का विकास, साइमन कमीशन के बहिष्कार से लाहौर कांग्रेस तक, पूण स्वराज का लक्ष्य घोषित नागरिक अवज्ञा आंदोलन, गांधी इविन समझौता, नागरिक अवज्ञा आंदोलन का पुनर्जन्म, नागरिक अवज्ञा आंदोलन से सबक, गांधी और गांधीवाद की सीमाएँ, उग्रवादी (मूलभूत परिवर्तन चाहने वाले) मगठनों का उदय, प्राता में कांग्रेस के मन्त्रिमंडल, गांधी और सुभाष बोस के बीच मतभेद ।

## राष्ट्रिक इकाइयों और अल्पसंख्यकों की समस्या

322

भारत में राष्ट्रिक इकाइया और अल्पसंख्यकों की समस्या, राष्ट्रिक इकाइया की उत्पत्ति के कारण, राष्ट्र और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक, उनके अंतर, भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन की विशिष्टता, सुपुत्र राष्ट्रिक इकाइया का जागरण, दो विरोधी प्रवृत्तियाँ, भारतीय मुस्लिम, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक, मुसलमानों में सांप्रदायिकता के उद्भव के कारण, मुसल-

मानों के राष्ट्रीय जागरण में विलंब के कारण, सर सैयद अहमद और मुस्लिम नवजागरण, मुस्लिम लीग और उसका सांप्रदायिक उच्च-वर्गीय स्वरूप, संप्रदाया, वर्गों और हितों की ब्रिटिश रणनीति, इस नीति की आलोचना, 1912 के बाद मुसलमानों में बढ़ता हुआ लडाकू पन, खिलाफत और हिजरत आंदोलन, सांप्रदायिकता के मूल तत्व, जिन्ना की चौदह सूत्री योजना, कांग्रेसी सरकारों की जिन्ना द्वारा की गई आलोचना, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग, दूसरे मुस्लिम संगठन, पाकिस्तान के सिद्धांत का इतिहास, पाकिस्तान के बारे में विभिन्न राजनीतिक दलों और नेताओं के विचार, (क) इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेताओं के एतद्विषयक विचार, (ख) कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी (ग) भारतीय उदारवादी, (घ) हिंदू महासभा, (च) डा० अम्बेडकर (छ) कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय इकाइयाँ की समस्या, इसकी आवश्यक शर्तें और इसका प्रगतिशील समाधान ।

उपसंहार

367

भारत में राष्ट्रवाद के विकास के प्रमुख चरण, प्रथम चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, पांचवा चरण, परिप्रेक्ष्य ।

ग्रथ सूची

375

सामान्य, सरकारी प्रकाशन

अनुक्रमणी

385

### राष्ट्रवाद ऐतिहासिक तथ्य

अप्य सामाजिक तथ्यों की तरह राष्ट्रवाद भी ऐतिहासिक तथ्य है। लोक जीवन के विकास क्रम में वस्तुनिष्ठ और भावनिष्ठ दोनों प्रकार के ऐतिहासिक तत्वों की परिपक्वता के पश्चात् राष्ट्रवाद का उदभव हुआ। जैसा ई० एच० कार ने लिखा है 'सही अर्थों में राष्ट्रों का उदय मध्ययुग की समाप्ति पर ही हुआ।'<sup>1</sup> व्यापक राष्ट्रीयता के आधार पर समाज, राज्य और सभ्यता के उदभव के पूर्व मनुष्य के विभिन्न भागों का जन जीवन, मोटे तौर पर इन स्थितियों से गुजरा कबीला की जिदगी, दास प्रथा सामंतवाद। सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के खाम तौर पर राष्ट्रों का जन्म हुआ। सामाजिक अस्तित्व के पूर्ववर्ती काल के अराष्ट्रिक जन समुदायों से आधुनिक युग के राष्ट्र अपने निम्नलिखित गुणों के कारण भिन्न हैं, राष्ट्र के सार सदस्य किसी निश्चित भूभाग में एक ही जतन के जतन परस्पर जटिल रूप से मयूक्त होत हैं, जिसके फलस्वरूप उनमें सम्मिलित जातीय अस्तित्व का भाव होता है, वे प्रायः एक ही भाषा का प्रयोग करते हैं, उनकी एक ही मनोवैज्ञानिक संरचना और उससे विकसित सामाजिक लोक संस्कृति होती है। ऐसा आदर्श राष्ट्र जा पूणत विकसित हो और जिसमें से सब गुण विद्यमान हो भावात्मक कल्पना मात्र है क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र के अथवा सामाजिक संगठन, चिंतन प्रकृति और सभ्यता में अतीत के तत्व विभिन्न अंशों में उत्तरजीवी रहते हैं। फिर भी सोलहवीं सदी से ही मानव इतिहास के विशाल रंगमंच पर राष्ट्रगत समेकन की विभिन्न अवस्थाओं में राष्ट्रीय जन समुदायों का आविर्भाव होता रहा है।

### ई० एच० कार द्वारा दी गई राष्ट्र की परिभाषा

जो विशिष्ट गुण किसी राष्ट्र को अराष्ट्रिक जन समुदायों से पृथक् करते हैं, उनके बारे में ई० एच० कार ने कहा है ' राष्ट्र शब्द से जैसे मानव समूह का बोध होता है उसके लक्षण हैं

- (क) अतीत और वर्तमान में वास्तविकता, अथवा भविष्य के लिए आकांक्षा के रूप में सवनिष्ठ सरकार की धारणा,
- (ख) अपना अलग विशिष्ट आकार और मदन्यों का पारस्परिक सपक्य-सामीप्य,
- (ग) 'यूनाधिक निर्धारित भूभाग,
- (घ) ऐसी चरित्रगत विशेषताएँ (भाषा इनमें सर्वाधिक बहुल है) जो किसी राष्ट्र को अन्य राष्ट्रों और अराष्ट्रिक समुदायों से अलग करती हैं,
- (ङ) सदस्यों के सम्मिलित स्वाय,
- (च) सदस्यों के मन में राष्ट्र की जो छवि है उससे संबंधित समवेत भाव या इच्छाशक्ति।'

### विभिन्न देशों में राष्ट्रवाद का विकास

राष्ट्रों के रूप में जन समुदायों का एकीकरण दीर्घकालीन ऐतिहासिक प्रक्रिया की परिणति है। अपनी प्रगति को अवरुद्ध करने वाले अनकानेक विघ्न बाधाओं के विरुद्ध नवजात राष्ट्रों को संघर्ष करना पड़ा। उदाहरणार्थ, इंग्लैंड में सामंतवादी राज्य व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई हुई। यह राज्य तब एक ऐसी अथव्यवस्था का समर्थक और पोषक था जिसके कारण लोग आर्थिक तौर पर एक दूसरे से अलग रहे और आर्थिक समन्वय के मूल उत्तोलक उद्योग एवं व्यापार की प्रगति अवरुद्ध रही। आर्थिक और सामाजिक अलगाव पर आधारित सामंती समाज और राज्य की पवित्रता प्रदान करनेवाले रामन चक्र की सत्ता के विरुद्ध भी नवजात राष्ट्र इंग्लैंड को घोर संघर्ष करना पड़ा और राष्ट्रीय प्राटेस्टेंट चक्र की स्थापना हुई, सुधारवादी एवं भ्रातृवारी दाना प्रकार के दीर्घकालीन राजनीतिक संघर्षों के बाद ही सामंती राज्य की जगह राष्ट्रवादी राज्य को प्रतिष्ठापित किया जा सका। राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक जीवन, अथव्यवस्था और संस्कृति को और अधिक सुमंगलित करने के लिए अंग्रेजों ने इस नई राज्य व्यवस्था का भरपूर उपयोग भी किया।<sup>3</sup>

इंग्लैंड में राष्ट्रवाद का जन्म अथ अनेक दशों के पहले हुआ। इसके जनक कारण हैं। यहाँ और दशों की तुलना में व्यापार और उद्योग का विकास पहले हुआ। इसके फलस्वरूप लोग वित्तीय नवधों से अधिकाधिक बंधत गए। इस तरह राष्ट्रीय अथतंत्र के विकास का रास्ता साफ हुआ और गणतान्त्रिक एवं राष्ट्रवादी विचारों का उदय हुआ जिन्होंने राज्य, समाज और व्यक्ति के पद और प्रतिष्ठा संबंधी सामंती सिद्धांतों पर आघात किया।

कालक्रम से आंतरिक एवं बाहरी शक्तियों के फलस्वरूप अथ दशों में भी राष्ट्रवाद के उदय के ऐतिहासिक कारण परिपक्व हुए। प्रत्येक देश में राष्ट्रवाद का विकास अलग अलग रास्ता से हुआ। किस देश में कौन सा रास्ता अपनाया यह उस देश के सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास, राजनीतिक और आर्थिक

सरचना के अतीतकालीन अवशेष और उन देशों में राष्ट्रीय आंदोलन की अगुआई करने वाले वर्गों की विशिष्ट भावधारा द्वारा निश्चित हुआ। प्रत्येक राष्ट्र का जन्म और विकास अपने आप में अद्वितीय रहा है।

सत्तरहवीं, अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दियाँ में संसार के अधिकाधिक क्षेत्रों में राष्ट्रों का निर्माण हुआ। पूर्ण विकसित होने के लिए नवजात राष्ट्र भीतरी और बाहरी अवरोधों के विरुद्ध संघर्षशील रहे, और आत्मरक्षा एवं आत्म-विवर्धन के लिए राष्ट्रों के बीच घमासान लड़ाइयाँ लड़ी गईं। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया बीसवीं सदी में भी जारी रही, जब एशिया, अफ्रीका और अथवा गैर यूरोपीय महादेशों के नवजात लोकसमुदायों ने स्वाधीन राष्ट्रों के रूप में अपने विकास के रास्ते में देशी सामंतवाद और विदेशी साम्राज्यवाद द्वारा लाई गई रुकावटों को दूर करने के लिए आंदोलन किए। राष्ट्रीय आधार पर आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के स्वतंत्र और अनवरुद्ध विकास की लालसा इन आंदोलनों के रूप में प्रतिफलित हुई। एशिया ही नहीं, यूरोप में भी, प्रथम विश्व युद्ध (1914-18) की समाप्ति पर बहुत सारी राष्ट्रजातियों ने अपनी स्वाधीनता के लिए संघर्ष किए। जैसे, मंग्यार, हंगरियन, चेक आदि जातियाँ ने बहुराष्ट्रीय आस्ट्रो-हंगेरियन साम्राज्य की सत्ता के विरुद्ध विद्रोह किया।<sup>4</sup>

प्रथम विश्वयुद्ध के उपरांत राष्ट्रमंडल और द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना इस बात का सबूत है कि आज का मानव समाज मूलतः राष्ट्र निर्मित है, विभिन्न राष्ट्रों की संयुटिका है। आधुनिक युग में राष्ट्र ही लोकजीवन का सर्वमाय, सर्वप्रचलित रूप है। समाज से वैमनस्य समाप्त करने और मानव की रचनात्मक प्रतिभा की स्वतंत्र और अक्षुण्ण अभिव्यक्ति के लिए आधुनिक समाजशास्त्रियों, राजनेताओं और राजनीतियों ने जो विभिन्न योजनाएँ बनाई हैं, वे वस्तुतः राष्ट्रवाद के सिद्धांत से ही सर्वाधिक प्रभावित हैं। सोवियत संघ ने इतिहास के विकासक्रम की दृष्टि से पूँजीवाद की अपक्षा उच्चस्तरीय समाजवादी आधार पर अपने यहाँ की अर्थव्यवस्था का परिशोधन किया। लेकिन इसने भी राष्ट्रवादी सिद्धांतों का मायता दी है यह स्वयं राष्ट्रीय गणतंत्रों का संघ है। अत्यंत साहसिक विचार वाले मार्क्सवादियों ने भी विश्व समाज के भविष्य के बारे में यही सोचा है कि यह समाजवादी राष्ट्रों का संघ होगा।

### आधुनिक युग में राष्ट्रवादी भावों की प्रधानता

इस तरह राष्ट्र ही आज का युग सत्य है, और राष्ट्रीयता मानवमात्र की मूल भावना। विज्ञान और औद्योगिकी जैसे वस्तुनिष्ठ शास्त्रों के परे अथ, राजनीति और संस्कृति के अत्याय क्षेत्रों में इधर जो आंदोलन हुए हैं वे सजग राष्ट्रीयता की भावना से ही उत्प्रेरित हुए हैं, चाहे इन आंदोलनों का संगठन राष्ट्रों ने अपनी स्वतंत्रता और संस्कृति की रक्षा और पुष्टि के लिए किया हो, या दूसरे राष्ट्रों की स्वतंत्रता और संस्कृति के अपहरण के लिए। समाजवादी या पूँजीवादी आधार



पर मानवता के एकीकरण और सारे मसाले के नवनिर्माण आदि के आधुनिक कार्यक्रमों के लिए भी राष्ट्र को ही मवप्रधान इकाई माना गया है।

### शोध का विशिष्ट क्षेत्र राष्ट्रवाद

मानव जीवन में राष्ट्रवाद की भूमिका के निर्णायक महत्त्व के कारण मसाले के कुछ सर्वश्रेष्ठ चिंतकों ने, पिछले वर्षों में राष्ट्रवाद को अपना अन्वेषण और अध्ययन का विशिष्ट क्षेत्र बनाया है। राष्ट्र किन तत्त्वों से बना है किन सामाजिक ऐतिहासिक स्थितियों में राष्ट्र का उद्भव हुआ मानव प्रगति की दिशा में राष्ट्रवाद का क्या अनुदान है, मानव के अंतरराष्ट्रीय एवं विश्वजनीन एकीकरण की आशाक्षा से इसका क्या संबंध है इन सारी समस्याओं के विवेचन और समाधान की चप्टा हुई है। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में राष्ट्रवादी भावनाओं के प्रतिफलन और उनकी अभिव्यक्ति की मीमांसा की गई है। विद्वानों ने विभिन्न देशों में राष्ट्रवाद के उद्भव और प्रसार का अध्ययन किया है और अलग-अलग देशों में इसके विकास के आनुवंशिक कारकों की खोज की है, उन्हें समझने की कोशिश की है। राष्ट्रवाद पर लिखा गया अभिनव साहित्य राष्ट्रों के रूप निरूपण की जटिल बहुविध प्रक्रिया उनके लक्षण मध्य और आत्मनिर्भरता की रीति आदि विभिन्न विषयों पर प्रचुर प्रकाश डालता है। प्रत्येक देश में राष्ट्रवाद का अपना विशिष्ट, अनन्य रूप है। अतः किसी भी देश की राष्ट्रियता का अध्ययन अपने आप में पृथक कार्य है।

### भारतीय राष्ट्रवाद के उद्भव और विकास का अध्ययन

भारतीय राष्ट्रवाद अर्वाचीन तथ्य है। ब्रिटिश शासन और विश्व शक्तिता के कारण तथा भारतीय समाज में उत्पन्न और विकसित अनेक भावनिष्ठ एवं वस्तुनिष्ठ कारकों की क्रिया प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ब्रिटिश काल में भारतीय राष्ट्रवाद का जन्म हुआ।

राष्ट्रवाद के सामान्य अध्ययन की दृष्टि से भारतीय राष्ट्रवाद के आविर्भाव और उत्थान का अपना विशिष्ट स्थान है। भारत में राष्ट्रियता के विकास की प्रक्रिया बड़ी जटिल और बहुअंगी है। उसके अनेक कारण हैं। अंग्रेजों के आगमन के पूर्व भारत की सामाजिक संरचना बड़े अर्थ में अद्वितीय थी। यहाँ की अथर्व व्यवस्था का आधार यूरोपीय देशों के मध्ययुगीन प्राक्पूजावादी समाजों से भिन्न था। भारत विभिन्न भाषाओं विभिन्न धर्मों और बड़ी आजादी वाला बहुत बड़ा देश है। आजादी का लगभग दो तिहाई भाग हिंदू है और हिंदू समाज विभिन्न जातियाँ उपजातियाँ में विभक्त है। फिर हिंदुत्व काई समशील धर्म भी नहीं बरन बहुत सारी उपासना पद्धतियों की मगुटिका है जिन्होंने इसे जन्म-अलग मप्रत्या में बाँट रखा है। भारतीय राष्ट्रवाद के विकास की पृष्ठभूमि की यह खामियत है कि विशेषतः हिंदू समाज और सामान्यतः सारा भारतीय समाज खडित और

विभाजित रहा है। किसी भी अय दश में राष्ट्रवाद का उदय ऐसी नितांत शक्तिशाली परंपरा और संस्थाओं के मदभ में नहीं हुआ। भिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचना एवं धार्मिक परंपरा, अत्यंत विस्तृत भूभाग, बढ़ती हुई जनसंख्या इन कारणों से भारतीय राष्ट्रवाद के उदभव और उत्थान का अध्ययन काफी कष्टसाध्य है लेकिन इसीलिए राचक और उपयोगी भी। मसाल के किसी भी अय दश की अपक्षा भारत में भूतकालीन सामाजिक, आर्थिक और साम्प्रतिक संरचना की आत्मरक्षात्मक इच्छाशक्ति अधिक प्रबल रही है। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का महत्व मानव इतिहास के वर्तमान और भविष्य के लिए यो भी बहुत अधिक है। राष्ट्रीयता का आंदोलन मानव समाज के बहुत बड़े जश का आंदोलन है और दिन प्रतिदिन अधिक गतिशील और गत्यात्मक होता जा रहा है।

भारतीय राष्ट्रवाद के द्वार में एक अय रोचक तथ्य यह है कि इसका आविर्भाव राजनीतिक पराधीनता के दिना में हुआ। पूर्ववर्ती राष्ट्र ब्रिटेन ने अपने स्वयं के हित में भारतीय समाज के आर्थिक ढांचे का आमूल परिवर्तन किया, केंद्रीभूत राज्य व्यवस्था की स्थापना की आधुनिक शिक्षापद्धति की नींव डाली, आवागमन के नए माधन और ऐसी अय संस्थाओं का निर्माण किया। इसके फलस्वरूप नए सामाजिक वर्गों का जन्म हुआ और अपने आप में अद्वितीय नई सामाजिक शक्तियों का उन्मोचन संभव हो सका।<sup>1</sup> य नए सामाजिक तत्व अपनी अपरिहाय प्रकृति के कारण ब्रिटिश साम्राज्यवाद से टकराए और भारतीय राष्ट्रवाद के विकास की आधारशिला ही नहीं, उसके लिए प्रेरणा स्रोत भी सिद्ध हुए। इस तरह भारतीय राष्ट्रवाद जटिल और विशिष्ट सामाजिक पृष्ठभूमि में जन्मा और सयाना हा रहा है।

प्रस्तुत पुस्तक इस सामाजिक मदभ का निर्माण करनेवाले विभिन्न तत्वों की भूमिका को समझने और उनका मूल्यांकन करने एवं राष्ट्रवाद के उत्थान की प्रक्रिया को अभिचित्रित करने का प्रयासमात्र है।

## सदभ

1 ई० एच० कार प० 7।

2 वहा प० 20।

3 दथ बीजबोड लास्की।

4 देखें मकादनी हाम बाहन रटातिन।

5 देखें बीजबोड कार।

## प्राक् ब्रिटिश भारत की अर्थव्यवस्था और संस्कृति

भारत में राष्ट्रवादी भावनाओं के उदय का इतिहास एकीकृत राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास से संबद्ध है। और यहाँ की अर्थव्यवस्था का एकीकरण उत्पादन के प्राक्पूजावादी रूपों के विघटन और उनके स्थान पर नए पूजावादी प्रकारों की स्थापना के बाद हुआ। यह आर्थिक परिवर्तन अंग्रेजों की भारतविजय के कारण ही संभव हो सका। हम इस समग्र प्रक्रिया का विभिन्न स्थितियों में, ठोस रूप से और विस्तार में, अध्ययन करेंगे। फिन्हाल नक्षेप में हम प्राक्ब्रिटिश भारत की अर्थव्यवस्था के मूलभूत लक्षणों का आकलन करें।

### आत्मनिर्भर ग्राम समुदाय

आदिम हल और बैल से खेती और साधारण औजारों की मदद से दस्तकारी की भित्ति पर टिका आत्मनिर्भर गाँव, यही अंग्रेजों के आने के पहले की भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल सत्य है। ये स्व पर्याप्त गाँव सदियों से भारतीय जीवन की मूल आर्थिक इकाई थे। इनमें 'यूनाधिक' परिशोधन हुए थे लेकिन राजनीतिक हलचल, धार्मिक उथल-पुथल और विकाशकारी युद्धों के बावजूद अंग्रेजों के आगमन के पहले तक गाँवों की चिरंतन प्रकृति लगभग अक्षुण्ण रही। विदेशी आक्रमण हुए राजवंश बदले, आपसी लड़ाइयों के बाद विभिन्न राज्यों के भूभागों का नया बंटवारा हुआ, नए राज्य बने और बिगड़े लेकिन आर्थिक इकाई के रूप में गाँवों की हैसियत ज्यों की त्यों रही। 'ग्राम समुदाय छोटे-छोटे गणतंत्र हैं। अपनी जरूरतों की सारी चीजें इन्हें अपने यहाँ प्राप्त हैं और विदेशी सबूझ से बचने में लगे हैं। जहाँ कुछ भी स्थान नहीं वहाँ ये जस जकले अमर हैं। राजकुल लुटते रहे, जातियाँ हातीं रहीं, हिंदू, पठान, मुगल, मराठा, सिक्ख, अंग्रेज क्रमशः मालिक बने, लेकिन ग्राम समुदाय यथापूर्व बने रहे।'

गाँवों में अक्सर किसान रहते थे और सारा गाँव गाँवों की जमीन का मालिक होता था। ग्राम पंचायत गाँवों की पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व करती थी, और जोत-खंड के रूप में जमीन को किसान परिवारों के बीच बाँट देती थी। परिवारों के सभी सदस्यों के सहयोग और आदिम हल-बल की मदद से प्रत्येक जोत-खंड में

खेती होती थी। किसान परिवार को परपरा से अपने जोत खडो पर पैतृक अधिकार था।

इन परिवारो के पारस्परिक सबध के बारे मे शेलवकर का कहना है 'इहे बहुत सारे सामूहिक प्रतिबध मानन पडते थे, और इहे बहुत सारी सामूहिक सेवाए प्राप्त थी। नगरपालिका जैसी सेवाए, पहरा, निगरानी आदि, सावजनिक चरानाहा और जगलो मे समानाधिकार, भूसिचन और जलापूति आदि के लिए आवश्यक सहयोग, लुटरो के विरुद्ध सुरक्षा सगठन, जगली जानवर और लावारिस गाय रैल इत्यादि से खेत और फसल को बचाने का प्रबध ग्राम जीवन की इन लाक्षणिक एव अनिवाय आवश्यकताओ के कारण किसानो पर एक ऐसा सहयाग शासन लागू था जिसके चलते तीव्र प्रतिरोधी एव असमाधेय वैयक्तिक दावो का प्रसरण सभव नही था। सारी समस्याओ के ऊपर थी गाव के अधिस्वामी को, चाहे वह स्वय शासक हो या मात्र मध्यवर्ती, मालगुजारी देने की सबदा प्रस्तुत आवश्यकता। लगान की राशि नियमत सारे ग्राम समुदाय की ओर से चुकाई जाती थी।'

### भारतीय और यूरोपीय सामतवाद

यूरोपीय सामतवाद से भारतीय सामतवाद यो भिन्न था कि भारत मे भूमिगत वैयक्तिक सपत्ति नही थी। 'हिंदू काल मे भूमि संपूण ग्राम समुदाय की हाती थी, इमे कभी राजा की सपत्ति नही माना गया।'<sup>3</sup> जमीन की पदावार के अशमात्र पर ही राजा या उसके प्रतिनिधि का अधिकार था, और यह अश सारे गाव की ओर से गाव की पचायत देती थी। 'राज्य का हक अश भाग तक ही सीमित था, और यह भाग उसे पदाय (फसल) के रूप मे ही मिलता था। मुसलमानो न पुरानी कर प्रथा और पटटेदारी को थोडे सशोधन के बाद अपना लिया।'<sup>4</sup>

राजा और उसकी प्रजा के बीच कई प्रकार के मध्यस्थ थे, जैसे, जमीदार या तहसीलदार या अभिजातवर्गीय ऐसे लोग जिन्ह राजा ने अनुग्रहवश क्षेत्र विशेष से कर वसूलन और उसे पूरा का पूरा या अशत स्वय रख लेने का अधिकार द रखा था, कुछ धार्मिक, दातव्य और शिक्षण मस्याओ को भी राजा से ऐसे ही अधिकार प्राप्त थे। लेकिन वास्तविक भूस्वामी न तो राजा स्वय था और न ये मध्यस्थ ही। फलत शासको मे परस्पर या मध्यस्थो अथवा ग्राम समुदायो से उनके जा सघप हुए प्राय उनका विषय यह होता था कि गाव की फसल और पैदावार का कितना हिस्सा कौन लेगा। परपरागत व्यवहार और विश्वास के कारण भूमि पर ग्राम समुदाय के अधिकार और नियंत्रण को न तो राजा ने और न मध्यवर्ती सत्ताधारियो ने ही कभी खतम करने की कोशिश की। लेकिन अगर इन लोगो ने भूमि पर अपना हक जमाने की कोशिश नही की, तो कृषि की उन्नति की ओर भी ध्यान नही दिया।

वस्तुत भारतीय इतिहास के महान सघपों मे किसी एक का भी उद्देश्य यह नही था कि गावो मे सत्ता का उपयोग कैसे हो, वरन यह कि गावो पर सत्ता का

उपयोग कैसे हो। विभिन्न स्तर के अधिस्वामियों के बीच य मघर्ष भूमि पर अधिकार के लिए नहीं बरन उससे लगान वमूलन के अधिकार के लिए होते थे। इसके विपरीत, यूरोपीय इतिहास में किसानों और भूपतियों के मघर्ष हुए हैं, जिनका कारण यह था कि भूपति फसल में हिस्सा तो मांगता ही था, लेकिन साथ ही धरार से खेती जैसे पुराने तरीके भी बनाए रखना चाहता था या फिर बाड़ा लगाना और बड़े पैमाने पर खेती करने जैसे नए तरीके चालू करना चाहता था। भारत में लड़ाइयाँ ऐसे भूपतियों के बीच हुईं जिन्हें खेती के तरीके से कोई मतलब नहीं था और जो किसानों से मात्र आय अर्जन चाहते थे। लड़ाई तलवार के धनी लोगों के बीच होती थी। गाँव और किसान इन मघर्षों के मूक, निष्क्रिय विषय होते थे, लूट की वस्तु जिसके लिए प्रतिद्वंद्वी शक्तियाँ परस्पर लड़ती रहती थी।<sup>6</sup>

### प्राक् ब्रिटिश भारत का ग्रामीण अर्थतंत्र

भारतीय गाँवों के कृषि उत्पादन की संरचना सदियों में ज्यादती रही। भूमि पर गाँव की जनता के परंपरागत स्वत्व का न तो किसी सम्राट और न उमके किसी प्रतिनिधि ने ही कभी चुनौती दी। गाँव के लोगों की जरूरतों को पूरा करना ही ग्रामीण कृषि का चरम उद्देश्य था। किसी निश्चित काल में क्षेत्र विशेष का जो अधिस्वामी होता था, कभी दिल्ली के शाहशाह का स्वदार, कभी पूना के पेशवा का स्वदार, उसे पदावार में हिस्सा देना पड़ता था, शेष लगभग सारी उपजाऊ गाँव की कृषक और गैर कृषक जनसंख्या के काम आती थी।

गाँवों में किसानों के अतिरिक्त बड़ई, लोहार, कुम्हार, जुलाहा, मोची, धाबी, तेली, हजाम जैसे मजदूर किस्म के लोग भी रहते थे। लेकिन ये भी गाँव की ही जरूरतों को पूरा करने के लिए खटते थे। ग्राम समुदाय में 'कमबरा' का भी बग होता था जो हठबोरों का काम करते थे और जड़ूत ममर्के जाते थे। इनमें अधिकांश देश के उन आदिम निवासियों के वंशज थे, जिनको समूह विनष्ट करने के बदले, प्राचीन काल के हिंदू समाज में आत्मसात कर लिया था।<sup>6</sup>

गाँव में जिन वस्तुओं का उत्पादन हुआ उनका विनिमय गाँव की जनता तक ही सीमित था। गाँव के लगभग संपूर्ण उत्पादन का उपभाग गाँव की ही जनता करती थी। गाँव के उत्पादन सबधा के बारे में शेतावरक न कहा है

यह कहना बदाचित्त मही नहीं कि व्यक्तियों के बीच परस्पर विनिमय मघर्ष था। जरूरत पड़ने पर किसान कारीगरों के यहाँ अपनी निजी हैसियत में ही जाते थे लेकिन जो भुगतान होता था वह अलग-अलग काम के हिसाब से नहीं जोड़ा जाता था और न प्रत्येक महत्त्व से अलग-अलग मिलता था। भुगतान सारे गाँव की एकत्र जिम्मेवारी थी और प्रत्येक कारीगर का सार समुदाय की ओर से गाँव की जमीन का कुछ अंश स्थाई तौर पर जोतने काटने के लिए मिला रहता था, या फसल काटने पर उस अनाज की निश्चित राशि दे दी जाती थी। बड़े जगह दाता तरह की व्यवस्थाएँ लागू थीं। गाँव के

विनिमय व्यापार का दूसरा साक्षीदार गाव का सामूहिक संगठन भी उतना ही था, जितना अलग अलग किसान। गाव का कारीगर स्वतंत्र उत्पादक न होकर समुदाय द्वारा नियुक्त जनसेवक जैसा था।<sup>8</sup>

इस तरह भारतीय गावों का बाहर की दुनिया से तो कोई विनिमय संबंध नहीं था, गावों के अंदर भी बाजार जैसी चीज नहीं थी। प्राफेसर गाडगिल ने कहा है, 'गावों का पृथक्त्व स्वतंत्र उल्लेख्य नहीं है और न यही कोई विशिष्ट तथ्य है कि सभी कारीगर गाव में ही रहते थे। भारतीय गावों की विशिष्टता यह थी कि अधिकांश कारीगर सारे गाव के सेवक हात थे।'<sup>9</sup>

गावों के आर्थिक जीवन के बारे में यह भी ज्ञातव्य है कि कृषि और उद्योग के अपर्याप्त विशिष्टीकरण के चलते श्रम विभाजन बहुत नहीं हो सका था। मुख्यतः कृषि केंद्रित होने पर भी किसान परिवार घर पर सूत कातने का काम करते थे। साथ ही कारीगरों को ग्राम पंचायत से खेत प्राप्त था, और साल के कुछ दिनों वे मूलतः खेती में ही मग्न रहते थे।

ग्रामीण कारीगरों को गाव से ही अपने शिल्प के लिए आवश्यक कच्चे माल, जैसे लकड़ी, मिट्टी और चमड़े का प्रबंध करना पड़ता था। बगल के जंगलों में लकड़ी मिल जाती थी, मरे हुए जानवरों की लाश से मोची अपने काम के लिए चमड़ा निकाल लेता था देश के प्रायः प्रत्येक भाग में खई की खेती होती थी। कंबल लोहा बाहर से लाना पड़ता था। कारीगर उद्योग के हेतु आवश्यक कच्चे माल के लिए गाव लगभग स्वपर्याप्त थे।

इस तरह आर्थिक रूप से गाव आत्मनिर्भर थे। स्थानीय श्रम और साधन प्रसूत स्थानीय उत्पादन का स्थानीय उपभाग होता था। गाव और बाहर की दुनिया के बीच विनिमय संबंध लगभग शून्य थे। अक्सर मप्ताह में किसी एक दिन किसी बड़े गाव के बाजार में कई केंद्रों से आए कई तरह के सामानों की बिक्री होती थी। उन दिनों जो थाड़ा बहुत व्यापार होता था वह इसी रूप में सम्भव था।

गाव संपूर्णतः स्वपर्याप्त थे कच्चा माल भी समीप ही प्राप्त था। गाव के अपने ही क्षेत्र में उगे हुए जंगल की लकड़ी का औजारों और मकान बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। खई देश के कई भागों में प्राप्त थी। जिन वस्तुओं का उत्पादन होता था, उनमें अधिकांश की रफत गाव में ही हो जाती थी, जो बचता वह मप्ताह में एक बार होने वाले ग्रामीण मेलों में बेचा जा सकता था। हस्तशिल्पियों की काय निपुणता सदियों की वंशगत परंपरा का परिणाम थी और उनके विभिन्न व्यवसाय घम संगत थे।<sup>10</sup>

गावों के कृषि और उद्योग की तकनीक निम्न स्तर की थी। कृषि और विनिर्माण के लिए मात्र हस्तचालित औजारों की ही जानकारी थी। वायु और जलचालित चकिया का भी शायद ही कभी इस्तेमाल हुआ हो। हसिया और हल, छेनी और आरा, चरखा और गत करघा कम समय में कम सामान में तैयार हो जाते थे, लेकिन पीटिया तक उनसे काम चलता था।<sup>11</sup>

इस अल्प शक्तिशील तवनीक सं चलने वाले कृषि और उद्योग पर आधारित गावों का आर्थिक जीवन सदियों तक अपरिवर्तनशील रहा। बाहर की दुनिया से लगभग स्वतंत्र और साथ ही सामाजिक विनिमय से अछूता आत्मनिर्भर गाव शताब्दियाँ तक स्थिर, अचल, रूढ़िगत सामाजिक अस्तित्व का अविच्छेद्य, अविजेय दुर्ग बना रहा। गाव के एकरस जीवन में एकमात्र क्रमबद्ध आकस्मिक विपत्ति, पहाड़ों के पार से भूभक्षी जातियों के आक्रमण या सूखा द्वारा उत्पन्न बाधा-विघ्न द्वारा हुआ।<sup>1</sup> कालमावस ने स्पष्ट और चित्रात्मक शैली में इस अपरिवर्तनशील सामाजिक जैव विधान का वर्णन किया है

ये छोटे और बड़े पुराने भारतीय जन समुदाय भूमि के मयुक्त अधिवासी, कृषि और हस्तशिल्प के संयोजन और अपरिवर्तनशील श्रम विभाजन पर आधारित हैं। इनमें प्रत्येक स्वयं एक संपूर्ण इकाई है जो आवश्यक वस्तुओं का खुद उत्पादन करता है। उत्पादन के बड़े भाग का समुदाय स्वयं उपभोग करता है और वह विक्रयशील पण्य का रूप नहीं लेता। भारतीय समाज की समग्रता में पण्य विनिमय द्वारा उत्पन्न श्रम विभाजन से उत्पादन मुक्त है। उत्पादन के अधिष्ठापक का अग्रमान ही पण्य का रूप लेता है जब वह राज्य शासन के पास पहुँचता है। प्राचीन काल से उत्पादना का कुछ हिस्सा भूमिकर के रूप में राज्य को मिलता रहा है। इन समुदायों का वैधानिक संगठन भारत के विभिन्न भागों में अलग-अलग है। जो सबसे सरल रूप है उसमें सब सम्मिलित रूप से खेत की जुताई करते हैं, और फसल समुदाय के सब लोगों में बाँट दी जाती है। साथ ही हर परिवार सहायक उद्योग के तौर पर कटाई और बुनाई भी करता है। ग्राम प्रमुख यायाधीश, पुलिस और तहसीलदार का सम्बन्धित रूप है, बही खाता रखने वाला जुताई का हिमायत रखता है, एक पदाधिकारी विशेष अपराधियों का चालान करता है, गाव से गुजरने वाले यात्रियों की रक्षा करता है और दूसरे गाव की सीमा तक पहुँचा देता है, सीमा रक्षक पड़ोसी समुदायों से गाव की चौहद्दी की रक्षा करता है पानी का ओवरसियर सामूहिक जलाशयों से सिंचाई के लिए पानी का बंटवारा करता है, ब्राह्मण धार्मिक कार्यों की देखभाल करता है, अध्यापक बच्चों को लिखना-पढ़ना सिखाता है, पचास ब्राह्मण या ज्योतिषी बीजारोपण और फसल की कटाई के लिए अच्छी और बुरी साइत बताता है, बडई और लोहार खेतों के औजार बनाते हैं और उनकी मरम्मत करते हैं कुम्हार गाव के लिए आवश्यक मिट्टी के सारे बर्तन बनाता है नाई, घोड़ी और सोनार अपने पेशे के काम करते हैं, जहाँ तहाँ कवि (या भाट) भी मिलते हैं जो कुछ ग्राम समुदायों में सोनार और कुछ में अध्यापन का भी काम करते हैं। इस तरह के दजन भर विस्मय के लोग समूचे समुदाय के खर्च पर चलते हैं। आबादी बढ़ जाने पर नई अनधिकृत घरों पर पुराने ढर्रे पर नया समुदाय कायम होता है समुदाय में श्रम विभाजन का नियोजन करने वाले कानून प्राकृतिक

नियमों की दृढ़ता से काम करते हैं ये स्वपर्याप्त समुदाय सदा अपने चिरतन रूप में ही फिर-फिर आविर्भूत होते रहते हैं, अगर दुर्योगवश नष्ट हो गए तो उसी स्थान पर उसी नाम से फिर उदित हो जाते हैं। इन समुदायों में उत्पादन का संगठन बड़ा सरल रहा है और यह सादगी ही एशियाई समाजों की अपरिवर्तनशीलता के रहस्य की कुंजी है। एशियाई राज्यों के निरंतर विघटन पुनरुत्थान और राजवशों में हरदम होते रहने वाले परिवर्तन से सामाजिक संगठनों की अपरिवर्तनशीलता का मेल नहीं बठा। राजनीतिक आकाश के बादल बबुल से समाज के आर्थिक तत्वों की संरचना अछूती रही।<sup>13</sup>

ग्राम समुदाय की यह भी चारित्रिक विशेषता रही है कि लोगों का व्यवसाय उनकी जाति पर पूर्णतः निर्भर था। जातियों की तरह व्यवसाय भी आनुवंशिकता के सिद्धांत पर आधारित थे। आर्थिक जीवन एवं विनियम गावों की सीमा में ही संकुचित था, अतः शादी-ब्याह या तीर्थयात्रा के अतिरिक्त यात्रा का न तो कोई औचित्य था और न आवागमन के साधनों के विकास के लिए कोई उद्दीपन। अंग्रेजों के आगमन के पूर्व बैलगाड़ी ही आवागमन का प्रमुख साधन थी। ग्रामीण जीवन के सामाजिक एवं अर्थ-पहलुओं के बारे में आंमिली का कहना है

गावों की मुख्य सामाजिक संस्थाएं अपनी समष्टि में व्यक्तिवादी नहीं बरन समुदायवादी थीं। मूल सामाजिक इकाई व्यक्ति न होकर परिवार था। परिवार ही समाज के मारे सदस्यों के पारस्परिक संबंधों को व्यवस्थापित करता था, और विभिन्न परिवारों के आन्तरिक संबंधों पर ग्राम समुदाय और जाति व्यवस्था का नियंत्रण था। ग्राम समुदाय सामुदायिक स्वशासन के लिए संगठित परिवारों का समूह था, जाति शादी-ब्याह खान-पान, पेशा, ग्राम समुदाय के अर्थ-सदस्यों से व्यवहार-विचार संबंधी समरूप विधानों द्वारा शासित परिवारों की मण्डिका थी, यद्यपि जाति-ग्राम समुदाय की तरह स्थानीय संस्था नहीं थी। व्यक्ति पर परिवार, जाति और ग्राम समुदाय का वैचारिक नियंत्रण था और उसे इनके द्वारा स्थापित आदर्शों को मानकर चलना पड़ता था। समष्टि की सदस्यता के अतिरिक्त जैसे व्यक्ति का कोई अस्तित्व ही नहीं था। समूह द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर ही आत्म-संकल्प भी संभव था। ग्राम समुदाय की सामाजिक हैमियत नगण्य थी। यह अधिकांशतः आर्थिक और प्रशासनिक संगठन था और इस पर राज्य को नियंत्रण रखने का भी हक था, यद्यपि इस हक का इस्तेमाल कम ही होता था। परंतु जातीय एवं पारिवारिक प्रश्नों से राज्य को कोई सीधा सरोकार नहीं था। लोगों के जातीय और पारिवारिक संबंध हिंदू धर्म और परंपरागत नियमों पर आधारित थे।<sup>14</sup>

प्राक् ब्रिटिश भारतीय समाज के दीर्घ अस्तित्व काल में व्यक्ति सदा जाति, परिवार और ग्राम पंचायत के अधीनस्थ रहा। अठारहवीं सदी के अंत में भी भारतीय समाज, मूलतः देहाती इलाकों में परिवार-जाति और ग्राम पंचायत के



प्रति एव शहरी इलाका में व्यापारजय निगमा और कमकर मगठनों के प्रति उत्तरदायित्व की भावना पर आधारित था।<sup>1</sup>

### प्राक् ब्रिटिश भारत में नागरिक अथव्यवस्था

प्राचीन भारत में छोटे-छोटे गावों के बीच कुछ शहर भी थे जिनका राजनीतिक धार्मिक या व्यापारिक महत्व था।<sup>10</sup> राजनीतिक महत्व वाले नगर राज्या या साम्राज्या की राजधानी थे। यहीं से शासन के कार्य परिचालित होते थे, ये सम्राटों और राजकुमारों के मुठ्यालय थे। विभिन्न राज्याधिकारी और सेनाध्यक्ष, अभिजातवर्ग के लोग और उनके पिठनगुण भी यहीं रहते थे। सेना की छावनी भी राजधानी में ही होती थी। शासन एवं अभिजात वर्ग की दैहिक या कलात्मक, स्वस्थ या अस्वस्थ आवश्यकताओं तथा मनोरंजन की पूर्ति के लिए वारागनाए संगीतज्ञ स्थापत्य कला विचारद, चित्रकार कवि आदि भी इहीं शहरों में रहते थे।

वनारस मथुरा पुरी नासिक जैसे दूसरे प्रकार के भी शहर थे जो मुख्यतः उपासना केंद्र या तीर्थस्थल थे। हजारों तीर्थ यात्रियों की जरूरतों का खयाल रखनवाले लोगों की इन शहरों में एक निश्चित आगामी हाती थी। इनके अनिश्चित व्यापारिक महत्व के ये शहर भी थे जो आवागमन के उपयुक्त नदियों के किनारे या प्रसिद्ध वाणिज्यिक मार्गों के मगम पर या समुद्र तट पर बसे थे। इन नगरों में विविध हस्तशिल्प उद्योग परलवित हुए। बैलवटन ने लिखा है

तीव्र बुद्धि सूक्ष्म योग्यता और सजनात्मक प्रतिभा के फलस्वरूप भारतीय उद्योग पाश्चात्य देशों से अपेक्षाकृत आगे बढ़े हुए थे। गुप्त की उन शताब्दियों में जो पाश्चात्य नौपरिवहन संस्था अविक्सित था, भारत ने भारी बोझ ढालने वाला समुद्री जहाज बनाए थे

वस्त्र निर्माण हिंदुस्तान का प्रमुख उद्योग था और यहाँ के सूती और रेशमी कपड़ों की सारी दुनिया में तारीफ और मांग थी। तरहवी, चौदहवी और पंद्रहवी शताब्दियों में धातु कार्य प्रस्तरशिल्प, शक्कर नील और कागज के भी उद्योग विकसित थे। कुछ भागों में काष्ठव्यय मृत्तिका पाल और चमकदार आदि उद्योग भी परलवित हुए। देश के कई हिस्सों में रंगाई प्रमुख उद्योग थी, कुछ भागों में साने के ताल और कसीदाकारी का काम पूणता के चरमबिंदु तक विकसित था

माना से रागा पारा और कुछ हद तक लाहा निकालने और शीश के निर्माण के कार्य भी महत्वपूर्ण और विकसित उद्योग थे। बहुत सारे यंत्रिया न भारत में निर्मित लोह और यहाँ के रामायनिक उद्योग की प्रशंसा की है। चीन की तरह भारत में भी चीनी मिट्टी के बरतना का उद्योग काफी विकसित था। गजदंत से भुजदंड, जगूठी, पाम मनका पलग और अन्य जनक चीजे बनती थी और सारी दुनिया में, खानकर यूरोप में, इनकी बड़ी मांग थी।

वेशमीमती पथग पर किए गए काम में भी बड़ी कुशलता का परिचय मिलता है।<sup>17</sup>

नगर उद्योग मपन बणिक और कुलीन परिवारों के लिए विलासिता के सामान, कुट्टित इस्पात से लड़ाई के हथियार तथा सेना के अन्य सरजाम, मैनिक दुग विशाल मंदिर, भव्य राजप्रासाद, ताजमहल और कुतुबमीनार जैसे अभियन्त्रण कला के विरल स्मारक, और नेता की सिंचाई के लिए नहरों का निमाण करता था।

प्राक ब्रिटिश भारत का नागरिक हस्तशिल्प अत्यंत विकसित था। यहां की उच्चकला गुणमपन विविध कृतिया सारी दुनिया में मशहूर थी और सब जगह उनकी मांग और खपत थी। कौलवटन ने लिखा है प्राचीन काल में जब रोम के निजी और सावजनिक भवनों में भारतीय कपड़ों, दीवारदरी तामचीनी मोजेक, हीरे-जवाहगत आदि का उपयोग होता था उस काल से औद्योगिक क्रांति के प्रारंभ तक जाकपक और उद्दीपक वस्तुओं के लिए सारा ससार भारत का मोहताज रहा।<sup>18</sup>

विभिन्न जननमुदाया की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला यह नगर उद्योग मूलतः तीन भागों में विभाज्य है। शहरों के सारे औद्योगिक रोजगार का बहुत बड़ा हिस्सा भारत और विदेशों के कुलीन और मपन लोगों के लिए विनासिता एवं जट्टविलासिता के सामान तैयार करता था। इसके बाद उन रोजगारों का नंबर आता है जो राज्य या अन्य सात्रजनिक संस्थाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। उद्योगों की जो तीसरी किस्म थी उसमें लोहा गलाने कलमीशोरा तैयार करने या चूड़ी बनाने जैसे काम थे। ये प्रायः स्थानीय उद्योग थे और देश के कुछ ही हिस्सों में प्रचलित थे।<sup>19</sup>

नागरिक उद्योगों में काम करनेवाले लोग मूलतः दो प्रकार के थे वे जो स्वतंत्र रूप से काम करते थे और वे जो राज्य या निगम या दूसरे लोगों की नौकरा करते थे।

स्वतंत्र उत्पादक की हैमियत रखनेवाले हस्तशिल्प कारीगर उत्पादन के लिए आवश्यक औजार और कच्चे माल के मालिक होते थे अपने खुद के मकान में काम करते थे और बाजार में मंत्रय अपना सामान बेचते थे। शहरों के जो मजदूर कारीगर रोजी पर काम करते थे, उन्हें कच्चा माल अपने मानिक से मिलना था निश्चित स्थान पर काम के लिए हाजिर होना पडना था, और जिन वस्तुओं का वे निर्माण करते थे वे उनका नियोजना के लिए हाती थी, न कि बाजार में मिक्री के लिए।

नगर उद्योगों के विषय में मभवत सर्वाधिक उल्लेख्य तथ्य यह है कि उनका बाजार अत्यंत सीमित था। इन उद्योगों में साधारण लोगों के दैनिक इन्तमाल की चीजों के बदले शीपमथ व्यक्तियों एवं मन्थाना के लिए आवश्यक उपकरण तैयार होते थे। फिर गाववालों की जरूरतें तां स्थानीय कारीगर उद्योगों से

ही पूरी हो जाती थी। इस तरह नगर उद्योग का बाजार इने गिने इलाकों में सीमित रहा।

आर्थिक और सामाजिक संरचना के पूँजीवादी रूप परिवर्तन के लिए जरूरी शर्तें प्राकृतिक भारत में मौजूद थीं, लेकिन इनमें इतनी ताकत नहीं आ सकी थी कि ऐसा परिवर्तन हो सके। वाणिज्यिक पूँजी और नगर उद्योग जैसी देशज सामाजिक शक्तियों के बल पर भारत में बुजुर्ग समाज का विकास नहीं हो सका, और इसकी वजह थी कि अंग्रेज पूँजी भारत की राजनीति एवं अर्थतंत्र की कुछ अपनी विशेषता थी, जैसे गावों की आत्मनिर्भरता जो देश की पूँजीवादी प्रगति की दिशा में सबसे बड़ी बाधा थी।

गृह शिल्प और कृषि के सहज सरल मयोजन एवं तज्जय अथतत्त्व के कारण गाव अपना सतुनन सुरक्षित रख सकता था और विघटन की प्रक्रिया का सबल प्रतिरोध प्रस्तुत कर सका।<sup>20</sup>

गावों में साधारणतः (यूरोपीय) कृषक दासता या बँरना द्वारा किए गए शोषण के लिए स्थान नहीं था। इसीलिए भारतीय गावों की आर्थिक संरचना काफी मुखर रही और वे अपना प्रभिन चरित्र बनाए रखने में सफल रहें यद्यपि इस काम में (यूरोपीय) मेजर असफल रहे थे। उन्नीसवीं सदी में जब बहुत बड़े पैमाने पर चीजों का उत्पादन होने लगा, तब इस नई परिस्थिति का सघात गावों ने बर्दाश्त कर लिया और अंत में राजनीतिक एवं आर्थिक परिवर्तन के सम्मिलित आघात से ये समाप्त हुए। अगर हम इन बातों पर दृष्टिपात करें तो इनके दीर्घकालीन अस्तित्व पर अचरज की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती।<sup>1</sup>

शहर के औद्योगिक एवं वाणिज्यिक वर्ग गावों में वहाँ की सतुलित अर्थ-व्यवस्था के कारण व्यापारिक क्रियाकलाप का विस्तार नहीं कर पाए। इस तरह प्राकृतिक भारत में व्यापार और उद्योग का विकास तो सीमित रहा ही ये वर्ग सामंती राजाओं और उनके कुलीन महचरा पर आश्रित बने रहें। वे न तो गावों पर अपना आर्थिक प्रभुत्व कायम कर सके और न सामंतवाद के विरुद्ध ग्रामीण जनता का समर्थन ही प्राप्त कर सके, और इस तरह सत्तासीन होने से वंचित रहें।

शेखर के अनुसार एक और कारण से भी प्रारंभिक भारतीय बुजुर्ग समाज सामंती राजतंत्र को समाप्त न कर सकी और सक्षम पूँजीवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना में असफल रही। भारत की कृषि व्यवस्था के लिए लोचननिर्माण और सिंचाई के कार्य आवश्यक थे और इन्हें ऐसा कोई संगठन ही पूरा कर सकता था जिसे राज्य के सार साधन एवं अधिकार प्राप्त हों। इस तरह भूमिकर्ता की बसूली एवं जनकाल के नियंत्रण, नियमन और पर्यवेक्षण के लिए राज्य को विभिन्न स्थानीय केंद्रों, अर्थात् शहरों में अपने प्रतिनिधि रखने का बाध्य होना पड़ा। इस तरह यद्यपि राज्यों की नियति भूमि पर आश्रित थी, फिर भी भारत में राज्यों ने शहर

को अपने क्रियाकलाप का केंद्र रखा और उन पर अपनी पकड ढीली नहीं होने दी।<sup>23</sup>

संभवत इही कारण से भारतीय बुर्जुआजी राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में शीपस्थ नहीं हो सकी और भारत में पूँजीवाद प्रबल आर्थिक व्यवस्था के रूप में नहीं पनप सका। 'गावों की अमेध दृढता और बुर्जुआजी की राजनीतिक नपुंसकता के कारण भारतीय अर्थतन्त्र का विकास अवरुद्ध रहा और पूँजीवादी व्यवस्था का स्वतः स्फुरण असंभव हो गया।'<sup>4</sup>

वाद में इंग्लैंड की अग्रवर्ती बुर्जुआजी ने भारत के सामंती रजवाड़ा की राजनीतिक शक्ति का उन्मोचन किया, देश पर अपना राजनीतिक स्वत्व स्थापित किया और यहाँ की ग्रामीण एवं नागरिक अथव्यवस्था का दूर तक पूँजीवादी रूपांतरण किया। मार्क्स के अनुसार भारतीय इतिहास की यह एकमात्र विशुद्ध सामाजिक क्रांति है।

### प्राक् ब्रिटिश भारत में ग्राम सस्कृति का रूप

अब हम प्राक्-ब्रिटिश भारत के लोगों की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति का सर्वेक्षण करें। भारत का सारा मानव समाज अनेकानेक गावों में फैला बटा था। इन गावों का बाहर की दुनिया से कोई सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक संपर्क नहीं था। इसलिए गावों के अधिकांश लोगों का मस्तिष्क पूर्णतः विकसित नहीं हो सका।<sup>25</sup> बाहर की दुनिया से गावों का आर्थिक विनिमय नहीं के बराबर था और ब्रह्मगण्डो आवागमन का एकमात्र साधन थी। फलस्वरूप गाव की आबादी एक छोटी इकाई बनकर रह गई जिसकी अपनी जलग जिंदगी थी। केवल देहाती मेला, तीर्थयात्रा या शादी-ब्याह जैसे मौकों पर ही गाव वाले बाहर जाते थे, और वह भी महज कुछ दिनों के लिए।

गावों के अंदर आदिम कृषि और उद्योग पर आधारित आर्थिक जीवन निम्न-स्तरीय और स्थिरप्रायः रहा। मुग़ल तक आदिम हल-बैल और कारीगर के अलग-अलग औजारों से उत्पादन का काम होता रहा। फलस्वरूप श्रम की उत्पादक शक्ति भी सीमित रही और क्रूर एवं लोभी सरकारी की लगान देने और रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद जनसाधारण के पास न तो उत्पादन का कोई अधिपेय ही बचता था और न भौतिक एवं सांस्कृतिक जीवन के उच्चस्तरीय विकास के लिए समय ही।

गावों के लोगों का वैज्ञानिक ज्ञान और भौतिक उत्पादन सबधी उनकी तकनीक दानी अत्यन्त तुच्छ और नगण्य थी। आवागमन के साधनों और बाहर की दुनिया से विनिमय संबंधों के अभाव के अलावा उपरोक्त कारणों से भी गावों के लोगों की जिंदगी अनिश्चित रही। फसल की बचाव या बाढ़ के वक्त तो सारा गाव के अस्तित्व पर ही खतरा आ जाता था क्योंकि बाहर से किसी की मदद नहीं मिल सकती थी।

अनिश्चित आर्थिक जीवन और प्राकृतिक विपत्तियों के सामने निस्महायता आदि के कारण गांव वाला की विचार पद्धति अधविश्वास, धार्मिक रहस्यवाद और प्राकृतिक शक्तियों की अपरिष्कृत उपासना के रास्ते विशिष्ट हुआ। उनके जीवनदर्शन में पराजय और नैराश्य की भावना बनवती रही।

विभिन्न जातियों में बड़े होने के कारण गांवों में व्यभिचरित पहलशक्ति दुस्साहस की भावना और नए रास्ते की खोज करने की आकांक्षा को कोई प्रश्रय नहीं मिल सका। जाति प्रथा का देनी विधान मानकर इसके सारे प्रतिबंध और प्रतिरोधों के सामने गांववाले आज्ञाकारी की तरह नतमस्तक थे और ग्रामीण जीवन की सामाजिक और आर्थिक मरचना में इश्वरकृत जाति प्रथा उनका जा स्थान और कम नियत कर देनी थी उसे निश्चेष्ट रूप से मान लेते थे। गांवों का आदमी जीवन की धार्मिक रहस्यवादी व्याख्याओं से पूर्णतया अभिभूत था और उस शायद ही कभी यह इच्छा हुई हो कि वह तत्कालीन सामाजिक मरचना और उसकी आधारभूत विचारपद्धति पर किसी प्रकार का अन्वेषण अनुसंधान या विचार विमर्श करे। गांवों का पथक और मरुत सामाजिक जीवन बाढ़ या सूखा जसी प्राकृतिक शक्तियों द्वारा मानवीय प्रयास पर तुपारापान जाति प्रथा और एकतंत्रवादी मयुक्त परिवार और धार्मिक रहस्यवादों दर्शन जिनमें मारी पागा पथी शक्तियों की बल मिला था मरु मिलकर बौद्धिक अभिन्नमशीलता, प्रयोग एवं अन्वेषण की भावना और त्रिद्रोहात्मक प्रवृत्ति का गला घाटते रहे।

सदियों तक गांवों की सामाजिक और बौद्धिक स्थिति अनुचर, अधविश्वास पूर्ण सन्तुष्टि और रुढ़ बनी रही। ये गांव जातिक प्रवाहहीनता, सामाजिक प्रतिन्यावाद और सांस्कृतिक अधेपन के अलग जनग तुग थे, नगभग सारा भारतीय समाज इन्हीं स्वायत्तशासी स्वपयाप्त मन्वगत गांवों में केंद्रीभूत था और यह मानव समाज एक ही प्रकार के अधविश्वासा प्राचीन दय देविया, मकुचिन ग्रामीण एवं राष्ट्रीय चेतना और एक म्याइ दृष्टिवाद के शिकज में युगा तक पडा रहा।

यत्नांदा जैसे समुद्रमुक्त या जकरर के शासनकाल में, भारत के गृहण बड़े भूभाग में एकछत्र राज्य स्थापित हुआ लेकिन उन दिनों भी स्वायत्तशासी गांवों की मूलभूत जीवन प्रक्रिया अक्षुण्ण रही। गांवों के जीवन में ऐसी घटनाओं का बंधन इतना ही जसर पडता था कि लोग जब पुरान के उदले नए समाट का निया जाना था। लेकिन गांव स्वपयाप्त बने रहे, पुराना समितिया और पुरान विधायो द्वारा उनका शासन चलता रहा, सामाजिक और आर्थिक विच्छेपन के कारण बौद्धिक एवं मानसिक जडता बनी रही। भारतीय इतिहास में लगातार जा गनिक, राजनीतिक और धार्मिक उथल पुथल होती रही उसके बावजूत रुटिवादी, अपरिवर्तनशील, आत्मनिर्भर गांवों का अमनी तन्ना नगभग ज्या का त्या बना रहा।

राष्ट्रीय चेतना के उदभव के लिए आवश्यक है मन्मिन्नित और एकतापूर्ण

राजनीतिक और आर्थिक जीवन, और इसके अभाव में भारत में राष्ट्रवाद का जागरण नहीं हो सका। एकीकृत राष्ट्रीय जीवन तभी संभव है जब उत्पादक शक्तियाँ काफी विकसित हों, श्रम विभाजन सावधानीपूर्ण हो और व्यापक आर्थिक विनियमन त्रिआशील हो। इसके लिए यातायात और मंचारक साधना का विकास आवश्यक है, इनसे आर्थिक जीवन और अधिक संपुष्ट होता है लोगों का इधर-उधर आना जाना बढ़ता है, बड़े पैमाने पर सामाजिक और बौद्धिक विनियमन संभव हो पाता है और इस तरह सारे देश में एकता की भावना बढ़ती है।

आत्मनिर्भर गाँवों के युग में देश में सम्मिलित आर्थिक जीवन नहीं के बराबर था और इसलिए सम्मिलित आर्थिक जीवन की चेतना आविर्भूत नहीं हो सकी।

इसी तरह सम्मिलित राजनीतिक अस्तित्व की चेतना का भी अभाव था, क्योंकि गाँवों के सामाजिक, वंचारिक, आर्थिक और प्रशासनिक जीवन पर राज्य का कोई प्रभाव नहीं था। यदा कदा योग्य और विजयी राजा देश में जो राजनीतिक और प्रशासनिक एकता कायम कर सके वह मात्र ऊपरी एकता थी। राजनीतिक परिवर्तनों का गाँवों की आर्थिक व्यवस्था पर तो कोई असर नहीं ही पड़ा उनका सामाजिक और नैयार्थिक जीवन भी पहले की तरह पंचायत समितियों और पुरानी महिाया द्वारा शासित रहा।

इसका यह अर्थ नहीं कि अपने दीर्घकालीन इतिहास में गाँवों को या गाँवों में कुछ हुआ ही नहीं। अपनी स्वपर्याप्तता और स्थिर के बावजूद गाँव जटिल आंतरिक सामाजिक क्रियाकलाप की रंगभूमि रहे। उनके अपने सामाजिक त्यौहार, रामलीला के रूप में अपना अनगढ़ सा रंगमंच, कथाओं के रूप में धार्मिक सभाएँ, और ऐसे अन्य सामुदायिक आयोजन थे। हिंदू धर्म में ही नई प्रवृत्तियों का जन्म होता रहा और फिर बौद्ध धर्म जैसे नए धर्मों का भी उदय हुआ। धार्मिक उथल-पुथल के ऐसे दिनों में लोगो के नए धर्म या संप्रदाय में दीक्षित करने के लिए धर्म के उपदेशक गाँवों में गए या फिर शंकराचार्य, बल्लभाचार्य, चतुर्थ, रामानुज आदि लोगो ने सनातन धर्म की ही नई व्याख्याएँ प्रस्तुत कीं और गाँवों में अपने संप्रदाय और अपने दल की शाखाएँ स्थापित कीं। इस तरह के धार्मिक प्रचारात्मक कार्य के कारण कभी-कभी सारा का सारा गाँव हिंदू से बौद्ध हो गया या बण्णव से शैव हो गया। लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण में एमें परिवर्तनों के बावजूद गाँवों के लोगो की चेतना का कोई विस्तार नहीं हो सका और न उनमें राष्ट्रीय चेतना का ही उदभव हुआ। उनका दृष्टिकोण पहले जसा ही मकीण बना रहा। हिंदू के बदले वे अब अपने को बौद्ध मानने लगे, या बण्णव के बदले शैव लेकिन भारतीय होने की राष्ट्रीय चेतना उनके दिमाग में नहीं आई। भारत की एकता की बात मूझी भी लगे धार्मिक अर्थ में, भारत उनके लिए धर्म के सूत्र में बंधे हुए हिंदुआ का देश था। उनके दिमाग में यह बात नहीं भारत भारतीयों का देश है उन सब लोगो का देश है जो भारतीय भूमि

है और जाथिक राजनीतिक इकाई के अंग है। उनकी चेतना धार्मिक वंचारिक एकता की चेतना थी, न कि राजनीतिक जाथिक एकता (राष्ट्रवाद) की।\*

### प्राक् ब्रिटिश भारत में नागरिक संस्कृति का रूप

आत्मनिर्भर गावा का आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन रुढ़, अनुवर, (लगभग) अपरिवर्तनशील, और अपनी चौहद्दी में ही सीमित था। इसके विपरीत नगर का जीवन गतिशील, मनुष्य जपेक्षाकृत अग्रगामी और बाह्य जगत के निरंतर मनुष्य में रहा। शहर प्रशासनिक कद्रय शाहशाह और उनके राजदरवारियों के निवास स्थल थे या वाणिज्य के केंद्र के रूप में अन्य शहरों और विदेशों से उनके जीवित संबन्ध हात थे या धर्म स्थल होने के कारण बाहर से यात्रियों का अधिरत आवागमन चलता रहता था। शहरों को राजा और अभिजात वर्ग, मनुष्य वर्णिक समुदाय और उच्च पदाधिकारी धार्मिक सभ्रातजन की जटिल एवं विविध आवश्यकताओं की पूर्ति करनी हाती थी इसलिए उनकी अथव्यवस्था अर्थिक अग्रवर्तों और अवकलित थी। राज्य द्वारा गावों से एकत्र भूमिकर का बहुलाश नगरों में खच होता था। वर्णिक समाज अपने लाभ का उपभोग शहरों में ही करता था। इस तरह शहरों की जाथिक व्यवस्था को प्रथम मिला और उहा की उत्पादन प्रक्रिया निर्धारित हुइ अछ्दे किम्म के सूती और रेशमी कपड कलात्मक वातुकम और सगमरमर के समान, दुप्तोपणीय अभिजात और वर्णिक वर्ग के लिए विलास के साधन और उपकरण युद्ध के अस्त्र शस्त्र ऐसे सारे उद्योगों का बहाजम हुआ।

राज्य के भूभाग की संपत्ति का अधिकांश शहरों में आया और वही खच हुआ, और इस तरह वहां के लोगों का जाथिक जीवन अपक्षाकृत उन्नतिशील रहा। देश के धन के बहुत बडे भाग का जा हथिया लेन थे वे धनी वर्ग भी शहरों में ही रहते थे। राजा महाराजा, अभिजात वर्ग, वर्णिक समाज, इनके पास धन

\*बौद्धधर्म का उत्थान मनान्तन धर्म को फिर से प्रतिष्ठित करन के लिए शकुराचार्य का अभियान रामानुज का मन्त्रि जागेलन हिंदू धर्म और इस्लाम के समन्वय की शिक्षा में कवार और नानक जस योगों के सम्प्रयास मनस भारतीयों के बीच न ता राष्ट्रीय भावना का जन्म हा सकता था और न हुआ। रन्ध्यान्ने जातिया में भारतीयों की धार्मिक वंचारिक प्रवृत्तियों में कुछ परिवर्तन अवश्य लिए लेकिन राष्ट्रीय दृष्टिकोण विनमित नहू कर सके। राष्ट्रवाद दृष्टिकोण का विकास हो इसके लिए वस्तुनिष्ठ आधार के रूप में समन्वय अथव्यवस्था विस्तृत आर्थिक और सामाजिक विनिमय के लिए जावागमन के सन्तर्गत तान्त्र साधन और अग्रजा द्वारा जाए गए सम्मिलित राजतंत्र का अन्तित्व जावश्यक है। भारतीय सामाजिक जयनत्र में आमून परिवर्तन के बिना रहस्य बाजा जाति स्पर्ण जाति होकर रू गई। ब्रिटिश शासन के चन्तन भारतीय सामाजिक अथव्यवस्था का आधार हा बन गया है।

का जो अधिशेष होता था उससे वे कलाकारों, दाशनिगों, कविया, चित्रकारों, मगीतज्ञा, मूर्तिकारों, भव्य स्मारका का निर्माण करनवाले वास्तुशिल्पियों विशाल प्रासादा के अभियानको ज्योतिषिया वैद्यों और अय वैज्ञानिकों को अपने यहा रख सकते थे और उनका भरण पापण कर सकते थे ।

इस तरह गावा के सीमित, सनुचित एव निम्नकोटि के जीवन के विपरीत शहरो म समृद्ध सास्कृतिक और आर्थिक जीवन विकसित हुआ । वस्तुतः शहरो म महान दाशनिक और कलात्मक आदोलन बढे और जीवत हुए । अभिजात और वणिक वग इन आदालना के मरक्षक थे ।

मनिक, राजनीतिक, व्यापारिक या सास्कृतिक कारणा से शहरो के बीच लागो का आवागमन भी लगातार बढे पैमाने पर होता रहा । इन शहरो म देश के अन्य शहरो से ही नहीं, उन अय देशो से भी लोग आते रहे जिनसे भारत युगो से मवध रखता बढाता आया था । बाहर के दोमन दशो से लोग राजदूत, यानी, वणिक दाशनिक कलाकार और धम प्रचारको के रूप मे आए । देश के भीतर के शहरो मे ही नहीं वरन दूर दूर के देशो मे भी इन शहरो के प्राय आर्थिक और सास्कृतिक विनिमय मवध थे ।

उन दिना की सारी वज्ञानिक दाशनिक कलात्मक और धार्मिक सस्कृति शहरो म ही केंद्रित थी । गावो म अर्धविश्वास और प्रकृति एव दवो की उपासना के अपरिष्कृत रूप प्रचलित थे । लेकिन प्रबुद्ध नागर समुदाया मे मूर्म जटिल, मुविवचित और व्यापक आदशवादी एव जाध्यात्मवादी दशन पल्लवित पुष्पित हुए । अपने युग की समग्र सस्कृति के विविध रूपा का प्रतिनिधित्व करने वाले कलाकारो दाशनिको, माहित्यका और वैज्ञानिको का हिंदू बौद्ध मुस्लिम सम्राटा न राज्य के सरक्षण मे भरण-पोपण किया । यह राजकीय सरक्षक अपने दरवार मे मतो और कलाकारो से घिरा रहता था, जो भारतीय इतिहास म नवरत्न के नाम से माय रहे नवरत्न अर्थात् सस्कृति के नौ प्रमुख रूपा के प्रतिनिधि ।

अशोक, विक्रमादित्य, भोज एव जय बौद्ध और हिंदू मन्नाटो के दरवार मे, और वंस ही अकबर, शाहजहा और दूसरे मुगत शाहशाहा के दरवार म भी कलाकारा, वैज्ञानिका, विचारको की भीड लगी रहती थी । कालिदाम, बाण एव हिंदू साहित्य के अय प्रभासमान नक्षत्र राजदरवारो के ही आकाश म चमके । मध्यकालीन भारत का मवश्रेष्ठ मगीतज्ञ और मगीत म नई प्रवृत्तिया का प्रतिष्ठाता अकबर के सरक्षण म रहता था । ज्यातिविदा का राजा प्रोत्साहन और मवल प्रदान करते थे और उनके लिए वेदशाला का निर्माण भी करत थे, जैसा राजा जयसिंह न किया । उन युगा का जो कुछ इतिहास हम उपलब्ध है उमे राजदरवार के इतिहास वारो न ही लिखा ।

हिंदू और मुस्लिम भारतीय सस्कृति प्रथमत और मूनत धार्मिक थी । इनक बौद्धिक और कलात्मक कृतित्व म धम की प्रधानता थी । आ मली न कहा है

हिंदू मस्कृति धार्मिकता से ओन प्रोत थी और धम इस मस्कृति का विशिष्ट



लक्षण था। हिंदू 'यायशास्त्र' धर्म से मलग्न था, 'याय' की पुस्तकें दवी प्रेरणा से प्रसूत मानी जाती थीं। धर्म और साहित्य का मग्न इतना घनिष्ठ था कि विभिन्न भारतीय भाषाओं में लिखे गए साहित्य का अधिकांश भक्तिवादी है। कला (सामान्यतः) लोगों की सौंदर्यवादी संवेदनशीलता की प्रतिच्छवि है लेकिन वह भी धर्म से मग्न और अनुशासित रही। म्यापत्य की अभिव्यक्ति मंदिरों के निर्माण में हुई और मूर्तिकला की, जो धार्मिक विचित्रता से प्रभावित रही। अभिव्यक्ति मंदिरों की दीवारों पर की गई नक्काशी में हुई।<sup>6</sup>

यही बात मुस्लिम संस्कृति के बारे में भी सत्य है। उसकी भी प्रकृति मूलतः धार्मिक थी। यगों की घनिष्ठता के फलस्वरूप जब हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों के सम्बन्ध की दिशा में प्रयास शुरू हुए तब भी दोनों संस्कृतियों का मूल धार्मिक स्वर इस सामाजिक सम्बन्ध में परिव्याप्त रहा।

### भारतीय संस्कृति की धार्मिक वैचारिक एकता

प्राकृतिक भारतीय सामंतवादी कृषि प्रधान समाज की संस्कृति (दार्शनिक, धार्मिक इत्यादि) प्रबलतः रहस्यवादी थी। इसका कारण यह था कि यह समाज निश्चल और दुर्लभ था। एवं इसका आर्थिक विकास निम्न स्तर का था। इस समाज में जो परिवर्तन हुए वे परिमाणात्मक थे गुणात्मक नहीं। मूलतः यह शताब्दियों तक एकरूप रहा। ऐसी सामाजिक भौतिक अस्तित्व के कारण अनिवायत रहस्यवादी जीवन दर्शन का जन्म हुआ। दर्शन कला और संगठन के क्षेत्र में इस समाज की उपलब्धियों का रूप निर्धारण इस रहस्यवादी दृष्टिकोण में ही किया।

अगर यह मान भी लें कि भारतीय समाज स्थिर नहीं था, तब भी सब मिलाकर यह आवश्यकता अवश्य थी। और जब युगों तक यह ऐसा ही बना रहा तो स्वाभाविक था कि, जैसा पी० सोराकिन ने कहा है 'इस संस्कृति के जादूशवादी, भावप्रधान लक्षण आ जाए। फलस्वरूप सामाजिक क्रिया कलाप अर्थात् आत्मतोष के लिए आवश्यक साधन और साधकों की प्रकृति के बारे में 'यूनायिक' परिभाषित विचारों का जन्म हुआ, सौंदर्य, नीति और समाज संबंधी समान मूल्यों और व्यवस्थाओं एवं सत्य ज्ञान, आत्मा और चरम वास्तविकता के बारे में समान धारणाओं की उत्पत्ति हुई। दूसरे शब्दों में कहें तो हिंदुओं, बौद्धों और मुसलमानों ने सम्मिलित तौर पर ब्रह्मांड की ऐसी धारणा बना ली थी जिसके अनुसार आत्मा का अस्तित्व चिरंतन सत्य था। क्षणिक और द्रव्यजन्म के प्रति विरक्ति ही काम्य थी, और इन प्रक्रियाओं से आत्मा चरम सत्य के अधीनस्थ रह सकती थी और अंततः उसमें विलीन हो जाती। उन प्रक्रियाओं के प्रति आसक्ति ही जीवन का आदेश थी। व्यवहार में व्यक्ति के लिए इसका अर्थ था कि रहने सहने और उपासना पद्धति के कारण वह अपने आंतरिक जीवन पर नियंत्रण के लिए मुक्त हो

गया। समाज में इस चिंतन शैली के फलस्वरूप ऐसी पद श्रृंखला का निर्माण हुआ जहाँ केवल वे मूल्य शाश्वत और महत्वपूर्ण थे जिनसे आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति की संभावना होती। इस श्रृंखलाबद्ध समाज का नेतृत्व जिन लोगों के हाथों में था, आध्यात्मिक संस्कार उनका एकमात्र जीवन व्यापार नहीं तो उनकी चरम उपलब्धि तो अवश्य था। पाश्चात्य वाणिज्य के प्रादुर्भाव के पहले भारत की मूल विचार पद्धति ऐसी ही थी।<sup>7</sup>

हिंदू और मुस्लिम दोनों सस्कृतियाँ धर्मप्रधान थीं, और शहरों में ही राजाओं, अभिजातवर्गीय लोगों और संपन्न वणिक समुदाय के संरक्षण में फली फूली। बनारस, पुरी, मथुरा, नासिक, मथुरा, सोमनाथ पाटन जैसे धार्मिक उपासना के अनेकानेक केंद्रों के विशाल हिंदू मंदिरों का हिंदू सम्राटों, अभिजात वर्ग और धनी व्यापारियों ने बनवाए। वस्तुपाल और तजपाल नामक दो धनी जैन व्यापारियों ने डेलवाडा में जा जैन मंदिर बनवाया वे अपने सादर एवं स्थापत्य गुण के लिए सुप्रसिद्ध हैं। अशोक के विख्यात शिलास्तंभों का सारे भारत में बिखरे हैं और जिन पर बौद्ध धर्म के तार्किक नीति सिद्धांत अंकित हैं इस बात के प्रमाण हैं कि प्राचीन भारत में राजकीय संरक्षण में महान कला पल्लवित पुष्पित हुई। आज भी भारत के लगभग प्रत्येक नगर में कोई न कोई ऐसा मंदिर है जो प्राचीन काल की धार्मिक लगन और कलात्मक प्रतिभा का परिचय देता है।

कला और सस्कृति के क्षेत्र में मुस्लिम सम्राट भी किसी से पीछे नहीं थे। दिल्ली, आगरा, लाहौर, अहमदाबाद और अन्य शहरों में मुस्लिम राजाओं द्वारा बनाई गई मसजिदें इन राजाओं के गहरे कलाप्रेम और उत्साह के प्रमाण हैं। जिन कलाकारों ने इन भव्य मसजिदों का निर्माण किया वे उन्हें शाही संरक्षण के बिना कभी नहीं बना पाते।

अत्यंत शुद्धतावादी और भजेव के अतिरिक्त अन्य सार भुगल शाहशाह कला के अनन्य पापक थे। सारी दुनिया में मशहूर ताजमहल जिसे मंगमरमररचित स्वप्न की मन्ना दी गई है, मोती मसजिद, दिल्ली और आगरा के राजप्रामाद का अभियंत्रण और कला नैपुण्य के उत्कृष्ट समन्वय है, धीनगर (शालीमार और निशातबाग) और लाहौर के खूबसूरत बगीचे, उस युग के कलात्मक उत्थान और कला के लिए राजाओं द्वारा दिए गए समयन सबल के प्रभावपूर्ण और अकाट्य प्रमाण हैं।

शहर उन दिनों के बौद्धिक जीवन के भी दुर्ग थे। राजदरबार में राजा के सम्मुख विराधी और प्रतिद्वंद्वी दशनों के प्रतिपादकों के बीच दार्शनिक शास्त्रार्थ होता था। प्रायः दूरस्थ देशों और नगरों से भी विभिन्न धर्मों के सुयोग्य समर्थकों को स्थानीय धर्मवैत्ताओं से शास्त्रार्थ के लिए राजा आमंत्रित करते थे, जिससे यह देखा जा सके कि कौन सा धर्म सर्वोत्तम है।

भारत और विदेशों के संपर्क के द्वारे में ओमली ने कहा है, 'मध्य एशिया, तुर्की, फारस, उत्तरी अफ्रीका से सत, कवि वास्तुकला विशारद और यात्री भारत

आए। फिरिस्ता नामक इतिहासज्ञ कस्पियन सागर के तटवर्ती एस्ट्रापाद से आया था, इन्वतूता उत्तरी अफ्रीका से आया थावर ने कुस्तुनिया से वास्तुकना विशारद बुलाए, पर्सियन विद्वानों के अनुसार ताजमहल का नक्शा बनाने वाला कुस्तुनिया का ही एक तुक था।<sup>6</sup>

इसके पूर्व, हिंदू मस्तिष्क जावा, बाली, सुमात्रा, मलाया और पूर्वी द्वीप समूह के अथ टापुआ तक फैली हुई थी। आज भी इनमें से कुछ टापुओं के अच्छेवासे हिंस्रों के लागा के जीवन और रहन सहन पर हिंदू धर्म का प्रभाव है।

प्राचीन काल में शहर अध्ययन-अध्यापन के भी केंद्र थे। कई शहरों में पहले हिंदू पाठशालाएँ चलती थीं और बाद में मुस्लिम पाठशालाएँ चलीं। इस तरह प्राकृतिक काल में शहरों का सांस्कृतिक जीवन अत्यंत संपन्न और जटिल था।

### राष्ट्रीय भावना का अभाव

लेकिन नगरों का यह संपन्न सांस्कृतिक जीवन किसी राष्ट्रीय भावना से अनुप्रेरित नहीं था। उस युग में यह राष्ट्रीय भावना न तो बही थी, और न हो ही सकती थी। अधार्मिक धर्मनिरपेक्ष कला भी विस्तार और वस्तु की दृष्टि से राष्ट्रीय नहीं थी। यह कला किसी राजा की गौरव गरिमा की कथा कहती थी, जैसे कुतुबमीनार, भव्य राजप्रसाद, वास्तुकला द्वारा सुनिर्मित कब्रों, या पति पत्नी के जामरण जखड प्रेम की महत्ता प्रदर्शित करती थी, जैसे, ताजमहल। यह कला अभिजातवर्गीय और धार्मिक हिंदुआ या मुसलमानों की थी यह सारे राष्ट्र की कला नहीं थी और न उन सामाजिक वर्गों की ही कला थी जो आधुनिक राष्ट्र का निर्माण करते हैं और जिनकी स्थिति रूपत राष्ट्रीय है और वस्तुतः वर्गीय। उन दिनों के शहरी लागा राजाओं और अभिजातीयवर्गीय, व्यापारी एवं कारीगरों लागों की चेतना राष्ट्रीय चेतना नहीं थी।

प्राकृतिक भारत में राष्ट्रीय सस्कृति के उदभव के लिए आवश्यक वस्तुनिष्ठ और भावनिष्ठ तत्व (जैसे सम्मिलित आर्थिक सामाजिक और राजकीय अस्तित्व और इस अस्तित्व की चेतना) विद्यमान नहीं थे। राष्ट्रीय सस्कृति के लिए सारे समुदाय का राष्ट्र के रूप में एकांकित होना आवश्यक है। और यह तभी संभव है जब आर्थिक उन्नति (जैसे, उत्पादक शक्तियाँ और श्रम विभाजन का पर्याप्त विकास जिससे समाज विनिमय संबंधों के जाल में धुन बंध जाए आवागमन के द्रुतगामी साधनों का चतुर्दिक् विस्तार, इत्यादि) के फलस्वरूप जाति जीवन पहले तो आर्थिक तौर पर और कालक्रम से सामाजिक तौर पर यूनाधिक एकांकित हो। सम्मिलित आर्थिक जीवन की अपेक्षाएँ सम्मिलित भाषा के विकास की प्रक्रिया का तीव्र करती हैं और फिर यह जनजीवन को राष्ट्र के रूप में सुशुद्ध कराने का एक और साधन है। मगठन की विभिन्न अवस्थाओं में राष्ट्र आर्थिक इकाई की गचेतना विकसित करता है और स्वतंत्र राज्य के अस्तित्व की लालसा पुष्ट करता है। राष्ट्र निर्माण एही सस्कृति की मरचना करता है जो मगीत, स्थापत्य,

चित्रकारी नाटक, उप-यास या समाजशास्त्रीय साहित्य के माध्यम से स्वतंत्र और संपन्न सामाजिक-आर्थिक जीवन के लिए व्यक्तियों, दलों और वर्गों की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को अभिव्यक्त करती है। प्राक् राष्ट्रीय ऐतिहासिक काल के सामंती अवशेष या विदेशी प्रभुत्व जैसी जो शक्तियां राष्ट्रीय समाज के विकास को अवरुद्ध करती हैं, राष्ट्रीय मस्कृति उनका पर्दाफाश करती है और उनके विरुद्ध मोघ एव शत्रुता की भावना जागृत करती है। राष्ट्र के उन्मुक्त भौतिक एव आध्यात्मिक उत्थान के पथ में जो अवरोध हैं, राष्ट्रीय सस्कृति अनुगम्य या चिंतनशील विलाप द्वारा उनका विरोध करती है।

पूजीवादी आर्थिक प्रक्रियाओं ने विभिन्न समुदायों को आर्थिक और सामाजिक तौर पर एकताबद्ध कर उनकी जगह आधुनिक राष्ट्रों को जन्म दिया है। इही प्रक्रियाओं ने भारतीय राष्ट्र की भी सृष्टि की है। सामंती व्यवस्था की तरह पूजीवादी समाज का भी अपना विशिष्ट वर्ग चरित्र है। बुजुआ समाज में भी विभिन्न वर्ग हैं, भारत में राजे रजवाड़े जैसे प्रतिक्रियावादी सामंतशाह, अधिसामंती जमींदार, इत्यादि भी इस समाज के अंग हैं। लेकिन नए राष्ट्रीय अर्थतंत्र के फलस्वरूप नए सामाजिक वर्गों का भी जन्म हुआ जैसे बुजुआजी के उन्नतशील भाग, क्षुद्र बुजुआजी, किसान और सबहारा ये वर्ग नवनिर्मित राष्ट्रीय समाज के एकांकित अंग थे, इनका राष्ट्रीय आधार और राष्ट्रीय विस्तार था। इन वर्गों ने विभिन्न मात्रा में अपने मुक्त विकास पर प्रतिक्रियावादी सामंती तत्वा और साम्राज्यवादी शासन का दबाव अनुभव किया। जस जसे इन वर्गों में दलीय चेतना का विकास हुआ, वसे वसे उन्नी अनुपात में इन वर्गों का विविध और विरोधी वर्ग स्वाथ भी बढ़ा। इन नए राष्ट्रीय सामाजिक वर्गों की मस्कृतियां रूपत राष्ट्रीय थीं, लेकिन वस्तुतः वर्ग मभूत, जैसे वर्ग चेतनाशील मजदूरों की मस्कृति मूलतः समाजवादी थी यद्यपि रूपत राष्ट्रीय बुजुआजी राष्ट्रीय सबहारा, राष्ट्रीय क्षुद्र बुजुआजी और कृषक, इन नए वर्गों की विकासमान मस्कृति भारत की समस्त राष्ट्रीय मस्कृति की सृष्टि करती है, साथ ही इस राष्ट्रीय मस्कृति में देश के विभिन्न भूभागों की बंगाली, गुजराती महाराष्ट्रीय, कर्नाटक इत्यादि नव जागृत राष्ट्र जातियां की अपनी विशिष्ट मस्कृतियां भी समाविष्ट हैं।

जागरणशील सामाजिक वर्गों और राष्ट्रीय उपजातियां की मस्कृतियां से आधुनिक भारतीय राष्ट्र बना है। यह राष्ट्रीय मस्कृति इन दलों के और भारतीय राष्ट्र की मपूणता के मुक्त विकास की आवश्यकताओं को प्रतिच्छवित करती है। स्पष्टतः ऐसी मस्कृति प्राक् ब्रिटिश भारत में नहीं पैदा हो सकती थी क्योंकि उस वक्त अपने विभिन्न एव विशिष्ट अवयवों सहित एक मयुक्त राष्ट्र का जन्म नहीं हुआ था। सामंती और वर्णिक वर्गों की मपन्न, मशिल्ल और व्यापक मस्कृति और जनसाधारण की मस्कृति जो लोककला परीकथा एव धार्मिक अनुष्ठानों आयोजनों के रूप में प्रस्फुटित हुई प्राक् ब्रिटिश भारतीय समाज की मस्कृति में मस्कृति में राष्ट्रीय विस्तार एव रूप का अभाव था।

## संदर्भ

- 1 सर चार्ल्स मटकाफ धुर्यो द्वारा उद्धृत प० 24 ।
- 2 शेलवकर प० 25 ।
- 3 वाडिया एड मचेंट प० 234 ।
- 4 वहा प० 234 ।
- 5 शलवकर प० 102 ।
- 6 वाडिया एड मचेंट प० 30 ।
- 7 देखें गाडगिल प० 10 12 ।
- 8 शलवकर प० 124 125 ।
- 9 गाडगिल प० 10 ।
- 10 वाडिया एड मचेंट प० 31 ।
- 11 युक्नन प० 15 ।
- 12 वही प० 15 ।
- 13 काल मानस प० 391 ।
- 14 ओ मेला प० 355 ।
- 15 डी० पी० मुखर्जी प० 1 2 ।
- 16 देख गाडगिल प० 6 ।
- 17 कलवटन प० 16 17 ।
- 18 वही प० 18 ।
- 19 गाडगिल प० 45 ।
- 20 शलवकर प० 139 ।
- 21 वही प० 139 ।
- 22 वही प० 142 ।
- 23 वही ।
- 24 वही प० 143 ।
- 25 गाडगिल, प० 12 ।
- 26 जो मेती प० 2 ।
- 27 मुखर्जी प 2 3 ।
- 28 जो मेती प० 8 ।

## ब्रिटेन की भारत विजय

### भारतीय समाज का रूपांतरण

#### अंग्रेजी की भारत विजय का परिणाम

पिछले अध्याय में हम प्राकृतिक ब्रिटिश सामंती अर्थतंत्र के मूल तत्वों का विवरण देख चुके हैं। इस अर्थव्यवस्था के पूँजीवादी रूपांतरण (सामंती अवशेषों के साथ ही सही) की प्रक्रिया काफी लंबी है। इस रूपांतरण के मुख्य कारण थे, अंग्रेजों द्वारा भारत की विजय, ब्रिटिश सरकार की राजनीतिक और आर्थिक नीतियाँ एवं आर्थिक विकास की तीनों दशाओं अर्थात् व्यापार, उद्योग तथा वित्त में अंग्रेजी पूँजीवाद का भारतीय अर्थतंत्र में विगिष्ट प्रवेश।

इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी और कुछ अन्य यूरोपीय देशों में उन्हीं देशों के पूँजीवादी वर्गों ने सामंती अर्थव्यवस्था के बदले पूँजीवादी अर्थव्यवस्था स्थापित की। भारत में यह कार्य ब्रिटेन के पूँजीवादी वर्ग द्वारा भ्रमण हुआ न कि देशी पूँजीवादियों के किसी वर्ग द्वारा। इस तरह यहाँ स्वतंत्र पूँजीवादी आर्थिक विकास नहीं हो सका अपितु अंग्रेजी पूँजीवाद की आवश्यकताओं और हितों में इस विकास की प्रकृति और व्यापकता निर्धारित की। इसीलिए भारत को ब्रिटेन का आर्थिक उपनिवेश कहा गया है।

जिस युग में ब्रिटिश, फ्रांसीसी और अन्‍याय विदेशी कंपनियों ने भारत से सबंध स्थापित किया और भारत में वाणिज्यिक पैठ और राजनीतिक प्रभुत्व का सिलसिला शुरू किया, उस युग में और उसके पहले भी इस देश में एक देशी वाणिज्यिक पूँजीवर्ग था जो निरंतर शक्ति संचय करता रहा था। वस्तुतः 'अठारहवीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में, मुगल साम्राज्य के विघटन काल में, नए मध्यवर्ग का उदय होने लगा था। स्वपर्याप्त गाँव उत्पादक इकाई बने रहे, लेकिन घनी-मुख मध्यवर्ग द्वारा पण्य वस्तुओं के वितरण और विनिमय के फलस्वरूप शहरों में व्यापारिक केंद्रों का जन्म हान लगा था। इन शहरों की ओर हस्तगिल्पियों के विभिन्न वर्ग आकृष्ट हुए, और यहाँ विनिमय और निर्यात के लिए उत्पादन काय हाता था न कि स्थानीय उपयोग-उपभोग के लिए। मुगल साम्राज्य के खडहरों के बीच जिन

नए राज्यों का उदभव हुआ उनकी राजनीतिक गरचना सामंती थी, फिर भी वित्तीय मामलों में उन पर व्यापारी वर्ग का नियंत्रण था। लेकिन यहाँ नई शक्तियाँ देश को एकता के सूत्र में बाँध सकें, इसके पहले ही एक-एक देश का हमला हुआ जो आर्थिक विकास का अग्रणी था। यह हमला भी ऐसे चकत्त हुआ जब देश मरुमण और विघटन की स्थिति में गुजर रहा था, जिसके कारण वह विद्वानों की आक्रमण के लिए नितांत आसान शिकार था।<sup>1</sup>

भारत का नवोदित वाणिज्यिक वर्ग पर्याप्त आर्थिक और सामाजिक शक्ति तक नहीं पहुँचा, सामंती वर्गों से राजनीतिक सत्ता के अपहरण और पूँजीवादी प्रसार के लिए इस शक्ति के प्रयोग द्वारा भारत की सामंती के बदले पूँजीवादी आधारभूमि पर प्रतिष्ठापित करे इसके पहले ही आर्थिक तौर पर अधिक शक्तिशाली हथियारबद्ध विदेशी वाणिज्य निगमों ने आर्थिक और राजनीतिक प्रभुता के लिए भारत का अपना रणक्षेत्र बना लिया। सबविदित है कि इस पदभंग अंततः इस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई।

### अंग्रेजों की भारत विजय के कारण

आर्थिक और सामरिक दृष्टि से आगे बढ़ी हुई सुगठित और एकताबद्ध विदेशी शक्ति द्वारा भारत की विजय के लिए यहाँ की राजनीतिक स्थिति अत्यंत उपयुक्त थी। मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद अराजकता और विनाशकारी पारस्परिक मघर्षों की जो स्थिति उत्पन्न हो गई वह ऐसी विजय के अनुकूल थी।

भारत में अंग्रेजों की प्रभुत्व की स्थापना आखिर हूँ कैसे? महान मुगलों की अधीश्वर सर्वोपरि शक्ति खंडित की मुगल राजप्रतिनिधियाँ न और इन राजप्रतिनिधियों की शक्ति खंडित की मराठों ने। मराठों की ताकत अफगानों ने खतम की और जब सब एक-दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, तब अंग्रेज आ पड़े और वे सब को दबा सकने में सफल हो सके। देश पहले से ही मुसलमानों और हिंदुओं के ही बीच नहीं बरन वनजातियों और जानियों में विभक्त था। यह समाज ऐसे सतुलन पर आधारित था जिसका आधार था सदस्यों का पारस्परिक विक्रमण और वधानिक पायबंद। ऐसा देश और ऐसा समाज तो मानो विजय का पूर्वनिश्चित भक्ष्य था।

लेकिन भारत पर अंग्रेजों की राजनीतिक सत्ता का स्वतः इतना अधिक महत्त्व नहीं जितना इस बात का कि उन्होंने इस सत्ता का खास ढंग से इस्तेमाल किया, जिसका भारतीय समाज पर गंभीर आर्थिक प्रभाव पड़ा।

भारत पहले भी कई बार विजित हो चुका था लेकिन इन विजयों से केवल राजनीतिक सत्ता में उलट फेर हुआ। मूलभूत आर्थिक ढाँचा पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। जातमतिभर गाँव इस अर्थतंत्र के धुराग्रस्वरूप थे और इनके आधार पर, धरती पर सामुदायिक स्वतंत्रता ग्रामीण कृषि और उद्योग की पारस्परिक एकात्मिकता का निश्चित करने के लिए गाँव का इकाई के तौर पर इस्तेमाल और

गावों के ही उपभोग के लिए गावा में ही उत्पादन। अपनी मूल बहिर्रेखा में प्राक् ब्रिटिश भारत की यह आर्थिक संरचना सदियों तक विदेशी आक्रमण, सैनिक उथल-पुथल, धार्मिक उलट फेर और राजवंशिक युद्धों के बाद भी बची रही। ऐसी घटनाएँ चाहें जितनी आश्चर्यजनक और विभीषिकापूर्ण रही हों, उन्हीं भारततीय समाज के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ढाँचे को ही प्रभावित किया, इसके आर्थिक आधार का नहीं। आत्मनिर्भर गाव, जिनमें लगभग सारी आबादी रहती थी, अत्यंत भीषण राजनीतिक तूफानों और सैनिक विश्वसों के बावजूद अपने मूल रूप में ही जीवित रहे।

भारत का इतिहास प्रधानतः युद्धों और आक्रमणों का ही इतिहास रहा है। इनके बावजूद अगर भारत का सनातन अथवा ज्यों का त्यों बना रहा तो इसकी वजह है कि बाहर के जो लडाकू और हमलावर लोग हिंदुस्तान आए, उनमें किसी के पास कोई ऐसा नया अथवा नई शक्ति या जाति भारतीय अथवा से आगे बढ़ा हुआ हो।\* वस्तुतः उत्तर से हमलावर आए और भारत पर कब्जा कायम कर, यहाँ शासकों के रूप में बस गए, वे सब भारत जाने के पूर्व ऐसे समाज में रहते आए थे जो आर्थिक विकास की उस स्थिति में नहीं पहुँच पाए थे जहाँ भारतीय समाज था। वे ऐसे समाज के सदस्य थे जो विकास के प्राक् सामंती खानाबदोश या अध-सामंती अवस्थाओं से गुजर रहे थे। उनकी भारत विजय उनका भारत निवास और उनके द्वारा इस देश पर शासन। ये सब भारतीय समाज के सामंती अथवा के पुनर्कल्पन और पुनर्गठन की दिशा में कुछ नहीं कर सका। नए शासकों ने पुराने आर्थिक आधार का स्वीकार कर लिया।

अरब, तुर्क, तातार, मुगल, जिन्होंने एक के बाद एक भारत पर जीत हासिल की, वे सब हिंदुओं जैसे ही गए। माना इतिहास के एक शाश्वत नियम की पुष्टि करते हुए, बबर विजेताओं ने अपनी प्रजा की श्रेष्ठ सभ्यता से स्वयं का परास्त कर लिया<sup>3</sup>।

### अंग्रेजों की भारत विजय के विशिष्ट लक्षण

अंग्रेजों की भारत विजय दूसरे प्रकार की थी। ब्रिटेन में सामंतशाही की जगह आधुनिक बुजुर्ग समाज की स्थापना हो चुकी थी। सामंती अथवा पर आधारित

\*प्राक् ब्रिटिश भारत में यूरोपीय सामंती अथवा से भिन्न विशिष्ट लक्षणों वाली पश्चिमी प्रकार की सामंती अर्थव्यवस्था थी। इस अर्थव्यवस्था के आधारभूत तत्व यथा जमीन पर व्यक्तिगत स्वत्व का अभाव, उस पर मारों गावों का सामूहिक अधिकार, उद्योग और कृषि की एकता पर निर्भर आत्मनिर्भरता, सिंचाई और जन-संवादाओं के विषय में राजकीय उत्तरदायित्व।

मात्र के अनुसार उन्हीं लक्षणों ने प्राक् ब्रिटिश भारतीय समाज के इतिहास और विकास (संभवतः विकास-गुण्यता या सापेक्ष स्थिति बढ़ना अधिक उचित होगा) का रूप दिया।



सामती अनैक्य की समाप्ति और पूजीवाद के उदभव और विस्तार द्वारा ब्रिटेन ने स्वयं को आधुनिक राष्ट्र के रूप में समन्वित कर लिया था। आधुनिक राष्ट्रों के इतिहास से स्पष्ट है कि पूजीवाद के द्वारा ही लोगो का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक एकीकरण संभव है।<sup>4</sup>

पूजीवादी राष्ट्र सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तौर पर सामती जन जीवन से अपेक्षाकृत अधिक शक्ति गाली होता है। पूजीवाद उनसे और परिष्कृत उत्पादन तकनीक पर आधारित है, इसलिए पूजीवाद राष्ट्र सामती जन जीवन से आर्थिक तौर पर अधिक शक्ति संपन्न होता है। पूजीवादी राष्ट्र में देशभक्ति और राष्ट्रवाद का बड़ा गहन भाव होता है। सामती जनसमुदाय भौतिक दृष्टि से असंबद्ध सामाजिक तौर पर असंयुक्त और राजनीतिक तौर पर जमपूक्त होता है। इसके विपरीत पूजीवादी राष्ट्र सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर समन्वित होता है वहाँ राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था सबके लिए एक सी जाती है। इसलिए वहाँ लोग देशभक्ति और राष्ट्रवाद की भावना से ओत प्रोत होते हैं। जंगलों की भारत विजय के सपने इतिहास में शायद ही कोई जंगल मिलागा जिसने भारत में अंग्रेजों के स्वाथ के प्रति गद्दारी की हा, यद्यपि ऐसे मैकडो हिंदुस्तानी मिलेंगे राजे रजवाड़े सिपहमालार, वणिक जो अंग्रेजों से मिल गए और जिहोंने भारत पर उनका प्रभुत्व कायम करने में मदद दी। अपने सामाजिक आर्थिक पर्यावरण के कारण पूजीवादी राष्ट्रों के लोक जीवन में राष्ट्रीय एकात्मता, अनुशासन, देश प्रेम सहयोग की आदत, संगठन की योग्यता आदि अत्यंत रूप से विकसित हैं।\* इसमें रचनात्मक भी आश्चर्य नहीं कि पूजीवाद ब्रिटेन ने असंयुक्त सामती भारत पर आसानी से विजय हासिल कर ली।

### भारत की आर्थिक संरचना पर प्रभाव

भारत पर पहली बार अब एक पूजीवादी राष्ट्र का शासन था और इसका भारत की आर्थिक संरचना पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। भारतीय समाज के पुरातन आर्थिक आधार का उन्मूलन कर उसकी जगह पूजीवादी व्यवस्था की स्थापना किए बिना ब्रिटेन अपनी खुद की पूजीवादी आर्थिक आवश्यकताओं के लिए

\* यह खयाल रखना होगा कि ऐतिहासिक तौर पर सामंतशाही से उच्चतर व्यवस्था होने पर भी पूजीवादी समाज परस्पर विरोधी और असंगत स्वार्थों वाले विविध युद्धरत वर्गों में विभक्त है। फिर भी अपने उन्भव के प्रारंभिक चरण में राष्ट्रीय बुजुर्गों का नियंत्रण, प्रगतिशील सामाजिक दलों की राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बाध पानी है और उनके बीच राष्ट्रवादी भावना का प्रचार प्रसार करता है एवं सामंतशाही के विरुद्ध आंदोलन, समाज के जनतांत्रिक पुनर्गठन और पूजीवादी संगठन और विस्तार की मांगनामा में उसे उन प्रगतिशील तत्वों का समर्थन प्राप्त होता है। पूजीवादी के ह्दय और वग-सपथ के मिश्रण पर आधारित श्रम अल्पानता व विनाश के युग में हम तरह का समर्थन अधिनाधिक कठिन माने जगता है।

औपनिवेशिक भारत का समुचित उपयोग नहीं कर सकता था। भारत पर अंग्रेजों के राजनीतिक प्रभुत्व के विस्तार की दिशा में उठाया गया हर कदम पुरानी अथव्यवस्था के विघटन और नए आर्थिक रूपा के उन्नयन की दिशा में ही अलग कदम था।<sup>5</sup>

भारत पर अंग्रेजों के निरंतर बधनशील प्रभुत्व का इतिहास प्राकृतिक ब्रिटिश भारत की सामंती अथव्यवस्था के पूजावादी रूपांतरण का भी इतिहास है, चाहे यह रूपांतरण अधूरा और विकृत ही क्यों न रहा हो। पुराने भूमि सबंधा एवं हस्तशिल्प उद्योग के ह्रास और उनकी जगह नए भूमि सबंधा और आधुनिक उद्योगों के उदभव से भी इसका बड़ा घनिष्ठ संबंध है। अंग्रेजों के राजनीतिक प्रभुत्व के विकास के साथ साथ पुराने उद्योगों और भूमि व्यवस्था पर आधारित पुराने वर्गों का विनाश हुआ और नए भूमि सबंधा और नए उद्योगों पर आधारित नए वर्गों का उदय हुआ है। गांवों के समुदायतंत्र (कम्यून) की जगह आधुनिक भूमिधर या जमींदार आविर्भूत हुए और जमीन पर उनकी निजी मिलकियत कायम हुई। ब्रिटिश शासन काल में स्थापित आधुनिक उद्योगों और आवागमन के साधनों के कारण नए वर्गों का जन्म हुआ, जैसे पूजावादी वर्ग, उद्योग धंधों और यातायात में लगे हुए मजदूरों का वर्ग, सेतिहर मजदूर वर्ग, काश्तकार वर्ग, नया वणिज्य वर्ग जो आधुनिक देशी विदेशी उद्योगों द्वारा उत्पादित पण्य वस्तुओं के क्रय विनय में लगा था। भारत पर ब्रिटिश प्रभाव के कारण न केवल भारत की आर्थिक बरत सामाजिक संरचना का भी रूपांतरण हुआ।

इंग्लैंड को भारत में दुहरे लक्ष्य की प्राप्ति करना है उसका एक लक्ष्य विनाशालोक है और दूसरा रचनात्मक प्राचीन एशियाई समाज का उन्मूलन कर उसकी जगह पाश्चात्य सभ्यता की भौतिक नींव डालना अंग्रेजों ने देशी जन जीवन और देशी उद्योगों को समाप्त कर हिंदू सभ्यता का विनाश किया।

महान मुगलों के गमने से भी अधिक संगठित और व्यापक राजनीतिक एकता इस नए जीवन की पहली गत थी जमींदारी और रेंयतदारी दो भिन्न रूप हैं जमीन पर व्यक्तिगत स्वत्व के जिसका एशियाई समाज में नितान्त अभाव रहा है।<sup>6</sup>

### ऐतिहासिक दृष्टि से प्रगतिशील महत्व

यह कहा जा सकता है कि आत्मनिर्भर स्वाधीन ग्रामीण अर्थतंत्र पर आधारित भारत के आर्थिक अवनय की समाप्ति और पूजावादी रूपों के आगमन से आर्थिक इकाई के तौर पर भारत का रूपांतरण अंग्रेजी शासन के ऐतिहासिक रूप से प्रगतिशील परिणाम था। फिर भी, चूंकि यह रूपांतरण ब्रिटिश व्यापार, उद्योग और बैंकिंग की आवश्यकताओं द्वारा संचालित हुआ और ब्रिटिश स्वार्थों की मिद्धि करता रहा, इसलिए भारतीय समाज का स्वतंत्र और अविच्छिन्न आर्थिक विकास

संभव नहीं हो सका।<sup>1</sup> इस तरह ब्रिटिश प्रभाव ने भारतीय समाज की ऐतिहासिक प्रगति को सहायता भी दी और उसे अवरुद्ध भी किया।

वस्तुतः भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन भारतीय जनता और उसके विभिन्न वर्गों के स्वतंत्र विकास पर ब्रिटिश स्वार्थों के दबाव का परिणाम था। ब्रिटिश स्वार्थों को भारत के सामाजिक और स्वतंत्र विकास के सामने प्रधानता दी गई। भारत के औद्योगिकीकरण की दिशा में अवरोध उपस्थित किए गए और उसे सीमित रखा गया, ब्रिटिश उद्योगों की कच्चे माल की आवश्यकता की पूर्ति के लिए भारत के कृषि उत्पादन को विकृत किया गया। संक्षेपतः, भारत को कच्चा माल पैदा करने वाला कृषि प्रधान उपनिवेश और ब्रिटिश उद्योगों के लिए बाजार की स्थिति में रखा गया। शुरू के भारतीय राष्ट्रवादियों ने भारत में ब्रिटिशों की प्रगतिशील भूमिका स्वीकार की, लेकिन उन्होंने इस बात की आशंका भी की कि अंग्रेजी शासन ने भारतीय जनता के स्वतंत्र और स्वस्थ ऐतिहासिक, आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को मूलतः अवरुद्ध किया।\* भारत पर ब्रिटिश दबाव की बात इसमें ही सिद्ध है कि भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन ब्रिटेन के विरुद्ध था।

पहले हम यह देखेंगे कि ब्रिटिश काल में पूंजीवाद कैसे भारतीय गांवों में प्रविष्ट हुआ। पूंजीवाद के विकास की इस प्रक्रिया का समझना आवश्यक है, क्योंकि इसने गांवों की स्वयंपूर्ण अव्यवस्था का विनाश कर गांवों की अव्यवस्था का मयुक्त भारतीय अस्तित्व का जग बनाया। मयुक्त राष्ट्र के रूप में मयुक्त लोक का एकीकरण राष्ट्रीय भाव और चेतना का उदय और राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सामाजिक सांस्कृतिक प्रगति के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उद्भव और विकास आर्थिक एकता नहीं इन सबको वस्तुनिष्ठ भौतिक आधार दिया।

### संदर्भ

- 1 जन श्लोक प 16।
- 2 काल मासम, प 58।
- 3 काल मासम प 59।
- 4 दश सांख्ये टाना और स्तलिन।
- 5 दश सांख्ये मार ० स्त।
- 6 काल मासम प 59 60।
- 7 देश सांख्ये वासिया एड मर्चे और जार पा स्त।

\* ब्रिटिश पूंजीवादी ने समाज के नए तंत्र को जो बाजू भारतीय समाज में बाण उनका फल भारतीयों का तंत्र तंत्र उपनायकता होगा जो तंत्र ब्रिटिश में ही स्वतंत्रता वगैरे का म्यानापन नया कर देना या जो तंत्र भारतीय ही पूरा तंत्र शक्तिशाली हानर अग्रणी जूए को उतार रहा फलन। —काल मासम।

## ब्रिटिश शासन काल में भारतीय कृषि का रूपांतरण

### भारतीय सामतवाद के मूलभूत तत्व

भारतीय सामतवाद यूरोपीय सामतवाद में यों भिन्न है कि भारत में भूस्वामिया का कोई ऐसा अभिजात वर्ग नहीं था जिसका जमीन पर मानिकाना हक रहा हो। प्राक् ब्रिटिश भारत में कभी भी जमीन पर किसी की निजी मिल्कियत नहीं रही। शाहशाह से सामती आभिजात्य को महज इतना ही हक हासिल था कि वह गावों से कर वसूली कर सके। सामत गावों का मालिक नहीं केवल तहसीलदार होता था जो सारा लगान या उमका कुठ भाग अपने लिए रख लेता था।<sup>1</sup> प्राक् ब्रिटिश भारत में मेजर जसी कोई सस्था कभी नहीं थी। शाहशाह भी दश की खेती वाली जमीन का मालिक नहीं होता था। शाहशाह या राज्य का फमल के कुछ हिस्से पर ही अधिकार प्राप्त था।

भारत में जमीन जनजाति (टाइत्र) या उमके किसी प्रविभाजन विशेष जैसे ग्राम समुदाय, गोत्र और विरादरी की हाती थी, वह कभी राजा की मपत्ति नहीं मानी गई।

जमीन का स्वतन्त्र कभी कृषक समुदाय के अलावा किसी अन्य के हाथ में नहीं रहा, न तो सामतों के गामन में और न सम्राटों के ही शासन में।<sup>2</sup>

चूँकि राजा जमीन का मालिक नहीं था, इसलिए वह ऐसे अभिजात वर्ग की सृष्टि नहीं कर सका जिसका जमीन पर स्वामित्व हो। भूमि कर वसूल करन का अपना अधिकार ही वह दूसरा को दे सकता था।

राजा किसी प्रकार का हो, दयालु या क्रूर परापकारी या निरकुण हिंदू बौद्ध या मुस्लिम कभी यह कोशिश नहीं हुई कि ग्राम समुदाय का जमीन से वचित किया जाए या जमींदारों का कोई वर्ग स्थापित किया जाए। यह इस बात का प्रमाण है कि जमीन को कभी राजा की मपत्ति नहीं समझा गया। ग्राम समुदाय ही गावों की भूमपत्ति का वास्तविक अधिकारी था। शाहशाह या राज्य का सालाना फमल के अंश मात्र पर ही अधिकार था। दूरगो तरफ किसी खाम बिसान का भी जमीन पर कोई निजी हक नहीं था। प्राक् ब्रिटिश भारत में भूमि

पर किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत स्वत्व नहीं था।

मुगल बादशाहों के युग में जो परिवर्तन हुए उनके बावजूद आधारभूत कृषि संबंधों में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ। रूपए पैसे द्वारा कर के सरकारी भुगतान की प्रथा शुरू हुई लेकिन जमीन पर गांव का ही कब्जा रहा और परंपरागत अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं किया गया। गांव पूर्ववत् कर निर्धारण का इकाई भी बने रह।

### भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व का प्रारंभ

अंग्रेजों की भारत विजय के बाद पुरानी भूव्यवस्था में आमूल परिवर्तन का सिलसिला शुरू हुआ। नई लगान व्यवस्था ने गांव की जमीन पर लोगों की जमान स चली आ रही अनिश्चित खतम कर उसकी जगह भूस्वामित्व के दो रूपों को जन्म दिया देश के कुछ भागों में जमींदारी और अन्य भागों में किसान की निजी मालिकियत।

सबसे पहले 1793 ई० में कानवालिंस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जमीन के स्थाई बंदोबस्त के जरिए भारत में जमींदारी का मूलन किया। अंग्रेज शासकों के राजनीतिक प्राधिकारियों ने इन प्रांतों में जिन तहसीलदारों को कमिशन के आधार पर भूमि कर की वसूली का अधिकार दिया था, उन्हीं में से जमींदारों को इस नए ढंग की सृष्टि हुई। पहले के जितने ऐसे तहसीलदार थे वे सब स्थाई बंदोबस्त में जमींदार हो गए।<sup>1</sup> बंदोबस्त की शर्तों के अनुसार जब उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार का निश्चित रकम देनी होती थी।

भारत की पुरानी भूमि व्यवस्था पर अंग्रेजों ने ही पहली गहरी चोट की। उन्हें खासकर तीन बातों से जमींदारी प्रथा लागू करने के लिए बाध्य होना पड़ा। एक ईस्ट इंडिया कंपनी जमीन के बंदोबस्त की अंग्रेजी याथिक एवं आर्थिक धारणाएँ ही अपना सकती थी। इंग्लैंड का आर्थिक अतीत भारत में मूलतः भिन्न था। अंग्रेजी जमींदारी प्रथा जमीन के व्यक्तिगत स्वामित्व की परंपरा और भावना में जमी और फली फूली थी, जिसके लिए भारत के आर्थिक इतिहास में कोई मिसाल नहीं थी। दो प्रशासकीय दृष्टि से ब्रिटिश शासन के शुरू के दिनों में, लाखा टोट किसानों की अपेक्षा कुछ हजार जमींदारों से लगान की वसूली आसान और आर्थिक दृष्टि से लाभजनक थी। तीन नवजात अंग्रेजी राज को अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए, राजनीतिक एवं सामरिक दृष्टि से, देश में सामाजिक समर्थन की आवश्यकता थी। ऐसी आशा स्वाभाविक थी कि जमींदारों का यह नया ढंग जो ब्रिटिश शासन के चलते ही जन्मा गया, अवश्य ही इस शासन की मदद करेगा। लाड बटिकन, जो 1828 से 1835 तक भारत का गवर्नर जनरल था वहा है

यद्यपि स्थाई बंदोबस्त कई अर्थों में यथा तक कि अपने मूलभूत तत्वों में भी असफल रहा फिर भी व्यापक जन विद्रोह या आतंक के विरुद्ध सुरक्षा की

दृष्टि से इसका यह बहुत बड़ा फायदा रहा कि इसके जरिए भूमिधरो का ऐसा बड़ा दल तैयार हो गया जिसको ब्रिटिश शासन के स्थायित्व से फायदा था, और जिसका जनसाधारण पर पूरा नियंत्रण था।

वाद की घटनाओं से यह सिद्ध है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की यह उम्मीद पूरी हुई। ब्रिटिश शासन को हरदम जमींदार वर्ग का तगड़ा समर्थन प्राप्त हुआ।

एक अन्य प्रकार से भी एक दूसरे किस्म के जमींदार वर्ग का जन्म हुआ। छोटे सरदारों के शुल्क और नजराने को लगान माना जाने लगा और उनके राजनीतिक सेना मजदूरी और प्रशासनिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। जमींदार वर्ग के सज्जनों के तीसरे तरीके का भी इस्तेमाल किया गया। जिन लोगों ने ब्रिटिश सरकार को बहुमूल्य सैनिक या अत्याय सेवाएँ प्रदान कीं, उन्हें जमीन का अनुदान देकर जमींदार बनाया गया।

जब अनुभव से पता चला कि जमींदारों से निश्चित स्थाई कर की वसूली सरकार के लिए आर्थिक तौर पर लाभजनक नहीं है तब जमीन के नए बंदोबस्त अस्थाई भूमिकर के आधार पर किए गए। जमीन के इन अस्थाई बंदोबस्तों में जो जमींदार बनाए गए उनकी जमीन पर मिलकियत तो स्थाई थी, लेकिन जा भूमिकर वे सरकार को देते थे, उसे बाद में पुनरीक्षित किया जा सकता था।<sup>6</sup> स्थाई बंदोबस्त ब्रिटिश भारत के लगभग 20 प्रतिशत भूभाग, बंगाल, बिहार और उत्तरी मद्रास के कुछ हिस्सों में लागू किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त भारतीय भूभाग के लगभग 30 प्रतिशत भाग, संयुक्त प्रांत के अधिकांश, बंगाल और बर्मा के कुछ हिस्सों एवं मध्य प्रदेश और पंजाब में लागू था।

देश के कुछ भागों में ब्रिटिश शासन न बड़े पैमाने पर भूस्वामित्व की सृष्टि की, और कुछ भागों में किसानों की निजी मिलकियत की। इस दूसरी व्यवस्था को रयतवारी कहते हैं। रयतवारी प्रथा में किसान का उस जमीन का स्वामी माना गया जिसे वह जोतता था।

सर टामस मनरो ने जमींदारी प्रथा को भारतीय परंपरा के प्रतिकूल माना, और उसकी जगह रयतवारी प्रथा का अनुमोदन किया। उसके अनुसार यह प्रथा परंपरागत थी, और इसलिए जब वह मद्रास का गवर्नर था, उसने 1820 में उस प्रांत में इस व्यवस्था की शुरुआत की और उसके बहुत बड़े भाग में इसे लागू किया। बाद में रयतवारी प्रथा दूसरे प्रांतों में भी लागू हुई। यह प्रथा बर्मा, सिंधु बरार, मद्रास, आसाम और कुछ और इलाकों में भी, कुल मिलाकर ब्रिटिश भारतीय भूभाग के 51% भाग में प्रचलित थी।

लेकिन जमींदारी की तरह रयतवारी भी जमीन पर निजी मिलकियत वाले सिद्धांत पर आधारित थी। प्रायः ब्रिटिश भारत में ऐसे व्यक्तिमूलक भूस्वामित्व की प्रथा नहीं थी। स्पष्टतः जमींदारी प्रथा की तरह रयतवारी भी भारतीय परंपरा के प्रतिकूल थी। रयतवारी प्रथा भारतीय परिपाटियों के अधिक् नजदीक

समझी गई और इसलिए उसका समर्थन किया गया। लेकिन वस्तुतः इसके अनुसार भी जमीन का निजी बंदोबस्त किया गया और भूमिकर फसल के प्रदत्त जमीन को आधार बनाकर तय किया गया। इस प्रथा ने भी भारतीय सस्थाओं का वैसे ही हनन किया जैसे जमींदारी प्रथा ने।<sup>17</sup> भारत में जमीन की निजी मिलकियत की प्रथा के कारण जमीन अब पण्य वस्तु हो गई जिसे रेहन किया जा सकता है या खरीदा बेचा जा सकता है।

इस तरह अंग्रेजों की भारत विजय से देश में एक कृषि नाति हुई। जमीन की निजी मिलकियत की प्रथा शुरू कर अंग्रेजों ने कृषि के पूजीवादी विस्तार की आवश्यक शर्तों की सृष्टि की। वाणिज्यिक एवं अन्य नए आर्थिक तत्वों ने गांवों की स्वपर्याप्त आत्मनिर्भरता की जड़ें हिला दीं। भारत के प्रायः पूजीवादी सामंती अर्थतंत्र के पूजीवादी रूपांतरण के कारणों में भूमि मन्वियों का परिवर्तन सबसे प्रमुख है। भारतीय समाज के इस भौतिक रूपांतरण के सामाजिक, राजनीतिक सांस्कृतिक और मनावनात्मिक परिणामों का विवरण हम आगे करेंगे।

### नई भूराजस्व व्यवस्था

जबतक जमीन में सारे गांवों की मिलकियत बरकरार रही, तबतक सारा गांव भूमिकर के निर्धारण की इकाई बना रहा। समस्त ग्राम समुदाय सरपंच या पंचायत के माध्यम से राज्य या मध्यस्थ का गांव के वार्षिक कृषि उत्पादन का निश्चित भाग भूमिकर के रूप में दिया करता था। यह अज्ञानपात बदलता रहा होगा लेकिन कुछेक त्रिरले स्थानों का छोड़कर बाकी लगभग गांव ही कर निर्धारण की इकाई होता था और वही भूमिकर देता था।

नई भूमि व्यवस्था में गांवों के निर्धारण और कर भुगतान की इकाई नहीं रह गई और जमीन की निजी मिलकियत के साथ ही व्यक्तिगत कर निर्धारण और कर अदायगी की प्रथा शुरू हुई। कर निर्धारण और कर अदायगी का नया तरीका भी शुरू हुआ। सीधे राज्य को या शाहशाहद्वारा नियुक्त मन्वियों को पहल जो लगान दिया जाता था वह वास्तविक फसल का एक भाग होता था और उसकी राशि हर साल भिन्न हो सकती थी। इसकी जगह अब रपण के नियत भुगतान की प्रथा आई जिसके अनुसार जमीन के आधार पर कर निर्धारण होता था। फसल चाहे अच्छी हो या बुरी जितनी जमीन पर होती हुई है या कम पर, साल में रपण की एक निश्चित राशि देय होती थी। जितने बंदोबस्त हात थे उनमें अधिकांश में निजी वास्तविकारों पर लगान नियत होता था, चाहे वे खुद मती करने वाले हों या राज्य द्वारा बहाल जमींदार हों।<sup>18</sup> भूमिकर के निर्धारण और भुगतान के नए रूप और ढंग का व्यापक प्रभाव पड़ा।

जब वास्तविक वार्षिक उपज का एक जगह भूमिकर के रूप में राज्य को देय होना था, उस वक़्त जमीन पर गांव के सामुदायिक स्वत्व को चाँदी छतरा नहीं था। किंगी सान फसल बर्बाद हो गई तो उस साल का भूमिकर स्वतः चुगुत हो

जाता था, क्योंकि भूमिकर नाम्नाविक फल के अंश के रूप में निर्धारित होता था। भूमिकर नहीं अदा कर पान पर भी जमीन पर गांव के अधिकार को कोई खतरा नहीं था। नई व्यवस्था में भूमिकर मानाना फसल के बढ़ते जमीन के आधार पर स्पष्ट के रूप में निर्धारित होने लगा और जमींदार या भूमिधर गृहस्थ को राज्य के कर दाय को हर माल हर हालत में पूरा करना पड़ता था चाहे फसल अच्छी हुई हो या बरबाद हो गई हो।

यह स्वाभाविक और अवश्यभावी था (और ऐसा हुआ भी) लगान की नई व्यवस्था के साथ जमीन के रहन और खरीद बिक्री की भी प्रथा शुरू हुई। जब फसल या अपनी जीविके के बल पर किसान राज्य को भूमिकर नहीं चुका पाता, तब उसे अपनी जमीन रेहन करनी पड़ती थी या बय। इस तरह नए शासन तंत्र में जमीन का स्वत्व और स्वामित्व अनिश्चित हो गया। नई भूमि व्यवस्था ने गांव के सामुदायिक जन जीवन और उसकी स्वतंत्रता को बेहतर शर्तों में दिया।

प्राक ब्रिटिश भारत में सारा गांव जमीन का मालिक हुआ करता था। परंपरागत ऋण के अनुसार जिन कृषक परिवारों को जमीन बांट दी गई थी उनके द्वारा की गई खेती का निरीक्षण सारा गांव करता था। इस तरह कृषि संप्रदाय आर्थिक उत्तरदायित्व तो गांव का था ही, तत्संबंधी झगड़ों के निपटारे का 'यायिन' काय भी गांव पंचायत के माध्यम से संपन्न होता था।

लेकिन नई भूमि व्यवस्था के अंतर्गत गांव अब जमीन का मालिक नहीं रहा इसलिए कृषि का अधीनत्व भी नहीं रह गया। हर किसान को जमीन की निजी मिलवियत के दौरेदार सरकारी सत्ता से मिलनी थी और उसी को कर चुकाना पड़ता था। इसलिए किसान का सरकार में सीधा संबंध बना। साथ ही अब जमीन संबंधी झगड़ों का निपटारा गांव पंचायतों के बदले राज्य द्वारा स्थापित कचहरियों में होना शुरू हुआ। सत्ताविहीन हा जान से ग्राम पंचायतों की प्रतिष्ठा का बड़ा आघात पहुंचा।

इस तरह नई भूमि व्यवस्था ने गांव को उनके कृषि संबंधी आर्थिक एवं 'यायिक' कार्यों में बचिन कर दिया। नई व्यवस्था ने उन संबंध मूलों का भी समाप्त कर दिया जिन्होंने जविक रूप से किसानों को गांवों से सामाजिक जीवन से बांध रखा था।

केंद्रीय सत्ता के विभिन्न अवयवों ने ग्रामीण जीवन के सारे क्रियाकलाप हस्तगत कर लिए। जो काय पहले स्वायत्तशासी ग्राम सभों में किया करते थे व सारे काय अब सरकार द्वारा संपन्न हो गए।

प्राक ब्रिटिश भारत में ग्रामीण उत्पादन का उद्देश्य होना था गांव की औद्योगिक एवं कृषि संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना। मध्ययुगीन उत्पादन का रूप और चरित्र इसी तथ्य द्वारा निर्धारित होता था। इसी आधार पर ग्रामीण कृषि और उद्योग की एकता मजबूत थी और बनी थी और इसी आधार पर वे मनुलिन थे।



## कृषि का वाणिज्यीकरण

नए भूमि सबधो एव नियत वन राशि के रूप में कर के भुगतान की प्रथा के फल स्वरूप ग्रामीण उपभोग के लिए उत्पादन के बदले बाजार में विनय के लिए उत्पादन शुरू हुआ। इस तरह उत्पादन के रूप और चरित्र में मूलभूत परिवर्तन हुए।<sup>9</sup>

आवागमन के साधनों में विकास और पूँजी के व्यापक प्रभाव के कारण किसान के लिए बाजार की सुविधा उपलब्ध हुई और वह अब मुख्यतया बाजार की दृष्टि से सामान पैदा करने लगा। भूमिकर की राशि प्रायः बहुत अधिक हुआ करती थी और पहले तो लगान की अदायगी के लिए और फिर कालक्रम से महाजन का ऋण चुकाने के लिए किसान को अधिक से अधिक पैसा बनाने की जरूरत हुई। वह विभिन्न कारणों से सूदखोर महाजनों के चंगुल में अधिवाधिक जकड़ता गया और इस तरह उस बाजार के लिए उत्पादन करने को बाध्य होना पड़ा।

पत्रस्वरूप एक ऐसे तथ्य का जन्म हुआ जिसे कृषि के वाणिज्यीकरण की सच्चाई दी गई है। किसान अग्र खास किस्म की फसल उगाने पर जोर देने लगे। अपनी विशिष्ट उपयुक्तता के कारण कई गाँवों की जमीन में बस एक ही फसल उगाई जाने लगी, जैसे, रूई, जूट, गेहूँ, ईख, तेलहन, इत्यादि।<sup>10</sup>

आवागमन के साधनों की सुविधा के कारण भारतीय कृषि में एक नया महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। इस परिवर्तन को, अग्र उपयुक्त शब्द के अभाव में, कृषि का वाणिज्यीकरण कहा जा सकता है। इस परिवर्तन की मुख्य विशेषता यह थी कि जब घरेलू उपयोग के बदले बाजार में बिक्री के लिए चीजाँ की खेती शुरू हुई आवागमन की सुविधाओं के प्रसारण गाँवों के संपृक्त चरित्र का खतम करना शुरू किया और गाँवों के कृषिजन का भी प्रभावित किया। खेती की जान वाली औद्योगिक फसलों के क्षेत्र विस्तार और विभिन्न जिलों में बोई जाने वाली फसलों के विशिष्टीकरण में यह परिवर्तन परिलक्षित है। निर्यात व्यापार बढ़ा और साथ ही बहुत दूर तक देश का अदरुनी व्यापार भी कर निर्धारण की नई प्रथा के कारण जब गाँवों में मुद्रा अयतन का प्रचलन शुरू हुआ तो वह वाणिज्यीकरण की दिशा में पहला कदम था। लेकिन इसका प्रभाव तब तक व्यापक नहीं हो सका जब तक आवागमन के साधनों का प्रसार नहीं हुआ था। धीरे-धीरे जिसके रूप में कर भुगतान की प्रथा खतम होने लगी और मुद्राकर का प्रचलन बना। लगान की नई निर्धारित राशि और मुद्राकर की नई प्रथा का यह अमर पड़ा कि यमनिहर को फसल बाटन के तुरत बाद उपज का एक अग्र बचने के लिए बाध्य होना पड़ा। धूम्र, साधारणतः महाजन को सूद इसी वकन देना होता था इसलिए किसान को अपनी फसल का बहुत बड़ा हिस्सा बच देना पड़ता था।<sup>11</sup>

इंग्लैंड में आधुनिक उद्योगों के उदय के साथ ही इन उद्योगों के लिए कच्चे माल की जरूरत बढ़ी। भारत की अंग्रेजी सरकार ने ऐसी नीतियाँ अपनाईं जिनके फलस्वरूप अधिक से अधिक इलाकों में ब्रिटिश उद्योगों की जरूरत वाले कच्चे माल की खेती होने लगी। इसके चलते भारतीय कृषि के वाणिज्यीकरण और विशिष्टीकरण की गति और अधिक तेज हुई।

खेती का वाणिज्यीकरण उन इलाकों में अधिक तेजी से हुआ जहाँ फसल मुख्यतया निर्यात के लिए उगाई जाती थी। ऐसा खास कर चर्मा के धान, पंजाब के गेहूँ, पूर्वी बंगाल के जूट, एवं खानदेश गुजरात और बरार के रूई वाले इलाकों में हुआ। निर्यात व्यापार में लगे हुए लोगों के क्रिया कलाप के चलते खेती की उपज को कम समय में बंदरगाह पहुँचाने के लिए कायक्षम बाजार मगठन का जन्म हुआ।<sup>1</sup>

पूरी फसल का बहुत बड़ा भाग अब घर पर रखे जाने के बदले बाजार में आ गया। स्वाभाविक था कि जिन फसलों में बहुत बड़े पैमाने पर देशी और विदेशी व्यापार चालू था, उनके अलावा ज्वार, बाजरा, कोदो इत्यादि चीजों का बहुत बड़ा भाग भी विभिन्न कारणों से बाजार में आ गया, यद्यपि इन वस्तुओं की देशी तिजारत नहीं के बराबर थी।

सरकारी कर निर्धारण और महाजन के सूद की अदायगी आदि के कारण ऐसा हुआ। इन दो भुगतानों के लिए किसानों को फसल बटने के तुरंत बाद बाजार जाना पड़ता था और जो कुछ कीमत मिल जाए उस पर अपनी फसल का बहुत बड़ा अंश बेच देना होता था। बहुत सारे गरीब किसानों को करीब छ महीने के बाद फसल के समय जो अनाज बेचना था उसका कुछ अंश वापस खरीदना पड़ता था। फसल के समय कीमतें बहुत कम होती थी, लेकिन छ महीने बाद उन्हीं चीजों की कीमत किसानों के लिए सत्यानाशी सिद्ध होती थी।<sup>13</sup>

भारतीय अर्थतंत्र के पूँजीवादी रूपांतरण के फलस्वरूप स्वपर्याप्त ग्रामीण समुदायों का जो विनाश हुआ उसके बाद लोगों को बड़े दुर्दिन देखन पड़े और उन्हें आर्थिक दुर्दशा का सामना करना पड़ा। फिर भी एवल राष्ट्रीय या विश्व-जनीन अर्थतंत्र के विकास की दृष्टि से यह प्रक्रिया प्रगतिशील ही मानी जाएगी। इसने भारतीय लोक के राष्ट्रीय समेकन और विश्व के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एकीकरण के लिए आवश्यक भौतिक आधार जैसे, भारत का आर्थिक समुक्तीकरण और भारत का दुनिया के साथ समुक्तीकरण इत्यादि, के निर्माण की दिशा में सायक योगदान दिया।

उत्पादन के भीमत्त मकुचित दृष्टिकोण से भी कृषि का वाणिज्यीकरण आग का कदम था। कहा गया है कि 'जो परिवर्तन हो रहे थे उनमें पहला स्थान कृषि के वाणिज्यीकरण का है, जो मंत्रत लाभकर प्रक्रिया है। इसके चलते चलने का पहले से अच्छा वितरण सम्भव हुआ और कृषिजय लाभ में वृद्धि हुई।'<sup>14</sup>

अपनी निजी और गाव की सामूहिक ज़रूरतों को पूरा करने के बदले जब भारतीय किसान सारे विश्व के लिए फसल उगाने लगा, और कृषि उत्पादन की दिशा में परिवर्तन के फलस्वरूप न केवल फमला का वाणिज्यीकरण और विगिप्टीकरण हुआ, वरन् भारतीय गावा की कृषि और उद्योग की प्राचीन एकता भी भंग हुई।

हम ऐसे कारणों का उल्लेख कर चुके हैं जिनके चलते किसान की बाजार की खातिर फमल उगाने का बाध्य होना पड़ा। ये है भूमिकर के भुगतान के लिए उसे अधिक से अधिक नगदी का इतजाम करना पड़ता था और चूनि कालक्रम से किसान प्रायः महाजन के चंगुल में फस ही जाता था, इसलिए उसे कज के दाव का भी लगातार पूरा करते रहने की ज़रूरत पड़ती थी। बिन्ती के लिए फसल उगाने का तीसरा कारण भी था। आत्रागमन की सुविधाओं में दिनानुदिन हो रही प्रगति के चलते किसान जब गाव के बाजार या जिले के मले में बन्ना बनाया कपड़ा और अपनी ज़रूरत की अन्य चीजें आसानी से खरीद सकता था। पहले नियमत वह अपना कपड़ा खुद बनाता था और सालाना फसल के अक्ष के एवज में गाव का बारीगर उसकी अन्य ज़रूरतों को पूरा कर देता था। अब वह ये सब चीजें बाजार में खरीदने लगा। गाव के हस्तशिल्प एवं अन्य उद्योगों के पतन का यह भी एक मुख्य कारण था।

ग्रामीण कृषि के वाणिज्यीकरण एवं अग्रिम की सस्ती, मशीन से बनी, चीजा और फिर दूसरे देशों की, और फिर भारत के ही उद्योगों की बनी चीजों के अत्रागमन न गाव के मत्तुलित अर्थतन्त्र पर गहरी चोट की।

### परंपरागत भारतीय गाव का विघटन

आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थतन्त्र के दा आत्रार स्तभों, ग्राम कृषि और ग्रामाद्योग के मत्तुलन के नष्ट हो जाने पर आत्मनिर्भर गावा के अस्तित्व का आर्थिक आधार कमजोर हो गया।

जिसके रूप में लगान देने की प्रथा जो विगिष्ट उत्पादन और उपज प्रणाली और उसमें मपूवन कृषि और उद्योग की अनिवाय एकता में मनिद्ध है किसान परिवार की लगभग मपूण स्त्र पयाप्तता और गाव के बाहर के सामाजिक क्षेत्रों के इतिहास और उत्पादन संबंधी जादालना से इसकी म्वाधीनता इन सब कारणों से भारतीय गावों की अर्थव्यवस्था, एगिया में जिस प्रकार का सामाजिक स्थैय हम देखते हैं, उसके अनुकूल है।<sup>15</sup>

फिर, भारत के जिन ममुदाया में रूढ, परंपरागत समाज ममठन विनष्ट नहीं है वहां और यूरोप के प्राचीन एवं मध्ययुगीन इतिहास में देखा जा सकता है कि इन पुराने प्राकृतिक अर्थव्यवस्थाओं की उत्पादन पद्धति कृषि पर आधारित है। सन्नि मूह हस्तशिल्प और बारीगर अर्थतन्त्र में उभरने वाली अर्थव्यवस्था के दा पार्श्व स्तभ हैं। पूजापादी उत्पादन पद्धति ऐस मवधा को समाप्त कर देती है।<sup>16</sup>

गाव का सामुदायिक और स्वायत्तशासी चरित्र और भी कई कारणों से कमजोर हुआ। गाव की जमीन पर अपने परंपरागत अधिकार से तो गाव वंचित हुआ ही, समीपवर्ती वनभूमि और चरागाह के मुक्त और निःशुल्क उपभोग का उसका अधिकार भी जाता रहा। सारे गाव के नियंत्रण में किसान और गावों के अन्य लोग इस जमीन का इस्तेमाल जलावन की लकड़ी के लिए और जानवर चराने के लिए करते थे। गाव की साधारण अर्थव्यवस्था और कृषि व्यवस्था के अनुरक्षण संपोषण के लिए भी इस जमीन का निर्णायक मूल्य था। नए राज्य ने समीपवर्ती भूमि पर गावों के स्वत्व और उसके निःशुल्क उपयोग के अधिकार को समाप्त कर दिया। जिन जंगल कानूनों के जरिए परंपरागत अधिकारों का अपहरण हुआ, उसके बारे में पट्टाभि सीतारमैया ने लिखा है, 'कलम की एक ही चाट से, सरकार ने, रैयत के चिरकालीन सामुदायिक अधिकारों को समाप्त कर दिया और इस तरह ग्रामीण समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए।'<sup>17</sup>

गाव की कृषि पर सारे गाव का अधिकार था और वैसे ही समीपवर्ती वनक्षेत्र पर सारे गाव का अधिकार और शासन था। उसके फलस्वरूप गावों का सामुदायिक जीवन संपन्न समृद्ध रहा। स्वायत्तशासी, आत्मनिर्भर ये गाव संपूर्ण जैविक इकाई थे। उनके सम्मिलित स्वायत्त बंधन थे, इसका फसला वे खुद करते थे और इन स्वार्थों की परिपूर्ति के लिए सहयोग मिलता रहा था। इसके कारण गावों में सामुदायिक चेतना उदभूत और संपोषित हुई। जब वनभूमि और कृषिभूमि दोनों पर से गाव सामूहिक नियंत्रण और स्वत्व जाता रहा और दोनों निजी या राजकीय संपत्ति हो गए तब गाव वालों के सम्मिलित स्वायत्त और आर्थिक सहयोग पर आधारित पारम्परिक मंत्र विनष्ट हो गए। जो आर्थिक कार्य पहले ग्राम समुदाय संपन्न किया करता था वे अब केंद्रीभूत राज्य सत्ता के हाथ चले गए। सदस्या के सहयोग और सामुदायिक जीवन पर आधारित स्वायत्तशासी गाव समाप्त हो गए। निजी संपत्ति और बाजार में भी पुरानी अर्थव्यवस्था पर आधारित सहयोगी मंत्रों के अंतर्बन्धन ढीले कर दिए और अंततः उन्हें खतम ही कर डाला।<sup>18</sup>

केंद्रीभूत सरकार ने गाव समुदाय की सुरक्षा का भी उत्तरदायित्व अपने हाथों में ले लिया। आमशासी ग्राम समुदाय का धीरे-धीरे रूप परिवर्तन होता गया। कालक्रम से यह केंद्रीय सत्ता की प्रशासकीय इकाई मात्र रह गया और राष्ट्रीय, या सब पूंछिए, तो विश्व की अर्थव्यवस्था पर निर्भर उसका एक साधारण अंग हो गया। परंपरागत गाव की आर्थिक और प्रशासकीय आत्मनिर्भरता समाप्त हो गई। सम्मिलित आर्थिक स्वायत्त और तज्जय सहयोगी मंत्रों पर आधारित सामुदायिक ग्रामीण जीवन के बदल प्रतियोगिता और मध्य पर आधारित नए जीवनरूप विकसित हुए। सहयोगी सामाजिक आर्थिक मंत्रों का स्थानापन्न कर निजी संपत्ति और बाजार के मिश्रता पर आधारित प्रतिद्वंद्वी आर्थिक मंत्र सामने आए।

पूजीवादी अथ सबधो की रचना हुई और गावो मे उनका प्रवेश हुआ, अब तक के सारे स्थानीय स्वाधीन केंद्र एकीकृत राष्ट्रीय व्यवस्था मे सम्मिलित हुए और इस तरह भारत का राजनीतिक प्रशासकीय एकीकरण हुआ। इन सबके कारण, अब तक अभेद्य से दीख पडने वाले गावो की परंपरागत व्यवस्था को घातक चोट पहुंची।

उत्पादन, वितरण और विनिमय के नए सामाजिक सबधो के साथ नई सस्थाएं उदित हुई। प्राक ब्रिटिश भारत मे ग्रामीण समुदाय के सदस्यो के आपसी सबधो का निरूपण परंपरासम्मत रीति रिवाज के आधार पर होता था। पचायतों इन सबधो का नियमन करती थी और आपसी झगडो का निपटारा भी। अब उनकी जगह नए शासन द्वारा स्थापित कानून संहिता और कानून की कचहरिया जमीन के निजी स्वत्व पर आधारित नई भूमि व्यवस्थाजय जटिल सामाजिक सबधो को रूपायित करने लगी। 'सोलहवीं सदी के इंग्लड मे जिस परिवतन हुए ये वसे ही परिवतन अब यहा कृषि के क्षेत्र मे हो रहे थे। इस परिवतन के मूल बिंदु थे, मध्ययुगीन समाज तंत्र का विघटन, विदेशी कारका और सपत्तिमूलाक भावनाओ का आगमन, अनुवधी सबध और परंपरासम्मत तरीका से सहयोगी प्रयत्न के बदले व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, उद्यम और स्वतंत्रता की भावना की स्थापना।<sup>19</sup>

युगो की चट्टान शिला भी, देखने मे अभेद्य, इस प्राचीन परंपरागत सस्था, भारतीय ग्राम समुदाय की जसे अब जीवन सध्या समीप आ गई थी। भारतीय ग्राम समुदाय पुरानी राजनीतिक उथल पुथल, युद्ध और आक्रमण का आधान सफलता पूवक सभाल सका था। लेकिन भारतीय इतिहास मे अभूतपूर्व नए प्रकार के राजनीतिक शासनतंत्र एव आधुनिक पूजीवाद के वाणिज्यिक और औद्योगिक शक्तिया से परास्त हो गया। आत्मनिभर गावा का विनाश ऐतिहासिक दृष्टि से प्रगतिशील काय था।

लेकिन गाव के सामुदायिक जीवन, उनके मधुर मानवीय सबधा और युद्ध एव दुर्भिक्ष के अतिरिक्त अन्य दिनों की पारम्परिक सुरक्षा की भावना का विनाश दुखद तथा कारुणिक भी था।

दूसरी तरफ यह भी जातव्य है कि गावो की जिंदगी सकुचित और मकीण थी, साम्प्रतिक दृष्टि से दरिद्र अप्रगतिशील और निष्क्रिय। अगर भारतीय जन जीवन को राष्ट्रत्व, आर्थिक एकता, बौद्धिक विकास, और सामाजिक अस्तित्व के उच्चतर लक्ष्या की प्राप्ति करनी थी, ता आत्मनिभर गावा का विनाश आवश्यक और अवश्यभावी था।

इतिहास की गति द्वातामक होती है। अतीत के अच्छे तत्वा के विवधन स नही, वरन उनसे गुणात्मक परिवतन से प्रगति आती है। सहयोग और सामाजिक अस्तित्व के उच्चन्तरीय रूप ऐसे पुरान तत्वा के परिमाण्वात्मक विस्तार स नही वरन उनके विघटन मे उद्भूत होते हैं। यह मस्य है कि गावा के जयनत्र के पूजी

वादी रूपांतरण की प्रक्रिया में ग्रामीण सहयोग की भावना का अंत हो गया, लेकिन इस रूपांतरण की ऐतिहासिक प्रगतिशीलता इस बात में निहित है कि इसने आत्मनिर्भर गावों के पाथक्य को समाप्त कर उनकी अर्थव्यवस्था को संयुक्त एकीकृत भारतीय, अर्थात् राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का जग बनाया। भारतीय जन जीवन के आर्थिक समन्वय के लिए ऐसी प्रगति ऐतिहासिक दृष्टि से आवश्यक थी। जन साधारण के लिए रेल और बस जैसे आवागमन के साधनों की स्थापना से सामाजिक विनिमय की संभावना तेजी से बढ़ी और गावों के लोगों का भौतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पाथक्य समाप्त हुआ।

ऐसे लागा का समन्वित राष्ट्र भला कैसे बन पाता जो विभिन्न केंद्रों में अलग-अलग, विभक्त जीवन जी रहे थे, जिनके बीच भौतिक संपर्क एवं आर्थिक और सामाजिक विनिमय शून्यसम था? छोटे समूहों में स्वतंत्र और पृथक् जीवनयापन करनेवाले लोगों की जन चेतना राष्ट्रीय स्तर की भला कैसे होगी? भौतिक अस्तित्व के प्रतिवध चेतना की प्रकृति निश्चित करते हैं, और आत्मनिर्भर गावों का सकीण जीवन जन साधारण में ग्राम चेतना को ही उद्भूत कर सकता था। वायुरुद्ध मुहरबंद गावों के जीवन में गावों के जीवन दशन और चिंतन पद्धति से कोई भी आगे नहीं बढ़ पाता था, और इसका अपवाद भी विरले ही कोई होगा।

यह सच है कि पूजावादी संघना ने ग्रामीण सहयोग का अंत कर दिया। लेकिन इस सहयोग का उद्देश्य था सकीर्ण आत्मनिर्भर ग्रामीण अस्तित्व की सुरक्षा और उसका मपोषण। इसीलिए आत्मनिर्भर गावों की आवादी शताब्दियां तक, साम्राज्यो और राजवंशों के उत्थान पतन जैसी गंभीर सामाजिक घटनाओं से, या अपनी क्षुद्र ग्रामीण सीमाओं से परे संपूर्ण जिलों और प्रदेशों के विध्वंस-विनाश से अनुद्वेलित रही। गावों की स्वपयाप्त प्रकृति द्वारा अनुकूलित ग्रामीण एकात्मकता फलती फलती रही उच्चस्तरीय राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय एकात्मकता के अभाव में। ग्रामीण सहयोग ग्रामीण आत्मपर्याप्तता मपक्त था और गावों की स्वपयाप्तता के समाप्त हो जाने पर वहां के लोगों की सहयोग भावना का भी अंत हो गया। इस सहयोग भाव को बचाया भी नहीं जा सकता था, क्योंकि यह स्वपयाप्तता से जुड़ा हुआ था।

लेकिन गावों की आत्मनिर्भरता एवं यहां के लोगों के सीमित सहयोग का विनाश कर दश का जा पूजावादी एकीकरण हुआ उसने अथतत्र एवं सामाजिक सहकमण के उच्चस्तरीय रूपों के आगमन के लिए माग प्रशस्त किया। इसमें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के संगठन और दश के पैमाने पर सहयोग का रास्ता तैयार किया। दश के एकीकरण के पहले भारतीय जन जीवन अनेकानेक गावों में बिखरा हुआ था और इन गावों में परस्पर सामाजिक या आर्थिक विनिमय नहीं के बराबर था। इसीलिए इनका कोई सम्मिलित स्वायत्त नहीं था। पूजावादी एकीकरण ही इस आकारहीन पिंड से भारतीय राष्ट्र के उद्भव का भौतिक आधार सिद्ध हुआ।

यह दुःखद भले हो, किंतु आत्मनिर्भर गावों और इनके लोगों के सहयोगी

जीवन भा विनाश ऐतिहासिक तौर पर भारतीय जन के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक एकीकरण के लिए आवश्यक था। यह इतिहास सिद्ध है कि प्रगति ऐतिहासिक शक्तियों के नैतिकेतर क्रियाकलाप से आती है। यह नहीं भूलना चाहिए कि गांव सामाजिक निष्क्रियता और बौद्धिक जड़ता के दुग् थे, और युगो तक एक ही प्रकार के अस्तित्व को प्रतिपादित करत रह। इनके चलत भारत के एकीकरण के रास्ते में रकावटें आती रही। उनके अवसान पर हमे आसू बहाने की जरूरत नहीं।

### सदभ

- 1 देखें आ मेली जीर बडन पावेल।
- 2 राधाकमल मुखर्जी प० 16।
- 3 वहा प० 36।
- 4 दध धामसन और गरट ओ मली और बउन पावेल।
- 5 काय द्वारा उद्धत खड 1 प० 215।
- 6 देखें रगा बडन पावेल जीर दत्त।
- 7 आर० पी० दत्त, प 213।
- 8 वही प० 207।
- 9 देखें गाडगिन प० 153 155।
- 10 दध गाडगिन और व्यूकनन।
- 11 गाडगिन प 153 154।
- 12 वही, प० 154।
- 13 वही प० 155।
- 14 वहा प० 162।
- 15 रात मासस प० 82।
- 16 वहा प० 82 83।
- 17 मीतारमया प० 62।
- 18 देख आर० मी० दत्त और शलवकर।
- 19 शलवकर प० 106।

## भारतीय कृषि के रूपांतरण के सामाजिक परिणाम

### राष्ट्रीय कृषि का उद्भव

भूमि पर व्यक्तिगत स्वत्व और भूमिपदा के विरुद्ध व्यक्तिगत अधिकार पर आधारित नए भूमि सबंधों की स्थापना हुई, और भारत के कृषीय अर्थतंत्र ने प्रगति के नए अनगूने ऐतिहासिक दौर में प्रवेश किया। इसी तरह यहाँ की कृषक आबादी ने भी सामाजिक और आर्थिक अस्तित्व के नए युग में प्रवेश किया। इस नई स्थिति में जा नई समस्याएँ आई, जब हम उनका अध्ययन करेंगे।

एक नया महत्वपूर्ण तथ्य यह था कि नए भूमि सबंधों के कारण, भारतीय कृषि के सकीण ग्रामीण चरित्र के बदल उसके राष्ट्रीय चरित्र का उद्भव हुआ। सुमबद्ध जोतों की स्थापना, आधुनिक मशीनों का नेती के लिए इस्तेमाल, बैज्ञानिक खाद और जल-याय तरीकों से खेती का तकनीकी नवनिर्माण कृषि सबंधी य सारी तकनीकी और आर्थिक समस्याएँ जब सारे राष्ट्र की समस्याएँ थीं।

अंग्रेजों के शासन काल में भारतीय कृषि के राष्ट्रीय रूप और महत्व का जन्म होता हुआ, लेकिन यह बहुत नपान और समझ नहीं हो सकी। कुल मिलाकर किसानों की भौतिक स्थिति में भी बहुत तरक्की नहीं हुई। सगठन और उत्पादन की दृष्टि से भी कृषि की हातत में बहुत मुधार नहीं हुआ। अंग्रेजों के शासन काल में भी, अपने नवीन राष्ट्रीय रूप के बावजूद भारतीय कृषि का इतिहास अविरत और बधनशील अमगठन का इतिहास रहा है। किसानों की दरिद्रता और ऋणग्रस्तता बढ़नी गई, उनके भूमिस्वामित्व का अपहरण होता रहा, और अनेक खेतिहर सबहारा की हैसियत में आ गए।

### जमीन का उपविभाजन और विखंडन

भूमि का उपविभाजन और विखंडन भारतीय कृषि का दुर्दांत और विनाशकारी तथ्य है। हर किसान की जमीन कम होती गई और जात वाली जमीन अधिराधित अनार्यिक होती गई।

इसके अनन्य कारण थे। यूरोप में जब कृषि व्यवस्था में पूँजीवादी संग्रहों का



जन्म हुआ, तो उसके साथ ही खेती की इकाई के रूप में सुमगठित फार्मों का जन्म हुआ। भारत में अंग्रेजों ने जमीन का ऐसा कुछ पुनर्गठन नहीं किया। स्वामित्व और निजी ज़ोत की दृष्टि से जमीन मिली जुली सी रही। जमीन के विखंडन और खुली हुई भूमि व्यवस्था से होने वाले नुकसान पहले की ही तरह जारी रहे।<sup>1</sup>

परिवार के सदस्य पहले गांव द्वारा पूरे परिवार को दी गई जमीन के समुक्त मालिक थे और उस पर एक साथ काम करते थे। अब जमीन के निजी स्वामित्व की स्थापना और इसके हस्तांतरण के आधार के साथ ही समुक्त परिवार में अपकेंद्रित प्रवृत्तियाँ का जन्म हुआ। इसके चलते पारिवारिक भूस्वपदा का विभिन्न दावेदारों के बीच वितरण होने लगा, और जमीन का अधिकाधिक उपविभाजन हुआ।

बटाईदारी प्रथा के उदय के कारण भी जमीन का विभाजन हुआ। छोटे छोटे खेत और अधिक छोटे हो गए। लेकिन जमीन के उपविभाजन और विखंडीकरण की प्रक्रिया में सबसे अधिक निर्णायक तथ्य था खेती पर निभर लोगों की संख्या में वृद्धि। इसके कारण शहर और गांव के हस्तशिल्पियों और कारीगरों की आर्थिक बर्बादी भी हुई। कृषि पर आश्रित जागीरों की संख्या में वृद्धि की प्रक्रिया निम्नांकित संसार रकड से स्पष्ट है

खेती पर निभर आबादी (प्रतिशत में)<sup>3</sup>

1891	61	1%
1909	65	5%
1911	72	2%
1921	73	0%
1931	75	0%

इधर कृषि पर आश्रित जागीरों की संख्या बढ़ रही थी और उधर उद्योग धंधों पर आश्रित जागीरों की संख्या घट रही थी।

उद्योग धंधों पर निभर आबादी (प्रतिशत में)<sup>4</sup>

1911	5	5%
1921	4	9%
1931	4	3%
1941	4	2%

यह प्रवृत्ति उन्नीसवीं सदी के मध्य से ही बढ़ती रही थी। 1840 के फेमिन कमीशन रिपोर्ट में भी कहा गया था कि वह कृषि के अतिरिक्त अन्य कोई राजस्वर नहीं है उनकी संख्या खेती के लिए आवश्यक जागीरों की संख्या से बहुत अधिक है।<sup>5</sup>

यूरोप में इसका उल्टा ही हुआ। फ्रांस में 1876-1921 के बीच मतिहर जागीरों 67.7% से घटकर 53.6% पर आ गईं जर्मनी में 1875-1919 के बीच 61% से 37.8% पर इंग्लैंड और बेल्जियम में 1871-1921 के बीच 38.2% से 20.7% पर डेनमार्क में 1880-1921 के बीच 71% से घटकर 57% पर।<sup>6</sup>

भारत के इस अनौद्योगीकरण, अर्थात् आधुनिक उद्योगों की समानुपाती वृद्धि के बिना पुराने हस्तशिल्प के विनाश के कारण जमीन पर जन सकुलता बढ़ती ही गई।

इस जन सकुलता के कारण जमीन के उप विभाजन और विखंडन की प्रक्रिया और तेज हुई। एच० मान नं दक्कन के एक ठेठ, सामान्य गांव के सर्वेक्षण के बाद लिखा कि वहाँ की औसत जोत 1771 में 40 एकड़ थी, लेकिन 1915 में केवल सात एकड़।

जमीन के उपविभाजन और विखंडन की प्रक्रिया दक्कन तक ही सीमित नहीं थी, बरन कर्नोवेग तेजी के साथ सारे भारत में और सब प्रांतों में जारी रही। (1936 के आम पाम) 'भयुक्त प्रांत में औसत किसान की जोत 25 एकड़, बंगाल में 31 एकड़, मद्रास में 49 एकड़, और वाघे में 122 एकड़ है।'<sup>7</sup>

यह तो हुई औसत जोत के आकार की बात। इससे यह पता नहीं चलता कि अधिसंख्यक जोतें छोटे आकार की और अनाधिक थी, उनसे अधिक लाभ की गुंजाइश नहीं थी।

1926 के एग्रीकलचरल जनल आफ इंडिया न जोता का निम्न लिखित वर्गीकरण किया

10 एकड़ से ऊपर	24%
5 से 10 एकड़	20%
1 से 5 एकड़	33%
1 एकड़ या उससे कम	23%

पंजाब अपेक्षाकृत समृद्ध क्षेत्र था, लेकिन उसके बारे में भी रायल कमीशन आन एग्रीकलचर की राय थी

पंजाब के आकड़ों में पता चलता है कि 22.5% किसान एक एकड़ या कम जमीन जोतते हैं, 15% एक और ढाई एकड़ के बीच, 17.9% ढाई एकड़ और पांच एकड़ के बीच, और 20.5% पांच और दस एकड़ के बीच।

जमीन के उपविभाजन और विखंडन की प्रक्रिया चलनी रही। काग्रेम अग्रेशन इक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट न संयुक्त प्रांत की एतद्विषयक स्थिति के बारे में कहा है

पिछले कई वर्षों से जातों के विखंडन की प्रक्रिया लगातार चलती रही है। ऐसे किसानों की संख्या का अनुमान करना कठिन है जो एक बीघा जमीन के शतांश या चार सौवा भाग के मालिक हैं। लेकिन इनकी संख्या काफी बड़ी है।<sup>8</sup>

जाता के अतिशय विखंडन के कारण किसानों के लिए सुचारु रूप से बेतरी करना बड़ा कठिन था।<sup>9</sup> उप विभाजन और विखंडन की स्थिति यह थी कि 'अनक छोटे बेतार म हत का भी इन्तेमाल संभव नहीं था। जाता के अधिकाधिक विखंडीकरण के कारण खेतिहर मजदूरों की तादाद बढ़ती है और मुदाल एव फावडे

का इस्तेमाल बताने लगता है।<sup>10</sup> जमीन के अत्यधिक प्रतिभाजन और विखंडीकरण का यह स्पष्ट तकनीकी साक्ष्य है।

जनमर्यादा में निषेध बद्ध भूमि की अनिमकुलता का एक अतिरिक्त कारण है। लेकिन इसके महत्व का प्रायः अनिश्चित किया गया है। यह समझना आवश्यक है कि 'यह पुरातन आदिम भारतीय समाज की आधुनिक युग में उत्तरजीवी कोई चरित्रगत विरासत नहीं कि आजादी के तीन चौथाई लोगों का एकमात्र पेशा खेती है और वे खेती पर बेतरह और बुरी तरह आश्रित हैं। यह वस्तुतः एक अर्वाचीन तथ्य है और साम्राज्यशाही का सीधा परिणाम। ब्रिटिश शासन काल में कृषि पर अनानुपाती निभरता लगातार बढ़ती ही गई है, और ऐसा कृषि और उद्योग के पुराने मतुलन के विनाश और साम्राज्यवाद के कृषि प्रधान उपाग के रूप में भारत के अपकष के फलस्वरूप हुआ है।'<sup>11</sup>

कृषि पर अतिरिक्त भार की व्याख्या इस बात में भी नहीं होती कि पर्याप्त भूमि का अभाव था। 'जमीन के 34.2% भाग पर ही खेती होती है। 35.2% भूमि जो खेती के लिए दुष्प्राय है उस छोड़ने के बाद भी 30.6% भूमि अभी एभी है जिस पर खेती हो सकती है। सिंध और पंजाब में प्रचण्ड उर्वरता के विशाल क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ केवल जन की आवश्यकता है लेकिन सरकार इन क्षेत्रों में मिर्चाई का कोई इंतजाम नहीं कर रही है। फिर, नए क्षेत्रों में खेती करने के लिए पूँजी की आवश्यकता है और भारतीय किसान बज से उतना दब हुए हैं कि वे गुरु में लगान भर पूँजी नहीं जुटा सकते। इस समस्या के प्रति सरकार की चरम विरक्ति कुछ एभी है कि वह आर्थिक अनुदान या किसी अन्य रूप में भी कोई जाति सहायता नहीं देती।'<sup>12</sup>

### विखंडीकरण के परिणाम

भूमि के अतिशय उपनिभाजन और विखंडन का कृषि और कृषक की आर्थिक स्थिति पर घातक प्रभाव पड़ा। बड़े पैमाने पर बनानिक ढंग से खेती करने में खेती की इकाई के रूप में बड़े सुमवद्ध भूखेती की आवश्यकता होती है। जोना और दूरस्थ भूखंडों के आधार पर संपन्न और समृद्ध खेती संभव नहीं है।

बहुत हद तक छाटी जाता के कारण किसान गरीब रह, और उनकी गरीबी का यह तर्जिजा हुआ कि वे उत्पादन के तरीका और तकनीक का विकास नहीं कर सके। जमीन की तकनी पर खर्च करने के लिए पैसा नहीं रहने की वजह से किसान आदिम तरीका आर माधना का अपनाए रहने के लिए विवश था। बनावित प्लाट और भूखेती के आधुनिक यांत्रिक साधना का इस्तेमाल कर मनन की हालत में किसान नहीं थे और न वे अपने पशुओं का ही मर्याद आर गति संपन्न बनाए रख सकते थे। इसके अलावा कृषि का उत्तरांतर हुआ होता गया।

भूखेती पर आश्रित आजादी की वृद्धि के कारण पशुओं के लिए चारा उगाने का उपाय आजादी का अतिप्रमाण होने लगा और उनमें भी खेती होने लगी। इसके

फलस्वरूप पशुओं के लिए चारापूर्ति में कमी हुई, पीण्डितता के अभाव में पशु शक्ति क्षीण होने लगी और कृषि की उत्पादनशीलता घटी। इस तरह अनेकानेक कारणों से जोती जाने वाली जमीन का प्रति एकड़ उत्पादन लगातार घटता गया। विश्वश्र्वरैया न कहा है, 'साधारण युद्ध पूर्व स्थिति को आधार मानकर ब्रिटिश भारत का औसत उत्पादन, सिंचाई पर निर्भर फसला का छोड़कर पचीस रुपए प्रति एकड़ से अधिक नहीं होगा जबकि जापान में यह डेढ़ सौ रुपया से कम नहीं होगा।'<sup>13</sup> अब हम कृषि और कृषक की स्थिति को प्रभावित करने वाले अन्य कारणों का विवेचन करेंगे।

### नई भूराजस्व व्यवस्था

पहले कहा जा चुका है कि अंग्रेजी सरकार ने बिल्कुल नई राजस्व व्यवस्था स्थापित की। नई व्यवस्था में फसल अच्छी हा या बुरी किसान का हर साल निश्चित धनराशि के रूप में सरकार को लगान देना ही पड़ता था। भारत में सिंचाई की कोई उपयुक्त व्यवस्था थी नहीं, इसलिए वर्षा न होने पर या कम होने पर फसल की बर्बाद की ही अधिक सम्भावना रहती थी। सामान्य औसत वर्ष में भी किसान को अपनी फसल के लिए हिंदुस्तान या बाहर के बाजार में बहुत कम कीमत ही मिल पाती थी। फलस्वरूप, कालक्रम से सरकार को मालाना भाग की पूर्ति करना किसान के लिए असंभव हो गया और वह लगातार गरीबी और वज्र के भार से दबता गया।

यह बात 1892 में ही मान ली गई थी कि किसान की बढ़ती हुई गरीबी के मुख्य कारणों में एक है, भूमिकर और नज्जनिन ऋणग्रस्तता।<sup>14</sup> द ग्रेट फॉर्मिग नामक अपनी पुस्तक में व्होन नैश ने लिखा है, 'बंबई के अपने प्रवास काल में मुझे ठीक से पता चला कि अधिकारी वगैरह वसूली के लिए सूद पर रुपया चलाने वाले साहुकार को ही आधार मानते थे।'<sup>15</sup>

अंग्रेजों द्वारा लागू की गई भूमिकर व्यवस्था कृषक समुदाय की ऋणग्रस्तता और गरीबी का मुख्य कारण सिद्ध हुई। तहसीलदारों और बजट बनाने वाले सरकारी राजनेतियों का ऐसी व्यवस्था सुविधाजनक मालूम पड़ सकती है, जिसमें एक ही साथ पैंतीस बरस की अवधि के लिए समरूप अथवा पर नगद राशि के रूप में कर निर्धारण होता था, लेकिन जिन्हें अनिश्चित आय से निश्चित धन राशि देनी पड़ती थी, उनके लिए यह व्यवस्था, बुरे वर्षों में बरबादी लाई, और इसके चलते लागू सूदखोर बर्तियों ने चंगुल में बुरी तरह जकड़न लगे। काफी बुरी हालत में कभी कभी लगान स्थगित या माफ कर दिया जाता था। इससे लोगों की दुरवस्था कुछ कम होती थी, समाप्त नहीं।<sup>16</sup> भूमिकर के रूप में निश्चिन्त की गई राशि इतनी अधिक होती थी कि दुर्लभ भूमिकर व्यवस्था के दुष्परिणाम और अधिक गंभीर सिद्ध हुए।

1857-58 में जब ब्रिटिश राज्य ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन

सूत्र अपने हाथों में लिया, उस वक़्त सारे भारत का भूमिकर 15.3 मिलियन पौंड था। बाद में यह राशि बढ़ती ही गई। 1900 में यह राशि 17.5 मिलियन पौंड थी, 1911-12 में 20 मिलियन और 1936-37 में 23.9 मिलियन।<sup>17</sup>

भूमिकर लगातार बढ़ता ही रहा है। लैंड प्रॉब्लम्स इन इंडिया नामक अपनी किताब में राधाकमल मुखर्जी ने लिखा है कि 'मद्रास, बंगाल और मयुक्त प्रांतों में लगान की राशि दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती रही है।'<sup>18</sup> उन्होंने जाग यह भी कहा है कि 'मयुक्त प्रांत, मद्रास और बंबई में 1890 में 1920 के तीन दशक में कृषिजय आय लगभग 30, 60 और 20 प्रतिशत बढ़ी है और भूमिकर क्रमशः 57, 22.6 और 15.5 प्रतिशत बढ़ा है। भूमिकर में यह वृद्धि, नगद राशि के रूप में इसकी गणना और फसल के वक़्त इसकी वसूली, इन प्रांतों के किसानों की आर्थिक स्थिति पर ज़हा अनाधिक जोत देने का ही मर्यादा अधिक है। इन बातों का बड़ा बुरा असर पड़ा है।'<sup>19</sup>

जमीन की जनसकुलता और उसके उपविभाजन के कारण अनाधिक जोता की संख्या में वृद्धि हुई और ऐसी स्थिति में लगान की राशि भी बहुत अधिक तय की गई। ब्रिटिश राज के प्रारंभिक चरण में भारतीय किसान की गरीबी का यह मूल कारण था। अपनी घटती हुई आय से सरकारी लगान के भुगतान में अपने को असमर्थ पाकर किसान अतिवाधिक ऋणग्रस्त होते गए।

### कृषि का वाणिज्यीकरण

ब्रिटिश शासन काल में कृषि का जो वाणिज्यीकरण हुआ, उसका भी किसान के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ा। अब उस भारतीय एवं विश्व की मंडी के लिए फसल उगाता पड़ता था और इसलिए वह व्यापार की निरंतर बदलती हुई गतिविधि का शिकार हुआ। उसे अब अमरीका, यूरोप, जास्ट्रेलिया के विशाल कृषि व्यापार मंडा जैसे बिकट दुर्जेय अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता से होड़ लेनी पड़ी। भूखे बलों की जोड़ी और आदिम हल से बह जपना छोटा भा वेत जोतना था, और उसके प्रतिद्वंद्वी ट्रैक्टर और जायुनिज कृषि यंत्रों की सहायता से बड़े पैमाने पर खाद्य राशि उत्पन्न करते थे। वाणिज्यीकरण के कारण किसान धीरे धीरे (मध्यस्थ) व्यापारियों पर निर्भर होता गया, और अपनी बहतर माली हालत के कारण व्यापारियों ने किसान की गरीबी का पूरा फायदा उठाया। गरीब किसान के पास कभी कोई संचित निधि नहीं रही। अब सरकारी लगान और महाजन के मुद्द में भुगतान के लिए उसे फसल के वक़्त ही अपनी उपज का अधिकांश मध्यस्थ का उच्च देना पड़ता था। अगर वह इतना बर पाना ता उस अधिव पस जाते सखिन उस लाचारी में मोटा करता पड़ना था, इसलिए उस बहून कम पस मिल पाता था। उसके मुनाफे का बहून उदा भाग रिचवान या दलाल को चना जाता था।

## किसानों की बढ़ती हुई दरिद्रता

किसानों की गरीबी के और भी अनेक कारण थे। समय समय पर होने वाले कृषि सकट के अतिरिक्त सूखा और जलिवर्षा जैसे गैर सामाजिक तथ्यों के कारण भी किसानों की तगहाली बढ़ी। भारतीय किसान बुरे दिनों के लिए अनरागि का मन्त्र नहीं कर पाता था। मानसून अच्छा नहीं होने पर अद्विकाश किमाना के पास लगान जमा करने के लिए पैसा नहीं रहता था और इसलिए वे कज मे फसत गए। हिंदुस्तान की जिदगी मे दुर्भिक्ष का नजदीक का सरोका रहा है।

भूमिकर के अतिरिक्त किसान का विरोसन, तेल आर नमक जमी निरी निपट आवश्यकता की वस्तुओं के लिए भी कर देना पडता था। गरीब किसान जमीन की अपना आय का बहुत र्ण भाग राज्य को दे दता है, और उसे चीनी, विरोसन तेल, नमक और साधारण उपभोग की आय चीजों पर लगाए जाने वाले कर का भी वांश बर्दाश्न करता पडता है। इसके त्रिपरीत स्थाई बर्दाश्त वाले इनका के जमींदारों का बहुत मारी मुक्तिप्राए प्राप्त है। उह बढ़ी दूग तक फैली हुई अपनी जमींदारी के लिए नाम मात्र का ही शुल्क दना पडता ह। वह शुल्क भी लगभग सौ साल पहल तय हुआ था और उममे कभी किसी रद्दावदल की सभावना नहीं थी। उसकी कृषि जाय पर आयकर भी नहीं लगता है।<sup>०</sup>

जगला पर सरकारी एकाधिपत्य के कारण जलावन या गृह निर्माण के लिए किसान जगल से लडती नहीं ला सकता था। उसे खाद के बदल जलावन के रूप मे गोबर का इस्तेमाल करना पडा। इसके चलते जमीन की उपज घटी आर किमानों की गरीबी बनी। 'जगल सबधी बानूनों के कारण जो नुकसान हुआ है, उस पर पूरा ध्यान नहीं दिया गया है और न उसे पूरी तरह से समजन की वाधिषा हुई है। दुनिवार जसह्य मीकचो म लोगो को जकटने म इसका भी उतता ही योगदान रहा तिनता भूमिकर निर्माण और नमक कर का।'<sup>१</sup>

किसान अपने और अपने परिवार के लिए तो पर्याप्त भाजन का प्रबन्ध कर ही नहीं पाता था, वह अपने जानवरा का भत्ता अच्छी हालत म कसे ररता? बैलों की सख्या बडती गई उह मिलने वाली छुराक घटती गई। दुखी भूयें और बकार जानवरा की तान्ता बडने से नमीन की उत्पादनशीलता और भी घटी।

ऊपर जिन सारे तत्वा की चर्चा है उनके समुक्न प्रभाव के कारण किसानों की गरीबी लगातार जसाधारण तौर पर बडती गई। उनकी आय और जिम्मे वारिया के बीच रन्ती हुई विपमना न किमाना का अधिक कज लेने के लिए बाध्य बिया, लेकिन वे उसका मूद भी चुकाते रहने की स्थिति म नहीं थ।

यह एक दूषित चक्र था जिसम किसान की गरीबी से ही अपनी उमकी ऋण-प्रस्तता जैसे-जैसे उही जैसे-जैसे उमकी बडती हुई गरीबी का कारण भी सिद्ध हुआ। किसान धीरे-धीरे न तो ऋण चुवान की स्थिति म रहा आर न उसका मूद। इस तरह वह महाजना का अपनी फसल दे देन के लिए ता बाध्य हुआ ही, तेजी से अपनी

जमीन भी उह बेचने लगा। किसानों की जमीन के स्वत्वापहरण की यह प्रक्रिया बीसवीं सदी में काफी तेज हुई।

### किसानों की बढ़ती हुई ऋणग्रस्तता

ब्रिटिश शासनकाल में किसानों की ऋणग्रस्तता प्रत्येक दशक में लगातार बढ़ती ही गई। 1880 में भी हालत काफी बुरी थी। 'एक तिहाई काष्ठकार या बेतरह ऋणग्रस्त है कि जब उनके लिए ऋणमुक्त होना असंभव है, लगभग एक तिहाई और लोग भी ऋण के चक्कर में हैं, यद्यपि वे कभी भी अपने को इसमें मुक्त कर लेने की स्थिति में हैं। किसानों की ऋणग्रस्तता 1880 के बाद ज्यामितीय दर से बढ़ना ही रही है। इस तथ्य का अन्वेषण करने वाले सभी लोगों ने यह बात मान ली है <sup>3</sup> 'बहुसंख्यक किसान मूल्पोरा से कजा लिए हुए हैं।' (साइमन रिपोर्ट, जिल्द 1, पृ० 16)।

समय समय पर किसानों की सतत बढ़ती हुई ऋणग्रस्तता का अध्ययन होता रहा है और इससे स्थिति की भयंकरता का अनुमान होता है। 1911 में, मकलान्त के अनुसार केवल ब्रिटिश भारत में, समस्त ऋण राशि लगभग 300 करोड़ थी 1925 में एम० एल० डालिंग के अनुसार, लगभग 600 करोड़, 1929 में, मॉटल वॉकिंग एक्वायरी कमिटी रिपोर्ट के अनुसार 900 करोड़, और 1937 में, एग्रीकल्चरल क्रेडिट डिपार्टमेंट के अनुसार 1800 करोड़। <sup>1</sup>

1929 के विश्वव्यापी आर्थिक संकट का भारत के कृषक समुदाय पर काफी बुरा असर पड़ा। घेती के उत्पादन की कीमत इतनी तेजी से घटी कि 1929 से 1936 के बीच समस्त ऋण की राशि 1800 करोड़ हो गई। इस असाधारण वृद्धि का मूल कारण यह है कि 1929 के बाद किसानों की आय आगे से भी कम हो गई लेकिन उनका कर भार ज्यादा बढ़ा रहा। कुछ विपदग्रस्त क्षेत्रों में सरकार ने कुछ माफी भी दी, लेकिन यह बहुत कम थी। जमींदारी वाले इलाकों में मुक्त दमराजी के खर्च के कारण भी किसानों पर ऋण बढ़ा। सांग कर चुका सकने में किसानों की असमर्थता के कारण देकाए की राशि बढ़ती गई और जमादारों की आर से कचहरियों में मुकदमों की दायर होते रहे। किसानों की हालत पर इसका बड़ा बुरा असर पड़ा। मुकदमों के खर्च के लिए वे हर तरह से सूदखोर महानों पर निर्भर रहे। <sup>5</sup>

ऋणग्रस्तता का मुख्य कारण यह है कि 75% किसान जमीन से अपनी माधारण जीविका भी अर्जित नहीं कर पाते। <sup>6</sup>

ऋणग्रस्तता आज भारतीय देहात की अनन्य समस्या है। आज स्थिति यह है कि किसानों में 80% लोग अपनी मीजदा जोत के घल पर अपना खर्च कभी नहीं चुका सकेंगे। <sup>7</sup>

भूमि का हस्तांतरण, काश्तकार से गैर काश्तकार मालिकों को

किमानों की बढ़ती हुई ऋणग्रस्तता के कारण रैयतवारी इनाकों में बड़े पैमाने पर जमीन काश्तकारों के हाथों से निकलकर मूखोर महाजना के हाथ में जाने लगी और जमींदारी इलाकों में बड़े पैमाने पर किमानों की बेदखली हुई।

निष्ठुर मूखोर महाजना ने तत्परता से किमानों की बढ़ती का अधिक से अधिक फायदा उठाया। सूत्र की दर हर प्रांत में एक जैसी नहीं थी, लेकिन सब जगह काफी ऊंची थी, 12% से लेकर कुछ इलाकों में 200 या 300% तक।<sup>8</sup> इसलिए सब जगह माहुकार घणा के पात्र थे। वे अमानुषिक अन्न लिप्सा के मूल रूप थे और इस देश के साहित्य मंच नाट्य और फिल्म कथाओं में खलनायक के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे।

किसानों से पैसा चूसने के लिए ये साहुकार कानूनी तरीकों के अलावा जात सभाओं से भी काम लेते थे जैसे मूल से अधिक का शननामा लिखवाना गलत हिस्सा रखना, इत्यादि। वे किसानों की गरीबी और उसके अज्ञान का भी फायदा उठाते थे। अपनी अनभिज्ञता के कारण किसानों का जालसाजी का पता नहीं लग पाता था, और इस तरह वह कानूनी कायदाही नहीं कर पाता था।

ग्रामीण ऋणग्रस्तता का वैधानिक उपायो द्वारा समाप्त करने की सरकारों को शिशु नाकामयाब रही। रायल कमीशन जान एग्रोकलचर की रिपोर्ट में कहा गया है कि 'ऋणग्रस्तता की समस्या के समाधान के लिए किए गए वैधानिक प्रयास अपेक्षाकृत असफल रहे हैं।' किसानों की इस असाध्य एवं असह्य ऋणग्रस्तता के कारणों के बारे में रायल कमीशन की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है

भारतीय किसान प्रायः लाभ और प्रनिफल के लिए नहीं, बरन जीवननिर्वाह के लिए घटता था। भूमि की अतिमकुलता, और जीवन निर्वाह के धक्कलपक साधनों एवं अपनी दुदगा से बचन के उपायो की कमी इस सबके कारण कहीं भी, किसी भी शत पर फसल उगाने को किसानों का चार था। याद सामग्री के लिए उस जमीन की जरूरत है और जमीन के लिए उसे महाजन की मिनत चिरीरी करनी पडती है, यद्यपि जितनी उसकी चल अचल संपत्ति है उमस अधिक उस पर महाजन का ऋण है जहा उसकी जमीन महाजन के हाथ में चली गई है, वहा किसी भी कायदे-कानून से उमकी जरूरत पूरी नहीं हो सकती काश्तकारी या कोई भी कानून उसकी रक्षा नहीं कर सकता।

नई भूमि व्यवस्था में भूमि पण्य-वस्तु हो गई थी। इससे किसानों का यह अधिकारता मिला कि वह अपनी जमीन का बय या रहन कर सके, तबिन महाजन को भी यह अधिकार मिला कि वह किसानों की जमीन हडप ले। नए आर्थिक पर्यावरण में जिम दरिद्रता का जन्म हुआ उमके कारण अधिनाधिक जमीन महाजना की होने लगी। फनम्नम्प भारतीय वृषिक समाज का व्यापक स्वत्वाप हरण हुआ और दूरस्थ जमींदारों के बग का आविर्भाव हुआ।



यह भी नातव्य है कि काश्तकार के बदले महाजन या साहुकार जैसे गैर काश्तकार मालिकों के हाथ में जमीन के चने जाने के बाद भी कृषि के तौर-तरीकों में कोई तरक्की नहीं हुई। एग्रीकल्चरिस्टस रिलीफ ऐक्ट के कार्यान्वयन पर प्रतिवेदन के लिए 1892 में स्थापित डेक्कन कमीशन ने इस बात की आलोचना की है कि 'कृषि प्रधान देश में, बहुत अधिक कर वसूलने के बावजूद खेती की तरक्की नहीं करने वाले बाहरी लोगों के हाथ में जमीन चली जाए।' 9

कज के भारी बोझ ने कृषि और कृषक की प्रेरणा और पहल शक्ति को क्षति पहुंचाई। इंटरनेशनल कांफेडरेशन ऑफ एग्रीकल्चरल अलायंस के भूतपूर्व सभापति ने लिखा है 'सारा देश जैसा सर हेमिल्टन ने चित्रमय शैली में कहा है, महाजनों के शिकंजे में है। ऋण के बंधन ने कृषि को जैसे जजीरा से जकट रखा है। सूदखोरी की इस मवव्याप्त और निमग्न प्रथा ने रैयत की हड्डियां का सारा रस चूम लिया है, और उसे गरीबी और गुलामी की जिदगी जीने को बाध्य किया है। ऐसी स्थिति में उत्पादन तो घटता ही है आदमी की नाकन और उसकी इच्छाशक्ति को लकवा भी मार जाता है, वह भाग्यवादी हो जाता है। आशाहीन, थका हारा, लाभशून्य और उद्देश्यहीन जीवन किसी तरह घिसटता हुआ चलता है। अब इस तथ्य से इकार नहीं किया जा सकता। इसे सब माफ-साफ देख सकते हैं।'

### कृषि दासता का उद्भव

भारत के कुछ हिस्सों में ऋणग्रस्तता के कारण कुछ किसान अततागत्वा कृषिदास की स्थिति में पहुंच गए। इस तरह आधुनिक कज भारत से उत्पन्न आर्थिक पराधीनता ने एक मध्यमगीन मस्था का जन्म दिया।

आर्थिक दासता किस हद तक पहुंच गई है और साहुकार की पकड़ कितनी मजबूत है इसके दा उदाहरण दिए जा सकते हैं। बिहार और उड़ीसा में कमिऑटी नाम की प्रथा प्रचलित थी। यह व्यवहारत कृषि दासों द्वारा खेती की प्रथा है। कमिया लाग अपन मालिक के बाड़े हुए नौकर हैं, ऋण के मूल पर जा मूद जाता है उसके एवज में उन्हें मारे भृत्याचित काम करने पड़ते हैं। जमींदार की निजी जमीन पर खेती के लिए जो मजदूर बहाल हात हैं, उन्हें सबसे पहले जमींदार के महा काम के लिए हाजिर हाना पड़ता है। इस तरह अग्रिम राशि इमी शत पर दी जाती थी कि कृषि सबधी काम के लिए मजदूर जमींदार के बुनान पर तुरत जा जाए। ऐसे मजदूर जिन दिनों अपने साहुकार के लिए काम करते हैं उन दिनों के लिए उन्हें जन्म राशि मजदूरी के रूप में मिलती है। इस प्रथा में कमिया लागों का जघपन अवश्यभावी है कमिया अपनी मजदूरी के लिए मोलतोत नहीं कर सकता है ठेकेदार मजदूर की मरम्मत के लिए निग्रह मजदूर का जा मजदूरी दता है उसकी तब निहाई मादरी ही कमिया का ली जाती है जा समय बच जाता है उसमें काम कर वह सभी सभी कुछेक पस जमा कर लेता है। इसक

अतिरिक्त और कभी उसे पैसा देखने को भी नहीं मिलता। अतः इस बात की कोई उम्मीद नहीं कि वह अपने कज की मूल राशि चुका कर कभी भी स्वतंत्र हो सके। कमिओटी का शतनामा जैसे सारी जिंदगी के लिए दंडाज्ञा है।<sup>30</sup>

नई विधि-व्यवस्था में गरीब किसान की तुलना में धनी साहुकार का पलड़ा भारी रहा, क्योंकि मुकदमेवाजी खर्चीली थी। साहुकार तो वकील बहाल कर सकता था और मुकदमा बहुत दिनों तक चले तक भी उसका खर्च बर्दाश्त कर सकता था। लेकिन बेचारा गरीब किसान, जो मुश्किल से अपना जीवन निर्वाह कर पाता था, वकील की महंगी विधि सेवा का कड़ा से प्रबंध करता? अपने दावे को पुष्ट करने में चालाक साहुकार इस बात का पूरा फायदा उठाता था।

किमानों के बारे में प्रायः कहा जाता था कि वे अपव्ययी थे और सामाजिक धार्मिक अवसरों पर पैसा पानी जैसा बहाते थे और यही उनकी ऋणग्रस्तता का कारण था। लेकिन सुविज्ञ विशेषज्ञों ने जब किसानों के पारिवारिक बजट का अध्ययन किया तो पता चला कि ऐसे व्योहारों पर वे जो धन खर्च करते हैं, वह उनकी सारी आमदनी का अल्पांश मात्र है।<sup>31</sup>

इस दयनीय स्थिति की एक विशेषता यह भी थी कि सरकारी या गैर सरकारी दातव्य सस्थाओं द्वारा जो कदम उठाए गए उनका पूरा लाभ उठा सकने की स्थिति में किसान नहीं थे। जमींदार या साहुकार के दावे को पूरा करना तो कभी संभव था ही नहीं, जा किंचित लाभ किसानों का होता, उस भी वे लोग हड़प लते थे।

भारतीय किसानों की बेहद गरीबी और तज्जय ऋणग्रस्तता, अनार्थिक जोतों और आदिम तकनीक पर आधारित कृषि की उबरशीलता में कमिओटी का— इन सबके कारण बड़े गहरे थे। भारतीय कृषि और व्यवस्था मूलतः औपनिवेशिक थी। यह तथ्य देश के मुक्त विकास में बाधक था, और किसानों की गरीबी आदि का मूल कारण था।

भारतीय किसानों की गरीबी और ऋणग्रस्तता के कारण किसानों की जमीन बंया, महाजन या जमींदारों के हाथ में जाने लगी। काश्तकार मालिकों की सहायता और जमीन धीरे-धीरे गिन चुने लागों के अधिकार में आती गई। गरीब और मध्यम किसानों का अल्पांश ही धनी हो सका, उनका अधिकांश बंयादार या खेतिहर मजदूर हो गया।

### कृषि क्षेत्र में वर्गों का बढ़ता हुआ ध्रुवीकरण

किसानों के बीच वर्ग विभेदकीय प्रक्रिया लगातार अधिकाधिक तीव्र होती गई। खेतिहर मालिकों और काश्तकारों की सहायता घटती गई और गैर काश्तकार जमातों की सहायता बढ़ती गई। बंगाल, पश्चिम उड़ीसा, मद्रास और अन्य भागों में ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए सहायक मालिकाना कदम

जमींदारों का जो बग बना था उससे अनिश्चित अब दूरस्थ और गैर काश्तकार जमींदारों के एक नए बग का जन्म हुआ। निम्नांकित अंकों से स्पष्ट है कि ब्रिटिश भारत में गैर काश्तकार जमींदारों और खेतिहर मजदूरों की संख्या बढ़ती रही<sup>30</sup>

1921 (मिलियन)

1931 (मिलियन)

गैर काश्तकार

जमींदार 37 41

काश्तकार (मालिक

या बटाईदार) 74.6 65.5

खेतिहर मजदूर 21.7 33.5

बंगाल और मद्रास के उदाहरण से स्थिति और भी स्पष्ट होगी।

मद्रास की एक तालिका (प्रति हजार)<sup>31</sup>

	1901	1911	1921	1931
गैर कामगार जमींदार	19	23	49	34
गैर कामगार बटाईदार	1	4	28	16
कामगार जमींदार	484	426	381	390
कामगार बटाईदार	151	207	225	120
सबहारा	345	340	317	429

बंगाल की एक तालिका (प्रति हजार)<sup>31</sup>

	1921	1931	प्रतिशत वृद्धि या कमी
गैर काश्तकार जमींदार			
या तहसीलदार	390	634	+ 62
काश्तकार मालिक			
और बटाईदार	9 275	6 041	-35
सबहारा	1 805	2,719	+50

किसानों के बीच बढ़त हुए बग विभेदीकरण की यही प्रवृत्ति दूसरे दशक में भी परिनिश्चित है। सब जगह समान कारण विद्यमान थे और उनसे समान परिणाम हुए। खेतिहर मजदूरों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई। 1882 में इनकी संख्या 7½ मिलियन थी 1921 में 21½ मिलियन 1931 में 33 मिलियन। इस विषय के विवेचना का अर्थ है कि 1931 के बाद खेतिहर मजदूरों की संख्या में और अधिक वृद्धि हुई है।<sup>32</sup> गैर काश्तकार जमींदार काश्तकार मालिक और बटाईदार खेतिहर मजदूर—ये तीनों में प्रथम कुल इतने ही बग नहीं थे। भूमिहीन मजहारा के बीच खेतिहर आबादी के दूसरे तबके भी ये जो अत्यंत निम्न लगभग शून्य-व्ययता की स्थिति में थे।

दशक पूर्व भाग में शून्य-व्ययता और अल्प-व्ययता जमीन के अल्प-व्ययता प्रचलित थी। गुजरात में हुन्ना और हान्नी, तमिलनाडु में पत्थियन, तमिलनाडु में भगवा, सी० पी० में उरुमनियन और दूसरे भागों में ही अल्प-व्ययता भारतीय समाज

के निम्नतम जग ये, जा लगभग मध्ययुगीन आर्थिक शोषण और सामाजिक प्रतिवधा की स्थिति में रह रहे थे।<sup>36</sup> इनमें कुछ समुदायों जैसे गुजरात के हालियों की दशा गुलामों जैसी थी। हाली खेतिहर मजदूर है जो अपनी सुविधा के अनुसार मजदूरी नहीं कर पाता है। बड़े बड़े जमींदारों के यहाँ स्याई नौकरों की तरह पीढ़ी दर पीढ़ी खटते जाते हैं। जमींदार उनके भरण-पोषण एवं भोजन आवास का प्रबंध करते हैं। ये इस्तीफा देकर दूसरी जगह काम नहीं खोज सकते हैं। हालियों और गृह युद्ध के पहले के अमरीकी गुलामों की स्थिति में कोई वास्तविक उत्तर नहीं है, सिवा इसके कि हालियों के शरीर और श्रम पर मालिक के निरंकुश स्वत्व को 'यायालयों की मायता नहीं मिलेगी। कानूनन यह लागू स्वतंत्र वस्तुतः गुलाम।'<sup>37</sup>

पूजावादी व्यवसायों में भी, घामकर जहाँ यूरोपियन मालिक थे जैसे खर, चाय और काफी के बड़े बड़े बागानों में, मजदूरों के जीवन और श्रम की शर्तें काफी बुरी थीं। यूरोपीय पूजा ने औपनिवेशिक देशों में पूजा लगाई, इसका एक प्रमुख कारण यह था कि यहाँ श्रम सस्ता था। यूरोपीय मालिकों के बागानों के मजदूरों की मजदूरी तो कम थी ही, उन पर बहुत गारी पावदिया भी थी, जिनके कारण उन्हें अपने परिवार के साथ मालिक की जायदाद पर ही जिदगी गुजारनी पड़ती थी।<sup>38</sup>

### खेतिहर सवहारा बग का उदय

पहले भी कहा जा चुका है कि अधिकांश किसान मालिकों के गरीब हो जाने की वजह से भारत में खेतिहर मजदूरों का बग तजी से बढ़ता गया। विशेषणों का अनुमान है कि यह बग इतना बढ़ा कि गरीब खेतिहर आबादी के आधे लोग इसी बग के हो गए। शिकमी कृषकों की और जिन गरीब किसानों के पास अब भी अपनी जमीन थी उनकी हालत भी खेतिहर मजदूरों की हानत से कुछ खास अच्छी नहीं थी।

शिकमी कृषक और खेत मजदूरों की मदद में की गई खेती का अंतर समय पाना कुछ कठिन है। शिकमी में शायद ही कभी नग्न लगान मिलता है यह साम्प्रदायिक सिद्धांत पर आधारित है, और इसमें फसल का 40 से 60 प्रतिशत, या 40 प्रतिशत तक जमीन के मालिक का मिलता है। जमीन का मालिक ही बीज, पशु आजार और ऋण का प्रबंध करता है और शिकमी कृषक एक ही जमीन पर साल दर साल किसी तरह अपनी जीविका चलाता है। इसी तरह खेत मजदूर भी मालिक के ही बीज, पशु और आजार का इस्तमाल करता है समय समय पर अपनी साधारण जरूरतों के लिए अग्रिम पैसा भी लेता है और अंत में उस फसल में एक प्रती हुई राशि मिलती है या फसल का कोई निश्चित भाग मिलता है। खेत मजदूर का जायदाद अनाज के साथ योग्य तरह से भी मिलता है। शिकमी कृषक

अपने सामान और औजार से भी खेती कर सकता है, लेकिन व्यवहारत शिकमी काश्तकार और खेत मजदूर का अंतर स्पष्ट नहीं है। जब जमीन का मालिक वही दूर रहता हो तब तो यह समझना और भी मुश्किल है कि जो आदमी खेती कर रहा है वह खेत मजदूर है या शिकमी काश्तकार।<sup>9</sup>

खेतिहर आबादी में उही लागत की मर्यादा अधिक है जो पूरा सबहारा है या अधिकांश गरीब किसानों की तरह अध सबहारा। उच्च कृषक वर्ग की बढ़ती हुई गरीबी और उनकी जमीन के अपहरण के कारण सबहारा और अध सबहारा वर्ग की मर्यादा बढ़ती ही जा रही है। मध्यम और उच्च कृषक वर्ग का अल्पांश ही छोट या बड़े समृद्ध जमींदारों की श्रेणी में आ सका।

### परजीवी जमीन मालिकों के नए वर्ग का उद्भव

साहूकारों, व्यापारियों और जिन लोगों ने किसी तरह के शहरी पैसे में रुपया बनाया था, भूस्वामियों के इस नए वर्ग की भी जमींदारों के पुराने वर्ग की ही तरह कोई प्रगतिशील भूमिका नहीं रही। इन्होंने भी खेती की तरबूती के कोई काम नहीं किए। नए और पुराने दोनों प्रकार के जमींदार वर्ग का बटाईदारा स लगान वसूलों के अलावा खेती में कोई रुचि नहीं थी। पूजा लगाने के औद्योगिक रास्ता की भारत में कमी थी और जमीन की मांग काफी ज़रूरी। इसलिए पैसा रहना पर लागत ने जमीन खरीदना पसंद किया और उसे फायदेमंद समझा।

व्यापारी साहूकार और शहर के धनी लोग, गैर खेतिहर किसानों के इन नए भूस्वामियों को खेती से अभी कोई मतलब नहीं था उनके लिए यह नई चीज थी। अपनी जमीन के उत्पादन का व्यवस्थित करना, उसकी देखरेख करने और उसके तकनीकी और तरीकों का बदलने की उन्हें कोई खास इच्छा नहीं थी।<sup>10</sup> खेती में उनकी कोई खास रुचि नहीं थी इसलिए ऋणग्रस्त किसानों से इन्होंने जमीन खरीती या अधिया ली वह एक जगह न हारकर कई जगह तितर बितर थी। लागत में जमीन खरीदने की इच्छा काफी कम थी इसलिए इन नए जमींदारों ने ऊँचे लगान पर बटाईदारा का अपनी जमीन दे दी।

जमींदारों के पुराने वर्ग की भी स्थिति यही थी। उन्हें भी गैरखेती पसंद ही रहा। बटाईदारा से लगान की ऊँची दर वसूल करने का अलावा खेती में इनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी।

पुराने जमींदारों के अप्रगतिशील चरित्र एवं रूढ़िवादी आचरण के कारण राष्ट्रवादियों ने ही नहीं, बल्कि अंग्रेज वायसरॉय राजनेताओं और प्रचारकों ने भी की। इन्होंने जमींदारों का उदात्त अपने वर्ग के हित में यह राय दी कि किसानों पर लगान की मर्यादा ही लागत पर व्यवस्थित रूप से ध्यान दिया जाए, जोर अक्षय तकनीकी एवं यंत्रणाओं का उदात्त पर ध्यान पुनर्गठित किया जाए। लगातार नए जमींदारों का यह रुढ़िवादी निरालोचन अज्ञानमय समाजिक अंधधर्मियों, अज्ञानित परोक्ष जमींदारों के रूप में परिगणित आचरण था, किंतु इन्होंने

राय दी गई थी उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया।

भारतीय जमींदार पाश्चात्य दशों के जमींदारों के समकक्ष नहीं हो सके। उन्होंने अपनी जमींदारी में खेती का वैज्ञानिक तरीका नहीं चलाया, खेती का मशीनीकरण नहीं किया, हल के बदले ट्रैक्टर जैसे यंत्रों का इस्तेमाल नहीं किया। किसान से अधिकाधिक लगान वसूल करना ही भारतीय जमींदार का एकमात्र उद्देश्य था। जमींदार के कानूनी और गैर कानूनी रवियों से किसान की रक्षा के लिए कई बटाईदार कानून भी बनाए, लेकिन वे बहुत कारगर नहीं हुए।

जमींदारी व्यवस्था की एक विशेषता यह भी थी कि बटाई और शिकमी के कारण रयत और जमींदार के बीच बहुत सारे मध्यस्थ आ गए। राधाकमल मुखर्जी ने उपसामतीकरण की इस प्रक्रिया के बारे में लिखा है, 'जमींदार अपनी जमींदारी को पूरी तरह से बंधे बिना भी अपनी मितकियत को कम कीमत वाली छोटी जमींदारियों में वितरित कर सपया बना सकता है। उसका ओहदा बना रहता है और उसे सालाना मालगुजारी मिलती रहती है, जिससे सरकारी लगान देने के बाद भी उसके पास पसा बचा रह जाता है। कम कीमत की छोटी जमींदारियों वाले लोग भी यही प्रथा अपनाते हैं, जिसके फलस्वरूप बहुत से मध्यस्थ तैयार हो जाते हैं, जिन्हें खेती और जमीन के विकास में कोई रुचि नहीं इटनी और स्पेन में भी उत्तरी भारत के जमींदारी राज्यों जैसे मगधन है। उधर इटली और स्पेन में और उधर भारत में बड़ी जमींदारियों की एकमात्र रचि अपने लगान में है। वे एक या अधिक मध्यस्थों का जमीन लगा देते हैं और ये मध्यस्थ अपनी बटाई की अवधि में अधिक से अधिक लाभ कमाते हैं बगल के बहुत से जमींदार स्पेन और इटली के जमींदारों की तरह ही अयत्नवासी हैं, और लगान वसूलने भर से उन्हें मतलब है।'<sup>41</sup>

कुछ जिलों में उपसामतीकरण इस आश्चर्यजनक सीमा तक पहुंच गया है की सबसे ऊपर जमींदार और सबसे नीचे वास्तविक वास्तकार के बीच पचास से भी अधिक मध्यस्थ स्वाय विद्यमान हैं।<sup>4</sup>

फलस्वरूप, खेती करने वाले किसान एक अनुक्रमिक श्रेणी शृंग्रता की अतिम निम्नतम बड़ी हैं, और उन्हें लगान वसूल करने वाले गैरवास्तकार लोगों की बहुत बड़ी फौज का भार सभालना पडा है। अलिफतता में नाविक सिद्धवाद की पीठ पर जा समुद्री बूडा सवार हुआ था, वैसे बहुत सारे बूडे, भारतीय किसान की पीठ पर सवार थे। किसान को इन सारे लोगों का दिए जाने वाले लगान का दुबह असह्य भार डोना था।

रयतवारी इलाका में भी बटाई और शिकमी की प्रथा लगातार बढ़ती गई और जमान काश्तदार मालिकों के हाथ से निकलकर गैर-वास्तकार भात्रिका के हाथ में पडती गई। नए जमींदारों ने जमीन बटाईदारों का लगा दी, जिन्होंने उसे फिर शिकमी पर लगाया। इस तरह मध्यस्था की एक पूरी शृंग्रता तयार हो गई, और वास्तकार को लगान वसूलन वाल सब सागा का बाय ढाना पना।

अधिक लगान वमूली की प्रथा जो पहले जमींदारी इलाकों तक ही सीमित थी, अब दूरस्थ भूमिवास्त्व के कारण रयनवारी इलाका में भी बटाईदारा और शिकमी काश्तकारों की सहायता में बढ़ि हुई है। बंबई और मद्रास में तीस प्रतिशत जमीन की खेती बटाईदारा खुद नहीं करत हैं। इसी तरह पंजाब में भी लगान वसूल करने वाला की सहायता हाल में साठ लाख से एक कराड हो गई है। युक्त प्रांत में 1891 और 1921 के बीच लगान वसूलन वाला की सहायता में 46% की बढ़ि हुई है, और इसी अवधि में मध्य प्रदेश में 50% की।<sup>43</sup> जमीन के विभाजन और उप-विभाजन कृषि की अतिसकुलता उसकी उत्पादनशीलता का क्रमिक ह्रास, उसका तकनीकी पिछड़ापन, किसानों की ऋणग्रस्तता उनकी दरिद्रता और उनका सवहाराकरण इन सबकी तरह अधिकाधिक लगान वमूली की समस्या भी अखिल भारतीय राष्ट्रीय समस्या थी। आखिर इस समस्या का जन्म भी उही कारणों से हुआ था जिनके परिणाम अत्यन्त भी परिलक्षित हो रहे थे।

### भारतीय कृषि का औपनिवेशिक चरित्र

अंग्रेजों की भारत विजय और नई प्रशासन व्यवस्था के फलस्वरूप भारतीय कृषि तत्त्व नए रास्ता से विकसित हुआ लेकिन भारत की औपनिवेशिक स्थिति के कारण न तो यह विकास ही सम्भव था और न यहाँ की कृषि और कृषकों आवादी ही समृद्ध और उन्नतिशील हो सकी।

इंग्लैंड, फ्रांस और दूसरे स्वतंत्र पूँजीवादी देशों में पूँजीवादी मजदूरी के प्रवर्तन के बाद खेती की उपज बढ़ी और किसानों में समान-समृद्ध हुए। कृषि के तकनीकी आधार का अधिकाधिक मशीनीकरण हुआ और मनीहरे मजदूरों की उत्पादनशीलता बढ़ी। हल और अनाज मध्ययुगीन औजारों की जगह जुताई कटाई और दबती के ट्रैक्टर हार्वेस्टर आदि जसी आधुनिक मशीनों का इस्तमाल शुरू हुआ। कृषि की भौतिक इकाई का रूप में छोटे छोटे खेतों की जगह सघन कृषि क्षेत्रों (फार्म) का जन्म हुआ। कृषकों की आवादी का भौतिक और सांस्कृतिक स्तर ऊँचा से ऊँचा उठता गया।

यह सही है कि स्वतंत्र पूँजीवादी देशों में भी पूँजीवादी अधव्यवस्था के साधारण ह्रास के कारण सबकट बन्त हो गए हैं और उनका असर कृषकों अत्यन्त और आवादी पर पड़ा है। फिर भी पूँजीवादी देशों में इन मजदूरों का अस्तित्व नष्ट करने प्रभाव नहीं पड़ा है, जितना भाग्य जन्म उपनिवेशों में।

पूँजीवादी देशों के विपरीत भारत में नए भूमि मजदूरों का आगमन के साथ समानांतर औद्योगिक विकास नहीं हुआ। ब्रिटिश उद्योगों का मशीन निर्माण सामान्य बाजार में आने से पहले ही भारतीय कारीगरों में उद्योगिक प्रयोग हो गए और बुनियादी उद्योगों का विकास नहीं हो रहा था इसलिए उद्योग अत्यन्त काम चाली मित मरना। इस कारण न जीविकाप्राप्त के लिए उद्योगों के साम्राज्य में मशीनों का महाराज विद्या और भूमि की जागृत्तता और पड़ा ही। यह

भारतीय कृषि के विकास के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा रही है। इस जनसकुलता के कारण जमीन का विभाजन उपविभाजन हुआ और अनाधिक जोतों की संख्या बढ़ी, कृषि की गुण क्षमता का ह्रास हुआ और किसानों के त्रिक दारिद्र्यकरण की प्रक्रिया तेज हुई। 1850 के बाद भारत में देशी उद्योगों का जो विकास शुरू हुआ उसकी गति पुरातन हस्त शिल्प के विनाश की गति से धीमी थी।

भूमि की जनसकुलता और तज्जय उपविभाजन एवं विखंडीकरण के फलस्वरूप किसानों की आय में लगातार कमी होती गई। किसानों का अपनी फसल की बिक्री के लिए महाजना और मध्यस्था का सहारा लेना पड़ता था और वे किसानों की अनभिज्ञता और लाचारी का नाजायज फायदा उठाया करते थे। कृषि संकट, विश्व-बाजार के उतार-चढ़ाव किसानों का महाजनो मध्यस्थों द्वारा शोषण इन सब कारणों से किसानों की आमदनी और भी घटी। वे बड़ी तजी से गरीब होते जा रहे थे।

भूमिकर्तृ की राशि इतनी अधिक थी कि अधिकांश किसान उसे चुकाने में असमर्थ थे। साधारण जरूरतों की जो चीजें किसानों को खरीदनी पड़ती थी उन पर सरकारी टैक्स की रकम बहुत अधिक थी। इस तरह किसानों में अधिकांश का साहुकारा या सहयोग समितियों से कर्ज लेना पड़ता था। साहुकार किसानों से बहुत ऊँची दर पर सूद लेते थे और किसान मूल तो क्या सूद भी नहीं चुका पाते थे। कृषक आवादी में अधिकांश बुरी तरह ऋणग्रस्त थे। इसके कारण भी किसानों की गरीबी बढ़ी ही।

जैसे जैसे दारिद्र्यकरण के चपेट में अधिकाधिक किसान आते गए, वैसे-वैसे कृषि की हालत और भी चौपट हुई। निधन किसान न तो नए जानवर खरीद पाते थे और न खाद का ही प्रबंध कर पाते थे। उन्हें पुष्ट भोजन नहीं मिल पाता था इसलिए वेत पर काम करने की उनकी शारीरिक क्षमता भी प्रमथ क्षीण होती गई। इस तरह भारतीय कृषि गतिहीन ही नहीं ह्रासो-मुख भी हुई। प्रति एकड़ फसल लगातार कम होती गई।

किसानों के हर तबके में बढ़ते हुए दारिद्र्यकरण और ऋणग्रस्तता के फलस्वरूप जमीन बड़ी तेजी से धनी भूमिस्वामियों, महाजना और साहुकारों के हाथ में जान लगी और अंग्रेजी शासन द्वारा निर्मित जमींदार वर्ग के अतिरिक्त जमींदारों के एक और नए वर्ग की सृष्टि हुई। जमीन स अलग, दूर शहर में रहने वाले इन मातियों को भेती की तरफकी में कोई रुचि नहीं थी और न उन्होंने कृषि के साधनों के तकनीकी विकास की ही कोई जरूरत समझी। दूसरी तरफ, किसानों की भूमिहीनता का लाभ उठाकर वे किसानों को लगान पर जमीन देने लगे, और किसान उसका शिकमी बदायस्त करने लगे। इस तरह कृषक आवादी में श्रेणी-शृंखला का जन्म हुआ। जो भेती करता था वह श्रेण शृंखला की निम्नतम कड़ी था। उसे पैर-बाधक जमींदारों, शासकियों, उप-शासकियों का तांगे योग बर्दास्त करना पड़ता था। बटार्ड और भिन्नी के कारण जमीन का



अधिक लगान वमूली की प्रथा जो पहले जमींदारी इलाको तक ही सीमित थी, अब दूरस्थ भूस्वामित्व के कारण रयतवारी इलाका मे भी बटाईदारा और शिकमी काश्तकारो की सख्या मे वद्धि हुई है। वकई और मद्रास म तीस प्रतिशत जमीन की लेती बटाईदार खुद नही करत है। इसी तरह पंजाब म भी लगान वसूल करन वालो की सख्या हाल मे साठ लाख से एक करोड हा गई है। युक्त प्रांत मे 1891 और 1921 क बीच लगान वसूलन वाला की सख्या म 46% की वद्धि हुई है और इसी अवधि म मध्य प्रदेश मे 50% की।<sup>13</sup> जमीन के विभाजन और उप विभाजन कृषि की अतिमकुलता उसकी उत्पादनशीलता का क्रमिक ह्रास, उसका तकनीकी पिछडापन किमानो की ऋणग्रस्तता उनकी दरिद्रता और उनका सवहाराकरण, इन सत्रकी तरह अविवाधिक लगान वमूली की समस्या भी अखिल भारतीय राष्ट्रीय समस्या थी। अखिर इस समस्या का जन्म भी उही कारणा से हुआ था जिनके परिणाम अयन भी परिलक्षित हो रहे थे।

### भारतीय कृषि का औपनिवेशिक चरित्र

अंग्रेजो की भारत विजय और नई प्रशामन व्यवस्था के फलस्वरूप भारतीय कृषि तत्र नए रास्ता स विकसित हुआ, लेकिन भारत की औपनिवेशिक स्थिति के कारण न ता यह विकास ही उमुक्त था और न यहा की कृषि और कृषक आवादी ही समृद्ध और अनतिशील हा सकी।

इंग्लैंड, फ्रांस और दूसरे स्वतंत्र पूजीवादी देशो म पूजीवादी सबधा के प्रवतन के बाद खेती की उपज बढी और किसान मपन समृद्ध हुए। कृषि के तकनीकी आधार का अधिकाधिक मशीनीकरण हुआ और खेतीहर मजदूर की उत्पादनशीलता बढी। हल और अयाय मध्ययुगीन औजाग की जगह जुताई, कटाई और दबती क ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रमेर जैमी आधुनिक मशीना का इस्तेमाल शुरू हुआ। कृषि की भौतिक इकाई के रूप म छोटे छोटे खेता की जगह सघन कृषि क्षेत्रा (फार्म) का जन्म हुआ। कृषक आवादी का भौतिक और सांस्कृतिक स्तर ऊचा से ऊचा उठना गया।

यह सही है कि स्वतंत्र पूजीवादी देशा म भी पूजीवादी अथव्यवस्था के साधारण ह्रास के कारण सकट बढत ही गए हैं और उनका असर कृषक जयतन और आवादी पर पडा है। फिर भी पूजीवादी देशा मे इन मकटा का उतना नष्टकर प्रभाव नही पडा है, जितना भारत जैसे उपनिवेशी देश म।

पूजीवादी देशो के विपरीत भारत मे नए भूमि सबधा के आगमन के साथ समानांतर औद्योगिक विकास नही हुआ। ब्रिटिश उद्योगो के मशीन निर्मित सामान के बाजार मे आन की वजह से भारतीय कारीगरो म बहुमह्यक वर्दां हा गए और चूकि देश मे उद्योगा का विकास नही हो रहा था इसलिए उन्हें अयत्न काम नही मिल सका। इन लोगो न जीविकापाजन के लिए बहुत बडी तादाद मे लेती का सहारा लिया और भूमि की जनमकुलता और बढी ही। यह

भारतीय कृषि के विकास के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा रही है। इस जनसकुलता के कारण जमीन का विभाजन-उपविभाजन हुआ और अनाधिक जोना की संग्या बड़ी, कृषि की गुण क्षमता का ह्रास हुआ और किसानों के क्रमिक दरिद्रीकरण की प्रक्रिया तज हुई। 1850 के बाद भारत में दश्री उद्योगों का जो विकास शुरू हुआ, उसकी गति पुरातन हस्त-शिल्प के विनाश की गति से धीमी थी।

भूमि की जनसकुलता और तज्जय उपविभाजन एवं विखड़ीकरण के फल-स्वरूप किसानों की आय में लगातार कमी होती गई। किसानों को अपनी फसल की विक्री के लिए महाजनों और मध्यस्थों का सहारा लेना पड़ता था और वे किसानों की अनभिज्ञता और लाचारी का नाजायज फायदा उठाया करते थे। कृषि मकट, विश्व बाजार के उतार चढ़ाव किसानों का महाजना मध्यस्थों द्वारा शोषण इन सब कारणों से किसानों की आमदनी और भी घटी। वे बड़ी तेजी से गरीब होत जा रह थे।

भूमिकर की राशि इतनी अधिक थी कि अधिकांश किसान उसे चुकाने में असमर्थ थे। साधारण जरूरतों की जो चीजें किसानों का खरीदनी पड़ती थी उन पर सरकारी टैक्स की रकम बहुत अधिक थी। इस तरह किसानों में अधिकांश का साहुकारों या सहयोग समितियों से कज लेत रहना पड़ता था। साहुकार किसानों से बहुत ऊंची दर पर मूद लेत थे और किसान मूल तो क्या सूद भी नहीं चुका पात थे। कृषक आवादी में अधिकांश बुरी तरह ऋणग्रस्त थे। इसके कारण भी किसानों की गरीबी बड़ी ही।

जैसे-जैसे दरिद्रीकरण के चपेट में अधिकाधिक किसान आत गए, वैसे-वैसे कृषि की हालत और भी चौपट हुई। निधन किसान न तो नए तानवर खरीद पाते थे और न खाद का ही प्रबंध कर पाते थे। उह पुष्ट भोजन नहीं मिल पाता था इसलिए खेत पर काम करने की उनकी शारीरिक क्षमता भी क्रमशः क्षीण होती गई। इस तरह भारतीय कृषि गतिहीन ही नहीं, ह्रासो-मुख भी हुई। प्रति एकर फसल लगातार कम हाती गई।

किसानों के हर तबके में बढ़ते हुए दरिद्रीकरण और ऋणग्रस्तता के फलस्वरूप जमीन बड़ी तेजी से धनी भूस्वामियों महाजनों और साहुकारों के हाथ में जान लगी और अंग्रेजी शासन द्वारा निर्मित जमींदार वर्ग के अतिरिक्त जमींदारों के एक और नए वर्ग की सृष्टि हुई। जमीन से जलज, दूर शहर में रहने वाले इन मालिकों की गती की तरफकी में कोई रुचि नहीं थी और न उहान कृषि के माधनों के तकनीकी विकास की ही कोई जरूरत समझी। दूसरी तरफ, किसानों की भू-शुधा का लाभ उठाकर वे किसानों का लगान पर जमीन देने लग, और किसानों उमका शिकमी बढावस्त करने लग। इस तरह कृषक आवादी में श्रेणी-श्रेणी का जम हुआ। जा गेती करता था वह इस श्रेणी श्रेणी की निम्नतम बड़ी था। उसे गैर-आश्रयकार जमींदारों, राजकारों, उप-आश्रयकारों का जग बान बर्दास्त करता पड़ना था। बटार और शिकमी के कारण जमीन का

उपविभाजन और बड़ा और जोतें अधिक-से अधिक अलाभकर होती गई।

खेतिहर मालिकों के हाथ से गैर काश्तकार मालिकों के हाथ में जमीन के जान से कृषि क्षेत्र में वर्गों का ध्रुवीकरण बढ़ा। कृषक आवादी के एक छोर पर गैर काश्तकार जमींदारों की मर्यादा बढ़ी। दूसरी ओर खेतिहर सबहारा वर्ग की मर्यादा बढ़ी। निधनतम किसानों और बटाईदारों की स्थिति खेतिहर मजदूर से कुछ खास भिन्न नहीं थी और ये तीनों खेतिहर सबहारा वर्ग के ही अंग माने जाएंगे।

भूमिहीन किसानों और साथ ही गैर काश्तकार कर वसूलन वाले लोगों की संख्या बढ़ती गई। कृषक समुदाय के एक छोर पर संपत्ति एकत्र होती गई, दूसरे छोर पर भूमिहीन और बेहद गरीबी। 1914 के बाद इस प्रवृत्ति ने विकराल रूप धारण कर लिया था। राधाकमल मुखर्जी ने कहा है 'जबतक जमीन के नए व्यवस्थापन, कृषि सहयोग और बज्ञानिक कृषि के जरिए ग्रामीण अर्थतंत्र में मूलभूत परिवर्तन नहीं होते तबतक भूमिहीन किसानों की समस्या और भी भयंकर होती जाएगी और यह वर्ग शहर के औद्योगिक सबहारा वर्ग जसा हाता जाएगा। यह प्रवृत्ति आगवाने सामाजिक उथल-पुथल की पूर्व-सूचना है।'<sup>44</sup>

इस तरह भारत की औपनिवेशिक स्थिति के कारण, खेती में नए भूमि स्वतंत्रों के आगमन से भी कृषि का आधुनिकीकरण नहीं हुआ और न कुछ ही दिनों के लिए सही, किसान समर्थ-संपन्न ही हो सके। जमीन पर सामाजिक स्वतंत्रों के बदले निजी स्वतंत्रों के आगमन से सामाजिक विनियम व्यवस्था का विकास हुआ लेकिन खेती के तकनीकी आधार में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ।

उपनिवेशी भारतीय किसान हल बल से छोटी, अलाभकर जोतों में खेती करता था। अब उसे इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे स्वतंत्र राष्ट्रों के शक्तिशाली कृषक पूँजीवादी व्यापार संघों और बड़े खेती या बड़ी जागीरों पर आधुनिक मशीनों की मदद से खेती करने वाले समर्थ पूँजीवादी किसानों से दुनिया के बाजार में होड़ लेनी पड़ी। किसी भी कृषि संकट का सामना करने में उसे दिक्कत होती थी। वह अधिकाधिक दरिद्र और ऋणग्रस्त होता गया।

भारतीय जनता को राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं थी। वह भारतीय अर्थतंत्र उद्योग, वाणिज्य और कृषि के उच्च विकास के लिए हितकर स्वतंत्र आर्थिक नीतियों और योजनाओं का न तो निरूपण ही कर सकती थी और न उनका कार्यान्वयन। भारतीय कृषि का विकास ब्रिटिश पूँजीवाद की आर्थिक आवश्यकताओं द्वारा अनुकूलित था, और ब्रिटिश पूँजीवाद को ब्रिटिश उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चे माल की आपूर्ति के लिए ही कृषक उपनिवेश के रूप में भारत की जरूरत थी। फलतः भारतीय कृषि का ऐसा स्वतंत्र विकास नहीं हो सका जिससे भारतीय जनता की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो। भारतीय कृषि की प्रगति एकांगी और विकृत रही।

फिर भी यह तो मानना ही होगा कि ब्रिटिश शासनकाल में गांव की फसल दश और दुनिया के बाजार में जाई और खेती सारे देश के अर्थतंत्र के तात्त्विक

अग के रूप में प्रतिष्ठापित हुई और यह अंग्रेजों की भारत-विजय का प्रगतिशील पहलू है।

इस तरह भारतीय कृषि और उसकी समस्याओं को राष्ट्रीय रूप और विस्तार मिला। स्वयंपूर्ण गावा के युग में ऐसी ग्रामीण अर्थतंत्र की सूझ से समन्वित थी, इसकी समस्याएँ गाव की आत्मनिर्भर अव्यवस्था की समस्याएँ थी। इनका प्रभाव गाव की आबादी तक ही सीमित था, बाहर की आबादी पर इनका कोई असर नहीं पड़ता था। भूमिकर के लिए राज्या को गावा की खेती का ही सहारा लेना होता था, लेकिन हर गाव की आबादी मुख्यतया अपने ही गाव की फसल पर निर्भर थी, दूररे गावों की फसल पर नहीं। हर गहर के इन्द्रगिद कुछ गाव होते थे जो उस शहर की कृषि सबधी जरूरतों की आपूर्ति कर देते थे। लेकिन मूलतः हर गाव की कृषि सबधी अपनी अलग समस्याएँ थी।

भारतीय कृषि के राष्ट्रीय उन्नयन के कारण अब कृषि सबधी समस्याएँ सारे देश की थीं। किसी गाव या जिला विशेष में खेती की स्थिति कसी है, इसका असर सारे देश पर पड़ने लगा, क्योंकि अब किसी क्षेत्र विशेष में केवल उस क्षेत्र के लिए नहीं बरन सारे देश के लिए फसल उगाई जाती थी। कृषि का अपकष, पशुआ की क्षीणता किमाना की दरिद्रता और ऋणग्रस्तता जमीन का विभाजन और विखंडीकरण, ये सब अब राष्ट्रीय समस्याएँ थीं। दूरस्थ मिलकियत, अतिशय भूमिकर, अपवाप्त औद्यागीकरण, देश की कृषक आबादी को ता यह एहसास था ही कि इही सब कारणों से उनकी सम्मिलित समस्याओं का जन्म हुआ है आधुनिक उद्योगों में सबधित बग भी इन समस्याओं का अपना ही समन्वित थे। खेती और गेतिहर की हालत का गैर गेतिहर वर्गों और उद्योगों की दशा पर भी असर पड़ा। किमानों की स्थिति और कृषि की अन्य समस्याएँ अब अखिल भारतीय समस्याएँ थीं।

चूँकि कृषि सबधी समस्याएँ सार राष्ट्र की समस्याएँ थीं, इसलिए उनके आधार पर सारे राष्ट्र का संगठित और जादालित किया जा सकता था। प्रत्येक पार्टी चाह यह किसी भी सामाजिक दल का प्रतिनिधित्व करती हो उसकी कृषि सबधी अपनी नीति थी और उस नीति के पीछे उस सामाजिक दल विशेष के स्वार्थ थे। विभिन्न वर्गों जैसे कृषक आबादी के ही विभिन्न अग, जमींदार, काश्तकार मालिक, बगानदार गेत मजदूर आदि के बीच जो स्वार्थों का मूषप था, उनका चलत विभिन्न वर्गों की नीति और उनका वायत्रम भिन्न थे। फिर भी विभिन्न और विराधी नीतियाँ भी अगिन भारतीय व्यवस्था के अभिन्न अग के रूप में राष्ट्रीय कृषि की समस्याओं से उत्प्रेरित थीं।

कृषि के पुनर्गठन की आवश्यक शक्तें

भारतीय कृषि का मर्मद करन के लिए उनका पुनर्र्धार और पुनर्गठन करन उन सभी वायत्रमा तथा नीतियाँ का सामाज्य लक्ष्य बन गया किन्तु भारतीय

कृषि समृद्ध हो सके तथा ऋषका का भौतिक स्तर सुधर सके ।

भारतीय कृषि के पुनरुद्धार और पुनगठन का प्रयास करने वाले विभिन्न दला के सभी आंदोलन ने इसके लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला, क्योंकि ब्रिटिश सरकार न ही भारत में नई कृषि की व्यवस्था की नींव डाली थी और ऐसी नीतियां अपनाई थीं जिनका भारतीय कृषि की स्थिति पर कुछ न कुछ असर पड़ा था । अंग्रेजों की सरकार विदेशी थी इसीलिए पुनरुद्धार और पुनगठन संबंधी आंदोलनों का रूप और विस्तार राष्ट्रीय था । कृषि क्षेत्र में सुधार या क्रांति के लिए जब विभिन्न दलों ने ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला तो वे राष्ट्रीय भावना से अनुप्रेरित थे, क्योंकि यह दबाव विदेशी सत्ता पर डाला जा रहा था । इस तरह अंग्रेजों की भारत विजय और उनके द्वारा लाई गई शासन व्यवस्था न राष्ट्रीय कृषि का प्रतिष्ठापित किया और भारतीय जनता में कृषि के विषय में राष्ट्रीय हित की भावना का विकास हुआ । इस राष्ट्रीय भावना के उदय के साथ साथ कृषि को समृद्ध बनाने की दिशा में भी प्रयास हुए ।

भारतीय कृषि के पुनगठन इसके विराम और किसानों की समृद्धि के सवाल बड़े बंधे थे । इनके समाधान के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी ऐसी योजना जो मुनियोजित राष्ट्रीय अर्थतंत्र से मेलबन हो । सारे अर्थतंत्र के विकास के बिना किसी एक अंग या उपाग का विकास पूरी तरह से संभव नहीं है । औद्योगिक उत्पादन की योजना के लिए कृषिजय उत्पादनों का समायोजन आवश्यक है, और इनकी सफलता मुनियोजित मुद्रा एवं ऋण तथा साख के संगठन पर निर्भर है ।<sup>45</sup>

नए भूमि-मवध और व्यापक ऋणग्रस्तता किसानों की गरीबी और कृषि के ह्रास के दो प्रमुख कारण थे । इसलिए राष्ट्रीय कृषि के उत्थान की किसी भी योजना की सफलता के लिए आवश्यक था कि पुराने संपत्ति मयदा का पुनर्गठन हो और ऋणग्रस्तता का खतम किया जाए । ऐसे किसी भी कार्यक्रम के कार्या बचन में जमींदारों, सूदखोरा और अन्य निहित स्वार्थियों जैसे शहरी मध्यमवर्ग जो तजी से जमीन खरीद रहा था का प्रतिरोध अवश्यभावी था । इसलिए जा भी आक्षिपक और छिटपुट कदम उठाए गए उनका कोई परिणाम नहीं निकला । खेतिहर वर्गों की ऋणग्रस्तता अमाध्य बीमारी थी ऋण को कम करने और साहुकारक क्रिया कलाप पर रोकथाम लगाने वाले विधान इस रोग का कोई इलाज नहीं कर सकेंगे ।<sup>46</sup>

फिर यह भी पाता है कि जबतक उनके ऋणों के समवत विलोपन जैसे उपायो द्वारा रंयता को एक सिरे से फिर से जिंदगी शुरू करने का मौका नहीं दिया जाता और जबतक उनकी गरीबी से संबंधित सारी समस्याओं पर विभिन्न दिशाओं से एक ही साथ आघात कर उन्हे कृषि नवधी क्रियाकलाप के लिए पूरी सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती तबतक भारतीय कृषि की समृद्धि की जाया बकार है ।<sup>47</sup>

उपरोक्त मतव्य के लेखकद्वय ने यह भी कहा है, 'अगर इस दिशा में एक-एक कर कच्चा काम करने के बढने हम जमीन के पुनर्वितरण ममग्र जोतो की स्थापना और बडे पैमाने पर सहयागी उत्पादन आदि की सभावना पर विचार करें, तो ऐसे उपाया का हमारी कृषि पर नातिकारी प्रभाव पडेगा। लेकिन इसका मतलब होगा कि साहुकारो से लेकर सामती और दूरस्थ जमीदारो तक हर प्रकार के निहित स्वार्थो से जमकर दीघवालीन मघप किया जाए हमारे पास दा ही विकल्प है, या तो हम सशक्त और मूलभूत परिवतन का रास्ता अपनावें, जिससे हमारे सामाजिक और आर्थिक सगठन का नवनिर्माण हो सके या फिर हम आज के अनियोजित नवहन की स्थिति का निर्वाह करते रहें। यह दूसरा रास्ता रुक-रुक कर चलने वाला सुधार का रास्ता है जिसकी परिणति होगी गभीर कृषि सबट में, और तब उसके कारण विध्वंसक नाति होगी।'<sup>48</sup>

भारतीय जनता की जरूरतो और उसकी साधारण आर्थिक प्रगति के लिए कृषि का मुक्त विकास आवश्यक है। ऐसा मुक्त विकास ही कृषि संबंधी राष्ट्रीय योजना का उद्देश्य है। लेकिन इस प्रकार की किसी भी योजना की सफलता की एक आवश्यक शत यह है कि राजनीतिक सत्ता भारतीय जनता के हाथ में हो। सुनियोजित और समृद्ध राष्ट्रीय कृषि के लिए दश की अपनी राष्ट्रीय सरकार आवश्यक है, ऐसी सरकार जो विदेशी या देशी निहित स्वार्थो के बदले भारतीय जनसमूह के हित और उसकी आकाक्षाओ को अभिव्यक्त कर, उन्हें सतुष्ट करे।

यह बात भी माननी होगी कि समस्त कृषि जय अथतत्र के नवनिर्माण जैसे वृहद काम, जिसका अर्थ है भारत जैसे उपमहाद्वीप के सारे उपलब्ध भौतिक तकनीकी और मानवीय साधनो का सुनियोजित सगठन और संचालन व्यवितगत उद्यम से संभव नहीं है। यह काम राज्य द्वारा ही संभव है। ऐसी योजना का यह भी मतलब होगा कि कृषि उत्पादन के क्षय में लाभ और प्रतियागिता की भावना गतम कर दी जाए। साथ ही भारतीय जनता की जरूरतो और भारतीय जयतत्र का सर्वांगीण प्रगति के दृष्टिवाण से कृषि उत्पादन को सहयोग के सिद्धांत पर निरूपित करना पडेगा। जिस प्रकार के कृषक सगठन की हम कल्पना करते हैं वह जनता के हितार्थ राज्य द्वारा उत्पादन के विनियमन और कृषि उत्पादन के जनापयोगी सवाआ के रूप में परिवतन पर आधारित होगा।'<sup>49</sup>

स्पष्टत, भारतीय जनता की राष्ट्रीय सरकार ही न कि भारतीय और विदेशी निहित स्वार्थो की सरकार, ऐसी योजना का सफल कार्यावयन कर सकेगी।

इस तरह भारतीय कृषि के पुनरुद्धार और उसकी प्रगति की समस्या महज तकनीकी आर्थिक समस्या नहीं थी। यह मूलतः सामाजिक आर्थिक और राजनितिक समस्या थी। भारतीय उद्योग के समुचित सवागीण, मिश्र और मुक्त विकास से इसका गहरा संबंध था। उद्योग के विस्तार में ही दहत की आगदी का अधिगण अथतत्र आत्मगत हा सक्ता था, और कृषि के आधुनिकीकरण और

कृषि समृद्ध हो सके तथा कृषक का भौतिक स्तर सुधर सके ।

भारतीय कृषि के पुनरुद्धार और पुनगठन का प्रयास करने वाले विभिन्न दलों के सभी जादोलन ने इसके लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने ही भारत में नई कृषि की व्यवस्था की नींव डाली थी और ऐसी नीतियाँ अपनाई थीं जिनका भारतीय कृषि की स्थिति पर कुछ न कुछ असर पड़ा था । जंग्रेजों की सरकार विदेशी थी इसलिए पुनरुद्धार और पुनगठन सबधी आंदोलनों का रूप और विस्तार राष्ट्रीय था । कृषि के क्षेत्र में सुधार या क्रांति के लिए जब विभिन्न दलों ने ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला तो वे राष्ट्रीय भावना से अनुप्रेरित थे क्योंकि यह दबाव त्रिदशे सत्ता पर डाला जा रहा था । इस तरह जंग्रेजों की भारत विजय और उनके द्वारा लाई गई शासन व्यवस्था में राष्ट्रीय कृषि का प्रतिष्ठापन किया और भारतीय जनता में कृषि के विषय में राष्ट्रीय हित की भावना का विकास हुआ । इस राष्ट्रीय भावना के उदय के साथ साथ कृषि को समृद्ध बनाने की दिशा में भी प्रयास हुए ।

भारतीय कृषि के पुनगठन इसके विकास और किसानों की समृद्धि के सवाल बड़े बड़े हैं । इनके समाधान के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी, ऐसी योजना जो सुनियोजित राष्ट्रीय अर्थतंत्र से सम्बन्धित हो । सारे अर्थतंत्र के विकास के बिना किसी एक अंग या उपाग का विकास पूरी तरह से सम्भव नहीं है । औद्योगिक उत्पादन की योजना के लिए कृषिजन्य उत्पादनों का समायोजन आवश्यक है, और इनकी सफलता मुनियोजित मुद्रा एवं ऋण तथा साख के संगठन पर निर्भर है ।<sup>15</sup>

नए भूमि-संबन्ध और व्यापक ऋणग्रस्तता किसानों की गरीबी और कृषि के ह्रास के दो प्रमुख कारण थे । इसलिए राष्ट्रीय कृषि के उत्थान की किसी भी योजना की सफलता के लिए आवश्यक था कि पुराने संपत्ति सत्रों का पुनरीक्षण हो और ऋणग्रस्तता को खत्म किया जाए । ऐसा किसी भी कार्यक्रम के कार्यायन में जमींदारों, सूदखोरों और अन्य निहित स्वार्थियों के जम शहरी मध्यमवर्ग जो तजी से जमीन खरीद रहा था का प्रतिरोध आवश्यक था । इसलिए जो भी आर्थिक और छिटपुट कदम उठाए गए उनका कोई परिणाम नहीं निकला । खेतिहर वर्गों की ऋणग्रस्तता जसाध्य बीमारी थी ऋण को कम करने और साहुकारों के विनाश के लिए पराक्रम लाने वाले विधान इस रोग का वाइ इलाज नहीं कर सकेंगे ।<sup>16</sup>

फिर यह भी याद रखें कि जबतक उनके ऋणों के समवेत विलोपन जैसे उपायों द्वारा रकबा का एक सिर से फिर से जिंदगी शुरू करने का मौका नहीं दिया जाता और जबतक उनकी गरीबी से संबंधित सारी समस्याओं पर विभिन्न दिशाओं से एक ही मान आघात कर उन्हें कृषि संबंधी क्रियाकलापों के लिए पूरी सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती तबतक भारतीय कृषि की समृद्धि की आशा बकार है ।<sup>17</sup>

उपरोक्त मतव्य के लेखकद्वय न यह भी कहा है, 'जगर इस दिशा मे रूढ़िवादी कृषि का काम करने के बदले हम जमीन के पुनर्वितरण ममग्र जोता की स्थापना और बड़े पैमाने पर सहयोगी उत्पादन आदि की सभावना पर विचार करें, तो ऐसे उपायों का हमारी कृषि पर आतिकारी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब होगा कि साहूकारों से लेकर सामंती और दूरस्थ जमींदारों तक हर प्रकार के निहित स्वार्थों से जमकर दीघवालीन मघप किया जाए हमारे पास दो ही विकल्प हैं या तो हम सशक्त और मूलभूत परिवर्तन का रास्ता अपनावे, जिससे हमारे सामाजिक और आर्थिक मगठन का नवनिर्माण हो सके, या फिर हम आज के अनियोजित मवहन की स्थिति का निर्वाह करते रहें। यह दूसरा रास्ता रूढ़िवादी चलने वाले सुधार का रास्ता है जिसकी परिणति होगी गभीर कृषि संकट में, और तब उसके कारण विध्वंसक आति होगी।'<sup>48</sup>

भारतीय जनता की जरूरतों और उसकी साधारण आर्थिक प्रगति के लिए कृषि का मुक्त विकास आवश्यक है। ऐसा मुक्त विकास ही कृषि मबधी राष्ट्रीय योजना का उद्देश्य है। लेकिन इस प्रकार की किसी भी योजना की सफलता की एक आवश्यक शत यह है कि राजनीतिक सत्ता भारतीय जनता के हाथ में हो। सुनियोजित और समृद्ध राष्ट्रीय कृषि के लिए देश की अपनी राष्ट्रीय सरकार आवश्यक है, ऐसी सरकार जो विदेशी या देशी निहित स्वार्थों के बदले भारतीय जनसमूह के हित और उसकी आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करे उ ह सतुष्ट करे।

यह बात भी माननी होगी कि समस्त कृषि जग्य अथतत्र के नवनिर्माण जसा वहद काय, जिसका अर्थ है भारत जसे उपमहादेग के सारे उपलब्ध भौतिक, तकनीकी और मानवीय साधनों का सुनियोजित मगठन और सचालन, व्यक्तिगत उद्यम से सभव नहीं है। यह काय राज्य द्वारा ही सभव है। ऐसी योजना का यह भी मतलब होगा कि कृषि उत्पादन के क्षेत्र में नाभ और प्रतियागिता की भावना सतम कर दी जाए। साथ ही भारतीय जनता की जरूरतों और भारतीय अथतत्र का सवागीण प्रगति के दष्टिकाण स कृषि उत्पादन को सहयाग के सिद्धांत पर निरूपित करना पड़ेगा। 'जिम प्रकार के कृषक मगठन की हम कल्पना करते हैं वह जनता के हितार्थ राज्य द्वारा उत्पादन के विनियमन और कृषि उत्पादन के जनापयोगी सेवाओं के रूप में परिवर्तन पर आधारित होगा।'<sup>49</sup>

स्पष्टतः, भारतीय जनता की राष्ट्रीय सरकार ही न कि भारतीय और विदेशी निहित स्वार्थों की सरकार एसी योजना का सफल कार्याचयन कर सकेगी।

इस तरह भारतीय कृषि के पुनरुद्धार और उसकी प्रगति की समस्या सहज तकनीकी आर्थिक समस्या नहीं थी। यह मूलतः सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्या थी। भारतीय उद्योग के समुचित सवागीण, निप्र और मुक्त विकास स इसका गहरा सबध था। उद्योग के विस्तार से ही देहात की आवादी का अविशेष अयत्र आत्मसात हो सकता था, और कृषि के आधुनिकीकरण और



मशीनीकरण के लिए औजार और यंत्र का निर्माण हो सकता था। भूमि सवधा के आमूल परिवर्तन के प्रश्न से कृषि के पुनरुद्धार का महत्वपूर्ण सरोकार था। यह राजनीतिक शक्ति और मत्ता का भी सवाल था। सवाल यह असल में भारतीय जनता के स्वतंत्र सावभौम राज्य की स्थापना का था, ऐसा राज्य जिसमें शक्ति निहित स्वार्थों के हाथ में न होकर आबादी के उत्पादक और शोषित तत्त्वों के पास हो।

इस तरह कृषि के नवनिर्माण की समस्या ऐतिहासिक तौर पर उच्चस्तरीय समाज के नवनिर्माण और स्वतंत्रता की समस्या से संपृक्त थी और यह ऐसी राष्ट्रीय समस्या थी जिसका प्रगतिशील निदान ही सम्भव था।

### संदर्भ

- 1 देखें शतवकर प० 106-7।
- 2 देखें वाडिया एड मर्चेन्ट प० 167।
- 3 वही प० 85।
- 4 वही प० 87।
- 5 अहमद द्वारा उद्धृत प 1।
- 6 वही प० 1।
- 7 वही प० 3।
- 8 कांग्रेस जर्नल इन्क्वायरी कमेटी रिपोर्ट प० 28।
- 9 देखें राघाकमल मुखर्जी मान विज्ञानारायण राग।
- 10 राघाकमल मुखर्जी प० 196।
- 11 आर० पी० दत्त प० 184।
- 12 अहमद प० 23।
- 13 विश्वेश्वरया अहमद द्वारा उद्धृत प० 8।
- 14 देखें कमाशन की रिपोर्ट (1892)।
- 15 आर० पी० दत्त द्वारा उद्धृत प० 22।
- 16 आर० पी० दत्त प० 227।
- 17 देखें आर० पी० दत्त 205।
- 18 राघाकमल मुखर्जी प 206।
- 19 वही प० 345।
- 20 इंडियन स्टैट्यूटरी कमाशन का रिपोर्ट 1930 जिल्द 1।
- 21 सीतारमया प० 62।
- 22 द फर्मिन कमीशन रिपोर्ट 1880।
- 23 देखें सर एडवर्ड मकनागन एम० एल० डालिंग द सट्टन बैकिंग इन्क्वायरी कमेटी का ज० थामस एग्राकल्चरल ट्रस्टि डिपार्टमेंट और अर्थ।
- 24 देखें वाडिया एड मर्चेन्ट प० 185।
- 25 अहमद प 26-27।
- 26 वही प० 27।

- 27 वाडिया एंड मर्चेंट पृ० 27 ।
- 28 प्रविणियल बनिंग इन्व्हायरी की रिपोर्ट दखें ।
- 29 आर० पी० दत्त द्वारा उद्धृत पृ० 235 ।
- 30 रायन कमीशन आन एघीरल्चर पृ० 433 34 ।
- 31 द डक्कन रायन्स कमीशन द गान प्रविणियल कमिटी रिपोर्ट कमिटी ऑन नो-आपरेयन ऑन मद्रास की रिपोर्ट ।
- 32 दवें आर० पी० दत्त पृ० 216 ।
- 33 वाडिया एंड मर्चेंट से उद्धृत पृ० 249 ।
- 34 वहा पृ० 249 ।
- 35 दवें सरकार इंडियन गान ऑफ इक्नामिक्स जुलाई 1939 पृ० 94 96 ।
- 36 दवें टिनकर देमाई अपरियन मफउम इन इंडिया इंडियन सांशियानिस्ट जुलाई 1942 ।
- 37 ज० एम० मेहता पृ० 125 ।
- 38 दवें रायन कमीशन ऑन लैबर आर० पी० दत्त जीर गिन राव ।
- 39 मद्रास बनिंग इन्व्हायरी कमिटी की रिपोर्ट पृ० 1930 ।
- 40 दय पनाउड कमिशन रिपोर्ट पृ० 37 ।
- 41 राधाकमल मुखर्जी पृ० 90 ।
- 42 साइमन कमीशन रिपोर्ट जिल्ड 1 पृ० 340 ।
- 43 वाडिया एंड मर्चेंट पृ० 231 ।
- 44 वायस इन्व्हायरी कमिटी की रिपोर्ट म उद्धृत पृ० 23 ।
- 45 वाडिया एंड मर्चेंट पृ० 231 ।
- 46 वहा पृ० 195 ।
- 47 वही पृ० 195 96 ।
- 48 वहा पृ० 182 ।
- 49 वहा पृ० 270 ।

## नागरिक हस्तशिल्प का अपकर्ष

### नागरिक हस्तशिल्प पर अंग्रेजी शासन का प्रभाव

डी० जार० गाडगिल ने नागरिक हस्तशिल्प पर अंग्रेजी शासन के प्रभाव का निम्नांकित शब्दों में बड़ा तात्त्विक, सांख्यिक और मशहूर विवरण प्रस्तुत किया है, पुराना हस्तशिल्पों का ह्रास भारत के आर्थिक संक्रमण की सर्वांगिक नाटकीय घटना है। इनका वस्तुतः बड़ा आकस्मिक और राक्षसी विध्वंस हुआ।<sup>1</sup> उ होने इसी प्रसंग में यह भी कहा है 'इसके अनेक कारण थे, लेकिन उन कारणों में सबसे महत्वपूर्ण ये हैं (1) भारत से पुराने देशी दरबारों का लोप (2) विदेशी शासन की स्थापना और तत्कालीन विदेशी प्रभावा का अन्वय (3) अधिकाधिक विकसित उद्योगों से प्रतियोगिता।' अंग्रेजी शासन काल में भारत के नागरिक हस्तशिल्प का यह जो आकस्मिक और संपूर्ण विध्वंस हुआ अब हम उसका विस्तृत सर्वेक्षण करेंगे।

### देशी राजवाडों अर्थात् नागरिक हस्तशिल्प के संरक्षकों का लोप

अंग्रेजों की भारत विजय के बाद लगातार एक के बाद एक तभी सदी राज्यों का पतन होने लगा। उनकी जगह इस्ट इंडिया कंपनी द्वारा विकसित शासन प्रशासन के नए रूप सामने आए। जहाँ देशी राज्य समाप्त नहीं हुए वहाँ भी अंग्रेजों का पराक्ष राजनीतिक प्रभुत्व बढ़ता ही गया। देशी राज्यों और उनके अधिकार के ह्रास का हिंदुस्तान की शहरी दम्पती पर तत्काल तब सीधा असर पड़ा। ये देशी राज्य ही शहरी शिल्पकारों के मामलों के सबसे बड़े भारीदार थे। इनमें से बहुतों के यहां कारखानों और शिल्पालय थे। इन कारखानों और शिल्पालयों में श्रेष्ठतम शिल्पी काम करते थे। इसलिए इन राज्यों के पतन का जान पड़ता है देशी कारीगरों की चीजा की मांग घट गई और यह देशी कारीगरों पर पहला बड़ा आघात था। इसके तत्कालीन परिणाम हुआ कि उन श्रेष्ठतम वस्तुओं का उत्पादन कम हो गया, जिसका फल यह हुआ कि राजा महाराजा राजकीय अवसरों पर उपयोग करते थे। राजदरबारों के खतम हो जाने पर साधारण चीजा

की मांग कुछ दिना तक बनी रही, लेकिन वह भी धीरे-धीरे कम हो गई।<sup>13</sup>

### नागरिक हस्तशिल्प पर विदेशी शासन का अनर्थकारी प्रभाव

भारतीय वस्तु निर्माण उद्योग पर विदेशी शासन का जो प्रभाव पड़ा, अब हम उसका विवेचन करेंगे। 1600 से 1757 तक ईस्ट इंडिया कंपनी मूलतः एक व्यापार संघ थी जो भारतीय राजाओं की अनुमति से, उनके संरक्षण में, या कभी-कभी उनकी अनिच्छा के बावजूद, भारत में तिजारत करती थी। यह व्यापार संघ प्रायः बाहर से बुलियन (साना चादी) लाता था और उसके बदले भारत से विलासिता के उपकरण जैसे मसाला, मूती, कपड़ा, इत्यादि विदेश ल जाता था। इस अवधि में भारत में बने सामान का निर्यात बढ़ा।

सत्तरहवीं सदी के अंत में रेशम और मूती सामान का बड़े परिमाण में निर्यात हुआ। [ईस्ट इंडिया] कंपनी के लिए यह बड़े लाभ का स्रोत बन गया, और 1672 में कंपनी ने बहुत सारे विलायती पैटर्न के साथ जेम्स धुनिया, रगरज और तागा बटन वाले को हिंदुस्तान भेजा कि वे यहाँ के कारीगरों को जेम्स और घूरापीय बाजार के उपयुक्त सामान बनाने के नए तरीके सिखा सकें।<sup>14</sup>

इस तरह जिन दिनों ईस्ट इंडिया कंपनी महज एक व्यापार संघ थी, और भारतीय सामान की खपत के लिए विदेश में जी तोड़ काशिश कर रही थी, उन दिनों भारत का निर्यात नरकही पर रहा। इंग्लैंड में भारतीय सामान के आधिकार से घबड़ा कर ब्रिटिश सरकार को उन दिनों ऐसे कानून बनाने पड़े जिनसे इंग्लैंड में भारतीय सामान की बिक्री कठिन हो जाए।<sup>15</sup>

पनासी की विजय ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के पैर जमा दिए। कंपनी के हाथ में अब राजनीतिक सत्ता भी थी, और उसकी मदद से अपनी तिजारत आगे बढ़ाने के लिए वह तरह-तरह की सुविधाओं की सृष्टि कर सकती थी जैसे कारीगरों को कंपनी की शर्तों पर काम करने के लिए बाध्य करना कम दाम में चीजे खरीदना कारीगरों के कामों पर अपना एकाधिकार बनाए रखना, बाहर से खरीदकर लाई गई चीजों का जबदस्ती भारत में बचना, राजनीतिक हथकड़ा से अपना एकाधिकार बनाए रखने के लिए दशों और विदेशी प्रतिद्वंद्वियों का उन्मूलन आदि।

1757 और 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के अधिकाधिक भू-भाग पर अपनी सत्ता का विस्तार किया, बहुत सारे देशी राज्यों को आत्मसत्त पर लिया और भारत में बहुत सारा धन विदेश पहुँचाया। ईस्ट इंडिया कंपनी के आलोचकों ने धन के इस निर्यात का लूट की मना दी है। इसी 'लूट' के जरिए ब्रिटन की औद्योगिक क्रांति के लिए आवश्यक पूँजी का 'आद्य मंचयन' हो सका। 'द ना जॉफ़ निग्रिलाइजेशन एंड चिके' नामक अपनी पुस्तक में ब्रुकस ऐडम्स ने इन तथ्यों के विस्तार से लिखा है।

पनासी की लड़ाई 1757 में हुई और इसके बाद अभूतपूर्व तेजी से बहुत

सारे परिवर्तन हुए। 1760 में तेज चलने वाली दरकी भरनी का आविष्कार हुआ और लाहा पिघलान के जलावन के रूप में तकड़ी ने बदले कायने का इस्तमाल शुरू हुआ। 1764 में हारग्रीम न सूत कातने वाली मशीन का आविष्कार किया, जोर 1776 में, नापटन ने एक ही साथ कई सूत कातने और उड़वटने वाली मशीन का, 1785 में वाटराइट ने मशीन में चलने वाले धरुके का पेटेंट कराया, जोर इन सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई कि 1768 में वाट ने भाष से चलने वाले इंजन का पूरा कर लिया। कर्मीभूत ऊर्जा के जितने सारे उदगम थे वाष्पचालित इंजन उनमें सबसे अधिक कायम था। युग की त्वरणशीलता को इन मशीनों से अभिव्यक्ति मिली लेकिन ये मशीनें इस गतिशीलता की कारक नहीं थीं। आविष्कार स्वतः निष्क्रिय हैं अनेक महत्वपूर्ण आविष्कार शताब्दियों तक मुप्तावस्था में पड़े रहे हैं इस प्रतीक्षा में कि प्रचुर शक्ति मचय हो और वे कायरेत हो सकें। यह शक्ति मचय धन वाय के रूप में ही संभव है। इस जन मपत्ति का गतिशील होना भी आवश्यक है भूगर्भ में मचिने काप में कोई लाभ नहीं। भारतीय जन के अतरागम के पूर्व जोर मज्जय वाणिज्यिक साग्य और विश्वास के बिना (ब्रिटेन के औद्योगीकरण के लिए आवश्यक) शक्ति बहा उपलब्ध नहीं थी। अगर गेट पचास साल पहले हुआ होता तो निश्चय ही वह और उसका आविष्कार नष्ट हो गए होते। मभजन मष्टि के प्रारंभ से जान तक कहीं भी पूजा लगान पर इनना फायदा नहीं हुआ है जितना भारत की लूट में ब्रिटेन को हुआ है। लगभग पचास वर्षों तक ब्रिटेन का कहीं कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं रहा। 1694 से पलासी (1757) तक विकास की गति धीमी थी 1760 से 1815 के बीच यह गति बड़ी तेज और अपूर्व रही।<sup>6</sup>

इस तरह जा औद्योगिक शक्ति आई उसके चलते इंग्लैंड में एक शक्तिशाली औद्योगिक वर्ग का जन्म हुआ। इस वर्ग ने धीरे-धीरे राज्य सत्ता पर अपना अधिकार जमाया और प्राच्य दशा में व्यापार करने के ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार का खतम करने के लिए इस राज्य सत्ता का उपयोग किया। इस वर्ग ने कंपनी को इसके लिए भी साध्य किया कि वह ऐसे राजनीतिक और आर्थिक काम उठाए जा ब्रिटिश उद्योगों के हित में हो। घोर मघप के बाद ही ब्रिटेन में व्यापारिक पूजा पर औद्योगिक पूजा की राजनीतिक विजय हो सकी।

जिन दिनों मज्जय में औद्योगिक वर्ग की ताकत बढ़ रही थी उस वकत भारतीय हस्तशिल्प तजी में श्री बिहीन हुआ। जा हम इसका विनाग के विभिन्न कारणों का अध्ययन करेंगे।

नवाहित ब्रिटिश उद्योग के लिए भारत में जन सामाना की प्रतियायिता में टिक पाना संभव नहीं था। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश बाजार में भारतीय सामान की प्राद रातन के लिए और इस तरह ब्रिटिश उद्योग का संरक्षण प्रदान

करने के लिए बहुत सारे कानून बनाए, जिनका भारत के निधान व्यापार पर बुरा असर पड़ा। होरेस विल्सन न बड़ी जानदार शैली में इसकी चर्चा की है

भारत के साथ सूती माता के व्यापार का इतिहास एक दुःखद प्रसंग है। इससे पता चलता है कि जिम देग पर भारत आश्रित हो चुका था, उसने भारत के साथ कैसा अत्याय किया यदि प्रतिरोध कर और कानून नहीं होते तो पजली और मैनचेस्टर की मिलें गुरु म ही बढ़ हो जाती, और भाप की ताकत से भी उह फिर चला पाना संभव नहीं होता। भारतीय निर्माण उद्योग का बलि चढाकर ही ब्रिटिश उद्योग की सृष्टि की गई। जिस तरह का प्रतिकार स्वाधीन रहने पर भारत कर सकता था, वसा कोई आत्मरक्षात्मक काय वह नहीं कर सका। वह अजनबी लोग की दया पर निर्भर था। ब्रिटेन में बने मामान पर कर नहीं लगता था और यह सामान खरीदन का भारत वाध्य था। ब्रिटिश उद्योगपतिया न राजनीतिक प्रभुता और अनीति की मदद स अपने भारतीय प्रतियोगिया को दवाए रखा और अततोगतता उह पूरी तरह समाप्त कर दिया, यद्यपि बगवर की लडाईं में नही टिक पाते।<sup>17</sup>

अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'रइन आफ इंडियन ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज' में वी० डी० बमु न भारत में इंगलड भज जाने वाल सामान पर लगाए गए करों की विस्तृत तालिका दी है। इस तालिका से स्पष्ट है कि अपन उद्योगों की तरक्की और उनके हिताय देशी बाजार का सुरक्षित रखने के लिए अयजी सरकार न जान बूझकर भारत के निर्यात व्यापार का गला घाट दिया।<sup>18</sup>

लकिन यह भी याद रखना चाहिए कि भारतीय हस्तशिल्प का विदेशी बाजार बहुत छोटा था। उसकी खपत के लिए सबसे अधिक गुजाइश हिंदुस्तान में ही थी।<sup>19</sup> यही विदेशी प्रभाव और शासन से सबसे भारी नुकसान हुआ।

### भारतीय हस्तशिल्प की वर्वादी के कारण

ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत के हस्तशिल्प उद्योग के लिए हानिकर था। इसके अनेक कारण थे। पहला कारण यह था कि अंग्रेजी शासन के चलते दशरी रजवाडे सतम हो गए। ये रजवाडे इस उद्योग के सबसे बडे खरीदार और मरक्षक थे। दूसरा कारण यह था कि या ईस्ट इंडिया कंपनी खुद उन उद्योगों को प्रथम द सकती थी लेकिन इसे अपने देश की सरकार के दवाव में ऐंसे काम करने पड जो भारतीय उद्योग के लिए अहितकर हुए। तीसरा कारण यह था कि कंपनी का स्वाय तिजारत में था और विदेशी मशीन पूरा फायदा उठान के लिए यह कम खच में चीजा का उत्पादन करना चाहती थी। इंगलैंड में भारतीय सामान पर जा कर नगाया गया उससे लाभ की राशि में कमी न हो इसलिए जरूरी हो गया कि उत्पादन पर कम खच हो। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कंपनी न धुनिया आर दूसरे कारीगरों पर अपना एवाधिकार जमाया और उह कम खच में चीजा के उत्पादन के लिए वाध्य किया। कंपनी के हाथ में राजनीतिक सत्ता थी, और

अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने इसका भी इस्तेमाल किया। भारतीय या गैर ब्रिटिश विदेशी सौदागरों को अधिक दाम में अपनी चीजें बेचने से कंपनी ने देशी कारीगरों का रोक दिया। इनकी स्थिति बहुत कुछ गुलामा की सी हो गई। चाथा कारण यह था कि कंपनी ने भारत में सीमा शुल्क लगाए और परिवहन के नियमन के तरीके अपनाए जिनके कारण भारतीय व्यापारियों को देश के अंदर तिजारत करने में भी कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ा। कंपनी द्वारा की गई इन कारवाइयों का उद्देश्य ही यह था कि प्रतिद्वंद्वी व्यापारियों का रास्ते से हटा कर भारतीय मंडी पर एकछत्र राज्य स्थापित कर लिया जाए। फलस्वरूप भारतीय हस्तशिल्प की कृतियों के लिए देशी बाजार नष्टप्राय हो गया। यह भी ज्ञातव्य है कि 1813 तक इंग्लैंड में वहां के औद्योगिक वर्ग राजनीतिक तौर पर समर्थ हो चुके थे। 1813 के चार्टर में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार का समाप्त कर भारत को अग्रज सौदागरों के निर्वाह व्यापार के लिए मुक्त कर दिया। यद्यपि सौदागर सोलहवीं-सत्रहवीं सदी में यहाँ आने वाले पुराने सौदागरों से भिन्न थे। यद्यपि सौदागर भारत में निर्मित सामान खरीदने नहीं, बरन इंग्लैंड की मिला में बने सामान बेचने आर इन मिलों के लिए बच्चा माल ले जाना आये थे। ईस्ट इंडिया कंपनी जब मुख्यतः इंग्लैंड के औद्योगिक वर्गों के राजनीतिक स्वार्थों की अनुचरी थी। 1814 के बाद अंग्रेजों उद्योगों के लिए आवश्यक बच्चे माल का आयात निर्यात ही इसकी नीतियों का मूल उद्देश्य रहा। यह भी उल्लेखनीय है कि अंग्रेजी शासन की स्थापना के कारण भारत में 'धनी व्यापारियों सफल साहूकारों और यूरोपीय लोगों की तरह रहने वाले सरकारी पदाधिकारियों के नए वर्ग' का जन्म हुआ। उनकी रुचि भी नहीं थी, और उन्हें अतिसारपूर्ण प्राच्य कला-कृतियों का कोई सौच नहीं था। ये कलाकृतियाँ बस्तुतः सामंती जीवन के ही उपयुक्त<sup>11</sup> आर इस नए वर्ग के रहने सहने के प्रतिकूल थीं।

अब आगे हम देखेंगे कि इन कारणों से नागरिक उद्योगों को कैसे नुकसान हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जा सामान इंग्लैंड ले जाते थे उन पर लगाए गए कर की राशि के असर को रोकने के लिए और अधिक से अधिक सस्ते भाव में सामान खरीदने के लिए कंपनी के सौदागरों ने हस्तशिल्पियों के खिलाफ बड़ी सख्त कारवाइयों की।<sup>1</sup>

बंगाल के 1793 के एक्ट जैसे कंपनी द्वारा बनाए गए विधानों और उच्च सौदागरों और एजेंटों द्वारा अपनाए गए दमनात्मक तरीकों का कारीगरों की जिदगी और उनके धन पर घातक प्रभाव पड़ा। जुलाहा के हजारों परिवारों को अपना पेशा छोड़ना शुरू किया। वोल्टस ने कहा है 'जुलाहा के मानों से भी अधिक परिवारों ने जंगलवाड़ी के इद गिद के इलाकों में दमनात्मक कारवाइयों के कारण अपना देश छोड़ दिया।'<sup>12</sup>

इस तरह देशी रजवाड़ों के बढ़ते जो नए शासन आए उद्योग कारीगरों का दाग मानकर छोटा और वे हस्तशिल्प उद्योग के मरने का अन्तिम कारण बने।

हुए। इसके चलते नागरिक हस्तशिल्प के कला कौशल एवं उसके विस्तार दोनों को नुकसान हुआ। कारीगरों व परिवार अपना पेशा छोड़ने लग।

देश के जदर लगाए गए परिवहन वर और सीमा शुल्क सबधी घोर अयायपूण नियमों और सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा अपनाए गए दमनात्मक कार्यों की सर चाल्स टिवेलियन न अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'रिपोर्ट आन ट्राजिट ड्यूटीज' म वडे स्पष्ट शब्दों म आलोचना की है। व्यक्तिगत और घरनू इस्तमाल की दा सौ पैतीस से भी अधिक वस्तुओं पर ये आदेशीय वर लग थे।<sup>14</sup> नवोदित ब्रिटिश उद्योगों के हित म जो काम किए गए उनका हस्तशिल्प के अतिरिक्त कुछ अन्य देशी उद्योगों पर भी बुरा अमर पडा। कंपनी के अविष्ठाताओं न निणय लिया कि विदेशी व्यापार के लिए केवल ब्रिटिश जहाजा वा इस्तमाल किया जाएगा। इसके चलते भारत के नौ परिवहन उद्योग को गहरी मार पडी। या इसके अशकन-अक्षम होन के अन्य कारण भी थे।<sup>15</sup>

इस अवधि म भारत के कागज उद्योग का भी क्षति पहुंची। ब्रिटिश गामको ने भारत म इस्तमाल के लिए केवल ब्रिटेन म बना कागज खरीदन का फसला किया। सर चाल्स उड क आदशानुमार भारत की ब्रिटिश सरकार विलायती कागज खरीदने को बाध्य थी। इसक कारण भारतीय कागज उद्योग अपने सबसे वडे खरीदार और मरक्षक स वचित हो गया।

एक अन्य महत्वपूर्ण उद्योग के विनाश के वार मे गाउगिल न कहा ह, 'ढात तलवार और अन्य हथियारों पर खूबनूरत दमिश्की बगर्ह जैसा काम भारत के उत्तर पश्चिम म, कच्छ, सिंध पंजाब म बहुत प्रचलित था। लेकिन इस विनिष्ट क्षेत्र म ब्रिटिश शासन न दम्नकारी को पूरी तरह खत्म ही कर दिया। अंग्रेजी शासन न हथियारों से लस रहने और उनके इस्तमाल की आवश्यकता समाप्त कर दी, और इस पर प्रतिबंध लगाए। अब विदेशी यात्रिया और अन्य लोगों के लिए जलवारयुक्त खूबनूरत नुमायशी चीज बनाना भर इस उद्योग का काम रह गया।'<sup>16</sup>

लोहा गलाने के उद्योग को भी वडी क्षति पहुंची। देशी राज्यों वा पतन इसका प्रमुख कारण था कयाकि राजे-रजवाडा क यहा ही इसकी खपत हाती थी। देशी राज्यों वा विनाश तो हुआ ही, साथ ही अंग्रेजी सरकार ने इंग्लैंड म भारतीय लोह के निर्यात पर वर लगा रखा था और नई सरकार ब्रिटेन के वन लोह के सामान को प्राथमिकता प्रदान कर रही थी। फिर 'अनुचित सीमा शुल्क और चीली नाइट्रेट के आनिष्कार स शारा उद्योग को काफी नुकसान हुआ। जंगलों के सरकारी मरक्षण और राने के विस्तार के कारण लकडी के कोयने की कीमत बढी, आर लाहा गलान वाले उद्योग को भी काफी नुकसान हुआ। इसकी एक वगह यह भी थी कि देशी उद्योग वा बाहर क कच्चे लोहे से होड लेनी पडी।'<sup>17</sup>

इस तरह, ब्रिटिश उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विदेशी सरकार न जा रक्षम उठाए उनकी वगह मे इन अवधि म एक के बाद एक देशी उद्योग



लगातार खतम होने लगे। वी० डी० बसु ने सरकार द्वारा किए गए इस तरह के मुख्य कार्यों की लिखित शब्दों में चर्चा की है

भारत पर राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के बाद इंग्लैंड ने भारतीय उद्योगों के विनाश के लिए नीचे लिखे तरीकों से काम लिया

- (1) भारत में अनाद्य त्रिटिंग व्यापार शुरू करना
- (2) भारत में निर्मित वस्तुओं पर त्रिटेन में वित्तीयों के लिए भारी कर लगाना
- (3) भारत से कच्चे काल का निर्यात करना
- (4) सीमा शुल्क और परिवहन कर लगाना,
- (5) भारत में रहने वाले जर्मनों को विशेष सुविधाएं प्रदान करना
- (6) भारत में रेलवे का निर्माण करना,
- (7) भारतीय कारीगरों का अपने राजगार की गुप्त बातें बतलाने का बाधक करना,
- (8) प्रदर्शनियों का आयोजन करना।<sup>18</sup>

ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद उदित मजदूर वर्गों के विचारों का भी भारतीय उद्योगों पर असर पड़ा।

नया शिक्षित वर्ग पुराने अभिजात वर्ग का स्वाभाविक उत्तराधिकारी था। यह नया वर्ग पश्चात्य देशों के बुजुर्गों पेशावरों तकनीकी तरीके से मुहयत नगरवासी और पेशावर वर्ग था। इतना यह उम्मीद की जा सकती थी कि यह हस्तशिल्प का संरक्षण प्रदान करेगा। लेकिन सत्य यह था कि कुछेक अपवाहों का छोड़कर इन लोगों ने देशी कलाकृतियों की ओर में मुह माड़ लिया। विजित जातियों पर विजयी जातियों के आदर्शों का प्रतिष्ठापन विदेशी शासन का एक अत्यंत हानिकारक परिणाम होता है। पिछली सदी के उत्तरार्द्ध की नवोदित बुजुर्गों की यूरोपीय मानदंडों का सुलेख से स्वागत किया। वे भारतीय वस्तु मात्र में घणा करते थे यूरोपीय फैशन का अनुसरण प्रबुद्ध नानोवय वर्ग प्रमाण चिह्न माना जाता था और इसमें देशी उद्योगों का नुकसान पहुंचा मनवत इस वर्ग के लिए ऐसा करना स्वाभाविक ही था। यह वर्ग पूरी तरह से ब्रिटिश शासन की ही दल था उसी से उदभूत लेकिन वह मौका पर यूरोपीय अफसरों की नाराजगी के भय से उलाहत भारतीय प्रबुद्ध वर्ग की रुचि निर्धारित हुई।<sup>19</sup>

इस तरह हस्तशिल्प का विदेशी बाजार ही नहीं, वरन् रजयाडे अभिजात वर्ग और समाज के अर्थ घनाढ्य वर्गों के रूप में उस जा देशी बाजार उपलब्ध था वह भी विनष्ट हो गया। विदेशी शासन के सचेत और अचेत क्रियाकलापों का भी इन उद्योगों पर असर पड़ा। पुराने अभिजात वर्ग और पुराने राज्यों के घनाढ्य नागरिक वर्गों की जगह जा गया घनाढ्य वर्ग आया उमने पुरानी कारीगरों की उपस्था ही की। इन सब कारणों से हस्तशिल्प उद्योग का प्रमाण शुरू हुआ और जा में यह लगभग पूरी तरह समाप्त हो गया। उद्योगों की मदी के चौपटार में

रलवे का विवास शुरू हुआ। उसके चलते देश के कोन-बान म विलायती सामान भर गया और भारतीय मडी पर विदेशी माल का प्रभुत्व न्यापित हुआ।

भारत म हस्तशिल्प उद्योग सदियों मे फलत फूलते रहे थे। उनके लिए भारत मार विश्व म प्रसिद्ध था और प्राचीन काल स ही मिस्रवासिया, ईरानियो, चीनियो, यूनानियो, रोमना, अरबा और यूरोपीयना की प्रशमा और ईर्ष्या का पात्र रहा। युगा तक इनके कारण भारत शानदार भारत रहा। अंग्रेजी शासन काल म इस उद्योग का बडा दुखद अंत हुआ। आज य प्राचीन काल के अवशेष कौतुहल के विषय और अजायबघरा की वस्तु भर रह गए ह। अब इनकी याद भर बाकी है पुरानी कलाकृतियों की उनकी नकली अनुकृतियों म जिह पुराने कारीगरा के बशज अभी भी आगरा, बनारस अहमदाबाद, सूरत राजपूताना के कुछ शहरो और ऐसे ही कुछ अन्य स्थानो म तैयार करते है। पुराने कारीगरा के व बशज जिह रोजगार का काइ दूसरा रास्ता नही मिला, जो पुराना रोजगार अपनाए रह और किसी तरह अपना अस्तित्व बनाए रह अभी भी छोट-छाट पूजीपतियों द्वारा चलाए गए कारखानो म बडी बुरी हालतो म काम करत है। 1880 तक हस्तशिल्प उद्योग लगभग पूरी तरह समाप्त हो गया था।

डी० जार० गाडगिल न लिखा है आठवें दशक म भारत जसा महान देश एक विचित्र दशावली था, जिसम हस्तशिल्प उद्योग नष्टप्राय था दूसरा काई उद्योग अभी विकसित नहां हुआ था, और अधिकाधिक लोग भूमि पर आश्रित होत लगे थ।<sup>०</sup> ब्रिटिश शासन काल म हस्तशिल्प के विनाश और पतन का यही इतिहास है। एक जमाने म ये उद्योग भारत के लिए गव और गौरव के विषय थे, लेकिन ये राजनीतिक, ऐतिहासिक और आर्थिक शक्तिया का दबाव नही सह सके।

### भारत के हस्तशिल्प के ह्रास की विशिष्टता

इंग्लैंड और दूसरे पूजीवादी दशा मे आधुनिक विनिर्माण और मशीन उद्योग की शुरुआत के बाद हस्तशिल्प का ह्रास शुरू हुआ। अथशास्त्र का एक आधारभूत नियम यह है कि सहज श्रम साध्य औद्योगिक तकनीक से वस्तुओ के उत्पादन पर अपक्षातृत कम खच होना है और वे तकनीकें पीछे छूट जाती है या बिल्कुल खतम ह जाती ह जो आदमी का काम उतना हल्का नही कर पाती। इस तरह मशीन उद्योग न धीरे धीरे हस्तशिल्प की जगह लनी शुरु की और सारी दुनिया मे आधुनिक उद्योग के बढ़ते हुए ज्वार के सामने हस्तशिल्प उद्योग का लोप होने लगा। इंग्लैंड और अन्य यूरोपीय देशा म देशी हस्तशिल्प की जगह देशी उद्योग का उदय हुआ और पुराने कारीगर प्राय नए उद्योगा म शामिल हो गए।

भारत मे देशी हस्तशिल्प का विनाश विदेशी सत्ता के राजनीतिक दबाव और विदेशी मशीन उद्योग के सस्त उत्पादन के कारण हुआ और इसलिए पुराने कारीगरा का जीविना का कोई नया साधन नही मिला। 1850 के बाद आधुनिक

उद्योग भारत में कुछ तेजी से बढ़े, लेकिन तब भी इतनी तेजी से नहीं कि तजी से वेकार और धर्वाद हो रहे कारीगरों के लिए पूरा रोजगार मिल सके। कुछ नए उद्योगों में गए जबकि लेकिन अधिकांश का जमीन का सहारा बना पड़ा। उनमें से कुछ किसान या बटाईदार हो सके लेकिन बहुत बड़ी तादाद में वे खतिहर मजदूर होने का वाध्य हुए।<sup>1</sup> इन कारीगरों का एक अर्थ तयका भी था, जो किसी तरह अपने पुराने रोजगार से ही जीविकापान करना रहा, लेकिन एत नोगों की सख्या लगातार घटती गई। जो पुराने राजगारों में लग रहे उह अपने सामान की खपत के लिए मंडी पर जाश्रित रहना पड़ा जोर व धीरे धीरे मीदागर वग व जाथिक शिकजे में और बुरी तरह जकडते गए और उनका शापण बढ़ना ही गया।

आधुनिक उद्योग का उदय हुए बिना नागरिक हस्तशिल्प के विनाश के कारण भारत में उद्याग और कृषि का असतुलन पैदा हुआ। जमीन पर जाश्रित लागों की मख्या बढ़ी और यह उन लागों के लिए और कृषि कौशल के लिए भी हानिकर था। ब्रिटेन की आर्थिक नीति के कारण पुराने हस्तशिल्प का विनाश हुआ, इस नीति ने नए उद्यागों का भी विकसित होने से रोका क्योंकि भारत में नए उद्योगों के विकास से ब्रिटिश उद्यागों व सामानों का यहा खपत घट जाती। इस तरह कृषि और उद्योग का पुराना मतुलन बिगड गया। ('भारत में आधुनिक उद्यागों का उद्भव और विकास शीघ्रक सप्तम अध्याय देखें')। एक नये कारण से भी ब्रिटेन ने भारत को मूलतः कृषि प्रधान देश बनाए रखने की कोशिश जारी रखी। इसे अपने उद्यागों के लिए भारत से समस्त कच्चे माल की जरूरत थी। इस तरह भारत एक औद्योगिक राष्ट्र का कृषि प्रधान औपनिवेशिक उपाग होकर रह गया।

भारतीय हस्तशिल्प की शिखर परिणति का स्वीकारत हुए भी हम उनकी सीमाओं और कमजोरियों का नहीं भूलना चाहिए। वे नागरिक हस्तशिल्प मूलतः मध्ययुगीन समाज की सीमित अभिजात वर्ग एवं संपन्न वर्गों की विलासिता संबंधी रचिया राज्यों की सभ्यता संबंधी आवश्यकताओं और धार्मिक दलों और मन्थानों के विशिष्ट उपकरणों या समय समय पर धार्मिक केंद्रों में जाने जाने वाले तीर्थ यात्रियों की विविध आवश्यकताओं आदि की ही आपूर्ति करते थे। वे साधारण लोगों की सामग्री की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं थे। इस कारण उनके द्वारा निर्मित पदार्थ और उनकी मंडी सदा सीमित रही। जब ये अपने बहुमूल्य पदार्थ विदेश भेजते थे तो वहा भी घनी लाग ही इन्हें खरीद पाते थे। बहुत अधिक खपत की गुंजाइश नहीं होने से इनके विस्तार एवं विनाश की संभावनाएं काफी सीमित थीं। यह विकास तभी संभव होता जब ये उद्योग साधारण लागों की जरूरतों को पूरा करते। राष्ट्र के रूप में देश का औद्योगिक एकीकरण तभी संभव था जब साधारण लोगों की प्राथमिक आवश्यकताओं के लिए उचित पैमाने पर चीजों का उत्पादन शुरू होता।

अनेकानक आत्मनिभर गावा म विपरे ठुण भारतीय लागा मे बहुसंख्यक की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति गात्र के कारीगर उद्योग द्वारा निर्मित चीजों के म्यानीय निमाण और उपभोग द्वारा होती थी। प्रत्येक गात्र स्वतंत्र उत्पादक और उपभोक्ता केंद्र या और देश म प्राथमिक दैनिक आवश्यकता की चीजों का विनिमय बहुत विरसित नहीं था।

## हस्तशिल्प के ह्रास का ऐतिहासिक महत्व

शहरी और देहाती दस्तकारी और कारीगर उद्योग के ह्याम और विनाश के कारण इनकी जगह आधुनिक विदेशी और फिर देशी उद्योगों के मस्त उत्पादनो की छपत गुरु हुई। परस्पर गावों के बीच, गावों और गहरो के बीच भारत और विदेशों के बीच नए विनिमय संबन्ध विलासिता के उपकरण और सय सबधी सामग्रियों तक ही सीमित नहीं थे। धरन दैनिक मानवीय उपभोग की सामग्रिया पर भी हावी थे। विनिमय संबन्धों का विस्तार हुआ और उन्होंने सारे भारतीय समाज को एक मूत्र में बाध लिया। इससे भारत के आर्थिक एकीकरण को मदद मिली।

यह सच है कि अपने रोजगार के छतम हा जाने के कारण शहरी कारीगरों को बड़ी तकलीफ का सामना करना पडा। इसका कारण यह था कि भारत म पर्याप्त मात्रा म समांतर औद्योगिक विकास नहीं हुआ था, जिससे बेकार कारीगरों का काम मिल सके। नतीजा यह हुआ कि खेती पर निर्भर लोगों की तादाद तेजी म बढ़ती गई और देहात के लाग लगातार गरीब होत गए। लोगों की तकलीफ से हम महानुभूति हो सकती है लेकिन यह तो मानना ही होगा कि जब आधुनिक उद्योग और वाणिज्य के कारण प्राक पूँजीवादी नागरिक हस्तशिल्प का विनाश हुआ, तभी आर्थिक इकाई के रूप में भारत का संगठन संभव हो सका। नए विनिमय संबन्धों ने सारी जनता को एक कर दिया और भारतीय जनता क मयुक्त अस्तित्व और विकास के लिए और उनकी अथव्यवस्था के राष्ट्रीय सम्बन्धों के लिए भौतिक आधार बनाने म मदद की।

पुराने कारीगरों में कुछ तो कारखानों और परिवहन उद्योग म लगे, लेकिन चूँकि इन उद्योगों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ इसलिये अविशेष खेती की ओर गए और खेत मजदूरी या बटाईदारी करने लगे। जमीन सरोदने लायक पूँजी उनके पास नहीं थी। इस तरह पुराने कारीगरों ने आधुनिक संवहारा वग, या बटाईदारा या खेत मजदूरों की तादाद बढ़ाई। ये उन वर्गों के अभिन अंग हुए जो ब्रिटिश शासन काल म उत्पन्न नए पूँजीवादी आर्थिक संबन्धों के आधार पर बने थे। अपर्याप्त रूप से ही विकसित नहीं, भारत की जो नई पूँजीवादी सामाजिक आर्थिक संरचना थी उसमें ये अंग थे। साथ ही उन्हें जिन नई गमम्याओं का सामना करना पडा वे शहर की परिसीमा के बाहर की थी वे राष्ट्रगत गममस्याए थीं। खेत मजदूरों, औद्योगिक संवहारा, बटाईदार, किसान मालिक, इन नए वर्गों

के कुछ ऐसे सम्मिलित स्वायत्त थे, उनकी ऐसी सम्मिलित समस्याएँ थी, जिनसे प्राकृतिक भारत के हस्तशिल्पकार अपरिचित ही रहेंगे। ये नष्टप्राय हस्तशिल्पकार नए युग में कुछ ऐसे वर्गों में सम्मिलित हुए जो भारतीय राष्ट्र के अगभूत भाग थे जिनके एक जैसे हित थे एक ही समस्याएँ थी, जो राष्ट्रीय इकाइयाँ थी। ऐसा होना निश्चय ही ऐतिहासिक दृष्टि से प्रगतिशील माना जाएगा।

### संदर्भ

- 1 गाडगिल प० १।
- 2 वही प० 37।
- 3 वही प० 38।
- 4 टामसन एंड ग्रेट प० 431 2।
- 5 देखें लेकी।
- 6 ब्रुकस एंड म्म प० 263 4।
- 7 मित्र द्वारा उद्धृत प० 385।
- 8 देखें मेजर बसु।
- 9 दक्ष गाडगिल और व्यूकनन।
- 10 टामसन एंड ग्रेट प० 434 5।
- 11 वही प० 434।
- 12 देखें बसु प० 85 7।
- 13 वोल्डस प० 195।
- 14 रामचंद्र राव प० 99।
- 15 देखें ए० म्मना।
- 16 गाडगिल प० 41।
- 17 वही प० 45।
- 18 बसु प० 10-11।
- 19 गाडगिल प० 40 1।
- 20 वही प० 43 4।
- 21 देखें गाडगिल।
- 22 देखें गाडगिल और व्यूकनन।

## ग्रामीण शिल्प उद्योग का हास

### प्राक् ब्रिटिश ग्रामीण शिल्प उद्योग

हम दाय चुके हैं कि ग्रामीण शिल्पकार उद्योग प्राक् ब्रिटिश आत्मनिभर ग्रामीण जयतन का औद्योगिक पक्ष था और उसस गाव की औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी। गावों की आर्थिक आत्मनिभरता का एक आधार स्तम्भ था ग्रामीण कृषि और दूसरा ग्रामीण शिल्प। यह भी नातव्य है कि गावों में श्रम विभाजन अभी आदिम स्थिति में था। कारीगर अपना कुछ समय घरेलू में लगाते थे और किसान खासकर उनकी जोरने, अपना कुछ समय मूत काल में जैसे औद्योगिक कामों में।<sup>1</sup>

गावों के आर्थिक मवस्था में एक विचित्र तथ्य यह था कि (गायद जुलाहा को छोड़कर बाकी) कारीगर गावों के सम्मिलित जनसमुदाय के नौकर जस थे। ग्रामीण जनसमुदाय की जार से गावों की जमीन का कुछ हिस्सा कारीगरों को देती के लिए दे दिया जाता था और उन्हें सालाना फल का भी कुछ जश मिलता था। लेकिन कारीगर स्वतन्त्र उत्पादकों की स्थिति में नहीं थे और अपनी सेवाओं और उत्पादनों का न तो आपस में जोर न किसानों के साथ ही विनिमय कर पाते थे।

कारीगर उद्योग में भी श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण बहुत कम था, जिनके फलस्वरूप कारीगरों का काय कौशल निम्नस्तरीय था। बाह्य प्रतिद्वन्द्विता का अभाव में कारीगरों को अपनी तकनीक और कायकुशलता को विकसित करने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन तो नहीं ही मिल सका। उद्योगों का स्थानीकरण भी नहीं हो सका।<sup>2</sup>

### ग्रामीण शिल्पकार उद्योग के हास के कारण

ब्रिटेन और अन्य देशों की मशीनों से बनी सस्ती वस्तुओं की भारत में जो बाढ़ आई, वह ग्रामीण शिल्प के हास का मूल कारण थी। रलवे और बसों की मदद से हर सामान आसानी से गावों में पहुँचाने लगा। रलवे और वाष्पचालित

जलयानों के कारण यूरोप के मशीन मालिकों के लिए भारतीय किसानों को उनके अपने ग्रामीण शिल्पकारों से भी कम दाम में सामान देना संभव हो गया। अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टता और वाणिज्य में आत्मपर्याप्त स्थायी अव्यवस्था की जगह ली और यह भारतीय कारीगरों के पराभव का मूल कारण था।<sup>1</sup> उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में और उसके बाद भी, स्वयं भारत में जो आधुनिक उद्योगों का विकास हुआ, उसके कारण भारतीय कारीगरी में विनाश की गति और तेज हुई। अब हम इस ह्रास की प्रक्रिया का निम्नलिखित सर्वेक्षण करेंगे।

### ग्रामीण हस्त शिल्प उद्योग के ह्रास की विपम प्रक्रिया

ग्रामीण हस्तशिल्प का ह्रास भारत के सब भागों में हुआ, लेकिन अनेकानेक सामाजिक, जातिगत और स्थानीय कारणों से यह ह्रास अनियमित रहा। बाजार में मशीन से बने सस्ते कपड़े की बाढ़ का हाथ करघा उद्योग पर बड़ा बुरा असर पड़ा और 1850 के बाद तबू से उसका विनाश शुरू हुआ। बाद में गांधी जन्म लेता और आल इंडिया स्पिनर एसोसिएशन जैसे मजदूरों और उनके प्रचारकत्वक काल के फलस्वरूप यह ह्रास कुछ हद तक रोक जा सका। लेकिन मिल मालिकों ने खट्टर के प्रचार का पूरा फायदा उठाया और मिल का बना खट्टर भी बाजार में आया जिसके कारण असली खट्टर की बिक्री को धक्का लगा।

फिर भी कारखाना में जा उत्पादन के मितव्ययी और लाभकर तरीके अपनाए जाते हैं उनके माध्यम प्रतियोगिता में हाथ से बस्ताई बुनाई का तरीका नहीं टिक पाता जिस तरह एक जमाने में यज्ञचालित कारखानों की होड़ के कारण यूरोप में हाथ करघा उद्योग का क्षति पहुँची वैसे ही भारत में भी हाथ करघा से काम करने वाला का दर्शी और विदेशी कारखाना में बन गस्ते माल की वजह से काफी नुकसान उठाना पड़ा।

ग्रामीण उत्पादन में जन्मे नये मशीन का उपयोग बटा, जैसे वस्त्रों के बढई की स्थिति पुरी हाती गई। लोह के हल और रिंग में रस निवालन वाले ताड़े के यंत्र जैसे नए तरीके में उस बहुत नुकसान हुआ। बकार बढईया में कुछ शहरों में फर्नीचर बनाने जैसे उद्योगों में लगे। जातिगत प्रगति का गांव के लोहार की स्थिति पर न्यूनतम प्रभाव पड़ा। मरम्मत के जो काम वह दहात में करता था वे खास घट नहीं। फिर भी कुछ लोहार शहरों की जाग गए और लोह के ढलाई घरों या इस तरह के अन्य उद्योगों और कारखानों में काम शुरू किया।<sup>2</sup>

गांवों के जातिगत स्थापत्य में सर्वाधिक क्षति ग्रामीण चमशोषकों को हुई। प्रायः ब्रिटिश भारत में उस गांव वालों में जातिगत की लागू मुफ्त मिल जाया करती थी। लेकिन भारत जब विश्वमंडी से मक्कन हो चुका था और यंत्र आधुनिक धमशोषक उद्योगों का विकास होने लगा था। अब ऐसे स्थानीय विदेशी उद्योगों के प्रतिनिधियों को चमशोषक में मत पहुँचा के मानिकों को अधिक फायदा था। शहरों के नए चमशोषक उद्योगों में कुछ पुराने चमशोषक

को अवश्य नाम मिला, लेकिन उनके बहुत बड़े अंश को खेतिहर मजदूर वनन को वाध्य होना पडा। सस्ते नीचिन रगा के आयात से गावा का रगरेज उद्योग चौपट हो गया। उनीमवी सदी के अत तक यह ग्रामीण रोजगार लगभग पूरी तरह नष्ट हो चुका था।<sup>18</sup> रागनी के लिए विगोमन तेल के अधिकाधिक प्रयोग के कारण गाव के तली की स्थिति घुरी होती गई। यो शहर म भोजन सबधी आवश्यकताआ के लिए तल निवालन का उद्योग विरामित हुआ, लेकिन इससे देहात के तेली के रोजगार को कोई नाम फायदा नही हुआ।

गाव के ऊपरी तबके के लोग धीरे धीरे विदेशी नामचीनी के बतन या शहरा के बहन हुए धातु उद्योग से निर्मित धातु के बतना का इस्तमाल करन लग। इसके चलते गाव के कुम्हार द्वारा बनाई गई चीजा का वाजार घटा। लेकिन चूनि गरीब तबके के लोग मिट्टी के बतन का ही इस्तमाल करत रहे इसलिए कुम्हार पूर्ण तरह बर्बाद नही हुए।<sup>19</sup> आर्थिक तौर पर निम्नहाय कुम्हार शहर के किसी उद्योग म तो लिया नही जा सक्ता था, इसलिए यह साधारणन खेतिहर मजदूर हो गया।

समय समय पर जो अकाल पडे उनका भी ग्रामीण हस्तशिल्प उद्योग के विनाश म योगदान रहा। अकाल के समय, गरीब कारीगर, खासकर जुलाह दूनरी तरह के काम द्वारा राजी कमान को खानार थे। लाहार जोर बढई को तो कभा कभी काम मिल भी जाता था जुलाहा या ऐसे ही अ य लागो को शारीरिक थम का सहारा लेना पडना था। मरुट की स्थिति समाप्त हो जाने पर फिर अपनी पुराना कायस्थता प्राप्त करना उनके लिए प्राय कठिन होता। 'वाहरी सहायता के अभाव मे बहुतेरे जुलाहो का दुभिन के समय अपना रोजगार छोडना पडता था। इनम से बहुत सार फिर अपन पुरान पेशे म वापस नहां लौट पाते थे और व साधारण मजदूरग की स्थिति मे रह जाते थे एव उही की मरुटा बढात थे।'<sup>20</sup>

कुत्र हस्तशिल्प उद्योग देहाता की दरिद्रता क कारण जीवित रह। जने, गाव क कुम्हार की चीजा की म्पत्त बनी रहा, कयो कि लोगो म अधिकाश इनने गरीब थे कि के धातु या तामचीनी के बतन नही खरीदते थे। इन तरह मिट्टी के बतन बनाने का रोजगार बन्ना रहा। लकिन गावो के उद्योग अब मूलत त्रिनामो मुख थे।

### वखेखुचे कारीगर और उनकी परिवर्तित स्थिति

देहात क कारीगरो के नाम की नड और पुरानी स्थिति म एक बडा फक था। पहले के ग्राम समुदाय के भत्य जसे थे। उह अपनी सेवाआ और सामगिया के लिए गाव की जार से मुफ्त जमीन मिलती थी और फसल के समय निश्चित अण राशि। लेकिन अब के मूलत द्रव्य के लिए काम करने थे और गाव टालो से उनके आर्थिक सबब जगापरी के थे। पुरान से नए तरीका मे सक्रमण की गति काफी धीमी थी और यह सक्रमण भी पूरा नही हुआ। लेकिन 'यह बात ध्यान दन की है कि लगभग हर जगह प्राय और अनुलाभ मे कारीगरो को हान वाली नियमित आमदनी की कीमत घटी।'<sup>21</sup>



ग्रामीण कारीगरों की स्थिति में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ कि धीरे-धीरे वे मजदूरी पर अधिकाधिक जाधित होने लगे। पुराने जमाने में गांव के जुलाहा गांव के लोग ही जरूरता के लिए बाड़े तयार करते थे, बाजार में बिक्री के लिए नहीं। बदली हुई परिस्थिति में जुलाहा (या तानी) स्थानीय या दूरस्थ मंडी में अपनी चीजा की खपत के लिए बनियों पर अधिबाधित निर्भर होने लगे। साथ ही, बढ़ती हुई प्रतियोगिता का यह परिणाम हुआ कि जितनी पूजा जुलाहों के पास थी, उमसे अधिक की उन्हें जरूरत पड़ी। इसलिए उन पर महाजनों का शिकजा बड़ा होता गया। अधिबाधित कारीगर अभी भी सिद्धांततः स्वतंत्र हैं और ऐसा समझा जाता है कि वे सूत खरीदते और कपड़ा बेचते हैं। लेकिन ऋणभार में लद होने के कारण हर कारीगर अपने महाजन से ही तिजारत करने का बाध्य है।<sup>1</sup> इस तरह किसानों की तरह कारीगर भी अधिबाधित महाजनों की गिरफ्त में आ गए।

गांवों में हस्तशिल्प उद्योग या नागरिक हस्तशिल्प के ह्रास का साथ जाधुनिक उद्योगों का समानर और समानुपाती उद्भव विकास नहीं हुआ। इसके कारणों का अन्वय (इस उद्योगों के विकास संबंधी अध्याय में) उल्लेख है।

लेकिन जाधुनिक उद्योगों में अपर्याप्त विकास की स्थिति में गांवों में बचे-बचे उद्योगों में, अपनी बढ़ती हुई नष्टशीलता के बावजूद देहात में लोगों की जरूरतों का पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आज भी भारत की औद्योगिक जावादी में गांवों के पुराने कारीगरों की ही महत्वाधिक है।<sup>13</sup>

### भारतीय हस्तशिल्प के नवनिर्माण के असफल प्रयास

गांवों में हस्तशिल्प उद्योगों के बदनशील विघटन की प्रक्रिया में रातों-रात के लिए और उन्हें पूर्ववर्ती शक्ति और प्रतिष्ठा प्रदान करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। इन उद्योगों को पुनर्जीवित करने में जो प्रयास हुए उनमें मद्रास और प्रभावशाली प्रयास वे थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस और गांधी जी ने किए। गांधी ने जाल इंडिया स्पिनम एम्प्लिएशन कम्पनी की। गांधी ने हाथ बंधा उद्योगों को पुनर्जीवित करना ही इसका उद्देश्य था। गांधी ने जाल इंडिया विनज इन्डस्ट्रीज एम्प्लिएशन भी उठाई। मद्रास बुटींग उद्योग का बोर्डे परिवर्तित रूप में पुनर्जीकरण इस कम्पनी का उद्देश्य था।

लेकिन इन प्रयासों का कोई विशिष्ट परिणाम नहीं निकला। नतीजा तो सामान्य की देगभक्ति और उनकी मानवीय भावनाओं का सहारा लेना पड़ा, न कि ग्रामीण उद्योगों की आर्थिक श्रेष्ठता और उमका लाभ का। उदाहरणार्थ गांधी ने लागों का प्रादी पहान के लिए उत्प्रेरित किया 'यद्यपि यह न तो दखन में नतीजा मुनायम और ललित ही जी और न इतनी मम्मी ही चिनगो चिनगी चम्बु।'<sup>14</sup> महात्मा गांधी का व्यक्तिगत प्रभाव दखन में पानक था और उन्होंने गांधी प्रचार के लिए प्रचुर धन राशि भी एकत्र कर ली थी। एवं अजोय जान यह है कि चिन

आधुनिक उद्योग घटा के कारण ग्रामीण उद्योगों का विनाश हुआ था उही उद्योग घटा से और आधुनिक उद्योगपतियों से यह धनराशि एकत्र हुई थी। लेकिन अपन प्रभाव और अतीव धनराशि के बावजूद गांधी ग्रामीण उद्योगों का कुछ विशेष कल्याण नहीं कर सके। उनके द्वारा दिए गए प्रयासों की असफलता का मूलभूत कारण यह था कि वे इतिहास की अप्रगामी प्रगति और आर्थिक विकास की शक्तियों के विरुद्ध थे।

आल इंडिया विलेज इंडस्ट्रीज एनालिसिस गांधी की पहलकदमी पर स्थापित हुआ। गांधी का मनीष के वन मामान से मुक्त करना और प्राकृष्ट पूजावादी हस्तशिल्प उद्योग (मृत या मृतप्राय) का पुनर्जीवन करना इस संगठन का एक उद्देश्य था। आर्थिक प्रतिगमन के इस कार्यक्रम ने इतिहास एवं जीवन के मूलभूत तथ्यों की उपेक्षा की। यह सामाजिक अस्तित्व के आधारभूत अटल नियमों के विरुद्ध था। इसमें ऐसे आर्थिक रूपा और तकनीकों को वापस लाने की कोशिश की जो ऐतिहासिक प्रगति की दौड़ में अप्रगामी आर्थिक रूपा और तकनीकों से बहुत पीछे छूट गए थे।

प्राकृष्ट पूजावादी हस्तशिल्प उद्योगों के विनाश के कारण इमोलिण ता नष्ट हुआ था कि आधुनिक मशीन आधारित उद्योगों से असम संघर्ष में यह टिक नहीं सका। मशीनी उद्योगों की शक्तिशीलता इस तथ्य में निहित थी कि इनके द्वारा निर्मित सामान हस्तशिल्प द्वारा निर्मित सामानों से मसते थे। उत्पादकों के विनियम पर आधारित समाज में उत्पादन के वे ही तत्व जीवित रह जाते हैं जो 'मूलतः परिश्रम में मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें, बाजार प्रमुख समाज में सस्त सामान हरदम महंगे सामान की अपेक्षा अधिक मात्रा में तयार हों और अधिक विकेंद्रित हों। आर्थिक चयन के लौह नियम के कारण हस्तशिल्प उद्योगों का ह्रास हुआ और मशीन उद्योगों का उद्भव एवं विवाम।

ऐतिहासिक विकास के साधारण क्रम में विनष्ट आर्थिक व्यवस्था का पुनर्जीवन करना संभव नहीं। आधुनिक उद्योगों ने बड़ी तेजी से प्राकृष्ट पूजावादी हस्तशिल्प को हटाकर अपने लिए जगह बना ली। पुरानी तकनीक और श्रम की निम्नस्तरीय उत्पादनशीलता पर आधारित हस्तशिल्प उद्योगों का पुनर्जीवन करने का गांधी और उनके जर्म अथवा तत्कालीन प्रयास अनिहार्य थे इसलिए उनकी असफलता निश्चित थी।

कताई और बुनाई के देहाती उद्योगों और कुछ अन्य उद्योगों के पुनर्जीवन का लगभग असफल उपाख्यान कई कारणों से संभव हुआ। 'कृषि की असंगठित दयनीय स्थिति, भूमि की जननकुत्ता जिसके कारण लगभग आधे साल की अवधि में अधिकांश लोग प्रकार रहते थे औद्योगिक विकास का अभाव इन सबके कारण हाथ से मूल बातों का हाथ करके पर कपड़ा बुनने और एस जैय उद्योगों को कुछ प्रथम अवश्य मिला, लेकिन यह अल्पकालीन उपचार था।

इस जाणिक और अत्यधिक सीमित प्रभाव वाले आर्थिक उपचार का अर्थ था

'भारतीय अथत्तन की तग और विवारग्रस्त स्थिति की निवृष्टतम वुराइयो को मान्यता प्रदान करना और इन वुराइयो को समाप्त करने के बदले उनके अनुकूलन का प्रयास करना।' 'पूजीवादी, जगत में हस्तशिल्प के कृत्रिम पुनर्जीवन का उपाय का कोई भविष्य नहीं है। खादी या हाथ से बने कपड़े कीमत की दृष्टि से मिल में बने कपड़ा से होड़ नहीं ले सकते, और इस तरह गरीब लोगों की पहुँच के बाहर है।<sup>16</sup> वस्तुतः यह कृत्रिम पुनर्जीवन, क्षणिक और सीमित ही सही, विडला और बजाज जैसे उद्योगपतियों की मदद से हुआ।\* इसे उन उच्चवर्गीय लोगों की भी मदद मिली जो इन उद्योगों के सामान खरीद कर आर्थिक त्याग कर रहे थे और समझते थे कि उनके त्याग का कारण मतप्राय हस्तशिल्प जिंदा होगा, अंग्रेजों की अव्यवस्था पर चोट पहुँचेगी और भारतीय साधारण जन की गरीबी दूर होगी। यह उम्मीद पूरी नहीं हो सकी क्योंकि यह कार्यक्रम नई जातिगत ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक शक्तियों के प्रतिकूल था। गांधी ने भी, जो गुरु में आधुनिक उद्योगों के अदम्य विरोधी थे अपने कार्यक्रम की असफलता के बाद उत्पादन के सीमित और अनुवर्धित शनदद मशीनीकरण का समर्थन किया।

### ग्रामीण उद्योग के ह्रास के परिणाम

गाँवों की अव्यवस्था कृषि और उद्योग के स्थानीय समर्थन पर निर्भर थी। ग्रामीण उद्योग के ह्रास ने इस समर्थन को नुकसान पहुँचा। गाँवों का औद्योगिक सामग्री के लिए शहरों पर आश्रित होना पड़ा। गाँवों जब पहले जसा संपूर्ण आर्थिक इकाई नहीं रह गया, बरन राष्ट्र और विश्व की अव्यवस्था का अनुसंगी हुआ।

नए भूमि सबंधी कानूनों के प्रत्येक विधान पर वसूली की जलज इकाई थी। लेकिन पूजीवादी भूमिसबंधों और नए भूमि कानूनों से ही गाँवों की आत्मनिर्भरता समाप्त नहीं होती। ग्रामीण हस्तशिल्प उद्योग कृषक अथत्तन का औद्योगिक आग्रह स्तम्भ था, और ग्रामीण आत्मनिर्भरता की समाप्ति के लिए इसका विनाश भी आवश्यक था। इस तरह नए भूमि सबंधों की स्थापना और ग्रामीण हस्तशिल्प उद्योग के विनाश की सम्मिलित क्रिया ने आत्मनिर्भर गाँवों की जड़ हिला दी।

\* कुछ मामलों में राष्ट्रीय और समाजवादी नेता के अनुसार यह भारतीय मित मातृका और जमींदारों की चान्दनी थी कि उन्होंने खेड़ और कुटीर उद्योगों को मराने की। ये मित मातृका और जमातार नहों चाहते थे कि कृषक की आवाज़ों का आर्थिक अस्तित्व जमींदारों मातृकारों और महाजन के विरुद्ध संघर्ष का रूप ले। गाँवों का गरीबी का सामाजिक कारण थे ऊँचा भूमिगत ऋण गोपण अभाव। लेकिन संपन्न लोगों ने गाँवों का आवाज़ों का ध्यान दूसरी तरफ़ आकर्षित करने की कोशिश की जिससे वे अपना गरीबी का बलिदान समाधान चाहते रहे। भारत में जमातार महाजन और मातृकार वर्गों में उद्योगपतियों का बड़ पतित आर्थिक संघर्ष था।

लगातार बढ़ती हुई गरीबी के कारण जतिनाधिक कारीगर अपना पुश्तैनी कारोबार छोड़ने लगे। इनमें कुछ शहरों में गेए और तेल, चीनी, चमड़ा, फर्नीचर आदि विभिन्न उद्योगों में लगे या कल कारखानों में मजदूरी करने लगे। जिन लोगों के पास कुछ पैसा था, उन्होंने जमीन खरीद ली। जो साधनहीन थे उनमें से कुछ खेत मजदूर हो गए और कुछ दरिद्र भिखारियों में। कृषि पर आश्रित लोगों की सख्या बढ़ी।

'लाखों करोड़ों बर्बाद कारीगरों, जुलाहा सूत कातने वालों कुम्हारों चमकारों, लाहा गलाने वालों वटइया आदि के पास, चाहे वे शहरों में हों या देहातों के, सिना इसके कोई चारा नहीं था कि वे खेती पर निर्भर लोगों की तादाद बढ़ावें। भारत में पहले कृषि और उद्योग का संयुक्त, समन्वित रूप विद्यमान था लेकिन अब वह ब्रिटिश पूंजीवाद का (कृषि प्रधान) उपनिवेश मान रह गया।'<sup>17</sup> इसका कारण यह था कि आधुनिक उद्योगों का बर्बाद कारीगरों का काम दे पाते, उनका विकास उस तेजी से नहीं हुआ जिस तेजी से पुराने उद्योगों की बर्बादी हुई। पुराने कारीगरों में कुछ के बच्चों-बच्चों में थोड़ी सी शिक्षा प्राप्त कर शिक्षक या किरानी भी बन। फिर भी, जसा पहले कहा जा चुका है भारत में औद्योगिक विस्तार की धीमी गति के कारण, अपनी घटती हुई जनसख्या के बावजूद, गांव के कारीगर देश की समस्त औद्योगिक आबादी का बहुत बड़ा भाग थे।

आत्मनिर्भर गांव राष्ट्रीय चेतना और सम्मिलित राष्ट्रीय जीवन के विकास के रास्ते में बृहत्तम बाधा थी। हस्तशिल्प उद्योग के सतत विघटन ने आत्मनिर्भर गांवों की आर्थिक नींव कमजोर कर इस राष्ट्रीय भाव की परिपक्वता के लिए मार्ग प्रशस्त किया।

'हजारों उद्यमी, निर्दोष सामाजिक संगठनों का विघटन, दुख के महासागर में उनका विलयन इन संगठनों के विभिन्न सदस्यों का जीविका विहीन होना मानवीय भावनाओं के लिए ये सब बालों बड़ी दुःखावह हैं। लेकिन हम यह नहीं खूलना चाहिए कि ये रमणीक बाध्यमय, देहाती जनसमुदाय प्राच्य निरकुशता के आधार थे और वे मानव मन को सर्वोत्तम परिधि में संकुचित किए रहे एवं उसे अधविश्वासा का दुग बनाए रहे पुराने कायद-कानून में बांधे रह और ऐतिहासिक प्रगति की गरिमा और शक्ति से शाय राना।'<sup>18</sup>

ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो भारतीय लोक की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकसित होने में पहले आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समाप्त होना ही था। इसी तरह समस्त भारतीय जन जीवन राष्ट्र के रूप में मजबूत हो सके और ऐतिहासिक दृष्टि से उच्चतर सामाजिक राजनीतिक आर्थिक और सांस्कृतिक अस्तित्व का विघटन होना भी आवश्यक था।

जा करीगर गांव छोड़कर शहरों में गए और मिला में मजदूर बन, वे मजदूर वर्ग के जग हुए और मजदूर वर्ग स्थानीय और प्रांतीय सीमाओं से परे राष्ट्रीय स्तर पर संगठित होने लगे। इस तरह देहातों के पुराने कारीगरों में

नई बृहत्तर चेतना और राष्ट्रीय दृष्टिकोण का उद्भव हुआ।

कारीगरों के उन वर्गों को भी वर्गों की सामना करना पड़ा जिन्होंने जमीन खरीदी और खेती शुरू की थी और उनको भी जा माघना के अभाव में खेत मजदूरी करने लगे थे। उनमें भी नई बृहत्तर चेतना का विकास हुआ। कृषि के रूपान्तरण के कारण हालातें बदल रही थीं और गावा की आत्मनिर्भरता समाप्त प्राय हो चुकी थी। इस नई परिस्थिति में गावा के विभिन्न वर्ग अब वस्तुतः ऐसे आर्थिक वर्गों से संपृक्त थे जो भारतीय राष्ट्र के अविच्छिन्न अंग थे। सारे भारत में अब एक ही जैसे भूमि-कानून लागू थे, इसलिए सारे भारत के किसानों और खेत मजदूरों के म्याथ अब लगभग एक जैसे थे। फलस्वरूप इनमें भी बृहत्तर वर्ग चेतना और राष्ट्रीय भावना का उदय हुआ और कालक्रम से वे अखिल भारतीय किसान सभा जैसे संगठनों में शामिल हुए।

जो कारीगर अपने पुराने रोजगारों में लगे रहे वे भी प्रायः ब्रिटिश युग के कारीगरों से भिन्न थे। पहले ये कारीगर गाव के भृत्य जैसे थे और गाव की जरूरतों को पूरा करना उनका धर्म था। अब वे बाजार के लिए सामग्री तैयार करने लगे। इस तरह सार-ससार के पैमाने पर कीमतों का जो संचरण होता था, उसका उन पर असर पड़ना शुरू हुआ। अपनी सुरक्षा के लिए उन्हें भी राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता हुई और जाल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन जैसी संस्थाओं की स्थापना हुई। इस तरह ग्रामीण कारीगरों में भी बृहत्तर चेतना और दृष्टि का विकास हुआ। इन लोगों में पुराने आत्मनिर्भर गावों के कारीगरों की अपेक्षा अधिक पहल शक्ति और व्यक्तित्व का भाव था।

ग्रामीण हस्तशिल्प के ह्रास का आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के विनाश में अपना योगदान रहा और इस विनाश के ऐतिहासिक दृष्टि से प्रगतिशील परिणामों की हमें चर्चा की।

## संदर्भ

- 1 देखें गाडगिन ।
- 2 देखें गाडगिन ब्यूकनन वाडिया एंड मर्सेट ।
- 3 देखें गाडगिन ब्यूकनन ।
- 4 ब्यूकनन पृ 130 ।
- 5 वही पृ 77-78 ।
- 6 देखें गाडगिन ।
- 7 देखें ब्यूकनन गाडगिन ।
- 8 देखें गाडगिन ।
- 9 वही ।
- 10 रिपान् थॉमस ए फोर्ब्स वामीशन 1896 ।

- 11 गाडगिल प० 175 ।
- 12 ब्युकनन प० 77 ।
- 13 गाडगिल प० 163 ।
- 14 गांधी हरिजन 19 नवंबर 1938 ।
- 15 आर० पी० दत्त प० 515 ।
- 16 वही प० 515 ।
- 17 आर० पी० दत्त, प० 129 ।
- 18 काल माक्स प० 20-21 ।

## भारत में आधुनिक उद्योगों का उद्भव और विकास

### भारत में आधुनिक उद्योगों का विकास

देश के राष्ट्रीय अर्थतंत्र के समेकन में आधुनिक मशीनी उद्योगों की स्थापना का बहुत बड़ा योगदान रहा। इससे ऐसी सामाजिक शक्तियों का भी जन्म हुआ जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय राष्ट्रवाद का अनुप्रेरित अनुप्राणित किया। अनकानूक कारणों से भारत का औद्योगिक विकास अपर्याप्त और एकांगी रहा। फिर भी इससे राष्ट्रीय प्रगति को मदद मिली। उदाहरणार्थ आधुनिक उद्योगों के चलते आधुनिक औद्योगिक नगरों का जन्म हुआ जो सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक क्रियाकलाप के बड़े जीवन्त रंगमंच सिद्ध हुए और जहाँ सारे प्रगतिशील आंदोलनों का जन्म हुआ। आधुनिक उद्योगों के कारण ही बुजुर्गों और सबहारा इन दो नए सामाजिक वर्गों का उदय हुआ। इन वर्गों की विशिष्ट स्थिति का आधुनिक समाज के विकास पर निर्णायक प्रभाव पड़ा है।

बुजुर्गों और सबहारा आधुनिक पूँजीवादी समाज के आधारभूत वर्ग हैं। प्रतिद्वंद्विता और माल के उत्पादन पर आधारित पूँजीवादी अर्थतंत्र के विकास के कारण कारीगरों जैसे धंदे उत्पादकों का मध्यवर्ती वर्ग जो अपने औद्योगिक प्रतिद्वंद्वियों से होठ तन में अक्षम है समाज के मजदूर होने लगता है और अंततः मजदूर वर्ग में परिणत हो जाता है। देहाना में भी पूँजीवादी जातिपरिवर्तन में वर्धनशील विपन्नता के कारण किसान मालिकों का मध्यवर्ती वर्ग साहूकारों, वनियाँ और अन्य पूँजीपतियों का अपनी जमीन उबन को बाँधे होता है और उनमें से अधिकांश भूमिहीन मजदूरों या श्रमिकों सबहारा की श्रेणी में पहुँच जाते हैं।

इस तरह मध्यवर्ती सामाजिक श्रेणियाँ अनस्थिर और विघटनशील हैं। सबहारा और बुजुर्गों का मध्य पूँजीवादी समाज का मूलभूत संघर्ष है और यह संघर्ष ही इस समाज को गति देता है। इस वर्ग संघर्ष में मजदूरों का लक्ष्य है समाजवाद। इस समाज व्यवस्था में मजदूरों पर आघातित श्रम और उत्पादन के साधनों पर निजी स्वतंत्रता के लिए कोई जगह नहीं है। यह व्यवस्था पूँजीवाद के विपरीत उत्पादन के साधनों के सामा

जिन स्वामित्व और कमबरो के मुक्त सहयोगी श्रम के सिद्धांत पर आधारित है। भारतीय मजदूर वर्ग के लिए राष्ट्रीय स्वातंत्र्य समाजवादी मुक्ति संग्राम के रास्ते में एक मील-स्तंभ भर था।

### भारत में आधुनिक उद्योगों के विकास का संक्षिप्त इतिहास

अब हम ब्रिटिश शासन काल में आधुनिक भारतीय उद्योग के उदभव और विस्तार, उसके विकास की प्रवृत्ति और सीमाओं तथा उसकी सामाजिक संरचना का सर्वेक्षण करेंगे। उन्नीसवीं सदी के मध्य में रेलवे की स्थापना से आधुनिक उद्योगों के विकास के लिए जरूरी एक बहुत बड़ी शक्ति पूरी हो गई। रेलवे पर अपनी प्रसिद्ध टिप्पणी में लार्ड डलहौजी ने रेलवे के निर्माण की एक प्रमुख अभिप्रेरणा का विवरण दिया है

इनकी स्थापना से भारत को जो व्यावसायिक और सामाजिक लाभ हाने उनकी कल्पना नहीं की जा सकती इंग्लैंड में भारतीय रुई की मांग बढ़ रही है, दूर के मैदानों से बदरगाहा तक इसे ले जाने के समुचित साधन उपलब्ध हैं तो पर्याप्त परिमाण में अच्छे किस्म की रुई उगाई जा सकती है। हमने यह भी देखा है कि व्यापार संबंधी सुविधाओं में थोड़ी सी भी वृद्धि होने पर भारत के दूरस्थ बाजारों में भी यूरोप के बने सामानों की मांग बढ़ रही है। धरती के इस छोर पर हमारे लिए जो बाजार बन रहे हैं, उनके भावी विस्तार और मभावित मूल्य को आकरना सूक्ष्म दिव्य दृष्टि वाले विद्वानों के लिए भी आसान नहीं है।<sup>1</sup>

इस तरह ब्रिटिश उद्योगों की कच्चे माल और बाजार संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना रेलवे के निर्माण का एक अत्यंत प्रयोजन था। इस निर्माण कार्य से ब्रिटिश पूंजी की लागत और ब्रिटेन के बढ़ते हुए अभियान उद्योग में बने पदार्थों के निर्यात के लिए क्षेत्र विस्तार भी हुआ।

रेलवे की स्थापना और भारतीय साहूकार वर्ग के पास पर्याप्त वचन, जिसने मूल पूंजी का काम किया, इन दो कारणों से भारतीय उद्योगपति भी नए उद्योगों की स्थापना कर सके। विकास की इस प्रक्रिया में रेलवे की भूमिका के बारे में काल मार्क्स ने लिखा है

जिस देश में लोहा और कायला प्राप्त है वहां के परिवहन यंत्र में मशीनों का इस्तेमाल शुरू हो जाने के बाद उस देश द्वारा खुद मशीनों के निर्माण को नहीं रोका जा सकता। रेलवे की तात्क्षणिक और मदा वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन औद्योगिक प्रक्रियाओं की जरूरत है उन्हें लाए बिना किसी भी बड़े देश में रेलवे का सुचारु संचालन संभव नहीं। उद्योग की जिन शाखाओं का रेलवे से सीधा संबंध है उनमें भी मशीनरी के इस्तेमाल की जरूरत पड़ती है। इसलिए रेलवे का प्रादुर्भाव भारत में आधुनिक उद्योगों के आगमन का पूर्वसूचक है।<sup>2</sup>



उन्नीसवीं सदी के मध्य तक भारत में आधुनिक उद्योग (जैसे नील, चाय, काफी के क्षेत्र में) स्थापित करने में अंग्रेज लोग आगे रहे। 1850 और 1855 के बीच सूती कपड़ों के पहले कारखाना, कुछ जूट की मिलों और कुछ कायला खानों की शुरुआत हुई। 1879 में भारत में 56 सूती कपड़ों के कारखाने थे। 1882 में जूट मिलों की संख्या 20 हो गई थी, इनमें अधिकांश यूरोपीय मालिकों के हाथ में थी। 1880 में देश में कोयला खदानों की संख्या 56 थी। 1880 के आसपास हिंदुस्तान में यही तीन प्रमुख आधुनिक उद्योग थे।

1880 और 1895 के बीच कोई नया महत्वपूर्ण उद्योग कायम नहीं हुआ लेकिन पुराने उद्योगों में काफी तरक्की की। सूती कपड़ों का उद्योग विशेष तजी से बढ़ा। 1894-95 में काटन मिला की संख्या 144 जूट मिलों की संख्या 29 और कोयला खदानों की संख्या 123 थी।<sup>3</sup>

रानाडे जैसे राष्ट्रवादी जनशास्त्री इस दौर में हुए भारतीय उद्योग के मुनियमित विस्तार से काफी प्रभावित थे और उन्होंने भारत के लिए महान औद्योगिक भविष्य का सपना देखा। रानाडे ने कहा भारत अब उस रास्ते पर चल चुका है, जिस पर अगर वह उसी जाति से चलता रहा जिससे अभी तक यहां के पूंजीपति अभिप्रेरित हैं तो वह अवश्य ही औद्योगिक मुक्ति प्राप्त कर सकेगा।<sup>4</sup>

लेकिन 1895 और 1905 के बीच भारतीय उद्योगों का संवर्धन सूती उद्योग के विकास की गति काफी धीमी हो गई। इसके दो मूल कारण थे। दो दुर्भिक्षों के चलते कृषक जावादी की आर्थिक हालत काफी खराब हो गई थी। फिर 1902 में अमरीकी सट्टवाजी के कारण रूढ़ि की कीमत बहुत बढ़ गई। इन दोनों बातों का भारत के मिल उद्योग पर बहुत बुरा असर पड़ा। ऐसी प्रतिबन्धित परिस्थिति के बावजूद भारतीय उद्योगों में इन वर्षों में कुछ मद्धम गति से ही सही लेकिन तरक्की की।

स्वदेशी आन्दोलन से भी जिन मुख्यतः इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1905 में शुरु किया, भारतीय उद्योगों को मदद मिली। 1913-14 में काटन मिला की संख्या बढ़कर 264 हो गई थी और जूट मिला की 64। कायला उद्योग लगातार बढ़ता ही रहा था, और 1914 में कुल 1,51,376 टोंन कायला खदानों में काम कर रहे थे। यह उद्योग मूलतः जावागमन के माध्यम से आरंभ उद्योग की प्रगति के कारण विकसित हुआ।

1890 और 1914 के बीच पटालियम, मैंगनीज, अयस्क और गारा जैसे नए उद्योगों का उदभव हुआ और चावल और टिंजर की भी कुछ मिलें खुलीं। इसके अतिरिक्त अभियंत्रण और रेलवे के कारखाने एवं साहजिक और पीतल के ढाँड घर भी खुले।<sup>5</sup> 1890 और 1914 के बीच हुए औद्योगिक विस्तार का डी० एच० ब्युबैन ने निम्नांकित विवरण प्रस्तुत किया है

1890 में विश्वयुद्ध तक प्रत्येक क्षेत्र में अतिरिक्त प्रगति हुई। सूती तराजू तराजू की संख्या दुगुनी हो गई गतिमान गतिमान कारण वरध चौगुन हो गए,

जूट के करघे साढ़े चार गुना बढ़े, कोयला उत्पादन का परिमाण 6 गुना बढ़ा <sup>6</sup>

अविरल प्रगति के बावजूद 1914 में भारतीय औद्योगिक विकास का स्तर काफी निम्न था। केवल वाटन और जूट उद्योग में ही कुछ विशेष प्रगति हुई थी। भारी उद्योगों का लगभग बिल्कुल अभाव था। अभियंत्रण के नाम पर केवल कुछ मरम्मत की दुकानें थी, तासकर रेलवे के लिए, 1914 की लड़ाई के पहले लाहा और इस्पात उद्योग की मामूली सी शुरुआत भर हुई थी मशीनों का उत्पादन नहीं था।<sup>7</sup>

भारत का औद्योगिक विकास तभी से नहीं हुआ, इसके अनेक कारण थे। तीव्र विकास के लिए नवजात भारतीय उद्योग को सरकारी सुरक्षा की आवश्यकता थी, जिससे वह ब्रिटन, जर्मनी आदि देशों के समर्थ और सुस्थापित उद्योगों से लोहा ले सके। मगर भारत की ब्रिटिश सरकार ने भारतीय उद्योगों को ऐसी कोई सुरक्षा नहीं दी और न उसे कोई अन्य ठोस मदद ही दी। ब्रिटिश लेखकों प्रचारकों ने भी इस भारत के तीव्र औद्योगिक विकास का एक प्रमुख अवरोधक माना है।

भारत के औद्योगिक विकास में हमारी काय तालिका जतीत में सबकुछ बहुत श्रेयस्कर नहीं रही है, यह तो केवल युद्ध की आवश्यकताओं के दबाव में सरकार को युद्ध भारतीय उद्योगों के प्रति निस्पृहता की संभवतः ईर्ष्या की भी, अपनी पुरानी भावना का परित्याग करना पड़ा।<sup>8</sup>

1921 के वार्षिक सरकारी प्रतिवेदन में यह माना गया कि भारत सरकार पर ब्रिटिश 'आर्थिक स्वार्थों' के दबाव के कारण भारतीय उद्योगों को सरकारी सहायता और सुरक्षा नहीं मिल सकी। रिपोर्ट में कहा गया है, युद्ध के कुछ दिनों पहले पायनियर कारखाना और सरकारी अनुष्ठानों के द्वारा भारतीय उद्योगों का सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करने के प्रयास को लंदन की सरकार ने पूरी तरह रोक दिया।<sup>9</sup>

क्षिप्र औद्योगिक विकास की राह में एक और बड़ी बाधा थी, वह यह कि पर्याप्त मर्यादा में टेक्नीशियन उपलब्ध नहीं थे। तकनीकी शिक्षा के साधन भी बहुत कम थे।

धीमे से भी अधिक वर्षों से तकनीकी और औद्योगिक शिक्षा का सवाल सरकार और जनता के सामने रहा है। शायद ही कोई ऐसा विषय हो जिस पर इतना अधिक लिखा और कहा गया हो और जिस पर इतना कम काम हुआ हो।<sup>10</sup>

जिन अन्य कारणों से भारतीय उद्योगों का विकास पर्याप्त और एकांगी रहा, हम उनका उल्लेख औद्योगिक विकास के सर्वेक्षण के अंत में करेंगे।

1914-18 के युद्ध के समय विदेशी सामानों के आयात में काफी कमी हुई साथ ही युद्ध संबंधी उपकरणों और सामग्रियों के उत्पादन की तात्कालिक आवश्यकता भी आ खड़ी हुई। इन कारणों से इस अवधि में भारतीय उद्योगों का विकास हुआ। सरकार ने उद्योगीकरण की नीति अपनाई। 1915 में वायसराय

नाड हाडिंग ने इस विषय में कहा

ज्यो ज्यो यह स्पष्ट होगा कि बड़े राष्ट्रों का राजनीतिक भविष्य उनकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर है वैसे वैसे विदेशी मंडी के लिए उनकी पारस्परिक होड़ बढ़ेगी। वैसे हालत में अगर भारत को विदेशों में निर्मित सामान के लिए क्षेपण भूमि नहीं बनना है तो स्पष्टतः लड़ाई के बाद, भारत की औद्योगिक सम्भावनाओं को विकसित करने की निश्चित और सचेत नीति अपनानी होगी। इस प्रश्न पर भारतीय जनता पूर्णतः एकमत है और उसकी राय को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता

औद्योगिक दश के रूप में यथासंभव विकसित होने के लिए लड़ाई के बाद सरकार से अधिकतम सहायता की मांग करना भारत अपना हक मानेगा।<sup>1</sup> इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 1916 में इंडस्ट्रियल कमीशन की स्थापना हुई।

1918 में प्रकाशित माटेगु चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में कहा गया है

प्रत्येक दृष्टिकोण से, न केवल भारत के आर्थिक स्थय के लिए वरन जनसाधारण की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भी औद्योगिक विकास की चरम आवश्यकता है। आर्थिक और नैतिक दानों दृष्टियों से साम्राज्यवादी स्वार्थों से भी यही अपेक्षा है कि भारत के प्राकृतिक साधनों का समुचित उपयोग हो। औद्योगिक भारत से साम्राज्य की सत्ता का जो शक्ति मिलेगी उसका अनुमान करना कठिन है।<sup>1</sup>

विदेशी प्रतियोगिताओं के अभाव में युद्ध के समय सूती और जूट उद्योगों का काफी विकास हुआ। इस्पात का उत्पादन 1913 में केवल 91,000 टन था, लेकिन 1918 में 1,24,000 टन।

धातु और मशीन उद्योगों जैसे आधारमूलक उद्योगों का अस्तित्व किसी भी देश के तीव्र औद्योगिक विकास की आवश्यक शर्त है। ऐसे उद्योग भारत में लगभग नहीं थे बराबर थे, इसलिए युद्धकाल में भी भारत का औद्योगिक विकास सीमित ही रहा। 'आधारमूलक' अभियान उद्योग और विशाल रासायनिक उद्योग भारतीय उद्योगतंत्र के दुर्बलतम अंग थे।<sup>13</sup> चूंकि देश के उद्योगों के लिए आवश्यक मशीन रसायन रंग जैसे पदार्थों के उत्पादन की व्यवस्था नहीं थी इसलिए युद्धकाल में भी भारतीय उद्योगों का उतना विकास नहीं हो सका जितना अपेक्षा हुआ होना। 1911 में जे० एन० टाटा द्वारा स्थापित 'तोहा' और इस्पात उद्योग भारतीय उद्योग की आवश्यकताओं की आंशिक पूर्ति ही कर पाता था।

युद्धकाल में पोत परिवहन युद्ध संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति में व्यस्त रहा, इसलिए बाहर से चीजों का आयात काफी घट गया। फिर भी इन दिनों भारतीय उद्योगों का जितना विस्तार होना चाहिए उनका नहीं हुआ। ऊपर जिन कारणों की चर्चा है उनके अलावा इस तथ्य के जोर भी जना कारण हैं। लोकनाथन 1 डम विषय में लिखा है

देशी पूजा, औद्योगिक नेतृत्व और तकनीकी नैपुण्य का अभाव तो था ही, उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल और साधनों की आपूर्ति में भी काफी कमी थी। गंधक, तावा, जस्ता, रागा और खर की खास कमी थी। कोयला प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था, लेकिन उसका समरम विनयन नहीं हुआ था। यह मुख्यतः बिहार और बंगाल में पाया जाता था, देश के सारे उत्पादन का 10% बिहार-बंगाल की खानों से ही आता था। फिर, भारत में जिस विशिष्ट औद्योगिक नेतृत्व, मैनेजिंग एजेंसी (प्रबंधन भिक्तार्ता) प्रथा का विकास हुआ, उसका यह हानिकर असर पड़ा कि नए और सभवतः अलाभकर उद्योगों में पूजा लगाने की चाह (और हिम्मत) खतम हो गई। मिल की बनी चीजों और मशीनों के आयात एवं व्यापार और बीमा से प्रबंध अभिक्तार्ताओं को बर्मीशन के रूप में काफी फायदा हो रहा था। लेकिन सबसे बड़ा एक और तथ्य था, वह यह कि अहस्तक्षेप की नीति भारत जैसे गरीब देश के लिए काफी नहीं थी, इसका आर्थिक विकास सुविचारित राजकीय नीति द्वारा ही सभव था

इस तरह पिछड़ी लड़ाई ने कुछ जमे हुए उद्योगों को कुछ थोड़ा अस्थायी लाभ पहुंचाने के अलावा देश के समुचित औद्योगिक विकास में कोई मदद नहीं दी।<sup>14</sup>

इंडस्ट्रियल बर्मीशन की मुख्य अनुशंसा यह थी कि सरकार देश के औद्योगिक विकास में क्रियाशील रुचि ले। इस विकास में मदद देने के लिए सरकार को कुछ आवश्यक कार्य करन हाने। उदारहणार्थ उसे बड़ी तादाद में बज्ञानिका और तकनीशियनों की बहाली करनी होगी, जो नए उद्योगों की स्थापना और स्थापित उद्योगों के समुचित विकास में उद्योगपतियों का मार्गदर्शन कर सकें। लेकिन बर्मीशन की इस अत्यंत महत्वपूर्ण शिफारिश पर कोई कारवाई नहीं हुई।<sup>15</sup>

1919 के रिफार्म्स ऐक्ट (सुधार विधेयक) के अनुसार उद्योग प्रादेशिक विषय हो गया। लेकिन विभिन्न प्रात आर्थिक और तकनीकी दृष्टि से इतने अक्षम थे कि औद्योगिक विकास की दिशा में वे विशेष सहायक नहीं हो सकते थे। डॉ० एच० ब्युकानेन ने इस विषय में कहा है

1919 के साविधानिक सुधारों के बाद उद्योगों में घड़े चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति जिम्मेवार सरकार के हाथ में आ गए। दुर्भाग्यवश उपलब्ध धनराशि नाकाफी थी, इसलिए महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाए जा सके। उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए दूरगामी समर्पित सरकारी नीतियां भी आवश्यकता हाती हैं। ऐसी नीतियां की जा कच्चे माल, उत्पादन के साधन और बाजार आदि सारी बातों का ध्यान रखें उद्योगों के विकास के लिए देश में जिन प्रादेशिक कार्यालयों की स्थापना हुई है उनसे किसी प्रकार के लाभ की संभावना कम है।<sup>16</sup>

1922 में फिन्बल बर्मीशन (राजस्व सवली आयाग) ने शिफारिश की कि

सरकार उद्योगों को विवेकपूर्ण, सोची समझी हुई सुरक्षा और सहायता प्रदान करने की नीति अपनावे। सरकार ने इस सिफारिश पर 1923 में अमल करना शुरू किया और नई नीति के तहत इसी साल टैरिफ बोर्ड (सीमा शुल्क विषयक पपद) की स्थापना हुई। 1924 में अभी हाल ही में स्थापित टाटा के लोहे और इस्पात उद्योग को सरकारी अनुदान मिला और 33½% तक सुरक्षा की गारंटी भी मिली। इसके अतिरिक्त मूल माचिस चीनी और कुछ अन्य उद्योगों को भी भिन्न मात्राओं में सुरक्षा प्रदान की गई। औद्योगिक विकास की मदद के लिए वाद में मैनूएल ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल इंटेलिजेंस एंड रिसर्च (औद्योगिक ज्ञान और अनुसंधान का केंद्रीय दफ्तर) की स्थापना हुई।

लेकिन इन सबके बावजूद भारतीय उद्योगों के स्वतंत्र त्वरित और प्रचुर विकास की बुनियादी शर्त पूरी नहीं हुई, अर्थात् भारी, विशाल उद्योगों की स्थापना नहीं हो सकी। प्लाट इकानमी फार इंडिया (1936) में एम० विश्वेश्वरैया ने लिखा है विशाल उद्योग आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है लेकिन उसके विकास पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है।<sup>17</sup> टाटा आयरन एंड स्टील उद्योग को दिया गया अनुदान 1927 में वापस ले लिया गया।

1927 के बाद भारतीय सीमा-शुल्क साम्राज्यवादी पूर्वाधिकार के सिद्धांत द्वारा नियंत्रित हुआ। इससे गर साम्राज्यीय और भारतीय मंडी में भी भारतीय उत्पादन की तुलना में ब्रिटिश उत्पादन का लाभ हुआ।<sup>18</sup> 1932 का जोटावा समझौता साम्राज्यवादी पूर्वाधिकार के सिद्धांत पर ही आधारित था। भारत में इसका बड़ा विरोध हुआ। फिर भी इस पर अमल हुआ। क्रेट मिशेल ने लिखा है 'तीसरे दशक के प्रारंभिक दिनों में जारी किए गए सीमाशुल्क के तारे में कहा गया था कि यह भारतीय उद्योगीकरण को बढ़ावा देगा। लेकिन इस व्यवस्था को एक ऐसी व्यवस्था में परिणत कर दिया गया जिसने भारतीय मंडी में ब्रिटिश उद्योगों की मदद की। इसके बदले भारत को अच्छे माल और अधि औद्योगिक सामान की ब्रिटेन में अच्छे दर पर बचने की सुविधा मिली। इस तरह स्पष्टतः 1914 के पहले की स्थिति फिर वापस आ गई।'<sup>19</sup>

1929-33 के आर्थिक संकट का भारतीय कृषक वर्ग पर गहरा ज़रूर पड़ा। उनके पास जा साना था उसे बचने के लिए वे बाध्य हुए।<sup>20</sup> 1936 और 1937 में भारतीय जनता की स्वर्ण राशि में दुबारा कमी हुई। इस तरह औद्योगिक सामान खरीदने की उनकी शक्ति घटी और इन बातों का औद्योगिक विकास की गति पर अनिवायत तुरा प्रभाव पड़ा।

स्वर्ण के निगमन के बारे में क्रेट मिशेल ने लिखा है, 'भारतीय कृषक वर्ग की बहुत दिनों की मर्चित स्वर्ण राशि के निगमन में भारतीय मंडी और अधिन चिपकन हुई और इन तरह भारतीय उद्योगों का और अधिन लाम हुआ।'<sup>21</sup>

उन कठिनाइयों के बावजूद जाधुनिक उद्योगों को महायुद्ध के बीच में वर्षों में लगातार विकसित होना रहा। इस अवधि में कुछ प्रमुख उद्योगों में

जो प्रगति हुई वह नीचे दी गई तालिका से स्पष्ट है

		1922-23	1938-39
सीमेंट	टन	1,93 000	1,170 000
कोयला	मिलियन टन	19	28 3
सूती सामान	मिलियन गज	1,713 5	4 269 3
जूट	मिलियन गज	1,187 5	1,174
सलाई	ग्रॉम डिब्बे (1934-35)	1,65,00,000	2 11,00,000
कागज	टन	23,576	59,198
कच्चा लोहा	टन	4,55,000	15,75 500
चीनी	टन	84 000	10 40 048
सल्फ्यूरिक एसिड	हडरवेट	5 29 637	6 07 000
इस्पात पिंड	टन	1 31 000	9 77 400

(वाडिया एंड मर्चेंट पृ० 285 86)

उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योग में विस्तार होने का कारण ऐसी वस्तुओं का आयात घटा। 'उपभोक्ता वस्तुओं के आयात की मात्रा में मापन गिरावट की प्रवृत्ति बढ़ रही है। 1926-27 में यह 37% था, और 1938-39 में घटकर यह 20% हो गया। रंग, पेंट आदि कच्चे माल का आयात बढ़ा है। 1922-23 में यह 16% था जो 1938-39 में बढ़कर 24% हो गया। मशीन और अथवा बड़ी पूंजी के सामान का आयात 1926-27 में सारे आयात का 19% था लेकिन 1938-39 में यह बढ़कर 25% हो गया।

हमारे युद्ध के पहले उपभोक्ताओं के मामले में भारतीय जनता की आत्मनिर्भरता निरंतर बढ़ती गई। वैसे ही बड़ी पूंजी वाले सामानों के मामले में उसकी पराश्रयिता भी बढ़ी। वाडिया एंड मर्चेंट ने इसकी या चर्चा की है

औद्योगिक विकास के संबंध पर वर्तमान युद्ध के पहले की आर्थिक स्थिति का या वर्णन किया जा सकता है। मरभित उद्योगों के विस्तार से राष्ट्रीय आय में विशेष वृद्धि नहीं हुई। इन उद्योगों और विदेशी मशीनों की जरूरतों को पूरा कर सकने की इनकी कार्यक्षमता से देश को वह आत्मनिर्भरता नहीं मिल रही है जो भविष्य के लिए आशामूलक है। चीनी, सूती सामान, लोहा और इस्पात के मामले में हम विदेशों पर निर्भर नहीं, लेकिन अपन कच्चे माल की खपत के लिए हम विदेशों का ही सहारा लेना है। लेकिन इन सबसे अधिक महत्व का तथ्य यह है कि मशीनरी और बड़ी पूंजी वाले सामानों के लिए हम अभी भी विदेशों पर आश्रित हैं। इनके बिना नए उद्योगों की स्थापना अमभव है।<sup>3</sup>

आधुनिक उद्योगों के निरंतर विस्तार के बावजूद भारत । 11

ही हुआ, क्याकि जिस गति से प्राक-आधुनिक दशे उद्योग का विनाश हो रहा था उतनी तजी मे नए उद्योगो का विकास गही हो रहा था। 1936 मे इकानमिस्ट के इडियन सप्लीमेट ने लिखा 'उद्योग पर जाश्रित जावादी घटती जा रही है भारत के उद्योगो का आधुनिकीकरण शुरू हो गया है लेकिन एसा नही कहा जा सकता कि उसका उद्योगीकरण हो चुका है।'<sup>4</sup>

1939 मे द्वितीय महायुद्ध शुरूजात होने पर भारतीय उद्योग के विकास की रफतार कुछ तेज हुई। यों नौपरिवहन वायुयान और एसे कुछ अय उद्योगो म शायद ही कोई खास प्रगति हुई और युद्ध काल की स्थिति के बावजूद भारी उद्योगो का भी विशेष विकास नही हुआ। भारी उद्योगो का विकास ही किसी दश के स्वतंत्र और तीव्र औद्योगिक विकास की मून शत है और उसकी आर्थिक प्रगति का परिचायक। फिर भी लडाई के दरम्यान कुछ हल्के उद्योगो का विकास हुआ। नीचे दी गई तालिका मे विकास की गति का पता चलता है

	1938 39	1939 40	1940-41	1941 42	1942 43	औसत
लाहा और						
इस्पात	100	110	125	150	200	146
मूती उद्योग	100	94	100	153	92	110
जूट उद्योग	100	106	91	103	85	96
ईंध के						
कारखाने	100	191	168	120	163	160
कागज	100	118	149	159	112	134
विद्युत उद्योग	100	109	115	135	135	123

(एन० सी० जैन, इडियन इकानमी डयूरिंग द वार पृ० 31)

युद्ध काल मे जो प्रगति हुई वह सब उपभोक्ता उद्योग म ही हुई। पूजीमान उद्योगो की दुखत और असाधारण उपेक्षा हुई है। सूती मामान चीनी, कागज सीमट चमडा इन सब उद्योगो का विस्तार हुआ है और मशीन और उमक बलपुर्जे मोटरगाडी आदि रलवे इतन जलयान और वायुयान सबकी उद्योग उपेक्षित रह हैं।<sup>5</sup> साथ ही युद्ध के कारण देग की जा औद्योगिक प्रगति हुई है वह कुछ हद तक कृत्रिम और अस्थाय है, थास्तनिक और चिरम्या नहीं।<sup>6</sup>

'मशीनीकरण' और उन्नतिक पुनगठन दाना दृष्टिवा से भारतीय उद्योग युद्ध के दिनों मे अपन प्रतियोगिता म सत्र मिनाकर बतरह पिछड रहा है और एम बात का प्रचुर साक्ष्य उपलब्ध है हिंदुस्तान के सामन युद्धोत्तर घतरा है जोद्योगिक विघटन का, और उमकी युद्धोत्तर आस्थिरता है औद्योगिक विकास की।<sup>7</sup>

व्यापार सघो और व्यावसायिक एकाधिकारो का आविर्भाव

ब्रिटिश शासन काल म भारत के आधुनिक उद्योगो का जा विकास हुआ उमका मक्षिण वणन हम द चुक है। अत्र यह दखें कि हम विनाम की विशिष्टता क्या

की। वाणिज्य, उद्योग और बैंकिंग के क्षेत्र में इस काल में जो आर्थिक विकास हुआ उसकी यह विशेषता है कि अधिकांश उद्योग कुछ इने गिन जादमियों के हाथ में मिमट गए।

अभी (1940 में) भारत में 1,000 कारखाने हैं जिनमें कुल 17,00,000 मजदूर काम करते हैं। भारत में पजीवद्ध कंपनियों में लगी पूंजी तीन हजार मिलियन रुपए के बराबर है।

औद्योगिक क्रियाकलाप के हर क्षेत्र में लगभग 500 कारखानों पर प्रवध अधिकर्ताओं के दल विशेष का अधिकार है। इन कारखानों में लगभग पंद्रह सौ मिलियन रुपए की पूंजी है। आर्थिक नियंत्रण का ऐसा केंद्रीकरण सब उद्योगों के बारे में सही है।<sup>9</sup>

भारत में जो हुआ वह इंग्लैंड, फ्रांस जैसी अमरीका जादि देशों के आर्थिक विकास के इतिसाम के विपरीत था। उन देशों के आर्थिक विकास के परवर्ती चरण में पूंजी और उद्योग का केंद्रीकरण हुआ।<sup>9</sup> भारत में इसके विपरीत उद्योगों की स्थापना के बाद कुछेक दशकों के अंदर ही ऐसा केंद्रीकरण हो गया।

इस केंद्रीकरण के कारण आधार और लव दोनों दिशाओं में उद्योगों का सम्मिलन हुआ और व्यापार संधा की स्थापना हुई। देश की आर्थिक जीवन के बहुत बड़े क्षेत्र में इन व्यापार संधा का अधिकार था। 1940 में ऐसे लगभग 40 व्यापार संध थे जिनका 450 कारों द्वारा पर कब्जा था और जिनमें लगभग ग्यारह सौ मिलियन रुपए की पूंजी लगी थी। ये कारोबार सब तरह के थे आद्योगिक, पशुवहन सबधी और विस्तीय। शक्ति भणन ब्रिटिश व्यापार संधा में कुछ थे किलिक निकसम, सैन्स, एण्ड्रयू यूल ब्रैडिज और जार्डिन एंड स्किनर टाटा, बिडना और डालमिया भारतीय एकाधिकारी मगठना में प्रमुख थे।

हर प्रकार के आर्थिक उद्यम पर इन व्यापार संधों का अधिकार था। उदाहरणार्थ, टाटा के जिम्म कुल 22 कारोंवार थे चार सूती कारखाने चार बिजली कंपनियां चार पावर कंपनियां एक लोहा और इस्पात का कारखाना एक वायु परिगमन कंपनी, एक तेल कारखाना, एक बीमा कंपनी और एक होटल। इसी तरह एण्ड्रयू यूल एंड कंपनी, जो पूर्वी हिंदुस्तान में काम करती थी कुल 42 कारों वारों पर अधिकार जमाए टुए थी। उसके पास 11 जूट, 11 कायला, 15 चाय, एक कामज, दो खर और एक तेल, इतने कारोंवार थे, और एक जमींदारी भी थी।<sup>10</sup> इन उदाहरणों से इने गिने व्यापार संधों के व्यापक क्रियाकलाप और लोगों के आर्थिक जीवन पर इनके प्रभाव का अनुमान किया जा सकता है।

इन व्यापार संधों में भी मत्ता उन डाइरेक्टरों के हाथ में थी जा बड़ी बड़ी जगहों पर बैठे थे। मत्तापी डाइरेक्टरशिप की प्रथा भी काफी प्रचलित थी और इससे कारण कुछ डाइरेक्टरों के अधिकार में और वृद्धि हुई। अशोक मेहता ने 1940 में लिखा, 'हमारे देश के पाच सौ प्रमुख औद्योगिक कारोंवारा का प्रवध केवल 2 000 डाइरेक्टर करते हैं। इनमें भी कुल डाइरेक्टरशिप केवल 850



ही हुआ क्योंकि जिस गति से प्राक-आधुनिक देशों उद्योगों का विनाश हो रहा था उतनी तेजी से नए उद्योगों का विकास नहीं हो रहा था। 1936 में इकानमिस्ट के इंडियन मण्डल ने लिखा 'उद्योग पर आश्रित आवादी घटती जा रही है भारत के उद्योगों का आधुनिकीकरण शुरू हो गया है लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उसका उद्योगीकरण हो चुका है।'<sup>5</sup>

1939 में द्वितीय महायुद्ध शुरू होना पर भारतीय उद्योगों के विकास की रफ्तार कुछ तेज हुई। यों नीपरिवहन, वायुयान और ऐसे कुछ अन्य उद्योगों में शायद ही कोई खास प्रगति हुई और युद्ध काल की स्थिति के बावजूद भारी उद्योगों का भी विशेष विकास नहीं हुआ। भारी उद्योगों का विकास ही किसी देश के स्वतंत्र और तीव्र औद्योगिक विकास की मूल शक्ति है और उसकी जाधिक प्रगति का परिचायक। फिर भी लड़ाई के दरम्यान कुछ हलकों उद्योगों का विकास हुआ। नीचे दी गई तालिका में विकास की गति का पता चलता है

	1938-39	1939-40	1940-41	1941-42	1942-43	औसत
लाहा और						
इस्पात	100	110	125	150	200	146
सूती उद्योग	100	94	100	153	92	110
जूट उद्योग	100	106	91	103	85	96
ईंधन के						
कारखाने	100	191	168	120	163	160
कागज	100	118	149	159	112	134
विद्युत् उद्योग	100	109	115	135	155	123

(एल० सी० जैन इंडियन इकानमी डयूरिंग द वार पृ० 31)

'युद्ध काल में जो प्रगति हुई वह सब उपभोक्ता उद्योगों में ही हुई। पूँजीवादी उद्योगों की दुखद और असाधारण उपेक्षा हुई है। सूती सामान, चीनी, कागज, सीमेंट, चमड़ा इन सब उद्योगों का विस्तार हुआ है और मशीन और उनके बलपूर्वक मोटरगाड़ी आदि रेलवे इंजन जलयान और वायुयान सबकी उद्योग उपजित रहे हैं।<sup>6</sup> साथ ही 'युद्ध के कारण देश की औद्योगिक प्रगति हुई है वह कुछ हद तक कृत्रिम और अस्थायी है, वास्तविक और चिरस्थायी नहीं।'<sup>6</sup>

'मशीनीकरण और वैज्ञानिक पुनर्गठन दोनों दृष्टियों से भारतीय उद्योग युद्ध के दिनों में अपन प्रतियोगिता से सब मिलाकर बतर्ह पिछड़ गया है और उस बात का प्रचुर साक्ष्य उपलब्ध है हिटलर के सामने युद्धोत्तर घतरा है औद्योगिक विघटन का, और उसकी युद्धोत्तर आवश्यकता है औद्योगिक विकास की।'<sup>7</sup>

व्यापार संधी और व्यावसायिक एकाधिकारों का आविर्भाव

ब्रिटिश शासन काल में भारत में आधुनिक उद्योगों का विकास हुआ उसका मक्षिप्त वर्णन हमें दे चुके हैं। अब यह देखें कि इस विकास की विशेषता क्या

थी। वाणिज्य, उद्योग और बैंकिंग के क्षेत्र में इस काल में जो आर्थिक विकास हुआ उसकी यह विशेषता है कि अधिकांश उद्योग कुछ इने गिने आदमियों के हाथ में सौंपे गए।

अभी (1940 में) भारत में 1,000 कारखाने हैं जिनमें कुल 17,00,000 मजदूर काम करते हैं। भारत में पञ्जीवद्ध कंपनियों में नगी पूजी तीन हजार मिलियन रुपए के बराबर है।

औद्योगिक क्रियाकलाप के हर क्षेत्र के लगभग 500 कारखानों पर प्रबन्ध अधिकारियों के दल विशेष का अधिकार है। इन कारखानों में लगभग पंद्रह सौ मिलियन रुपए की पूजी है। आर्थिक नियंत्रण का ऐसा केंद्रीकरण सब उद्योगों के बारे में सही है।<sup>8</sup>

भारत में जो हुआ वह इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, अमरीका आदि देशों के आर्थिक विकास के इतिहास के विपरीत था। उन देशों के आर्थिक विकास के पृष्ठभूमि चरण में पूजी और उद्योग का केंद्रीकरण हुआ।<sup>9</sup> भारत में इसके विपरीत उद्योगों की स्थापना के बाद कुछेक दशकों के अंदर ही ऐसा केंद्रीकरण हो गया।

इस केंद्रीकरण के कारण आधार और लव दानों दिशा में उद्योगों का सम्मिलन हुआ और व्यापार मण्डलों की स्थापना हुई। देश की आर्थिक जीवन के बहुत बड़े क्षेत्रों में इन व्यापार मण्डलों का अधिकार था। 1940 में ऐसे लगभग 40 व्यापार मण्डल थे जिनका 450 कारोबारों पर बन्ना था और जिनमें लगभग ग्यारह सौ मिलियन रुपए की पूजी लगी थी। ये कारोबार सब तरह के थे औद्योगिक परिवहन सबंधी और वित्तीय। शक्ति संपन्न ब्रिटिश व्यापार मण्डलों में कुछ थे वे किनिक निर्यात, संसूत, एण्ड्रयू यूल ब्रिडज और जार्डॉइन एंड स्विनर टाटा, विडना और डानमिया भारतीय एकाधिकारी मण्डलों में प्रमुख थे।

हर प्रकार के आर्थिक उद्यम पर इन व्यापार मण्डलों का अधिकार था। उदाहरणार्थ, टाटा के जिम्मे कुल 22 कारोबार थे चार सूती कारखाने, चार बिजली कंपनियां चार पावर कंपनियां एक लोहा और इस्पात का कारखाना एक वायु परिगमन कंपनी, एक तेल कारखाना, एक बीमा कंपनी और एक होटल। इसी तरह एण्ड्रयू यूल एंड कंपनी, जो पूर्वी हिंदुस्तान में काम करती थी कुल 42 कारोबारों पर अधिकार जमाए हुए थी। उसके पास 11 जूट, 11 कोयला, 15 चाय, एक कागज, दो रबर और एक तेल, इतने कारोबार थे और एक जमींदारी भी थी।<sup>10</sup> इन उदाहरणों से इने गिने व्यापार मण्डलों के व्यापक क्रियाकलाप और लोगों के आर्थिक जीवन पर इनके प्रभाव का अनुमान किया जा सकता है।

इन व्यापार मण्डलों में भी नत्ता उन डाइरेक्टरों के हाथ में थी जो बड़ी-बड़ी गण्डलों पर बैठे थे। समाप्ति डाइरेक्टरशिप की प्रथा भी काफी प्रचलित थी और इसके कारण कुछ डाइरेक्टरों के अधिकार में और वृद्धि हुई। अशोक मेहता ने 1940 में लिखा 'हमारे देश के पांच सौ प्रमुख औद्योगिक कारखानों का प्रबन्ध केवल 2,000 डाइरेक्टर करते हैं। इनमें भी कुल डाइरेक्टरशिप केवल 850

व्यक्तियों के हाथ में है और 1000 डाइरेक्टरशिप के मालिक महज 70 व्यक्ति हैं। इस पिगमिड के शीप पर दस जादूगी हैं जो 300 डाइरेक्टरशिप के मालिक हैं। दस व्यक्ति हमारे देश के औद्योगिक अथवा के भाग्य विधाता हैं।<sup>31</sup>

उदाहरणार्थ, सर पुस्तोत्तमदास ठाकुरदास 51 कारावारा के डाइरेक्टर थे। ये कारावारा विभिन्न कोटि के थे जैसे बी० ई० एस० एड टी० क० (वावे एलेक्ट्रिक सप्लाय एंड ट्रांसपोर्ट कंपनी), दि जोरियटल गवर्नमेंट मिक्युरिटी लाइफ अस्पारेंस कंपनी दि इंडियन रडियो एंड वेवल कम्युनिकेशंस कंपनी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कई छापखाने, बहुत सारी मूती मिलें बहुत सारी रेलवे कंपनियां टाटा हाइड्रो एलेक्ट्रिक कंपनी और अने कई विजली और दूसरे मामाना की कंपनियां।

### वित्तीय पूजा का प्रावृत्त्य

आधुनिक उद्योगों के लिए बड़ी पूजा की आवश्यकता होती है और छोट लोगों के पैसा लगान में बड़ी पूजा का इकट्टा होना संभव नहीं। इसलिए बैंक और वित्तीय व्यवसाय मधो से महायता लेनी पडी और भारतीय उद्योग पर वित्तीय पूजा का नियंत्रण कायम हुआ। अथवा के लगभग सारे जगा पर वित्तीय पूजा का नियंत्रण आज के पूजावादी देशों के आर्थिक जीवन का सामान्य लक्षण है और यह भारत में भी परिलक्षित हुआ। 'बैंक बीमा कंपनियां और लायत मधो पर अपने नियंत्रण और प्रभाव के कारण महज दस हजार लोग बचक के औद्योगिक जीवन पर कब्जा किए बैठे हैं। सर पुस्तोत्तमदास ठाकुरदास और उनके रिश्तदार सर चुनीताल महता बचक के लगभग प्रत्येक व्यापार मधो और प्रमुख कारोबार में ऊंची जगहा पर हैं। अपने मुद के फायद नुकसान को नजर में रखकर उन्होंने बहुत सारे सभावित प्रस्तावित एकीकरणों और विलयनों को सफल या विफल बनाया है। अपनी वित्तीय स्थिति के चल पर प्रेमचंद प्रदम जीजीभाद प्रदम कोवासजी जहागीर जानि भी अपने तौर पर इसी तरह से अपने प्रभाव का उपयोग करते हैं।<sup>32</sup>

भारतीय और अंग्रेजी शाना प्रकार की वित्तीय पूजा सामान्य मैननेजिंग एजेन्सी (प्रबंध अधिकर्ता) वाली प्रथा के जरिए अपना काम करती है। इस प्रथा के अनुसार अपेक्षाकृत अल्पमूल्यक मैननेजिंग एजेन्सी बहुत सी औद्योगिक कंपनियां और उद्योगों को स्थापित करती है, उन पर नियंत्रण रखती है, उन्हें पैसा देती है, उनको त्रियाकलाप और उत्पादनों पर बड़ी नजर रखती है और उनको द्वारा तैयार माल को बिक्री का भी प्रबंध करती है। कंपनियां के डाइरेक्टर नाम मात्र की या अधीनस्थ की भूमिका जगा करत हैं। लाभ का अधिकांश हिस्सा शाना का न जाकर मैननेजिंग एजन्सी का जाता है।<sup>33</sup>

भारतीय अथवा पर ब्रिटिश पूजा की घातक जकट

ब्रिटिश मैननेजिंग एजन्सी भारतीय एजन्सी में लगती थी। एण्ड्रयूज एंड कंपनी

## भारत में आधुनिक उद्योगों का उद्भव और विकास

और जार्ज टॉन एंड स्विनर इस तरह की दो बड़ी सक्षम कंपनियां थीं। अबहतर वित्तीय शक्ति और औद्योगिक कंपनियों पर अपने नियंत्रण के कारण भारतीय उद्योगों पर खासकर मकट के दिनों में, अधिवाधिक अधिकार सक्ती।<sup>1</sup>

ब्रिटिश और भारतीय दोनों प्रकार की वित्तीय पूंजी बैंकों के माध्यम से काम करती थी। 1934 में स्थापित रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और 1928 में स्थापित इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया देश के सर्वाधिक शक्तिशाली बैंक थे। विनिमय बैंक भी काम करते थे और आयात निर्यात में लगे थे। चाटबैंक इंडिया और मकेंटॉइल बैंक ऑफ इंडिया इनमें प्रमुख थे। दश में एक तीसरे बैंक के बैंक भी थे, भारतीय ज्वायंट स्टॉक (मयुक्त पूंजी) बैंक जिनमें भारतीयों का प्राबल्य था। इंपीरियल बैंक और विनिमय बैंक गैर भारतीय थे। उन सम्मिलित वित्तीय संपत्ति भारतीय ज्वायंट स्टॉक बैंकों जो मूलतः भारतीय नियंत्रण में थीं, की पूंजी से अधिक थी।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दश का सत्रमें तगड़ा बैंकिंग संगठन था। इसकी शक्ति काफी व्यापक थी और इस पर सरकारी नियंत्रण था। सरकार ही इसका प्रमुख अफसरों जैसे गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और कुछ डाइरेक्टरों को भी बना करती थी।

उन दिनों कई भारतीय राष्ट्रवादी अग्रशक्ति और राजनीतिकों ने कहा कि भारतीय बैंकिंग पर व्यापक ब्रिटिश प्रभुत्व भारत के क्षिप्र और उच्च औद्योगिक विकास के पथ में बहुत बड़ा अवरोध है। भारतीयों द्वारा चलाए गए उद्योगों में पैसा या पूंजी उठाने के सवाल पर ब्रिटिश प्रभुत्व वाले बैंक और ब्रिटिश सरकार दोनों ऐसी नीतियां अपनाते थे जो ब्रिटिश आर्थिक हितों निर्धारित हात में थे न कि भारत के औद्योगिक विस्तार के दृष्टिकोण से।<sup>2</sup>

इस तरह ब्रिटिश वित्तीय पूंजी के नियंत्रण के कारण भारत का तीव्र उद्योगिक और सामाजिक आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा। भारतीय जनता की भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति के लिए देश का आर्थिक विकास आवश्यक था। इसलिए राष्ट्रवादी आंदोलन इस आर्थिक विकास का पक्षधर और ब्रिटिश वित्तीय पूंजी के हथ और सरकारी नीति का घोर आलोचक।

इंडियन नेशनल कांग्रेस एवं उदारवादी और अन्य राजनीतिक दलों ने संगठनात्मक उद्योगशील देश के रूप में भारत का रूपान्तरण की बात की। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में अंग्रेजी वित्तीय पूंजी को जा वैधानिक सुरक्षा प्रदान हुई, उसकी उद्देश्य बड़ी तीव्र आलोचना की। इन दलों ने कहा कि भारतीय मंत्रियों का फल को रद्द कर देने का जो अधिकार प्रायः के गवर्नरों का दिया गया है वह भारतीय अर्थतंत्र पर ब्रिटिश पूंजी के नियंत्रण और उसके प्राबल्य का जड़ों की रचना और देश के सामाजिक एवं औद्योगिक विकास का अवरुद्ध करेगा।

या भारतीय उद्योगों के विकास और जर्मनी, जापान और अमरीका

ब्रिटेन के गर हिंदुस्तानी प्रतियोगिता की बढ़ती हुई ताकत के कारण भारतीय मंडी में ब्रिटेन का हिस्सा कम होता गया।<sup>36</sup>

1936 के बाद भारत ब्रिटेन का प्रमुख खरीदार नहीं रहा जैसे वह पिछले सौ साल से था। 1937 में ब्रिटेन के सामानों के खरीदारों में भारत की दूसरी जगह थी और 1938 में तीसरी।

1918 के बाद भारतीय मंडी में ब्रिटेन की स्थिति का विशेष ह्रास हुआ। यह ह्रास सूती माल के निर्यात में खासकर दिखाई पड़ता है हालांकि उन्नीसवीं सदी में सूती कपड़ों का ही रोजगार भारत के औद्योगिक पूंजीवादी शोषण का प्रमुख क्षेत्र था

इस तरह पुराने आधार तो खत्म हो रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ वित्तीय पूंजीवादी शोषण द्वारा लाभ के नए आधार भी तेजी से बन रहे थे। फाइनेशियल टाइम्स के अनुसार बड़े मतुलित अनुमान के आधार पर भी 1929 में भारत में लगी हुई ब्रिटिश पूंजी की राशि 573 मिलियन पाउंड थी जो मभयत यह राशि वस्तुतः 700 मिलियन पाउंड थी।<sup>37</sup>

ब्रिटिश एसोसिएटेड चयम आफ कामस क अनुसार 1933 में यह रकम 1000 मिलियन पाउंड थी। भारत में ब्रिटिश और विदेशी पूंजी की ताकत का एक यह पहलू है कि औद्योगिकरण के परिणाम और उसमें लगी पूंजी का अनुपात सत्तापजनक नहीं है। इसका कारण यह था कि विदेशी पूंजी का बहुत बड़ा भाग गैर औद्योगिक क्षेत्रों में लगा था क्योंकि गैर औद्योगिक क्षेत्रों में अधिक लाभ होता था। जहाँ पूंजी उद्योगों में लगी थी, वहाँ हल्के उद्योगों में ही अधिक पैसा लगा।<sup>38</sup>

### भारतीय उद्योग के एकांगी विकास के कारण

दशौं पूंजी ऐसे भी बहुत कम थी लेकिन इसे भी लागान अधिक फायदा वाला गैर उद्योगी क्षेत्रों में लगाया। डी० जार० गार्टगिनन लिखा है भारतीय पूंजी उद्योगों में नहीं लगी इसके कई कारण थे। भारतीय पूंजी की राशि बहुत कम थी और कृषि एवं उद्योग दोनों में इस पूंजी की भाग थी। सूदखारी और वाणिज्य में बहुत अधिक फायदा था खासकर फसल के दिनों में पैसा लगान से जा फायदा होता था उसकी दर काफी ऊंची थी।<sup>39</sup>

भारत का औद्योगिक विकास बड़ा धीमा और एकांगी था। भारत में उद्योग तब विकसित हुए जब इंग्लैंड अमरीका, जर्मनी और अन्य देशों में बड़े बड़े उद्योग स्थापित हो चुके थे। इसलिए भारतीय उद्योग विदेशी उद्योग से होकर लगे थे। विकसित देशों के उद्योगों का अपनी सरकारों का समर्थन और उनकी सुरक्षा उपलब्ध थी। इसके विपरीत, भारत में मुक्त व्यापार के सिद्धान्त की आड़ में, ब्रिटिश सरकार ने 1924 तक भारतीय उद्योगों का कोई सुरक्षा नहीं प्रदान की। दूसरे देशों के सरकारी सहायता प्राप्त उद्योगों से हाटकर लगे थे। इसलिए भारतीय उद्योगों का इस तरह की सरकारी सुरक्षा की बड़ी आवश्यकता

थी। टैरिफ बोर्ड की स्थापना और सुरक्षा प्रदान करने वाले करों के लगने के बाद भी भारतीय उद्योगों को खास मदद नहीं मिल सकी क्योंकि जसा पहले बताया जा चुका है इंपीरियल प्रेफरेंस (साम्राज्यी अधिमान) के सिद्धांत के सामने सुरक्षा के सिद्धांत का बहुत कम महत्व था। फिर भी सुरक्षा प्रदान करने की नीति से उपभोक्ता सामान पैदा करने वाले कुछ उद्योगों का फायदा हुआ।

सुस्थापित धातुमूलक और मशीन बनाने वाले बड़े बड़े उद्योगों के जन्म के कारण भी देश के तीव्र औद्योगिक विकास में दिक्कत हुई। औपनिवेशिक अर्थतंत्र का यह लक्षण है कि इसको अपना भारी उद्योग नहीं है और इसलिए इसे साम्राज्यी जयव्यवस्था के अधीन रहना पड़ता है। आधुनिक समाज के मुक्त, समानुपाती और तीव्र औद्योगिक विकास के लिए ऐसे उद्योग आवश्यक हैं।

किसी भी देश में वास्तविक परिवर्तन की तत्र शुरुआत होती है जब उस देश में लोहा और इस्पात उद्योग क्रियाशील होने लगते हैं धातु के उद्योगों के विकास का जय है वास्तविक औद्योगिक क्रांति। इंग्लैंड, जर्मनी और अमेरिका ने पहले अपना लोहा और इस्पात उद्योग शुरू किया, बाद में अपने सूती कारखाने।<sup>40</sup>

कृषक आवादी की अद्यतन निधनता भी भारतीय उद्योगों के विकास में बहुत बड़ी रकबट थी। कृषक आवादी सारी आवादी का 4/5 भाग थी और औद्योगिक माल के लिए यह बहुत बड़ा बना बनाया बाजार था। हम कृषि वाले अध्याय में देख चुके हैं कि ऋण, जमान, जमीन से होने वाली आय के ह्रास जादि कारणों से कृषक आवादी के बहुसंख्यक लोग काफी गरीब हो गए थे। मूलभूत भूमि सुधार के बिना क्रिमाना की आर्थिक स्थिति में बुनियादी तरहकी सभय नहीं थी, और उमठे बिना भारतीय उद्योग का समुचित विकास सभय नहीं था। आवश्यकता थी भूमि मरघा के पुनरीक्षण की और कृषि के नवीकरण के लिए क्रिमाना को सरकारी सहायता की जिसमें आवादी के इस बहुत बड़े की त्रय शक्ति बड़े और औद्योगिक सामानों की बिनी हो।

भारतीय औद्योगिक विकास ब्रिटिश वित्तीय पूंजी पर आश्रित था और भारतीय उद्योगों पर ब्रिटिश पूंजी का नियंत्रण था। इसका भी उद्योगों के विकास पर बुरा असर पड़ा। वित्तीय सहायता जक्सर इसी शत पर दी गई थी कि भारतीय उद्योगपति ब्रिटिश कारखानों से ही औद्योगिक मशीन खरीदें। या फिर यह सहायता उन उद्योगों को दी गई जो ब्रिटिश उद्योगों से होड लेने वाले नहीं थे।

तकनीकी शिक्षण मस्थाएं बहुत कम थी और इसलिए तकनीकी काम करने वाले प्रशिक्षित लोग भी कम थे। उद्योगों के विकास में यह भी एक बड़ी बाधा थी। उनके जन्मकाल से ही भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की यह मांग थी कि तकनीकी शिक्षा का विस्तार हो। इंडियन नेशनल कांग्रेस और उदारवादी एवं अन्य प्रगतिशील राजनीतिक दल न तकनीकी शिक्षा के प्रश्न को भी अपने

कायक्रम में प्रमुख स्थान दिया। यह भी नातव्य है कि भारतीय उद्योग पर बहुत जल्दी केंद्रीकरण और एकाधिकार हावी हो गया। औद्योगिक विकास और विस्तार में एकाधिकारी मगठनों के जो नुकसान थे, वे भारत की स्थिति में अवश्यभावी थे।

### भारतीय इजारेदारी के विशिष्ट लक्षण

अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस एवं अन्य पूर्ण विकसित पूँजीवादी देशों के एकाधिकारी मगठनों से भारत के एकाधिकारी मगठन कई प्रकार से भिन्न थे। इन उन्नत देशों में 'मुक्त प्रतिद्वन्द्विता' के आधार पर विकसित पूँजीवादी जगत के चरम विकास की स्थिति में एकाधिकार का उद्भव हुआ था। भारत में पूँजीवाद देर से आया इसलिए देशी पूँजीवादी विकास के गैर एकाधिकारी चरण की विशिष्ट परंपरा और उसके सुदीर्घ अस्तित्व के बिना ही उद्योगों ने एकाधिकार का रूप ले लिया। ऊपर जिन देशों की चर्चा है वहाँ पूँजीवादी इजारेदारी का जब जन्म हुआ तब उत्पादन की शक्तियों और साधारण आर्थिक जीवन का काफी विकास हो चुका था। इसके विपरीत भारत में इजारेदारी जब आई तब उत्पादन की शक्तियाँ अभी पूर्णतः विकसित नहीं थीं। एक तरफ औद्योगिक और अन्य आर्थिक तत्व अभी भी अपरिपक्व थे, दूसरी तरफ था एकाधिकारी मगठन का विकराल रूप, और इन दोनों स्थितियों में परस्पर घात विरोध था। पूँजीवादी आर्थिक मगठन के एकाधिकारी रूप का अर्थ है पराधीनता और सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक अधोगति। भारतीय आर्थिक विकास के लिए यह स्थिति और अधिक नुकसानदायक थी क्योंकि यहाँ विकास का स्तर काफी निम्न था।\*

भारतीय इजारेदारी और उन्नत देशों की इजारेदारी में यह भी फर्क था कि राज्य से उनके मन्वय भिन्न कोटि के थे। अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस और एम्पे अन्य

\* एकाधिकार का जन्म पूँजीवादी व्यवस्था के विभिन्न उद्योगों का पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के कारण होता है। समस्त राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय उद्योग पर और उद्योग की मारा शाखाओं पर एकाधिकारों का स्वत्व और नियंत्रण होता है। एकाधिकारों के जन्म का कारण प्रतिद्वन्द्विता खत्म न होना होता है। अब सार विश्व में उद्योगों में एकाधिकार एक दूसरे से हाँड लते हैं एक दूसरे की ताकत को चुनौती देने हैं। एकाधिकारों के आर्थिक दत्तों का पारस्परिक मन्वय विश्वजनीन और भयंकर होता है इनके सन्वय के कारण पूँजीवादी राष्ट्रों का विरोध बढ़ता है और उनके बीच घात आर्थिक और सैनिक युद्ध होता है।

एकाधिकार का उद्भव उत्पादन की शक्तियों और उनके सामाजिक चरित्र के असाधारण विकास का ओर शक्ति करता है। उत्पादन का आधुनिक शक्तिशाली विकास की जिम्मेदारियाँ आज हैं वहाँ उनका मन्वय और लाभप्रद कार्यालयों में मुक्त मन्वयों के बिना संभव नहीं। एकाधिकारों के जन्म का अर्थ है कि एक पूँजीवादी मानव ने मुक्त मन्वयों का आवश्यकता स्वीकार की है। फिर भी उत्पादन के साधनों के पूँजीवादी निजास्वत्व का स्थिति में उत्पादन की संपूर्ण समय विश्वजनीन योजना संभव नहीं। या आधुनिक युग का अर्थ जिम्मेदार उत्पादन विद्या ही समाजवादी का भौतिक आधार है तब तक समाजवादी अध्ययन में ही उत्पादन की शक्तियों का स्वच्छ विकास संभव है।

देशों में साधारणतः एकाधिकार ही अपने देश की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों का निर्णायक था। उसे राज्य का संरक्षण भी प्राप्त था। इसके विपरीत भारतीय स्वामित्व वाले एकाधिकार, नियमित, मूलभूत आर्थिक नीतियों को प्रभावित करने में असमर्थ रहें। भारतीय सरकार तो देशी थी नहीं, और उसकी रुचि भी ब्रिटिश आर्थिक हितों की सुरक्षा में। वह भारतीय स्वामित्व वाले एकाधिकार को क्यों कोई सुरक्षा या समर्थन देती ?

भारतीय एकाधिकार की तीसरी विशेषता यह थी कि इसका उदय कृषि प्रधान देश में हुआ था जहाँ के अधिकांश निवासी गरीब थे। भारतीय औद्योगिक एकाधिकार के लिए मछी का प्रश्न बड़ा बौहूड था। भारत में पूँजीवादी विकास का यह एक स्पष्ट अंतर्विरोध है कि यहाँ पूँजीवादी आर्थिक संगठन के उच्चतम रूप एकाधिकार का दरिद्र और आदिम कृषिमूलक आर्थिक परिवेश में उद्भव हुआ। इस आर्थिक परिवेश में जड़ सामंती और प्राकृतिक सामंती तत्व अब भी शेष थे।

उन देशों की तरह भारत में भी निजी एकाधिकार के साथ ही साथ राजकीय एकाधिकार भी मौजूद था। लेकिन भारत के और अन्त्य दशों के राजकीय उद्योगों में मौलिक अंतर था। भारत में रेलवे जैसे राजकीय एकाधिकार विदेशी सत्ता के हाथ में थे। यह विदेशी सत्ता भारतीय जनता के स्वतंत्र आर्थिक विकास के बदले ब्रिटिश पूँजीवाद के हितों की रक्षा के लिए राजकीय एकाधिकार का इस्तमाल करती थी। इसलिए रेलवे केंद्रीय विधान सभा के नियंत्रण के बाहर था। जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे स्वतंत्र देशों में जब राज्य ने कुछ उद्योगों को अपने अधिकार में लिया तो उन उद्योगों के मंचालन संबंधी नीतियों नियमों पर वहाँ की सीनेट या सदन का पूरा नियंत्रण था। जब तक उन दशों में पूँजीवादी वर्ग का शासन रहेगा तब तक ये नीतियाँ उस वर्ग के हित में होंगी, लेकिन वे किसी विदेशी स्वार्थ की रक्षा के लिए नहीं थीं। भारत सरकार की मूल आर्थिक नीति जनमत के दबाव पर यदाकदा संशोधित होती रही, लेकिन यह नीति न तो भारतीय जनता द्वारा निर्धारित होती थी और न भारतीय मिलकियत वाली इजारेदारी द्वारा, और ब्रिटिश वित्तीय पूँजी का हित साधन करती थी।

भारत का औद्योगिक विकास सरकार की मुद्रा नीति के कारण भी रुक रुक कर हुआ। इस नीति के अनुसार विनिमय के दर का नियमन भारतीय हितों के विरुद्ध होता था।

भारत के क्षिप्र और सर्वांगीण औद्योगिक विकास की राह में यही कुछ मुख्य अवरोध थे। समय और उन्नतिशील उद्योगों का विकास और स्वतंत्र, संपन्न औद्योगिक राष्ट्र के रूप में भारत के उद्भव के लिए आवश्यक सारी मानवीय और भौतिक सुविधाएँ भारत में वतमान थीं। फिर भी ऊपर जिन अवरोधों की चर्चा हुई है उनसे कारण भारत मुख्यतः गरीब, कृषि प्रधान जनसमुदाय बना रहा, राष्ट्र के रूप में उसके उद्भव में कठिनाई हुई और यहाँ उद्योगों का विकास भी नावाणी रहा। इस प्रसंग में डॉ० एच० व्युर्नैन न 1934 में लिखा



इस देश में वे सारे अनगढ़ तत्व मौजूद थे जिन पर वस्तु निर्माण निभर है। फिर भी पिछले सौ साल में इस देश में बाहर के कारखानों में बनी चीजों का बड़ी तादाद में आयात हुआ है। यहाँ केवल कुछ सरलतम उद्योगों का उदभव हो सका है, ऐसे उद्योग जिनके लिए मशीन और सगठन जय दशों में पूरी तरह विकसित हो चुके हैं। कच्चा सूत, कच्चा जूट, सहजोपलब्ध कायना, आसानी से खान से निकाला जा सके ऐसा अच्छे किस्म का लोहा बहुत बड़ी आवादी जिसमें लाभप्रद कारोबार के अभाव में प्रायः लोग भुखमरी के शिकार हैं, सोना और चादी का ढेर, ब्रिटिश सरकार के माध्यम से ऐसी मुद्रा मंडी की सहज साध्यता जो सार ससार को बहुत बड़े अंश में पूजा दे रही थी देश विदेश में जो पूजोवादी उद्योग शुरू कर रहे थे ऐसे ब्रिटिश कारोवारी जगत के नेताओं के लिए अपनी स्वयं की विजय पताका की छत्रछाया, देश की सीमाओं में ही बहुत बड़े बाजार का अस्तित्व इन सबके बावजूद, सौ साल के बाद भी, भारत की सारी आवादी का केवल दो प्रतिशत उद्योग पर आश्रित है देश अभी भी लगभग पूरी तरह कृषि प्रधान है।<sup>11</sup>

### स्वस्थ औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक शर्तें

भार प्रगतिशील राष्ट्रवादी दल दश के उद्योगीकरण के पक्ष में थे और उन्होंने इसके लिए जार लगाया। इन दलाने भारतीय जनता की आर्थिक, प्रजातान्त्रिक सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति के लिए उद्योगीकरण को आवश्यक माना। कृषि की अनिःसकुलता किसानों की गरीबी का प्रमुख कारण थी और उद्योगीकरण इस सकुलता को कम करने का तरीका। इसलिए सार मतभेदों के बावजूद देश के सारे सामाजिक राजनीतिक दलों के आर्थिक कार्यक्रम में उद्योगीकरण को अनिवार्यतः जगह मिली। स्वदेशी आंदोलन रूप्य के विनिमय अनुपात के विरुद्ध मध्य, 1935 के विधान में प्रातः व गवनों को दिए गए अधिकारों के खिलाफ की गई लड़ाई ब्रिटिश आर्थिक स्वार्थों की सुरक्षा के लिए अपनाए गए उपायों का विरोध, इन मध्यों में मारे राजनीतिक दल साथ थे और इन सबका उद्देश्य था भारत का सुमपन्न औद्योगिक राष्ट्र बनाना। टाटा विडला याजना के प्रवक्ता इसी उद्देश्य से अनुप्रेरित थे और इसीलिए राजभवन दलाल उदारवादी टाटा और गांधीवादी कांग्रेसी विडला ने इस मद में सम्मिलित स्वाय की पूर्ति के लिए सम्मिलित प्रयास किए।

भारतीय उद्योगों के विकास के रास्ते में जो बाधा विघ्न थे उनकी गिती हम लोग कर चुके हैं, सरकार की मूलभूत आर्थिक नीतियाँ किसानों की औद्योगिक माल के ग्राहक हो सकतं थे उनकी चरम दरिद्रता, भारतीय बुजुर्गों की आर्थिक हीनता अपनी सरकारों द्वारा समर्थित विदेशी प्रतिद्वंद्वियों के साथ तीव्रतर होनी हुई होड, इत्यादि।

एमी हासन में आर्थिक जीवन में हर क्षेत्र पर जा ध्यान देनी पड़ी

सुनियोजित अथर्वव्यवस्था के कार्यक्रम से ही उद्योगों का तेज, समरूप और निश्चित विकास संभव है। इस तरह के किसी भी कार्यक्रम के उद्देश्य होने चाहिए आदिम और विपन्न कृषि का पुनरुद्धार और समृद्धिशील आधुनिक कृषि के रूप में उसकी स्थापना, उद्योगों का आधुनिकीकरण और विस्तार, धातु रसायन, विद्युत और मशीन संबंधी भारी उद्योगों और ऐसे ही अन्य उद्योगों की स्थापना और विकास रेलवे, बस और आवागमन के अन्य साधनों का विस्तार, तकनीक और अभियंत्रण में प्रशिक्षित तागा की सख्या में वृद्धि बड़ी तादाद में कृषि अथर्विदों का प्रशिक्षण। सुनियोजित राष्ट्रीय अर्थतंत्र का अर्थ है भारतीय जनता के जीवन में तकनीकी आर्थिक प्रगति और भारतीय उपमहाद्वीप के सारे भौतिक और मानवीय साधनों का अधिकतम और योजनाबद्ध उपयोग। ऐसे कार्यक्रम के बिना साधारण आर्थिक प्रगति और तीव्र औद्योगिक विकास संभव नहीं था।

देश के सुदृढ़ आर्थिक अस्तित्व और विस्तार के लिए राष्ट्रीय आर्थिक योजना की आवश्यकता थी, और अब बुजुर्गों भी यह बात मान रही थी, यद्यपि आर्थिक संकट के पहले वाले युग में अहस्तक्षेप और उन्मुक्त व्यवसाय उनका परम पवित्र सिद्धांत था।

### बाबे प्लान और उसकी कमजोरियाँ

भारतीय उद्योगपतियों ने भी राष्ट्रीय अर्थतंत्र का योजनाबद्ध करने की चरम आवश्यकता को स्वीकार किया। औद्योगिक दलों द्वारा बनाई गई योजनाओं में बाबे प्लान सबसे अधिक प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय अर्थतंत्र के विकास की किसी भी योजना को कार्यान्वयन के लिए राजनीतिक सत्ता की जरूरत है। बाबे प्लान के प्रवक्तों ने भी यह समझा और राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की आशा प्रकट की ऐसी सरकार जो योजना के कार्यान्वयन में सहायक हो।

बाबे प्लान में कुछ बहुत बड़ी कमजोरियाँ थीं। इसके समर्थकों की यह समझ थी कि भूमि संबंधों के मूलभूत पुनरीक्षण के बिना भी देश का व्यापक औद्योगिक विकास संभव है लेकिन किसानों की गरीबी दूर करने और उनकी त्रय शक्ति वृद्धि के लिए ऐसा पुनरीक्षण आवश्यक था। कृषक अर्थतंत्र और अधिक हास्त-ग्रस्त न हों और किसान और भी अधिक गरीब न हों। इसके लिए भूमि संबंधों में आधारभूत परिवर्तन लाना ही था।

योजना के प्रवक्तों ने यह भी उम्मीद की थी कि प्रतिद्वंद्विता, लाभार्थ उत्पादन, उत्पादन तंत्र पर निजी स्वत्व आदि पूँजीवादी मायताओं की आधारभूमि पर भी उनकी योजना का कार्यान्वयन हो सकेगा। पूँजीवादी आधार पर भी कुछ हद तक योजना संभव है लेकिन राष्ट्र के पैमाने पर व्यापक आर्थिक संयोजन के लिए भूमि उद्योग आवागमन के साधन और उत्पादन के भौतिक उपकरणों पर सामाजिक स्वत्व आवश्यक है। इन्हीं मूल मालिकों के यदने जनसाधारण के उपयोग और उनके हितों में साधनों के मुक्त संयोजित और महत्तम उपयोग उपयोग के लिए

इन साधनों पर समूचे समाज का अधिकार जरूरी है। पूजीवादी व्यवस्था में उत्पादन का उद्देश्य है नफा कमाना लेकिन इसकी जगह वस्तुआ के उपभोग को उत्पादन का आधार और उद्देश्य बनाना होगा।

यह ज्ञातव्य है कि आज हम अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन और विश्व के पमाने पर एकाधिक अथतत्र के युग में रह रहे हैं। इसलिए अत्यधिक योजनाबद्ध राष्ट्रीय अथतत्र भी विश्व की आर्थिक व्यवस्था द्वारा संचालित है और सुनियोजित राष्ट्रीय अथतत्र सुनियोजित अंतर्राष्ट्रीय अथव्यवस्था का ही जग हो सकता है। फिर भी, भारत जैसी बड़ी आबादी और मपन आर्थिक साधना के देश में सुनियोजित राष्ट्रीय अथतत्र मभव है। यो इसके लिए राष्ट्रीय स्वातव्य, निहित स्वार्था से सत्ता का अपहरण, मूल उत्पादका के हाथ में सत्ता का हस्तांतरण और उत्पादा के साधनों पर सामाजिक अधिकार की आवश्यकता है। बाव प्लान के प्रतिपादका के दिमाग में दूसरी बातें थी

हम माफ बतला देना चाहते हैं कि यह योजना समाजवादी आधार पर, उप भाकनाआ के हित में, आर्थिक नियंत्रण की बात नहीं करती, यह बतमान आर्थिक संरचना की दृष्टि से योजना की बात साचती है। जब तक पूजीवादी संरचना में लाभ की भावना है आवर्ती मकट और चिरकालिक धरोनगारी की समस्या समाप्त नहीं होगी। इस योजना में कही भी पूजीवादी व्यवस्था की इस अतनिहित कमजारी की चचा नहीं है। लेकिन इस योजना के प्रवतक बड़े भावेपन से ऐसा मान बैठे हैं कि आर्थिक जीवन का ऐसा मगठन मभव है जिममें अथव्यवस्था के कुछ जगा पर पूरा सरकारी प्रवध और अधिकार हो। दूसरे शब्दा में वे मिश्रित, द्वैत अथतत्र का प्रस्ताव करत हैं, जिसमें एक भाग विल्कुल स्वतंत्र हो और दूसरा कुछ हद तक नियंत्रित और अथवा सरकार द्वारा प्रवधित हा। लोग प्रायः भूल जात हैं कि आर्थिक संरचना में एक भाग का नियमन सारी संरचना में द्वंद्विताजय संघष को तीव्र कर सकता है।<sup>4</sup>

### भारतीय औद्योगिक विकास का सामाजिक महत्व

अपर्याप्त और अनतुलित होन के बावजूद उद्योगीकरण ने भारतीय जन जीवन में क्रांतिकारी भूमिका अदा की। कृषि के क्षेत्र में पूजीवादी आर्थिक रूप रान के प्रयास संसार की व्यावसायिक शक्तिया द्वारा भारत की घुमपंठ और आजागमन के आधुनिक साधनों के विस्तार के फलस्वरूप जिस एकाधिक राष्ट्रीय अथतत्र का भारत में विकास हुआ था उसका सुमगठन उद्योगीकरण के चलत मभव हा सका। इसके चलत भारतीय अथतत्र अधिक समन्वित समरूप और जीवत हो सका और उसे निश्चित रूपरेखा मिली। इसने चलते आधुनिक शहरों का भी आविभाजन हुआ जो आधुनिक मस्कृति और वधनशील प्रजातांत्रिक सामाजिक जीवन के बद्र बने, और जहा सभी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक प्रगतिशील आन्दोलनों का जन्म हुआ।

भारत के प्रगतिशील सामाजिक और राजनीतिक दलाने उद्योगीकरण के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभों को समझा। उद्योगों एवं अन्य आर्थिक शक्तियों और साधनों के सामाजिक संगठन के बारे में इन दलों में मतभेद था। इन दलों में परस्पर इस बात पर भी झगडा था कि आर्थिक संगठन निस्सीम व्यक्तिगत प्रतिद्वन्द्विता और व्यक्तिगत अध्यक्षता के अहस्तक्षेप वाले सिद्धांत के आधार पर किया जाए, या राष्ट्रीय योजना के आधार पर, चाहे वह योजना पूंजीवादी हो या समाजवादी। लेकिन उद्योगों के सर्वांगीण विकास के पक्ष में सब थे। बहुत सारी बातों पर उनमें घोर मतभेद था लेकिन इस सवाल पर सब एकमत थे। औद्योगिक विकास के अवरोधों के खिलाफ उन्होंने जमकर लड़ाई की और उद्योगीकरण की उनकी सम्मिलित मांग राष्ट्रीय मांग थी। आधुनिक उद्योगों की स्थापना के फलस्वरूप भारतीय समाज में दो महत्वपूर्ण वर्गों का जन्म हुआ, बुजुर्गों और सबहारा। राष्ट्रीय आंदोलन में इन वर्गों की भूमिका की विवेचना हम बाद में करेंगे।

## संदर्भ

- 1 नाग इनडूस्ट्रीज मिनिस्ट्रियल रिपोर्ट 1922।
- 2 काल मासिक पृ० 62।
- 3 देखें गाडगिन पृ० 74-77।
- 4 रानाड पृ० 18।
- 5 गाडगिन पृ० 117-18।
- 6 ब्युक्नन पृ० 139।
- 7 आर० पी० दत्त पृ० 153।
- 8 सर वल्टेराइन शिरान आवर 2 अप्रैल 1922।
- 9 मारल एंड मेटेरियल प्रोग्रेस आफ इंडिया 1921 पृ० 144।
- 10 सर जान हिचेट यू० पी० व लेफ्टिनेंट गवर्नर इन्डियन इन्स्टिट्यूट ऑफ साइंस 1907।
- 11 डिप्लॉय टु दि इंडियन सेक्टर 26 नवंबर, 1915।
- 12 माग्नेटु चम्पलेट रिपोर्ट पृ० 267।
- 13 लावनाथन पृ० 6।
- 14 वही पृ० 6।
- 15 देखें वाडिया एंड मर्चेंट पृ० 285।
- 16 डी० एच० ब्युक्नन पृ० 464।
- 17 सर एम० विश्वेश्वरय्या पृ० 247।
- 18 वाडिया एंड मर्चेंट पृ० 285।
- 19 कट मिशन पृ० 285।
- 20 देखें वर्ग।
- 21 कट मिशन पृ० 280।
- 22 लावनाथन पृ० 78।

- 23 वाशिंग्टन एंड मचेंट प० 287 ।
- 24 अ सर्वे आफ इंडिया टु डे 12 दिसबर 1936 ।
- 25 जन प० 48 ।
- 26 वही प० 128 ।
- 27 वही प० 128 ।
- 28 अशोक मेहता प० 3 ।
- 29 देखें ग्रामिन और लेनिन ।
- 30 देखें अशोक मेहता ।
- 31 वही प० 11 12 ।
- 32 वही प० 14 ।
- 33 आर० पा० दत्त प० 168 ।
- 34 रिपोर्ट जाफ द सद्वल व किंग इक्वायरी कमेटी 1931 जिल्ड 1 ।
- 35 देखें विश्वेश्वरदा प० 64 65 ।
- 36 देखें रिथ्यू आफ टूड इन इंडिया 1937 8 भारत सरकार व आर्थिक मामला के सलाहकार डा० ग्रगरी द्वारा प्रस्तुत ।
- 37 आर० पा० दत्त प 146 ।
- 38 देखें आर० पा० दत्त ।
- 39 गाडगिल पृ० 193 ।
- 40 सी० एच० अयुक्तरन प० 450-5 ।
- 41 वही ।
- 42 वाशिंग्टन एंड मचेंट द वाव प्लान ज त्रिटसिग्म प० 3 4 ।

## आवागमन के आधुनिक साधन और भारतीय राष्ट्रवाद का उदय

### प्राक् ब्रिटिश भारत में आवागमन

आधुनिक राष्ट्रों के संगठन में रेलवे, बस और स्टीमर जैसे आवागमन के अर्वाचीन साधनों का बहुत बड़ा महत्व है। यह महज मयोग की बात है कि राष्ट्र का उदय अविभाजित उनीसवीं शताब्दी में हुआ जब आवागमन के आधुनिक साधनों का आविष्कार हुआ। इंग्लैंड और फ्रांस अठारहवीं सदी में ही राष्ट्रवाद के पथ पर अग्रसर हो चुके थे लेकिन राष्ट्र के रूप में उनका संपूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक विकास उनीसवीं सदी में ही संभव हो सका जब आवागमन के नए साधन इन देशों को आर्थिक और सांस्कृतिक रूप में सुमंगलित कर सके।<sup>1</sup>

भारत में भी रेलवे और मोटर बसों के आगमन जो प्रसार से भारतीय जनता के राष्ट्रीय समेकन में काफी मदद मिली। आवागमन की तकनीक किसी देश के आर्थिक विकास की स्थिति विशेष पर निर्भर और उसी से निर्धारित होती है। प्राक् ब्रिटिश भारत में यातायात व्यवस्था बहुत कमजोर थी, क्योंकि वैज्ञानिक और तकनीकी पिछड़ेपन के कारण आधुनिक उद्योग नहीं बन पाए थे, और आधुनिक उद्योग के बिना आवागमन के आधुनिक साधनों का निर्माण संभव नहीं। अधिकांश आवादी गावा में रहती थी और गाव आत्मनिर्भर थे। दुबल अर्थव्यवस्था के कारण आवागमन के साधनों की अक्षमता बनी रही और इन साधनों की दुबलता ने अर्थव्यवस्था के विकास को अवरुद्ध किया।

अधिकांश लोग अलग-अलग गावा में रहते थे। साधारण आकार और अधिक मूल्य की कुछ चीजों, जैसे औषधि, रेशम और देशकीमती पत्थर जो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जा सकते हैं, और फिर कुछ भारी भटकन सामान जैसे लोहा और नमक जिनकी कम मात्रा में ही सही, लेकिन सबका जरूरत पड़ती है, इनके अतिरिक्त बाकी सब चीजों के लिए गाव वाले गाव की ही उपज पर निर्भर थे। विभिन्न समुदायों में विशिष्टीकरण का अभाव था, इसलिए वस्तुओं और व्यक्तियों का आवागमन नहीं के बराबर था। मैला से फसल घर लाना, और उसका कुछ अंश निर्यात

व्यापार केंद्र तक पहुंचाना, वस्तुओं का मात्र इतना ही स्थानांतरण आवश्यक था, और यह काय लाग सामान को आदमिया के सिर पर या जानवरा की पीठ पर ढाकर लिया करते थे। कभी कभी जब बहुत दूर जाना जाता था तो सूखे के मौसम में बैलगाडिया का इस्तेमाल किया जाता था। कुछ इलाकों में, खामकर बगाल में नदिया और गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर स्थित खाडिया में नजदीक और दूर की भी यात्रा पानी के रास्ते होती थी। उत्तर और पश्चिम के इलाका में गंगा और सिंधु और दक्षिण में कृष्णा और गोदावरी के रास्ते छोटे छोटे यान भीतर के इलाका तक पहुंच जाते थे। मुगल काल में राजधानिया को मिलाने वाली कुछ गद्दी सड़कें थी, और अंग्रेजों ने भी शासक बनने से पहले सड़कें नहीं बनवाईं।<sup>9</sup>

प्राकृतिक भारत में आवागमन के साधनों की कमजोरी के कारण लागा ब्यापक एकाधिक सामाजिक, जातीय और सांस्कृतिक जीवन संभव नहीं हुआ। जातीय, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों के लिए लोगों में परस्पर आदान प्रदान संभव नहीं था, क्योंकि यात्रा के द्रुतगामी साधन उपलब्ध नहीं थे। केवल कुछ विद्वज्जन कुछ व्यापारी, राज्य काय से संबंधित कुछ व्यक्ति और तीर्थयात्री ही दश में भ्रमण करते थे, लेकिन आवादी के अविमर्शक लाग आत्मनिर्भर गांवों में रहते थे और शायद ही कहीं गांवों से बाहर जाते थे। सामाजिक विनिमय के अभाव में केवल ग्रामीण या जाति चेतना का ही विकास हो सका राष्ट्रीय चेतना और दृष्टि विकसित नहीं हो सकी।

### आवागमन के आधुनिक साधनों का उद्भव

उनीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध में टकनालाजी की अभूतपूर्व प्रगति और पिछले युग के व्यापार से संप्रहीत पूंजी के कारण, इंग्लैंड में मशीन पर आधारित उद्योग धंधा का जन्म हुआ। अंग्रेज उद्योगपतियों के सामने प्रश्न था इन नए और निरंतर वृद्धिशील उद्योगों से बन सामानों की तजी से छपत और उनके लिए भारत और दुनिया के अन्य भागों से कच्चे माल की आपूर्ति।

ब्रिटिश उद्योग की आवश्यकताओं के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार का भारत में रेलवे और सड़कों का निर्माण करना पड़ा। लाड डलहौजी ने भारत में रेलवे निर्माण का व्यापक कार्यक्रम प्रारंभ किया। उसने अपनी मशहूर मिनिट आन रेलवेज में रेलवे के निर्माण के आर्थिक कारणों की स्पष्ट व्याख्या की है।

ब्रिटिश पूंजीवाद के सामने यह समस्या भी थी कि ब्रिटन में अधिक पूंजी एकत्र होती जा रही थी और उसका बड़ा लाभदायक इस्तेमाल संभव नहीं था। इस पूंजी के लिए निवास की जरूरत थी। रेलवे निर्माण का कार्यक्रम शुरू करने पर भारत सरकार का पूंजी की जरूरत होती थी। ब्रिटन में एनर्जि पूंजी के जति रक का एक जग भारतीय सरकार का बजट रूप में दिया जा गया और इस तरह उसका विनाश संभव हुआ।

इन आर्थिक कारणों के अतिरिक्त भारत में रेलवे की स्थापना के राजनीतिक प्रशासनिक और सामरिक रणनीतिक कारण भी थे। अंग्रेजों की भारत विजय पूरी हो जाने पर अपने मद्रिया पुरान इतिहास में भारत पहली बार एकल राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में जाबद्ध हुआ और भारत की यह राजनीतिक प्रशासनिक एकता मात्र सतही नहीं थी।

प्राक् ब्रिटिश भारत की सरकारें लगान वसूली की एजेसी भर होती थी। अंग्रेजी सरकार ने गावा के जतर्जीवन पर आघात किया, उनके यायिक और पुलिस मबधी स्वातंत्र्य को समाप्त किया, उसकी जगह पर सारे देश को एक जैसी विधि व्यवस्था प्रदान की और उसके कार्यालय के लिए गावा में अपन प्रतिनिधि भेजे। वस्तुतः उहाने पहले के स्वशासित गावों से वे सार काय हथिया लिए जो राज्य द्वारा मचालित होते थे लेकिन जिह प्राचीन काल से ही ग्रामीण सस्थाए चलाती रही थी।

इस तरह अंग्रेजों ने भारत में एक विंगाल प्रशासनिक यंत्र की स्थापना की। इसके लिए रेलवे की स्थापना और उसका विकास, आधुनिक सडको का निर्माण और डाक और तारघर की स्थापना अनिवाय थी। गावा शहरा जिला और प्राता का एक राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में मगठित करने की आवश्यकता से रेलवे निर्माण का काफी प्रोत्साहन मिला।

सैन्य और सामरिक कारणों से भी भारत में आवागमन के आधुनिक साधनों की स्थापना आवश्यक थी। भारत में स्थापित अंग्रेजी राज्य की भीतरी विद्राह और बाहरी जात्रमण दाना में रक्षा करनी थी। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों में सेना का तेजी से ले जाने के लिए पर्याप्त रेलवे लाइनों की स्थापना और आधुनिक पक्की सडको का निर्माण आवश्यक था। इस तरह सैन्य और सुरक्षा मबधी कारणों से भी रेलवे की स्थापना हुई और सचार साधनों का विकास हुआ।

### आवागमन के आधुनिक साधनों का एकागी विकास

भारत में आवागमन के आधुनिक साधनों की स्थापना और विस्तार भारतीय राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक राजनीतिक और मासृतिक जीवन के सहज म्वतप्र और बहुमुखी विकास के दृष्टिकोण से नहीं, वरन मूलतः भारत में अंग्रेजों के आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए किया गया। इस कारण भारतीय आवागमन और सचार व्यवस्था का रूप उन्नितेगी रहा। इसलिए भारत में रेलवे और सडको का विकास अपर्याप्त, एकागी और त्रिकृत रहा।

रेलवे के माइलेज की दृष्टि से भारत की तुलनात्मक हीनता इसी स्पष्ट है कि जब भारत में हर 100 बगमील पर 2.2 मील रेलवे है और हर मील रेलवे लाइन पर 7.894 वागिद है जमरीका में जा भारत की तरह विशाल रूषि प्रधान देश है, हर 100 बगमील पर 8.42 मील रेलवे है और हर मील



रेलवे लाइन के लिए 469 वाशिदे है। फिर कर्जेटिना, अटिना और यूजी लड म औमतन हर भील रेलवे लाइन पर केवल 300 वाशिदे ह।<sup>4</sup>

ब्रिटिश सरकार ने भारत म ब्रिटिश मत्ता और पूजी की रक्षा के लिए रेलवे की जीवत भूमिका का समया और रेलवे पर अपन प्रतिनिधि बडे टाट का हरदम नियंत्रण रखा। 1935 के गवर्नमंट आफ इंडिया एक्ट के अनुसार भी रेलवे के नियमन और निर्माण मपोषण और मचालन पर फेडरल रेलवे अथारिटी का कायकारिणी अधिकार होगा। यह फडरन रेलवे अथारिटी मीधे गवर्नर जनरल के अधीन होगी और विज्ञापिका का उम पर काइ नियंत्रण नही होगा। यद्यपि भारत म रेलवे और सडका का निर्माण ब्रिटिश हित की दृष्टि से किया गया और एकाकी रहा, फिर भी भारतीय जनता के जीवन म इसकी प्रगतिशील भूमिका रही।

भारत क पुरान समाज के आर्थिक आधार का नष्ट करने म रेलवे ने एतिहासिक दृष्टि से प्रगतिशील नई आर्थिक शक्तिया की मदद की। उन्हाने आधुनिक समाज के औद्योगिक माल को भारत मे पहुंचान म मदद की और इस तरह गावा की आर्थिक आत्मनिभरता का ममाप्त किया। उन्हाने भारत का एक आर्थिक इकाई बना म मदद की और विश्व की मडी स भारत का सबब जोडा। रेलवे क कारण राष्ट्रीय जगव्यवस्था मभव हो सकी जो भारतीय राष्ट्र का भौतिक आधार है।

रेलवे के पास अतीव शक्ति थी। विनिष्ठीकरण के लिए आवश्यक शर्तों की मष्टि द्वारा उसन उत्पादन और वाणिज्य के क्षेत्र म घानि ला दी, और उमके कारण बड बडरगाहा और औद्योगिक केंद्रों की स्थापना हुई। रेलवे के चलते मार दश म साला भर कीमते स मरूप रह सगी और राष्ट्र का एकीकरण हुआ। दुर्भिक्ष की समस्या के निगन्त्रण म दुर्भिक्ष रिनीफ मगठना से भी बडी भूमिका रेलवे की रही। इनक चलते दाम मुनिन मभव हुई कयाकि लोगो को नकल्पिक रातगाए और मनिशीलता मिनी।

काल माम म 1853 म ही भविष्यवाणी की थी कि अंग्रेजो को यह पान हा या न हा भारत म रेलवे की स्थापना स भारतीय पूजी की मिनकियत मे भारतीय उद्योग का उन्भव अवस्यभात्री था

मुझे मालूम है कि अंग्रेज मित्ताधिपति अपन उद्योगों के लिए कम रुपये म रुई और जय कच्चे माल का भारत स बाहर निकालन के लिए भारत म रेलवे की स्थापना करना चाहते हैं। उनिन जिन देश म कायना और बाहा मिनता है उम देश म एक मार मशीन का टम्नमान मरु हा जान पर फिर उम देश को मशीन के निर्माण म बचित करना जगभव है। मीमी मना म्ने दश म रेलवे का जाल आप बिछाए म्में तो म्मर के नचापना की तात्परिक और आपन आदशमनाभा की पूर्ति के लिए औद्योगिक प्रक्रियाए भी अपनाती हागी और तत्र धीरे धीरे उद्योग की उा शाखाया म भी मशीन



रेलवे और बसों के कारण दश के एक भाग से दूसरे भाग में लोग का प्रवासन मभव हुआ। नौकरी की खोज में या अपने भविष्य की बढ़ाचढ़ी के लिए लोग प्रस या रेल द्वारा मद्रास में बंबई या लाहौर से कलकत्ता गए। शिक्षित लोग, डाक्टर शिक्षक, किरानी, इन लोगों ने रोजगार के लिए अपन प्रात छोड़े और प्रई जैसे शहरो में नौकरी पशा और यावसायिक वग में देश के हर प्रात के लोग मौजूद है।

यात्रा की व्यापक सुविधाओं के कारण लोग का जा सम्मिश्रण मभव हुआ उसके बड़े गहरे नतीजे निकले। कुछ दिनों तक पुराने स्थानीय और प्रातीय दृष्टि काण बन रह, लेकिन उनके विनाश की प्रक्रिया शुरू हो गई। पुराने मकीण विचार और दृष्टिकोण निरंतर समाप्त होते गए। इसके चत व्यापक राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रीय आधार पर सहयोग का रास्ता प्रशस्त हुआ।

भोजन पान, शारीरिक मवध व्यवहार, और ऐसी ही अय वाता के विषय में जा रूढ़िवादी या सामाजिक आदतें थी उनको समाप्त करने में रेलवे ने बहुत बड़ा योगदान दिया। रेलवे ने निष्पक्ष रूप से केवल भाड़ा चुकान के आधार पर, हिंदू, छूत अछूत समका एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया। कुतीन हिंदुओं का पहने तो यह बात कुछ जची नहीं, लेकिन शीघ्र ही उहान अछूता के साथ याया की बात में ममत्रोता कर लिया क्योंकि रेलगाडी से यात्रा करत के जा लाभ थे उनसे वे बचित रहना नहीं चाहत थे। इस तरह रेलवे ने सतातनी हिंदुओं की कट्टर रूढ़िवादिता और भाजन पान छूत अछूत समधी उनकी पापशका को नाल प्रम से समाप्त किया। रेलवे के चत लोग का आवागमन बना और व आपस में मिलन जुलने गे। लगातार मिलने जुलने और सामाजिक आदान प्रदान में सामाजिक पथरना के पुराने भाव भी धीरे धीरे निराहित हान लगे।

रेलवे, माटर, बस और आवागमन के आधुनिक साधना के त्रिना राष्ट्रीय स्तर पर रात्रनीतिक और सांस्कृतिक जीवन मभव गरी हाना। अगर य साधन भारत में अंग्रेजी शासन को मुदर और मुरक्षित करन के माध्यम में ता साथ ही उहान इस शासन के विरुद्ध भारतीय जनता के राजनीतिक जादान के मगठन करन का भी काम किया। आधुनिक रेलवे बस टार और तार के त्रिना रूढ़ियन नश नत्र काफ्रेम, निवरन फंडरसन नगनन डेमाफ्रेम यूथ लीग, जाल रूढ़िया बीमस काफ्रेम, अखिन भारतीय छात्र मगठन आन रूढ़िया विमान मभा, आन इंडिया टेट यूनिजन काफ्रेम जमी मस्वाका का न ता जम ही होना और न के राष्ट्रीय स्तर पर अपना साथ ही बन पानी। त्रिभिन्न शहरा, गावा, त्रिना, प्राता के नागा का रेलवे के द्वारा आपस में मिलन का, त्रिचांग में जादान प्रदान का और आदान के लिए कायप्रम निश्चित करन का मौता भिना। और मवे त्रिना राष्ट्रीय आदोतन की कन्यता ही नहीं की जा सतनी। आवागमन के आधुनिक साधना के त्रिना कई राष्ट्रीय काफ्रेम मभव नहीं हुआ हाना।

रेलवे और बसों के द्वारा लागा के बीच प्रगतिशील सामाजिक और बर्तानिक

विचारों का प्रचार प्रसार हुआ। आवागमन के आधुनिक साधनों के बिना वैज्ञानिक और प्रगतिशील साहित्य (किताबें और पत्र पत्रिकाएँ) सारे देश में तेजी से वितरित नहीं हो पाती। प्राथमिक कक्षाओं के लिए छपी छपाई किताबों के होने से सर्वसाधारण में शिक्षा का प्रसार हो सका। हजारों लाखों की तादाद में किताबों का मुद्रण तो संभव होता लेकिन हजारों गाँवों और शहरों में उनके क्षिप्र वितरण की व्यवस्था के बिना जो रेलवे और बसों के कारण संभव था, वे किताबें विभिन्न क्षेत्रों में नहीं पहुँच पाती। आवागमन के आधुनिक साधनों के बिना व्यापक शिक्षा का प्रवर्धन नहीं हो पाता।

रेलवे की मदद से किसी एक क्षेत्र की वैज्ञानिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों को राष्ट्रीय संपत्ति बनाया जा सकता था। वैज्ञानिक कलाकार, समाजशास्त्री, दार्शनिक और अर्थविद अपना ज्ञानभंडार और कलाजय आनंद लोगों तक पहुँचा सकते थे, क्योंकि अब वे एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा कर सकते थे और लोगों के सामने आ सकते थे। दार्शनिक और सांस्कृतिक काफ़रें, जहाँ भारतीय बुद्धि और कलात्मक प्रतिभा का भारतत्व प्रतिपादित और प्रदर्शित हो सकता था तभी संभव हुए जब रेलवे और बसों का आविर्भाव हुआ। इस तरह राष्ट्रीय स्तर की सर्वोपलब्ध व्यापक जनशिक्षा और संस्कृति रेलवे पर भी उतनी ही निर्भर थी जितनी किन्हीं अन्य कारक तत्वों पर।

भारत में आवागमन और संचार के आधुनिक साधनों का विकास एकांगी और सीमित था। श्रेष्ठतर सामाजिक और आर्थिक एकीकरण और भारतीय जनता की क्षिप्रतर सांस्कृतिक प्रगति की दिशा में इन साधनों की अतर्निहित क्षमता का पूर्ण विकास नहीं हुआ। इन साधनों के विस्तृत और पर्याप्त विकास की समस्या का राजनीतिक सत्ता पर भारतीय जनता के अधिकार की समस्या में बड़ा गहरा संबंध था, साथ ही आर्थिक नवनिर्माण-मुख्य वैज्ञानिक याचना द्वारा भारतीय समाज की उत्पादक शक्तियों के तीव्र विकास से भी इसका संबंध था। और सही अर्थों में यह तभी संभव था जब उत्पादन के साधनों पर समाज का पूरा अधिकार हो।

## संदर्भ

1. देखें सास्त्री ।
2. देखें डी० एन० व्यवनन गाँवगिल अभिला ।
3. व्युत्पन्न, पृ० 176 ।
4. मोती प० 24 ।
5. आभता प० 269-70
6. बाल मास्य पृ० 62-63 ।
7. ज्ञान व्युत्पन्न प० 42 ।
8. बलित मध्युज अभिला प० 248 द्वारा उद्धृत ।

## भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में आधुनिक शिक्षा का योगदान

### शिक्षा का सामाजिक महत्व

आर्थिक क्रियाकलाप किसी भी समाज के अस्तित्व के लिए नितांत आवश्यक है। अपने सदस्या के महज भौतिक अस्तित्व के लिए भी समाज का उत्पादन की प्रक्रिया चालू रखनी पड़ती है। उत्पादन का अर्थ है प्रकृति में उपलब्ध पदार्थों का मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकने वाले रूपों में परिवर्तन, और इसमें लिए आवश्यक है प्रकृति के क्रियाकलाप की समझदारी अर्थात् विज्ञान। जबकि अस्तित्व के लिए आवश्यक सामाजिक क्रियाकलाप के मित्तिले मेघनासत्र भौतिकी रसायन कृषिशास्त्र और दूसरे वैज्ञानिक विषयों का विकास हुआ। छोट या बड़े समूहों में संगठित लोगो ने इस विज्ञान का उपयोग किया और इस तरह विज्ञान अर्थात् प्राचागिकी (टेक्नाजी) का विकास हुआ और हस्तशिल्प उद्योग के जाजार और हल जमी चीजा का आविष्कार-उत्पादन हुआ। आधुनिक युग में उत्पादन के जिन आवश्यकतों का साधना का आविष्कार हुआ है वे भाप विजली या जाणविक शक्ति द्वारा संचालित हान हैं। बहुत पिछड़े हुए देशों में भी वैज्ञानिक ज्ञान और शिल्प विद्या कुछ हद तक पायी थी। उनमें पाग भी अपना जीवन दशन था चाहे वह कितना ही अपरिष्कृत या अनगुन क्या न हो।

सदियों से जीवन प्राप्त ब्रिटिश भारत में भी वैज्ञानिक मन्त्रि विद्यमान थी। हमका अस्तित्व कृषि और हस्तशिल्प पर निर्भर था, जिनमें विज्ञान विद्याशास्त्र कृषि विज्ञान गणित और भौतिक विज्ञान की जानकारी आवश्यक थी। प्रायः ब्रिटिश भारत का अपना जापधि विज्ञान भी था।

अंग्रेजों के जान के पहले भारत का जापधि और वैज्ञानिक विकास बहुत कम हुआ था। विश्व के बहुत सारे राष्ट्र जिनमें जीवन के पथ पर अग्रसर हुए उनमें मन्त्रिया पहले भारतीयों ने गणित, रसायन और जापधि विज्ञान में पथप्रदर्शक का काम किया। लेकिन मन्त्रियत दमीने भारतोय समाज लगभग उनी गुरा जापधि और मास्त्रुनिक स्तर पर बहुत दिना तक स्थिर रखा और भारतीय जनजातों का समुचित विकास नहीं हुआ। भारतीयों ने हम लगी अवधि में उपनिषद् के

जादूवादी दशन के अनेकानेक भाष्य प्रस्तुत किए। लेकिन प्रकृति विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इनकी देन कुछ विशेष नहीं रही। आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ कर अंग्रेज वैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय ज्ञान के क्षेत्र में भारत को आधुनिक पाश्चात्य उपलब्धियाँ के संपर्क में ले आए।

‘समय आ गया है जब यूरोप एशिया को मध्यता के पुराने ऋण का भुगतान करे। विज्ञान जो पूरब के देशों में जन्मा और पश्चिम के देशों में सपना हुआ, अब सारी दुनिया पर छा जाने वाला है।’<sup>1</sup>

### प्राक् ब्रिटिश भारतीय मस्कृति के बारे में दो गलत धारणाएँ

अंग्रेजों के आने के पूर्व की भारतीय मस्कृति के बारे में दो गलत धारणाएँ प्रचलित थीं। अधःदेशभक्त और अतिराष्ट्रीयतावादी आय समाज ने भारत के अतीत का आदर्श रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने यह भी दावा किया कि आर्यों ने संपूर्ण सामाजिक वैज्ञानिक आध्यात्मिक ज्ञान बहुत पहले प्राप्त कर लिया था, और वह ज्ञान चिरजीवी वंश में सदा के लिए एकत्र है। आय समाज ने कहा कि आधुनिक युग के सभी आश्चर्यजनक आविष्कार-जैसे वैद्यक, एव आधुनिक भौतिकी, रसायन, प्राणिशास्त्र और अभियंत्रण के सारे सिद्धांत और निष्कर्ष वंश में उल्लिखित हैं। आवश्यकता केवल इस बात की है कि ताग वेदों को ठीक तरह से समझें और उनकी समुचित व्याख्या करें।

आय समाजियों ने ऐसे अतिराष्ट्रीयतावादी दावे इसलिए किए कि उन्हें यह समझदारी नहीं थी कि सारा ज्ञान इतिहास द्वारा निर्णीत नियंत्रित है, कि ज्ञान सदा वधनशील ता है। लेकिन इतिहास के किसी क्षण विशेष में वह परिमित और सीमाबद्ध है और इसकी व्यापकता और गहराई लोगों के सामाजिक विकास के स्तर पर निर्भर है। प्राक् ब्रिटिश भारतीय समाज, अपने दीर्घकालीन अस्तित्व की लंबी अवधि में सदा सामाजिक और आर्थिक विकास के निम्न स्तर पर रुका रहा, और इसलिए इसका ज्ञान भंडार आधुनिक ज्ञान भंडार से निश्चय ही छोटा था।

दूसरी तरफ ताड मैकाले एक अन्य प्रकार की गलत धारणा के शिकार थे। उन्होंने सारी भारतीय मस्कृति की घोर अवहेलना की और उस अधविश्वास का पुत्र मात्र माना। उन्होंने कहा कि भारतीय अधिष्ठान में जिस तरह के सिद्धांत हैं उन पर इंग्लैंड के एक देहाती वंश का भी नाम आणगी आर जिस तरह का खगोलशास्त्र भारत में प्रचलित है, उस पर इंग्लैंड में स्कूली लड़कियाँ होंगी। यहाँ का इतिहास लखन नीम पुत्र लख राजाओं की कहानी है जिनका शासनकाल तीस-तीस हजार बरस तक चला, यहाँ भूगोल का अर्थ है चाशनी और मजजून का समुद्र। मैकाले एमी शिक्षा पर गरवारी पैसा खर्च करना गलत समझते थे।

यह भारत की प्राचीन मस्कृति का एकांगी रूप है। यह सही है कि हर पिछड़े हुए देश में अधविश्वास का व्यापक प्रचलन होता है। लेकिन अधविश्वास के मात्र ही हर समाज में वैज्ञानिक ज्ञान के भी कुछ तत्त्व रहने हैं। जैसा पहन कहा जा

चुका है अपने अस्तित्व के लिए उसे चीजा का उत्पादन करना ही होता है, और जिस किसी मात्रा में हो प्रौद्योगिकी और विज्ञान के बिना उत्पादन संभव नहीं। कोई भी समाज इनके बिना जीवित नहीं रह सकता। प्राक् ब्रिटिश भारत के दीर्घ कालीन अस्तित्व और इतिहास से यह स्वतः मिथ्य है कि भारत में वैज्ञानिक ज्ञान था। हर समाज का यह काय है कि वह अतीत की मस्कृति को आलोचनात्मक तौर पर आगे बढ़ावे अर्थात् अतीत की मस्कृति के वैज्ञानिक तत्वों का आत्मसात करे। मकाले ने जो बिना सोचे-समझे भारत की समस्त प्राचीन मस्कृति का नकारा, वह उतना ही अनैतिहासिक था जितना आय समाज द्वारा उस मस्कृति का आदर्श रूप में प्रस्तुत करना।

### प्राक् ब्रिटिश भारत में शिक्षा

हिंदू समाज विभिन्न जातियाँ में बँटा था और इस जाति व्यवस्था में जहाँ प्रत्येक जाति का अपना विनिष्ट सामाजिक काम था ब्राह्मणों को ही धार्मिक सूत्रों के प्रवचन, पूजा-यात्रा करवाने और शिक्षा देने का एकमात्र अधिकार था। जय जातियों के लिए उच्च शिक्षा धार्मिक सूत्रों द्वारा निपिद्य थी और हिंदू राज्य इस व्यवस्था का समस्त प्रतिपालक था। ब्राह्मण टोल विद्यालय और चुन्पाठी जैसे विद्यालय शिक्षानयों में पढा करते थे। हिंदूओं की पवित्र भाषा मस्कृत ही शिक्षा का माध्यम थी और मारा धार्मिक और उच्च धर्मनिरपेक्ष ज्ञान मस्कृत में ही निहित था।<sup>3</sup>

जनसाधारण के लिए हर गाँव और शहर में स्थानीय स्कूल थे जहाँ ग्राम तौर पर लिखना पढ़ना और जाड घटाना सिखाया जाता था। इन विद्यालयों में लड़कों का धार्मिक शिक्षा भी दी जाती थी।<sup>4</sup> इन स्कूलों में ग्रामवर्ग बनियाँ महाजन के लड़के पढ़ते थे। औरना गिम्न जातियाँ एवं किमाना के लिए शायद ही कोई शिक्षा व्यवस्था थी। इस तरह प्राक् ब्रिटिश भारत में शिक्षा का क्षेत्र बहुत ही संकुचित था और ब्राह्मणों के अतिरिक्त जय जागों के लिए शिक्षा नगभग तत्त्व हीन और सारशून्य थी। उच्च शिक्षा पर ब्राह्मणों का एकाधिकार था।

यह शिक्षा ब्राह्मणों द्वारा नियंत्रित और प्रशासित हिंदू समाज की समस्त मस्कृति का विनिष्ट अंग थी। लेकिन इसका उपयोग मूलतः जाति व्यवस्था का सावजनीन मायता और स्वीकृति प्रदान करने और बँदा की मर्यदा एवं उनकी व्याख्या परिभाषित करने में ब्राह्मणों की दक्षता में जाम्या जमान के लिए मायन के रूप में किया गया। इस शिक्षा के माध्यम में मा राय एवं गुर्जन गिम्न और राजा की जाना को जिना गन मानने की भी मीग्य दी गई। बन्तुल डम शिक्षा पद्धति का उद्देश्य यह था कि व्यक्ति समाज की श्रेणीबद्ध मरचना का स्वीकार कर ले और अपने व्यक्तित्व का उमर अजीत रत।

प्राक् ब्रिटिश काल में मुसलमानों के बीच शिक्षा पर किसी बग विरोध का एकाधिकार नहीं था। इसका कारण था इस्लाम का प्रजातांत्रिक स्वरूप। मदर्ग

में कोई भी मुसलमान पढ़ सकता था। लेकिन, चूँकि कुरान अरबी भाषा में लिखा गया था, इसलिए यह विदेशी भाषा मुसलमानों के बीच सारी उच्च शिक्षा का माध्यम थी, कुछ ऐसे स्कूल भी थे जहाँ कुरान के अलावा, दूसरे विषयों की भी पढ़ाई होती थी, जैसे फारसी की, जो इस्लामी मस्जिदों और प्रशासन की भाषा थी।

‘[हिंदू और मुस्लिम] शिक्षा व्यवस्थाओं में काफी मेल था। दोनों व्यवस्थाओं में ऐसी भाषाएँ शिक्षा का माध्यम थीं जो जनसाधारण के लिए पराई थीं, दाना का अपनी धर्मो-मुख प्रकृति से बल मिलता था और अपरिचितनीय प्रभुत्व पर आधारित होने के कारण ये शिक्षा पद्धतियाँ स्वतंत्र अन्वेषण की भावना के प्रतिकूल थीं। लेकिन एक दृष्टि से दोनों पद्धतियाँ काफी भिन्न थीं। हिंदू स्कूल समाज के एक विशिष्ट अधिकार संपन्न वर्ग के लिए थे, लेकिन मुस्लिम स्कूलों में वे सब लोग जा सकते थे जिनकी यह आस्था थी कि भगवान एक ही और मुहम्मद उनके पैगंबर हैं।’<sup>5</sup>

प्रायः ब्रिटिश भारत के इन स्कूलों में छात्रों में न तो व्यक्तित्व का विकास हो सकता था और न बुद्धिवाद का ही। इस शिक्षा का उद्देश्य था छात्रों को कट्टर हिंदू या मुसलमान बनाना अपने विभिन्न धर्मों और इन धर्मों द्वारा समर्थित सामाजिक संरचना का अविवेकी अनुयायी बनाना। आधुनिक शिक्षा की शुरुआत का भारत के लिए ऐतिहासिक महत्त्व है। इसके द्वारा ब्रिटिश शासन ने निश्चय ही एक प्रगतिशील कार्य किया।

### आधुनिक शिक्षा का जन्म

भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का श्रेय विदेशी ईसाई मिशनरियों, ब्रिटिश सरकार और प्रगतिशील भारतीयों को है। ईसाई मिशनरियों ने भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार के लिए बहुत सारे कार्य किए। लेकिन इनकी मूल प्रेरणा थी भारतीय जनता में ईसाई धर्म का प्रचार। उनका यह सच्चा विश्वास था कि भारतीयों के धर्म परिवर्तन का उनका लक्ष्य वस्तुतः सभ्यता के प्रसार प्रचार का लक्ष्य है। उन्होंने हिंदुओं के अनेकेश्वरवाद और उनकी जातिगत विषमताओं पर प्रहार किया, क्योंकि मूलतः ईसाई धर्म एकेश्वरवाद और सामाजिक समानता में विश्वास करता है। ये मिशनरी भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रथम प्रचारक थे। उन्होंने अपने स्कूलों में आधुनिक धर्मनिरपेक्ष शिक्षा तो दी ही, उसके साथ ही ईसाई धर्म की भी शिक्षा दी। मूलतः धर्मनिरपेक्ष इन शिक्षण संस्थाओं में भारतीयों को एक साथ लाकर उनके बीच ईसाई धर्म का प्रचार किया जा सकता था। लेकिन ऐसा हुआ कि जो लड़के इन संस्थाओं में आए उनमें अधिकांश न आधुनिक शिक्षा प्राप्त की, बहुत ही कम लोग ईसाई हुए। इन मिशनरी संस्थाओं का लक्ष्य तो धार्मिक था लेकिन भारतीयों के बीच आधुनिक शिक्षा का प्रचार में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका अदा की।<sup>6</sup>

फिर भी भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार सबने अधिक ब्रिटिश सरकार



ने किया। इसमें मारे दश में स्कूला और कालेजा की स्थापना की जिनमें हजारों की तादाद में भारतीय शिक्षित हुए। इस शिक्षा की सीमाओं और विकृतियों के बावजूद जिनकी भारतीय राष्ट्रवादियों ने आलोचना भी की, भारत में अपनी जरूरतों के लिए हा सही उदारवादी और तकनीकी शिक्षा का प्रसार कर अंग्रेजों ने वस्तुनिष्ठ तौर पर प्रगतिशील भूमिका अदा की।

भारत में अंग्रेजों की जा राजनीतिक-प्रशासनिक एवं आर्थिक आवश्यकताएँ थीं मूलतः उन्हीं के कारण भारत में आधुनिक शिक्षा की गुरुआत हुई। यह महज समय की बात नहीं कि उन्नीसवीं सदी के मध्य में, खासकर लाइ डलहौजी के शासन काल में, भारत में आधुनिक शिक्षा का बड़े पैमाने पर प्रारंभ हुआ। तब तक भारत का बहुत बड़ा अंग्रेजी शासन के अधीन हा चुका था। उन्हीं दिनों ब्रिटेन के औद्योगिक उत्पादन भारत में आने लगे थे और भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार बहुत तजी से बढ़ा, यद्यपि इसका अधिक फायदा अंग्रेजों को ही हुआ।<sup>7</sup>

ब्रिटिश सरकार ने विजित भू-भाग के लिए व्यापक प्रशासन तंत्रव्यवस्था की। इस वृहद् राजनीतिक प्रशासकीय यंत्र के संचालन के लिए शिक्षित व्यक्तियों की बहुत बड़ी तादाद में जरूरत थी। इतने सारे शिक्षित लोग मीघे ब्रिटेन से तो आ नहीं सकते थे। नए प्रशासन के लिए सुयोग्य व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए भारत में स्कूल और कॉलेज खोलना आवश्यक हो गया। महत्वपूर्ण ओहदा पर अंग्रेजों की ओर अधीनस्थ ओहदा पर शिक्षित भारतीयों की बहाली हुई।

भारत के साथ बढ़ते हुए व्यापार और जा याड़े बहुत उद्योग अंग्रेज धीरे धीरे भारत में खोलने लगे उसके लिए भी अंग्रेजी जानने वाले किरानिया, मैनजर और एजेंटों की जरूरत थी।

इन राजनीतिक-प्रशासनिक और आर्थिक आवश्यकताओं ने खास तौर पर ब्रिटिश सरकार का इसके लिए प्रेरित किया कि वह भारत में स्कूल और कॉलेज खोल, जहाँ आधुनिक शिक्षा दी जा सके, क्योंकि ऐसी शिक्षा ही किसी आधुनिक राष्ट्र की आवश्यकताओं का पूरा कर सकती थी। इन शैक्षणिक समस्याओं ने सरकारी और व्यावसायिक कार्यालयों का किर्तनी दिए नई विधिव्यवस्था में पारगट वकील दिए, आधुनिक विज्ञान में प्रशिक्षित डाक्टर दिए, टैक्नीशियन दिए, शिक्षक दिए।

कुछ और कारण थे जिनके चलते ब्रिटिश राजनीतिज्ञों और अंग्रेजी विचारकों ने भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रथम दिया। इन प्रयुक्त अंग्रेजों का यह विश्वास था कि ब्रिटिश समृद्धि मसाले में सर्वश्रेष्ठ और सबसे अधिक उत्पन्न थी और अगर भारत, दक्षिणी अफ्रीका और फिर सारा मसाले सामूहिक तौर पर अंग्रेजीकरण हा जाए ता मसाले के सामाजिक और राजनीतिक एकीकरण का समस्त प्रशस्त हागा। ब्रिटिश शिक्षा और समृद्धि के प्रमाण के लिए अंग्रेजों में मिशनरियाँ जता जाश थी। मकान ब्रिटिश राजनीतिज्ञों के इसी गुट में था

रचनात्मक शक्ति के लिए ये पुराने आदर्शों का काम कर रहे थे, लेकिन नवशिक्षित भारतीय पुराने आदर्शों के बदले व्यक्तिगत आचार में नए बौद्धिक आदर्शों और मानदंडों को अपना सकने में सदा सफल नहीं हुए। उन्होंने यह गलत समझदारी हासिल कर ली कि अब बौद्धिक निषेधों से मुक्ति का अर्थ है आकस्मिक उत्तेजना द्वारा अनुप्रेरित परिचालित होना। उन्होंने मान लिया कि आजादी का मतलब है मदिरापान और अस्वास्थ्यकर यौन संबंधों का रसास्वादन। सामाजिक जीवन की पुरानी सत्तावादी धारणाओं का तिरस्कार करते हुए भी, वे स्वतंत्र सामाजिक धारणा विकसित नहीं कर सके। पुराने सामाजिक पर्यावरण के प्रति उनकी प्रतिक्रिया मूलतः निषेधात्मक थी। उन्होंने पुराने रूपांतर विचारों की अबोधिता को समझा लेकिन सामाजिक और व्यक्तिगत व्यवहार के लिए नए प्रगतिशील सिद्धांतों का निर्माण नहीं कर सके। इससे व्यक्तिगत जीवन में अराजकता और जनजीवन में भ्रम का जन्म हुआ। बुद्धिजीवियों के इस हरावल दस्त की ऐतिहासिक जिम्मेदारी यह थी कि वे लोगों को गतिशील और अधविश्वासपूर्ण सामाजिक अस्तित्व से प्रगतिशील, प्रजातान्त्रिक स्वतंत्र राष्ट्रीय जीवन की ओर ले जाएं लेकिन इसके विपरीत इन लोगों ने साधारण लोगों के सामाजिक और सांस्कृतिक पिछड़ेपन के प्रति अशोचपूर्ण अवज्ञा का भाव अपना लिया। उनके साधारण लोगों के बीच दरार पड़ गई। इन बुद्धिजीवियों को 'गली कहना गुरु' कहा, और साधारण लोगों ने 'गली' और 'राष्ट्रीय भावनाओं से शून्य कहना गुरु' कहा।

एव कालजय प्रामाणिकता को जारी रखना। 'अगर ब्रिटिश राष्ट्र को वास्तविक ज्ञान से अनभिज्ञ रहना होता तो मध्यकालीन दार्शनिक तब मोह, जो उनके अज्ञान को बनाए रख सकता था की जगह वेकन का दशनवाद कभी नहीं जाता। इसी तरह अगर अंग्रेजी शासन का यह उद्देश्य हाता कि भारतीया को अज्ञान के अधकार में रखा जाए ता मस्कृत शिक्षा प्रणाली को ही जारी रखा गया होता।'<sup>10</sup>

वाद में बहुत सारे संगठनान, जैसे ब्राह्मसमाज, रामकृष्ण मिशन, अलीगढ़ आदोलन आर फिर देशमुख, चिपलूणकर, अप्रकार मगनभाई करमचद, कर्वे, तिलक, गाखल, मालवीय, गाधी जीर अन्य लोगो ने औरत मद दोना के लिए एसी शिक्षण सस्थाओ की स्थापना की जिनसे देश में चारा और शिक्षा का प्रसार हुआ। यह सही है कि वे इस शिक्षा प्रणाली के कुछ पहलुओ के आलोचक थे, लेकिन उन्होंने इसका महत्व समझा और कुछ परिवर्तनो के बाद लागी में इसके प्रसार का समर्थन भी किया। कुछ लोगो ने इसकी धर्मपरिपक्ष प्रकृति की आलोचना की और जिन शिक्षण मस्याओ की उन्होंने स्थापना की उनमें उन्होंने धार्मिक शिक्षा का भी प्रवर्ध किया। इस आदोलन के प्रमुख उदाहरण ये पंडित मालवीय द्वारा स्थापित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और मयद अहमद खा द्वारा स्थापित अलीगढ़ विश्वविद्यालय। कुछ लोगो की शिकायत यह थी कि सरकारी और मिशनरी स्कूलों में जो पाठ्य पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं वे भारत के अतीत का अवमूल्यन करती हैं या फिर जीवन की वास्तविकता से उनका कोई संबंध नहीं। इन लोगो ने दूसरे पाठ्य ग्रंथ लिखे जिनसे भारतीया में राष्ट्रीय आत्मसम्मान के भाव का उदय हुआ। लेकिन सवने आधुनिक शिक्षा के सारतत्व—जैसे सत्ता के प्रति इस शिक्षा का विरोध भाव, उदारवादी विचारधारा, व्यक्तिगत स्वातंत्र्य की पुष्टि, अधविश्वास का निराकरण और आधुनिक प्रकृति विज्ञान की पढ़ाई का अपनाया ही। आय समाज विदेशी प्रभावा का लडाकू दुश्मन था, लेकिन उनके (लाजपत राय सेवशन) द्वारा खोले गए स्कूलों और कालजो ने भी आधुनिक शिक्षा पद्धति को स्वीकार किया और केवल इसमें धर्म का पुट डाना, जस यह सिद्धांत कि वेद भ्रातिया से पर है अमोघ अचूक, भ्रमातीत, हालांकि इस तरह का विश्वास जो उदारवादी शिक्षा उन्होंने छुद प्रदान की उसकी आत्मा के प्रतिकूल है। इस नई शिक्षा का मूल तत्व था प्रयाग और निवेक के आधार पर तथ्यो का मूल्यांकन करना।

### आधुनिक शिक्षा के प्रति अस्वस्थ प्रतिक्रिया

जिन लोगो को आधुनिक शिक्षा मिली, उनमें से कुछ लोगो पर इसका बड़ा बुरा प्रभाव पडा। आधुनिक पाश्चात्य सभ्यता के साथ भारतीया के इस प्रथम संपर्क में प्रिजली की ताकत से काम किया। तैरिन कुछ लोगो ने इसके सामानि बौद्धिक और मुनिनलपीयी सारतत्व का आत्मसात नहीं किया। उन्होंने पुरान जाणों और मानदंडों का बहिष्कार किया जा टीर ही नुआ, कपारि व्यक्ति की स्वनय

रचनात्मक शक्ति के लिए ये पुरान आदश जजीर का काम कर रहे थे, लेकिन नवशिक्षित भारतीय पुराने आदर्शों के बदले व्यक्तिगत आचार में नए बौद्धिक आदर्शों और मानदंडों को अपना मकन म सदा सफल नहीं हुए। उन्होंने यह गलत समझदारी हासिल कर ली कि अबौद्धिक निपेधों से मुक्ति का अर्थ है आकस्मिक उत्तेजना द्वारा अनुप्रेरित परिचालित होना। उन्होंने मान लिया कि आजादी का मतलब है मदिरापान और अस्वास्थ्यकर यौन संबंधों का रसास्वादन। सामाजिक जीवन की पुरानी सत्तावादी धारणाओं का तिरस्कार करते हुए भी, वे स्वतंत्र सामाजिक धारणा विकसित नहीं कर सके। पुरान सामाजिक पर्यावरण के प्रति उनकी प्रतिनिया मूलतः निपेधात्मक थी। उन्होंने पुराने रूपांजीर विचारों की अबौद्धिकता का समझा लेकिन सामाजिक और व्यक्तिगत व्यवहार के लिए नए प्रगतिशील सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सके। इससे व्यक्तिगत जीवन में अराजकता और जनजीवन से बिलगाव का जन्म हुआ। बुद्धिजीवियों के इस हरावल दस्ते की ऐतिहासिक जिम्मेदारी यह थी कि वे लोगों को गतिशून्य और अधविश्वासपूर्ण सामाजिक अस्तित्व से प्रगतिशील प्रजातांत्रिक स्वतंत्र राष्ट्रीय जीवन की ओर ले जाएं लेकिन इसके विपरीत इन लोगों ने साधारण लोगों के सामाजिक और सांस्कृतिक पिछड़ेपन के प्रति अशोयपूर्ण अबना का भाव अपना लिया। उनके और साधारण लोगों के बीच दरार पड़ गई। इन बुद्धिजीवियों ने साधारण लोगों का जगली कहना शुरू किया, और साधारण लोगों ने उन्हें 'आंग्लीयता का उपासक' और 'राष्ट्रीय भावनाओं' से शून्य कहना शुरू किया।

पाश्चात्य सभृति ने हानिकर व्यक्तिगत आदतों का समर्थन नहीं किया था और न साधारण लोगों के प्रति दुर्भाव का ही। आधुनिक बुद्धिवाद की महज इतनी ही मांग थी कि जीवन के बारे में बुद्धिवादी दृष्टिकोण और स्वस्थ व्यक्तिगत आचार व्यवहार का विकास हो, अधविश्वास का बहिष्कार हो एवं अतीत के सार सांस्कृतिक विचारों और सामाजिक संगठनों के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाए अर्थात् उन सभृतियों और प्रथाओं में जो कुछ बहुमूल्य हैं उसका आत्मसात किया जाए और आधुनिक समाज के बारे में सही दृष्टिकोण से जो गलत समझा जाए उसका या जिन बातों की अब कोई ऐतिहासिक आवश्यकता नहीं रह गई हो और इसलिए जो परिवर्तित सामाजिक स्थिति की आवश्यकताओं से मेल नहीं खाती हैं उनका परित्याग किया जाए। व्यक्तिगत स्वातंत्र्य, सामाजिक एकरता, और विचारों और मस्याओं के विवेचन के एवमात्र सही मानदंड विवेक-बुद्धि का उपयोग—पाश्चात्य उदारवाद की ये ही आधारशिलाएँ थीं। वानजुद इसके कि सामाजिक अस्तित्व की पूंजीवादी स्थिति के कारण इनमें से कुछ सिद्धांत केवल विचार के रूप में ही प्रतिपान्ति हुए थे और धार्मिक जीवन में अशन ही प्रयुक्त हुए थे।<sup>11</sup> मानव जाति के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में इन सिद्धांतों का प्रतिपादन महान प्रगति का सूचक था और इनका अर्थ या मध्ययुगीन

समाज स आधुनिक पूंजीवाद की दिशा में विकास जा ऐतिहासिक दृष्टि से समाज का उच्चतर रूप है। कुछ शिक्षित भारतीया न स्वस्थ मानसिक और नैतिक समय की अवहलना की, और जा कुछ भी भारतीय था उसकी अविवक्षित उपेक्षा भी। लेकिन इसका एक विशिष्ट कारण था। मध्ययुगीन सामाजिक संरचना पूर्णतः सत्तावादी थी और जाति एवं सामाजिक रीति रिवाज के माध्यम से उसने वैयक्तिक स्वातंत्र्य पर जा नियंत्रण लगाए थे, व इतने दमघोटू थे कि पश्चिमी देशों के सामाजिक इच्छा स्वातंत्र्य संबंधी विचार पद्धति के प्रथम प्रभाव के समय शिक्षित भारतीयों के एक अंश न ही सही किसी भी तरह के समय के विरुद्ध विद्रोह किया। सत्तावादी सामाजिक व्यवस्था एवं विचारधारा द्वारा लगाए गए शारीरिक एवं मानसिक दाना प्रकार व अवरोधा से मुक्ति की उच्चतम कामना के कारण कुछ दिनों—और कुछ दिना के लिए ही यद्यपि सामाजिक प्रतिश्रिया के कारण इस मतिभ्रंश न अतिरिजित रूप लिया—इन भारतीया न पश्चात्य उदारवाद द्वारा समर्थित स्वातंत्र्य सिद्धांत को अराजकतापूर्ण जीवन का सिद्धांत मान लिया। सामाजिक इतिहास के प्रत्येक सश्रमणात्मक काल में इस तरह की अनसोची प्रतिश्रिया हाती ही है।<sup>1</sup>

नई शिक्षा प्रणाली में कुछ ऐसे दाप भी थे जिनके कारण यह प्रतिश्रिया और अधिक तीव्र हुई। नई शिक्षा प्रणाली न अंग्रेजी भाषा का बहुत अधिक महत्व दिया जिसके कारण शिक्षित भारतीय और जनमाधारण के बीच का अंतर बहुत बढ़ा। यह शिक्षा भारतीय जनता के वास्तविक जीवन से बहुत अनग थी और भारतीय राष्ट्र की प्रगति की समस्याओं से इसका कोई संबंध नहीं था। इसने ब्रिटिश शासन को आदेश के रूप में प्रस्तुत किया, उस गौरवपूर्ण माना और भारत के अतीत के आलोचनात्मक वैज्ञानिक विमर्श के बंदने इसका नितांत अवमूल्यन किया। इनने ब्रिटिश इतिहास के अध्ययन पर ज़रूरत से अधिक ज़ार देकर राष्ट्रीय भाव का उद्भव नहीं होने दिया। इन सबके कारण भी शिक्षित भारतीय अपने देश के जनजीवन से विमुख होत गए और शामक राष्ट्र के साथ उनका तालमेल एवं साधारण लागा के प्रति घृणा और उपेक्षा के भाव प्रकट गए।

शिक्षित भारतीया का यह वग पश्चिम की बुद्धिमान्नी और प्रजातान्त्रिक परंपरा को सही तौर पर अपनाते न समर्थ रहा और सामाजिक एवं धार्मिक प्रतिश्रियावाद न समस्त पश्चात्य संस्कृति की अविवक्षित भयना के लिए इस बात का उपयोग किया। इन प्रतिश्रियानादी शक्तिना का पश्चात्य संस्कृति का गलत चित्र उपस्थित करने का मोना मिना। उनके अनुसार यह शरायखारी, अस्वस्थ यौन जीवन एवं उद्धत समाज और राष्ट्र विरागी अहम की पूरी छूट देता है। सामाजिक स्वातंत्र्य और बुद्धिनादी जीवन रक्षण जाधुनिक पश्चात्य संस्कृति के मूल तत्व थे और पुरान प्रतिश्रियानात् पर इनका जा हमला हुआ उसके विरुद्ध अपने न मुद्दु करने के लिए इन गलत प्रचार का महाग किया। यद्यपि स्वातंत्र्य पर लगाए गए पुरान भयनात्मक निषेधा को इन सामाजिक

अधिक उदार और प्रबुद्ध शिक्षा प्रणाली को प्रथम दिया जाए।<sup>15</sup> इस विषय में राजा राममोहन राय का दृष्टिकोण भारतीय राजनीति के उदार पथ का अग्रदूत सिद्ध हुआ। इस उदार पथ में पाश्चात्य शिक्षा का आदर्श रूप में प्रस्तुत किया और इसके लिए वह हमारे राष्ट्रवादी दला (पाल घोष, गांधी और अन्य) द्वारा आलोचना का भागी हुआ।

अतः विचार पद्धतियों का यह मध्यम अंग्रेजीवादी लोगों के पक्ष में निर्णय हुआ। 1835 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्सली ने उनका विचारों का अनुमोदन किया और उन्हें अपनाया। सरकार द्वारा प्रकाशित प्रस्ताव में कहा गया कि ब्रिटिश सरकार का सबसे बड़ा उद्देश्य यूरोपीय साहित्य और विज्ञान का देशी लोगों में प्रचार करना है और शिक्षा पर उपलब्ध धनराशि का सर्वांश केवल अंग्रेजी शिक्षा पर ही खर्च होना चाहिए। साथ ही यह भी कहा गया कि 'आगे से यह सारी राशि अंग्रेजी भाषा के माध्यम से देशी जावादी को अंग्रेजी साहित्य और विज्ञान की शिक्षा देने में खर्च किया जाए।'<sup>16</sup>

कंपनी की सरकार ने अपनी शिक्षा नीति में जनशिक्षा और गांवों के पुराने स्कूलों की पूरी अवहलना की यद्यपि अपनी सीमाओं और अपरिष्कृत रूप में वावजूद यह पाठशालाएँ ही लोगों का प्राथमिक शिक्षा देती थीं। अंग्रेजीवादी लोग अध्यात्मिकी सिद्धांत में विश्वास करते थे जिसके अनुसार गहन धीरे धीरे शिक्षित वर्गों के स्वतंत्र प्रयास से आम जनता तक पहुंच जाएगा।

बंबई के जो लोग शिक्षा के माध्यम के रूप में देशी भाषाओं का समर्थन करते रहे थे उनकी हार हुई। एजुकेशन ग्रांड वे तीन हिंदुस्तानी सदस्य थे जगन्नाथ शंकर सठ, प्रामजी कोवासजी और एन० जाई० मरुवा। अपनी टिप्पणी (मिनिट) में शंकर सठ ने लिखा, 'मराठों में विश्वास है कि पश्चिमी भारत में उपयोगी शिक्षा के माध्यम के रूप में देशी भाषाओं का इस्तमाल अंग्रेजी के मुकाबले अधिक फायदे का है। लोगों को अपनी भाषा में जो कुछ शिक्षा दी जाएगी उस समझन में उन्हें कम कठिनाई होगी, और किसी विदेशी भाषा के माध्यम से उन्हें वह शिक्षा दी जाए तो उन्हें अधिक कठिनाई होगी। मैं अंग्रेजी की शिक्षा का विरोधी नहीं हूँ लेकिन मैं यह मानता हूँ कि यह साधारण लोगों की पहुंच के बाहर है।'<sup>17</sup> बंबई में जो मतभेद चला उसका एक फायदा अवश्य हुआ। कालजस्तर पर अंग्रेजी ही शिक्षा का एकमात्र माध्यम स्वीकृति हुई लेकिन माध्यमिक स्तर पर देशी भाषाओं का इस्तमाल जारी रहा।

बुद्धि डिस्पेंच से लॉर्ड कर्जन के युनिवर्सिटी एक्ट तक

भारत में आधुनिक शिक्षा के इतिहास का प्रथम चरण 1854 में बुद्धि डिस्पेंच के साथ समाप्त हो जाता है। इसमें शिक्षा विषयक मार्लेट मतभेद का सुपरिभाषित विचारों के पारस्परिक विरोध के रूप में प्रस्तुत किया। इस भारतीय शिक्षा में मंगलाकांक्षा के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसमें सरकार के लिए कुछ

उच्चस्तरीय काय निर्धारित किए। भारतीय आलोचको ने वाद मे इसके कायावयन का नाकाफी कहा। डिस्पैच मे कहा गया कि भारत की शिक्षा पद्धति के तीन उद्देश्य थे (1) पाश्चात्य मस्कृति का प्रसार, (2) जन प्रशासन के लिए सुप्रशिक्षित जनसेवक तैयार करना और (3) भारतीय प्रजा को राजा के प्रति अपना कृतव्य निभाने की योग्यता प्रदान करना।<sup>18</sup>

शिक्षा के माध्यम के बारे मे डिस्पैच का निणय था कि (1) कालेज स्तर पर शिक्षा के माध्यम क रूप मे अंग्रेजी का प्रयोग हो, (2) माध्यमिक शिक्षा अंग्रेजी और भारतीय दोनो भाषाओ के माध्यम से दी जानी चाहिए, और (3) आधुनिक भारतीय भाषाओ को प्रोत्साहन देना चाहिए जिससे कालांतर मे वे उच्च शिक्षा के माध्यम के रूप मे प्रयुक्त हो सके।

सरकार के हिंदुस्तानी आलोचका का आक्षेप था कि पिछले दानो निणयो का मही कायावयन नही हुआ और सरकार इसके लिए जिम्मदार थी।<sup>19</sup> डिस्पैच न यह भी कहा कि औरता और जनसाधारण की शिक्षा का सारा उत्तरदायित्व सरकार को लेना होगा, इस तरह पहले के अविमुखी मतरण या निष्पदन के सिद्धांत का परित्याग हुआ। 1854 के वुडस एजुकेशन डिस्पैच न ही भारत मे आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की और इसके बाद शिक्षा का तजी स विकास हुआ।

1880 के बाद यह नई शिक्षा और अधिक तजी स विकसित हुई। विदेशी मिशनरियो सरकार के शिक्षा विभाग और अधिकाधिक बडी तादाद मे प्रगतिशील भारतीया ने बहुत बडे पमान पर शिक्षा प्रसार का काय मगठित किया। इनमे भी, खासकर 1901 मे शिक्षा का सबसे अधिक श्रेय भारतीय व्यक्तिगत पूजी का मिलना चाहिए।<sup>20</sup>

पिछली सदी के सातने दशक मे तिलक और जागरकर ने वाय प्रसिडेसी मे डकन एजुकेशन सोसायटी की स्थापना की जो राष्ट्रवादी भारतीया क शिक्षा सवधी प्रयास और उद्यम का बहुत अच्छा उदाहरण है। सासायटी क सस्थापका ने भारतीय जनता की सामाजिक, राजनीतिक और सास्कृतिक प्रगति मे आधुनिक शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका का समया। वे अपनी सस्था क इद गिद कुछ एस आत्मत्यागी शिक्षित भारतीया को भी मगठित करना चाहत थे जा शिक्षा सवधी एव अयाय राष्ट्रवादी काय कर सकें। बहुत सार देश मक्त भारतीय, जिनमे भारतीय राष्ट्रवाद क प्रमुख नेता तिलक और गोखले भी थे, सासायटी के कार्यो मे मवधित थे।

विजापुरकर की विशेष चर्चा आवश्यक है क्वाकि उन्हान उन्नीसवी सदी के अंत मे तलगाय मे एर राष्ट्रीय स्कूल खाला जा नभवत भारतीया द्वारा किए गए स्वतंत्र शक्षणिक प्रयाग मे पहला था। एम प्रयोगा मे, वाद मे, विद्यापीठा और वर्षा शिक्षा याजनाओ का नाम आता है। यह स्कूल जीवागिक शिक्षा प्रदान करता था। अब तक भारतीय उद्याग काफी विकसित हो चुक था। स्कूल क सस्थापन का उद्देश्य था इन उद्यागो के लिए टक्नीशियन पैदा करना, जिसमे

विदेशी टेकनीशियन पर इन उद्योगों की निर्भरता कम हो जाए। संभवतः इस सस्था का एक उद्देश्य यह भी था कि बढ़ते हुए जातकवादी आंदोलन को टेकनीशियन की ऐसे लोगों की जो आंदोलन के लिए हथियार बना सकें, जो जरूरत की उसे पूरा किया जा सके।

उन्नीसवीं सदी के अंत तक देशी स्कूल व्यवस्था तभी से समाप्त हो चुकी थी। इसके मुख्यतः दो कारण थे (1) राज्य से आर्थिक मदद का अभाव और (2) जो नए स्कूलों में शिक्षा प्राप्त वे वे ही नौकरियां में लिए जा सकते थे। अपने निजी कारोबार में लोगों को नियुक्त करने वाले भी उन्हें ही पसंद करते थे जो आधुनिक शिक्षा प्राप्त थे।

### आधुनिक शिक्षा के विकास का तीसरा चरण, 1921 तक

1901 और 1920 के बीच का काल राजनीतिक उथल-पुथल का काल था। यह बंगाली आंदोलन, माले मिटो सुधार प्रथम विश्वयुद्ध, हार्मरन और असहयोग आंदोलन का युग था। यह भारतीय जनता के राष्ट्रीय जागरण और ऊर्ध्वमुखी राजनीतिक चेतना का युग था जब राजनीति अत्यंत और शिक्षा क्षेत्र में सरकारी कार्यों की अधिकाधिक जांचोचना हुई।

1880 और 1901 के बीच शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से विस्तार हुआ। लार्ड कर्जन और दूसरे लोगों ने गुण की दृष्टि से इस विकास की जांचोचना की। उन लोगों ने कहा कि 1880 के बाद शिक्षा का स्तर काफी नीचे जाया था व्यक्तिगत नियंत्रण वाली शैक्षणिक मस्याएँ ठीक से काम नहीं कर रही थी शिक्षित भारतीय विदेशी मस्कृति को आत्मसात करने में प्रवृत्त अयोग्य थे। और चरित्रहीन व्यक्तित्व के निर्माण की दृष्टि में शिक्षा व्यवस्था का पुनर्गठन होना चाहिए।<sup>1</sup>

दूसरी तरफ भारतीय जातिवाद ने भारतीय जनता की संपूर्ण सांस्कृतिक प्रगति के लिए परिमाणिक विस्तार के महत्त्व पर जोर दिया। उनके अनुसार जरूरत इस बात की थी कि गुण के नाम पर शिक्षा का सीमित न किया जाए वरन् स्वच्छा के आधार पर उच्च शिक्षा का तीव्र विकास हो और जनसाधारण के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रवर्धन हो।

सरकार यह न सोच कि कालज्वाला प्रदान की जान वाली शिक्षा अगर बिल्कुल सर्वोत्तम प्रकार का नहीं है तो वह उत्तर मिद्धागी और हानिकारक भी। फिर वादिक क्षेत्र में हमारे स्नातकों की उपस्थिति का इन शिक्षा पद्धतियों की प्रगति का एतना भार नहीं पड़ा जाता। मरा यथार्थ है कि भारत की अभी की हालत में मारी पाश्चात्य शिक्षा उपयोगी और बहुमूल्य है। मर अनुसार, अभी पाश्चात्य शिक्षा का महत्तर उद्देश्य विद्वत्ता का प्रवर्धन नहीं वरन् पुरानी विचार पद्धतियों की गुनाहों से भारतीय मानव का मुक्त करना है। इस उद्देश्य के लिए मध्यम ही नहीं बल्कि हर प्रकार की पाश्चात्य शिक्षा उपयोगी है।<sup>2</sup>



चालू शिक्षा पद्धति के जालोचक शिक्षण मस्याओं के क्षेत्र में व्यक्तिगत उद्यम और प्रयास के भी पूरे समर्थक थे। घोष वधुजी और पाल जैसे जतिवादियाने इस पद्धति पर इसलिए आघात किया कि इससे जराष्ट्रीय भावनाओं का विकास होता था। उनकी आलोचनाओं की चर्चा बाद में की गई है।

लगभग सावभौमिक भारतीय विरोध के बावजूद, 1904 का इंडियन युनिवर्सिटीज एक्ट पास हुआ गया। इसने कई प्रतिबंध लगाए और साथ ही किसी विश्वविद्यालय से किसी कालेज के संबद्ध होने की शर्तों को और अधिक कड़ा कर दिया। इसके अनुसार, विश्वविद्यालय की परिषद द्वारा बनाए जाने वाले नियमों के बारे में भी सरकार को बहुत सारी शक्तियाँ प्रदान की गईं। विश्वविद्यालय के पापदा में अधिकांश का नामजद करने का अधिकार भी सरकार का मिला और कालेजों को संबद्ध असंबद्ध-करने के प्रश्न पर सरकारी स्वीकृति आवश्यक हो गई। इसके जालोचकों ने कहा कि एक्ट के अनुसार विश्वविद्यालय महज सरकारी विभाग जैसे हुए थे।

विश्वविद्यालयों को आर्थिक सहायता देने वाले मिडिल का 1904 और 1908 के बीच का पुनरीक्षण हुआ उससे शिक्षा प्रसार में एक और गतिरोध आया। इससे स्कैंडनी स्कूलों के विस्तार पर बुरा असर पड़ा। जनत, गाँवले ने शिक्षा को अनियंत्रित बनाने के सिलसिले में जो विधेयक प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्नाकार्टा कहा गया उसकी हार के कारण भारत की साधारण जनता का शिक्षित करने के सपने फिलहाल चूर-चूर हो गए।

शिक्षा संबंधी सरकारी नीति व प्रति बढ़त हुए जमतपोष के कारण भारतीयों ने यह साचना शुरू किया कि शिक्षा विभाग पर उनका अपना नियंत्रण होना आवश्यक है। कुछ नेताओं ने नए स्वतंत्र शिक्षा संबंधी प्रयोग की भी बात मंची।

### चौथा चरण 1921-1939

1921 में द्वितीय शासन पद्धति व जतगत शिक्षा विभाग भारतीय मंत्रियों का मीपा गया। इस व्यवस्था में प्रांतीय सरकारों का शिक्षा प्रसार संबंधी योजनाओं का स्वीकार करने और उन्हें लागू करने की अधिक जाजानी थी। परिणामस्वरूप 1921 के बाद शिक्षा का तेजी से विस्तार हुआ।

आर्थिक साधनों की कमी के कारण यह विकास शीघ्र धीमा पड़ गया। 1901-21 के बीच भारत सरकार से मिलने वाली विशिष्ट राशि की प्राप्ति रुक जाना में और विश्व आर्थिक मंदी से उत्पन्न आर्थिक कठिनाइयाँ के कारण शिक्षा प्रसार की बड़ी योजनाओं का काम बढ़ाना कठिन हो गया। फिर भी 1921 और 1937 के बीच शिक्षा का काफी विस्तार हुआ। पृष्ठ 128 पर नीचे लिखे गए आँकड़ों से यह बात स्पष्ट हो जाती है।

## शिक्षा सबंधी आंकड़े 1921-22 और 1936-37

संस्थाओं का प्रकार	संस्थाओं की संख्या		विद्यार्थियों की संख्या	
	1921-22	1936-37	1921-22	1936-37
विश्वविद्यालय	10	15	आंकड़े 9,697 उपलब्ध नहीं	
कला महाविद्यालय	165	271	45,418	86,273
व्यावसायिक महाविद्यालय	64	75	13,662	20,645
माध्यमिक विद्यालय	7,530	13,056	11,06,803	22,87,872
प्राथमिक विद्यालय	1,55,017	1,92,244	61,06,752	10,224,288
विशिष्ट विद्यालय	3,344	5,647	1,20,925	2,59,269

## माध्यमिक प्राप्त संस्थाओं

का योग	1,66,130	2,11,308	73,96,560	1,28,88,044
ऐसी संस्थाएँ जिन्हें माध्यमता प्राप्त नहीं थी	16,322	16,647	4,22,165	5,01,530
मपूर्ण योग	1,82,452	2,27,955	78,18,725	1,33,89,574

(ऊपर के आंकड़े बर्मा को छोड़कर ब्रिटिश भारत के लिए हैं।)

शिक्षा विभाग पर भारतीय नियंत्रण के अतिरिक्त शिक्षा प्रसार के कुछ अन्य कारण भी हैं। इन अवधि में लोगों के बीच अभूतपूर्व सामाजिक और राजनीतिक चेतना का उदभव इसका कारण है।<sup>3</sup>

जनसाधारण की शिक्षा का तर्जनी से विस्तार होना इस युग की महत्वपूर्ण घटना है। अधिकांश प्रान्तों में अनिवाय शिक्षा के विधायक पारित हुए और जहाँ भी इस तरह के अधिनियम थे वहाँ इनका क्रमावश कार्यान्वयन भी हुआ। 1922 और 1927 के बीच प्राथमिक शिक्षा का जो विकास हुआ उसका पता नीचे के आंकड़ों से लगता है।

## प्राथमिक शिक्षा सबंधी आंकड़े

	1921-22	1926-27
प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	1,55,017	1,84,829
प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षार्थियों का संख्या	61,09,752	81,07,927
प्राथमिक विद्यालयों पर व्यय (मी.घा.)	4,94,69,080	6,75,14,802

1927 के बाद प्राथमिक शिक्षा के विभाग का गति रुक जान लगी। बाद के वर्षों में जो आर्थिक संकट आया वह इसका एक प्रमुख कारण था। राजस्व चलते प्राथमिक शिक्षा के प्रसार को बहुत भारी बाधाएँ छाड़ देने पड़ीं। इस विभाग की गति के मंदम ह्रा जानना एक कारण यह भी था कि हाटांग कमिटी ने यह

मिफारिश की कि प्राथमिक शिक्षा के विस्तार से अधिक उसके संगठन पर जोर दिया जाय। गैर सरकारी तत्वों ने इस अनुशंसा की जालोचना ही की, क्योंकि व साक्षरता और शिक्षा की परिमाणात्मक वृद्धि के समर्थक थे। 'शिक्षा की तो मूसलाधार हानी चाहिए न कि बूदाबूदी।'

दूसरे देशों के उदाहरण से ही नहीं, बरन उन देशों की शिक्षा के इतिहास में भी स्पष्ट है कि जब शिक्षा मजबूती सुधारों के पहले शिक्षा का तीव्र प्रसार होना चाहिए। जनशिक्षा के संदर्भ में इस महान सत्य को भारत ने कभी नहीं पहचाना है कि बीबी प्रगति काई प्रगति नहीं है।'<sup>4</sup>

1921 और 1937 के बीच प्रमुख भारतीय शिक्षाविदों और भारतीय राष्ट्रवाद के जगन्नी नेताओं ने शिक्षा विषयक बहुत सारे प्रयोग किए। कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती कलेज द्वारा गठित एम० एन० डी० टी० बी०एम विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ जामिया मिलिया गुजरात विद्यापीठ और तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ इनमें प्रमुख थे।

1937 के बाद तीन ऐसी बातें हुईं जिनका भारतीय जनजीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ा (1) 1937 में प्रांतीय स्वायत्त शासन की स्थापना (2) 1939 में द्वितीय महायुद्ध की शुरुआत, और (3) अगस्त 1942 में भारत में जो राजनीतिक बवंडर आया, और उसके बाद की घटनाएँ।

प्रांतीय स्वशासन से प्राथमिक शिक्षा के विकास को बल मिला। लेकिन कुछ प्रांताओं में कांग्रेसी मंत्रियों द्वारा गांधीवादी विचारधारा पर आधारित विद्यालयों की योजना जैसे जो प्रयोग किए गए उनकी कुछ बुद्धिवादियों और गैर हिंदुओं ने बड़ी बटु आलोचना की। जब दो घटनाओं का भी भारतीय जनता के आर्थिक राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर बड़ा गहरा असर पड़ा।

### भारत में आधुनिक शिक्षा की आलोचना के मूल तत्व

भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ अंग्रेजी शासन की ऊपर गिनाइ गई जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया। अतः इसकी प्रगति काफी जबरदस्त भी रही और भारतीय जनता की उन्नति की दृष्टि में काफी अमत्तापजनक। आधुनिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश शासनतंत्र को अंग्रेजी के जानकार कार्यकर्ता देना, इसलिए जनसाधारणों की शिक्षा इस पूरी अवधि में बंद रह गई।

सो साल से ऊपर के ब्रिटिश शासन के बाद भी 1911 में भारतीय जनता की 94% भाग निरक्षर थे और 1931 में 92% भाग। प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षार्थियों की कुल संख्या 1934-35 में केवल 13.5 मिलियन थी। अर्थात् कुल जनसंख्या का 4.9 प्रतिशत। इनमें प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों का भाग केवल 1.5 प्रतिशत ही था। इन सालों के बाद पढ़ने वाले बच्चों का भाग 1.5 प्रतिशत से बढ़कर 3.5 प्रतिशत हो गया।<sup>5</sup>

'प्राथमिक पाठशालाओं में अधिकांश बच्चे तीन-चार वर्षों के बच्चे शिक्षा

पाते और अधिकांश समय हर पांच में चार बालक सबसे नीचे की कक्षा में ही पड़े रहते हैं। फलस्वरूप, शिक्षा की स्वल्प अवधि के अंत में प्रायः फिर निरक्षरता की ओर अग्रसर होने की प्रवृत्ति रहती है।<sup>6</sup>

जनसाधारण की निरक्षरता और तज्जय जनान के कारण सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रगति अवरुद्ध रही।

1941-42 में उच्च शिक्षा के मस्याना के अध्ययनों की संख्या 1,59,254 थी सारी जावादी का लगभग 0.5 प्रतिशत। पिछड़े हुए देश में आर्थिक विकास के लिए तकनीकी विषयों के जानकारों की आवश्यकता होती है। 1934-35 में इंजीनियरिंग, कृषि और वाणिज्य के स्नातक शिक्षार्थियों की संख्या केवल 960 थी। सबसे अधिक अभाव तकनीकी शिक्षा के ही क्षेत्र में था कृषि वाणिज्य और अभियानिकी जैसे क्षेत्रों में अमरीका के क्षीण आवादी वाले आइसोवा जैसे राज्य में भी जहाँ की जावादी ब्रिटिश भारत की जावादी का एक प्रतिशत मात्र है, भारत से अधिक छात्र हैं।<sup>7</sup>

राष्ट्रवादियों ने आधुनिक शिक्षा की इसलिए भी आलोचना की कि वह अत्यधिक व्ययसाध्य है। अत्यंत निम्न भारतीय जनता के लिए खर्चीली शिक्षा का भार उठाना मुश्किल था। इसीलिए लाइव कंजनों के त्रिस्वविद्यालय सुधार का, जिनके अनुसार शिक्षा अधिक फलदायक लेकिन साथ ही अधिक व्ययसाध्य भी हो रही थी व्यापक विरोध हुआ। भारतीय राष्ट्रवादियों को यह संदेह भी था कि बार्ड कंजनों शिक्षा को समय और सक्षम बनाने के नाम पर उसे सीमित तकुचित करना चाहते हैं क्योंकि कंजनों का मत था कि शिक्षा के प्रसार से राजद्रोह की भावना का जन्म होता है। और भारतीयों ने भी इस बात की उर्चा की थी कि ब्रिटिश अग्रसर राजनीतिक विभाजन के लिए अग्रणी शिक्षा के प्रसार का जिम्मेदार मानते थे। 'भारत में बहुतरे अग्रसरों का मंचमुच यह विश्वास था कि शिक्षा से जनजाती बढ़ेगा और प्रशासन का साथ अधिक कठिन हो जाएगा या (शिक्षा प्रसार के विरुद्ध) मूल तक जाँचेंगे या।'<sup>8</sup> व्ययसाध्य होने के कारण उच्च शिक्षा अधिकांश भारतीयों की पहुँच से बाहर थी।

भारतीय राष्ट्रवादियों ने इन बातों की भी आलोचना की कि शिक्षा पब्ली सरकारी उजट की राशि बहुत कम थी। शिक्षा सदा अन्य सरकारी सजाओं की तुलना में उपभिता सी रही। सरकारी जाय का जोमतन एक तिहाई मना पर रखे जाता था, लेकिन शिक्षा के मद में बहुत कम राशि ही खर्च होती थी।

अन्य कई मुद्दों पर भी राष्ट्रवादियों ने आधुनिक शिक्षा की आलोचना की। उनके अनुसार इन शिक्षा का भारतीय जनजीवन में कोई संबंध नहीं था। इससे भारतीय जीवन की मही तकनी तहाँ मिलती थी, न सामाजिक गुणों की ओर न भारतीय समाज के आर्थिक और साम्प्रतिक पिछड़ेपन के मही कारणों की। इनसे भारतीय समाजों के प्रस्तुतीकरण और भारतीय दृष्टिकोण में उनसे समाधान का कोई प्रयाग नहीं किया। इनसे भारतीय इतिहास का भ्रष्ट विवरण

प्रस्तुत किया, भारत के ब्रिटिश विजेताओं का गुणगान किया और अंग्रेजों का भारत को मध्य बनाने वाला बतलाया। इसमें राष्ट्रभिमानी और आत्मसम्मान के भाव का दुगुण करने की वाशिश की। फिर, चकि अंग्रेजों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विदेशी भाषा अंग्रेजी के माध्यम से यह शिक्षा दी जाती थी, इसलिए ज्ञान का शीघ्र और मध्यक स्वागीकरण संभव नहीं हुआ और शिक्षित भारतीयों और भारत के साधारण लोगों में दुराव आता गया। भारतीय राष्ट्रवादियों ने शिक्षाव्यवस्था की रीति और उसके मगठन की भी आलोचना की।

जनशिक्षा की उपेक्षा से स्पष्ट है कि भारत में नए शासक इस देश के सामाजिक उत्थान के लिए यहां नहीं आए थे। अंग्रेजों का इतना अधिक महत्व देने का कारण यह था कि वे स्वभावतः यहीं चाहते थे कि शासन में कम खर्च हो। हर किरानी और सरकारी अफसर को इंग्लैंड से बुलाना पड़े इससे जासमान होता कि यहीं निम्न श्रेणी के अफसरों का बग तयार किया जाए।

इस शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य था मध्यमवर्गीय भारतीय नौजवानों पर ब्रिटेन के गरव और समृद्धि की छाप डालना और उन्हें विदेशी अफसरशाही के सुयोग्य नौकर बनाना। यह पक्षेय शिक्षा का चरम रूप था पक्षेय शिक्षा जो पाठ्यक्रम में अंग्रेजी वाक्य रचना, शेक्सपियर के छंद शान्त्र और अंग्रेज राजा रानिया के शासन काल की तिथियां पर जोर देती थी।<sup>9</sup>

‘गुरु स ही भारत की अंग्रेजी सरकार ने जनशिक्षा का रूपायित और नियंत्रित करने की चेष्टा की है दश में अपनी राजनीतिक मत्ता की नींव मजबूत करना उनका लक्ष्य रहा है।’<sup>10</sup>

भारत के राष्ट्रवादी दलों ने राष्ट्रीय पद्धति पर समानांतर शिक्षा व्यवस्थाएँ मगठित करने की जनक कोशिशें की, लेकिन उन्हें विफलता में मिली।

राष्ट्रीय शिक्षा की योजनाओं की असफलता के कारण ही वे। सरकारी एवं निजी दोनों प्रकार की नौकरियों में वहाली के लिए सरकारी मायता प्राप्त विश्वविद्यालयों की उपाधियां जरूरी थीं, इसलिए स्वतंत्र राष्ट्रीय शिक्षा मस्वाजा में, जो सरकारी विश्वविद्यालयों से संबद्ध नहीं थी, कम ही छात्र आए। गांधी द्वारा गुरु किए गए गुजरात विद्यापीठ का अंत उनका एक उदाहरण है। कांग्रेस में रचित राजन वाले नियामना भी इस विद्यापीठ के म्नातकों को वाय विश्वविद्यालय में स्नानकों के समकाल नहीं मानते थे।

जिन सिद्धांतों के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा की योजना बनाई जा सकती है, उनमें विषय में भारतीय राष्ट्रवादियों में सहमति भी नहीं थी। मालवीय, गांधी और जयममामजिया जैसे कुछ लोगों ने सरकारी स्कूलों और कालों में दी जाने वाली शिक्षा के धर्मनिरपेक्ष चरित्र की आलोचना की। उन लोगों ने धर्म (हिंदुओं के लिए गीता और मुसलमानों के लिए कुरान) की शिक्षा का अनिवार्य अंग माना। जयपुरलान जैसे उतासना नृपत धर्मनिरपेक्ष शिक्षा का महत्व दिया,

पाते ह जोर अधिकांश समय हर पाच म चार बालक सबसे नीचे की कक्षा म ही पड़े रहते हैं। फलस्वरूप शिक्षा की स्वल्प अवधि के जत म प्रायः फिर निरक्षरता की ओर अग्रसर हान की प्रवृत्ति रहती है।<sup>6</sup>

जनसाधारण की निरक्षरता और तज्जय ज्ञान के कारण सामाजिक राज नीतिक और जायिक प्रगति अवरुद्ध रही।

1941-42 म उच्च शिक्षा क मस्याना के अध्ययताओं की संख्या 1,59,254 थी, सारी जावादी का लगभग ०.5 प्रतिशत। पिछड़ हुए दश के जायिक विकास क त्रिए तकनीकी विषयो के जानकारा की आवश्यकता हाती है। 1934-35 म इंजीनियरिंग, कृषि और वाणिज्य के स्नातक शिक्षार्थियों की संख्या केवल 960 थी। सबसे अधिक अभाव तकनीकी शिक्षा के ही क्षेत्र में था, कृषि वाणिज्य और अभियांत्रिकी जस क्षेत्रा म अमरीका के क्षीण जावादी वाले आइयाया जस राज्य म भी जहा की जावादी ब्रिटिश भारत की जावादी का एक प्रतिशत मात्र है, भारत से अधिक छात्र ह।<sup>7</sup>

राष्ट्रवादियों ने आधुनिक शिक्षा की इसलिए भी आलोचना की कि वह अत्यधिक व्ययसाध्य है। अत्यंत विधन भारतीय जनता के लिए खर्चोली शिक्षा का भार उठाना मुश्किल था। इन्हींलिए लाड कजन के विश्वविद्यालय सुधार था, जिनके अनुसार शिक्षा अधिक फलात्मादक लेकिन साथ ही अधिक व्ययसाध्य भी हा रही थी, व्यापक विरोध हुआ। भारतीय राष्ट्रवादियों का यह मद्दह भी था कि लाड कजन शिक्षा का समर्थ और महाम बनाने के नाम पर उस सीमित मद्दुचित करना चाहते हैं क्योंकि कजन का मत था कि शिक्षा का प्रसार से राजद्रोह की भावना का जन्म हाता है। पर भारतीयों ने भी इस बात की चर्चा का था कि ब्रिटिश अफसर राजनीतिक विभाजक लिए अग्रणी शिक्षा का प्रसार का निम्नस्तर मानते थे। भारत म बहुतर अफसरों का मसमुच यह विन्यास था कि विभाजक अशांती बढ़ेगा और प्रशासन का साथ अधिक कठिन हा जाएगा। या (शिक्षा प्रसार का विरोध) मूल तर्क जायिक था।<sup>8</sup> व्ययसाध्य हान के कारण उच्च शिक्षा अधिकांश भारतीयों की पहुंच से बाहर था।

भारतीय राष्ट्रवादियों ने इस बात की भी आलोचना की कि शिक्षा अवधी गरतारी बजट की राशि बहुत कम थी। शिक्षा का जन्म गरतारी तज्जय का तुलना म उपक्षिता भी रही। गरतारी जाय का जीमत्तन एक विहाइ मना पर मत्र हाता था, लेकिन शिक्षा के मद म बत कम राशि हा खर्च हाता थी।

जय कद मुद्रा पर भी राष्ट्रवादियों ने आधुनिक विभाजक की आलोचना का। उनके अनुसार इस विभाजक भारतम जनभावना काई मसज नहा था। मना भारतम नीयन की तही जारी रहा भिन्ती थी, न राजनीतिक गुप्तता का जोर न भारतीय समाज का जायिक और सामाजिक पिछड़ेपन का मस्य कारण थी। इस म भारतीय समस्यारा का प्रस्तुतीकरण और भारतम दृष्टिकान न काई समाज का काई प्रभाव नहा सिपा। इस भारतम दीक्षा का विद्वान विवरण

प्रस्तुत किया, भारत के ब्रिटिश विजेताओं का गुणगान किया और अंग्रेजों को भारत का मध्य बनाने वाला बतलाया। इन राष्ट्रप्रेमियों और आत्मसम्मान के भाव का दुबल करने की कोशिश की। फिर, चकि अंग्रेजों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विदेशी भाषा अंग्रेजी के माध्यम से यह शिक्षा दी जाती थी, इसलिए ज्ञान का शीघ्र और सम्यक स्वांगीकरण संभव नहीं हुआ और शिक्षित भारतीयों और भारत के साधारण लोगों में दुराव आता गया। भारतीय राष्ट्रवादियों ने शिक्षाव्यवस्था की रीति और उसके संगठन की भी आलोचना की।

‘जनशिक्षा की उपेक्षा से स्पष्ट है कि भारत के नए शासक इस देश के सामाजिक उत्थान के लिए यहाँ नहीं आए थे। अंग्रेजों को इतना अधिक महत्त्व देने का कारण यह था कि वे स्वभावतः यही चाहते थे कि शासन में उनका हाथ रहे। हर किरानी और सरकारी अफसर को इंग्लैंड से बुलाना पड़े इससे आसान होता कि यहाँ निम्न श्रेणी के अफसरों का वर्ग तैयार किया जाए।’

इस शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य या मध्यमवर्गीय भारतीय नौजवानों पर ब्रिटेन के गौरव और समृद्धि की छाप डालना और उन्हें विदेशी अफसरशाही के सुयोग्य नौकर बनाना। यह पेशेवर शिक्षा का चरम रूप था पेशेवर शिक्षा जो पाठ्यक्रम में अग्रणी वाक्य रचना, लेखन, लेखन और अंग्रेजों राजा रानिया के शासन काल की विधियों पर जोर देती थी।<sup>9</sup>

‘यूरोप ही भारत की अंग्रेजी सरकार ने जनशिक्षा का रूपान्तरित और नियंत्रित करने की चेष्टा की है देश में अपनी राजनीतिक मत्ता की नींव मजबूत करना उनका लक्ष्य रहा है।’<sup>10</sup>

भारत के राष्ट्रवादी दल ने राष्ट्रीय पद्धति पर समानांतर शिक्षा व्यवस्थाएँ संगठित करने की अनेक योजनाएँ की, जिनमें उन्हें विशेष सफलता नहीं मिली।

राष्ट्रीय शिक्षा की योजनाओं की असफलता का कारण भी ये थे। सरकारी एवं निजी दोनों प्रकार की नौकरियों में बहाली के लिए सरकारी मायता प्राप्त विश्वविद्यालयों की उपाधियाँ जरूरी थीं, इसलिए स्वतंत्र राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं में, जो सरकारी विश्वविद्यालयों से संबद्ध नहीं थीं, रुक ही छात्र आए। गांधी द्वारा शुरू किए गए गुजरात विश्वविद्यालय का जन्म इसका एक उदाहरण है। कांग्रेस में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों भी इस विश्वविद्यालय के स्नातकों का बाय विश्वविद्यालय के स्नातकों के समान ही मानते थे।

जिन सिद्धांतों का आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा की योजना बनाई जा सकती है, उनसे विपरीत भारतीय राष्ट्रवादियों में सहमति भी नहीं थी। मातृवीय, गांधी और जाधुनिकवादियों जैसे कुछ लोगों ने सरकारी स्कूलों और कालों में दी जाने वाली शिक्षा का घमनिरक्षण चर्चित की जालाचता की। उन लोगों ने धर्म (हिंदुओं का विशेष गौरव और मुसलमानों के लिए कुरान) का शिक्षा का अनिवार्य अंग माना। जवाहरलाल जैसे नेताओं ने पूणत घमनिरक्षण शिक्षा को महत्त्व दिया

क्याकि शिक्षा का आधार बौद्धिक हाना चाहिए जबकि हम जास्था जीर जनदृष्टि पर आधारित ह।

सरकारी शिक्षा के धमनिरपक्ष चरित्र पर जाघात कर गाधी जैसे नेताओं न उस शिक्षा के प्रगतिशील तत्वों पर हमला किया। पाठ्यक्रम में धार्मिक शिक्षा का भी स्थान हो, इस तरह का उनका सुझाव प्रतिक्रियावादी था। गाधी ने विद्या मंदिर याजना को विकसित किया। उन्होंने इसको शिक्षा की बहुशिल्पीय योजना कहा, क्योंकि इसमें व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए वैदिक और प्रायोगिक शिक्षा दोनों का स्थान था। बहुशिल्पीय शिक्षा का सिद्धांत तो प्रगतिशील था लेकिन जब यूरोप में इस शिक्षा का सिद्धांत निरूपित हुआ, तो उसका जन्म था आधुनिक वैदिक ज्ञान और आधुनिक उद्योग का समन्वय। लेकिन गाधी ने आधुनिक शिक्षा पर धम का मुलम्मा चढ़ाया, और उस जगत हुए युग के हस्तपिंप से जोड़ दिया। आधुनिक शिक्षा आधुनिक सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में जन्मी थी और उनका पथप्रदर्शन कर रही थी। गाधी का प्रयाग पुरातन शिल्पी और आधुनिक शिक्षा का जनतिहासिक मयोग प्रस्तुत करता है। जास्तविकता और जनतिहासिकता पर आधारित ऐसी शिक्षा मंत्री याजनाओं का व्यापक समन्धन नहीं मिल सकता था और न मिला। फिर जिस तरह की शिक्षा का प्रथम आधुनिक स्कूलों में था, उसकी राष्ट्रवादी जाओचना काफी सही थी।

जनशिक्षा पर भी भारतीय राष्ट्रवादियों का ध्यान गया। स्पष्ट है कि जनान रत निरक्षर राष्ट्र ठास प्रगति नहीं कर सकता और शिक्षा की दौड़ में अजस्य पीछे पड़ जाएगा। इसलिए हम सत्रम प्राथमिक शिक्षा के पूर विस्तार और जनसाधारण के लिए प्राथमिक स्कूलों की जागरण और व्यापक व्यवस्था की नितात आवश्यकता है। इस जाय में निम्नी ही तरहागी बुनियाद राष्ट्र में अपना सही स्थान प्राप्त करना हमारे लिए उत्तना ही कठिन होगा।<sup>31</sup> राष्ट्र की तरवनी के लिए जनशिक्षा की स्पष्ट जास्यकता बताइ गइ और गार प्रगतिशील भारतीयों ने इस दशा में अधिवाधिक प्रयास किए। निरक्षरता का समाप्त करन के लिए जाओलना का मगठन हुआ। छात्र दल साधारणता के प्रयास के लिए गर्मी की छुट्टियां देहाता में जातात थे। इसी उद्देश्य से शहरों में मजदूरों के लिए रात्रि पाठशालाओं का प्रथम किया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस, मांगल सत्रिम लीग, जगिल भारतीय विद्यार्थी गणठा और एनी जय बन्त गारी गस्था हैं। इस दिशा में काम किए। लेकिन यह इनका महद जायकन था कि गार प्रयास केवल ममम्मा का छूकर रह गए।

### आधुनिक शिक्षा के प्रगतिशील तत्व

ऊपर गित पुरादशा की गथा है जा पुरी है उात जासूद नागत में आधुनिक शिक्षा की पुरातत प्रिटिन जासतत है प्रगतिशील जाय है। यह गित में समनिरपक्ष। उगारजात जा प्रथम प्रिटिन शिक्षा का गित है पद्धति के निरसन गति



और धर्म का ख्याल किए बिना सर्वसुलभ थी। सर्वोपरि, इनमें भारतीयों के लिए आधुनिक पाश्चात्य सभ्यता के बुद्धिवादी और प्रजातांत्रिक विचारों के विशाल भंडार का द्वार खोल दिया। यह मात्र नयोंग नहीं कि भारतीय राष्ट्रवाद के प्रारम्भिक और परवर्ती नेता सभी शिक्षित वर्गों से आए।

‘उदीयमान पीढ़ी ने यूरोपीय शिक्षा का विस्मयकारक ग्रहणशीलता के साथ आत्मसात किया। इस पीढ़ी के लोग तेजी से राष्ट्रवादी, गणतन्त्रवादी और समाजवादी हुए।

‘कैम्ब्रिज मजिनी, काराथ, पार्नेल मिल का उन्होंने अपने शिक्षक और नायक के तौर पर स्वीकार किया। अंग्रेजी सरकार ने उन्नीसवीं सदी के यूरोपीय साहित्य की पढ़ाई की भारतीय स्कूलों में मनाही कर दी। लेकिन काफी देर हा चुकी थी। जो प्रक्रिया शुरू हो गई थी उस रोकना संभव नहीं था, और इस बिंदु पर इस प्रक्रिया का नई दिशा मिली। यूरोपीय संस्कृति का घनिष्ठ परिचय प्राप्त हो गया था और उसकी अधस्वीकृति समाप्त हो चुकी थी। रस्किन, कार्लाइल टाल्सटाय आदि जिन यूरोपीय लेखकों ने स्वयं यूरोप की आलोचना की थी उनकी इस दिशा में यह महत्वपूर्ण भूमिका रही।’

शिक्षित भारतीयों ने अपने अंग्रेजी ज्ञान के कारण यूरोप के राजनीतिक साहित्य से जो अतिवादी राजनीतिक विचार ग्रहण किए उनके प्रचार में अंग्रेजी सरकार प्रायः मन्त्रस्त हो जाती थी। इसने प्रशासनिक कारवायों की ओर भारत में विदेशी साहित्य के आगमन पर रोक लगाई। इटालियन राष्ट्रवाद के नेता मजिनी के जीवनचरित्तें सर्वथी साहित्य के भारत आन पर निषेध लगा। कुछ खास किस्म के आधुनिक यूरोपीय विचारों के आगमन पर सरकारी प्रतिषेध के बावजूद यह तो मानना ही होगा कि अंग्रेजी ज्ञान के कारण ही भारत में आधुनिक यूरोपीय साहित्य का अध्ययन संभव हुआ। सब प्रकार के आधुनिक यूरोपीय विचारों में उन्मुक्त मनष की आजादी के लिए भारतीय राष्ट्रवाद ने सदा मघप किए।

इस तरह आधुनिक शिक्षा की विरोधी, द्वेष भूमिका रही। इसकी गुरजानत तो की गई भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए और भारत पर विदेशियों के आधिपत्य का मजबूत करने के लिए, लेकिन इन शासन के विरुद्ध मघप में भारतीय राष्ट्रवाद का इस शिक्षा पद्धति से मदद भी मिली।

### भारतीय राष्ट्रवाद आधुनिक शिक्षा का परिणाम नहीं

अन्य ब्रिटिश राजतन्त्राजों की तुलना में दावा किया है कि भारतीय राष्ट्रवाद भारत में अंग्रेजों द्वारा लाई गई आधुनिक शिक्षा का परिणाम है। उन्होंने इन बातों पर ज़ोर दिया कि आधुनिक शिक्षा ने भारतीयों का पाश्चात्य लेखकों द्वारा प्रतिपादित स्वतन्त्रता के अधिकारों से परिचित कराया और इसलिए भारतीय जनता में राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य का इच्छा पैदा हुई। शिक्षा का प्रातिगोत्र भूमिका का

मानते हुए भी यह समझ लेना गलत होगा कि भारतीय राष्ट्रवाद इस शिक्षा की मतति है।

भारतीय राष्ट्रवाद का जन्म वस्तुतः नई सामाजिक-भौतिक स्थितियों के कारण हुआ, उन नई सामाजिक शक्तियों के कारण जो अंग्रेजों की भारत विजय के बाद पदा हुईं। यह विभिन्न स्वार्थों के वस्तुनिष्ठ संघर्ष का परिणाम था— अंग्रेजों का स्वार्थ जो भारत का राजनीतिक और आर्थिक तौर पर गुलाम बनाए रखने में था और भारतीय जनता का हित जो ब्रिटिश शासन से मुक्त भारतीय समाज के स्वतंत्र राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में निहित था।

भारतीय राष्ट्रवाद ने उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप लिया। उस वक्त तक देश में एक शिक्षित वर्ग तैयार हो गया था और भारतीय उद्योगों के उदय के साथ ही भारतीय औद्योगिक बुजुर्गों का भी जन्म हो चुका था। इन्हीं वर्गों ने राष्ट्रीय आंदोलन का मगठन किया और अपनी विराध पताका में निम्नांकित नारे लिखे, सरकारी नौकरियों का भारतीयकरण, भारतीय उद्योगों के लिए सुरक्षा, वित्तीय स्वायत्तता आदि। आर्थिक एवं अन्य क्षेत्रों में ब्रिटिश और भारतीय हितों के संघर्ष के कारण यह आंदोलन शुरू हुआ। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के जन्म का उत्पत्तिमूलक कारण यही हितों का संघर्ष था।

'भारत का राष्ट्रीय आंदोलन साम्राज्यवाद और इसकी शोषण व्यवस्था से पैदा हुआ शिक्षा व्यवस्था चाहती भी रहती भारतीय बुजुर्गों का उदय और ब्रिटिश बुजुर्गों के प्रभुत्व के खिलाफ इसकी बढ़ती हुई प्रतिद्वंद्विता अवश्यभावी थी। अगर भारतीय बुजुर्गों को संसूत में लिने गए बंदों की ही शिक्षा मिली रहती दूसरी सारी विचारधाराएँ अलग, तो उन्हें वही जपन संघर्ष के सिद्धांत और नारे मिल जाते।'<sup>22</sup>

वस्तुतः विपिनचंद्र पाल जैसे बुद्धिवादी राष्ट्रीय नेताओं के लिए उपरि भाषित हिंदू धर्म राष्ट्र धर्म का जोर वाली इस राष्ट्रीयता की देवी प्रतिमूर्ति थी।

ब्रिटन के खिलाफ विभिन्न वर्गों की अपना-अलग-अलग शिकायतें थीं। उद्योगपति भारत का निर्वाध उद्योगकरण और दली उद्योगों के लिए सुरक्षा चाहते थे। शिक्षित वर्ग नौकरियों का भारतीयकरण चाहते थे, क्योंकि ऊँचे जाति, वर्ण और अंग्रेजों के लिए थे। किसान भूमिकर में घटना चाहते थे। मजदूर काम की अच्छी हालत और जीवन राशन के लिए भरपूर मजदूरी का मांग करते थे। राष्ट्र अपनी मजबूती में प्रसन्न और मगठन की आशाएं चाहता था, विद्यालय समाज, निर्वाचित विधायक, प्रतिनिधि संस्थाएँ स्वतंत्र उपनिवेश की हेतुव्यवस्था स्थापना और फिर अंततः पूर्ण स्वतंत्रता चाहता था। ब्रिटन और भारत के इन विरोधांतरों की टकरार से ही भारतीय राष्ट्रवाद का जन्म हुआ।

लेकिन यह मानना होगा कि आधुनिक शिक्षा के जन्म और राष्ट्रवादी तत्त्व पश्चिम में आधुनिक साम्राज्यवाद के जन्म के साथ ही और नए नए राष्ट्रीय आंदोलनों का जन्म आदि। पश्चिम में साम्राज्यवाद

विचारों से प्रभावित नेताओं के पथप्रदर्शन के कारण राष्ट्रीय आंदोलन ने स्वराज्य प्राप्ति के बाद प्राकृतिक काल के राजतंत्रवाद और सत्तावादी सामाजिक व्यवस्था का फिर से स्थापित करने की कामना नहीं की। राष्ट्रीय आंदोलन मूलतः चुनाव, प्रजातांत्रिक कमिटियाँ, बहुसंख्यक मत द्वारा किए गए निर्णय आदि आधुनिक उदारवादी सिद्धांतों पर आधारित था। इससे स्वतंत्र भारत के लिए लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित प्रतिनिधि संस्थाओं की कल्पना की। इस तरह आधुनिक शिक्षा ने, परोक्ष ही सही, भारतीय राष्ट्रवाद को प्रजातांत्रिक दिशा दी।

### आधुनिक शिक्षा के लाभ

अंग्रेजों के चान के अनगिनत फायदे थे। इसमें आधुनिक अंग्रेजी साहित्य के द्वार भारतीयों के लिए, और यह अगर विश्व का सर्वोत्तम साहित्य नहीं था तो विश्व के सर्वोत्तम साहित्यों में तो इसकी गिनती हो ही सकती है। यह ब्रिटिश राष्ट्र का साहित्य था, इतिहास का पहला आधुनिक राष्ट्र, जिसने अठारहवीं सदी के अंत तक मध्ययुगीन परंपरा को समाप्त कर दिया था। मध्ययुग के विरुद्ध संघर्ष में इसने आधुनिक प्रजातांत्रिक, वैज्ञानिक बुद्धिवादी संस्कृति की नींव डाली, और अपने गौरवशाली अस्तित्व के अगले चरण में इसे और अधिक विकसित किया। राजाओं के दबी अधिकारक सिद्धांत पर आधारित मध्यकालीन राज्य की निरकुशता के विरुद्ध अपने संघर्ष में अंग्रेजी राष्ट्र ने जनता की सार्वभौम सत्ता और लोकतांत्रिक राष्ट्र के सिद्धांत की बुनियाद डाली। मध्यकालीन दक्षिणपूर्वी और धार्मिक विचार पद्धति के विरुद्ध इसने आधुनिक बुद्धिवाद का संस्करण तैयार किया। कृपिदास प्रथा और उत्तराधिकार के सिद्धांत पर आधारित मध्यकालीन पदानुक्रमित सामाजिक संरचना के विरुद्ध इसने व्यक्ति स्वातंत्र्य का सिद्धांत घोषित किया। इसने सुनपन्न वैज्ञानिक और तकनीकी संस्कृति को विकसित किया और आधुनिक प्राकृतिक विज्ञान जैसे भौतिकी, रसायन विज्ञान, कृषिशास्त्र आदि को जन्म दिया। जीवविज्ञान और अभियंत्रण के क्षेत्र में इसने काफी प्रगति की। इसने आधुनिक समाजशास्त्र के जरिए समाज का भी वैज्ञानिक अध्ययन शुरू किया।

सामाजिक क्रियाकलाप के प्रत्येक क्षेत्र में सोलहवीं सदी से ही ब्रिटन में सामाजिक उद्यम के प्रत्येक क्षेत्र में जनक महान विचारक पैदा हुए। बचपन में सामाजिक और प्राकृतिक दोनों प्रकार के तथ्यों और उक्त क्रियाओं के अध्ययन के लिए आगमनात्मक तत्वशास्त्र की वैज्ञानिक पद्धति दी। उसने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रयोग ही वैज्ञानिक सिद्धांत का आधार और उसकी कसौटी है। इसने प्राग्भूत और निगमनिक तत्वशास्त्र पर सांपातिक प्रहार किया जिसकी बड़ी आवश्यकता थी, और इस तरह ममान और प्रकृति दोनों में ही प्रगति और वास्तविक प्रगति के लिए पथ प्रशस्त किया। बचपन के बाद और भी जनक तभी विचारक ब्रिटन में पैदा हुए। जॉन स्टॉन वैज्ञानिक था और न्यूटन गणितज्ञ, भौतिकशास्त्री एवं विचारक, एडम स्मिथ ने आधुनिक अर्थशास्त्र का जन्म दिया

मानते हुए भी यह समझ लेना गलत होगा कि भारतीय राष्ट्रवाद इस शिक्षा की सतति है।

भारतीय राष्ट्रवाद का जन्म वस्तुतः नई सामाजिक नीतिक स्थितियों के कारण हुआ, उन नई सामाजिक शक्तियों के कारण जो अंग्रेजों की भारत विजय के बाद पदा हुई। यह विभिन्न स्वार्थों के वस्तुनिष्ठ सघर्ष का परिणाम था— अंग्रेजों का स्वायत्त जो भारत का राजनीतिक और आर्थिक तौर पर गुलाम बनाए रखने में था और भारतीय जनता का हित जो ब्रिटिश शासन से मुक्त भारतीय समाज के स्वतंत्र राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में निहित था।

भारतीय राष्ट्रवाद न उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप लिया। उस वक़्त तक देश में एक शिक्षित वर्ग तैयार हो गया था जो भारतीय उद्योगों के उदय के साथ ही भारतीय औद्योगिक बुजुर्गों का भी जन्म हो चुका था। इसी वर्गों ने राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन किया जो अपनी विरोध पत्रिका में निम्नांकित नारे लिखे, सरकारी नौकरियों का भारतीयकरण, भारतीय उद्योगों के लिए सुरक्षा, वित्तीय स्वायत्तता आदि। आर्थिक एवं अन्य क्षेत्रों में ब्रिटिश और भारतीय हितों के सघर्ष के कारण यह आंदोलन गुरू हुआ। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के जन्म का उत्पत्तिमूलक कारण यही हितों का सघर्ष था।

‘भारत का राष्ट्रीय आंदोलन साम्राज्यवाद और इसकी शोषण व्यवस्था से पदा हुआ शिक्षा व्यवस्था चाह जो भी रहती, भारतीय बुजुर्गों का उदय और ब्रिटिश बुजुर्गों के प्रभुत्व के खिलाफ इसकी बढ़ती हुई प्रतिद्वंद्विता अवश्यभावी थी। अगर भारतीय बुजुर्गों को मस्जुत में लिखे गए वेदों की ही शिक्षा मिली रहती, दूसरी सारी विचारधाराओं से अलग, तो उन्हें वही अपने सघर्ष के सिद्धांत और नारे मिल जाते।’<sup>33</sup>

वस्तुतः विपिनचंद्र पाल जैसे बुद्धिमान भारतीय नेताओं के लिए नवपरिभाषित हिंदू धर्म राष्ट्र धर्म था जो एक ही राष्ट्रीयता की देवी प्रतिमूर्ति थी।

ब्रिटेन के खिलाफ विभिन्न वर्गों की अपनी स्वयं अलग-अलग शिकायत थी। उद्योगपति भारत का निर्वाह उद्योगीकरण और देशी उद्योगों के लिए सुरक्षा चाहते थे। शिक्षित वर्ग नौकरियों का भारतीयकरण चाहते थे, क्योंकि ऊंचे औहदे केवल अंग्रेजों के लिए थे। किसान भूमिकर कम करना चाहते थे। मजदूर काम की अच्छी हालतों और जीवन यापन के लिए मजदूरी की मांग करते थे। राष्ट्र अपनी संपूर्णता में प्रेम और संगठन की आजादी चाहता था, विधान सभा निर्वाचित विधायक, प्रतिनिधि संस्थाएँ स्वतंत्र उपनिवेश की हैसियत स्वशासन और फिर अंततः पूर्ण स्वतंत्रता चाहता था। ब्रिटेन और भारत के इन विरोधी स्वार्थों की टक्कर से ही भारतीय राष्ट्रवाद का जन्म हुआ।

लेकिन यह मानना होगा कि आधुनिक शिक्षा के चलते जनक राष्ट्रवादी नेता पश्चिम के आधुनिक लोकतांत्रिक विचारों को आत्मसात कर सकें और इस तरह राष्ट्रीय आंदोलन को लोकतांत्रिक रूप और उद्देश्य मिला। पश्चिम के लोकतांत्रिक



और गाडविन दाशनिक् अराजकतावाद या प्रणेता था। गिब्वन और वक्ल आधुनिक काल के महान इतिहासज्ञ हुए हैं, रिक्टो सर्वाधिक निर्भीक ब्रिटिश जयशास्त्री था। जान स्टुअर्ट मिल सत्तावाद का निष्कलुप शत्रु था और व्यक्तिगत स्वातंत्र्य एवं जनगण की सावभौमता का महान पक्षधर। कालाइल और रस्किन न समस्याओं का सम्भवतः प्रतिक्रियावादी अतीताम्य समाधान दिया लेकिन दाना ने अपन युग की सामाजिक अनीति की निमम आलोचना की। डाविन न जीवा विशेषकर मानव जाति के विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इस तरह उन धार्मिक विद्वानों पर जो मानव जन्म के प्रारंभिक काल की सिद्धांत प्रचलित करती आई थी गहरी चाट पड़ी। स्पेन्सर विद्वान समाजशास्त्री था। हाव हाउस, रिक्स रिफोल्ड, गाडन चाइल्ड गिंस बगजसे समाजशास्त्री, बर्ट्रेंड रसल जैसे विश्व विद्वान गणितज्ञ और दाशनिक् एच० जी० वल्स जस प्राकृतिक ऐतिहासिक और सामाजिक ऐतिहासिक विकास के सजीव शब्द चित्रकार जिसने चमत्कारपूर्ण और कल्पना प्रभूत रचनात्मक सामाजिक उपयोग लिये जन्म सामाजिक व्यवहार वर्नाड शा, विश्वविख्यात एडिंग्टन और जोन्स जैसे खगोल शास्त्री और ह्यूडन जसा प्राणिशास्त्रज्ञ जो बाद में भारतीय नागरिक हुआ आल्डु अस और जुलियन हकमल लेवी और बनल जस वनानिक, और एम्मे और भी कितने लोग ब्रिटेन में पैदा हुए। इन महान विचारका न विभिन्न क्षेत्रों में मानव ज्ञान को विकसित किया है और आधुनिक विश्व संस्कृति के निर्माण में योगदान दिया है।

शिक्षित भारतीयों ने अंग्रेजी साहित्यिक साहित्य का अध्ययन किया और लोकतांत्रिक सिद्धांत का आत्मसात किया। इसमें उन्हें व्यक्ति को गुलाम बनाने और उसकी मुक्ति पहले शक्ति का शमन करने का प्रयास करने वाले सत्तावादी दशन और बीते युग की जाति जसी प्रतिक्रियावादी सामाजिक संस्थाओं और तदनुसार दृष्टिकोण के विरुद्ध विद्रोह करने की प्रेरणा मिली। उन्होंने जनतांत्रिक आधार पर भारतीय जनता के मुक्त राष्ट्रीय अस्तित्व की बात साधनी गुरू की। इसके कारण भारतीय राष्ट्रीयता के आंदोलन को जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत औपनिवेशिक स्थिति की ही उपज था जनतांत्रिक दिशा मिली। यह आंदोलन चुनाव और निर्वाचित समितियाँ जैसे जनतांत्रिक सिद्धांत एवं व्यवहार और मताधिकार के विस्तार, समाचार पत्रों व्याख्यान और सगठन की स्वतंत्रता, प्रतिनिधि सरकार, जनता के प्रति उत्तरदायी कार्यकारिणी आदि की मांग के आधार पर विकसित हुआ।

अंग्रेजी भाषा के अध्ययन से उस भाषा में उपलब्ध सामाजिक समता और प्राकृतिक वैज्ञानिक बुद्धिवादी दशन सबंधी साहित्य के अध्ययन मनन का मौका मिला, जिसने जनतांत्रिक और बुद्धिवादी दृष्टिकोण का प्रथम दिया। सामाजिक समता सबंधी दशन से व्यक्तिगत और राष्ट्रीय स्वतंत्रता की प्राप्ति सरल हुई। बुद्धिवादी दशन की मदद से मन गहन अधविश्वास और हजारों लाखों देवताओं एवं नायबवाद और परनायबवाद की जकड़ से बाहर निकल सका।

प्राक त्रिटिश भारतीय साहित्य में, चाहे वह हिंदू साहित्य हो या मुस्लिम, राष्ट्रवाद पर कोई पुस्तक नहीं थी। इसका ऐतिहासिक कारण यह है कि आर्थिक पिछड़ेपन की वजह से भारतीय जन सामाजिक और राजनीतिक तौर पर एक राष्ट्र के अभिन्न अंग नहीं हो सके थे।

अंग्रेजी भाषा के अध्ययन से बहुमूल्य ग्रंथों में संकलित प्रजातांत्रिक और राष्ट्रीय विचारों का खजाना खुल गया। ब्रिटिश शासन के अधीन रहने से ही नवजात राष्ट्रीयता का जन्म हुआ, लेकिन इस साहित्य के अध्ययन से यह नवजात राष्ट्रीयता पल्लवित-पुष्पित हुई थी। अंग्रेजी भाषा के ज्ञान से ही शिक्षित भारतीयों को गैर अंग्रेजी साहित्य के महत्वपूर्ण तत्वों, जैसे उनकी वचनिक, दार्शनिक, समाज-शास्त्रीय, साहित्यिक और कलात्मक उपलब्धियों का भी परिचय प्राप्त हुआ।

अंग्रेजी अनुवाद के माध्यम से ही वे डमोक्राइस, हराक्लाइटस, प्लेटो, अरिस्टोटल स्पिनोजा, डेकार्त लाइबनिट्ज, कांट, कामटे नित्शे, हीगल, मक्स स्टर, वनिडेरो रोसे, जासवंल्ड स्पेगलर, काल मार्क्स, आदि की दार्शनिक पद्धतियों का अध्ययन कर सके और प्लेटो मेकियावेलि, दिदरो हालबाष, हल वेसियस, वाल्टर और अट्टारहवी मदी के अन्य विचारकों एवं आगस्ट कामट मॅट साइमन, समाजवादी मार्क्स और एगल्स, अराजकतावादी बाकुनिन सिडि-कलिस्ट प्रूधा, आदि का सामाजिक सिद्धांतों को जानने में सक्षम हो सके। आइन्स्टाइन, डिब्राक, थ्राडिगर, हाइसनबर्ग जैसे गैर अंग्रेजी भाषाभाषी विश्व विभूत गणितज्ञों भौतिकशास्त्रियों और दार्शनिकों की रचनाओं के अनुवाद पढ़ने से भारतीयों का वचनिक ज्ञान बढ़ा। वे अनुवाद के ही माध्यम से चण्ड, दास्तवस्की, तुगनव, गांगोल गोर्की, जाला, बालजाक, फ्लोबेयर, हाइने, मापासा अनातोली फ्रांस, रिक्टर ह्यूगो, मोलिएर गेट इन्सन, मेटर्लिक, मंडम जेने साहित्यकारों की रचनाओं का ज्ञान ले सके। इस तरह अंग्रेजी के अध्ययन द्वारा शिक्षित भारतीयों गैर अंग्रेजी भाषा-भाषियों की सांस्कृतिक उपलब्धियों का भी फायदा उठा सके।

विश्व मस्तिष्क के संपर्क में आने से शिक्षित भारतीयों का ज्ञानवृद्धि ता हुआ ही, उन्हें एक विश्वजननीय दृष्टिकोण भी प्राप्त हुआ। इससे उन्हें विश्व के विचारों की एकल प्रक्रिया की जानकारी हुई और वे भारत के सामाजिक विकास के पृथक्त्व की गलत धारणा से मुक्त हो सके और यह समझ सकें कि भारतीय राष्ट्रीय विचारों के ही विकास का अंग है। धीरे धीरे उनकी यह गलत समझदारी खत्म हो गई कि भारत के विकास का अपना स्वतंत्र और विशिष्ट नियम है और विश्व के विकास से इसका कोई संबंध नहीं है। राष्ट्रीय विशिष्टताओं की उपस्था ही बिना भी, उन्होंने यह समझा कि जिन नियमों से दूसरे समाजों का विकास होता है, उन्हीं नियमों से भारतीय समाज का भी विकास होता है।

भारत पर अंग्रेजों की विजय और उनके शासन ने जिन नए राजनीतिक एवं आर्थिक परिवर्तनों का दृष्टि को नए कारण भारतीयों का ऐसी नई समझना का जन्म देना पड़ा जिनका समाधान पुनः भारतीय मस्तिष्क में नहीं था।

और गाडविन दार्शनिक अराजकतावाद का प्रणेता था। गिब्वन और वकल जाधुनिक काल के महान इतिहासक हुए हैं। रिक्कार्डों सर्वाधिक निर्भीक ब्रिटिश जयशास्त्री था। जान स्टुअर्ट मिल सत्तावाद का निष्प्लुत शत्रु था और व्यक्तिगत स्वातन्त्र्य एवं जनगण की सावभोमता का महान पक्षधर। कार्लाइल और रस्किन ने समस्याओं का सभ्यत प्रतिन्यावादी जतीता-मुख समाधान दिया लेकिन दाना ने अपने युग की सामाजिक अनीति की निमम जालाचना की। डार्विन ने जीवा विषयकर मानव जाति के विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इस तरह उन धार्मिक किंवदंतियों पर जो मानव जन्म के वार में न्यायानुमी सिद्धांत प्रचलित करती आई थी गहरी चाट पड़ी। स्पेन्सर विद्वान समाजशास्त्री था। हाव हाउस, रिवस त्रिफोल्ड, गोडन चाइल्ड गिंस बग जैसे समाजशास्त्री, बर्ट्रेंड रसल जैसे विश्व विद्युत गणितज्ञ और दार्शनिक एच० जी० वल्म जैसे प्राकृतिक-ऐतिहासिक और सामाजिक-ऐतिहासिक विकास के सजीव शब्द चित्रकार जिसने चमत्कारपूर्ण और कल्पना प्रसूत राचक सामाजिक उपचास लिये अमर सामाजिक व्यंग्यकार बर्नाड शा, विश्वविख्यात एडिंग्टन और जीन्स जैसे खगोल-शास्त्री और हाल्डेन जसा प्राणिशास्त्रज्ञ जो बाद में भारतीय नागरिक दुआ, आल्डु-अस और जुलियन हक्सले लेवी और वनल जैसे वनानिक, और ऐस और भी कितने लोग ब्रिटन में पैदा हुए। इन महान विचारवान विभिन्न क्षेत्रों में मानव ज्ञान को विकसित किया है और जाधुनिक विश्व संस्कृति के निर्माण में योगदान दिया है।

शिक्षित भारतीयों ने अंग्रेजी लोकतान्त्रिक साहित्य का अध्ययन किया और लोकतान्त्रिक सिद्धांत को आत्मसात किया। इससे उन्हें व्यक्ति को गुलाम बनाने और उसकी मुक्त पहल शक्ति का शमन करने का प्रयास करने वाले सत्तावादी दशन और बीते युग की जाति जसी प्रतिन्यावादी सामाजिक संस्थाओं और तदरूप दृष्टिकोण के विरुद्ध विद्रोह करने की प्रेरणा मिली। उन्होंने जनतांत्रिक आधार पर भारतीय जनता के मुक्त राष्ट्रीय अस्तित्व की बात सोचनी शुरू की। इसके कारण भारतीय राष्ट्रीयता के जादोलन को, जो ब्रिटिश शासन के अतगत औपनिवेशिक स्थिति की ही उपज था जनतांत्रिक दिशा मिली। यह जादोलन चुनाव और निर्वाचित समितियाँ जैसे जनतांत्रिक सिद्धांत एवं व्यवहार, और मताधिकार के विस्तार, समाचार पत्रों व्याख्यान और संगठन की स्वतंत्रता, प्रतिनिधि सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी कार्यकारिणी, आदि की मांग के आधार पर विकसित हुआ।

अंग्रेजी भाषा के अध्ययन से उस भाषा में उपलब्ध सामाजिक समता और प्राकृतिक वनानिक बुद्धिवादी दशन सबधी साहित्य के अध्ययन मनन का मौका मिला, जिन्होंने जनतांत्रिक और बुद्धिवादी दृष्टिकोण को प्रश्रय दिया। सामाजिक समता सबधी दशन से व्यक्तिगत और राष्ट्रीय स्वतंत्रता की प्राप्ति सरल हुई। बुद्धिवादी दशन की मन्द से मन गहन जयविश्वास और हजारों लाखों देवताओं एवं तार्क्यवाद और परलोकवाद की जकड़ से गहर निकल सका।



प्राकृतिक भारतीय साहित्य में चाहे वह हिंदू साहित्य हो या मुस्लिम, राष्ट्रवाद पर कोई पुस्तक नहीं थी। इसका ऐतिहासिक कारण यह है कि आर्थिक पिछड़ेपन की वजह से भारतीय जन सामाजिक और राजनीतिक तौर पर एक राष्ट्र के अभिन्न अंग नहीं हो सके थे।

अंग्रेजी भाषा के अध्ययन से बहुमूल्य ग्रंथों में संकलित प्रजातांत्रिक और राष्ट्रीय विचारों का खजाना खुल गया। ब्रिटिश शासन के अधीन रहने से ही नवजात राष्ट्रीयता का जन्म हुआ, लेकिन इस साहित्य के अध्ययन से यह नवजात राष्ट्रीयता पल्लवित पुष्पित हुई थी। अंग्रेजी भाषा के ज्ञान से ही शिक्षित भारतीयों को गैर अंग्रेजी साहित्य के महत्वपूर्ण तत्वों, जैसे उनकी वैज्ञानिक, दार्शनिक समाजशास्त्रीय, साहित्यिक और कलात्मक उपलब्धियों का भी परिचय प्राप्त हुआ।

अंग्रेजी अनुवाद के माध्यम से ही वे डेमोनाइटस, हराक्लाइटस, प्लेटो, अरिस्टोटल स्पिनाजा डेकार्त, लाइबनिटज काट, कामटे, निश्च, हीगल, मार्क्स स्टरन, वनिडेता क्रोशे आसवल्ड स्पेंगलर, काल मार्क्स आदि की दार्शनिक पद्धतियों का अध्ययन कर सके और प्लेटो मेकियावेलि दिदरो, हालबास हल वेसियस, वाल्टर और अठारहवीं सदी के अन्य विचारकों एवं आगस्ट कामटे, मॉट साइमन, समाजवादी मार्क्स और एंगल्स, अराजकतावादी बाबुनिन सिडि वलिस्ट प्रूधा, आदि के सामाजिक सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त कर सके। आइस्टाइन, डिराक थ्रोडिंगर हाइसनबर्ग जैसे गैर अंग्रेजी भाषाभाषी विश्व विभूत गणितज्ञ भौतिकशास्त्रियों और दार्शनिकों की रचनाओं के अनुवाद पढ़ने में भारतीयों का वैज्ञानिक ज्ञान बढ़ा। वे अनुवाद के ही माध्यम से चखव, दास्तवस्की, तुगनेव, गोगोल थोर्की, जाला बालजाक फ्लोबेयर हाइने, मोपासा, अनातोले फ्रांस, विक्टर ह्यूगो, मोलिएर गेट इन्सन मेटर्लिक, सैंडस जैसे साहित्यकारों की रचनाओं का ज्ञान ले सके। इस तरह अंग्रेजी के अध्ययन द्वारा शिक्षित भारतीय गैर अंग्रेजी भाषा-भाषियों की सांस्कृतिक उपलब्धियों का भी फायदा उठा सके।

विश्व संस्कृति के संपर्क में आने से शिक्षित भारतीयों का ज्ञानवृद्धि तो हुआ ही, उन्हें एक विश्वजनीन दृष्टिकोण भी प्राप्त हुआ। इससे उन्हें विश्व के विकास की एक प्रक्रिया की जानकारी हुई और वे भारत के सामाजिक विकास के पृथक्त्व की गलत धारणा से मुक्त हो सके और यह समझ सके कि भारतीय राष्ट्रीय विकास विश्व के ही विकास का अंग है। धीरे धीरे उनकी यह गलत समझदारी खत्म हो गई कि भारत के विकास का अपना स्वतंत्र और विशिष्ट नियम है और विश्व के विकास से इसका कोई संबंध नहीं है। राष्ट्रीय विशिष्टताओं की उपेक्षा किए बिना भी, उद्योग यह समझा कि जिन नियमों से दूसरे समाजों का विकास होता है, उन्हीं नियमों में भारतीय समाज का भी विकास होता है।

भारत पर अंग्रेजों की विजय और उनके शासन ने जिस नए राजनीतिक एवं आर्थिक वातावरण की मज्जा की उससे कारण भारतीयों का ऐसी नई समस्याओं का सामना करना पड़ा जिनका समाधान पुरानी भारतीय संस्कृति में नहीं था।

उदाहरणार्थ, प्रहत्तर उद्योगीकरण और उन्नतिशील कृषि के विकास से जिन आर्थिक समस्याओं का सजन हुआ उनके समाधान के लिए गांधी, रानाडे, गाडगिल, या के० टी० शाह जैसे भारतीय जयविदो का ऐडम स्मिथ, रिकार्डो लिस्ट या मार्क्स के अधशास्त्र मवही मद्दातिक निरूपणो ही शरण लनी पडी। जयशास्त्र के रचयिता चाणक्य या महाभारत के ववि वेदव्यास के पास इन नई आर्थिक समस्याओं का कोई समाधान नहीं था।

प्रबुद्ध लोगो के वग का साधारण जनता पर बहुत बडा वचारिक प्रभाव पडता ह। भारत म जाग बडे बुद्धिवादी लोग जिहान अग्रेजी के माध्यम मे विश्व का आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान आत्मसात किया, यह ज्ञान अपनी जनता का भी देने लग। इनमे से कुछ न विभि न देशी भाषाओ मे वज्ञानिक ग्रथो कला का दष्टि से श्रेष्ठ साहित्यिक रचनाओ और राजनीतिक, आर्थिक और समाजशास्त्रीय महत्व की पुस्तका का अनुवाद भी किया। अग्रेजी कित्तावा से मिले विचारा और वैज्ञानिक तथ्या के आधार पर उहाने स्वतंत्र रचनाए भी की। उहोन जनता के उस वग की जा पडा लिखा तो वा लकिन जिसे अग्रेजी का ज्ञान नहीं था, ससार का ज्ञान प्राप्त करने म मदद दी। वार्ताश्री और व्याख्यानों द्वारा इस नए विद्वत्समाज न नए विचार और तथ्य निपट और निरक्षर लोगो का भी दिए। इससे साधारण जनता की भी दष्टि व्यापक हुई और उनका ज्ञानवद्धन हुआ।

अग्रेजी भाषा न देश भर म शिक्षित भारतीयो के बीच सचारण मप्रेपण के माध्यम के रूप म, सामाजिक राजनीतिक और वज्ञानिक हचि के विभिन्न विषयो पर राष्ट्रीय स्तर पर विचारो के आदान प्रदान के माध्यम के रूप म काम किया। शुरु क दिनो म राष्ट्रीय कांग्रेसो और सम्मलनो म अभिव्यक्ति के माध्यम के तौर पर इसका बहुमूल्य योगदान रहा।

आधुनिक शिक्षा और तज्जय पाश्चात्य सस्कृति से सपक की अत्यंत प्रगतिशील भूमिका थी और इसका सबसे बडा प्रमाण तो यही हे कि आर्थिक राजनीतिक, सामाजिक धार्मिक और सास्कृतिक सारे प्रगतिशील जागेलना के लगभग सभी नेता अग्रेजी शिक्षा प्राप्त बुद्धिवादी वग के थे। लगातार बढत हुए और गहर होते हुए राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओ म अधिवाश आधुनिक पद्धति से ही शिक्षित हुए थे।

### आधुनिक शिक्षा की उन्नति की आवश्यक शर्तें

आधुनिक बुद्धिजीवी और शिक्षित मध्यम वग के विकास के बावजूद अधिकांश भारतीय निरक्षर थे। उनकी गरीबी ही इसका मुख्य कारण थी। जनसाधारण की निरक्षरता का सवाल उनकी गरीबी के सवाल से जुडा हुआ था और इसलिए उनकी निरक्षरता का खतम करने के लिए गरीबी को खतम करना जरूरी था।

हम दय चुके हे कि इस गरीबी का कारण था भारतीय जयव्यवस्था का उपनिवेशी रूप, उसके चलते उत्पादन की शक्तिया का स्वल्प विकास और परंपरा

से चली जा रही भूमि व्यवस्था और पुराने आर्थिक संकट। इसलिए लोग की गरीबी ख़तम करने का ज़रूरत था राष्ट्रीय स्वातंत्र्य, निहित स्वार्थों के बदल भारतीय जनता के हाथों में शक्ति और राष्ट्रीय सामाजिक-आर्थिक नवनिर्माण के लिए व्यापक परियोजना। जब उत्पादन के साधन समाज के हाथ में हों, तभी ऐसी योजना पूरी तरह सारक हो सकती है। स्वतंत्र और आर्थिक तौर पर समृद्ध देश ही ऐसा बजट बना सकता है जो जनसाधारण की शिक्षा और सामाजिक संवाओं पर भरपूर ध्यान दे सके।

जनसाधारण की निरक्षरता के पूरा समाधान और लोग के बीच अर्वाचीन युग के समृद्ध वैज्ञानिक और कलात्मक संस्कृति के व्यापक प्रसार का सवाल राष्ट्रीय आजादी और उत्पादन के साधनों के समाजीकरण के प्रश्न से जुड़ा हुआ था।

### संदर्भ

- 1 ट्रिवेलियन पृ० 168।
- 2 मकान ज मिनिट 1935 टाममन एंड गेटेद द्वारा उद्धृत पृ० 66।
- 3 आ मला पृ० 134।
- 4 वही पृ० 138।
- 5 वही पृ० 139।
- 6 संवाद नूहला एंड नायक पृ० 92।
- 7 देखें टाममन एंड गेटेद।
- 8 हास काहन पृ० 34-35।
- 9 आ मनी पृ० 658-59।
- 10 राजा राममोहन राय 471-74।
- 11 लास्की पृ० 18 और उमक जान।
- 12 देखें हास काहन पृ० 117।
- 13 संवाद नूरला एंड नायक पृ० 67।
- 14 सनवगम फाम एजुकेशन रकॉर्ड्स जिल्हा I पृ० 130-31।
- 15 वही जिल्हा II पृ० 16-17।
- 16 संवाद नूरला एंड नायक पृ० 179।
- 17 वहा पृ० 181।
- 18 वही।
- 18 वही।
- 20 गाखले स्पीचेज पृ० 23-35।
- 21 रिपोर्ट आफ द हाटिंग कमटी पृ० 31 विवनवेनियन रिब्यू आफ द प्रोग्रम आफ एजुकेशन इन इंडिया 1927-32 जिल्हा I पृ० 3।
- 22 पन्तकर पृ० 110-11।
- 23 दत्त पृ० 78।
- 24 मारन एंड मॉर्गिन प्राप्रिस आफ एजुकेशन इन इंडिया 1923-24 पृ० 22।

- 25 व्युत्पन्न प० 479 ।
- 26 वही, प० 480 ।
- 27 शलवकर प० 54 55 ।
- 28 बी० सी० पाल बक द्वारा उद्धृत प० 150 ।
- 29 गाखले प० 74 75 ।
- 30 हास काहन प० 118 ।
- 31 दत्त प० 271 ।

## ब्रिटिश शासन काल में भारत का राजनीतिक और प्रशासनिक एकीकरण

### प्राक्-ब्रिटिश भारत में आधारभूत राजनीतिक और प्रशासनिक वकृता का अभाव

केंद्रीय राज्य सत्ता की स्थापना ब्रिटेन की भारत विजय का एक महत्वपूर्ण परिणाम था और इसके कारण भारत के इतिहास में पहली बार देश का वास्तविक और आधारभूत राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकीकरण हुआ। प्राक् ब्रिटिश भारत में ऐसी एकता का सबूत अभाव था और यह निरंतर विभिन्न सामंती प्रदेशों में बढ़ रहा, जो अपनी सीमाएं बढ़ाने के लिए प्रायः आपस में लड़ते रहते थे। अशांत, समुद्रगुप्त और जकवर जैसे महान राजाओं के शासन काल में सारे भारत को एक राजकीय सत्ता और प्रशासनिक व्यवस्था में लाने के प्रयत्न अवश्य हुए थे। भारत के बहुत बड़े भूखंड को ये सम्राट अपने शासनसूत्र में बांध भी सके, लेकिन जो राजनीतिक और प्रशासनिक एकता ये ला सके वह नाममात्र ही ही रही, क्योंकि जिन हजारों लाखों स्वशासित गांवों में भारत की बहुमध्यक जनता रहती थी उनमें कोई चिरंतन परिवर्तन नहीं आया। ये गांव चिरकाल से स्वशासित गणतंत्र थे। इन गांवों का वास्तविक शासन गांव और जाति की पंचायतों चलाती थी।

‘गांव आत्मपोषक और स्वशासित इकाइयों के रूप में संगठित थे। उनकी स्वायत्तता एक शिथिल शासन व्यवस्था का अंग थी। सावभौम सत्ता स्थानीय जाति मण्डलों को अपने सीमित क्षेत्रों में कार्य करने के लिए स्वतंत्र छोड़ देती थी। प्रत्येक गांव अपने निवासियों के सामाजिक क्रियाकलाप को संगठित करता था और स्वतंत्र इकाई था।’<sup>1</sup>

एकीकृत राष्ट्रीय अथतंत्र और आवागमन के व्यापक एवं समय साधनों के अभाव में प्राक् ब्रिटिश युग में भारत का सायक राजनीतिक और प्रशासनिक ऐक्य संभव भी नहीं था। यूरोप के केंद्रीभूत राज्यों के उदय के इतिहास से स्पष्ट है कि ऐसे राज्यतंत्र का विकास एकीकृत राष्ट्रीय अथतंत्र और तीव्र आवागमन के सुचारु साधन से अभिन्न तौर पर जुड़ा हुआ है।<sup>2</sup>

प्राक् ब्रिटिश भारत में भी एकता की भावना विद्यमान थी और फली फूली

भी। लेकिन यह देश की भौगोलिक एकरता और हिंदुओं की धार्मिक मासुद्धनिक एकता की धारणा थी। भारत 'भौगोलिक और धार्मिक दृष्टि में अवच्छिन्न था।'<sup>3</sup> जा मेली न कहा है जिनकी अपनी एक सम्मिलित भाषा नहीं, जा सामाजिक और राजनीतिक तौर पर खडो म विभाजित रे लेनिन जिनकी सहानुभूति समधम पर जाधारित थी, उनम परस्पर एकरता लाने का काम हिंदू धम न किया।<sup>4</sup>

लेकिन एसी सामाजिक और ऐतिहासिक स्थिति म समस्त भारतीय जनता की राजनीतिक एकता का प्रश्न ही नहीं था। लग सामाजिक और आर्थिक तौर पर भी एक नहीं थ। अग्रजा ने भारत म जिंग नए प्रकार के केंद्रीय राज्यतंत्र की स्थापना की वह सार देश म परिव्यात था।

### न्यायिक एकता

अग्रजा ने भारे देश म समरूप न्यायतंत्र की स्थापना की। उन्होंने कानून बनाए और उह महितावद्ध किया। य कानून राज्य के सभी नागरिका पर लागू थ और न्यायालयो की श्रेणीवद्ध व्यवस्था द्वारा लागू किए जाते थे। सरकार के न्यायिक पदाधिकारी सरकारी न्याय की व्याख्या करते और हर गाव और शहर म उसका सपोषण मरक्षण करते थ। इस तरह दश म लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट और अतत फेडरल कोर्ट और प्रिवी काउंसिल की व्यवस्था कायम हुई।

कानून और कचहरियो की नई व्यवस्था स्थापित कर अग्रजा न परंपरागत विवि व्यवस्था को न्यानच्युत कर दिया और गाव और जाति की पचायता स पुराने कानून को लागू करने वाले अधिकार ल लिए। समरूप विधि व्यवस्था के अभाव म पुराने कानून हर जगह भिन्न भिन्न थे।

अग्रजा द्वारा लाया गया न्यायतंत्र परंपरागत विवि व्यवस्था से अधिक समतावादी था क्योंकि पुरानी व्यवस्था म जाति जाति म जार सप्रदाय सप्रदाय म विभेद था, जिसे धम का समथन प्राप्त था। धम श्रेणीवद्ध जाति व्यवस्था और अय विभेदो का पबित्र मानता था।

नई व्यवस्था कानून की दृष्टि म सभी नागरिका की समानता व गणतान्त्रिक सिद्धांत पर आधारित थी। प्राक ब्रिटिश भारत मे एव ही अपराध के लिए न्यायिक प्रक्रिया को गर द्राह्यणा से हलकी सजा मिलती थी। किसी की जाति और उसका धम चाह जो हा नए कानून की दृष्टि म प्रत्येक नागरिक बराबर था। और ये कानून राज्य के सार मूभाग म लागू थ। इस तरह भारतीय इतिहास मे पहली बार, अग्रजो के शासन काल म यरोपीया क लिए पक्षपातपूर्ण विवेद के दाबजूद जनतान्त्रिक आधार पर भारत का न्यायिक एकीकरण हुआ।

### प्रशासनिक एकता

अग्रजो ने एक और प्रगतिशील काम किया। उन्होंने श्रेणीवद्ध नोकसन्त्राओं की स्थापना द्वारा देश का प्रशासनिक एकीकरण मपन किया। इस तरह साम्राज्यिक,

प्रादेशिक और अवर (जमीनस्थ) सेवाओं का निर्माण हुआ जो केंद्रीय राज्य सत्ता का कार्याकारिणी पक्ष था। प्राकृतिक भारत में जब देश का बहुत बड़ा भाग राजा के मातहत रहा, तब भी देश का मूलभूत वास्तविक प्रशासनिक एकीकरण नहीं हुआ था, क्योंकि सम्राट के प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों का देश के दूर-दूर के भागों में रहने वाले माध्यायण लोगों के जीवन से कोई संबंध नहीं रहा, सिवा इसके कि वे गांवों से लगान वसूल करें, सजा जमा करें, सम्राट के लिए खिराज इकट्ठा करें, नागरिकों से उनका प्रतिनिधित्व या मगठनों के जरिए सिंचाई और सड़क निर्माण जैसे कुछ काम करावें या कभी कभी खुद ऐसे काम करें। गांवों में गांव और जाति की पंचायतें ही वस्तुतः सरकार या प्रशासन का सारा काम करती थीं। ये पंचायतें ही गांव के किसान परिवारों में जमीन का बंटवारा करती थीं, कारीगरों और किसानों के संबंध का नियंत्रण करती थीं शिक्षा, सफाई, झण्डा के फेंकने आदि के काम को अंजाम देती थीं। राज्य केवल फसलों में अपने हक का दावेदार था और गांव के प्रशासन का काम ग्राम समुदाय के जिम्मे था। जंगलों में जा प्रशासनिक पद्धति गुरु की वह इसके विपरीत थी सरकार ने गांव और जाति की पंचायतों से उनका काम ले लिया और गांव की अदरुनी हालत की देखभाल का भी जिम्मा अपने पर ले लिया। अब सरकार द्वारा बहाल अफसर गांव के हर काम की देखभाल करते थे और वे गांव की जनता के बदले केंद्र में सरकार के प्रति जवाबदेह थे। स्वशासन गांव अब दशव्यापी प्रशासनतंत्र की इकाई बन रहा था।

भारतीय इतिहास में पहली बार ब्रिटिश शासन की स्थापना के कारण देश का व्यापक और मूलभूत राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक एकीकरण हो सका। भारत में जो नई अव्यवस्था कायम हुई उसके कारण इस तरह का शासनतंत्र आवश्यक था। भारत के पूँजीवादी आर्थिक परिवर्तन में गांवों के क्षुद्र पथक विभिन्न अर्थतंत्रों को समाप्त कर दिया, नए विनियमन व्यवस्था द्वारा भारतीय जनता का आर्थिक रूप से समन्वित किया और अनुबंध को आर्थिक संबंधों का मूलधार बनाया। ब्रिटिश सरकार ने व्यक्तिगत मपत्तियों के सिद्धांतों के आधार पर एक नई भूमि व्यवस्था की स्थापना की और मुद्रा-अर्थ की गुरुत्वात् की। नए भूमि व्यवस्था की स्थापना और उनके नियंत्रण के लिए समरूप आर्थिक व्यवस्था की आवश्यकता थी और नई व्यवस्था से नए आनुबन्धिक क्रियाकलाप जैसे नए विनियम, जमीन का गिरनी उधक रखने आदि की जरूरत पड़ी।

### समरूप मुद्रा व्यवस्था

ब्रिटिश शासन काल में केवल पण्य वस्तुओं का उत्पादन होता था। भारत दुनिया की मंडी से पहले की अपेक्षा अधिक व्यापक रूप में संबद्ध हो गया था। भारत के दक्षिण और विदेशी व्यापार के क्षेत्र और परिमाण दोनों बढ़े। पूँजीवादी आधार पर आधुनिक उद्योग लगातार विकसित हुए। ऐसी आर्थिक व्यवस्था के कारण जो

नए आनुवंशिक और अन्य प्रकार के जटिल सत्रध विकसित हुए उनका नियमन क लिए नए राज्य को तरह तरह के कानून बनाने पड़े। किसान और जमीनार मजदूर और मालिक, उद्योगपति व्यापारी और बैंकर (धनपति) जादिके पारस्परिक संबंधों के निरूपण और संचालन के लिए तथा भारत और विदेशों के व्यापारिक और अन्य प्रकार के संबंधों के लिए नए कानून बन। देश में नई समस्याएँ मुद्रा व्यवस्था की भी आवश्यकता पड़ी।

नए राज्य ने शिक्षा का भी उत्तरदायित्व मंभाला। यह आवश्यक भी था क्योंकि नए अर्थतंत्र और प्रशासनतंत्र के लिए आधुनिक उदारवादी, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा में प्रवीण लोगों की आवश्यकता थी। जंग्रेजों द्वारा स्थापित नए राज्य ने भारत और भारत के लोगों को एकताबद्ध किया, जसा उसके पहले कभी कोई शासन या राज्यनत्र नहीं कर सका था। पहली बार भारत की जनता के आर्थिक और सामाजिक जीवन का अधिकांश विश्वजनीन और समरूप विधि व्यवस्था द्वारा संचालित हुआ।

### एकीकरण की त्रुटियाँ

ब्रिटिश शासन ने भारतीय जनता का जो राजनीतिक आर्थिक और प्रशासनिक एकीकरण किया जब हम उसकी प्रमुख त्रुटियाँ की चर्चा करेंगे। 1857 तक भारतीय भूभाग के अधिकांश जस को सीधे ब्रिटिश शासन के मातहत लेने की प्रक्रिया लगातार चलती रही। लेकिन जब भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सरकार ने ले लिया ता गनी विकटारिया की घोषणा द्वारा यह तय हुआ कि बाकी बचे देशी राजाओं के राज्या पर अत्र कब्जा नहीं किया जाएगा। ये देशी राज्य जंग्रेजों की श्रेष्ठतर शक्ति द्वारा समाप्त किए जा सकते थे लेकिन ये बचे रह गए और ब्रिटिश शासन के छोटे छोटे स्तंभ के तौर पर काम करते रहे।

इन छोटे और बड़े बहुतेरे सामंती राज्या के रहने के कारण एक राज्यतंत्र के रूप में भारत के राजनीतिक और प्रशासनिक एकीकरण की प्रगतिशील प्रक्रिया सीमित सी रही। भारत दो भागों में विभाजित रहा एक देशी रजवाड़ा द्वारा शासित, दूसरा ब्रिटिश सरकार द्वारा। इस विषय पर कोपलड का कहना है 'इन दो विभिन्न क्षेत्रों में सरकार के आधार और रूप बिल्कुल भिन्न थे।' कोपलड ने जाग यह भी कहा है कि, देशी राज्यों और ब्रिटिश भारत का यह विभाजन भूगोल के पर है देशी राज्य अंतरतीव तौर पर नक्सों पर दिखते हैं जहा तहाँ ब्रिटिश भूखंड उनके क्षेत्रों से बिल्कुल जुड़ा हुआ है।<sup>16</sup>

इन देशी राज्या के शासक निरकुश और स्वेच्छाचारी थे लेकिन इनकी आर्थिक मरचना में परिवर्तन हुए। ब्रिटिश भारत में भूमि और भूमिकर की जो नई व्यवस्था स्थापित हुई, उस उन्होंने अपन यहा भी लागू किया। आत्मनिभर और स्वशासित गाव इन राज्या के क्षेत्रों में भी खतम हुए। बडौदा, मैसूर और त्रावणकोर जसे कुछ जाग बड़े राज्या ने अपन यहा लगभग वही प्रशासनिक व्यवस्था



चालू की जो ब्रिटिश भारत में चल रही थी। उन्होंने समरूप विधिव्यवस्था भी स्थापित की और कानून की पावती के लिए कच्छहरिया की स्थापना भी की। फिर भी, ये राज्य पथक सरकारी एवं प्रशासनिक इकाइयाँ थीं और ये ब्रिटिश भारत एवं एक दूसरे से भी पथक रहे।

ब्रिटिश भारत के राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकीकरण की एक चारित्रिक विशेषता यह भी थी कि जिस राज्यतंत्र ने यह प्रगतिशील काम किया वह विभिन्न चरणों में ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधिनियमों द्वारा निरूपित संविधान के अनुसार विकसित हुआ था। जिस संविधान ने ब्रिटिश भारत के राज्यतंत्र का निरूपण किया, वह भारतीय जनता के चुन हुए प्रतिनिधियों की संविधान सभा द्वारा पारित नहीं हुआ था। फलस्वरूप भारत की ब्रिटिश सरकार कानूनन और नियमित ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति जिम्मेदार थी, न कि भारतीय जनता के प्रति जिस पर यह शासन करती थी। भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित राज्यतंत्र का यह एक अवश्यभावी अजनतांत्रिक वैशिष्ट्य था।

चूँकि यह नया राज्य ब्रिटेन की भारत विजय का परिणाम था। इस लिए ऊपर गिनाई गई त्रुटियाँ अवश्यभावी थीं। यह राज्य मूलतः और प्रथमतः ब्रिटिश पूँजी की राजनीतिक जायिक और युद्धनीतिक आवश्यकताओं और उसके हितों की पूर्ति के लिए बनाया गया था। इसलिए ऐतिहासिक दृष्टि से प्रगतिशील कुच्छेक तत्वों के बावजूद इसमें त्रुटियाँ और कमजाँरियों का होना लाजिमी था।

देशी आवादी पर विदेशी सरकार का शासन, यह विरोध भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के जन्म का एक मूल कारण था।

‘अंग्रेजों ने सारे भारतीयों का कायक्षम राज्य व्यवस्था के अधीन लाकर और उन्हें पश्चिम के विचारों से परिचित कराकर तो उनमें राष्ट्रीय चेतना जगाई ही, साथ ही एक विदेशी जाति के साथ संपर्क का जो स्वयं अपनी राष्ट्रीयता और अपने वर्ण भाव से उत्प्रेरित थी, यह स्वाभाविक असर पड़ा कि विजित जाति में भी ऐसे ही भावों का उद्भव हुआ।’

ब्रिटिश शासन से भारतीयों को यह जानकारी तो प्राप्त हुई थी कि उनकी अपनी कुछ सम्मिलित पारस्परिक विशिष्टताएँ हैं, उनका अपने सम्मिलित स्वायत्त भी बन और विरोध का सम्मिलित आधार भी प्रस्तुत हुआ।’

भारतीय जनता में ज्यों-ज्यों राजनीतिक चेतना आई वैसे-वैसे उहोने प्रशासनिक सुधार, नौकरियों के भारतीयकरण प्रतिनिधि संस्थाएँ, जातिगत पक्षपात और भेदभाव की समाप्ति मताधिकार, निर्वाचित विधायिका सभाएँ इन विधायिका सभाओं के प्रति जवाबदेह कार्याकारिणी, नागरिक स्वातंत्र्य, जात्म शासित उपनिवेशों जैसे संविधान, और फिर भारतीय जनता के लिए संविधान

वनाने व एकमात्र अधिकारी मविधान सभा की स्थापना जादि भागा के लिए आदोलन का मगठन किया ।\*

वस्तुतः इन लोगो न राज्य व्यवस्था के लोकतन्त्रीकरण का प्रयास किया और इस बात की कोशिश की कि प्रशासनिक जागुजाई और राजनीतिक सत्ता वार धीरे जग्रेजा के हाव स हटकर भारतीय जनता के हाव म जा जाए । इस तरह राष्ट्रीय आदोलन मूनत जनतात्रिक आदोलन वा ।

इस बात का खयाल रखना चाहिए कि राष्ट्रीय आदोलन न जग्रेजा द्वारा स्थापित भारत के राजनीतिक और प्रशासनिक एकीकरण को कायम रखना चाहा, क्याकि ऐतिहासिक दष्टि स यह जाग वढा हुआ कदम था । इसन जात्म शासित गाव और प्राक ब्रिटिश लिा के सामती भारत के राजनीतिक जाग प्रशासनिक अनैक्य का पुनर्जीवित करन का प्रयास नही किया । भारतीय राष्ट्र वादियो ने राज्य व्यवस्था का जनतात्रिक जाधार बन की कोशिश की । इनम सबसे आगे वडे हुए तत्वा न जतत भारतीय जनता के लिए स्वतन्त्र सावभौम राज्य-सत्ता का उद्देश्य सामन रखा ।

## सदम

- 1 आ मनी प० 34 ।
- 2 बखवार ।
- 3 आ मनी प 1 ।
- 4 वही ।
- 5 वापनड प० 7 ।
- 6 वही प० 14 ।
- 7 कारे प० 153 ।

\*भारत के राष्ट्रीय आदोलन का जाधार बहुवर्गीय वा और यह कित्थी ब्रिटिश शासन क विरुद्ध था । प्रत्येक सामाजिक वग या दल न अपना भाग सामन रखा जो उस वग के हिता आकांक्षा का प्रतिफल था । सकिन प्राय ये दल नागरिक स्वातन्त्र्य स्वराज्य और एमा अन्य सम्मिलित भागा के सवान पर एकजुट थे ।

भारत का राष्ट्रीय आदानन भारत की जनता के लिए स्वतन्त्र सावभौम राज्य का माग करन की स्थिति म पणुच गया था लेकिन भारत के भावा रायतन के बारे म विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करन वाल विभिन्न दला की अपनी जलग-जदग राय थी । मतानिम नीग तो इस पक्ष म थी कि भारत का हिंदू और मुसनिम सावभौम राष्ट्रो म विभाजन न जाए लेकिन बाकी मार दल और सगठन जल्पमन्थका के लिए जात्मनिधय का मिद्धात मानत हुए थे, ब्रिटन द्वारा लाए गए एक राष्ट्र और एक राज्य के अस्तित्व का बनाए रखना चाहत थे । फिर भा कुछ लोग तो आधुनिक पूजीवादा अवतत पर आधा रित जनतात्रिक भारतीय राय चाहत थे जबकि दमर कुछ नन जैसे आन इडिया टूड यूनियन वाग्रम और समाजवादा अवतत पर जाधारित समाजवादा राज्य चाहत थे ।

## भारत में नए सामाजिक वर्गों का उदय ,

### नए सामाजिक वर्गों का असमान उदय

नए सामाजिक वर्गों का उदय अंग्रेजी शासनकाल में नए सामाजिक अस्तित्व नई राज्य व्यवस्था नए प्रशासन और नई शिक्षा का सीधा परिणाम था।<sup>1</sup> अतीत के भारतीय समाज में नए वर्ग नहीं थे। ये तो नई पूँजीवादी व्यवस्था की देन हैं जो अंग्रेजों की भारत विजय और विदेशी अस्तित्व के भारत पर पड़े प्रभाव के कारण इस देश में आई। भारतीय समाज के मूलभूत पूँजीवादी आर्थिक रूपांतरण के फलस्वरूप यहाँ की जनता अब नए सामाजिक दल और नए वर्गों में नए सिरे से संगठित हुई।

लेकिन देश के विभिन्न भागों और विभिन्न समुदायों में नए सामाजिक वर्गों के उदय की प्रक्रिया बड़ी विषम रही। इसका कारण यह था कि नया सामाजिक अस्तित्व, समय और क्षमता दोनों दृष्टियों से, असमान रूप से विकसित हुआ, क्योंकि इसका प्रसार भारत में अंग्रेजों की राजनीतिक प्रभुता के प्रसार पर निर्भर रहा। भारत पर अंग्रेजों की विजय जिसके कारण भारत की व्यवस्था में आमूल परिवर्तन हुए कोई समकालिक घटना नहीं थी। भारत पर ब्रिटेन ने अपनी प्रभुता कई किस्तों और कई चरणों में स्थापित की। देश के विभिन्न भागों अपनी राजनीतिक दासता के क्रम में पूँजीवादी परिवर्तन की दिशा में जागे बढ़े। इसलिए जो प्रायः अंग्रेजों के प्रभाव में पहले आए वहाँ इन नए सामाजिक वर्गों का जन्म पहले हुआ। बंगाल में अंग्रेजों का शासन सबसे पहले कायम हुआ और यहीं अंग्रेजी सरकार ने भारतीय इतिहास में पहली बार जमींदारी के रूप में निजी संपत्ति की मृष्टि की। इसलिए बंगाल में ही सबसे प्रथम पट्टेदार और जमींदार जैसे दो नए वर्गों की स्थापना हुई। बंगाल और बम्बई में ही सबसे प्रथम जूट और सूती कपड़े के कारखानों की स्थापना हुई और सबूतों और उद्योगपति जैसे नए वर्गों का जन्म हुआ। इसी वजह से सबसे पहले यहाँ प्रायः ब्रिटेन ने व्यापक और जटिल प्रशासनिक व्यवस्था कायम की और नई शिक्षण संस्थाओं का निर्माण किया, जहाँ आधुनिक विज्ञान और विज्ञान शास्त्र, कानून इत्यादि की शिक्षा दी गई,

जिससे इन प्रांतों में ही सबसे पहले पेशवर वर्ग का जन्म हुआ।

फिर भी चूँकि जतन में अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत पर कब्जा कर लिया, इसलिए नए सामाजिक अर्थतंत्र प्रशासनिक व्यवस्था और आधुनिक शिक्षा का मारे दश में प्रचार हुआ और सारे देश में नए सामाजिक वर्ग का उदय हुआ।

विभिन्न समुदायों में भी नए सामाजिक वर्गों का उदय की प्रक्रिया विपरीत रही। इसकी वजह यह थी कि कुछ समुदाय प्राकृतिक ब्रिटिश काल में भी विशिष्ट आर्थिक सामाजिक और शैक्षणिक पंथों में लग गये। उदाहरणार्थ बनिया लोग व्यापारी और सराफों का काम करते थे और ब्राह्मण लोग हिंदुओं की शिक्षा दीक्षा के लिए जिम्मेदार थे। नए सामाजिक परिवर्तन में बनिया लोग (पारसी लोग भी) सबसे पहले आधुनिक पूँजीवादी व्यापार और वैज्ञानिक क्षेत्र में जागे और इस तरह वाणिज्यिक और वित्तीय बुजुर्गों का जन्म हुआ। इसी तरह ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाए गए नए शिक्षातंत्र को सबसे पहले ब्राह्मणों ने ही अपनाया और इस तरह उनके बीच आधुनिक बुद्धिवादी और शिक्षित मध्यम वर्ग का जन्म हुआ। प्राकृतिक ब्रिटिश काल में मुसलिम समुदाय के जन्मनातक वर्ग का रूप के लेन-देन या मध्ययुगीन व्यापार तंत्र से कोई संबंध नहीं था। इस वर्ग के लिए मुख्यतः प्रशासनिक और जय संवादा में लगे थे। ये प्रायः उत्तरी भारत में रहते थे जो बहुत बाद में अंग्रेजों के प्रभाव में आए। बंगाल की बहुमतक मुसलिम जावादी मुख्यतः गरीबों की थी। इसलिए आधुनिक बुद्धिवादी वर्ग, शिक्षित मध्यम वर्ग और बुजुर्गों का जन्म मुसलिम संप्रदाय में हिंदू संप्रदाय की अपेक्षा बहुत बाद में हुआ।<sup>3</sup> (देखें अध्याय 9 और 19)।

### नए सामाजिक वर्ग

अब हम उन सामाजिक वर्गों के नाम गिनाएंगे जो ब्रिटिश शासन के दिनों में भारत में आविर्भूत हुए। कृषि के क्षेत्र में मुख्यतः ये वर्ग थे (1) ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया जमींदार वर्ग (2) जयवासी भूस्वामी (3) जमींदार और जयवासी भूस्वामियों के मानहृत पट्टेदार, (4) वास्तुकार मालिकों का वर्ग, जिसकी उच्चतम मध्यम और निम्न तीन श्रेणियाँ थीं, (5) खतिहर मजदूर (6) व्यापारियों का नया वर्ग, और (7) सूदखोर महाजनों का नया वर्ग।

नगरों में ये वर्ग मुख्यतः निम्नलिखित थे (1) वाणिज्यिक और वित्तीय पूँजीपतियों और उद्योगपतियों का वर्ग (2) औद्योगिक जावागमन के साधन संबंधी खनिज विषयक और ऐसे जय कार्यों में लगे आधुनिक मजदूर वर्ग, (3) आधुनिक पूँजीवादी अर्थव्यवस्था से बंधा छोटे व्यापारियों और दुकानदारों का वर्ग, (4) पेशेवर वर्ग, टेक्नीशियन, डाक्टर वकील प्रोफेसर, पत्रकार मनजर, किरानी और जय लोगों का पेशेवर वर्ग, जिसमें बुद्धिवादियों और शिक्षित मध्यम वर्ग के लोग हैं।

## नए वर्गों के उदय के कारण

मूलतः ब्रिटिश सरकार के अधिनियम (जैसे नए प्रकार के भूमि मबध) द्वारा लाए गए आधारभूत आर्थिक परिवर्तन, भारतीय समाज में बाहर की पूँजीवादी दुनिया के वाणिज्यिक और अन्य प्रकार के तत्वों के प्रवेश और भारत में नए उद्योगों की स्थापना के कारण ही नए वर्ग उदित हुए।

ब्रिटिश सरकार ने जमींदारी और रयतदारी प्रथा के द्वारा जमीन पर निजी मिल्कियत की शुरुआत की और इससे जागीरों के मालिकों एवं जमींदारों और खेतीकर मालिकों के वर्ग का जन्म हुआ। फिर, जमीन को पट्टे पर देने के अधिकार की शुरुआत से बटाईदारों और पट्टेदारों के वर्गों का जन्म हुआ, तथा जमीन की खरीद बिक्री के अधिकार और जमीन पर मजदूर लगान के अधिकार की शुरुआत के कारण अन्यत्रवासी जमींदारों और रूपक सबहारा वर्ग के उदय के लिए स्थिति तैयार हुई।

1853 में माक्स ने लिखा जमींदारी और रयतदारी दोनों व्यवस्थाएँ अंग्रेजों द्वारा लाई गई कृषिक क्रांतियाँ थीं, और एक दूसरे की विरोधी थीं। इनमें पहली अभिजाततन्त्रीय और दूसरी जनतांत्रिक थी। जमींदारी प्रथा अंग्रेजी भूस्वामित्व का विकृत रूप थी और बटाईदारी प्रथा फ्रांसीसी किसान मिल्कियत का। हानिकारक दाना व्यवस्थाएँ थीं, बिल्कुल विरोधी तत्वों के सम्मिश्रण से कोई भी न तो जमीन जोतने वालों के हित में थी और न जमीन के मालिकों के हित में। केवल भूमि कर लगाने वाली सरकार को इन व्यवस्थाओं से फायदा था।<sup>4</sup>

इस नई आर्थिक व्यवस्था की आर्थिक तांत्रिक परिणति के रूप में जमींदारी क्षेत्रों में जमींदारों और खेती करने वाले किसानों के बीच मध्यस्थों की श्रेणीबद्ध शृंखला का विकास हुआ, और रयतदारी क्षेत्रों में खेती करने वाले किसानों और राज्य के बीच सूद पर रुपया लगाने वाले महाजनों दूरस्थ जमींदारों और बड़े व्यापारियों जैसे मध्यस्थों की शृंखला बनी। कृषि वाले अध्याय में जिन तत्वों की गिनती और चर्चा की जा चुकी है उनके कारण भारत में इंग्लैंड और अमरीका के पूँजीपति जमींदारों के वर्ग का उदय नहीं हो सका, और न फ्रांस की तरह आर्थिक तौर पर स्थिर और समृद्ध सबल किसान मालिकों का ही वर्ग बन सका।<sup>5</sup>

इसके विपरीत भारत में जमींदार, पट्टेदार, किसान मालिक खेत मजदूर के साथ ही खेती वाले क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर आधुनिक मूदबोर महाजन, व्यापारी जाकिमान और मंडी के बीच मध्यस्थ का काम करते थे दूरस्थ जमींदार जो कर की बसुली में ही रुचि रखते थे आदि के नए वर्ग पदा हुए। प्राक ब्रिटिश भारतीय समाज में ऐसे वर्ग नहीं थे।

प्राक ब्रिटिश भारत के देहाती क्षेत्रों में मूदबोर महाजना और व्यापारियों के वर्ग तो थे लेकिन समाज में उनके स्थान और कार्य पुराने समाज की तुलना में बिल्कुल भिन्न थे। पुराने भारतीय समाज में सूद पर रुपया चलानेवालों की स्थिति

और भूमिका नगण्य थी। वे यदाकदा किसान या कारीगर को उधार पैसा देते थे, लेकिन गांव की पचायत मूद की दर निश्चित किया करती थी। फिर, अगर कोई किसान मूद की मांग पूरा नहीं कर पाता तो मूददार किसान की जमीन या उसका हल-बैल पर कब्जा नहीं कर सकता था। इसी तरह पुरानी सामाजिक व्यवस्था में गांव का व्यापारी बाहर की मनाइ कुछेक चीजें ही लाता था। लेकिन नई भूमि व्यवस्था के लागू होने पर इन वनिया महाजना की स्थिति बदली और उनका महत्व बढ़ा। जब जमीन पर निजी मिलकियत आई और खेती के सामान की कीमतें होने लगी तो व्यापारी मध्यस्थ के रूप में, देशी त्रिदशी बाजार में सामान का बिक्री के लिए, किसान के लिए अपरिहाय हो गए।

चूँकि इनका काम इनकी भूमिका पहले से भिन्न थी, इसलिए कृषि के क्षेत्र में आधुनिक व्यापारियाँ और मूदखोर महाजना का वग एक नया वग माना जा सकता है। इनका संबंध नए पूँजीवादी जगत से था और जब यहाँ काम करते थे, वे प्रायः ब्रिटिश मध्ययुगीन भारतीय समाज में उनके काम से बिलकुल भिन्न थे। आधुनिक वाणिज्यिक बुजुर्गाजी भी नवविकसित वग थे।

ब्रिटिश शासन में कृषि उद्योग का देहाती एन शहरी सारा उत्पादन पण्य वस्तु हो गया। फलस्वरूप देशी शराब का विस्तार हुआ और देशी तिजारत करने वाले व्यापारियाँ का बहुत बड़ा वग तैयार हुआ। ब्रिटिश शासन काल में विदेशी बाजार से भी पहल की अपेक्षा अधिक बड़े पैमाने पर व्यापार शुरू हुआ। इसके चलते आयात निर्यात में लगे हुए बड़े व्यापारियाँ का वग का विकास हुआ। यह वाणिज्यिक बुजुर्गाजी बहुत बड़े पैमाने पर देशी विदेशी व्यापार में लगी।

प्रायः ब्रिटिश भारत में भी देशी विदेशी व्यापार चलता था, लेकिन जायतन और विस्तार में वह सीमित था। इसलिए प्रायः ब्रिटिश भारत में व्यापारी वग बहुत छोटा था। देश के जगत में इसका महत्व और विशिष्ट बल बहुत कम था।

नई जायिक स्थिति में जो नए वाणिज्यिक वग उत्पन्न हुए वे प्रायः ब्रिटिश युग के वैसे ही वर्गों से बिलकुल भिन्न थे। ये नए वग कृषि और उद्योग के देहाती और शहरी सभी प्रकार के उत्पादनों की तिजारत करते थे। ये जमींदार, पट्टेदार और किसान मालिकों से खेती के उत्पादनों की खरीद करते थे और उमदशी और विदेशी बाजार में बेचते थे। आधुनिक उद्योगों से भी वे माल खरीदते थे और भारत के अंदर और बाहर उस वकत थे। प्रायः ब्रिटिश भारत में देश के उत्पादन का बहुत बड़ा जग बाजार की सीमा के बाहर था वह खरीद बिक्री के लिए नहीं था। इसलिए उम वकत व्यापारी वग की भूमिका नगण्य सी थी। जब उनकी भूमिका जगत प्रभावशाली और भव्य हो गई।

रुलव की स्थापना और भारतीय व्यापारी वग एवं जमींदार तथा पेटेवर वग के कुछ सदस्यों के पास लाभ और वकत के पैसों के जमा होने के कारण (व्यापारिक वे पैसों पूँजी का काम कर सकते थे) भारतीय मिलकियत में मूती नारखानों, खनिज उद्योगों और उस ही जगत भारतीय उद्योगों की स्थापना हुई और देश में जीविक

बुजुआजी के नए वर्ग का जन्म हुआ। इसके साथ ही अनिवायत आधुनिक सव-हारा वर्ग का भी जन्म हुआ। भारतीय समाज में अब ऐसे नए समुदाय थे जैसे मिल मालिक, खान मालिक, नए पूँजीवादी उद्योगों के अधिपति, फिर मिल मजदूर, खान मजदूर रेलवे मजदूर बागान मजदूर आदि भी। ये वर्ग और समुदाय प्राक्-ब्रिटिश भारतीय समाज में नए थे, नए हो सकते थे क्योंकि आधुनिक कारखाने, खान, बागान और रेलवे भारत में पहले नहीं थे।

भारत में आधुनिक उद्योगों के उदय के साथ, आधुनिक बुजुआजी और मजदूर वर्ग का भी जन्म हुआ।<sup>8</sup> उन्नीसवीं सदी के अंतिम कुछ दशक में और उसके बाद भारतीय उद्योगों की स्थापना और तरक्की हुई। जैसे-जैसे इन उद्योगों में वृद्धि हुई, वैसे वैसे औद्योगिक बुजुआजी और मजदूर वर्ग बढ़े।

आधुनिक वकील, डाक्टर नई शिक्षण संस्थाओं से सवधित शिक्षक और प्राफेसर, आधुनिक वाणिज्यिक और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले मनजर और किरानी राज्य के प्रशासन तंत्र में काम करने वाले पदाधिकारी इंजीनियर रसायनविद टेक्नोलॉजिस्ट, कृषि अर्थविद, पत्रकार और अन्य लोगों के नए पेशेवर वर्ग भी ब्रिटिश काल में भारत में आविर्भूत हुए। नए आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के लिए आधुनिक कानून, टेक्नोलॉजी औपधि विज्ञान, अर्थशास्त्र, प्रशासन विज्ञान और अन्य विषयों में प्रवीण शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता थी। नए वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और प्रशासनिक व्यवस्था की ज़रूरतों के कारण ब्रिटिश सरकार को भारत में तेजी से नई नई शिक्षण संस्थाओं को खोलने के लिए बाध्य होना पड़ा। नए राज्य और समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानून वाणिज्य और अन्य विषयों के स्कूल कालेज खोले गए। इस तरह ज्यों-ज्यों नए प्रकार का समाज विकसित होता गया, वैसे वैसे आधुनिक पेशेवर वर्गों का जन्म और विकास हुआ। ये वर्ग आधुनिक उद्योग कृषि, वाणिज्य, वित्त प्रशासन प्रेम और नए सामाजिक जीवन के अन्य जगहों से जुड़े हुए थे। प्राक् ब्रिटिश काल में इनका अस्तित्व नहीं था क्योंकि उस वक्त इस तरह की सामाजिक, आर्थिक और वर्गीय व्यवस्था नहीं थी।

प्राक् ब्रिटिश भारत में गांव और जाति की पंचायत ही गांवों के न्यायिक, प्रशासनिक और आर्थिक कार्य संपादित करती थी। गांवों का बुद्धिजीवी वर्ग महज देहाती शिक्षकों और पुराहिता का वर्ग था जो सारे ग्रामीण समुदाय का सेवक था और लोगों के सांस्कृतिक धार्मिक त्रियाकलापों के लिए जिम्मेदार था। शहरों में पढ़े लिखे, पंडित और मौलाना, महान कलाकार और साहित्यिक, ज्यातिपि और रंगोलशास्त्री, वैद्य और हकीम कारीगर और हस्तशिल्पविद रहते थे। लेकिन ये रजवाडों अभिजातवर्गीय लोगों और धनी व्यापारियों के मातहत काम करते थे और प्रायः अपने मालिकों की ज़रूरतों का पूरा करने में लग रहते थे। वे साधारण जनता के लिए अपने ज्ञान का उपयोग नहीं करते थे जनसाधारण को उनसे बहुत लाभ नहीं था। उनकी बलात्कार, वैधानिक और तकनीकी सामर्थ्य

का लाभ मुख्यतः उनके मालिकों का ही हो पाता था।<sup>10</sup>

आधुनिक पेशेवर वर्ग ब्रिटिश शासन काल में आधुनिक पश्चात्य शिक्षा और संस्कृति के प्रसार और नए समाज की जरूरतों के आधार पर विकसित हुए थे और प्राकृतिक ब्रिटिश काल के ऐसे ही दला से बिल्कुल भिन्न थे। आर्थिक दृष्टि से उनका मान और उनकी कलात्मक वैज्ञानिक और तकनीकी कार्यकुशलता अब उस नागरिक के लिए थी जो इसके लिए पैसा दे सकता था। सामाजिक तौर पर ये नवविकसित पूंजीवादी समाज के अभिन्न अंग थे। फिर, इनके पास आधुनिक पश्चात्य विज्ञान और कला का मान था। वकीलों ने ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए और लागू किए गए कानून और विधिशास्त्र का अध्ययन किया, डॉक्टरों ने आधुनिक औषधि विज्ञान का मनन किया। इंजीनियरों आधुनिक टेक्नालाजिकल विज्ञान से परिचित हुए, शिक्षकों ने आधुनिक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, प्राकृतिक आदि विज्ञानों को पढ़ा पढ़ाया। पत्रकारों और लेखकों ने किताबें लिखीं और अखबारों का संपादन किया जो बाजार में बिके और जिन्हें लोगो ने हजारों लाखों की तादाद में पढ़ा। मनेजर्स और अफसरों ने राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से एकीकृत भारत को जटिल और विशद आर्थिक और प्रशासनिक राज्यतंत्र को चलाया और सारे राष्ट्र की जीवन मसलतों को सुलचाया। यह एक नया सामाजिक वर्ग था जो इसी तरह के प्राकृतिक ब्रिटिश भारत के स्वल्प वर्ग से भिन्न था, क्योंकि उन दिनों शिक्षक वर्ग या कलाकारों की प्रतिभा और क्षमता सीमित थी और उन पर या तो राज-रजवाड़ों का एकाधिकार था या छोटे से ग्राम समुदाय का।

ऊपर गिनाए गए नए वर्गों के अलावा, नागरिक क्षेत्रों में हर शहर और महानगर में, छोटे दुकानदारों और बनियों का भी एक बहुत बड़ा वर्ग था जो आधुनिक शहरों और महानगरों के विकास का परिणाम था।

### उत्तरजीवी पुराने वर्ग और उनकी परिवर्तित स्थिति

ब्रिटिश काल में भारत का सामाजिक अर्थतंत्र मध्ययुगीन आधार से आधुनिक पूंजीवादी आधार पर प्रतिष्ठापित हो चुका था और यह ऐतिहासिक दृष्टि से भारतीय समाज का आगे बढ़ा हुआ चरण था। लेकिन यह परिवर्तन उतना व्यापक और गहरा नहीं था जितना फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका जैसे देशों में हुआ था। भारतीय अर्थतंत्र विषयक पहल में एक अध्ययन में इस संकुचित विकास के कारणों की चर्चा हो चुकी है।

अपर्याप्त औद्योगिक विकास के कारण पुरानी आर्थिक व्यवस्था के अवशेष जैसे प्राकृतिक पूंजीवादी हस्तशिल्प और ग्रामीण कारीगर के उद्योग अभी बचे रह गए थे। पुराने अर्थतंत्र के इन अवशेषों के अनुसंगी प्राकृतिक पूंजीवादी भारतीय समाज के कुछ वर्ग, जैसे ग्रामीण कारीगर और शहरी हस्तशिल्पविदों भी अभी भारत में नए वर्गों के साथ विद्यमान थे।



लेकिन यह ध्यान देने की बात है कि पुराने वर्गों के ये अवशेष काय और लक्षण की दृष्टि से पुराने वर्गों के समरूप नहीं थे। पूजावादी पर्यावरण से घिरे होने के कारण इनके कुछ नए लक्षण भी थे अब वे ग्राम समुदाय के भृत्य की तरह काम नहीं करते थे लेकिन अपनी बनाई हुई चीजों को बाजार में लाने लगे थे। उसी तरह से नागरिक हस्तशिल्पकार भी काफी बड़ी तादाद में बच रहे थे, लेकिन अब केवल रजवाडों अभिजात वर्ग और धनी व्यापारियों के लिए ही काम नहीं करते थे। वे भी अपने उत्पादनों को बाजार में लाने लगें थे, यद्यपि टक्की और सगठन की दृष्टि से उनका पुराने वर्गगत लक्षण बने रहें।

छोटे बड़े भारतीय रजवाडा का वर्ग भी जो भारतीय भूभाग के लगभग एक तिहाई हिस्से पर शासन करता था प्राकृतिक काल का ही उत्तरजीवी अवशेष था। यह वर्ग इसलिए बचा रह गया था कि ब्रिटिश सरकार ने राजनीतिक कारणों से इसे बनाए रखने का फैसला किया था। ये रजवाडे अपने दरबार लगाते थे और दूसरे प्रकार से भी अपनी पुरानी कार्यप्रणाली और साज सज्जा को बनाए रखते थे। लेकिन वे प्राकृतिक काल के रजवाडा से कई बातों में भिन्न थे। उनके सारे प्रकाय परम सर्वोच्च ब्रिटिश सत्ता द्वारा अपहृत हो चुके थे या नियंत्रित थे। इन राज्यों की आर्थिक मरचना भी पहले से भिन्न थी। कृषिदास प्रथा जैसे पुराने आर्थिक और सामाजिक संबंधों के अवशेष के बावजूद, मूलतः इन राज्यों के अर्थ देश के राष्ट्रीय अर्थतंत्र के अंग हो चुके थे। इन राज्यों में से कुछ में एकाधिकारवाद चलता रहा फिर भी कुछ प्रगतिशील अग्रणी राज्यों में नई विधि व्यवस्था लागू हुई। इन राज्यों में जनतांत्रिक स्वतंत्रता थी ही नहीं या बहुत कम मात्रा में थी जिसके फलस्वरूप इन राज्यों के वाणिज्य का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास बड़ा संकुचित रहा।

इन कारणों से इन राज्यों के शासकों का वर्ग प्राकृतिक काल के रजवाडा के वर्ग से भिन्न नहीं माना जा सकता। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से इन राज्यों का आधुनिकीकरण नहीं हो सकता था, फिर भी ये अंग्रेजों के आने के पहले के राज्यों के प्रतिरूप नहीं माने जा सकते हैं।<sup>11</sup>

भारतीय रजवाडे मध्ययुगीन अभिजात वर्ग के भी शुद्ध सदस्य नहीं माने जा सकते वे भूमि से प्राप्त कर पर ही जीवन यापन करते थे। नए रजवाडों में कई एक नए आधुनिक वाणिज्यिक, औद्योगिक वित्तीय उद्योगों में पैसा लगाया ऐसे उद्योगों में भी जो उनकी अपनी राज्य सीमा के बाहर थे। इस तरह से कुछ हद तक यह वर्ग आधुनिक पूंजीपतियों के वर्ग में परिवर्तित हो रहा था, जिसका नए पूजावादी अर्थतंत्र से संबंध था।

उत्तरजीवी नए रजवाडा का वर्ग रजवाडों के पुराने वर्ग का ही परिशोधित रूप था और अपने नए रूप में भारतीय समाज के अर्थ नए वर्गों के साथ ही रह रहा था।

पुराने वर्गों के अवशेष बदल हुए रूप में नए वर्गों के साथ रह रहे थे, और

इसके कारण भारतीय समाज मश्लिष्ट जवयवी था, जिसमें विभिन्न और विराधा सामाजिक शक्तिया अपने विभिन्न हिता के लिए एक दूसरे क साथ मघष करती रही । नया भारतीय समाज नए पुरान वर्गा का वतरनीय जमाव था । यह नए पुराने सामाजिक तत्वा और दना मरना था । इस चरते नई पुरानी विचार धाराए एक दूसरे से अजीव तौर पर मिनी जुली चल रही थी । राष्ट्रीय चतना और राष्ट्रीय एकता की धीमी प्रगति का यह एक कारण था । जब हम ऊपर वताए गए वर्गों म जो प्रमुख थे उनके हिना चारित्रिक विघेपताजा समस्याओं कायक्रम, सगठन और आदोलना की मक्षिप्त चचा करेग ।

### जमीदार वग के हित और सगठन

हम दख चुके हे कि जमीदारो का वग मुख्यत ब्रिटिश सरकार का बनाया हुआ था ।<sup>1</sup> एन० एन० घोष ने लिखा हे, 'जमीदार जिसके साथ म्वाई उदोवस्त (पमनिट सेटलमट) किया गया लाड कानवालिम द्वारा निमित्त अभिजात वग था । वे राज्य की सृष्टि थे ।'<sup>2</sup> चूकि ब्रिटिश सरकार ने उनकी सृष्टि की थी इसलिए उन्होंने प्राय हरदम उसकी मदद की और उसका तभी विराध किया जब उनकी अपनी जमीदारी क अधिकारा पर किसी तरह का आघात हुआ । अपनी ओर से अग्रेजी सरकार ने भी उह भरोसे का राजभक्त माना और उनका पक्ष लिया । 'सर लारेस ने तालुकदारा को अपनी शक्ति भर सारा मान सम्मान दिया ।'<sup>3</sup> लाड लिटल ने साफ शब्दो मे कहा कि अग्रेजी शासन को भारतीय समाज के भूस्वामी अभिजातवग जैसी अनुदार रूढिवादी शक्तिया का समर्थन मिलना चाहिए (देखे अध्याय 10) । सुधार और मविधान की याजनाओ मे अग्रेजी सरकार ने जमीदारा को विशिष्ट प्रतिनिधित्व दिया (देखे अध्याय 10) और विद्यायिका सभाओ मे और बाहर भी इस वग न राष्ट्रवादी शक्तियो के विरुद्ध सरकार की सब तरह से मदद की । जब कभी इंडियन नशनल कांग्रेस ने उदारवादियो, जतिवादियो या गाधी के नेतृत्व म प्रजातान्त्रिक अधिकारा प्रशासनिक सुधार या स्वराज्य की माग रखी और इसके लिए ससदीय गर मसदीय सघर्षा का सगठन किया तब तब अभिजात वग ने सरकार का पक्ष लिया (देखें अध्याय 18) । इसकी वजह थी कि भूसंपन्न जाभिजात्य को यह भय था कि अगर देश का सामाजिक राजनीतिक और जायिक पुनर्निर्माण जनतान्त्रिक आधार पर हुआ तो उनक वग स्वार्थों और वग अस्तित्व पर भी खतरा जाएगा ।

जमीदार लोग मूलत रूढिवादी और अनुचमशील थे । 1851 म उन्होंने ब्रिटिश इंडियन एमोसिएशन नाम से अपना मुख्य सगठन कायम किया । इ० ए० माटस्यु न 1930 म प्रकाशित अपनी इंडियन डायरी म इस सगठन की या चर्चा की हे 'ब्रिटिश इंडियन एमोसिएशन बहुत हद तक रूढिवादी अनुदार सस्था हे जिसके मुखिया हे बदवान व महाराजा जा रूढिवादी भारतीय के सर्वोत्तम प्रतीक हे ब्रिटिश मवधो से उह घोर प्याग हे उनक प्रति निष्प्रिय मौन सहमति

नहीं, वरन् उनमें दृढ़ आस्था है व विनाश और मरण जमींदार है और स्वतन्त्र प्रभुत्व की सत्ता चाहते हैं।<sup>15</sup>

भारत में अंग्रेजों ने जो राज्यतंत्र स्थापित किया, उसमें सबसे पहले इन्हीं देशी राजाओं को स्थान मिला। 1862 में पटियाला व महाराजा और बनारस के राजा गवर्नर जनरल की विधान परिषद में मनोनीत हुए। मनोनयन के दूसरे चरण में जमींदार लिए गए। इस विषय में क० वी० कृष्ण ने लिखा है, 'राजा जमींदार, सेवा निवृत्त सरकारी पदाधिकारी, व्यापारी और पेशेवर वर्ग इसी क्रम में भारतीय विधान परिषद में मनोनीत हुए।'<sup>16</sup>

देश के जनजावन संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जमींदारों ने प्रायः अजनतांत्रिक कदम उठाए। वी० सी० पाल ने लिखा है 'लिटन कं प्रस ऐक्ट का विरोध करने के लिए इंडियन एसोसिएशन टाउन हॉल में कलकत्ता के वाशिदा की एक आम सभा बुलाई। बंगाल के जमींदारों का प्रतिनिधित्व करने वाली ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने इस सभा में जान स इकार कर दिया। लेकिन कलकत्ता और बंगाल ही नहीं वरन् दूसरे प्रदेशों के भी शिक्षित मध्यम वर्ग के इंडियन एसोसिएशन द्वारा किए गए विरोध का समर्थन किया।'<sup>17</sup>

चूँकि जमीन से होने वाली आय का बहुत बड़ा हिस्सा जमींदार हड़प लते थे इसलिए जमींदारी वाले क्षेत्रों में साधारण बटाईदारों की हालत दिन पर दिन बुरी होती गई। यह अधिकाधिक गरीब होत गए और अच्छी खाद अच्छे बीज आदि के अभाव में कृषि का भी हानि होता गया। राष्ट्रवादियों एवं ब्रिटिश राजनताओं ने भी जमींदारी वाले क्षेत्रों में कृषक अथवा श्रमिकों की ओर बटाईदारों की विपन्नता का देखा-समझा।

भूमि में जातिजात्य के देशी और विदेशी आलोचकों ने यह टिप्पणी की कि भारत में अत्याचार में जमींदारों की कोई उत्पादक भूमिका नहीं है। भारत की जावादी के बहुत बड़े जश की जायिक स्थिति कृषि पर निर्भर थी और इसके पुनरुद्धार और विकास के लिए एक बहुत जरूरी शक्ति यह थी कि जमींदारी पद्धति का निमूना नहीं तो कम से कम उसका बर्तानिक पुनर्गठन तो अवश्य हो।<sup>18</sup>

सामाजिक क्षेत्र में जमींदारों ने प्रायः आमूल सामाजिक सुधार का विरोध किया। दरभंगा महाराज ने जाति जसी अजनतांत्रिक प्रथा को बनाए रखने के पक्ष में यह दलील दी कि मानव सम्भ्रता के सामने आज जो दुरुह विपत्ति आ खड़ी हुई है उससे बचाव का एकमात्र उपाय है। (देखें अध्याय 14 जाति प्रथा के विरुद्ध धर्मयुद्ध)। कुछ प्रबुद्ध जमींदारों ने जनतांत्रिक-सामाजिक प्रगति का समर्थन किया और बस आंदोलन की मदद की, लेकिन बगत उनका रव दक्षिण-पक्षी विरोध नहीं था। रिलिजन एंड दि राइज आफ कैपिटलिज्म' में टोनी ने लिखा है 'मुख्यतः भूमि पर आश्रित राष्ट्र का मनोविज्ञान वाणिज्यिक समाज के मनोविज्ञान के विरुद्ध विपरीत होता है। वाणिज्यिक समाज में, अगर ठीक है तो अविच्छिन्न विस्तार जीवन का विधान माना जा सकता है

सामन जाते रहते हैं और 'उद्यम को प्रोत्साहन' राजनीति का नारा हाता है। लेकिन कृषि प्रधान समाज में जिन दरवा में हर नई आन वाली पीढी फिट की जा सकती है, उनकी संख्या कम है आदोलन का जग ह जशाति, उत्पात और राजनीतिज्ञो का उद्देश्य होता है व्यक्तिगत पहलू-उदमी को प्रोत्साहन देने क बदले सामाजिक अव्यवस्था को रोकना।<sup>19</sup> भारतीय जमींदारों ने पूरी ताकत से सुधार और प्रगति का विरोध किया।

राष्ट्रवादी आदोलन भारतीय समाज के जनतांत्रिक पुनर्गठन का कार्यक्रम को लेकर चला या फिर वाद में किसानों, पट्टेदारों और खेत मजदूरों को भी तगडे आदोलन हुए। इसलिए जमींदार अपने स्वार्थों और अधिकारों की रक्षा के लिए पहले से अधिक ब्रिटिश सरकार का सहारा ढूँढने लगे। अपने संगठनों के द्वारा उन्होंने विधायिका सभाओं में उचित प्रतिनिधित्व की भी मांग की।

### पट्टेदारों के हित और संगठन

जमींदारी की सृष्टि के साथ ही भारत में पट्टेदारों के भी वर्ग का जन्म हुआ। चूंकि पट्टेदारों से बहुत अधिक लगान वसूला जाता था इसलिए वे गरीब होते गए। वे जमींदारों द्वारा लगातार सताए जाते रहे। जस जैसे समय बीता, जमींदार और खतिहर बटाईदार के बीच अनकानूक मध्यस्थों के वर्ग बनते गए और खेतिहर बटाईदारों की हालत दिन पर दिन और बिगड़ती गई। 1859 और 1885 के बंगाल टेनेसी एक्ट ने बटाईदारों की हालत सुधारने की दिशा में काम किया। फिर भी इसके अधिनियमों से बहुत फायदा नहीं हुआ। अधिकांश बटाईदारों की हालत दिन ब दिन बुरी ही होती गई। जमींदारों के क्षेत्र में बटाईदारों के वर्ग के अतिरिक्त रयतवारी क्षेत्रों में भी बटाईदारों का नया वर्ग उत्पन्न हुआ। रयत मालिकों की बढ़ती हुई गरीबी के कारण जमीन लगातार जयस्रवासी भूस्वामियों के हाथ में जान लगी।

धीरे धीरे विभिन्न प्रदेशों के बटाईदारों में जागरण आने लगा।<sup>20</sup> उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और दूसरे क्षेत्रों में उन्होंने अपना जलग संगठन कायम किया था वे किसान सभाओं में शामिल हुए। किसान सभाएं सब जगह संगठित हो रही थीं और इनमें किसान बटाईदार और खेत मजदूर खेत में काम करनेवाले सब प्रकार के लोग शामिल थे। बटाईदारों के इन संगठनों और किसान सभाओं ने बटाईदारों की विशेष मांगों और शिकायतों की सूची बनाई और इन मांगों के समर्थन में आदोलन भी संगठित किए। इन मधो, सभाओं, आदोलनों के संगठनकर्ता जवाहरलाल नेहरू, प्रोफेसर एन० जी० रंगा स्वामी सहजानंद जैसे धीरे राष्ट्रवादी नेता थे। इसलिए जमीन पर काम करनेवाले जय लोगो के साथ बटाईदार भी राष्ट्रवादी प्रचार से प्रभावित हुए और अपने वर्ग की मांगों के साथ एन जपन ऋडे के नीचे वे राष्ट्रवादी आदोलन में सम्मिलित हुए। आर्थिक और सामाजिक तौर पर पिछड़े हुए इन बटाईदारों में भी धीरे धीरे राष्ट्रवाद की भावना का

प्रवेश हुआ। किसान सभाओं और बटाईदार सघों ने केवल ब्रिटिश सरकार की ही आलोचना नहीं शुरू की वरन् इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी आलोचना की, क्योंकि इनके अनुसार यह मुख्यतः जमींदारों के स्वार्थों की रक्षा करना चाहती थी। उन्होंने अपनी मांगों का कार्यक्रम बनाया—मालमुजारी कम करना, अधिक कर या गैर कानूनी पावना वसूल करने के रिवाज को खतम करना, आदि। किसान सभाओं ने जमींदारी प्रथा को खर्चीला और अक्षम, अकुशल और अय्यायपूर्ण एवं राष्ट्र विरोधी बताया।

### किसान मालिकों के विभिन्न उपभाग, हित और संगठन

रैयतदारी के रूप में भूमिगत संपत्ति की मजबूती के कारण भारत में किसान मालिकों का वर्ग पैदा हुआ। यह मोटे तौर पर अपनी आर्थिक सामर्थ्य के अनुसार तीन मुख्य श्रेणियों में विभाजित था, ऊपरी मध्यम और निम्न। भूमिकर की ऊंची दर, ऋणग्रस्तता और ऊपर गिनाए गए अन्य कारणों की वजह से यह वर्ग अपने अस्तित्व काल से ही अधिकाधिक दरिद्र होता गया था। यह स्थाई विघटन की स्थिति में था। इस वर्ग में विशिष्टीकरण की प्रक्रिया लगातार जारी रही। किसान मालिकों के दल का जल्पाश धनी किसानों की श्रेणी में समाहित होता रहा और अधिकांश गरीब किसानों, अय्यनवासी भूस्वामियों के बटाईदारों या खेत मजदूरों की श्रेणी में। जैसे-जैसे किसानों के दरिद्रीकरण की गति तेज हुई वैसे-वैसे विभेदीकरण की यह प्रक्रिया भी तीव्र होती गई। इस तरह जमीन तेजी से किसान मालिकों के हाथ से निकलकर साहूकारों, व्यापारियों आदि के हाथ में जाती रही और दूरस्थ भूस्वामियों के नए वर्ग का जन्म हुआ। किसानों का मध्यम तबका तेजी से विघटित होता गया, और ज्यों-ज्यों इनमें से अधिकांश निम्न किसान या दरिद्रों या कृषक-सवहारा की श्रेणी में मिलत गए इनकी संख्या कम होती गई। जसा कृषि वान-जघ्याय में हमने देखा है दूरस्थ भूस्वामियों और कृषक-सवहारा वर्गों के वर्गों में बड़ी तेजी से बढ़ते रहे।

किसान मालिकों में बटाईदारों की अपेक्षा पहले राष्ट्रीय चेतना का प्रादुर्भाव हुआ। इसकी वजह थी कि किसान मालिकों का सीधा संबंध राज्य से था। किसान मालिकों सीधे राज्य को भूमिकर देते थे। उसके विपरीत कर के मामले में बटाईदारों का सीधा संबंध जमींदारों से था, सरकार से नहीं।

एक और वजह थी जिसके कारण किसान मालिकों में बटाईदारों की अपेक्षा पहले राजनीतिक चेतना आई। इंडियन नेशनल कांग्रेस गांधी की अगुआई में वर्ग सम-वय की गांधीवादी विचारधारा द्वारा शासित थी और उसी विचारधारा के आधार पर अपना कार्यक्रम बनाती थी।<sup>1</sup> बटाईदारों की मांगों के लिए सघों का कार्यक्रम उस वर्ग का समर्थक और जमींदारों का विरोधी होता। और चूंकि जमींदारों और बटाईदार दोनों भारतीय थे इसलिए गांधीवादी विचार के अनुसार स्वराज के सघों के लिए वने सभी वर्गों के राष्ट्रीय समुक्त मोर्चे को बटाईदारों की

मागो के प्रश्रय से नुकसान होता। फिर भी, किसान आंदोलन का इंडियन नेशनल कांग्रेस पर कुछ प्रभाव पड़ा और इसे बटाईदारों की मागो का कार्यक्रम अपनाने के लिए बाध्य होना पड़ा। लेकिन ग्रामी सहजानंद, एन० जी० रंगा, दुलाल यागिनिक और किसान आंदोलन के अन्य नेताओं की यह शिक्षायत्त थी कि कांग्रेस के नेतृत्व ने इस कार्यक्रम में रुचि नहीं ली। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार और कुछ अन्य प्रदेशों में गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित दक्षिणपंथी नेता बटाईदारों के खिलाफ जमींदारों से मिल गए थे, और कांग्रेसी सरकार ने बटाईदारों के न्यायसम्मत सघप के विरुद्ध राज्यसत्ता का दमनात्मक प्रयोग किया।<sup>22</sup>

### भारतीय किसानों के प्रमुख आंदोलन

अब हम संक्षेप में ब्रिटिश शासन काल के भारतीय किसानों के आंदोलनों और भेत मजदूरों के मुख्य आंदोलनों और संगठनों की चर्चा करेंगे।

1918 के बाद किसानों में राजनीतिक चेतना की शुरुआत हुई। वे मजठित राष्ट्रीय संघर्षों में भाग लेने लगे और बाद में उन्होंने अपने-अपने संघों और कार्यक्रमों के साथ अपने संगठनों भी बनाए और अपने-ही नेताओं की अगुआई में अपने कार्यक्रमों की पूर्ति के लिए संघर्षों का संगठन किया। लेकिन 1918 के पहले भी कुछ किसान आंदोलन हुए थे जो स्वतंत्र स्फूर्त और अनियमित थे और जिनके सीमित, स्थानीय आर्थिक उद्देश्य थे।

1870 और 1897 के बीच भारत में कई बहुत बड़े दुर्भिक्ष पड़े, जिनमें 1870-1896 और 1897 के अकाल सबसे अधिक विनाशकारी थे। अकाल वाले क्षेत्रों में किसानों का बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ा। गीच-बीच में होने वाले आर्थिक संकटों के कारण भी उनकी बड़ी तकलीफें हुईं। फलस्वरूप समय-समय पर जमींदारों साहूकारों और सरकारों के विरुद्ध किसानों के संघर्ष उभरते रहे।

1870 में बंगाल के बटाईदारों आर्थिक संकट की गहरी चपट में आए और उनकी गरीबी गहन हो गई। हजारों ने जानबूझ कर लगानों से इन्कार कर दिया, कचहरिया के हुकमनामा का उल्लंघन किया, प्रदखली का विरोध किया जो हथियार प्राप्त थे उन्हें से लड़ाई की। बंगाल और मथाली देहाती किसानों के बहुत बड़े हिस्से में लगभग अज्ञानता की स्थिति थी। विद्रोह का तात्पर्य न देना दिया लेकिन उसने एक कमीशन बैठाया और बाद में 1885 का प्रणाली टनेसो ऐक्ट बना।

अमरीकी गह-गुड़ के बांध रुई की कीमत में मंदी आने से भी भारतीय किसानों की हालत खराब हुई। फलस्वरूप उन पर ऋण का बोझ बढ़ा और 1970 में डेक्कन में मराठा किसानों साहूकारों के खिलाफ उठ खड़े हुए क्योंकि साहूकारों ने कचहरी की मदद से बंदखनी का डर दिखाया। उन्होंने भूदखारों के घरा पर हमला किया कर्जों के वागजात नष्ट कर लिए और कुछ लोगों को जान से भी मार डाला। बलवा शांत कर दिया गया लेकिन सरकार ने किसानों के लिए

रिलीफ की जरूरत ममझी और 1879 का डेक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ ऐक्ट पारित हुआ।

उन्नीसवीं सदी के अंतिम दशक में, जब सूखखोरो ने वेदखली का भय दिखाया, ता पजाब में भी किसान बिद्रोह कर उठे। स्थिति का शांत करने के लिए सरकार ने 1902-3 में पजाब एलियनशन ऐक्ट पारित किया। लाड कजन के जमाने में भूमिकर नीति पर सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसका उद्देश्य था जमींदारों की मांग के दबाव से बटाईदारों की रक्षा करना।

इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1905-19 की अवधि में किसानों को राहत देने की जरूरत पर उतना जोर नहीं दिया जितना भारतीय उद्योगपतियों की जरूरतों पर, जैसे वाणिज्यिक सुरक्षा के प्रश्न पर।<sup>23</sup> राष्ट्रवादी लोग साधारणतः जमींदारों तथाकथित रूप से रहने वाले बटाईदारों की चर्चा से अलग रहे। कांग्रेस के एक भूतपूर्व सभापति रमेशचंद्र दत्त को दी गई लाड कजन की इस चुनौती का कि जमींदारों की धनप्रियता से बटाईदारों को बचाने की सरकार ने जोरा से अधिक कोशिश की है जवाब नहीं दिया जा सका था।<sup>4</sup>

1917-18 में गांधी के नेतृत्व में बिहार के चंपारन जिले में किसानों ने नील बगीचों के मालिकों को अतिक्रमण यूरोपीय थे, के खिलाफ सघष किया। यहाँ पहली बार गांधी ने सत्याग्रह के अपने अस्त्र का प्रयोग किया। सरकार ने एक जाच कमेटी बठाई जिसके गांधी भी सदस्य थे और इस कमेटी के प्रतिवेदन के आधार पर जो अधिनियम बना उससे किसानों का कुछ राहत मिली। एन० जी० रंगा इस सघष में गांधी के नेतृत्व के विरुद्ध थे और उन्होंने कहा जिस तरह रमेशचंद्र दत्त के नेतृत्व में अस्थाई बंदोबस्ती के खिलाफ चलाए गए आंदोलन ने जमींदारों द्वारा किसानों के शोषण की बात नहीं की वैसे ही चंपारन में गांधी के नेतृत्व वाला आंदोलन भी चंपारन के किसानों की गरीबी और तकलीफ के मूल कारणों के विरुद्ध सघष का रूप नहीं ले सका। ये मूल कारण थे, अत्यधिक लगान और ऋणभार यह बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है कि गांधी और राजेन्द्र प्रसाद दोनों जमींदारी व्यवस्था के अग्रय के विरुद्ध धर्मभीरुओं की तरह चुप रहे।<sup>25</sup>

इसके बाद गांधी ने कर की वसूली के विरुद्ध कैंरा के किसानों का सत्याग्रह आंदोलन सगठित किया। ये किमान फसल मारे जाने की वजह से लगान का भुगतान नहीं कर पाए थे। 1919 के अमहयाग आंदोलन के पहले के ये ही कुछ प्रमुख किसान आंदोलन थे। इन आंदोलनों में राजनीतिक तथ्य का अभाव था, और ये प्रायः अनियमित और जराजक थे।

असहयोग आंदोलन के दिनों में भारतीय किसानों के कुछ अंश में राजनीतिक चेतना आई। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भूमिकर न देने का नारा दिया और इसका बहुत गहरा असर पड़ा। किसानों ने स्वराज्य के राजनीतिक सघष के भूमिकर के विरुद्ध सघष माना और उनमें से कुछ ने इस आंदोलन के साथ नुभूति दिखाई उसे समर्थन दिया और उसमें भाग लिया।

जादोलन में भारतीय किसानों ने पहली बार हिस्सा लिया।

जसहयोग जादोलन के दिना में किसानों के ऐसे भी मधप हुए जिन्हें वाप्रस न नहीं संगठित किया था जम कर्नाटक के गुदूर जिले में 1921 का जवध रेंट ऐक्ट भी इसी काल में पारित हुआ था और इससे किसानों की बहुत सारी मांगों की पूर्ति हुई।

1922 के मोपला विद्रोह का आधार सांप्रदायिक और आर्थिक दोनों थे। मोपला मुख्यतः मुसलिम किसान थे और मानावार के नम्बूदिरी ब्राह्मण जमींदार उनका शोषण करते थे। मोपला के अंतर्गत को मुसलिम सांप्रदायवादियों ने सांप्रदायिक दिशा दी, जिसके फलस्वरूप जा जादोलन तत्त्वतः आर्थिक था उसका रूप धार्मिक हो गया और इससे जान-माल का दानाक, गैर जरूरी नुकसान हुआ। जहां भूस्वामी हिंदू और किसान मुसलमान थे वहां सांप्रदायवादियों की उत्प्रेरणा और उनके द्वारा भड़काए जाने से आर्थिक वगैरे मधप ने सांप्रदायिक रूप लिया।

दो और किमान मधपों की चर्चा आवश्यक है। एक तो नरसिपत्तन तालुका के कोया लागा का मधप जिसके नेता थे सीतागम राजू दूसरा रायवरेना सीतापुर और उत्तर प्रदेश के जय जिला के किमानों का मधप। लेकिन ये मधप स्वतः स्फूर्त थे, उन्नीसवीं सदी के मधपों जैसे।

जसहयोग आदोलन के बाद ही किसानों के स्वतंत्र वगैरे संगठन के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। जात्र में 1923 में रैयता और खेतिहर मजदूरों के जपन जलंग संगठन बने। 1926-27 में पंजाब बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में किसान सभाओं की स्थापना हुई। 1920 में बिहार और उत्तर प्रदेश की किसान सभाओं के प्रतिनिधियों ने मोतीनाल नेहरू की अध्यक्षता में होने वाले सर्वदलीय सम्मेलन का एक स्मारक पत्र दिया जिसमें सावजनीन मताधिकार, आधारभूत जनतांत्रिक अधिकार और राष्ट्रीय स्वतंत्रता की मांग प्रस्तुत की गई थी। 1928 में जाध्र प्रदेश के रयला का संगठन बना।

गुजरात में वारदोली जिले के किसानों के दो मधप हुए, एक 1928-29 में और दूसरा 1930-31 में। पहले के नेता बल्लभ भाई पटेल थे और सरकार से अधिकार मांगों को मनवा लेने में इस जादोलन को जो सफलता मिली उससे किसान आंदोलन को बड़ा पल मिला।

1930 में गांधी कांग्रेस के निर्विवाद नेता थे। उन्होंने समझौते के लिए जपेजी सरकार के सामने अपनी ग्यारह सूची मांग रखी। वामपंथी राष्ट्रवादियों और समाजवादियों ने उनकी इस आधार पर आलोचना की कि इन ग्यारह मुद्दों में भारतीय पूंजीपतियों की सभी मुख्य मांगें शामिल थीं, लेकिन भारतीय मजदूरों और किसानों की कोई मांग नहीं थी। \* एन० जी० रंगा ने लिखा है महात्मा जी ये मांगें तो रख ही सकते थे कि जमींदारों द्वारा बसूल किए जाने वाले लगान में कमी की जाए, किमानों को ऋण से छुटकारा दिलाया जाए मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी निश्चित की जाए मूल उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया



जाए वगैरह सहयोग की अपनी नीति और अपनी इस चिंता के कारण कि लोग आर्थिक स्वार्थों के आधार पर राजनीतिक दलों में विभक्त न हो जाए गांधी इस तरह की मांग रख भी नहीं सकते थे।<sup>7</sup>

1929 में सारी दुनिया में जो कृषिक और अन्य प्रकार के आर्थिक संकट उसका भारतीय किसान समुदाय पर बड़ा गहरा असर पड़ा। इस विक्षुब्ध किसान समुदाय ने कांग्रेस द्वारा संगठित आंदोलन और सभाओं में भाग लिया। उत्तर प्रदेश, आंध्र, गुजरात कर्नाटक और अन्य भागों में किसान आंदोलन हुए जिनमें कुछ को कांग्रेस का समयन मिला कुछ को नहीं।<sup>8</sup>

नागरिक अथवा आंदोलन के बाद किसानों के स्वतंत्र संगठनों के निर्माण की प्रक्रिया में तजी आई। किसान आंदोलन के जाग बड़े हिस्सा और उग्र राष्ट्रवादियों में यह धारणा घर करती जा रही थी कि कांग्रेस का नेतृत्व पूंजीपतियों और बड़े बड़े भूस्वामियों के स्वार्थों के प्रति अत्यधिक जागरूक था। उनका खयाल था कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए उनके स्वतंत्र वगैरह संगठनों और नेतृत्व की आवश्यकता है। उनका यह भी खयाल था कि जब किसान अपनी वगैरह की मांगों के साथ स्वराज्य के राष्ट्रीय संघ में भाग लें तभी यह संघ सफल हो सकेगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और जवाहर लाल जैसे वामपंथी राष्ट्रवादियों ने दश में किसान संगठनों के निर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया।

इस सदी के चौथे दशक में किसान आंदोलन ताकतवर होने लगा। किसान आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ताओं को प्रचार और आंदोलन का प्रशिक्षण देने के लिए 1938 में निद्रोल में पहला भारतीय किसान स्कूल खोला गया। 1935 में मद्रास प्रेसीडेसी रयट्स एसोसिएशन कायम हुआ, और 1937 में मद्रास प्रेसीडेसी एग्रीकल्चरिस्ट एसोसिएशन।

किसानों का सांप्रदायिक आधार पर भी संगठित करने की चेष्टा हुई। मुसलिम किसानों का गोलबंद करने के लिए सर अब्दुररहीम और फजलुलहक ने वगाल में प्रजा पार्टी का संगठन किया। बाद में इसका नाम कृषक प्रजा पार्टी हुआ। इसने कृषि संबंधी सुधारों और जमींदारी उन्मूलन का कार्यक्रम बनाया। वगाल के मुसलमान किसानों में इस पार्टी का काफी प्रभाव था।

1927 में बिहार किसान सभा बनी। 1934 के बाद यह संगठन काफी व्यापक हो गया था। इसका श्रेय स्वामी सहजानंद सरस्वती का है। जाल इंडिया किसान सभा का, जो बाद में बनी, सबसे मजबूत वगैरह बिहार किसान सभा ही थी। उत्तर प्रदेश प्रांतीय किसान सभा 1935 में बनी। इसके कार्यक्रम में जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन की भी मांग थी। दश के दूसरे भागों में भी किसान सभाएं बनीं।

किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने कई नए कदम उठाए। उत्तर प्रदेश में 1934 में पांच डेट रिलीफ एक्ट में, पंजाब में 1934 में ही रगुलेशन आफ एकाउंट्स ऐक्ट पारित हुआ वगाल में 1933 में मनीलैंड्स ऐक्ट पारित हुआ और 1935 में रिलीफ आफ इंडेब्टेड्स ऐक्ट। इन सबके बावजूद किसानों की हालत

बहुत सुधार नहीं हुआ। इसलिए उनका असताप बढ़ता गया और किसान जादो लन में तीव्रता जाती गई।

1935 में लेखनऊ में पहला आल इंडिया किसान कांग्रेस की बैठक हुई और यह तय हुआ कि यह कांग्रेस देश में सर्वोपरि किसान संगठन हो। जवाहरलाल नेहरू ने इस कांग्रेस के प्रति सहानुभूति और समर्थन का इजहार किया।

आल इंडिया किसान कांग्रेस देश की सारी कृषक जावादी का जपन प्रभाव में नहीं ला सका, लेकिन इसकी स्थापना का ऐतिहासिक महत्व है। सम्मिलित मागों के कार्यक्रम और सार किसानों की समवेत जाकाशाजा के आधार पर देश के इतिहास में पहली बार किसानों का अखिल भारतीय संगठन बना। यह संगठन नई उच्चतर चेतना के उदय का परिचायक था और इस तरह प्राकृतिक भारतीय किसान के स्थानीय परिप्रेक्ष्य की जगह राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का जन्म हुआ।

आल इंडिया किसान सभा ने भारतीय किसानों के बीच बहुत बड़े पैमाने पर शिक्षा और प्रचार का काम किया। इन्होंने देश में अपने संगठन का विस्तार भी किया। इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस से सामुदायिक संबद्धता की भी माग की। लेकिन कांग्रेस इस माग को स्वीकार नहीं कर सकी।

1937 में नए संविधान के आधार पर प्रांतीय विधायिका सभाओं के लिए होने वाले चुनाव के पहले, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक चुनाव घोषणा पत्र प्रकाशित किया जिसमें नागरिक स्वातंत्र्य संबंधी जनतांत्रिक मागों और किसानों की हालत में सुधार की मागें भी थीं। किसानों को इस घोषणा पत्र से काफी बल मिला और कांग्रेसी उम्मीदवारों के पक्ष में इनका मतदान चुनाव में उनकी जीत के लिए बहुत दूर तक उत्तरदाई है।

वाद में कई प्रांतों में जो कांग्रेसी सरकारें बनीं उन्होंने किसानों से किए गए वादों को पूरा नहीं किया। कुछ प्रांतों में उन्होंने कृषि संबंधी कुछ अधिनियम पारित किए (विस्तार के लिए देखें अध्याय 10), लेकिन इनसे किसानों के निम्नतम स्तर को कोई फायदा नहीं हुआ। कांग्रेसी सरकार से किसानों के असंतोष की अभिव्यक्ति विरोध सभाओं, सम्मेलनों और प्रदर्शनों में हुई। इन सभाओं, सम्मेलनों में किसान नेताओं को गिरफ्तारी, किसानों की सभाओं पर प्रतिबंध, और खासकर बिहार में किसानों के विरुद्ध पुलिस की ताकत के प्रयोग आदि के लिए सरकार की जालोचन की गई।

असंतोष माग मनवान के लिए सरकार पर दबाव डालने के लिए कांग्रेसी सरकारों के जमानत में किसान सभाओं ने बहुत सी सभाओं, सम्मेलनों और किसान मोर्चों का संगठन किया। कांग्रेस के दक्षिण पश्चिम में सभाओं और कांग्रेसी मंत्रियों को इस बात से शिक्षाप्रद थी कि जब कांग्रेसी सरकारें काम कर रही थीं, उस वक़्त गरमसदीय विरोध का संगठन किया गया। 1934 के बाद किसान आंदोलन के विकास काल में कई जगहों पर किसानों के बीच स्वयंसेवक संगठन भी बने।

## किसानों के विशिष्ट मानसिक और चारित्रिक लक्षण

मालिक किसानों, बटाईदारों और खेत मजदूरों के विकास, उनकी हालत और उनके आंदोलनों और संगठनों की चर्चा के बाद अब हम इन सामाजिक वर्गों के विशिष्ट मानसिक एवं चारित्रिक लक्षणों की चर्चा करेंगे।<sup>29</sup>

मालिक किसानों की अपनी जमीन थी जिस पर वे काम करते थे और जिसकी उपज वे बाजार में बेचते थे इन आधारों पर वनी उनकी अपनी मनश्चेतना थी। चाहे कम ही सही किसान मालिकों को अपनी मर्पति तो होती है, इसलिए साधारणतः उनका दृष्टिकोण रूढ़िवादी होता है और उनमें वह साहसिकता नहीं होती जो मर्पतिहीन मिल मजदूरों में होती है। विभिन्न देशों का यही साधारण अनुभव है। फिर वैयक्तिक उत्पादन की रीति जिससे मालिक किसान खेती करता है, उसके कारण भी वह व्यक्तिवादी हो जाता है और किसी भी सहयोगी प्रयास में सम्मिलित होना उसके लिए कठिन होता है। इस मुद्दे पर किसान और मिल में काम करने वाले मजदूर में अंतर है क्योंकि मिल का काम व्यापक श्रमविभाजन पर आधारित है। इसीलिए किसानों के संगठनों के पहले मजदूरों के ट्रेड यूनियन बन। इसीलिए यद्यपि किसानों की स्थिति प्रायः मजदूरों से बुरी रही है फिर भी उनकी अपेक्षा मजदूर वर्ग में सहयोगी, संगठित आर्थिक और राजनीतिक काम अधिक हुए हैं।

किसान बहुत बड़े क्षेत्रों में बिखरे हुए हैं। इसलिए भी किसानों के बीच संगठनात्मक काम अधिक मुश्किल रहा है।<sup>30</sup> फिर किसान देहात में रहते हैं जो सामूहिक तौर पर पिछड़ा हुआ इलाका है, और जहाँ जिदगी मजदुर एन्टरस गति से चलती है, जबकि शहरों में देश की संस्कृति केंद्रीभूत है समसामयिक जीवन की गत्यात्मक प्रक्रियाएँ कार्यरत हैं सामाजिक राजनीतिक, आर्थिक और अन्य आंदोलन जगत बढ़त हैं। नागरिक संस्कृति और आधुनिक जीवन की गत्यात्मक प्रक्रियाएँ संप्रत्यक्ष, और सांस्कृतिक रूप से विपन्न देहात में पला-पासा किसानों में अपेक्षाकृत सुस्त मदबुद्धि और अशिक्षित होता है। शिक्षक एवं सांस्कृतिक कार्यकर्तों और राष्ट्रवादी प्रचारकों ने शहरी जावादी के निम्नतम स्तर की अपेक्षा किसानों में व्यापक सामाजिक राजनीतिक एवं अर्थ-व्यवस्था के काम करना अधिक कठिन पाया।

देश के कुछ अन्य पिछड़े हुए लोगों की तुलना में किसानों के अधिक अध-विश्वासी एवं शिथिल होने का एक और कारण है। उद्योग के विपरीत कृषि मुख्यतः वर्षा जैसी प्राकृतिक शक्तियों पर निर्भर है और इन पर विज्ञान और टेक्नालाजी का पूरा नियंत्रण नहीं हो सका है। अच्छी जमीन अच्छे बीज अच्छे हल बैल और अपना श्रम फसल के लिए बचल इन्हीं की ज़रूरत नहीं है, अच्छी फसल जगत प्रवृत्ति की अनियंत्रित शक्तियों पर निर्भर है। इसके कारण किसान अक्सर अध-विश्वासी हो जाता है और कुछ हद तक अधिक आत्ममंथनी और

पराजयवादी भी। इसीलिए देहात की आवादी में अधविश्वास पलत है। सुमगठित, सामूहिक काय द्वारा जीवन सघप में रत होने के बदल किमान निस्सहाय से सकट के सामन नतमन्तर हा जात है, या फिर जब वे स्वत स्फूत, अमगठित और निष्फल विद्राह का रास्ता अपनाने हैं ता निराशो मत्त जादमी के अधे साहस के प्रतीक के रूप में।\*

राष्ट्रीय आंदोलन का विकास सामाजिक राजनीतिक और जय प्रकार के कायकर्ताओं के शैक्षिक और प्रचारात्मक काय, उनकी अपनी बढ़ती हुई गरीबी, आदि महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कारणों से, शिथिल गतिशील, क्रियाहीन भारतीय किसान की सामाजिक और मानसिक जडता और धक्कमप्यता समाप्त होने लगी। जैसा ऊपर बतलाया जा चुका है, धीरे धीरे ही सही, वे अपने सगठन बनाने लगे, अपनी माग को रूप देने लगे और अपने वग एव राष्ट्र के आंदोलनों में भाग लेने लगे। इसकी यह भी वजह थी कि भारतीय राष्ट्रवादी यह समझने लगे थे कि किसानों की मदद के बिना वे स्वतंत्रता नहीं प्राप्त कर सकते और इस तरह वे उन पर अधिक ध्यान देने लगे। कांग्रेसी सोशलिस्ट कम्युनिस्ट आदि सब दलों ने किसानों के बीच काम करना शुरू किया।

कृषक आवादी के बीच विभेदीकरण की तीव्र प्रक्रिया के कारण खेत मजदूरों का वग तर्जों से बढ रहा था। इस वग के पास कोई संपत्ति नहीं थी, ये गरीब थे, अपने पिछड़ेपन की वजह से इनमें अब भी पूरी चेतना का विकास भी नहीं हो सका था। लेकिन किसान आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन की चपेट में ये भी आ रहे थे।

### आधुनिक बुद्धिवादी वग का उदय

अब हम भारतीय जनता की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास परंपरा में बुद्धिवादियों की भूमिका का अवलोकन करें।

भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना और औद्योगिक बुजुर्गों के उदय के कई दशक पहले ही आधुनिक बुद्धिवादी वग का जन्म हो चुका था।<sup>31</sup> भारत में

\* बहुत बड़े क्षेत्र में विद्यमान विभिन्न प्रकार के सामाजिक सगठन और हितवादिता जसा आर्थिक सामाजिक मानसिक जविक कमजोरिया के कारण सामाजिक सघर्षों के इतिहास में किसानों की अपना कोई स्वतंत्र भूमिका नहीं होती। आधुनिक काल में यह याता बज जाजी का था फिर मजदूर वग की जगुआई में रण। 1789 की फ्रेंच क्रांति में इपि दासा ने उध्वोमुखा बुजुर्गों का नतत्व माना जिमने मामता जाभिजात्य के विरुद्ध अपने सघप में उनके महयोग के लिए उन्हें स्वतंत्रता और जमान प्रदान करने का वादा किया। 1917 की रूसी क्रांति में किसानों ने बोल्शविक पार्टी का समर्थन किया। केवल रूस के मजदूर वग का इस पार्टी ने ही उन्हें जमान दिलवाने का वादा किया। सामल रिवाल्युनरी पार्टी जा विभिन्न तबका के किसानों का प्रतिनिधित्व करती थी टूट गई और उनका वामपंथी भाग बोल्शविक दाला में मिन गया।

बुद्धिवादियों की पहली पीढ़ी के राजा राममोहन राय और उनके दल ने पाश्चात्य सस्कृति का अध्ययन किया और इस सस्कृति के बौद्धिक और प्रजातान्त्रिक सिद्धांतों, धारणाओं और सत्य का अंगीकृत किया।

उन्नीसवीं सदी के प्रथम कुछ दशकों में शिक्षित भारतीयों की संख्या बहुत कम थी। जब अंग्रेजी शासन ने अधिकाधिक स्कूल कालेज खोले और उनके साथ ईसाई मिशनरियों ने भी इस दिशा में प्रयास किए तभी उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में शिक्षित भारतीयों के बहुत बड़े वर्ग का जन्म हुआ और उससे बुद्धिवादियों का बहुत बड़ा वर्ग उभर कर सामने आया।

आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास में बुद्धिवादियों की भूमिका निर्णायक रही है। बहुत दूर तक उन्होंने भारतीय जनता का आधुनिक राष्ट्र के रूप में एकांकित किया और अनेक प्रगतिशील सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का संगठन किया। ये सारे राजनीतिक राष्ट्रवादी आंदोलनों के जनक, प्रणेतार, संगठनकर्ता और अग्रणी थे। घोर आत्मत्याग और अनेक कष्टों के बावजूद उन्होंने जनता के बीच शिक्षक और प्रचारार्थक कार्य के द्वारा स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद के विचारों का अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने राष्ट्रीयता और जनतंत्र की भावनाओं से आत प्रोत सपन प्रादेशिक साहित्य और सस्कृति की सृष्टि की। इनके बीच में महान वैज्ञानिक, कवि, इतिहासज्ञ, समाजशास्त्री, साहित्यिक दार्शनिक और अर्थशास्त्री उत्पन्न हुए। प्रगतिशील बुद्धिवादी वर्ग ने आधुनिक पाश्चात्य जनतान्त्रिक सस्कृति का स्वांगीकरण किया और नवजात भारतीय राष्ट्र की जटिल समस्याओं को समझा। वस्तुतः वे ही आधुनिक भारत के निर्माता थे।

1851 और 1884 के बीच पेशेवर वर्गों में देश में तीन संगठन बनाए गए मद्रास नेटिव एसोसिएशन, बांग एसोसिएशन और इंडिया एसोसिएशन (अध्याय 10 देखें)। इन्होंने नौकरियों के भारतीयकरण के लिए सरकार पर जोर डाला। इनका तर्क था कि किसी देश का राजतंत्र वही के दशवासियों द्वारा चलाया जाना चाहिए, विदेशियों द्वारा नहीं। इस तर्क में उनका अपना वर्ग स्वाथ भी निहित था।

1857 के बाद देश में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई तो शिक्षित भारतीयों की संख्या तेजी से बढ़ी। राष्ट्रीय चेतना सबसे पहले इन्हीं शिक्षित भारतीयों में आई। बुद्धिजीवी वर्ग के अग्रणी नेताओं ने वाणिज्यिक और आर्थिक औद्योगिक वृद्धि के समर्थन और बल पर 1885 में भारतीय जनता का पहला राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन कायम किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस ने अंग्रेजों को अपनी भाषा बनाया और इस तरह प्रबुद्ध शिक्षित वर्ग के लोग ही सबसे पहले इसके नेता हुए (देखें अध्याय 10)।

भारत का राष्ट्रीय आंदोलन मुख्यतः इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेतृत्व में बीसवीं सदी के पहले दशक में व्यापक मध्यमवर्गीय आधार पर और 1918 के बाद और अधिक व्यापक जन आधार पर विकसित हुआ। इसका वाद का इतिहास राजनीति वाले अध्याय में चर्चित है। अभी ध्यान देने की मुख्य बात यह है कि अपने

विकास के प्रत्येक चरण में प्रबुद्धवर्ग ने ही इस आंदोलन का नेतृत्व किया, इस वर्ग के चाहे जिस अंग ने जिस किसी विचार पद्धति, क्रिया प्रणाली और कार्यक्रम के साथ यह काम किया हो। उदारवादी चरण में राष्ट्रीय आंदोलन की जगुआई आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त गोपालकृष्ण गाखल, दादाभाई नौरोजी, एस० बनर्जी एम० जी० रानाडे, फिरोजशाह महता आदि उदारवादी नेताओं की। दूसरे लड़ाकू चरण में बाल गंगाधर तिलक, बी० सी० पाल, अरबिन्द घोष, लाला लाजपत राय जैसे अंग्रेजी के ही जानकार प्रबुद्ध वर्ग के लोग और महान आत्म त्यागी नेताओं ने इस आंदोलन की जगुआई की। आतंकवादी आंदोलन में अपेक्षा कृत कम लोगो ने सक्रिय भाग लिया लेकिन इसकी भी गुरुआत और जगुआई मध्यमवर्गीय युवक वर्ग ने ही की जिन्होंने जाइरिश आतंकवादी और रूसी शूयवादी (निहिलिस्ट) आंदोलनों का अध्ययन किया था। 1918 के बाद भी, जब राष्ट्रवादी आंदोलन कई ऐतिहासिक कारणों से (देखें अध्याय 10) जनसाधारण में फैल चुका था, इसका नेतृत्व गांधी, सी० आर० दास मोतीलाल नेहरू बिटठल भाई पटल सी० राजगोपालाचारी राजेन्द्रप्रसाद, जवाहरलाल नेहरू सुभाष बोस और समाजवादी और साम्यवादी बुद्धिवादियों जैसे शिक्षित वर्ग के ही लोगों ने किया।

हिंदुओं मुसलमानों और अन्य संप्रदायों में जो विभिन्न सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए उनका भी संगठन उन संप्रदायों के शिक्षित लोगों ने ही किया। उदाहरणार्थ शिक्षित वर्ग के ही सदस्य बी० आर० जवेदकर ने दलित जातियों के बीच सामाजिक सुधार और राजनीतिक शिक्षा के आंदोलन का नेतृत्व किया। वस्तुतः ब्रिटिश शासनकाल में भारत में जितने भी प्रगतिशील सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक आंदोलन हुए वे शिक्षित लोगों के ही काम थे जिन्होंने नई पाश्चात्य संस्कृति और शिक्षा का अध्ययन मनन किया था।

आधुनिक जगत में सब देशों में प्रबुद्ध वर्ग ने ही प्रगतिशील आंदोलनों का संगठन और नेतृत्व किया है। चीन भारत और ऐसे कुछ अन्य देशों में जहाँ साधारण जनता अधिकांशतः अशिक्षा और अज्ञान के गत में पड़ी है, वहाँ प्रबुद्ध वर्ग की भूमिका और अधिक विशिष्ट और महत्वपूर्ण है क्योंकि इन देशों की जनता जाति संगठन और जाति प्रबोध में यूनतम पहलकदमी भी नहीं ले सकती। शिक्षित भारतीयों ने ही दूसरे देशों में हुए किसान और मजदूर आंदोलनों की जानकारी और उनके अध्ययन के आधार पर भारतीय किसानों और मजदूरों का पथ प्रदर्शन किया और अपने संगठन और आंदोलन बनाने में उनकी मदद की। अगर भारतीय जनता शिक्षित नहीं होती तो वह स्वाध्याय द्वारा दूसरे देशों में मजदूर एवं अन्य आंदोलनों की जानकारी हासिल कर सकती थी और अपना पहलकदमी पर जैसे संगठन बना सकती थी। शिक्षित भारतीयों ने जनतंत्र और स्वतंत्रता के आधुनिक विचारों को भी जात्मसात किया था और उन्हें दूसरे देशों में सामाजिक सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उपलब्धियों का ज्ञान था। इस

लिए उ होने शिक्षित भारतीय जनता के बीच इस ज्ञान का भी प्रचार किया ।

भारत में जंग्रेजी शासन द्वारा चलाई गई शिक्षा पद्धति के फलस्वरूप इस शिक्षित मध्यम वर्ग का जन्म हुआ था । वकील, डाक्टर, टेकनीशियन, प्रोफेसर, पत्रकार, सरकारी नौकर, किरानी विद्यार्थी इत्यादि इस वर्ग के सदस्य थे । उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में और उसके बाद भी आधुनिक शिक्षण मस्थाओं की सख्या में जनवरत वृद्धि के कारण शिक्षित मध्यम वर्ग की तादाद लगातार बढ़ती गई । 1861 का काउंसिल ऐक्ट शिक्षित जाभिलात्य को एक तरह की रियायत थी । ' 1892 का काउंसिल ऐक्ट पेशेवर वर्गों की बढ़ती हुई शक्ति और उनको दी गई रियायत का एक अर्थ सूचक था ।<sup>3</sup>

भारत का आर्थिक विकास भारत में आधुनिक शिक्षा के विस्तार का समानुपाती नहीं था । किसी भी समाज में साधारण आर्थिक प्रगति औद्योगिक विकास से ही आती है और इस तरह उस देश की मपत्ति और समृद्धि बढ़ती है, नौकरिया की सख्या में वृद्धि होती है आय के अर्थ साधन उपलब्ध होते हैं, लेकिन भारत में मुख्यतः ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीति के कारण यह औद्योगिक विकास तेजी से नहीं हो रहा था । आर्थिक और शैक्षिक विकास में विपमता के कारण उन्नीसवीं सदी के अंत तक शिक्षित वर्गों में बेकारी बहुत बढ़ गई थी । शिक्षित बेरोजगारों के कारण बड़े हुए आर्थिक कष्ट से उत्पन्न राजनीतिक असंतोष लडाकू राष्ट्रवाद के उदय का एक प्रमुख कारण था बालगगाधर तिलक, लाला लाजपत राय विपिनचंद्र पाल, अरवि द घोष इस लडाकू राष्ट्रवाद के प्रमुख नेता थे । शिक्षित लोगों की बेरोजगारी के कारण जातकवाद का भी जन्म हुआ ।

बाद के दशक में जैसे जैसे देश में शिक्षित मध्यम वर्ग बढ़ा और अपनी वर्गीय मांगों के प्रति जागरूक हुआ वैसे वैसे वे लोग अपने विशिष्ट संगठन बनाने लगे और अपनी मांगों को रूप देने लगे । इस तरह बढ़ती हुई तादात्त में इन लोगों के अपने संगठन बनने लगे उनके आम संगठन के अलावा जैसे नौजवान और स्वयं-सेवक संघ इत्यादि । 1930 के बाद यह प्रक्रिया विशेष तौर पर तीव्र हुई । इस काल में अपने हितों की रक्षा और अपनी शिकायतों को दूर करने के मध्यम के लिए शिक्षक वकील, इंजीनियर इत्यादि विभिन्न दलों के मध्य और संगठन बने । ये संगठन किसान सभाओं और मजदूर संघों जैसे थे, जो मजदूरों और किसानों के वर्गीय हितों की रक्षा के लिए बने थे । 1934 के बाद छात्र संघों और संगठनों की तेजी के साथ वृद्धि हुई और उनके जखिल भारतीय संगठन भी बने ।

### आधुनिक भारतीय बुर्जुआजी के हित, संगठन और आंदोलन

अब हम भारतीय समाज में उदित एक और नए वर्ग पर विचार करेंगे । जंग्रेजी शासन काल में देश एवं विदेशी व्यापार के विस्तार और समयांतर से उद्योगों और बंधों की स्थापना के कारण भारत में आधुनिक वाणिज्य औद्योगिक और वित्तीय बुर्जुआजी का जन्म हुआ । अर्थ दशा की तरह यहां भी यह नया

आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से सबसे तगड़ा बग था।

भारतीय बुर्जुआजी की उत्पत्ति और उसका विकास व्यापार, वाणिज्य और उद्योग के विस्तार से संबंधित रहें हैं। जावुनिक उद्योगों वाले अध्याय में इनके विस्तार की कथा कही गई है। यहाँ हम इस बग के मुख्य हिता, विशिष्टताओं, समस्याओं, मगठना और संघर्षों की चर्चा करेंगे।

ज्ञातव्य है कि व्यापार, उद्योग और बैंकिंग में यूरोपियन भी लग हुए थे। अपने स्वार्थों की रक्षा के लिए उन्होंने आर्थिक उद्यम के आधार पर भारतीयों से मिलकर या फिर अलग से अपने मगठन बनाए। यूरोपियनों का पहला चेम्बर आफ कामर्स (वाणिज्य मंडल) कलकत्ता में 1834 में स्थापित हुआ, और बंबई और मद्रास में 1836 में। पहला भारतीय चेम्बर आफ कामर्स, बंगाल राष्ट्रीय चेम्बर आफ कामर्स 1887 में शुरू हुआ। इंडियन मर्चेंट्स चेम्बर 1907 में बंबई में स्थापित हुआ था। मारवाड़ी चेम्बर आफ कामर्स कलकत्ता में 1900 में शुरू हुआ और मद्रास में 1909 में साउथ इंडियन चेम्बर आफ कामर्स का स्थापना हुई। जिस व्यापार वाणिज्य, उद्योग आदि में भारतीय लग थे या जिससे उनका संबंध था उसकी रक्षा के लिए 1925 में इंडियन चेम्बर आफ कामर्स की स्थापना हुई।<sup>33</sup>

वाद में भारतीय वाणिज्यिक समुदायों के प्रादेशिक मगठन भी बने, जैसे 1927 में महाराष्ट्र चेम्बर आफ कामर्स बना। भारतीय और यूरोपिय वाणिज्यिक वर्गों के पारस्परिक द्विधाघात के कारण इन दलों को अपने स्वतंत्र मगठना की आवश्यकता पड़ी। लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि 'जहाँ दोनो व्यापार में लगे थे वहाँ उनके स्वाथ भिन्न थे, जहाँ वे मिल मालिक थे या लोगों को रोज गार और नौकरी दिए हुए थे, वहाँ उनके स्वाथ अभिन्न थे, जैसा बंबई के मिल ओनर्स एसोसिएशन से स्पष्ट है।'<sup>34</sup>

भारतीय व्यापारियों की मुख्य शिकायत यह थी कि व्यापार के क्षेत्र में भारतीयों की तुलना में यूरोपियनों को सरकार से अधिमानिक सुविधाएँ प्राप्त थीं और गर ब्रिटिश देशों के साथ भारतीयों के तिजारत पर बहुत सारे जंकुग लग थे। भारत में ब्रिटिश वाणिज्यिक हिता को जा विशेषाधिकार प्राप्त थे, भारतीय वाणिज्यिक समुदाय ने उनकी आलाचना की और उनके विरुद्ध मघष भी किए, जैसे उन्होंने तटीय पोत परिवहन में ब्रिटिश व्यवसायियों के प्राधिकारों पर हमला किया। मि० हाजी न लेजिस्लेटिव असेम्बली में रिजर्वेशन आफ द कोस्टल टर्फिक आफ इंडिया (भारत के तटवर्ती नौ परिवहन के अभिरक्षण) का प्रश्न उठाया। उनका तर्क था कि भारत के तटीय व्यापार में विदेशी एकाधिकार से भारतीय नौ परिवहन की प्रगति को बाधा पहुँच रही है।

राष्ट्रवादी वैज्ञानिक सर पी० सी० राय ने कहा 'अगर इस देश में जिस स्थिति का उपभाग करत रहें हैं और नए संविधान में जो कुछ वे चाहत हैं, वह अधिकारों की समानता नहीं बरन शासक जाति के रूप में विशेषाधिकार अपनी खुद की सरकार में मिलन वान प्राधिकारों की सुरक्षा और नियमान्जसमानताओं



की अवस्थिति। अगर य अधिकार समाप्त नहीं होते हैं तो भारतीयों को अपना आर्थिक भविष्य बनाने के अवसर नहीं मिलेंगे।<sup>35</sup>

फिर भी वाणिज्यिक समुदायों ने ब्रिटिश सरकार का वसा प्रखर विरोध नहीं किया, जैसा उद्योगपतियों ने, जिनका मध्य कालांतर में विकसित हुआ। इसकी वजह यह थी कि विदेशी और नवजागत भारतीय औद्योगिक स्वार्थों के बीच मड़ी के लिए जो अवश्यभावी मध्य हुआ, उसमें ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश उद्योगों की रक्षा की हर संभव कोशिश की।

‘बुजुआजी की राष्ट्रीयता का जन्म मड़ी में होता है।<sup>36</sup> अपने जन्मकाल से ही, औद्योगिक बुजुआजी ने सरकार के विरुद्ध, नवजात भारतीय उद्योगों को सुरक्षा प्रदान करने के सवाल पर, घनघोर मोर्चाबंदी की। 1880 के बाद आधुनिक उद्योग भारत में तभी से बढ़े और औद्योगिक बुजुआजी की ताकत बढ़ी। राष्ट्रवादी प्रवृद्ध वर्ग ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत की और 1885 में प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई।

1905 तक ऊर्ध्वो-मुख औद्योगिक वर्ग काफी तगड़ा और जागरूक हो चुका था। पेशेवर वर्ग नौकरियाँ और पेशा में अग्रजों के एकाधिपत्य को समाप्त करने के लिए पहले ही से मध्य कर रहे थे। 1905 के लगभग औद्योगिक वर्गों ने भी पेशेवर वर्गों को अपना समान प्रदान करना शुरू कर दिया।

पेशेवर वर्गों का यह उद्देश्य था कि उन अग्रजों का स्थान ग्रहण कर सकें जो मेडिसिन, कानून और पत्रकारिता के क्षेत्र में एक प्रकार से एकाधिकार जमाए हुए थे। उद्योगपतियों का वर्ग भी औद्योगिक क्षेत्र में अग्रजों के एकाधिकार को समाप्त करना चाहता था। सूती कपड़ा का उद्योग सबसे बड़ा भारतीय उद्योग था और यह ब्रिटिश व्यापारियों के हितों के लिए नुकसानदेह था। भारत में पूँजीवाद का विकास औपनिवेशिक प्रकार का था। देश के सामाजिक अस्तित्व और ब्रिटिश शासक वर्ग के अनन्य मुक्त व्यापार के कारण भारत के उदीयमान उद्योगपतियों के हितों को नुकसान हो रहा था। उह वाणिज्यिक विभेद और अबाध व्यापार के विरुद्ध मध्य करना पड़ा। उनका नारा था स्वदेशीवाद और संरक्षणवाद। इन उदीयमान औद्योगिक वर्गों ने स्वभावतः पेशेवर वर्गों के साथ एकता कायम की।<sup>37</sup>

ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीति के आलोचकों का कहना था कि ब्रिटिश उद्योगों के हितों में भारतीय उद्योगों के मुक्त विकास पर रुकावटें लगाई जा रही थीं।<sup>38</sup>

इसके कारण भारत ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चा माल उत्पन्न करने वाला कृपि प्रधान देश रह गया था। भारतीय आर्थिक विकास ब्रिटिश उद्योगों के हितों की दृष्टि से अनुकूलित और अधीनस्थ था, भारतीय अस्तित्व ब्रिटिश अस्तित्व का औपनिवेशिक सहायक होकर रह गया था। जान ब्यूकन ने कहा है कि भारत के औद्योगिक विकास पर निम्नलिखित प्रतिबंध लगेंगे (क) यह ब्रिटिश पूँजी के

नियंत्रण में रह, भारतीय पूँजी की जूनियर पाटनर की स्थिति हो, (ख) भारतीय उद्योग वरावरी के स्तर पर ब्रिटिश उद्योग से होड़ न ले सके, और न उस कच्चे माल का इस्तेमाल कर सकें जिसकी ब्रिटिश उद्योगों का जरूरत हो (ग) ब्रिटन में बने सामान के भारतीय बाजार पर किसी तरह का आघात न पहुँचे, और (घ) उत्पादन के साधनों का निर्माण कर सकने वाले उद्योगों का विकास न हो।<sup>39</sup>

सरक्षण, अनुकूल विनियम अनुपात बढ़ते हुए उद्योगों के लिए अथ साहाय्य, आदि अपने खुद के नारों के साथ औद्योगिक बुजुआजी न भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पदापण किया। बीसवीं सदी के पहले दशक में औद्योगिक पूँजीपतियों ने राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लेना शुरू किया। इसी काल में यह वग इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर जादृष्ट हान लगा और इसने विदेशी माल के बहिष्कार और स्वदेशी के कार्यक्रम का उत्साहपूर्ण समर्थन किया, यथाकि इनसे उनका वग स्वायत्त पूरा होता था। स्वदेशी आंदोलन सफल रहा, कुछ दिनों तक, और इससे भारतीय उद्योगों का बल मिला खासकर सूती कपड़ों के उद्योग को।

राष्ट्रीय आंदोलन अब तक प्रबुद्ध वग वाणिज्यिक बुजुआजी के कुछ अर्थ और शिक्षित मध्यम वग तक ही मर्यादित सीमित था लेकिन 1905 के बाद इस अधिक व्यापक आधार मिला क्योंकि मध्यम वग और राजनीतिक चेतनाशील उद्योगपतियों ने बड़ी तादाद में इसमें हिस्सा लेना शुरू किया।

प्रथम विश्वयुद्ध (1914-18) के काल में देश में औद्योगिक विकास बहुत तेजी से हुआ। इसकी खास वजह यह थी कि ब्रिटिश और दूसरे विदेशी उद्योग मुख्यतः युद्ध की ओर लगे और भारतीय बाजार के लिए सामान न दे सके। इस तरह भारतीय उद्योगों का तेजी से विस्तार हो सका। फिर, सामरिक कारणों से ब्रिटिश सरकार ने स्वयं भी इस्पात जैसे कुछ अन्य उद्योगों को प्रथम दिया। इससे चलते उद्योगपतियों की सामाजिक और आर्थिक शक्ति में और अधिक वृद्धि हुई।

लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन और उसके प्रमुख संगठन इंडियन नेशनल कांग्रेस में इस वग के बल और प्रभाव में युद्ध काल के बाद ही विशेष प्रगति हो सकी। खासकर 1919-20 के बाद कांग्रेस संगठन पर इसका विजिष्ट प्रभुत्व स्थापित हुआ। अब उद्योगपतियों के प्रभाव ने कांग्रेस के कार्यक्रम का निरूपित करना शुरू किया और इसके सघर्षों के रूप और ढंग प्रकार और प्रणाली को भी निर्धारित किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस पर इस वग का नियंत्रण लगातार बढ़ता ही रहा।

1919-20 में इंडियन नेशनल कांग्रेस गांधीवादी विचारधारा के प्रभाव में और गांधी के राजनीतिक नवतृत्व में जाई। गांधी ने आधुनिक मशीनतंत्र और उद्योग से अपने जनम्य विरोध की घोषणा कर दी थी। लेकिन भारतीय उद्योगपतियों की आशाका तब समाप्त हो गई जब 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी ने स्वदेशी विषयक प्रस्ताव का समर्थन किया। प्रस्ताव में कहा गया था कि सूती माल में स्वदेशी का ही व्यापक रूप में उपयोग हो (दश राजनीतिक विषयक अध्याय)।

इतिहास एवं अत्यंत के नियमों से परिचित इन उद्योगपतियों ने खद्दर के समांतर प्रचार को अपने औद्योगिक कार्यक्रम के लिए खतरनाक नहीं माना। यह बात ज़ीव लग सकती है, लेकिन मशीन पर आधारित आधुनिक उद्योगों को चलाने बढ़ाने और उससे फायदा कमाने वाले कुछ लोगों ने भी हाथ के बुने खद्दर का इस्तमाल शुरू किया और खद्दर आदानों को आर्थिक सहायता भी दी। उन्होंने यह समझा कि कांग्रेस और कांग्रेस द्वारा चलाए गए आंदोलनों में ब्रिटिश सरकार को आर्थिक और राजनीतिक रियासत के लिए बाध्य किया जा सकता है और इससे उनके वर्ग को फायदा है।

फिर वर्ग मम व्यवस्था पर पूंजीपतियों की 'यासिता और पूंजीवादों पिता है, मजदूर उनकी सतान' आदि सिद्धांतों पर आधारित गांधीवादी समाज दशन उद्योगपतियों को भी पसंद आया। वर्ग संघर्ष के आधार पर विकसित हो रहे मजदूर आंदोलनों से उन्हें इस दशन में बचाव जरूर आया।

वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का गांधी ने जो जनवरी विरोध किया, उसके कारण वे उद्योगपतियों के बीच समाप्त हुए। उद्योगपतियों ने आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को पसंद नहीं किया क्योंकि यह ब्रिटिश ट्रेड यूनियन कांग्रेस की तरह ही वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर आधारित था। लेकिन उन लोगों ने मजदूर महाजन का समर्थन किया जो अहमदाबाद के सूती मिलों के मजदूरों का गांधी द्वारा शुरू किया गया संगठन था और वर्ग सामंजस्य के सिद्धांत पर आधारित था।

विडला, बजाज, जम्बालाल, साराभाई, कस्तूरभाई लालभाई और अन्य घनाढ्य उद्योगपतियों ने गांधी के एकछत्र नतत्व में कांग्रेस का समर्थन किया और इसके कार्यक्रमों के लिए पैसा दिया। उन्होंने प्राक पूंजीवादी हस्तशिल्प के पुनरुज्जीवन जैसी योजनाओं को भी आर्थिक सहायता दी। मूलतः इन उद्योगपतियों द्वारा आल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन और एस अर्थ संगठनों को दिए गए अर्थ माहाय्य के कारण ही तेजी से खतम हो रहे उत्पादन के पुराने तरीकों को बनावटी तौर पर अवलंबन देकर जिंदा रखा जा रहा था।

गांधीवादी दशन में गरीबी को गौरवित किया गया और विराधी के प्रति प्रेम भावना की शिक्षा दी गई, कम मजदूरी और काम की बुरी स्थिति के कारण बढ़ते हुए मजदूर अमत्तों का शायद यह दशन सबसे अच्छा बात था, और इसी लिए इसके प्रचार के लिए भी उद्योगपतियों ने पैसा दिया। अगर गरीबी अच्छी चीज है तो ऊंचे जीवन स्तर की मांग स्पष्टतः गलत है।

यह बात अंतर्विरोधी लग सकती है, लेकिन इन घनाढ्य उद्योगपतियों ने स्वयं जीवन का गांधीवादी सिद्धांतों का अनुकरण करने की कभी कोई चेष्टा नहीं की। गांधीवादी का होने समर्थन प्रदान किया लेकिन वे स्वयं संपत्ति और मुनाफे के प्रेम में पड़े रहे, और उससे चिपटे रहे।

उद्योगपतियों ने फिर भी गांधी के नेतृत्व में गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा संगठित जा आंदोलनों का महत्व

सरक्षण, अनुकूल अनुपात (जो गांधी के ग्यारह सूत्री मागा में एक था, देखें अध्याय 10) जसी अपनी मागा की पूर्ति के लिए उद्योगपतियों ने इन आंदोलनों का इस्तेमाल किया।

कृषि संवर्धन के रूप और प्रकार के कारण भी भारत का तेज आर्थिक विकास संभव नहीं हो पा रहा था। कृषि के पुनर्निर्माण के लिए और कृषक आंदोलनों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए, जिससे लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि हो, मूलभूत सुधार की आवश्यकता थी। भारतीय उद्योग तेजी से तरक्की करे इसके लिए आवश्यक था कि उनके उत्पादों को खरीदने वाली कृषक आंदोलन समृद्ध हो।

लेकिन भारतीय उद्योगपतियों ने मूलभूत कृषि संवर्धन सुधारों के वायज में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसकी वजह थी कि भारत में जमींदार और पूँजीपति वर्ग एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जमींदारों ने उद्योगों और बकायों में पैसा लगाया और बकर और उद्योगपतियों को भी जमीन जायदाद दी।

1937 में जो कांग्रेस सरकारें बनीं, उनकी वामपंथी राष्ट्रवादियों ने पूँजीवादी झुकाव रद्द करने के लिए आलोचना की (देखें अध्याय 10)। इन आलोचकों का विचार था कि उद्योगपतियों ने कांग्रेस का इसीलिए समर्थन किया कि कांग्रेस में उनके हितों की रक्षा की।

बंबई के सूती मिल मजदूरों की हड़ताल के वक़्त सरकार द्वारा पुलिस का इस्तेमाल ट्रेड्स डिम्प्युटस एक्ट, अहमदाबाद और शालापुर में मजदूरों की सभाओं पर प्रतिबंध विभिन्न प्रांतों में कांग्रेसी सरकारों द्वारा कुछ मजदूर नेताओं को जेल में डालना या दश निकाला देना, आलोचकों ने इन बातों की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित कर यह सिद्ध किया कि कांग्रेसी सरकारें पूँजीवादी हितों का समर्थन करती थी।<sup>40</sup>

दूसरे वर्गों की तरह औद्योगिक बुजुर्गों ने भी अपने हितों की रक्षा के लिए और अपनी मागा को आगे बढ़ाने के लिए कई संगठन बनाए। 1875 में वाव मिल ओनर्स एसोसिएशन 1881 में इंडिया टी एसोसिएशन 1884 में इंडियन जूट मिल एसोसिएशन 1891 में अहमदाबाद मिल ओनर्स एसोसिएशन बना 1927 में इंडियन चेंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री का महासंघ 1920 में सदन इंडिया एम्प्लायर्स फेडरेशन 1933 में आल इंडिया जागनाइजेशन आफ इंडस्ट्रियल एम्प्लायर्स और 1933 में एम्प्लायर्स फेडरेशन आफ इंडिया बना।

भारतीय अर्थतंत्र विकास के एकाधिकार पूँजी वाले चरण में पहुंच चुका था। उद्योगों वाले अध्याय में इस बात की चर्चा की गई है कि कस उद्योगपतियों की दिनानुदिन घटती हुई संख्या में यह प्रवृत्ति बढ़ती गई कि उद्योगों की किसी विशेष शाखा पर या किसी उद्योग की समष्टि पर या उद्योगों के समुदाय पर ही एकाधिकार स्थापित कर लिया जाए। इसके कारण देश की जनता के आर्थिक हित नहीं बरतने सामाजिक, बौद्धिक राजनीतिक जीवन पर भी कुछ बड़े उद्योगपतियों और अर्थपतियों की जबड़ में जकूत होती गई। जमींदारों के उदाहरण से इस स्थान का साम

तौर पर समझा जा सकता है। ब्रिडला ने बहुत सारे अखबार खरीद लिए जिससे उसे इन अखबारों को पढ़ने वाली जनता के विचार और दृष्टिकोण का अपने इच्छानुसार मोड़ सकने की ताकत मिली। यह स्थिति पहले की स्थिति से भिन्न थी, अब सुरे द्रनाथ वनर्जी आगरकर तिलक और जया य लोग अखबार चला सकते थे और अपने विचारों का स्वतंत्र प्रचार कर सकते थे। बड़े बड़े व्यवसायियों ने अधिकाधिक अखबारों पर अपना शासन और प्रबंध कायम किया और इस तरह जनसमुदाय के विचारों पर नियंत्रण प्राप्त किया। दूसरे उद्योगों में भी यही प्रवृत्ति देखी जा सकती है। जायिक एकाधिकार के कारण लोगों के बौद्धिक, राजनीतिक और सामाजिक जीवन पर भी एकाधिकार का नियंत्रण बढ़ता जा रहा था।

### भारत में आधुनिक सवहारा वर्ग का उदय

अब हम भारत के आधुनिक मजदूर वर्ग की चर्चा करेंगे जो कई अर्थवर्गों की तरह नया वर्ग था। भारत में अंग्रेजी शासन काल में आधुनिक उद्योग धंधों, यातायात के आधुनिक साधनों और वागानों की स्थापना हुई, जिसके कारण आधुनिक मजदूर वर्ग का जन्म हुआ। जैसे जैसे वागाना आधुनिक कल कारखानों, खनिज उद्योगों, आवागमन के साधनों आदि में वृद्धि हुई वैसे-वैसे इस वर्ग की संख्या में भी वृद्धि हुई। भारतीय सवहारा वर्ग मुख्यतः उन किसानों और हस्तशिल्पकारों से निर्मित हुआ जो दरिद्र हो गए थे और अब मजदूरी कमाने लग गए थे।<sup>41</sup> भारतीय मजदूरों के जीवन यापन और कार्य के हालात इतने निम्न स्तर के थे कि सरकारी और गैर सरकारी दोनों प्रकार के लखकानों की चर्चा की।

सब तरह की जाच पड़ताल में यही पता चलता है कि भारत के अधिकांश मजदूर एक शिल्प प्रतिदिन से अधिक नहीं कमाते हैं।<sup>42</sup>

हम लोग जहाँ कहीं भी ठहरें, वहाँ हमने मजदूरों के घर देखे, और अगर हम इन्हें नहीं देखते तो हम यह विश्वास नहीं कर पाते कि इतनी बुरी जगह भी कहीं है।

हर जगह लोगों की भीड़ और अस्वास्थ्यकर हालातों से पता चलता है कि सरकारी पदाधिकारियों ने अपने स्पष्ट कर्तव्यों की निम्न उपेक्षा की है।<sup>43</sup>

1938 में जिनवा में हुए इंटरनेशनल लेबर कांफ्रेंस में भारतीय मजदूरों के प्रतिनिधि एस० पी० परुलेकर ने अपने भाषण में कहा कि भारत में अधिकांश मजदूरों को जो मजदूरी मिलती है वह इसके लिए भी काफी नहीं कि उन्हें जीवन की पूनर्तम आवश्यकताएँ उपलब्ध करा सकें। बीमारी बरोजगार बुढ़ापा और मृत्यु के विरुद्ध भारत के मजदूरों को कोई सुरक्षा नहीं प्राप्त है।<sup>44</sup>

जितनी कम मजदूरी उन्हें मिलती थी उसके आधार पर वे अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करने में असमर्थ थे। इसलिए उनमें से अधिकांश ऋणग्रस्त थे। ब्रिटली कमिशन ने अपने निष्कर्ष में कहा, अधिकांश औद्योगिक केंद्रों

में दो तिहाई परिवार और व्यक्ति कम हैं।<sup>45</sup> खान मजदूरों के जीवन और श्रम की हालतें खास तौर पर बुरी थी।<sup>46</sup>

बागानों में अधिकांश यूरोपियन लोगों की मिलकियत थी और वहाँ के मजदूरों का शायद सबसे कम मजदूरी मिलती थी। इसके बारे में शिवराय ने लिखा है, 'जासाम घाटी के चाय बागानों में वैसे मजदूरों की औसत माहवारी आमदनी कुल 7 रुपया 3 आन थी, औरतो और वच्चा की क्रमशः 5 रुपए 14 आने और 4 रुपए 4 आने थी।'<sup>47</sup>

सरकार ने मजदूरों की सुरक्षा के लिए कुछ कानून बनाए जसे 1931 का इंडियन पाटन ऐक्ट, 1934 का वकमस कपनसेशन ऐक्ट, 1934 का फक्टरीज ऐक्ट, 1935 का माइम ऐक्ट 1936 का पेमेंट आफ वेजेज ऐक्ट, इत्यादि।

लेकिन सरकार द्वारा पारित श्रम और समाज संबंधी विधेयकों को बहुत सारे लेखकों ने अप्रयाप्त प्रतीत किया है।

कारखानों, खानों, बागानों, जहाजी मालघाट रेलवे, बंदरगाह इत्यादि में काम करने वाले सारे मजदूरों के बारे में पारित विधेयकों का लखा जोखा लिया जाता कुल मिलाकर महज सत्तर या अस्सी लाख मजदूरों का ही इससे संरक्षण मिल सकता है। शेष मजदूर जो बहुत बड़ी संख्या में हैं, वे श्रम उद्योग या जिन्हें अनियंत्रित उद्योग कहा जा सकता है उनमें लगते हैं।<sup>48</sup>

जीवन और श्रम की इन बुरी शर्तों के कारण भारत में 1918 के बाद मजदूर वर्ग के आंदोलन काफी तेजी से बढ़े।

भारतीय मजदूर वर्ग में राष्ट्रीय और वर्गीय चेतना प्रबुद्ध वर्ग शिक्षित मध्यम वर्ग और बुजुर्गों के बाद आई। इसका कारण था कि मजदूर वर्ग सांस्कृतिक तौर पर पिछड़ा हुआ वर्ग था, लगभग निरक्षर। मजदूरों की पहली कुछ पीढ़ियाँ, दरिद्र किसानों और बर्बाद ग्रामीण कारीगर, शहरों में आने और मजदूर हो जाने के बाद भी गाँवों के पिछड़ेपन से जागरूक रही। बाद में भी अधिकांश मजदूरों के संबंध गाँवों में बने रहे।

### आधुनिक संवहारा, इसकी चरित्रगत विशिष्टताएँ

अपने जीवन और श्रम की हालतों के ही कारण मजदूर वर्ग की अपनी चारित्रिक विशेषताएँ और शक्तियाँ विकसित होती हैं जो उन्हें किसानों और नागरिक मध्यम वर्ग से अलग करती हैं। उन्हीं के कारण उनके लिए अपने वर्ग स्वार्थों के लिए संगठित और एक्जुटिव हाना और अपना सामूहिक संघ चलाना आसान होता है। सबसे पहले संवहारा संपत्तिहीन होने के कारण किसानों से अलग लड़ाने होता है। किसानों के पास थोड़ी ही सही जमीन तो होती है जिससे उसका लगाव हो जाता है और वह विद्रोह से हिचकता है। दूसरे कारखानों और शहरों में अपने-अपने औद्योगिक केंद्रों में मजदूर बहुत बड़ी तादाद में एक साथ रहते हैं। इससे

कारण किसानों की अपेक्षा मजदूरों का संगठित होना आसान होता है। किसान बहुत बड़े क्षेत्र में फल होते हैं और एक सघ की छत्रछाया में नहीं लाए जा सकते। फिर, मजदूर आधुनिक शक्ति चालित यंत्रों में काम लेते हैं और अपने श्रम की सिद्धि के लिए वे प्रकृति की स्वेच्छाचारी शक्तियों पर निर्भर नहीं हैं। इसलिए जहाँ किसान के मन में जात्ममशय और पराजय घर किए हैं, वहाँ मजदूर इसके विपरीत जात्म विश्वासी तकशील और साफ सोचने वाला होता है। श्रम की जिस प्रक्रिया में मजदूर लगे हैं वहाँ जटिल और व्यापक श्रम विभाजन लागू है। रोज रोज आपस में एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत के चलते धीरे धीरे मजदूरों में सामूहिक भाव और सहयोग की योग्यता आ जाती है। यही कारण है कि मजदूर संगठन तेजी से उत्पन्न होते हैं और किसान संगठन और किसान आंदोलनों की तुलना में मजदूरों की हड़ताले और सामूहिक मधम अधिक जल्दी जल्दी होते हैं।

यह भी खयाल रखना चाहिए कि आधुनिक समसामयिक समाज में मजदूर की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह मिला और कारखानों को एक रेलवे और बसा को चलाता है गैस और बिजली जैसे शक्ति स्रोतों का सृजन करता है, कोयला खोद लाता है और डाक तार से सूचना भेजता है। आधुनिक समाज के मंचानन के लिए ये कार्य सामाजिक और आर्थिक दृष्टियों से अत्यंत महत्व के हैं। इसके कारण अपनी सांख्यिक शक्ति की तुलना में आधुनिक मजदूर वर्ग का विशिष्ट सामाजिक बल बहुत अधिक है।

दूसरे दशकों के मजदूर वर्ग की तरह भारतीय वर्ग भी उत्पादन के आधुनिक साधनों से वंचित है, यद्यपि इन साधनों के संचालन का उत्तरदायित्व उसी पर है, और वह धीरे धीरे समाजवादी व्यवस्था की धारणा एक कानून की ओर चुकन लगा। यह आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के सविज्ञान में परिलक्षित होता है जिसने भारत में समाजवादी राज्य की स्थापना अपना उद्देश्य माना। ब्रिटन फ्रांस और दूसरे दशकों के इतिहास से पता चलता है कि आधुनिक समाज में अपनी विशिष्ट स्थिति के कारण, मजदूर वर्ग इस अंतिम उद्देश्य की ओर जाकृष्ट होकर उसके लिए सघम करता है। समसामयिक भारतीय समाज के अन्य वर्ग महज राष्ट्रीय स्वातंत्र्य की कामना करते हैं लेकिन भारतीय श्रमिक शुरु से ही स्वतंत्र समाजवादी भारत का सपना साकार करना चाहते थे।

मजदूरों के जीवन और श्रम की स्थिति के कारण उनके जात्म संगठन की प्रक्रिया को बन मिला। लेकिन उनका सांस्कृतिक पिछड़ापन उनके जाति और समुदायगत विभेद, धार्मिक अधविश्वास जीवन के प्रति भाग्यवादी दृष्टिकोण जिनके कारण निभय हाकर काम करने की इच्छा शक्ति कमजोर होती है, इन कारणों से आत्म संगठन की प्रक्रिया में रुकावट भी आई। फिर भी सब मित्राकर भारतीय मजदूर वर्ग के ट्रेड यूनियन और उनके राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन बढ़ते रहें।

## मजदूर आंदोलनों का विकास

संगठित आंदोलन के रूप में भारतीय मजदूर आंदोलन 1914-18 के विश्वयुद्ध के बाद ही शुरू हुआ। लेकिन उसके पहले भी यदा कदा भारतीय मजदूरों के संघ होते रहे थे। ये संघ स्वतः स्फूर्त थे, और उनका कोई निश्चित, जागरूक और सचेत ढंग उद्देश्य नहीं था।

अमलगमेटेड सासाइटी आफ रेलवे सर्वेंट्स की स्थापना 1893 में हुई थी। लेकिन रेलवे के उच्च अफसर, प्रायः एंग्लो इंडियन ही इसके सदस्य थे। बीसवीं सदी के पहले दशक में कलकत्ता में प्रिंटर्स यूनियन और वर्रई में पोस्टल यूनियन जैसे कुछ मजदूर संघों की स्थापना हुई। लेकिन इनकी सदस्य संख्या कम थी और इनका समुचित सहायक या कार्यक्रम संवर्धन कोई आधार नहीं था। 1918 के पहले कुछ औद्योगिक हड़तालों भी हुई थी। ये प्रायः स्वतः स्फूर्त, और असंगठित थीं, और इनकी कोई विशिष्ट मजदूर संघीय चेतना भी नहीं थी।<sup>49</sup>

राजनीतिक तौर पर भी 1918 तक भारतीय मजदूरों का लगभग सुप्त और निष्क्रिय रहा। केवल एक ही उपवाद था। 1908 में जनप्रिय राष्ट्रवादी नेता बालगंगाधर तिलक की गिरफ्तारी के विरोध में वर्रई के मूती मिलों के मजदूरों ने हड़ताल की। भारतीय मजदूरों की यह एकमात्र राजनीतिक कार्यवाही थी। लेकिन ने उनकी बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना के प्रतीक के रूप में इसका अभिनय किया था (देखें अध्याय 10)।

लेकिन 1918 के बाद भारतीय मजदूरों का नया ढंग नए ढंग के आधार पर अपने को संगठित करना शुरू किया और तेजी से टेड यूनियन और राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। ह्यूटली कमिशन की रिपोर्ट में इस परिवर्तन की चर्चा है

1918-19 की संघों के पहले भारतीय उद्योग में शायद ही कभी हड़ताल हुई। संगठन और नेतृत्व के अभाव में और जीवन के प्रति निष्क्रिय दृष्टिकोण के कारण औद्योगिक मजदूरों में अधिकांश का विचार था कि वापस गांव चल जाना औद्योगिक जीवन की कठिनाइयों का एकमात्र विकल्प है। युद्ध के बाद उस स्थिति में शीघ्र परिवर्तन हुए। 1918-19 के जाड़े में कुछ महत्वपूर्ण हड़तालों हुईं, दूसरे साल के जाड़े में हड़तालों की संख्या और बढ़ी और 1920-21 के जाड़े में संगठित उद्योग में औद्योगिक हड़तालों का जन्म हो गया। अपने कारणों से जो नए नए परिस्थितियों में हड़तालों की शक्ति को समझा, और इस बात का मजदूर संघों के संगठनकर्त्तों को आविर्भाव, जनसाधारण का युद्ध से मिली शिक्षा उद्योगों के विस्तार से श्रमिकों की संख्या में कमी जो इंग्लैंड के मकामक हाने की वजह से और बढ़ी, यदि कारणों से मन्द मिली।<sup>50</sup>

1918 के बाद भारतीय मजदूरों का संगठित आंदोलन की गुरुत्व का निम्नलिखित कारण भी थे, युद्ध के बाद का जागतिक मकामक जिम्मेदारों का कारण मजदूरों के



कष्ट बढ़े, भारत की समस्त जनता पर जिसमें मजदूर वर्ग भी था जमनी, आस्ट्रिया टर्की और अन्य देशों की जनतांत्रिक क्रान्तियों और रूस की समाजवादी क्रान्ति का प्रभाव, और देश के अंदर बढ़ता हुआ विक्षोभ ।

1918 और 1920 के बीच देश भर में, बंबई, कानपुर, बलकंठा, शालापुर जमशेदपुर, मद्रास और जहमदाबाद जैसे विभिन्न औद्योगिक केंद्रों में लगातार कई हड़तालें हुईं । पहली बार इतनी अधिक हड़तालें इतने व्यापक रूप में हुई थीं ।<sup>51</sup> इन आर्थिक हड़तालों के अतिरिक्त बंबई और कुछ अन्य औद्योगिक शहरों में रीलेट एक्ट के विरुद्ध मजदूरों ने राजनीतिक हड़तालों भी कीं और इस तरह अपनी बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना का परिचय दिया । इससे पता चलता है कि राष्ट्रीय आंदोलन में मजदूर वर्ग का भी प्रवेश हो चुका था ।

इसी काल में पहली बार बंबई, मद्रास और कुछ अन्य केंद्रों में विभिन्न उद्योगों में मजदूर संघों की स्थापना की चेष्टा हुई । कुछ ही दिनों में देश में बहुत सारे मजदूर संघ बन गए । 1920 में एन० एम० जोशी, लाला लाजपत राय और जोसेफ वेपटिस्टा के प्रयास के फलस्वरूप आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई । उनका उद्देश्य था देश के सारे प्रांतों में मजदूरों के सारे संगठनों के कार्यों को समन्वित करना और आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक मसलों पर भारतीय मजदूरों के हितों को प्रथम देना ।<sup>52</sup>

भारतीय मजदूर वर्ग के इतिहास में आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना युगांतरकारी घटना है । पहली बार बढ़ते हुए ट्रेड यूनियन आंदोलन को अखिल भारतीय आधार मिला । लगभग एक दशक तक ए० आई० टी० यु० सी० का नेतृत्व एन० एम० जोशी जैसे उदारवादी राजनीतिज्ञों के हाथ में रहा । आगे चलकर सी० आर० दास जैसे राष्ट्रवादियों के भी इससे संबंध रहे । मजदूरों के बीच होने वाला प्रचार नेतृत्व के राष्ट्रवादी और सुधारवादी विचारधारा के अनुकूल था । लेकिन ए० आई० टी० यु० सी० की सदस्य संख्या बहुत कम थी ।

1927 के बाद ट्रेड यूनियन आंदोलन में वामपंथी नेतृत्व विकसित हुआ और इसमें वामपंथी राष्ट्रवादी, समाजवादी और साम्यवादी लोग आए । इस नए नेतृत्व ने तेजी से पुराने नेतृत्व को विस्थापित करना शुरू किया । 1922 से ही भारतीयों के बीच समाजवादी और साम्यवादी विचार फल रहे थे और इस तरह देश में समाजवादी और साम्यवादी दलों की स्थापना हो रही थी । इन दलों ने राष्ट्रीय आंदोलन की सफलता के लिए मजदूर वर्ग का महत्व समझा और बकम एंड प्रेजेंट्स पार्टियों का संगठन किया । इन पार्टियों के सदस्य ट्रेड यूनियन कांग्रेस में अधिकाधिक प्रभावशाली होते गए । उनका उद्देश्य था ट्रेड यूनियन आंदोलन वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का और राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम में मजदूरों का प्रवेश । मीठे संघर्ष के माध्यम से राष्ट्रीय स्वाधीनता की प्राप्ति उनका कार्यक्रम था ।

जोशी गुट वाला पहले का नेतृत्व कुछ दिनों में कमजोर होकर रह गया, और वामपंथी लोग ए० आई० टी० यु० सी० का नेतृत्व ले सकेन में सफल हुए । 1929

में रायल कमीशन आन लेबर के वहीष्कार और जिनवा के इटरनशनल वाफरेंस में प्रतिनिधित्व के सवाल पर दोनों पक्षों में घोर विभेद उठ खड़ा हुआ। इसका चलते आपस में फूट पड़ गई और कई एक ट्रेड यूनियन अलग हो गए। अब जोशी गुट के नेतृत्व में इंडियन ट्रेडस यूनियन फेडरेशन की स्थापना हुई।

ए० आई० टी० यु० सी० में 1931 में फिर फूट पड़ गई, लेकिन दोनों दल फिर 1935 में एक हो गए। 1938 में ए० आई० टी० यु० सी० और इंडियन ट्रेडस यूनियन फेडरेशन भी एक हो गए और पहले से अधिक मजदूरों जाल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का उदय हुआ।

ए० आई० टी० यु० सी० का कार्यक्रम काफी आगे बढ़ा हुआ था। इसके उद्देश्य थे, भारत में समाजवादी राज्य की स्थापना, यथामुभव उत्पादन के साधन एवं विनिमय और वितरण का समाजीकरण और राष्ट्रीयकरण, मजदूर वर्ग की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार, वाक स्वातंत्र्य और प्रस, संगठन, सभा और हड़ताल आदि की स्वतंत्रता जैसे नागरिक अधिकार मजदूरों का उपलब्ध कराना, मजदूर वर्ग के हितों की दृष्टि से राष्ट्रीय सघष में हिस्सा बंटाना और जाति धर्म, समाज, प्रजाति और आस्था पर आधारित विशेषाधिकारों की समाप्ति।<sup>3</sup> यह आगे बढ़ा हुआ जनतांत्रिक और समाजवादी कार्यक्रम था।

1942 में ए० आई० टी० यु० सी० जिसमें विभिन्न उद्योगों के ट्रेड यूनियन शामिल थे की समस्त सदस्य संख्या 3,37,695 थी। यह मजदूरों की समस्त संख्या का अल्पांश ही था। भारत के ट्रेड यूनियनों की सदस्य संख्या कम होने की वजह थी, मजदूरों की गरीबी और उनका सांस्कृतिक पिछड़ापन नियोजकों द्वारा दंडन उत्पीड़न का आतंक आदि। लेकिन हड़तालों के वक्त ट्रेड यूनियनों को मजदूरों का जयंती समारोह प्राप्त हुआ और उस वक्त उनकी सदस्य संख्या भी बढ़ी।

1927 के बाद भारतीय मजदूर वर्ग ने आर्थिक और राजनीतिक सघष कक्ष में अपने क्रियाकलाप का जयंती विस्तार किया। 1928-30 में कुछ महान आर्थिक सघष हुए, जिनमें बंबई के सूती मिन के मजदूरों की हड़ताल भी थी। 1927 के बाद भारतीय मजदूर वर्ग ने स्वतंत्र राजनीतिक हैमियत प्राप्त करनी शुरू की। उसका अपना ऋंडा और अपना स्वतंत्र वर्गीय कार्यक्रम था। मजदूर वर्ग का अच्छा खासा जश संयुक्त राष्ट्रीय आंदोलन में अपने खुद के नेतृत्व के पीछे चला। साइमन कमीशन के विरुद्ध इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा संगठित विरोध प्रदर्शनों में मजदूरों ने अधिकतर अपने बड़े के नीचे, अपने नारा के साथ, अपने नेतृत्व में भाग लिया। सरकार ने इसको बहुत खतरनाक माना और इस मामूलीवादियों की जालसाजी का परिणाम बताया। इसलिए इनमें ट्रेडस डिस्प्युट ऐक्ट बनाया और 1929 में पब्लिक सप्टी बिल का जाडिनेंस जारी किया। इनमें स पहल कानून की मदद से सरकार ने हड़ताल करन की स्वतंत्रता को सीमित किया और दूसरे की मदद से अवाचित विदेशियों का देश निवाला दन का अधिकार प्राप्त किया। बहुत नार वामपंथी मजदूर नेताओं की गिरफ्तारी भी हुई और भरठ कासपिरनी केस किया गया। 1930-33

## भारत में नए सामाजिक वर्गों का उदय

के नागरिक जवजा आदालत में भी मजदूर वर्ग के कुछ लोगों ने भाग लिया। 1937 के चुनावों में कांग्रेसी उम्मीदवारों की महान सफलता का एक यह भी कारण था कि मजदूरों ने उन्हें जोरदार समर्थन दिया, क्योंकि कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र उनके मन लायक था। लेकिन कांग्रेसी सरकारों से शीघ्र ही उनका मोह-भंग भी हुआ। मजदूरों की यह शिकायत थी कि उनकी हालत सुधारने के लिए इन सरकारों ने कुछ नहीं किया वरन् वाटर टेड्स डिस्प्यूट ऐक्ट जैसे अजनतांत्रिक और पूँजीवादी व्यवस्था के समर्थक विधेयक बनाए। बंबई में हड़तालियों पर गोली चलाया, मजदूरों की सभाओं पर प्रतिबंध लगाए और मजदूर नेताओं को गिरफ्तार किया।

1938 के बाद देश में टेड यूनियन संगठना की संख्या तेजी से बढ़ी। ए० आई० टी० यु० सी० से संबद्ध ट्रेड यूनियनों की संख्या में वृद्धि से इस वृद्धि का परिचय मिलता है।<sup>54</sup> यह नया सामाजिक वर्ग धीरे-धीरे प्रभावशाली भूमिका अदा करने लगा था।

## नए सामाजिक वर्ग, उनका राष्ट्रीय चरित्र

मुख्य नए सामाजिक वर्गों का हिता, लक्षणों समस्याओं, संगठना और जादोलना की चर्चा करने के बाद अब हम इन वर्गों के कुछ ऐसे लक्षणों की चर्चा करेंगे जो इन्हें प्राकृतिक भारत के पुराने वर्गों से पृथक् करते हैं। नए वर्गों का एक उल्लेखनीय लक्षण यह है कि वे राष्ट्रीय हैं। वे समग्र राष्ट्रीय अर्थतंत्र के अंग हैं और एकल राज्यतंत्र के अधीन हैं। इस तरह प्रत्येक नए सामाजिक वर्ग का आर्थिक राजनीतिक और सामाजिक हिता का अखिल भारतीय एकीकरण हुआ। इस वर्ग के व्यक्ति और समुदाय जैसे-जैसे हिता साम्य की बात समर्थन लग (यद्यपि उनमें परस्पर अपने-अपने विभिन्न हिताओं के लिए होड़ भी लगी रहती थी), वैसे-वैसे उनमें अखिल भारतीय संगठन बनाने और अपने-अपने सम्मिलित स्वार्थों के लिए संघर्ष करने की इच्छा बलवती हुई। प्राकृतिक भारत में ऐसी स्थिति नहीं थी, क्योंकि उस वक़्त देश में कोई राष्ट्रीय अर्थतंत्र या राजतंत्र नहीं था। उदाहरणार्थ, प्राकृतिक भारत में किसी एक गांव का कारीगरों का दूसरे गांव के कारीगरों से कोई युक्त आर्थिक संबंध नहीं था, क्योंकि वह गांव की स्वायत्त स्थिति से संबंधित था। वैसे ही, किसी शहर का हस्तशिल्पकार का दूसरे शहर के हस्तशिल्पकारों से कोई आर्थिक संबंध नहीं था। भारत में दिन-दिवस असाधारण स्थानीय अर्थतंत्रों का और अनेक राज्यों का समूह था। इसलिए कारीगरों हस्तशिल्पकारों और किसानों के सम्मिलित राजनीतिक और आर्थिक स्वार्थ नहीं थे और न ही वे राष्ट्रीय आधार पर व्यापक संगठन बनाने की इच्छा रखते थे।

सम्मिलित स्वार्थों को चेतना

राष्ट्रीय अर्थतंत्र राज्य व्यवस्था का आधार पर और उनके संरक्षण में

सामाजिक वग जाविभूत हुए वे पुराने वर्गों से बिल्कुल भिन्न और विपरीत थे। उद्योगपति, मिला और जावागमन के साधनों को चलाने वाले मजदूर, आधुनिक व्यापारी, किसान मालिक, पेटटदार, खेत मजदूर और पेशेवर वग के अपने पथक, विभिन्न स्वायत्त थे, जस, मरक्षण अनुपात, मजदूरी और काम की हालतों मूल्या का राज्या द्वारा नियंत्रण कर निर्धारण का मन्त्र, मालभाडा नौकरिया आदि आर्थिक समस्याएँ, और मनाधिकार विधायिका सभाओं में प्रतिनिधित्व, अपने वग स्वार्थों की उपलब्धि के लिए नागरिक स्वातन्त्र्य, आदि राजनीतिक समस्याएँ।

नई आर्थिक व्यवस्था में पुराने समाज के अवशेषों के वावजूद पूँजीवादी समाज और केंद्रित राज्य सत्ता को जन्म दिया। इस व्यवस्था की स्थापना और विकास के साथ प्रत्येक नया वग अपने स्वार्थों के वशीभूत जैसे जैसे अधिक जागरूक हुआ वैसे वैसे राष्ट्रीय अखिल भारतीय मगठन की ओर अग्रसर हुआ। बुआजुजी राष्ट्रीय बुजुआजी की तरह मोचने और काम करने लगी और उसमें इंडिया चंबर आफ कामर्स और फेडरेशंस आफ इंडस्ट्रीज की स्थापना की। सत्रहारा में अपना राष्ट्रीय अखिल भारतीय रूप और अस्तित्व पहचाना और कालक्रम से आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जैसे अपने अखिल भारतीय मगठन बनाए। सांस्कृतिक तौर पर पिछड़े हुए गरीब किसानों खेत मजदूरों, खेतमालिकों और बटाईदारा, न भी पहली बार आल इंडिया किमान सभा जस अखिल भारतीय मगठन बनाए।

विद्यार्थी आरत पिछड़े हुए वग, डाक्टर मपादक और अन्य ऐसे सामाजिक दल जस-जैसे अपने सम्मिलित हितों के प्रति जागरूक हुए, वैसे वैसे उठाने जाल इंडिया चीमर्स आफ फरेम आल इंडिया मेडिकल प्रक्टिसनर्स एसोसिएशन, आल इंडिया जननिस्ट और एडिटम आफरेस आदि मगठन बनाए। अपने नए रूपों में पुराने वर्गों में भी अपने-वगे अलग-अलग भारतीय स्तर पर मगठित किया जैसे आधुनिक रजवाडा ने इंडियन चंबर आफ प्रिसेज की स्थापना की।

नए भारतीय समाज की एक विशिष्टता यह भी थी कि ये नए सामाजिक वग राष्ट्रीय मगठन बना रहे थे और अपने विभिन्न स्वार्थों की पूर्ति में लगे थे। लेकिन आवश्यकतानुसार आपस में एकताबद्ध होकर या लड़ते रहकर भी ये वग धीरे धीरे अधिक-अधिक यह भी समझने लगे थे कि भारतीय जनता की समष्टि की अपनी कुछ सम्मिलित आवश्यकताएँ हैं, जस उत्पादन की शक्तियों का विकास, भारतीय समाज की सामान्य आर्थिक प्रगति, राज्यसत्ता पर भारतीय नियंत्रण आधुनिक शिक्षा और संस्कृति का प्रसार, आदि। इन नए वर्गों के प्रबुद्ध तत्वों में यह समझगरी बतन लगी कि उनकी अपनी प्रगति समस्त भारतीय समाज की प्रगति से जुड़ी हुई है, उद्योगों के तीव्र विकास के लिए कृषि का पुनर्गठन और नवनिर्माण आवश्यक है, अपने कृषि के लिए उद्योगों का विकास आवश्यक है जिससे भूमि कुलना कम हो सके पशुवर्गों की प्रगति अन्य वर्गों की समष्टि पर आश्रित है, सामाजिक और आर्थिक प्रगति के लिए शिक्षा और संस्कृति का प्रसार आवश्यक है। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन के लिए राजनीतिक सत्ता की महत्वपूर्ण भूमिका को भी समझा।

इस तरह देश के सभी प्रगतिशील सामाजिक दलों और वर्गों का संयुक्त राष्ट्रीय आंदोलन विकसित हुआ जिसके कार्यक्रम में निम्नांकित मुद्दे थे, मूलभूत प्रशासनिक सुधार, कार्यकारिणी पर विधायिका सभाओं का नियंत्रण, व्यापक उच्च उदारवादी और तात्त्विक सावजनीन प्राथमिक शिक्षा और अधिक व्यापक उच्च उदारवादी और तकनीकी शिक्षा होमरूल, डोमिनियन स्टेटस, स्वराज्य आदि।

### विभिन्न वर्गों की चेतना का विपरीत विकास

नए वर्गों में राष्ट्रीय और वर्गीय चेतना का विकास एक साथ नहीं हुआ। प्रबुद्ध वर्ग में राष्ट्रवाद, जनतंत्र और बुद्धिवाद के सिद्धांतों को सर्वप्रथम जमींदार किया और आर्थिक राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलनों में वे ही नेता और पथ प्रदर्शक रहे। जागे चलकर शिक्षित मध्यम वर्ग बुजुर्गों, सर्वहारा किसान आदि वर्गों में अधिकाधिक मर्यादा में राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाया। 1918 के बाद व्यापक जन आधार पर राष्ट्रीय आंदोलन के लिए स्थिति परिपक्व हुई और संयुक्त राष्ट्रीय आंदोलन का उदभव हुआ (राजनीति वाला अध्याय देखें)।

मर्यादावाद (जो प्रादेशिक और अल्पमर्यादक समुदायों के अपने पथक राष्ट्रीय अस्तित्व की चेतना और भावना से भिन्न है) एक कुछ जय तत्वा के विकास के कारण राजनीतिक स्वतंत्रता तथा सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक उत्थान के निमित्त संगठित संयुक्त राष्ट्रीय आंदोलन की प्रवृत्ति को घटका भी लगा। प्रायः नौकरियों या विधायिका सभाओं में स्थान या व्यापार में प्रतिद्वंद्विता जैसे अनुभागीय स्वार्थों के नाम पर शिक्षित वर्ग के प्रतिक्रियावादी तत्वों में कुछ निहित स्वार्थों की मदद से विभिन्न मर्यादाओं के बीच पारस्परिक भेदभाव अविश्वास को जीवित रखने और उस तीव्र करने की कोशिश की (देखें अध्याय 19)। लोगों के सांस्कृतिक पिछड़ेपन से मर्यादावादियों के राष्ट्र विरोधी कार्य को मदद मिली।

प्रगतिशील नए सामाजिक वर्गों का कार्यक्रम पथक या समग्रत राष्ट्रवादी और प्रगतिशील था। आधुनिक शिक्षा और संस्कृति का प्रसार, व्यापक उद्योगीकरण भूमि सवदा का जनतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर परिशोधन और कृषि सुधार व्यवस्था का जनतंत्रिक स्वधीनता आदि मांगा संयुक्त कार्यक्रम बना था और ऐसा खयाल था कि इन मांगों की पूर्ति के द्वारा समग्रत राष्ट्रीय अस्तित्व की स्थापना हो सकेगी। इन वर्गों का लक्ष्य था भारतीय जनता के लिए उच्चतर, भौतिक और सांस्कृतिक अस्तित्व की स्थापना, उनकी प्रेरणा थी जनतांत्रिक सामाजिक और राजकीय संरचना, समृद्ध अक्षतत्र सपन प्रगतिशील सांस्कृतिक जीवन इत्यादि की आकांक्षा।

प्रगतिशील वर्गों में बढ़ती हुई प्रतिक्रियावादी प्रवृत्तियाँ

खयाल रहना चाहिए कि जीवित राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान के लिए समनुरूप तौर पर जनतांत्रिक नहीं बल्कि उग्रहरणात्मक, कृषि के क्षेत्र में

कृषक आवादी की आर्थिक अवस्था में सुधार लाने के लिए भूमि सवधा में जामूल परिवर्तना और जमींदारी उन्मूलन नहीं ता जमींदारा के बहुमूल्य अधिकारो का हनन तो निश्चय ही आवश्यक था। लेकिन भारतीय बुजुर्गों को ऐस कायन्म में कोई रुचि नहीं थी। यहा उन्हान राष्ट्रीय आर्थिक प्रगति के साधारण स्वार्थों को अपने अनुभागीय हितो के लिए, जिनको जमींदारी उन्मूलन से नुवसान था (दखें कृषि और राजनीति सवधी अध्याया को), बलि दे दी। एक अन्य उदाहरण भी दिया जा सकता है। जब कांग्रेस की सरकारें बनी तो उन्होने बावे ट्रेड डिस्प्युटस ऐक्ट पारित कर नागरिक स्वतन्त्रताओं पर जाघात किया और इस तरह अपने पूजीवादी रचान का परिचय दिया।

भारत की राष्ट्रीय बुजुर्गों की पूजीवादी ह्वास जोर बढ़ती हुई अंत पूजीवादी आर्थिक प्रतिद्वंद्विता के युग में जी रही थी। वह ब्रिटिश या अमरीकी वित्तीय पूजी पर अधिकाधिक आश्रित हाती जा रही थी, दक्षी भूपतियो के हितो से जुडी हुई थी, उसको स्थिति औपनिवेशिक थी और उसके पास राज्यसत्ता नहीं थी। मजदूरों, किसानों, बटाईदारों को हालत जैसे जैसे बुरी हाती गई वैसे वैसे उनके तजी स बढ़ते हुए आदोलना का सामना भी भारत की नवजात बुजुर्गों को करना पडा। अपने वर्ग की स्थिति एवं स्वार्थों के कारण भी यह अधिकाधिक अप्रगतिशील और प्रतिस्पर्धावादी हाती जा रही थी। फलस्वरूप इसकी विचार पद्धति में धार्मिक रहस्यवाद का जोर राजनीति में एक सत्तावादी धारणाओं, जैसे एक नेता, एक दल, एक कायन्म और नागरिक स्वतन्त्रताओं के सपेक्षण (मजदूरों की हडताल करन की जाजादी पर रोक, जादि) के सिद्धांत का प्रभाव बढा। इस वर्ग में यह प्रवृत्ति लगातार बढ़ती रही।

### भारत में दो प्रकार के आदोलन

इस तरह देश में एक ही साथ दो राष्ट्रीय, अखिल भारतीय आदोलन चल रहे थे। एक तरफ उद्योगपतियो व्यापारियो मजदूरों, किसानों, पेशेवर लोगो, विद्यार्थियो औरता जादि विभिन्न सामाजिक वर्गों के अनुभागीय हितो और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उनके अपने अपने अलग अलग आदोलन मगठित हुए। विभिन्न सामाजिक वर्गों या दलों के अपने अलग मगठन बन और अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए उन्हान अलग मधय किए। या, इन वर्गों के पारस्परिक सवधा का एक ठास ऐतिहासिक आधार था जिसके चलते उनको दास्ती दुश्मनी बनती बिगडती रही।

दूसरी तरफ, विदेशी शासन के विरुद्ध, सभी या कई एक वर्गों का चिरस्थाई या प्रसगात्मक संयुक्त आदोलन चल रहा था। इस अखिल भारतीय राष्ट्रीय आदोलन में हामरूल, डोमिनियन स्टेट्स पूर्ण स्वतन्त्रता आदि की माग की। भारत की विदेशी राजनीतिक नियन्त्रण से मुक्त करना इस आदोलन का सम्मिलित साध्य था। लेकिन सत्ता प्राप्ति के बाद राज्य एवं आर्थिक, सामाजिक मरचना का रूप क्या हो, उसके धार में प्रत्येक वर्ग की अपनी अलग धारणा थी।

प्राकृतिक भारत में राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न वर्गों के अपने वर्गीय आंदोलन नहीं थे और राजनीतिक स्वातंत्र्य एवं आर्थिक सांस्कृतिक प्रगति के लिए सारे राष्ट्र का समुक्त राष्ट्रीय आंदोलन भी नहीं था।

हम आगे आने वाले अध्यायों में देखेंगे कि विभिन्न सामाजिक वर्गों के अधिकाधिक अनुभवात्मक नई राष्ट्रीय चेतना से प्रभावित हुए, लेकिन इस नई चेतना का विकास फिर भी बड़ा सीमित और सुस्त था।

## संदर्भ

- 1 देखें गाडगिल एम० एन० राय और कृष्ण ।
- 2 देखें अधिकारी जी० डब्ल्यू० सी० रिमथ ।
- 3 ग्रेव ओ मली टामसन एड ग्रेट ।
- 4 रल्फ फ्रांस द्वारा उद्धृत प० 18 ।
- 5 देखें शानकर ।
- 6 देखें वाडिया एड मर्सेट ।
- 7 देखें पलेकर ।
- 8 दश गाडगिल जी० ब्युक्नन ।
- 9 देखें कृष्ण ।
- 10 देखें अल्लेकर मथाइ गाडगिल ।
- 11 दश ई० टामसन खुदर जी० बटनर कमीशन रिपोर्ट ।
- 12 ग्रेव बेंडन पावल जी० आर० सी० दत्त ।
- 13 देखें एन० एन० घोष पृ० 117 ।
- 14 एडवर्ड म एड मरिवेल प 229 ।
- 15 मात्स्य पृ० 79-80 ।
- 16 कृष्ण, प० 67 68 ।
- 17 पाल प० 288 ।
- 18 देखें रंगा जवाहरनाथ नेहरू ब्रह्मफोड जी० पलाउड कमीशन रिपोर्ट ।
- 19 टोना प० 166 ।
- 20 आगे क किसान आन्दोलन मबधी प्रकरण क लिए देखें रंगा स्वामी सहजानंद और इंदुलाल यामिन ।
- 21 दश रंगा ।
- 22 देखें रंगा और स्वामी सहजानंद ।
- 23 रंगा प 11 ।
- 24 वही, पृ० 12 ।
- 25 वही प० 13 ।
- 26 देखें आर० पी० दत्त ।
- 27 देखें रंगा ।
- 28 दश पट्टाभि नीतारमथा ।
- 29 दश टोना, एग्लस मनाइ लेनिन ।

- 30 देखें रंगा ।
- 31 देखें गाडगिल कृष्ण वरव ।
- 32 कृष्ण प० 137 38 ।
- 33 वही प० 176 ।
- 34 वही, प० 178 ।
- 35 स्टेटसमन कलकत्ता 2 फरवरी 1931 में उद्धृत ।
- 36 स्टालिन प० 15 ।
- 37 कृष्ण प० 140 ।
- 38 देखें गाडगिल वाडिया एड जोशी शाह ।
- 39 जोन ब्यूकप प० 53 ।
- 40 देखें रंगा और स्वामी सहजानंद ।
- 41 देखें गाडगिल और ब्यूकनन ।
- 42 पर्सल एड हात्मवय प० 10 ।
- 43 वही प० 8 9 ।
- 44 आर० पी० दत्त द्वारा उद्धृत प० 351 52 ।
- 45 वही प० 355 ।
- 46 देखें ब्यूकनन वाडिया एड मर्वेट गिव राव ।
- 47 शिवराव प० 128 ।
- 48 वही प० 210 ।
- 49 देखें ब्यूकनन प० 426 ।
- 50 जोन ब्यूकप द्वारा उद्धृत प० 135 ।
- 51 एच आर० क० दास प० 36 7 ।
- 52 शानवकर द्वारा उद्धृत प० 209 ।
- 53 आल इंडिया ट्रेड यूनियन काग्रस व जनीमव अधिवेशन कानपुर 1942 की रिपोर्ट प० 71 ।
- 54 देखें आन इंडिया ट्रेड यूनियन काग्रस की सालाना रिपोर्ट ।



## आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास में समाचारपत्रों की भूमिका

### समाचारपत्रों का निर्णायक सामाजिक महत्व

समाचारपत्र आधुनिक युग के एक शक्तिशाली सामाजिक संस्थान है। यह इससे भी सिद्ध है कि यह राज्य के चतुर्थ अवयव की सना प्राप्त है। समाचारपत्र आधुनिक जीवन की विभिन्न जटिल प्रक्रियाओं की सृष्टि ही नहीं करते, बरन उन्हें प्रतिबिंबित भी करते हैं। ये अल्पमत अवधि में विचारों का वहतम विनिमय संभावित करते हैं। इनकी मदद से सम्मेलनों का संगठन होता है, विचार युद्ध होता है, विवाद निर्णीत होते हैं आंदोलन संगठित होते हैं संस्थाएँ बनती हैं। जो समाज में शीघ्रस्थ है और जन जीवन जिनके हाथ में है, उनके समस्त कार्य कलाप पर समाचारपत्र कड़ी निगरानी रखते हैं और इस तरह उन पर जनतांत्रिक नियंत्रण स्थापित करने में सहायक होते हैं।

सत्रहवीं, अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दियों में राष्ट्र के रूप में समन्वित होने के लिए सामंती आभिजात्य द्वारा परिपोषित सामंती अनकथ के विरुद्ध संघर्ष के लिए आधुनिक राष्ट्रीय राज्य, समाज और संस्कृति की स्थापना के लिए यूरोप के देशों ने समाचारपत्रों के दुर्जेय अस्त्र का उपयोग किया। फ्रांस में, नई समाज व्यवस्था और उसकी अग्रवर्ती सामाजिक धारणाओं के अग्रदूत प्रबुद्ध वर्ग ने सामंती शासक वर्ग के नैतिक ह्रास, प्रतिक्रियावादी सांस्कृतिक सामाजिक दृष्टिकोण और क्रिया कलाप आदि का अनावरण करने में समाचारपत्रों का कारगर इस्तेमाल किया। समाचारपत्रों के माध्यम से ही वाल्टेयर, हालबाख, हलवेमियस आदि ने जनसाधारण के बीच वैज्ञानिक सामाजिक विचारों का प्रचार किया, और अपने युग के धार्मिक अधविश्वास और सामाजिक शापण के विरुद्ध श्रेष्ठान्नि प्रज्वलित की। उन्होंने कृपिदासता के विरुद्ध संघर्ष किया और सामंती आभिजात्य एवं उसकी राज्य व्यवस्था के विरुद्ध कृपिदासों को संघर्ष के लिए उत्प्रेरित किया। उन्होंने हजारों पुस्तक पुस्तिकाओं में जर्मन पर आधारित विशेषाधिकार के अजनतांत्रिक सिद्धांतों की आलोचना की, क्योंकि यह सामंती समाज का आधारभूत सिद्धांत था और इसे वैयक्तिक अधविश्वास में परमपावन बना रखा था। सामंती विशेषाधिकारों के स्थान पर उन्होंने, ज्वलंत मुद्रित शब्दों में व्यक्तियों के समानाधिकार



प्राक-ब्रिटिश काल में बड़े बड़े धनी व्यापारी भी निजी समाचार लिखने वाला को नियुक्त करते थे जो अपने मालिकों को समाचार की चिट्ठियाँ भेजते थे जिनमें वाणिज्यिक और अन्य प्रकार की खबरें थीं।<sup>3</sup> छापे की मशीन की सुविधा नहीं प्राप्त होने की वजह से सार खबर कागज और खबर की चिट्ठियाँ हाथ की लिखी होती थीं। वे आवादी के अल्पांश के लिए ही उपलब्ध और उपयोगी होती थीं और उनमें छपी खबरें बहुत सीमित प्रकार की होती थीं।

### भारतीय पत्रकारिता का विकास, 1900 ईस्वी तक

भारत में छापे की मशीन की शुरुआत यहाँ के लोगों के जीवन में नातिकारी महत्व की घटना थी। उनमें जब राष्ट्रीय चेतना का जागरण और विकास हुआ तो राष्ट्रीय पत्रकारिता का जन्म हुआ।

भारत में राष्ट्रीय प्रस के संस्थापक राजा राममोहन राय थे। उनके पहले भी कुछ लोगों ने कुछ अखबार शुरू किए थे, लेकिन उनके द्वारा 1821 में बंगाली में प्रकाशित भवाद कौमुदी और 1822 में फारसी में प्रकाशित मिरात उल अखबार भारत में स्पष्ट, प्रगतिशील राष्ट्रीय एवं जनतांत्रिक प्रवृत्ति के सबसे पहले प्रकाशन थे। ये समाज सुधार के प्रचार और धार्मिक एवं दार्शनिक समस्याओं पर आलोचनात्मक वाद विवाद के मुख्य पत्र थे। बंबई में देशी (गुजराती) प्रेम के प्रणेता फरदूनजी मजवान ने 1822 में वाव समाचार शुरू किया जो दैनिक अखबार के रूप में अब भी निकलता है।

लाड वेटिक के प्रगतिशील प्रशासनिक कार्यों से भारतीय पत्रकारिता को बल मिला। 1830 में द्वारकानाथ टगोर, प्रस ने कुमार टगोर और राजा राममोहन राय जैसे प्रगतिशील भारतीयों के प्रयास से बंगाली में बगदत्त की स्थापना हुई। उद्यमशील पारसी पी० एम० मोतीवाला ने, 1831 में गुजराती में बंबई से जामे जमशेद का प्रकाशन शुरू किया, जो अब भी दैनिक के रूप में छप रहा है। 1851 में बंबई में गुजराती के दो और पत्रों, रस्त गोपतार और जखवारे मोदागर की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के जग्रणी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक नेता दादाभाई नौरोजी ने रस्त गोपतार का संपादन किया।

1858 में प्रख्यात राष्ट्रवादी और समाज सुधारक ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने बंगाली में शोम प्रकाश का प्रकाशन शुरू किया। इसका दृष्टिकोण राष्ट्रवादी था और राजनीतिक पत्रकारिता में इसका बड़ा ऊँचा स्थान था। जब 1869 में बंगाल के नील पैदा करने वाले इलाक़ा में अशांति बढ़ी तो इसमें किसानों के हितों का जमकर समर्थन किया।

1861 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट के अंतर्गत पहली बार बधानिक कार्यवाही में भारतीयों का सहभाग लिया गया। इससे भारतीय समाज में ऊपरी तबका में राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। फलस्वरूप इसके बाद के वर्षों में भारतीय और गर भारतीय दाना तरह के पत्रों की संख्या बढ़ी। 1861 में बंबई में टाइम्स



अखिल भारतीय सागठनिक जाधार और अभिव्यक्ति मिली, जिसके कारण भारतीय जनता के ऊपरी तबका के राष्ट्रीय जागरण की प्रक्रिया तेज हुई। उनीमवी शताब्दी का अत आत-आते राजनीतिक विचारो की एक नई धारा का ज-म हो चुका था। उदारवादी राष्ट्रीय विचार पद्धति के ही साथ समकक्ष और लगभग विरोधी धारा के रूप म अतिवादी लडाकू राष्ट्रवाद का भी उदभव हुआ। इस विचारतन के नेता थे बालगगाधर तिलक, विपिन चद्र पाल, अरविद एव वारीद्र घोष और लाला लाजपत राय।

विभिन्न प्रकार के समाचारपत्रा के ज-म से 1889 के बाद राष्ट्रीय जादोलन क विकास प्रसार का अनुमान किया जा सकता है। तिलक ने मराठी म कसरी का प्रकाशन शुरू किया। इमने राष्ट्रीय मुक्ति नग्नम की विचारवारा और कायपद्धति का प्रचार किया। तिलक सुयोग्य पत्रकार थे, और इन्होंने कसरी और मराठा (अग्रेजी साप्ताहिक) की मदद स लोगा के बीच लडाकू राष्ट्रीय भावनाओ का सफल वीतारोपण किया। 'कसरी' मराठी म पाक्षिक रूप म छपता रहा और इसम छपे अपन लेखो के कारण तिलक का दो बार जेल जाना पडा।

घोष बधुओ क नेतृत्व म लडाकू राष्ट्रीयता के बगाल ग्रुप ने राष्ट्रीय मुक्ति और नवनिमाण के अपने विचारो के प्रचार के लिए प्रभावशाली पत्र 'जुगातर' और 'वदमातरम' की स्थापना की। इन पत्रा के माध्यम से बग विभाजन का विरोध किया गया, और वायकाट और स्वदेशी का प्रचार किया गया।

राष्ट्रीय चतना का समाज सुधार के क्षेत्र म भी प्रसार हुआ। बवई म 1890 म इडियन माशल रिफारमर अग्रेजी साप्ताहिक की स्थापना हुई। समाज सुधार ही इसका प्रमुख लक्ष्य था। 1899 म मच्चिदानंद सिंहा न अग्रेजी मासिक 'हिंदुस्तान रिब्यू' की स्थापना की। इस पत्र का राजनीतिक और वचारिक दष्टिकोण उदारवादी था।

### भारतीय पत्रकारिता का विकास, 1900 के बाद

1900 म जी० ए० नटेसन न मद्रास से 'इडियन रिब्यू' का और 1907 म कलकत्ता स रामानंद चटर्जी ने माडन रिब्यू का प्रकाशन शुरू किया। माडन रिब्यू देश का सबसे अधिक विख्यात अग्रेजी मासिक सिद्ध हुआ। इसम समाजिक, राजनीतिक एतिहासिक और वतानिक विषया पर लेख निकलते थे और अत-राष्ट्रीय घटनाआ के विषय म भी काम की खबरे हाती थी। इमने इडियन नेशनल कांग्रेस मे प्राय दक्षिणपथिया का समवन किया।

जब 1907 म मूरत म इडियन नेशनल कांग्रेस क नरम दल और गरम दल क बीच फूट पड गई, तो नरम दल के सर फिराजग्राह महता, सर दिनशा वाचा और गाणले जैसे नेताआ न अपन विचारो के प्रचार के लिए बवई स पत्र निकालन की जरूरत महसूस की।

1913 म वी० जी० हार्नीमन के सपादकत्व म फिराजग्राह महता न बाय

क्रान्तिकल निकालना शुरू किया। हार्नीमन के सुयोग्य और अनुभवी संचालन में 'वावे क्रान्तिकल' काफी लोकप्रिय रहा।

1914-18 के प्रथम विश्वयुद्ध के समय, गांधी जी उदारवादी नेताओं ने जनता की मांगों की पूर्ति के सरकारी आश्वासनों का भंगमा किया और वे युद्ध में सरकार की भरपूर मदद के पक्ष में थे। तिलक के नेतृत्व में कुछ अन्य लोगों का विचार था कि स्वायत्त शासन के लिए शीघ्रताशीघ्र आंदोलन शुरू किया जाए। डॉ० एनीबेसेंट इस मांग के पक्ष में थीं और उन्होंने मद्रास स्टैंडर्ड (अंग्रेजी) को अपना हाथ में ले लिया और इसे नया नाम दिया, 'यू इंडिया', यह होमरूल आंदोलन का मुखपत्र था।

1918 में सर्वेंट्स आफ इंडिया सामाजिकी ने श्रीनिवास शास्त्री के संपादकत्व में अपना मुखपत्र 'सर्वेंट्स आफ इंडिया' (अंग्रेजी साप्ताहिक) निकालना शुरू किया। इसमें उदारवादी राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देश की समस्याओं का विश्लेषण और समाधान प्रस्तुत किया। 1939 में इसका प्रकाशन बंद हो गया।

युद्धोत्तर काल में राष्ट्रीय जन आंदोलन की पहली लहर उठी। यह गहरे राजनीतिक एवं जायिक संकट और तज्जय जन विक्रोभ का परिणाम थी। गांधी, सी० आर० दास पंडित मोतीलाल नेहरू अली बघु, हजरत मोहाना, और कांग्रेस एवं खिलाफत संगठनों के जय नेताओं ने इस आंदोलन का पक्ष प्रदर्शन किया। इस आंदोलन ने भारतीय जनता की राष्ट्रीय चेतना को अभिव्यक्ति और गति प्रदान की और इनके कारण भारतीय राष्ट्रवादी जयवारा की मह्यता और बढ़ी।

1919 में गांधी ने यय इंडिया का संपादन किया और इसके माध्यम से अपने राजनीतिक दशन, कार्यक्रम और नीतियों का प्रचार किया। 1933 के बाद उन्होंने 'हरिजन' (अंग्रेजी हिंदी और कई अन्य देशी भाषाओं में प्रकाशित साप्ताहिक) का भी प्रकाशन शुरू किया।

पंडित मोतीलाल नेहरू ने 1919 में इलाहाबाद में 'इन्डिपेंडेंट' (अंग्रेजी दैनिक) का प्रकाशन शुरू किया। शिवप्रसाद गुप्त ने हिंदी 'आज' (दैनिक साप्ताहिक) की स्थापना की। अंग्रेजी से जनमिन्न माधारण जनता को राजनीति एवं संस्कृति से परिचित कराना ही 'आज' का उद्देश्य था। वाद में हिंदी भाषा में जनक राजनीतिज्ञ और साहित्यिक पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हुईं।

जसहयाग आंदोलन की समाप्ति के कुछ बाद मोतीलाल नेहरू और सी० आर० दास के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक दल ने काउंसिल में प्रवेश के प्रश्न पर पारस्परिक मतभेद के कारण कांग्रेस के अंदर स्वराज पार्टी की स्थापना की। इसके विरोधी दल वाले काउंसिल का वहिष्कार जारी रखना चाहते थे और वे सब तरह से केवल गांधी के रचनात्मक कार्य का पूरा करने के पक्ष में थे। स्वराज पार्टी के नेता ने दल के कार्यक्रम के प्रचार के लिए 1922 में दिल्ली में के० एम० पनीकर के संपादकत्व में हिंदुस्तान टाइम्स (अंग्रेजी दैनिक)

का प्रकाशन शुरू किया। इसी काल में लाला लाजपत राय के फलस्वरूप लाहौर से अंग्रेजी राष्ट्रवादी दैनिक 'पीपल्स' का प्रकाशन शुरू हुआ।

1923 के बाद धीरे-धीरे समाजवादी साम्यवादी विचार भारत में फैलने लगे। वक्स एंड पीजट्स पार्टी ऑफ इंडिया का एक मुख्य पत्र मराठी साप्ताहिक 'नाति' था। मेरठ कामपिरेसी केस के एम० जी० देसाई और लेस्टर हचिसन के संपादकत्व में क्रमशः 'स्पाक' और 'यू स्पाक' (अंग्रेजी साप्ताहिक) प्रकाशित हुए। मार्क्सवाद का प्रचार करना और राष्ट्रीय स्वातंत्र्य एवं किसानों मजदूरों के स्वतंत्र राजनीतिक, आर्थिक संघर्षों को समर्थन प्रदान करना इनका उद्देश्य था।

1930 और 1939 के बीच मजदूरों, किसानों के आंदोलनों का विस्तार हुआ और उनकी ताकत बढ़ी। कांग्रेस के नौजवानों के बीच समाजवादी साम्यवादी विचार विकसित हुए। इस तरह कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई जिसने अपने अधिकारी पत्र के रूप में कांग्रेस सोशलिस्ट का प्रकाशन किया। कम्युनिस्टों के प्रमुख प्रचार पत्र 'नेशनल फ्रंट और बाद में पीपल्स वार' थे। ये दोनों अंग्रेजी साप्ताहिक थे। एम० एन० राय के विचार अधिकारिक साम्यवाद से भिन्न थे। उन्होंने अपना जलजल दल कायम किया जिसका मुखपत्र 'इन्डिपेंडेंट इंडिया'।

जैसे-जैसे भारतीय जनता की सामाजिक राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रगति हुई, वैसे-वैसे भारतीय पत्रकारिता का विकास हुआ। हर प्रांत में हर प्रमुख नगर में, अंग्रेजी और हिंदी उद्गू एवं अन्य दशों भाषाओं में दैनिक साप्ताहिक, मासिक पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित होने लगीं। इनमें राजनीति, अर्थशास्त्र, सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याएँ तकनीकी और वैज्ञानिक महत्व के प्रश्न आदि सार-संभव विषयों की चर्चा होती थी। यहाँ केवल उन्हीं पत्र-पत्रिकाओं की चर्चा की जा सकती है जो सर्वाधिक लोकप्रिय और महत्वपूर्ण थीं।

विभिन्न राजनीतिक दलों, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक समुदायों, जमींदारों, उद्योगपतियों, किसानों, मजदूरों जैसे सामाजिक आर्थिक वर्गों, एवं विद्यार्थियों और तो दलित जातियों जैसे सामाजिक विभाजनों के अपने कार्यक्रमों और विचारों के प्रचार के लिए अपने-अलग-अलग पत्र थे। मुसलिम लीग और हिंदू महासभा जैसे सांप्रदायिक संगठनों के भी अपने-अपने पत्र थे। 1941 में, सार देश में, सत्तरहूँ भाषाओं में लगभग 4,000 पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित होती थीं।<sup>4</sup>

### भारतीय समाचार पत्रों की मूलभूत राजनीतिक प्रवृत्तियाँ

इन पत्र-पत्रिकाओं को कई श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है।

'स्टेट्समैन', 'टाइम्स ऑफ इंडिया', 'सिविल एंड मिलिट्री गवर्नट' पायनियर', और 'मद्रास मेल' जैसे प्रसिद्ध पत्र अंग्रेजी सरकार और शासन की नीतियों एवं कार्यक्रमों का समर्थन करते थे।

'अमृत बाजार पत्रिका', 'बाव नैनिकल', 'वायें मॅटिनल 'हिंदुस्तान टाइम्स', 'हिंदुस्तान स्टैंडर्ड', 'फ्री प्रेम जनल', 'हरिजन', 'नेशनल हरल्ड' नेशनल काल

अंग्रेजी में छपनेवाले लघुप्रतिष्ठ राष्ट्रवादी दैनिक और साप्ताहिक पत्र थे। 'हिंदू', 'लीडर', 'इंडियन सोशल रिफॉर्मर', 'माइन रिव्यू', उदारपंथी राष्ट्रीयता की भावना को अभिव्यक्ति देते थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की नीतियाँ और कार्यक्रम का राष्ट्रीय पत्रों में पूरा और उदारपंथी पत्रों में जालाचनात्मक समर्थन दिया। 'डान' मुसलिम लीग के विचारों का पापक था। देश के विद्यार्थी मगठना के अपने पत्र थे जैसे 'स्टूडेंट' और 'साथी'।

देशी भाषाओं के अखबारों की भी मध्या तेजी से बढ़ रही थी। इन भाषाओं के कुछ मुख्य दैनिक और साप्ताहिक पत्र पत्रिकाओं के नाम ये हैं दक्कन में 'जनशक्ति', 'जानद बाजार पत्रिका', 'वगवासी', मराठी में 'कसरी', 'लोकमान्य', 'नवकाल' और 'किल्लेस्कर', गुजराती में 'वाक समाचार', 'जन्मभूमि', 'हिंदुस्तान', प्रजामित्र' 'सदश' और 'बदेमातरम्', मलयालम में 'मानुभूमि', तमिल में 'स्वदेश मित्रम्'। इतिहास, 'जमल', 'हमदम', 'खिलाफत', 'तेज' और रियासत, उर्दू के प्रमुख पत्र थे और वीर अजुन, आज, मैनिक और विश्वमित्र प्रमुख हिंदी पत्र थे।

रायटर का 1860 में भारत में पदापण हुआ, एसोमिपेटेड प्रेस आफ इंडिया की स्थापना 1905 में हुई फ्री प्रेस यूज सर्विस की 1927 में और युनाइटेड प्रेस आफ इंडिया की 1934 में। ये दश की मुख्य समाचार एजेंसियाँ थीं।

### समाचारपत्रों के मथर एव स्वल्प विकास के कारण

या भारत में समाचारपत्रों की सख्या लगातार बढ़ती रही लेकिन इनके विकास की गति बड़ी धीमी थी। जनसाधारण की निरक्षरता और गरीबी और पत्रकारिता संबंधी दमनात्मक कानून के कारण समाचारपत्रों का भारत में तेजी से विकास नहीं हो सका। कई प्रेस एक्ट वन थे जिनके अनुसार अखबार वालों को जमानत देनी होती थी। समाचारपत्रों के मुक्त क्रियाकलाप पर ऐसे और भी प्रतिबंध थे।

भारतीय राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी आंदोलन के विकास में समाचारपत्र कारगर हथियार का काम कर रहे थे। ब्रिटिश सरकार भारतीय राष्ट्रीयता की मांग को पूरा नहीं करना चाहती थी इसलिए समाचारपत्रों पर अकुश लगाए रखना चाहती थी। अंग्रेजी सरकार का कई प्रेस एक्ट बनाने पड़े इसी से यह सिद्ध होता है कि समाचारपत्रों राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहे थे।

अपने जन्मकाल से ही भारतीय राष्ट्रवाद ने जन चेतना के स्फुरण के लिए प्रेस के महत्व को समझा और इसकी स्वतंत्रता का विच्छिन करने के हर प्रयास का घोर विरोध किया। इसलिए प्रेस की स्वतंत्रता का मध्य राष्ट्रीय जन संग्राम का अनिवार्य अंग रहा है। प्रेम की आजादी एक ऐसा मौलिक जनतात्त्विक अधिकार है जिसके लिए अपने विकास के प्रत्येक चरण में भारतीय राष्ट्रवाद ने हर संभव मध्य किया है।

अंग्रेजों के बीच भी स्वतंत्र भारतीय प्रेम विवादास्पद विषय रहा। उन्नीसवीं



सदी में वेलजली, मिंटो, एडम, कनिंग और लिटन प्रेस की आजादी पर कठोर प्रतिवध के पक्षधर रह, लेकिन हैस्टिंग्स, मेटकाफ मेकाले और रिपन ने भारत में स्वतंत्र प्रेस का समर्थन किया।<sup>5</sup> सर टामस मनरो और लाड एल्फिंस्टन जैसे उदारवादी ब्रिटिश नेताओं ने भी भारतीय प्रेस पर कठोर प्रतिवधों का समर्थन किया। उनका तर्क था कि पिछड़े हुए देश पर विदेशी शासन बनाए रखना कठिन होगा, अगर प्रेस का आजादी दी गई क्योंकि इसका सेनाओं के अनुशासन पर भी बुरा असर पड़ सकता है।<sup>6</sup>

### समाचारपत्रों के विरुद्ध दमनात्मक कार्रवाइयों का इतिहास

भारतीय समाचारपत्रों का इतिहास उनकी स्वतंत्रता के अनवरत ह्रास का इतिहास है। जिस अनुपात में भारतीय राष्ट्रवाद का विकास हुआ उन्ही अनुपात में भारतीय समाचारपत्रों की स्वतंत्रता पर आघात हुआ।

भारतीय राष्ट्रवादी पत्रकारिता के जनक राजा राममोहन राय भारतीय समाचारपत्रों की स्वतंत्रता के भी प्रथम याददाता थे। एडम के जमाने में जब प्रेस की स्वतंत्रता पर आघात हुआ तो उन्होंने चंद्रकुमार टैगोर, हरचंद्र घोष, द्वारका नाथ टैगोर, गौरीचरण बनर्जी और प्रसन्नकुमार टैगोर आदि प्रबुद्ध भारतीयों को मिलकर सुप्रीम कोर्ट के नाम अर्जी तैयार की। प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रक्षिप्त आघात को इस अर्जी में अजनतांत्रिक, असमयोजित और दकियानूमी कहा गया। इन दस्तावेजों पर दस्तखत करने वाले भारतीय समाचारपत्रों की स्वतंत्रता की लड़ाई के अनुयायी थे। मिस सोफिया कोर्ट ने इस दस्तावेज का भारतीय इतिहास का 'एरिआपजेटिका' कहा। आर० सी० दत्त ने लिखा है कि राजनीतिक अधिकारों के वैधानिक भंग का जो रास्ता आज इतना जनप्रिय है उसकी गुरुज्ञान इस अर्जी से होती है।<sup>7</sup>

वेलजली के माक वींग ने 1799 में सरकारी मसूर (सवाद नियंत्रक) की नियुक्ति की जिसका कर्तव्य था प्रकाशनाथ प्रत्येक वस्तु की जांच करना। वेलजली ने न्याय भंग के लिए दंड का विधान भी किया। हैस्टिंग्स ने 1818 में प्रेस में शिप समाप्त कर दिया और सारे प्रतिवध हटा लिए। इससे प्रेस ने जो राहत की सांस ली, उससे पत्रों के विकास का कुछ बल मिला, जब 1822 में बापे समाचार का प्रकाशन शुरू हुआ। 1823 में एक्टिंग गवर्नर जनरल एडम ने प्रेस के विरुद्ध फिर दमनात्मक कार्रवाई शुरू की। इसका राजा राममोहन राय और उनके राष्ट्रवादी दास्तों ने विरोध किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का दी गई उनकी अर्जी नामजूर हो गई, और प्रेस पर प्रतिवध लगे रह।

1825 में उदारवादी मेकाल की मदद से मेटकाफ ने एक विधेयक पारित किया जिसके अनुसार बंगाल और बरहम प्रेस पर लगाए गए प्रतिवध हटा लिए गए। उसके अनुसार कित्वा और जखबारा के मुद्रण के लिए सरकारी लाइसेंस लेना भी जरूरी नहीं रह गया।

1857 तक भारतीय प्रेस काफी स्वतंत्र रहा। विद्रोह की शुरुआत होने पर लाड कैनिंग ने 1857 का प्रेस ऐक्ट पारित किया जिसकी कठोरता के कारण इस गैंगिंग (मुंह बंद करना) ऐक्ट भी बहा गया है। इस ऐक्ट के अनुसार सरकार मुद्रणालयों की स्थापना पर नियंत्रण लगा सकती थी और पुस्तकें और पत्रों के वितरण पर भी। लेकिन यह ऐक्ट महज साल भर रहा।

1867 के प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ़ पुब्लिक ऐक्ट ने क्वितावो और अखबारा की छपाई और प्रकाशन पर नियंत्रण लगाया। तभी से बंद रहे देशी समाचारपत्रों पर नियंत्रण के लिए 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस ऐक्ट लागू किया गया। दशवीं पत्र राष्ट्रवादी विचारों और ब्रिटिश सरकार की जासूसी के मुद्दों पर हो रहे थे।

लाड रिपन के विचार उदारवादी थे और उन्होंने 1882 में वर्नाक्युलर प्रेस ऐक्ट को रद्द कर दिया। 1908 तक फिर भारतीय प्रेस को काफी स्वतंत्रता प्राप्त रही। लेकिन 1908 से पहले के दस वर्षों में राष्ट्रवादी आंदोलन तभी से विकसित होता रहा था, इसलिए सरकार ने फिर अखबारों की आजादी की बाट छांट शुरू की। 1908 में 'न्यूजपपर (इनसाइटमट टु जफेसेज) ऐक्ट पास हुआ और 1910 में इंडियन प्रेस ऐक्ट।

### 1910 के प्रेस ऐक्ट पर सर जेनकिंस के विचार

1910 के प्रेस ऐक्ट भारतीय समाचारपत्रों के विरुद्ध अंग्रेजी सरकार की कठोरतम कायदाही था। इसने प्रेस पर कायकारिणी का नियंत्रण बढ़ा दिया। कायकारिणी को यह अधिकार दिया गया कि वह जमानत की बहुत बड़ी राशि मांगे और उसे इच्छानुसार जब्त कर ले। कायकारिणी का अखबारों के मुद्रणालयों पर बर्बाद कर लेने का भी अधिकार मिला। अखबारों को 'याचलयों में अपील का अधिकार था था लेकिन उसका कोई जख भी नहीं था। एक भारतीय 'याचलय के अंग्रेज जज सर लारेस जेनकिंस ने कहा है, संवर्षन 4 की धाराएँ बहुत व्यापक हैं, और इसमें उन सारी बातों का समावेश है जो कभी भी किसी भी आदमी के दिमाग में जा सकती हैं। कहना मुश्किल है कि कोई तज्ज चानाक आदमी किस हद तक इस संवर्षन का इस्तेमाल कर लेगा। इसका इस्तेमाल कुछ ऐसी भी क्वितावा के खिलाफ हो ही सकता है जो तारीफ के काबिल है दूसरों के आश्रित, दयनीय स्थिति में रहने वाले गरीब लोगों पर भी इसके द्वारा आघात संभव है। किसी बग विशेष की तारीफ खतरे में पाली नहीं होगी। जो सत्साहिय माना जाता है उसका अधिकारिता निम्पदह इसकी पकड़ में आ ही जाएगा।<sup>8</sup> संवर्षन 4, 1910 के प्रेस ऐक्ट का अनुभाग है। यह बाद में 1931 और 1932 के ऐक्टों में भी रखा गया। भारतीय हाईकोर्ट के एक अंग्रेज याचकीय की इस सम्मति में 1910 के प्रेस ऐक्ट की दमनात्मक प्रवृत्ति स्पष्ट है।

इस ऐक्ट और इसके पहले के ऐक्टों के विरुद्ध देशव्यापी राष्ट्रवादी आंदोलन के कारण 1922 का प्रेस ला रिपील एंड जमडमट ऐक्ट पारित हुआ। इसमें

अनुसार 1908 और 1910 के ऐक्ट रद्द कर दिए गए, और प्रेम एंड रजिस्ट्रेशन आफ बुक्स ऐक्ट और पोस्ट आफिस ऐक्ट की धाराओं का हल्का कर दिया गया।

### 1931 और 32 के प्रेस ऐक्ट का महत्व

1930 तक इंडियन प्रेस को अपेक्षाकृत अधिक आजादी प्राप्त रही। 1922 और 1929 के बीच राष्ट्रवादी आंदोलन का जन-यापी रूप हासिल-मुख्य रहा। लेकिन 1929 में आंदोलन में नए तूफान आने के बाद सरकार का फिर प्रेस पर नियंत्रण करने का फैसला लेना पड़ा। 1931 में इंडियन प्रेस इमर्जेंसी पावर्स ऐक्ट पारित हुआ। बाद में इस विधेयक को 1932 के इमर्जेंसी पावर्स आर्डिनेंस के जरिए और अधिक शक्तिसंपन्न और व्यापक बनाया गया। 1932 के क्रिमिनल ला अमंडमेंट ऐक्ट की धारा 14, 15 और 16 की मदद से इसका मसौदा भी हुआ। 1932 के संशोधन ऐक्ट (आर्डिनेंस ऐक्ट) ने प्रेस संबंधी कानून को और अधिक सख्त बनाया, इसका क्षेत्र व्यापक किया और कार्याकारिणी को 1931 के ऐक्ट की तुलना में और अधिक अधिकार दिए।<sup>9</sup>

अपने संशोधित रूप में 1931 के प्रेस कानून न भारतीय प्रेस की आजादी में काफी कटौती की। इसके अनुसार कार्यावाही अधिकारी को जमानत मांगने और जमानत बनाने का पूरा अधिकार था। इसका क्षेत्र इतना व्यापक था कि उदारवादी एव नरमदिल के अखबार भी इसकी पकड़ में आ सकते थे। ऐक्ट में यह स्पष्ट कहा गया कि 'प्रेस पर अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रण शामिल करना इसका उद्देश्य था। जिन नए अपराधों के विरुद्ध इसका इस्तेमाल हो सकता था, उसमें ऐसे प्रकाशन भी थे जो सीधे या परोक्ष रूप में ब्रिटिश महाराज या भारत में कानून द्वारा स्थापित शासन, सरकार या न्याय के प्रशासन या ब्रिटिश महाराज के राज्य के किसी भी वंश या अंश अनुभाग को घना या पात्र बनाने या सरकार के प्रति विराग पदा करने की काशिश कर। कानून और व्यवस्था के मंचालन और अनु-रक्षण या भूमिकर और खेती नायक जमीन पर लग टक्स, रेंट या धनाया के तौर पर वसूल की जा सकने लायक अन्य चीजों की बमूली जाति में हस्तक्षेप, सरकारी अफसरों को त्यागपत्र देने के लिए उकसाने, सरकार की प्रजा के विभिन्न तत्वों में घणा के भाव फैलाने, और लोगों को डराने-धमकाने के लिए इस विधेयक में सजा का प्रवर्धन था।'<sup>10</sup> इस तरह यह ऐक्ट अत्यंत व्यापक था। इसके विभिन्न अनु-च्छेदों को पढ़ने से पता चलता है कि प्रेस का स्वरूप और चरित्र इस पर निर्भर था कि मजिस्ट्रेट, पुलिस अफसर और स्थानीय शासक क्या चाहते हैं।<sup>11</sup>

सरकार ने भी इस विधेयक की उग्रता का पहचाना। सेंट्रल असेंबली में हाम मन्तर नर हनरी हग ने कहा 'महाशय, मैं यह मानता हूँ और सरकार भी मानती है कि इस विधेयक की विभिन्न धाराएँ जिम्मेवार मपादना के लिए कष्टप्रद हैं और ऐसे मपादकों की सट्टा कम नहीं। मुझे मान्य है, महाशय कि सुनचित्त पत्रों का कैम्पे कठिनाइयां भुगतनी पड़ रही है।'<sup>12</sup>

1932 के प्रेस ला के अनुसार, सरकार न अक्सर ऐसा किया कि किसी प्रांत विशेष के पत्रों को कोई खास समाचार छापन की मनाही कर दी, हालांकि दूसरे प्रांत के पत्रों न उम समाचार को छापा। इमने दो स्तंभों के शीपक, माट टाइप और समाचारों के क्रम विचाम, और कुछ राजनीतिक नेताओं के फाटा छापने पर भी प्रतिवध लगाए। भारतीय पत्रकारों और प्रचारकों न इन प्रतिवधों का काफी कठोर माना है।

1932 के फारेन रिलेशंस एक्ट न उन प्रकाशना के लिए दंड का विधान किया जिनसे ब्रिटिश सरकार और अन्य विदेशी राज्यों के दोस्ताना भवदा पर प्रभाव पड सकता था। इंडियन स्टेटस (प्रोटेक्शन) ऐक्ट 1934 म बना। वो राज्य ब्रिटिश सरकार की सर्वोपरि सत्ता के अधीन थे उन राज्यों के प्रशासना का जिन क्रियाकलापों के द्वारा कमजोर किया जा सकता था या जिनके द्वारा बहाने अमृतोप फलाया जा सकता था या बहाने के प्रशासन के रास्त म कठिनाइया खडी की जा सकती थी उन क्रियाकलापों से इन राज्यों के प्रशासना की रक्षा करना इस एक्ट का उद्देश्य था। इस एक्ट म उन प्रकाशनों के लिए भी दंड विधान था जिनके कारण भारत के किसी भी राज्य म घणा या अमृतोप का बढावा मिल सकता था। इन दो विधेयकों ने भारतीय प्रेम की आजादी का और अधिक हनन किया।

### तीन समाचार एजेंसियां

1941 तक भारत म तीन प्रमुख समाचार एजेंसियां की स्थापना हो चुकी थी, रायटर एसोसिएटेड प्रेस फ्री प्रेस यूज सर्विस। सरकार पहले दाना को प्रथम देती थी और उनके माध्यम से समाचारों का वितरण करती थी। तीसरी एजेंसी भारतीय थी और समाचारों के चयन और वितरण म राष्ट्रीय दृष्टिकोण से प्रभावित थी।

सरकारी ममयन के कारण भारत को विदेशी समाचार देन और वितरण का भारतीय समाचार देन म रायटर का लगभग पूरा एकाधिकार प्राप्त था। इसका कारण भारतीय राष्ट्रवादी बाहर वाले के लिए भारतीय घटनाओं के समाचार का राष्ट्रीय दृष्टिकोण से चयन या विवचन नहीं कर पाते थे।

ब्रिटिश सरकार की नीतियों के अनुसार, रायटर कुछ प्रकार के समाचारों को बाहर भजने म दर कर देत था। अमृतसर की जनहत्या के समाचार बाहर का दुनिया को सात महीने तक मालूम नहीं हुए ब्रिटेन की आम जनता का भी इसकी खबर नहीं थी।<sup>13</sup>

जिन भारतीयों ने स्वतंत्र समाचार एजेंसियां स्थापित करने की कोशिश की उ हान देखा कि सरकारी सहायता किसी समाचार एजेंसी के सफल मचालन के लिए एक अनिवार्य शर्त है। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जब तक सरकार कुछ समाचार मगठनों के प्रति आर्थिक तौर पर अन्य प्रकार से पक्षपातपूर्ण रव्य अपनाती रहेगी, तब तक दूसरी कंपनियां की स्थापना असंभव है।<sup>14</sup>

कुछ विशेष प्रकार के विदेशी खासकर वामपंथी, साहित्य के भी भारत जाने पर प्रतिवध था। इन प्रतिवधों को लागू करने के लिए भी कस्टम्स डिपार्टमेंट का एक अपना अलग विभाग ही था। इस प्रतिवध के कारण भारतीय जनता दूसरे देशों के आंदोलन और विचारधाराओं की जानकारी नहीं प्राप्त कर पाती थी।

भारतीय राष्ट्रीयता के आंदोलन ने प्रेम की स्वतंत्रता को कम करने की सारी सरकारी कायवाहिया का हरदम विरोध किया। प्रेस की स्वतंत्रता का मध्य राष्ट्रीय आंदोलन का अनिवार्य अंग था। राजा राममोहन राय और उनके सहयोगी, भारतीय राष्ट्रवाद के अग्रणी नेताओं नरम गरम उदारवादियों और वसेंटॉइन होमरूल वालों, गांधी के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस, समाजवादियों, साम्यवादियों छात्र मण्डल, मजदूर और किसान संघों और आल इंडिया सिविल लिबरटीज यूनियन आदि विभिन्न दलों और मण्डलों ने प्रेस की स्वतंत्रता को कम करने वाले सरकारी कार्यों की तीव्र आलोचना की।

इससे यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय आंदोलन के जन्म और विकास में प्रेस का कितना बड़ा महत्व है। आल इंडिया सिविल लिबरटीज यूनियन ने भी, जिसने भारतीय जनता की जनतांत्रिक स्वतंत्रता के लिए काम किया प्रेस की स्वतंत्रता के लिए मध्य किया। आल इंडिया जनलिस्ट एसोसिएशन, आल इंडिया एडिटर्स काफेरेस, प्रायेंसिव राइट्स काफेरेस आदि ने भी प्रेस की आजादी को लड़ाई लड़ी।

### भारतीय प्रेस की प्रगतिशील भूमिका

भारतीय राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी आंदोलन के सामाजिक, सांस्कृतिक राजनीतिक और आर्थिक, प्रत्येक रूप के विकास में प्रेस का बहुत बड़ा हाथ रहा। प्रेस द्वारा उपलब्ध राजनीतिक शिक्षा और प्रचार की सुविधा के कारण ही राष्ट्रीय आंदोलन का राजनीतिक पक्ष संभव हुआ। इसकी ही मदद से भारतीय राष्ट्रवादी दल लोगों के बीच प्रतिनिधि सरकार, स्वतंत्र, प्रजातांत्रिक संस्थाएँ, होमरूल डोमिनियन स्टेट्स और स्वाधीनता आदि विचारों का प्रचार कर सका। इनके जरिए वे ब्रिटिश सरकार और शासन की कारवाइयों की दिन प्रतिदिन आलोचना कर सका और लोगों को राजनीतिक समस्याओं की समझ और शिक्षा दे सका।

विभिन्न राष्ट्रीय दलों के बीच विभिन्न राजनीतिक कार्यक्रमों और मध्य पद्धतियों आदि को जनप्रिय बनाने के लिए प्रेस का हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया और उसकी मदद से जन मण्डलों की स्थापना की। प्रेस के बिना राष्ट्रीय मण्डलों के आल इंडिया काफेरेसों की तैयारी संभव नहीं हो पाती और न बड़े राजनीतिक आंदोलन ही संगठित हो पाते। उदाहरणार्थ, 1930-32 के जन आंदोलन के समय कांग्रेस और कांग्रेस समर्थक लोग गांधी के अनुदेशों की जानकारी के लिए यही इंडिया पढ़ते थे। चूंकि प्रेम राष्ट्रीय मध्य के लिए फायदे का था इसलिए हर प्रकार के राष्ट्रवादियों ने भारतीय राष्ट्रवादी प्रेस की स्थापना के लिए मध्य किया।

भारतीय राष्ट्रीयता के निर्माण में प्रेस का महत्व इस बात से ही स्पष्ट है कि राजा राममोहन राय, केशवचन्द्रसन, गोखले, तिलक, फिरोजशाह महता, दादा भाई नौराजी सुरेन्द्रनाथ वनर्जी, सी० वाई० चिंतामणि, एम० के० गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे अनेक लोगों ने 'नैतिक मूल्यों' में अपनी अपनी विचारों के प्रचार के लिए माध्यम रूप में प्रेस का उपयोग किया।<sup>11</sup>

प्रेस के ही कारण देश के विभिन्न भागों में रहने वाले विभिन्न सामाजिक दलों के बीच जनवर्त और व्यापक विचार विनिमय संभव हो सका और प्रादेशिक आवाजियों के बीच सामाजिक और मानसिक संबंध स्थापित हो सके। सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में राष्ट्रीय सहयोग और अंतर्प्रादेशिक कार्यक्रमों पर विचारों और तर्कों का आदान प्रदान हुआ और सामाजिक राजनीतिक और सांस्कृतिक राष्ट्रीय सम्मेलन संगठित हुए। इन सम्मेलनों में पारित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय समितियों की स्थापना हुई। इसके चलते बहुराज्यीय मंचों जटिल, सामाजिक सांस्कृतिक राष्ट्रीय अस्तित्व के लिए रास्ता प्रशस्त हुआ।

प्रेस ने प्रादेशिक साहित्य और संस्कृतियों के विकास में भी मदद दी, यह रूप में प्रादेशिक है लेकिन बस्तुतः राष्ट्रीय। बंगाल महाराष्ट्र, आंध्र, गुजरात मालाबार यू० पी० और अन्य प्रदेशों में कविता नाटक उपन्यास आदि से संपन्न प्रादेशिक साहित्य की स्थापना हुई।

जाति, बाल विवाह, विधवा विवाह तथा वे सामाजिक न्यायिक और अन्य प्रकार की असमानताएँ जिनकी ओरते शिकार थीं इन सामाजिक कुरीतियों का विरोध करने में प्रेस ने सुधारवादी दलों की मदद की। छुआछूत के खिलाफ प्रचार में भी प्रेस से मदद मिली। भारतीय समाज के जनतांत्रिक पुनर्निर्माण के सिद्धांत और कार्यक्रमों से साधारण जन को अवगत कराने में भी प्रेस का सहयोग प्राप्त हुआ। प्रेस के ही माध्यम से समाज सुधारकों ने इन कुरीतियों को हटाने के सर्वोत्तम उपायों पर लगातार विचार विनिमय किया और संयुक्त कार्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय सम्मेलनों का आयोजन किया।

प्रेस के माध्यम से भारत की जनता को दुनिया में होनेवाली घटनाओं की भी खबर मिलती रही। प्रेस के जरिए दुनिया के बहुत सारे राष्ट्रों के बारे में एक अपना दृष्टिकोण कायम कर सके हैं और इस तरह मारे ससंसार के विकास की दृष्टि से अपने सिद्धांत और कार्यक्रमों का निर्धारण करते रहते हैं। विभिन्न देशों की प्रगतिशील शक्तियों में पारस्परिक सहयोग भी प्रेस के माध्यम से ही संभव हो सका है।

इस तरह भारतीय जनता के बीच राष्ट्रीय भाव और चेतना का उदय और उत्थान में, उनके राष्ट्रीय आंदोलन के संगठन और विकास में प्रादेशिक साहित्य और संस्कृतियों की मृष्टि और विभिन्न देशों के साथ सन्तुष्ट की स्थापना में प्रेस का बहुत बड़ी भूमिका रही है।

## प्रेस के विकास की आवश्यक शर्तें

स्वतंत्र, व्यापक, प्रगतिशील, सुविस्तृत, पत्रकारिता के विकास मे निम्नलिखित बाधाएँ आई

- (1) सरकार द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता पर लगाए गए प्रतिबंध,
- (2) लोगों की गरीबी जिसने अखबारों, पत्रों और अन्य प्रकाशना की बिक्री का साक्षर लोगों तक ही सीमित रखा
- (3) लोगों की निरक्षरता,
- (4) कुछ धनी, ब्रिटिश और भारतीय दला द्वारा प्रेम पर एकाधिकारी नियंत्रण की बढ़ती हुई प्रवृत्ति (जायिक क्षेत्र म जो एकाधिकार की वृद्धि हो रही थी, प्रेस म एकाधिकार उसी का प्रतिफलन था ।)

इस तरह यह स्वतंत्र सिद्ध था कि भारतीय जनता की सामाजिक, जायिक, मास्टृतिक प्रगति के सूचक व रूप म प्रेस का व्यापक और स्वतंत्र विकास स्वतंत्र भारत मे ही नभव था, भारत जो ब्रिटिश शासन और भारतीय एव विदेशी यस्त स्वार्था से मुक्त हो ।

## सदभ

- 1 देखें लास्की टोना नापाटकिन ।
- 2 देखें श्री मली प० 189 ।
- 3 वहाँ ।
- 4 वही प० 188 ।
- 5 देखें ओ मेनी मार्गारिटा वास ।
- 6 देख मागारिटा वास प० 251 ।
- 7 आर० सा० दत्त जो मेली द्वारा उद्धृत ।
- 8 इंडियन ला रिपोट म न० 41 (कलकत्ता) ।
- 9 भारतीय शिष्ट मडल का प्रतिवेदन प० 286 ।
- 10 वहाँ प० 290-291 ।
- 11 वही प० 292 ।
- 12 वही ।
- 13 आर० पी० दत्त प० 35 ।
- 14 मागारिटा वास (2) पृ० 188 ।
- 15 मागारिटा वास पृ० XV ।

## सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन राष्ट्रीय जनतांत्रिक जागरण की अभिव्यक्ति

### सुधार आंदोलन राष्ट्रीय जागरण के प्रतीक

अंग्रेजी शासन के दिना में भारत में समाज और धर्म सुधार सवधी जा आंदोलन शुरू हुए वे भारतीय जनता की उदीयमान राष्ट्रीय चेतना और उनके बीच पश्चिम के उदारवादी विचारा के प्रसार के परिणाम थे। इन आंदोलन ने धीरे धीरे सामाजिक और धार्मिक नवनिमाण का कार्यक्रम अपनाया और सारा देश इन आंदोलनो की चपेट में आया। सामाजिक क्षेत्र में जाति सुधार या जाति प्रथा की समाप्ति, औरता के लिए समानाधिकार, बाल विवाह के उन्मूलन और विधवा विवाह के समथन सामाजिक और कानूनी असमानता के विरोध, आदि प्रश्नो पर आंदोलन हुए। धार्मिक क्षेत्र में जो आंदोलन हुए उहाने धार्मिक अधविश्वास और मूर्तिपूजा बहुदेवतावाद वशानुगत पुराहिती आदि का विरोध किया। इन आंदोलनो ने कमावश मात्रा में व्यक्ति स्वातन्त्र्य, सामाजिक एकता और राष्ट्रवाद के सिद्धांतो पर जोर दिया और उनक लिए मधप किए।

भारत में ब्रिटिश शासन के आगमन के बाद यहा जो नया समाज विकसित होता जा रहा था, उसकी जरूरते पहले के पुराने समाज की जरूरता से भिन्न थी। उदारवादी पाश्चात्य मस्कृति में दीक्षित नए प्रबुद्ध वर्ग ने इन जरूरता को पहचाना और सुधारवादी आंदोलन शुरू किए या सामाजिक मस्थाआ, धार्मिक दृष्टिकोण, परंपरागत नतिक धारणाआ में नातिकारी परिवर्तन की चेष्टा की, क्योंकि उनके अनुसार य राष्ट्रीय प्रगति के रास्ते में बाधक थीं। उह विश्वास था कि नए समाज का राजनीतिक साम्कृतिक और आर्थिक विकास व्यक्ति स्वातन्त्र्य व्यक्ति की उन्मुक्त अभिव्यक्ति के लिए जबसर सामाजिक समानता जादि उदारवादी सिद्धांतो के आधार पर ही सभव है। इन सुधार आंदोलनो में भारतीय जनता के जागरूक और प्रगतिशील वर्ग की नई सामाजिक आवश्यकताआ के परिप्रेक्ष्य में पुराने धार्मिक दृष्टिकोणा के परिभाजन और सामाजिक मस्थाआ के प्रजातंत्रीकरण की इच्छा का प्रतिफलन हुआ।

भारतीय समाज सुधारका को यह शिकायत थी कि समाज सुधार तंत्री से



नहीं हो रहा था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार उसे पूरी मदद नहीं दे रही थी। उनका कहना था कि सरकार सामाजिक प्रतिक्रियावाद और अत्याय के गढ़ को ध्वस्त करने में उनकी मदद नहीं कर रही थी। समाज सुधार मवधी विधेयक पारित होने की गति बड़ी धीमी थी और सरकार जो थोड़े बहुत काम कर रही थी देश के प्रगतिशील विचारों के दबाव में कर रही थी। उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध में ब्रिटिश शासकों ने स्वयं ही दास व्यवस्था सती प्रथा और बाल मृत्यु जसी क्रूरतियों के उन्मूलन में प्रगतिशील काम किए थे। लेकिन बाद में शासक वर्ग के दृष्टिकोण में परिवर्तन आए। एज आफ कंसेंट ऐक्ट 1891 में पास हुआ लेकिन कइ दशकों के बाद यह पहला सरकारी सुधार कानून हुआ था। इन सब कारणों से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं को इस विचार को बल मिला कि राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना आवश्यक है, जिससे लोग सामाजिक और धार्मिक सुधार की गति को तीव्र कर सकें।

### सुधार आंदोलन में जनतांत्रिक भाव

गुरु से ही भारतीय राष्ट्रवाद की प्रवृत्ति जनतांत्रिक थी। समाज और धर्म सुधार के आंदोलनों में भी यह प्रवृत्ति विद्यमान रही। कर्मावश मात्रा में इन आंदोलनों में सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में सामाजिक विशेषाधिकार को समाप्त करने, देश की सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के जनतंत्रीकरण और राष्ट्रीय एकता के रास्ते में लागू हुए अडगो जैसे जाति आदि अनिष्टकर संस्थाओं को सुधारने या खत्म करने के प्रयास किए। वे जाति और लिंग के परे सबको समान अधिकार दिलवाना चाहते थे।

सुधारकों का कहना था कि भारतीय जनता की राजनीतिक स्वतंत्रता और सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति और राष्ट्रीय एकता के लिए यह आवश्यक था कि सामाजिक मवधों और संस्थाओं का जनतंत्रीकरण हो।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक जागरण का राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में असर पड़ा। राजनीति में, उसके चलते प्रशासनिक सुधार स्वायत्त शासन होमरूल, डामिनियन स्टेट्स और अंततः स्वाधीनता के सपने का जन्म हुआ। सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में भारतीय राष्ट्रवाद ने व्यक्ति स्वातंत्र्य, समानता और आत्मनिर्णय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसने जन्म और जन्म पर आधारित विशेषाधिकार पर जिनसे जानि जसी संस्थाओं का मपोषण हुआ था और जो अजनतांत्रिक सिद्धांत थे, आघात किया। इस तरह भारतीय राष्ट्रवाद सारत जनतांत्रिक या और मध्ययुगीन सिद्धांतों और विदेशी शासन के विरुद्ध संघर्षरत रहा। समाज और धर्म सुधार के आंदोलन भारत के राष्ट्रीय जागरण के मूचक थे और उनका उद्देश्य था मध्ययुगीन सामाजिक संरचना और धार्मिक दृष्टिकोण का कर्मावश जनतांत्रिक अर्थात् व्यक्ति स्वातंत्र्य और मानव एकता के सिद्धांतों के आधार पर परिशासन।

## जाति प्रथा के विरुद्ध धर्मयुद्ध

### जाति प्रथा हिंदू धर्म का लौह ढांचा

जाति प्रथा न हिंदुओं को जन्म पर आधारित परस्पर पृथक् पदानुक्रमित श्रेणियों में बांट रखा था और इसलिए समाज सुधार जादोलनों ने इनके उन्मूलन को अपना प्रमुख लक्ष्य बनाया। जाति प्रथा हिंदू धर्म का लौह ढांचा थी। वेदों में भी इसके अस्तित्व की चर्चा है और इस तरह यह प्रथा वेदों से भी पुरानी है। शुरू में हिंदू समाज में तीन या चार वर्ण थे। लेकिन बाद में प्रजातीय सम्मिश्रण भौगोलिक विस्तार हस्तशिल्प के विकास और तत्पश्चात् नए व्यवसाय व उदभव आदि कारणों से प्रारम्भिक वर्ण विविध जातियों उपजातियों में विभक्त हो गए।

अतीत में हिंदू धर्म सभी हिंदुओं की सांस्कृतिक एकरता का आधार था जाति प्रथा ने उन्हें विभिन्न दलों और उपदलों में अलग अलग बांट दिया। शादी, विवाह, पान और रोजगार जैसे सभी महत्वपूर्ण सामाजिक मामलों में ये दल एकात्मिक और विशिष्ट थे।

जाति प्रथा मत्तावादी और अजनतांत्रिक थी। इस पदानुक्रमित श्रेणी शृंखला में प्रत्येक जाति अपने नीचे की जाति से श्रेष्ठ और ऊपर की जाति से निम्नोत्पन्न थी। इस शृंखला में जाति विशेष की स्थिति से ही उस जाति में पैदा हुए व्यक्ति का सामाजिक स्थान निर्धारित होता था। व्यक्ति विशेष के जन्म से ही उसकी अपरिवर्तनीय स्थिति पूर्वनिर्धारित हो जाती थी। जादमी का सामाजिक अस्तित्व उसके जन्म पर निर्भर था, न कि उसके योग्यता एवं मर्यादा पर।

इसी तरह जिस जाति में आदमी पैदा होता था उसी से यह पूर्व निर्धारित हो जाता था कि उस जादमी का पेशा क्या होगा। अलग में अपना पेशा चुनने की आजादी उसे नहीं थी। जन्म ही यह फैसला करता था कि आदमी कौन सा पेशा चुनेगा। प्रत्येक जाति और उपजाति में आपस में ही शादी की प्रथा थी। किसी जाति विशेष का आदमी अन्य जाति में शादी नहीं कर सकता था। इस तरह जीवन साथी चुनने का क्षेत्र भी अत्यंत सीमित था।

जाति न व्यक्तिगत क्षमता नहीं बल्कि जन्म पर आधारित जातिजात्य की

मण्डि की। व्यक्ति की अपनी विशिष्ट प्रतिभा और क्षमता का मुक्त उपयोग इसके कारण असंभव हो रहा था और साथ ही उसकी उपनमन शक्ति, आत्मविश्वास और उद्यमशीलता का हनन भी हो रहा था। यह स्थिति राष्ट्र भावना और प्रजातान्त्रिक राज्य व्यवस्था के विकास को अवरुद्ध करती है। छुआछूत की समस्या जाति व्यवस्था का ही परिणाम है।<sup>1</sup>

जाति व्यवस्था पदानुक्रमित श्रेणी शृंखला जाबद्ध थी और इसलिए सामाजिक और धार्मिक विषमता पर आधारित थी। सामाजिक पिरामिड में शीर्षस्थ ब्राह्मण जाति के ही लोग धार्मिक और सामाजिक क्रिया कलाप में पुरोहित का कार्य कर सकते थे और उच्च धार्मिक या धर्म निरपेक्ष शिक्षा और ज्ञान की प्राप्ति के एकमात्र अधिकारी भी वे ही थे। इन पिरामिड के निम्नतम धरातल पर शूद्रों, अछूतों की जगह नियत थी जिन्हें धर्म द्वारा पुनीत घोषित और राज्य की अवपीडक सत्ता द्वारा समर्थित हिंदू समाज ने जय जातियों की सेवा करने और हलखोर, चमार आदि पशु जैसा निम्न कार्य करने के लिए बाध्य कर रखा था।

जाति व्यवस्था की अन्यायता इस बात में निहित नहीं थी कि यह बतव्या की विभिन्नता पर आधारित थी, वरन् इस बात में कि इसमें जन्म को सामाजिक विभाजन का आधार बनाया। इसका अर्थ इतना ही नहीं है कि यह व्यवस्था समानता के सिद्धांत के विरुद्ध थी, वरन् यह भी है कि इसमें असमानता पूर्णतः वशानुगति के आधार पर संगठित रूप में मिलती है। किसी भी समाज व्यवस्था में कार्य की विभिन्नता तो रहेगी ही, इस बविध्य की अवश्यभाविता की पहचान जाति व्यवस्था की विशिष्टता नहीं है, इस कम बविध्य को व्यवस्थापित और नियंत्रित करने का इसका तरीका अवश्य विशिष्ट है।

### जाति बनाम वर्ग

चूँकि जादमी की जाति उसके जन्म द्वारा निर्धारित होती थी इसलिए वह अपरिवर्तनीय थी। इसी जन्म में जाति व्यवस्था समाज की पूँजीवादी व्यवस्था द्वारा प्रभूत वर्ग विधान से भिन्न है।

जातियाँ जन्म मानव समुदाय का अपना स्वयं का पूर्ण विनियमित जीवन होता है। स्वच्छिन्न मर्यादा और वर्गों में विपरीत जातियों की सदस्यता चयन पर नहीं वरन् जन्म पर निर्भर है। आधुनिक यूरोप के सामाजिक वर्गों में व्यक्ति की पदवी प्रतिष्ठा संपत्ति पर निर्भर है इसके विपरीत भारत में जादमी की पदवी प्रतिष्ठा जन्म जाति के परंपरागत महत्त्व पर निर्भर थी जिसमें भाग्यवश उसका जन्म हुआ था। जाति और वर्ग के विभेद पर जहाँ तक इनका अर्थ स्पष्टतः पृथक् विभाजना से है, भगवान् न कहा है प्राचीन सभ्यताओं में जन्म ही वर्ग और प्रतिष्ठा का निर्णायक हाता था, लेकिन आज की पारंपरिक सभ्यताओं में संपत्ति उतना ही, या और भी अधिक महत्वपूर्ण या निर्णायक है, और संपत्ति जन्म की अपेक्षा कम दुर्लभ निर्णायक है। यह अधिक ठीक

है, इसलिए उसके दावों को जासानी से चुनौती दी जा सकती है। चूकि संपत्ति परिणामतः कम या अधिक हो सकती है इसलिए यह जाति या दलगत विभिन्नताओं का जनक नहीं हो सकती, हस्तांतरणीय, प्राप्य और अय सन्नाम्य होने के कारण यह वैसे चिरस्थायी विभेदों की सृष्टि नहीं कर पाती जैसे की सृष्टि जन्म कर सकता है।<sup>3</sup>

‘वर्ग के सदस्यों के आचार-विचार व संचालन नियमन के लिए समस्त समाज के कानूनों के अतिरिक्त अपनी कोई विशिष्ट स्याइ या जस्थायी पचायत नहीं होता।’<sup>4</sup>

जाति की पचायता को जध कानूनी क्षमता प्राप्त थी, जिसकी मदद से वे दावी सदस्यों को जाति निकाला, जुर्माना और शारीरिक दंड की सजा दे सकती थी। जाति का सदस्य पहले अपनी जाति के प्रति वफादार होता था तब सार समाज के प्रति। इसके कारण सामाजिक एक्य और बहुत्व की भावना दुबल पड़ जाती थी।

प्रत्येक जाति की आचार विचार संबंधी अपनी धारणाएँ थी, अपन जन्मे बुर आदश थे। ये धारणाएँ और आदश उस जाति के मत्स्या पर लागू थे, और इस तरह कालक्रम से प्रत्येक जाति एक दूसरे से पृथक होती गई प्रत्येक जाति एक अलग सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय के रूप में विकसित हुई।

फिर जाति व्यवस्था का धर्म का भी समर्थन प्राप्त था। जाति की शुरूआत ही भगवान ब्रह्मा से मानी जाती थी। जाति नियमों का उल्लंघन जाति विराधी ही नहीं बरन अर्वाभिक कृत्य भी माना जाता था। धर्म तरह धर्म के कारण लोगों पर जाति की पकड़ मजबूत हुई।

अपने अनुयायियों से हिंदू धर्म की पहली मांग यह थी कि ‘जिस सामाजिक स्थिति में उनका जन्म हुआ है उसे वे खुशी से स्वीकार कर लें ज्यों अपनी जाति की मायताओं का मजूर कर लें क्योंकि जाति तो नसर्गिक विधान है और जाति द्वारा निर्धारित कर्म से ही उन्हें माध भिल मकेगा और मृत्युपरांत वह उच्चतर अंतरिक्षी जीवन का भागी होगा।

शादी ब्याह पेशे का चुनाव, पारस्परिक ध्यान पान और जीवन के जया ये बहुत सारे परम व्यक्तिगत प्रश्नों पर भी जाति का नियंत्रण था। जाति की मायताओं का धर्म और हिंदू राज्य की अवपीठक शक्ति का समर्थन प्राप्त था और वह स्वयं भी अपराधी का दंड दे सकती थी इस तरह इस व्यवस्था में व्यक्तिगत आजादी थी ही नहीं। व्यक्ति अपने पेशे का चुनाव नहीं कर सकता था, अपनी इच्छा और मर्जी से शादी नहीं कर सकता था और न जिस किसी के साथ भोजन ही कर सकता था। फिर जिस जाति में किसी व्यक्ति विशेष का जन्म हुआ है, उस जाति की प्रतिष्ठा से ही उसे आदमी की सामाजिक प्रतिष्ठा निर्णयित मिलती थी और कानून की नजर में उसकी स्थिति तय होती थी। सरकारी कानून एक नहीं थे, वे अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग थे।

पदानुक्रमित श्रेणी शृंखला जावद्ध होने के कारण जाति व्यवस्था ने जातियाँ के बीच परस्पर असमानता की मण्टि की। नीची और ऊँची जातियों के आधार भी अलग हात थे। नीची जातियाँ को शहर या गाँव में जलम जमीन पर प्रसाया जाता था। अछूत और अपवित्र जातियाँ के लोगों को समाधारण क कुँजो और तालाबो से पानी भी नहीं मिल सकता था। वे मंदिरों में भी प्रवेश नहीं पा सकते थे। जाति प्रथा के कारण सामाजिक प्रपीडन इतना जमानवीय हो गया था कि निम्नतम स्तर के कुछ लोगों को अछूत और निकृष्ट मान लिया गया। उन पर दृष्टिपात होने भर से लोग अपवित्र हो जाते थे और जो अछूत जान अनजान किसी ब्राह्मण को दिखाई पड़ जाता था उसे बड़ी कठोर सजा मिलती थी।<sup>6</sup>

### जाति व्यवस्था के प्रमुख लक्षण

पदानुक्रमित श्रेणी शृंखला सामाजिक असमानता सजातीय व्याह भोजन पान पर प्रतिबन्ध पेशे के चुनाव में स्वतन्त्रता का अभाव ये ही जाति व्यवस्था के प्रमुख लक्षण थे।

मक्षेप में, प्रत्येक भाषा क्षेत्र में लगभग दो सौ समुदाय थे जिन्हें जाति के नाम से जाना जाता था और जिनके अपने अलग अलग नाम थे। उनमें किसी एक में भी जन्म होने पर व्यक्ति विशेष की सामाजिक पदवी प्रतिष्ठा नियत हो जाती थी। ये जातियाँ लगभग दो हजार उपजातियों में विभक्त थीं। उपजातियाँ शादी व्याह और साधक सामाजिक जीवन और विशिष्ट सांस्कृतिक परंपरा की स्थापना आदि का सीमा निर्धारण किया करती थीं। कुछ उपवाद हा सकते हैं लेकिन इन बड़े-बड़े दलों के पुरोधा प्रायः एक ही हात में जा सारे दलों को बाधे रहते थे जो विभिन्न दलों इस व्यवस्था के जग में उठाने इसके मूल विदुआ को पूणत स्वीकार कर लिया था और गाँव में वे दलों परस्पर एक दूसरे पर जाश्रित थे, इसलिए ये विशिष्ट एकांतिक दल समस्त व्यवस्था को विभिन्न स्वतंत्र दलों में विखंडित नहीं कर सकें यरन उठाने नागरिक जीवन में एक प्रकार का तालमेल बनाए रखा। या निश्चय ही यह सामजस्य बसे तत्वा का सामजस्य नहीं था जिनका मूल्य समान हा। यह एसी एकांतिका का सामजस्य था जो एक दूसरे पर जाश्रित थी।<sup>7</sup>

मूलतः भारतीय जनता के जाश्रित अस्तित्व क अविनशित हान के कारण जाति प्रथा सदिया तक फलनी-फूलती रही। जिस प्राक पूजावादी अथतत्र पर यह जाश्रित थी गाँव का स्वशासन त्रिनिमय मवधा का अपूण विकास और यातायात क अक्षम और स्वरूप पाधन उसका आधार थे।

भारत पर अत्रजो शासन ने जिस नई सामाजिक, जाश्रिक और राजनीतिक स्थिति की मण्टि की और उनका परिणाम हुए उनका चलते जाति प्रथा के जा भी फायदे कभी रहे हा व घतम हा गए।

## जाति प्रथा के ह्रास के कारण

अंग्रेजा की भारत विजय के फलस्वरूप जिन आर्थिक शक्तिवा का जन्म हुआ उहोन जाति का आर्थिक आधार ही खतम कर दिया। गावा के स्वशासन का हनन, भूमिगत वैयक्तिक संपत्ति का सजन देश का अनवरत उद्योगीकरण जिसके कारण नए पेशा का जन्म हुआ और आधुनिक शहर बस जि होने जातिगत विधि निषेधो पर कुठाराघात किया, रेलवे और बसो के यत्नजाल का विस्तार जिसके कारण भारतीय इतिहास में पहली बार बड़े पैमाने पर लोग घाना करने लगे और इस तरह चाह अनचाह एक दूसरे के संपर्क में आए, इन कुछ प्रमुख कारणों से जातियों का पेशागत आधार और इसके सदस्या के एकांतिक आचार विचार समाप्त हुए।

## नए संपत्ति संबंधों का प्रभाव

भूमिगत सांपत्तिक अधिकार और इनमें हर फेर कर करने की स्वतंत्रता नभावना एवं औद्योगिक वाणिज्यिक प्रशासनिक और डाकटरी एवं वकालत जैसे पेशा और व्यवसायों की मृष्टि के कारण गावा के समुक्त परिवारों में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्तिया उभर आई। परिवार के जिन सदस्या ने बाहर शहरों में जाकर विविध पेशों का अख्तियार किया उहान संपत्ति के विभाजन की माग करनी शुरू की।

भारतीय कृषि का तकनीकी पिछडापन एवं नई भूमिगत व्यवस्था किसानों की बढ़ती हुई ऋणग्रस्तता आर समानुपाती औद्योगिक विकास के अभाव में हो रहे हस्तगिरि के ह्रास और फलस्वरूप भूमि पर बढ़ती हुई जनसकुलता इन सब कारणों से किसान बहुत बड़ी तादाद में शहरों में जान के लिए बाध्य हो रहे थे। वहां इहाने मिला में मजदूरी या घरेलू नौरु का काम किया। इसके चलते भी जाति का पेशागत आधार विघटित हुआ।

जाति पचायता का जानि संबधी नियमों के उल्लघन के लिए दंड देने का जो अधिकार था उस त्रिटिंग सरकार ने अपहृत कर लिया। शहर जाति बाध्यता और नई आर्थिक राजनीतिक हालाता में सुलभ नए अवसरों के कारण लोग न जाति सम्मत पतृक पेशा को छोडना शुरू किया। पुरोहित या शिक्षक का काम करने के बंदे ब्राह्मणों में डाकटर, व्यापारी मिन मालिक, किरानी या हवाई जहाज मचालन का काम करना गुरु किया। आधुनिक बाध्यता या आकाक्षा के कारण शिक्षित ब्राह्मण नम उत्राग जस काय भी गुरु कर रहे थे जो आज से पचास बप पहले घणा की दृष्टि से दया जाता था।<sup>४</sup>

## आधुनिक शहरों का प्रभाव

आधुनिक उद्योगों के कारण जिन आधुनिक शहरों का जातिभाव हुआ उनमें उड्डे होटल, जनपानघर, थियेटर ड्राम, बम जादि भर पडे थे। विभिन्न जातियों के बान घान पान और शरीरि संपर्क न प्रश्न पर एक दूसरे में जिस पाबन्ध का

निर्वाह करते जाएं ये वह नियमित रूप से समाप्त हाने लगा। विभिन्न पेशा या सामाजिक उत्तमता में जय जातियों और संप्रदायों के सदस्यों से भी संबंध रखने की आवश्यकता से इस प्रक्रिया को बन मिला। यूरोपिया से संबंध और राजनीतिक जयवा आर्थिक सम्मेलना से संबंधित सामाजिक मनोरंजनों के कारण सब जातियों के और बिना जाति के भी लोग एक दूसरे के साथ आए।<sup>19</sup>

ताज होटल में ब्राह्मण मिल मालिक शूद्र मिल मालिक के साथ भोजन करने लगा। शहरों में मजदूरों और मध्यम वर्गीय लोगों के मावहारण होटलों और जल पानघरों में विभिन्न जातियों और धर्मों के लोगों की भीड़ लगने लगी। टेना और बसा में लागू कृतित जातियों के लोगों और कभी-कभी अठूना से भी कथा सटा कर चलने लगे। आधुनिक सामाजिक अस्तित्व की सुविधाओं ने जाति या संप्रदायगत विभाजनों को कोई मायता नहीं दी, जलबता के निष्पक्ष रूप से उन सबके लिए थी जो उनके लिए पसा दे सकें।

फिर भी यह समझना गलत होगा कि जातिगत विभाजन समाप्त हो गए थे। शहरों में भी दक्षिणानुसी जातिपरियों ने हरचद कोशिश की कि जाति द्वारा निर्धारित नियमों का पूरी तरह पालन किया जाए। ऊपर केवल यह बताने की कोशिश की गई है कि इन रीति रिवाजों की ऐतिहासिक गति ह्लासा मुख थी।

### नए न्यायतंत्र का प्रभाव

दण्ड में समरूप न्यायतंत्र लागू कर ब्रिटिश सरकार ने प्राक ब्रिटिश भारत में प्रचलित सामाजिक और न्यायिक अमानताओं का गहरी चोट पहुंचाई। प्राचीनकाल में यह जाति की प्रतिष्ठा से निश्चित होता था कि किसी को क्या सजा मिलगी। हिंदू राज्य, जाति और गान एक ही अपराध के लिए विभिन्न जाति के अपराधियों को विभिन्न सजा दिया करत था। अत्र न्यायगत जाति निरपक्ष समानता की स्थापना हुई।

ब्रिटिश सरकार ने जाति की पचायतो से दंड देने का अधिकार ले लिया। इस तरह जाति के पास वह अस्थ नहीं रह गया जिसके माध्यम से वह जाति के उदबड उजडड सदस्यों पर नानू रख सके। जाति जय स्वच्छिक मगठन भर रह गया और अगर जाति के नियमों के उल्लंघन के लिए पचायत न जुर्माना लाया या जय सजा दी ता इसके लिए उस नानून की सहमति नहीं प्राप्त थी। इससे चलत जाति की शक्ति काफी कम हो गई।

कास्ट डिजब्रिटीज रिमूवल एक्ट आफ 1850, द स्पेशल मरिज एक्ट आफ 1872 और स्पेशल मरिज अमंडमट एक्ट आफ 1923 ने जाति के नव्य प्राणों का ध्वस्त करने में मदद दी।

### नए सामाजिक वर्गों के उदय का प्रभाव

नई आर्थिक व्यवस्था के कारण आर्थिक क्षेत्र में जावादी नए मगठन तयार हा

गए। पुराने कायवाही विभाजनो पर नयी जातिया नई कायवाही के अनुकूल नही थी। भारतीय जनता अब पूजीपति मजदूर, किसान मालिक व्यापारी, बटाईदार, खेत मजदूर, डाक्टर वकील टेक्निशियन जैसे विभिन्न दलों में विभक्त थी, और प्रत्येक दल में विभिन्न जातिया और मजदूरी के लोग थे यद्यपि इन दलों के अपने विशिष्ट भौतिक और राजनीतिक स्वार्थ थे। नए वर्गों के अनुसार इन इन नए समस्तर विभाजनो न पुराने श्रेणीगत विभाजना को कमजोर किया। इस तरह मिल आनम एसोसिएशन, आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, आल इंडिया किसान सभा लैड लाड स यूनियन जसी नई जमाने बनी। इन दलों ने अपने विभिन्न स्वार्थों के लिए मजदूरी किए। इन मजदूरों के सिलसिले में इन्होंने नया दृष्टिकोण, नई चेतना, और नई मजदूरी विकसित की जिस क्रम में लोगों की जातिगत चेतना का ह्रास हुआ। वेग मजदूरों और मजदूरों से भारतीय जनता को नया नया दृष्टिकोण नया नया व्यवहार प्राप्त हुआ। इस तरह वे लगा तार जाति व्यवस्था को कमजोर करते गए।

### वेग मजदूरों का प्रभाव

हटनाली मजदूरों में मजदूरी बढान और काम की हालता में सुधार और तरक्की के शामिल उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऊंची जातिया के मजदूर जखून मजदूरों से कथा मिलाकर लडे। इसी तरह ब्राह्मण हां या वैश्य और शूद्र पूजीपतिया ने भी मजदूरों से अपने स्वार्थों की रक्षा के लिए अपनी एकता कायम की। हिंदू मुस्लिम, इसाई विभिन्न मजदूरों के एक ही वेग के लागू वेगगत एकता की परिधि में आए। ऐतिहासिक प्रवृत्ति यह थी कि वेग सूत्र मजदूर हुए, और जाति सूत्र कमजोर क्योंकि वेग विभाजन जाधुनिक आर्थिक जस्तिव समाज के नए आर्थिक विभाजन, और वेग के सदस्यों के समरूप भौतिक स्वार्थों पर आधारित था।

राष्ट्रीय अथवा भी वेग विभाजन का आधार था। प्राकृतिक भारत में पेशा ही जाति का आधार था और देहात या शहर का स्थानीय अथवा उसका जवलवन। किसान और कारीगर बहुमध्यक जातिभर स्वशासित शहरों या गावा में स्थानीय दलों में विभक्त थे, उनके कोई जगिल भारतीय सम्मिलित भौतिक स्वार्थ नहीं थे। उनके अपने स्थानीय स्वार्थ थे और इसलिए उनकी एकता स्थानीय थी।<sup>10</sup> लेकिन इसके विपरीत परवर्ती काल में किसान मजदूर व्यापारी और मिल मालिक आदि विभिन्न नए वर्गों की अपनी जगिल भारतीय एकता बनी।

पेशागत विभिन्नता के कारण लोगों की जावादी और उनके जीवन स्तर में विभेद आए। इससे लोगों के आचरण और व्यवहार, दृष्टिकोण और चिंतनशली एवम भावाक्षया में भी अंतर आए और जाति विरोधी भावनाएं बनीं। या पुरानी विचारधारा जडता नतिक माहस का अभाव, जाति धारणा में जाति विरोधी भावनाएं व्यापक विद्रोह का रूप ले लीं।



## आधुनिक शिक्षा का प्रभाव

जाति के प्रति श्रद्धा की भावना समाप्त करने में आधुनिक शिक्षा की भूमिका भी कम नहीं है। प्राकृतिक शिक्षा भारत में जो कुछ शिक्षा भी वह ब्राह्मणों के एकाधिकार द्वारा निर्देशित थी और वह धर्म से ओतप्रोत थी। चूंकि जाति व्यवस्था को धर्म का समर्थन प्राप्त था, इसलिए हिंदू धर्म से ओतप्रोत वह शिक्षा पद्धति लोगों को जाति व्यवस्था को स्वीकार करने की शिक्षा देती थी और व्यक्तियों में जाति विवेक स्थापित करने में मदद देती थी। लोग यह मानकर चलते थे कि जाति दैविक विधान है और यह समझते थे कि जाति के नियमों का उल्लंघन धर्मपाप है। प्राकृतिक शिक्षा पद्धति का एक काम था व्यक्ति में हिंदू समाज की जाति व्यवस्था के प्रति श्रद्धा की भावना का संचार करना और उसे जातिगत मस्कारों और स्वतंत्रता का उत्साही और इच्छुक अनुयायी बनाना।

ब्रिटिश शासन ने शिक्षा पद्धति को धर्म निरपेक्ष बनाया। अब यह सबको सहज सुलभ थी। अपनी सीमाओं और विवृत्तियों के बावजूद यह शिक्षा पद्धति सारत उदारवादी थी। धर्म के समक्ष व्यक्तियों की समानता राज्य के सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार, मनमाफिक पेशा अग्नितयार करने की आजादी, नई शिक्षा पद्धति ने इन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। यूरोपियन उदारवाद इसका आधार था। प्रतिनिधि सभाओं और एसोसिएशन और अमेरिकी की स्वतंत्रता जैसे विचारों का इसने प्रचार किया। ब्रिटिश शासन भारतीय जनता पर विदेशियों का शासन था और इसलिए अप्रजातांत्रिकता थी ही। फिर भी इस शासन द्वारा संगठित और चलाई गई शिक्षा पद्धति प्राकृतिक शिक्षा भारत की शिक्षा पद्धति की तुलना में, जिसमें हिंदू समाज की जातिगत विभिन्नताओं और विशेषाधिकारों का समर्थन दिया, धर्म निरपेक्ष और मूलतः उदारवादी तो थी ही।

भारतीय समाज के शिक्षित वर्ग के एक जमाने पाश्चात्य देशों के उदारवादी दशन और प्रजातांत्रिक मस्यौदों का अध्ययन किया और उन्होंने जाति विरोधी विद्रोह की पतानी फहराई। राजा राममोहन राय दबदबनाथ टैगोर रसवचंद्रसन, जैसे प्रबुद्ध भारतीयों ने जाति सुधार को अपने कार्यक्रम का मूलभूत तत्व बनाया।

जैसे-जैसे हिंदू समाज के निम्नतम स्तर में शिक्षा का प्रसार हुआ, वैसे-वैसे हिंदू समाज के चिरदासीन अंधाधुंध शिकार इन वर्गों में साम्य भाव का उदय हुआ। फलस्वरूप डा० जम्नदत्त के नेतृत्व में दलित जातिवादी के आन्दोलन और दक्षिणी भारत के सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जन्म जाति विरोधी आंदोलन का जन्म हुआ।

## राजनीतिक आंदोलन का प्रभाव

जाति चेतना का दुबल करने में राष्ट्रीय आन्दोलन ने विशाल भूमिका रखी है। भारत में विदेशी शासन के कारण लोगों का राष्ट्रीय धर्म पर संगठित होने का आवश्यकता महसूस होना रही। जन्म वर्ग विदेशी शासन के विरुद्ध

राष्ट्रीय सघष व्यापक और तीव्र हुआ, वैसे वैसे मकीण स्थानीय, प्रांतीय, जातिगत और सांप्रदायिक चेतना भी कमजोर हुई। लिबरल फेडरेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस आदि संस्थाओं के कार्यक्रम, युद्धनीति और कार्य पद्धति भिन्न हो सकती हैं, लेकिन इनका आधार जाति या संप्रदाय नहीं था। इन्होंने जाति और धर्म से ऊपर उठकर सार भारतीयों का आह्वान किया। इन्होंने भारत के लिए जिस राजनीतिक रूपरेखा की कल्पना की उसमें जातियों के विशेषाधिकार के लिए कोई स्थान नहीं था। 1921-22 के असहयोग आंदोलन और 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे राजनीतिक आंदोलनों के चलते भारत में राष्ट्रीय चेतना काफी मजबूत हुई। इन आंदोलनों के कार्यक्रम और युद्ध पद्धति चाहे जा भी हों, ये स्वयं राष्ट्रीय चेतना के प्रतिफल थे और इन्होंने इस चेतना को गहराई और व्यापकता प्रदान की। इस तरह राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में भी कुछ हद तक हिंदुओं की जातिगत चेतना को कमजोर किया। वस्तुतः वगजन्म एवम् राष्ट्रीय दोनों प्रकार के आंदोलनों में भारतीय जनता की वग चेतना को दुबल बनाया।

### जाति प्रथा का प्रतिक्रियावादी रूप

ब्रिटिश शासनकाल में स्थापित आधुनिक अर्थतंत्र और राष्ट्रीय स्वातंत्र्य के सघष में विजय के लिए आवश्यक राष्ट्रीय ऐक्य की राह में जाति व्यवस्था बाधा स्वरूप थी। औद्योगिक विकास के लिए श्रम आपूर्ति की आवश्यकता थी। जाति के नियमों के अनुसार सभी के लिए पैतृक पेशा अपनाना जरूरी था और इस तरह उद्योगों के लिए पर्याप्त मजदूरों का मिलना मुश्किल था। जाति भक्ति का स्वान सर्वोपरि था, इसलिए राष्ट्रवाद जैसे बहुरंग विचारतंत्र के प्रति भक्ति का स्थान बाधा में आता था। बारीगरी की बर्बादी और किसानों के दारिद्र्य के कारण यह आवश्यक हो गया कि ये लोग दूसरे पैसे अर्द्धित्यार करें। व्यक्ति स्वातंत्र्य जैसे प्रजातान्त्रिक विचारों के प्रचार के कारण शिक्षित भारतीयों में जातिगत विभेद और असमानता के प्रति विद्रोह की भावना जगी। इस तरह धीरे-धीरे जाति विरोधी आंदोलनों का जन्म हुआ और वे शक्तिशाली हुए यद्यपि सजातीय विवाह की व्यवस्था, जो जाति प्रथा का मूलधार थी, अक्षुण्ण रही। जाति व्यवस्था के कारण सामाजिक जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी सुधार की प्रक्रिया अवरुद्ध रही। हमारी तरफ भरा जाशय गुजरान में है जाति समाज सुधार के माग में सबसे बड़ी बाधा रही है।<sup>11</sup>

शिक्षित भारतीयों ने ही जाति व्यवस्था पर आघात किया क्योंकि उन्होंने नए भारत के मद्देन में इसकी असंगति को पहचाना। राष्ट्रीय स्वतंत्रता और दण की राजनीतिक सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति के लिए जाति संरचना का सुधार या उन्मूलन आवश्यक था। व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा हानी चाहिए थी और जाति की जकड़ से व्यक्ति की पहल-रुदमी का मुक्त होना था। तभी दण के सभी व्यक्तियों की नियातमक शक्ति का स्फुरण संभव था। जाति का शिरजा स

व्यक्ति की मुक्ति राष्ट्रीय प्रगति के लिए आवश्यक थी। जातिगत विशेषाधिकार और अपगता की समाप्ति के बाद ही सामाजिक न्याय संभव था। एक जमाने में कहा जाता था कि मृत्यु के बाद जादमी को अपवग तभी मिलेगा जब जाति के नियमों का पालन हो। जब समाज सुधारकों ने राष्ट्रीय प्रगति का मानव जीवन का ध्येय बताया।

### जाति प्रथा के विरुद्ध आंदोलन

समाज सुधारकों ने मध्ययुगीन समाज व्यवस्था के आधारभूत विचारों पर ही आघात किया। 'पथकता, उत्तर्विवेक के बदले बाह्य शक्तियों के प्रति आत्मसमर्पण मानव के बीच जन्म या उत्तराधिकार पर आधारित काल्पनिक विभेद, सांसारिक सुख के प्रति निरपेक्षता जो भाग्यवाद का रूप ले सकता था, य हमारी प्राचीन समाज व्यवस्था के मूल सिद्धांत हैं। इन्हीं से जाति का हमारा पारिवारिक प्रबंध निर्धारित होता है और इन्हीं के कारण हमारे परिवार में स्त्री पुरुष के जीवनस्थ है और निम्न जाति के लोग उच्च जातियों के अधीनस्थ। इस तरह लोग में मानव जाति के प्रति कोई श्रद्धा की भावना नहीं रह गई।'<sup>1</sup>

समाज सुधारकों ने सामाजिक वषम्य और पाषण्य पर चोट की और समानता (उदारवादी बुजुआ अर्थों में) और सहयोग का समर्थन किया। उन्होंने जन्म और उत्तराधिकार को विभेद का आधार मानते स इनकार कर दिया, और कम के सिद्धांत का विरोध किया। गर प्रजातान्त्रिक, एकतात्रिक जाति व्यवस्था को इससे धार्मिक, दार्शनिक बल मिलता था। उन्होंने लोगों से अपील की कि मृत्युपरांत मुक्ति के लिए प्रयास करने के बजाय वे वास्तविक दुनिया में अपनी स्थिति में सुधार करें। उनके अनुसार राष्ट्रीय ऐक्य और संगठन के रास्ते में जाति व्यवस्था बहुत बड़ी बाधा थी।<sup>12</sup>

विभिन्न समाज सुधार दलों ने विभिन्न दृष्टियों से जाति व्यवस्था पर आघात किया। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय ने हिंदुओं के प्राचीन समाजशास्त्रीय धर्मग्रंथ महानिर्वाण तंत्र की मदद से यह सिद्ध किया कि जाति व्यवस्था की अब कोई आवश्यकता नहीं। ब्रह्म समाज ने इन शब्दों में जातिग्रन्थ सामाजिक विभाजना की निंदा की 'यहानिर्वार विभेद जो हमारे जन जीवन का धूम पी रह है, क्या समाप्त हाग? देना ने इस देश के लिए जिस श्रेष्ठ उत्कृष्ट नियति का विधान किया है उस पूरा कर मकने के लिए यह दंग तंत्र संगठित आर शक्तिगाली हा सवेगा? इससे बड़ा सत्य कोई नहीं कि जाति व्यवस्था, 'ना हमारे समाज की भारी बुराईया के मूल में है व पूण उन्मूलन के बिना इस नियति की पूर्ति नहीं हो सकती।'<sup>14</sup>

द्वेन्दनाथ टगार और कान्धचंद्र सन, जो राजा राममोहन राय के बाद ब्रह्म समाज के नेता हुए हिंदू धर्मप्रथा के उनसे भी उड़े आलोचक थे। कान्धचंद्र सन ने धर्म प्रथा की मदद के बिना ही, बड़े माफ गन्ना में जाति व्यवस्था की धारण

निंदा की। राजा राममोहन राय न सामाजिक विद्रोह की जिस भावना का उदघाटन किया, उसकी चरम परिणति हुई केशवचंद्र सेन के नेतृत्व में।

ब्रह्म समाज ने जाति विरोधी आंदोलनों की जो शुरुआत की, उसके बाद के संगठनों ने उन्हें जारी रखा। बावे प्रायना समाज न जाति विरोधी आंदोलन लगभग उसी तौर पर चलाया जिस तौर पर ब्रह्म समाज ने चलाया था। पाश्चात्य देशों के प्रजातांत्रिक और सांस्कृतिक प्रभाव में ब्रह्म समाज और प्रायना समाज दोनों ने जाति नामक सस्था की ही जालोचना की। इसके विपरीत स्वामी दयानन्द के आय समाज ने जाति व्यवस्था का विरोध नहीं किया वरन् चार वर्णों पर आधारित वैदिक काल के हिंदू समाज को पुनरुज्जीवित करना चाहा। आय समाज ने हिंदू समाज के जनगिनत उपविभाजन के विरुद्ध सघष तो किया, लेकिन शुरू के चार विभाजनों के आधार पर इनके नव निर्माण की भी चेष्टा की। फिर इसने यह भी कहा कि निम्नतम जाति शूद्रा का भी धर्मग्रन्थों के पठन-पाठन का आधार दिया जाए। इस तरह ब्रह्म समाज और प्रायना समाज जाति भ्रंशक आंदोलन थे, लेकिन आय समाज उपजातियों के उन्मूलन के द्वारा जाति व्यवस्था में सुधार लाने के पक्ष में था।

ब्रह्म समाज, प्रायना समाज और आय समाज के अतिरिक्त भी जाति विरोधी आंदोलन हुए। तेलग रानाडे और फूले, जिन्होंने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की और मालावारी, कवि नमद और अन्य लोगों ने भी जाति व्यवस्था का जमकर विरोध किया। दक्षिण में सेल्फ रिसपेक्ट मूवमेंट ने उन अपमानजनक अपगताओं के विरुद्ध सघष किया जिनसे गैर ब्राह्मण जातियाँ पीड़ित थीं।

भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के वामपक्षी नेताओं ने यह तक उपस्थित किया कि चूँकि प्रतिगामी सामाजिक सस्थाएँ देश के निम्न आर्थिक विकास पर निर्भर हैं और चूँकि देश के आर्थिक विकास की इस स्थिति का कारण यह है कि भारतीय जनता के हाथ में राजनीतिक सत्ता नहीं है, इसलिए भारतीय समाज के नव निर्माण के लिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता अनिवार्य है। इस तरह जाति व्यवस्था का उन्मूलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता के प्रश्न से जुड़ा हुआ माना गया। सामाजिक और सांस्कृतिक पिछड़ापन आर्थिक पिछड़ापन और राजनीतिक गुलामी का परिणाम है, उसकी अभिव्यक्ति है इसका मूल कारण आर्थिक राजनीतिक है।<sup>15</sup> वामपक्षी नेताओं का विश्वास था कि भारतीय समाज का मूलभूत सुधार तभी संभव है जब भारतीय जनता को आत्म शासन का अधिकार मिले, इसलिए उन्होंने स्वराज के लिए अधिकाधिक घोरतर सघष किए।

यद्यपि भारतीय राष्ट्रवादियों की यह समझदारी थी कि राजनीतिक सत्ता भारतीय समाज के प्रजातांत्रिक, मूलभूत सुधार के लिए आवश्यक है, फिर भी उन्होंने सामाजिक बुराईयों के विरुद्ध सघष कमजोर नहीं हान दिया। लेकिन इन लोगों ने अपन कार्यक्रम में समाज सुधार का प्राथमिकता नहीं दी।

## जाति प्रथा के समर्थक आदोलन

प्रायः सबने ब्रिटिश सरकार की इसलिए आलोचना की कि उसने जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। कुछ ब्रिटिश इतिहासकारा, पत्रकारों और प्राध्यापका न कभी-कभी यह भी कहा कि ब्रिटिश शासन को बनाए रखने के लिए जाति व्यवस्था को जीवित रखना आवश्यक है। जेम्स कर ने कहा है यह सदिग्ध है कि जाति प्रथा का अस्तित्व सब मिलाकर ब्रिटिश शासन के स्थायित्व के प्रतिकूल है। अगर हम बुद्धि और धर्म से काम ले तो यह हमारे अनुकूल भी हो सकता है। जाति भावना राष्ट्रीय ऐक्य के विरुद्ध है।<sup>16</sup>

कुछ ऐसे छोटे छोटे कारण भी थे, जिन्होंने जाति भावना को जीवित रखा। 1921 के सेंसस आपरेशंस के दो सुपरिटेण्डेंटों में एक मिडल्टन थे जिन्होंने पंजाब में जाति व्यवस्था पर अंग्रेजी शासन के प्रभाव के बारे में महत्वपूर्ण बातें कही हैं।

मैंने यह दिखाना चाहा था कि जातियों के पेशागत वर्गीकरण के विरुद्ध व्यापक विद्रोह भावना थी कि ब्रिटिश सरकार ने प्रायः इन जातियों का निर्माण किया था, और हर हालत में उन्हें विभिन्न जातियों के रूप में सुरक्षित रखा था। जातियों की प्रचीन जड़ता को हमारे लैंड रेड कंस न लौह बंधन में बांध दिया है हमने प्रत्येक व्यक्ति की जाति के अनुसार खानावदी कर दी और जहाँ हमने उनके लिए कोई निश्चित जाति नाम नहीं पाया, वहाँ हमने पतृत्व पेशे के आधार पर उन्हें एक नया नाम दे दिया। हम जाति व्यवस्था और आर्थिक और सामाजिक समस्याओं पर उसके दुष्प्रभाव की निंदा करते हैं, लेकिन जिस व्यवस्था कि हम निंदा करते हैं, उसके लिए बहुत हद तक हम ही उत्तरदाई भी हैं। या छोड़ दिया जाए तो लोहार और सानार जसी जातियों का तुरंत लोप हो जाएगा खानावदी और लेवल के सरकारी माह के कारण जाति व्यवस्था को निश्चित रूप मिला है।<sup>17</sup>

राष्ट्रीय आंदोलन और मजदूरों एवं मालिकों तथा किसानों एवं जमींदारों के बीच मध्य के विवास एवं उनकी तीव्रता के कारण धनी वर्गों के कुछ नागान जाति प्रथा का बनाए रखने के भी प्रयास गुरू किए। उनका उद्देश्य था, जनता की बढ़ती हुई राष्ट्रीय एजता और विभिन्न जातियों एवं संप्रदायों के मजदूरों, किसानों की बढ़ती हुई वग एकता को छिन्न भिन्न करना। जैसे जैसे मजदूरों और किसानों या बटाईदारों ने वह नमयना गुरू किया कि व्यक्तिगत रूप में वे जिन किसी जाति के हों उनके सम्मिलित आर्थिक और राजनीतिक स्वाध और हित ह वस वस व अपने को एक जाति के बदल एक वग का सदस्य मानने लग, और ट्रेड यूनियन, किसान सभा बटाईदार संघटन, सतमजदूर संघटन जैसे संघटनों में एकत्रित होने लग। उन्होंने सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टियों जसी जन वग की पार्टियों का भी गठन किया। धर्म और जीवन के अच्छे हागत के लिए मालिकों और जमींदारों के खिलाफ उन्होंने सम्मिलित गणप भी किए। स्वभाव

यह बात जमींदारों और मालिकों को पसंद नहीं आई और उनमें जो सर्वाधिक प्रतिक्रियावादी थे उन्होंने जनसाधारण की बढ़ती हुई एकता को समाप्त करने के लिए जाति की प्रतिगामी संस्था का भी इस्तेमाल किया।

प्रत्येक जनगणना में हिंदू आवादी का जातियों के आधार पर किए गए जा वर्गीकरण का विरोध किया गया, क्योंकि इसने उन जातिगत मतभेदों को जीवित रखा, जिन्हें खत्म कर देना चाहिए था। दूसरी तरफ जाति व्यवस्था के भी अपने पक्षधर थे, जो जाति व्यवस्था का समाज के सिमेट के रूप में गुणवान मानते थे। ऐसा सिमेट जाति हिंदुत्व को जकड़े रखता है और बाहरी आघातों से उसकी रक्षा करता है। दरभंगा महाराजाधिराज ने कहा है कि जाति व्यवस्था विद्रोह की भावना बर्गों और लोगों एवं पूजा और धर्म के बीच की बढ़ती हुई पारस्परिक कटुता, जो सभ्यता के लिए सदा हानिकारक है से सुरक्षा प्रदान करती है।<sup>19</sup>

जातिगत दानशीलता और जाति पर आधारित पारस्परिक सहायता संगठनों के कारण भी जाति के विनाश की प्रक्रिया में बाधा आई। जातिगत भाइचारे की भावना से प्रभावित और जाति में बढ़ती हुई अपकेन्द्रीय प्रवृत्तियों से घबड़ाए हुए जाति के सदस्यों ने पारस्परिक सहायता के लिए समितियों का संगठन किया। जाति के गरीब सदस्यों को आर्थिक सहायता दी गई और जाति के ही सदस्यों को कम किराए पर आवास की सुविधा प्रदान करने के लिए मकान बनाए गए। जाति विशेष के बालक बालिकाओं की शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियां दी गईं और जाति विशेष के सदस्यों के लाभार्थ सहायक समितियां संगठित हुईं।

इन सबके कारण जाति चेतना मजबूत हुई और जाति भक्ति बढ़ी, और इन बातों की राष्ट्र विरोधी अप्रगतिशील भूमिका रही। पहले तो जाति दल शहर के गिल्ड का या ग्राम समुदाय का अनिवाय अंग होता था। पर्याप्त आर्थिक विनिमय और जावागमन की सुविधाओं की अनुपस्थिति में दूसरे गांव या शहर में रहने वाले उसी जाति के सदस्यों से उनका संपर्क नाममात्र का था। अब रेलवे और बसा के कारण यात्रा की जो सुविधाएं प्राप्त हुईं उसके कारण जातियों का राष्ट्रव्यापी संगठन बने, जिन्होंने जाति के सम्मेलन बुलाए और सारे देश में फैले हुए जाति विशेष के सदस्यों के हितों की देखरेख के लिए जाति की कार्यकारिणी सभाएं बनाईं। जातिगत भाइचारे की भावना के प्रचार के लिए पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ। इन सबके कारण राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत चेतना का उद्भव और विकास हुआ।

लेकिन जाति का आर्थिक आधार लगातार कमजोर होता जा रहा था और इससे सदस्यों के सम्मिलित आर्थिक हितों का ह्रास हुआ। एक ही पेशा करने वाले, सम्मिलित भाविक स्वायत्त और नृष्टिकाण वाले लोगों की जमात के रूप में जाति धीरे धीरे मिथक का रूप लेने लगी। यह नए समाज के वास्तविक विभाजन के रूप में लागू होने गठित हानि में बाधक होकर रह गई।

## निम्न जातियों के आंदोलनों का द्वैत रूप

अप्रजातान्त्रिक जाति व्यवस्था जय सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक अपगताओं से पीड़ित हिंदू समाज की निम्न जातियों के आंदोलनों के दो रूप थे प्रगतिशील एवं अराष्ट्रवादी और प्रतिगामी। निम्न जातियों ने जाति का आधार पर अपने संगठन बनाए और जनतान्त्रिक स्वतंत्रताओं के लिए संघर्ष किए तो इनसे सारे देश की जनता के ऐक्य की लड़ाई को बल मिला। संप्रदायवाद एक तरफ विशेषाधिकार और दूसरी तरफ अपगताओं पर फलता-फूलता है। जनतान्त्रिक स्वतंत्रता की प्राप्ति और समाज की पदानुक्रमित संरचना पर आधारित सामाजिक और आर्थिक असमानताओं के उन्मूलन से ही संप्रदायवाद समाप्त होगा और तब दो संप्रदायों के सदस्यों के बीच विभेद नहीं रह जाएगा। नया समाज सभी व्यक्तियों का प्रजातान्त्रिक सम्मिलन होगा और नई सामाजिक आर्थिक संरचना में उनकी वास्तविक भूमिका के आधार पर उनका नया वर्गीकरण होगा जो ऐतिहासिक दृष्टि से अधिक सगत होगा। संप्रदायवाद तभी खतम होगा, जब अधिकार विहीन सामाजिक दलों को भी प्रजातान्त्रिक अधिकार मिलेंगे।

लेकिन देश के संविधान में अपने विशिष्ट अधिकार के लिए संगठित होकर पंच चुनाव क्षेत्रों की मांग करना प्रतिक्रियावादी एवं राष्ट्र विरोधी कार्य है। पंच चुनाव क्षेत्रों से तो संप्रदायवाद को और अधिक बल मिलेगा और समाज के सांप्रदायिक विभाजन और अधिक स्थायी और दृढ़ होगा। अगर निम्न जाति के लोग यह मांग करते हैं कि उनकी प्रतिभा के विकास के रास्ते में समाज की पदानुक्रमित संरचना ने जाति विशेषता ला खड़ी की है उसे हटाया जाए तो यह एक सही जनतान्त्रिक मांग होगी और इस तरह लोगों की रचनात्मक प्रतिभा के विकास का रास्ता प्रशस्त होगा। अगर कोई जाति विशेषाधिकार मांगती है तो उसका काम गैर जनतान्त्रिक और राष्ट्र विरोधी होगा। दलित जाति के सदस्यों के अपने सम्मिलित नकारात्मक हित थे क्योंकि वे अपनी सामाजिक आर्थिक अपगताओं का समाप्त करना चाहते थे। लेकिन जब नई आर्थिक व्यवस्था की स्थापना के कारण प्रत्येक जाति का वेगान्त आधार छिन्न भिन्न हो गया और प्रत्येक जाति में विभिन्न पक्षों का मिलाप लग, जिनके अपने भिन्न, विरोधी भौतिक हित थे, तब उन सदस्यों का अपना कोई स्पष्ट सम्मिलित स्वार्थ सम्भव नहीं था।

ऐस ही, गैर ब्राह्मण जातियों का भी अपना कोई निश्चित स्वार्थ सम्भव नहीं था। ये जातियां बागीरों, बत मजदूरों, जमींदारों, मिल मजदूरों, बटाइयारों और अन्याय से बनी थीं। इन उपविभाजनों के स्वार्थ बिलकुल भिन्न थे। सभी-सभी एक ही जाति में विभिन्न पक्षों के कई दल थे। ब्राह्मण विरोधी आंदोलन अभी तक सही और प्रगतिशील था, जब तक उसने आर्थिक और सामाजिक अपगताओं का हटाने के लिए संघर्ष किया। विशिष्ट प्रतिनिधित्व का सम्मिलित स्वार्थों का दम भंगता था उसानी या शक्ति गैर ब्राह्मण समुदाय की विभिन्न जाति

अपने कोई सम्मिलित स्वाथ नहीं थे, इस समुदाय की जाति विशेष के सदस्यों के भी अपने सम्मिलित स्वाथ नहीं थे। वस्तुतः गैर ब्राह्मण मिल मालिकों के आर्थिक और राजनीतिक स्वाथ की पूर्ति मिल मालिकों के संगठन में शामिल होने से ही होती, और यह संगठन सब जातियाँ और संप्रदायों के मिल मालिकों का संगठन था। उसी तार पर, गैर ब्राह्मण मजदूरों के स्वार्थों की पूर्ति विभिन्न जातियाँ और संप्रदायों के मजदूरों के संगठन द्वारा ही संभव थी।

विशिष्ट प्रतिनिधित्व से तो सांप्रदायिक विभाजन बने रहें और बढ़ें, वैसे ही जैसे सामाजिक, यायिक और धार्मिक एक्य के लिए संगठित ब्राह्मणों के प्रजातान्त्रिक आंदोलनों से सांप्रदायिक विभाजनों के विनाश का रास्ता साफ हुआ। सुरक्षित प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है। अलबत्ता, यह नुकसानदेह है क्योंकि इससे जन्म पर आधारित विभेद बढ़ते ही जाएंगे। उन दशों में जहाँ राष्ट्र समुदाय एकता की भावना पर आधारित है विभिन्न स्वार्थों के प्रतिनिधित्व के लिए ऐसे किसी प्रतिनिधित्व का सिद्धांत माय नहीं है यद्यपि विरोधी स्वार्थों के रूप में उनका विभाजन संभव है। जाति की विभिन्नता की बात करते रहना और पृथक प्रतिनिधित्व की मांग स्वीकार कर लेना इसका अर्थ है सामुदायिक भावना के विकास की आधारभूत शक्त को ही नकार देना।<sup>19</sup>

जाति की भावना को समाप्त करने में राष्ट्रीय आंदोलन की भूमिका नगण्य नहीं है। यह सही है कि जाति का मूलधार अर्थात् जाति के भीतर ही शादी करना, ज्यों का त्यों बना रहा लेकिन आर्थिक राजनीतिक और धर्म निरपेक्ष सांस्कृतिक सहयोग और सहकर्मण बढ़ता गया। राष्ट्रीय आंदोलन को जनसाधारण का व्यापक आधार मिल चुका था और नरणीय जाति संघर्ष पर इसका असर पड़ा। फिर, राष्ट्रीय आंदोलन सिद्धांततः जनतान्त्रिक था और इसका कार्यक्रम दल और व्यक्तियों के समानाधिकार के सिद्धांत पर आधारित था। इसने जन्म पर आधारित असमानताओं की सुरक्षा प्रदान करने वाली पदानुक्रमित जाति प्रथा का वस्तुतः और पराक्षत विरोध किया। राष्ट्रीय आंदोलन न लागू हो एकजुट किया, जब कि जाति न उन्हें अलग-अलग कर रखा था। राष्ट्रीय आंदोलन ने व्यक्तिगत स्वातंत्र्य और आत्मनिर्णय के सिद्धांत का उसी तरह समर्थन किया जिन तरह राष्ट्रीय स्वातंत्र्य और आत्मनिर्णय के सिद्धांत का।

भारतीय जनता की अग्रगामी शक्तियाँ जाति निरक्षरता अज्ञानता की स्थिति और जो कुछ भी योग को पिछला बनाए हुए है, उन सबके विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व कर रही है। सनातन भारतीय सभ्यता और उसके अपरिवर्तनीय लक्षणों पर द्विधापूर्ण व्याख्यान दिए जा रहे हैं, और उधर बहुमन्यक लोगों द्वारा समर्थित राष्ट्रीय आंदोलन ने अपनी संघर्ष पंक्ति पर नारे लिख रखे हैं जाति, धर्म, संवस निरपेक्ष विश्वजनीन समतापरिवर्तन के सभी पदद्वियाँ और विशेषाधिकारों के उन्मूलन के, सावजनीन वयस्क मताधिकार और सावजनिक निःसुनक अनिवाय शिक्षा के धर्म के मामलों में राज्य की निष्पक्षता के,



वाक स्वतन्त्रता और प्रेस, विवेक, सगठन और सभा की स्वतन्त्रता के नारे जो ब्रिटेन के अर्द्ध प्रजातन्त्र की मायताओं से काफी आगे बढ़े हुए थे।<sup>०</sup>

महत्त्वपूर्ण देशी और विदेशी घटनाओं का भी लोगों के दिमाग पर प्रभाव पड़ा। उनसे जन जीवन आदोलित हुआ और लोगों के मन में यह इच्छा चलवती हुई कि वे पुरानी सस्थाओं और रहन सहन से आगे बढ़ें। 1914-18 की लड़ाई के बाद इस प्रक्रिया में और तेजी आई।

युद्ध विराम के 18 बरस बाद हम यह समझते हैं कि भारत का पुराना सतुलन, विश्व शक्तियों द्वारा अप्रभावित फिर कभी वापस नहीं जाएगा। ब्रिटिश राज की रूढ़िवादिता ने युग सम्मत बुराइयों को समर्थन प्रदान किया था। प्रजातन्त्र की परिवर्तनपरक भावना ने मत के लिए एक दूसरे की हाड में लगी हुई पार्टियाँ के माध्यम से काम किया, और मताधिकार के साथ शक्ति का एहसास हुआ। इन सबके कारण पुराने विशेषाधिकारों का अंत अवश्यभावी था, विशेषाधिकार जिन्हें बुद्धि बल और साहस का समर्थन प्राप्त नहीं था। जातिगत विशेषाधिकार के पक्षधर पीछे हट रहे हैं और लगता है अब उनमें नगदड मच जाएगी। अगर छुआछूत खतम होना हो तो जातिगत विभेद कैसे रह सकेगा? हिंदू धर्म की शक्ति न तो विधायिका सभाओं में है और न मंदिरों में, वरन् घर में अदर है। लेकिन घर में भी स्त्री शिक्षा के माध्यम से आधुनिकता की भावना तेजी से काम कर रही है। हिंदू सयुक्त परिवार जो जाति का मूलाधार है, स्त्री शिक्षा, आवागमन एवं यात्रा की सुविधा और विदेशों से मपक के कारण खडित हो रहा है।<sup>1</sup>

## भावी प्रवृत्तियाँ

मक्षेप में ऊपर चर्चित बहुत सारी वस्तुगत और भावगत शक्तियों का जाति व्यवस्था पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा। जाति का पशागत आधार खेत-रह कमजोर हो गया। नए समानांतर राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक नगठन बने जिन्होंने विभिन्न जातियों के सम्मिलित स्वाथ वाल लोगों को एक जुट किया। इन नगठनों और इस नई चेतना के जो नए रूप सामने आ रहे हैं उनका कारण जाति नगठना का महत्व कम हुआ और जाति भावना कमजोर हुई।

कानून के क्षेत्र में जाति के विशेषाधिकार लगभग समाप्त हो गए। पुराने तौर तरीक़ों, रहन-सहन आदि, और लोगों की जडता के कारण सामाजिक दाय में ये जीवित रहे। विजातीय लोग के साथ खान-पान मिलवक जाति के कानून अक्सर भंग हाते रहे और शहरों में व्यवहारत लगभग समाप्त हो गए। लेकिन सजातीय ब्याह जाति व्यवस्था का सबसे बड़ा आधार था और यह प्रथा ज्या की त्यो बनी रही, जाति के बाहर ग़ादी ब्याह अपवाद बना रहा।

फिर भी जाति के प्रगतिशील उन्मूलन की प्रवृत्ति जारी रही। व्यापक जाधिक विद्या शिक्षा के प्रसार, राष्ट्रीय और वागत जागतता के विचार एवं राजनीतिक

स्वतंत्रता और प्रगति के साथ-साथ जाति व्यवस्था के विनाश की प्रक्रिया अवश्य काफी तेज होगी। प्रकृति की तरह समाज में भी प्रगति और ह्रास समरूप गति से नहीं होता। युगों की संचित जाति विरोधी चेतना कभी न कभी तो व्यापक जाति विरोधी विद्रोह का रूप लेती ही, शादी ब्याह के मामला में भी। सजातीय ब्याह जाति प्रथा का जतिम मूल स्तम्भ है, और इसके समाप्त होते ही जाति का महल धराशायी हो जाएगा।

### संदर्भ

- 1 बख प० 23।
- 2 शलवकर प० 20।
- 3 घुर्गे प० 2।
- 4 वही प० 3।
- 5 देखें रिजली प० 298।
- 6 आ मेनी प० 374 75।
- 7 घुर्गे प० 27।
- 8 जो मेली प० 310।
- 9 वही।
- 10 मथाई प० 65।
- 11 नेडी विद्या गौरी नीलकण्ठ घुर्गे द्वारा उद्धृत प० 161।
- 12 इंडियन स्कूल रिफॉर्म खंड II प० 91।
- 13 देखें बख।
- 14 फिलासफी ऑफ ब्रह्माइज्म प० 330।
- 15 आर० पी० दत्त प० 60।
- 16 घुर्गे द्वारा उद्धृत प० 164।
- 17 वही प० 160।
- 18 जो मेली प० 373।
- 19 घुर्गे प० 169।
- 20 आर० पी० दत्त प० 500।
- 21 मेनचेस्टर गाजियन बीकली डिसेम्बर 1936।

## अस्पृश्यता के विरुद्ध धर्मयुद्ध

अस्पृश्यता हिंदू समाज का अमानुषिक विधान

प्राक ब्रिटिश काल के हिंदू समाज में कई बड़े क्रूर और अजनतात्रिक तत्व थे। कुछ हिंदुजा का जछूता के रूप में पृथक्करण अत्यंत अमानुषिक सामाजिक अत्याचार था। अछूता को मदिरा में जाने का या सावजनिक कुआँ और तालाबों के इस्तेमाल का अधिकार नहीं था और उनके स्पृश मात्र से ऊँची जातियों के लोग अपवित्र हो जाते थे। हिंदू समाज के जग होत हुए भी अछूत इस समाज से बहिष्कृत जैसे थे।

अस्पृश्यता आर्यों की भारत विजय का सामाजिक परिणाम है। सामाजिक वात व्यवहार के फलस्वरूप पराजित जाति के भी बहुत सारे लोग आर्यों के प्रभाव में आए। आर्यों की समाज व्यवस्था में समाविष्ट होने वालों में जो सबसे अधिक पिछड़े हुए या सबसे अधिक तिरस्कृत थे उन्हीं से अछूता की पुश्तैनी जाति का निर्माण हुआ।

हिंदू समाज में सदियों से अस्पृश्यता का प्रचलन रहा है। बुद्ध रामानुज, रामानंद, चैतन्य कबीर, नानक तुकाराम और अय सागा द्वारा चलाए गए व्यापक और आधारभूत मानवीय एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों का भी युगा की पुरानी इस अमानुषिक प्रथा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। परंपरा सम्मत, धर्मभूत यह प्रथा अपनी मजबूत बरत शक्ति के साथ सदियाँ तक जीवित रही।

विभिन्न राष्ट्राँ और विभिन्न युगों में कई प्रकार के पदानुक्रमित मानव समाजों का उद्भव हुआ है। ये समाज वषम्य और विशेषाधिकार की नींव पर बनते थे। लेकिन किसी भी अय समाज में हिंदू समाज जसा आत्यंतिक श्रेणीकरण और अधिचार वषम्य नहीं था। हिंदू समाज में अछूता के साथ जैसा हुआ, उसी शारीरिक पृथक्करण शायद ही किसी अय समाज में रहा है।<sup>1</sup> अछूत का स्पृश मात्र जघन्य पाप और जुगुप्सा का कारण था।

हिंदू समाज में हलखोर, मुर्दा जानवर हटाने वाला और दस तरह के अन्य जातियों के साथ पुश्तैनी अछूता के जिम्म हस्त थे।<sup>2</sup> विधि और समाज के अनुसार काद भी दूसरा पेशा बनने लिए वर्जित था। दुस्साह परिस्थिति के विरुद्ध विद्रोह

करने वाले अछूतों को सजा देने के लिए हिंदू राज्य ने बहुत तरह के कानून बनाए। उन्हें पठन-पाठन या मंदिर में प्रवेश का अधिकार नहीं था। गांव या शहर में उन्हें बस्ती से बाहर अलग इलाके में रहना पड़ता था। जिन सावजनिक कुओं और तालाबों का उपयोग ऊंची जातियों के हिंदू किया करते थे, उनके इस्तेमाल का अछूतों का कोई अधिकार नहीं था।<sup>3</sup> गांव की पंचायत, जिसमें अदिकाश कुलीन हिंदू ही होते थे, और हिंदू राज्य एक ही अपराध के लिए अछूतों को ऊंची जाति के हिंदुओं से अपेक्षाकृत अधिक कठोर दंड दिया करते थे। अछूतों का यह सामाजिक उत्पीड़न धर्मममत्त था और इसलिए इसकी जड़े बहुत गहरी थीं। किसी भी अन्य विधान में आदमी इतना अधिक अपमानित और दलित नहीं हुआ। इस व्यवस्था में मानव व्यक्तित्व और प्रतिष्ठा के साथ चरम अत्याचार हुआ।

अस्पृश्यता जैसे क्रूर सामाजिक तत्व का उन्मूलन भारत के सभी समाज सुधार आंदोलनों का प्रमुख लक्ष्य था और ऐसा हाना स्वभाविक ही था। समाज सुधारकों के विभिन्न दल विभिन्न कारणों से अस्पृश्यता निवारण की तरफ झुके, लेकिन इनकी आवश्यकता समाज में महसूस की। यह सच है कि भारतीय समाज में पोगोपयियों ने, जो बहुत बड़ी तादाद में थे अस्पृश्यता निवारण और दलित जातियों की अशक्तता के उन्मूलन का घोर विरोध किया। फिर भी, समाज इन विषयों को समाप्त करने की दिशा में ही अग्रसर हो रहा था।

### पददलित वर्गों की शक्ति

1931 के जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार सारे भारत में पददलित वर्गों की संख्या 50,192,000 थी। उत्तर प्रदेश में वे सारी जावादी के 23 प्रतिशत थे।<sup>4</sup> इस तरह सामाजिक तौर पर निकृष्ट वे बगैर सारी हिंदू जावादी के पांचवें भाग थे। इसलिए राष्ट्रीय आजादी और सामाजिक नवनिर्माण की किसी भी योजना में अछूतों द्वारा का बहुत बड़ा महत्व था।

पददलित जातियों में भी सामाजिक श्रेणियां थीं। सामाजिक अत्याय के शिकार इन वर्गों में भी सामाजिक तौर पर उच्चतर और निम्नतर जातियां थीं। इसलिए यह समस्या और कठिन एवं जटिल होती गई। अस्पृश्यता और सामाजिक अशक्तता के अत्यंत रूपों की व्यापकता के विषय में क्षत्रगत विभिन्नताएं भी थीं। फिर भी, पददलित जातियां उच्चकुलीन हिंदुओं से भिन्न थीं क्योंकि वे समान सामाजिक अत्याय से उत्पीड़ित थीं।<sup>5</sup>

अस्पृश्यता और दलित वर्गों की सामाजिक अयोग्यता के अत्यंत रूपों का उन्मूलन उन सारे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का लक्ष्य था जो ब्रिटेन के शासनकाल में उदित हुए।

### अछूतों की हालत में सुधार के आंदोलन

अस्पृश्यता जैसी अमानुषिक और अत्यायपूर्ण प्रथा के प्रति राग प्रबुद्ध और शक्ति

भारतीयों के सामान्य प्रजातांत्रिक रोप का ही एक रूप था।

ब्रह्म समाज, जाय समाज, समाज सुधार सम्मेलन, इंडियन नेशनल कांग्रेस जस राजनीतिक संगठन, गांधी द्वारा स्थापित अखिल भारतीय हरिजन मंच जैसी और राजनीतिक संस्थाएँ, इन सबने प्रचार, शिक्षा और अन्य व्यावहारिक उपायों द्वारा अछूता को सामाजिक धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकार दिलाने की चेष्टा की।

छुद दलित जातियों में एक नई चेतना, नए बोध का जागरण हो रहा था। शिक्षा के प्रसार से उनके बीच भी डा० अम्बेदकर जैसे विश्वजनों का दल तैयार हुआ। डा० अम्बेदकर ने उनकी तकलीफों के खिलाफ आवाज बुलंद की और उनके मूलभूत मानवीय अधिकारों के लिए जमकर मंथन किए। थाल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन और जाल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज फंडेशन इन जातियों के प्रमुख संगठन थे। दूसरे संगठन को डा० अम्बेदकर ने स्थापित किया और उन्होंने ही इसका नेतृत्व और पथ प्रदर्शन किया। इनके जलावा, दलित वर्गों में शुमार होने वाली जातियों के और भी अनेक स्थानीय और जातीय संगठन थे।

ये सारी संस्थाएँ विभिन्न तरीकों से दलित जातियों की अशक्तता समाप्त करने के प्रयास में लगी हुई थीं। मदिरा और मावजनिक पाठशालाओं में प्रवेश और सावजनिक कुआरों का उपयोग पर प्रतिबंध तथा निवास स्थान का प्राथक्य अछूतों की अशक्तता के ये कुछ प्रमुख रूप थे। इन अशक्तताओं के विरुद्ध लड़ने के अतिरिक्त डा० अम्बेदकर ने दलित जातियों को राजनीतिक सेना के रूप में भी परिणत करने का प्रयास किया। उनके राजनीतिक दावे डा० अम्बेदकर की कालत के कारण, मान भी लिए गए और इनके लिए 1935 के विधान में विशेष प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। या दलित जातियों की विशेष प्रतिनिधित्व की मांग राष्ट्र विरोधी थी और उससे राष्ट्रीय एकात्मता कमजोर होती थी, फिर भी यह मांग इन जातियों के राजनीतिक जागरण की परिचायक थी।

जाय समाज, ब्रह्म समाज और अन्य धार्मिक सुधारवादी आंदोलनों का उद्देश्य था कि बौद्धिक आधार पर भारतीय समाज का नवनिर्माण किया जाय। इनके नेताओं ने हिंदू सामाजिक व्यवस्था के प्रजातंत्रिकरण की दिशा में प्रयास किए। उन्होंने उन घोर सामाजिक अनीतियों के विरुद्ध मंथन किया जिनसे दलित वर्गों के हिंदू पीड़ित थे और हिंदू शास्त्रों की ही नई व्याख्या के आधार पर परंपरागत अनीतियों के उन्मूलन का उपदेश दिया।

और धार्मिक सामाजिक सुधारवादी आंदोलनों ने, अपने पक्ष में वेदा का निष्पक्ष उपलब्ध करवाने की चेष्टा किए बगैर, व्यक्तिगत स्वतंत्र्य और मानवीय अधिकारों की समानता के नाम पर, अस्पृश्यता और अन्य सामाजिक कुरीतियों अनीतियों को भंगाने की।

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के माधव, गांधी, आदि जस उदारवादी और उनका साथ कामरुधी राबनीतिज्ञान यह तक भी उपस्थित किया कि ब्रिटिश

सरकार से स्वाधीनता या स्वराज्य की उनकी मांग प्रजातांत्रिक है, इसलिए भारतीयों को अपने सामाजिक जीवन में प्रजातन्त्र के आदर्श का अनुकरण करना चाहिए, समुदायो जातियों और व्यक्तियों के पारम्परिक संबंधों का साम्य, स्वातंत्र्य और मानव के अधिकारों जैसे प्रजातांत्रिक सिद्धांतों की बुनियाद पर नवनिर्माण करना चाहिए।

फिर, राष्ट्रीय स्वातंत्र्य राष्ट्रीय एकता और संयुक्त राष्ट्रीय शक्ति का ही प्रतिफल है। राष्ट्रीय एकता और ताकत की यह मांग थी कि सब आत्मविकास के लिए स्वतंत्र हों और सबके लिए आत्मविकास के समान साधन और अधिकार हों। जस्पृश्यता निवारण और लाखा करोड़ों दलित लोगों की अशक्तता के उन्मूलन से राष्ट्रीय एकता और शक्ति दोनों का तेजी से विकास होता है।

सावरकर जैसे जो हिंदू 'हिंदू राज' की मांग करते थे, उन्होंने भी दलित जातियों की स्थिति में सुधार की चेष्टा की। इसकी वजह यह थी कि अछूत लगातार धर्म परिवर्तन कर इस्लाम या इमाई धर्म में शामिल हो रहे थे (क्योंकि उन्हें वहां अधिक सामाजिक साम्य प्राप्त था) जिसके कारण हिंदू धर्म को मानने वालों की संख्या घटती जा रही थी और हिंदू राज की मांग करनेवालों के लिए यह बहुत बड़ा संकट था।

इस तरह दलित जातियों के उद्धार का आंदोलन लगातार बढ़ता गया और उसमें तेजी आती गई। इस आंदोलन के उद्देश्य थे दलित जातियों की दयनीय आर्थिक स्थिति को सुधारना उन्हें शिक्षित करना उन्हें कुओं पाठशालाओं और सड़कों के उपयोग और मंदिर में प्रवेश की स्वतंत्रता प्रदान कराना, और उनके लिए विशेष राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अधिकार हासिल करना। जल प्राप्ति के समानाधिकार के लिए डा० अम्बेडकर के नेतृत्व में चलाया गया महान सत्याग्रह हरिजनों के लिए समान सामाजिक हक्क हासिल करने के लिए लड़ा गया महान संघर्ष था। यह प्रक्रिया अवश्य बड़ी धीमी थी। दलित जातियाँ भारतीय समाज की सबसे गरीब श्रेणी की थीं। उनके बीच साक्षर लोग भी बहुत कम थे।

गांधी और उनके द्वारा 1932 में स्थापित आल इंडिया हरिजन संघ संघ और अन्य संस्थाएँ भी दलित जातियों के लिए व्यापक समाज सुधार संघर्षों और शैक्षिक कार्य कर रही थीं। संघ ने हरिजनों के लिए बहुत सारी पाठशालाएँ शुरू कीं, जिनमें कुछ आवासीय व्यावसायिक पाठशालाएँ भी थीं। इसके अतिरिक्त हलखोरा की मूनीयने सहकारिता ऋण समितियाँ, जावाम संघी समितियाँ आदि भी निर्मित हुईं।<sup>9</sup>

1937 के बाद कुछ वर्षों तक विभिन्न प्रांतों में जो कांग्रेस की सरकारें बनाई जाने लीं दलित जातियों के उद्धार के लिए काफी अच्छे काम किए। बंबई की कांग्रेसी सरकार ने सारे हरिजन टेंपल वर्ग (रिभूतन आफ डिजेविलिटीज) एकट पारित किया, जिसमें मंदिरों के व्यवस्थापकों को यह अधिकार मिला कि व्यवस्थापन की शर्तों के बावजूद अगर वे चाहें तो हरिजनों को मंदिरों में आने दे

सकत है। सी० पी० जी० बिहार की कांग्रेसी सरकारों ने अपने प्राता म हरिजनो क लिए, प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय तक, नि शुल्क शिक्षा का प्रवध किया। कांग्रेस गणित अय प्रदेशा म भी कुछ इसी तरह की व्यवस्था हुई।

हरिजनो ने कुछ सत्याग्रह आंदोलन भी किए जिनम उन्होंने मंदिर प्रवेश पर जो प्रतिवध था उसका विरोध किया, और मंदिरा म जाने का प्रयास किया। इन आंदोलना जीर दलित जातियो की प्रजातांत्रिक मागो के प्रति लोगो की सहानुभूति के कारण कई जगहो म हरिजनो का मंदिर म प्रवेश का अधिकार मिला भी।

त्रावनकोर, इंदौर, देवास जैसे कुछ देशी राज्या के शासको ने जाग बढकर राजकीय फरमान द्वारा राज्य के मंदिरा के सारे दरवाजे हरिजना के लिए खुलवा दिए।

ब्रिटेन की तटस्थता की नीति, और उसकी आलोचना

हिंदुस्तान के राष्ट्रवादिया का कहना था कि ब्रिटिश सरकार दलित वर्ग के अधिकारो को वापस दिलान के लिए जमकर जोश व साथ कुछ नहीं कर रही थी, और न अछूतो के मूलभूत मानवीय अधिकारो के अप्रजातांत्रिक हनन को समाप्त करन के लिए ही अपनी शक्ति का प्रयोग कर रही थी। डा० अम्बेदकर पूरी तरह अंग्रेजी सरकारके विरुद्ध नहीं थे लेकिन उन्होंने भी अछूतो को संबोधित करते हुए कहा

अंग्रेजा क आने के पहले आपकी स्थिति बड़ी दयनीय थी। लेकिन अस्पृश्यता निवारण व लिए अंग्रेजी सरकार न ही क्या किया है? अंग्रेजा के जाने के पहले आप गांव क कुआ से पानी नहीं पीच सकत थे। क्या अंग्रेजी सरकार न आपका यह अधिकार दिला दिया है? अंग्रेजा क आने के पहले आप मंदिरा म नहीं जा सकत थे। अब क्या आप वहा प्रवेश कर सकत हैं? अंग्रेजा क आने के पहले आप पुलिस म भर्ती नहीं हो सकत थे। क्या अंग्रेजी सरकार आपको पुलिस म भर्ती कर रही है?

डा० अम्बेदकर का विचार था कि जब तक भारतीय जनता राजनीतिक सत्ता हस्तगत नहीं कर लेती और अगर यह सत्ता भारतीय समाज के सामाजिक तौर पर प्रपीडित वर्ग के हाथो म नहीं आती, तो इस वर्ग की सामाजिक कानूनी और सांस्कृतिक अमान्यताओ को पूरी तरह खतम नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा

दूसरा यह आपकी गिनायतो को उतनी अच्छी तरह से दूर नहीं कर सकता जितनी अच्छी तरह से आप खुद उन्हें दूर कर सकत हैं। और आप उन्हें दूर नहीं कर सकत अगर राजनीतिक सत्ता आपके हाथो म नहीं है। हम एंगो सरकार चाहिए जो सामाजिक और धार्मिक जीवन महिता का उचित और व्यापक गणधन करन से त डर। ब्रिटिश सरकार तथापि यह नुस्खिया नहीं जदा कर पांगी। जनता की जनता क लिए, जनता द्वारा गणित सरकार जर्घत स्वराज्य की सरकार ही इस तरह का काम कर सकगी।\*

सामाजिक और धार्मिक मामला म अंग्रेजा की तटस्थता की नीति का

वास्तविक परिणाम यह हुआ कि प्रतिगामी और दमनात्मक सामाजिक प्रथाएँ और सस्थाएँ बनी रही। उद्धृत अंश इस बात के लिए अंग्रेजी शासन तीव्र आलोचना करता है। यह ठीक है कि हिंदू रूढ़िवादिता ने सारे प्रगतिशील सामाजिक कार्यों का विरोध किया लेकिन, भारतीय राष्ट्रवाद और दलित वर्गों के प्रतिनिधियों ने कहा कि सामाजिक अनीतियाँ एवं विषमताओं को खतम करने का अपना राजकीय कर्तव्य ब्रिटिश सरकार को नहीं छोड़ना चाहिए था। अंग्रेजी सरकार ने सामाजिक मामला में भी हस्तक्षेप किया, और सती प्रथा के उन्मूलन एवं छूत और अछूत सती प्रकार के नागरिकों का यायिक समता प्रदान करने जैसे सुधार किये। फिर भी, जिस गति से ये सुधार किये जा रहे थे वह गति बड़ी धीमी थी, और इससे पता चलता है कि किस तरह प्रतिक्रियावादी सामाजिक तत्वों की भावनाओं का सरकार खयाल करती थी।

भारत में प्रचलित पुरानी प्रतिगामी और मरणशील सामाजिक सस्थाओं और प्रथाओं के प्रति अंग्रेजी सरकार की सहिष्णुता की एच० एन० ब्रेल्सफोर्ड जैसे प्रगतिशील अंग्रेजों ने भी ऐसी ही नटुआलोचना की। सबजेक्ट इंडिया नामक अपनी किताब में ब्रेल्सफोर्ड ने कहा

फिर भी हमारी सरकारी नीति पहले भी यह थी, और अब भी है कि भारतीय सस्थाओं में यथामानव कम से कम दखल दिया जाए। बाल विवाह जैसी स्वास्थ्य के लिए अहितकर सामाजिक रीतियों का विरोध नहीं किया गया। सरकार का भारतीय पर्यावरण का बदलने की हिम्मत नहीं थी और छुआछूत को भी इस पर्यावरण का अपरिवर्तनीय सत्य मान लिया गया। जैसे जैसे समय गुजरता गया, हमारे यायालय मानो पुरातनिक निष्ठा से हिंदू ला नानू करने लगे। इस मनावृत्ति का परिणाम हुआ कि जिसे देश में अतीत का पूरी तरह परित्याग नहीं हुआ है वहाँ यह अतीत रुढ़िवाद होता गया।<sup>9</sup>

अंग्रेजी शासन काल में भारतीय जनता का जो साधारण राष्ट्रीय एव प्रजातान्त्रिक नवजागरण हुआ, उसी का एक अंग था दलित वर्गों का प्रजातांत्रिक नवजागरण और अपने मूलभूत मानवीय अधिकारों का बख्ता हुआ एहसास। उस युग में सारे भारत में एक नए जायिक और राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना हुई। इस व्यवस्था का मंडातिक आधार यह था कि समाज के सारे व्यक्ति समान इरादे हैं और कानून की दृष्टि में वे सब बराबर हैं। इन सिद्धांतों से उत्तराधिकार और सामाजिक पद प्रतिष्ठा के सिद्धांतों पर आधारित प्राकृषीमादी मध्ययुगीन भारतीय समाज पर पड़ी गहरी चोट पड़ी। हर व्यक्ति के अधिकार समान हैं और हर व्यक्ति जो पशा चाह सकता है। नई व्यवस्था में कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति बराबर है। इसके कारण सामाजिक रूप से पददलित जातियों में अपनी स्वतंत्रता पर लग हुए सदियाँ पुराने मित्रता का तात्कॉर्न की तात्कॉर्न जासाधा जाग्रत हुई। दलित जातियों के विद्रोहात्मक मद्यों और उच्च जातियों के मानवीय व्यवहार, इही ने भारत के समाज सुधार जागृतन नन व।



## नई आर्थिक शक्तियों का प्रभाव

बहुत सारे वस्तुनिष्ठ कारण थे जिनके चलते धीरे धीरे जनमानस ही सामाजिक विषमता और विभेद कम हुए। रेलवे और बसा के कारण छूत और अछूत दोनों तर्जों से एक दूसरे के करीब आए। भारत में जिन नए उद्योगों की स्थापना हुई, उनमें निरपेक्ष तौर पर छूत और अछूत दोनों प्रकार के लोगों की बहाली हुई और ये एक दूसरे के अगल-बगल खड़े होकर मशीनों पर काम करते थे। हड़तालों में छूत और अछूत दोनों प्रकार के मजदूर एक साथ मिलकर अपनी बड़ाई लड़ते थे। इस तरह उनमें नई बग चेतना का उदय हुआ जिसमें पुरानी जाति भावना का स्थान लिया। शहरों के जलपान गृहों में भी जातिगत भाव प्रश्रित्य खतम हुई। इन जलपान गृहों के मालिकों को यह बड़ा मालूम था कि वे जातिगत विषमता और विभेद का समाप्त करने के जादालन में ही लगे हुए हैं।

## आधुनिक शिक्षा का प्रभाव

दलित जातियों में शिक्षा के प्रसार के कारण इन जातियों के लोग अधिकाधिक उन पेशा में जाने लगे जिन पर अभी तक ऊँची जातियों का एकाधिकार था। एक ही बंधे के लोगों के अपने सम्मिलित साथ में और जब पुरानी पूजाग्रह धीरे धीरे खतम हुए तो अपने समष्टिगत हितों की पूर्ति के लिए ये लोग परस्पर एकजुट हुए, चाहे वे दलित जातियों के रहे हों या ऊँची जातियों के।

आधुनिक शिक्षा के प्रसार से भारतीय पश्चिम के प्रजातांत्रिक और समतावादी सिद्धांतों के संपर्क में आए। इनके फलस्वरूप ऊँची जातियों के अछूत लोगों को भारतीय समाज की पुरानी जातिगत विषमताओं और अन्यायों से नफरत होने लगी। इसके साथ ही दलित जातियों के शिक्षित सदस्यों में विद्रोह की भावना जगी तथा उनका सामाजिक प्रपीड़न को समाप्त करने के लिए लोगों का गालबंद किया।

अछूत निम्न पेशे ही अपनाते थे, क्योंकि उनमें शिक्षा का अभाव था। इसके चलते आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों से वे काफी निधन थे। जम-जम उन्हें साधारण और तकनीकी शिक्षा मिलती गई जैसे-जैसे उनकी आर्थिक स्थिति में तरक्की हुई और विभिन्न पेशा में लगे हुए लोग बग-बग आधार पर बस ही पेशा में लगे हुए अन्य जातियों के लोगों के साथ समानता में हान लगे। इस तरह समानता और समान बग पर आधारित नए किस्म के एकरा तंत्र निर्मित हुए। अछूतों का जनसाधारण विभिन्न नए सामाजिक दल में परिणत होने लगा, जिनमें मजदूर, शिक्षक, किराँती, महाजन (आपारी), मस्त्री, उद्योगपति, एक या अधिक विधाकृताप में लगे हुए अछूत और अछूतों के बीच जाने आर्थिक तंत्र में, उनमें चलते अस्पृश्यता निषेध पुरानी भाव प्रश्रित्य काफी कमजोर हुई। यह प्रवृत्ति विज्ञान-आधुनिक धर्मों में परिणत हुई जहाँ समानता और समानता के लिए लड़े गए सपनों के आधार पर अछूत और अछूतों के बीच एकरा

के भाव पैदा हुए और बढ़े। धीरे-धीरे नई बग भावना पुरानी जातिगत पूर्वाग्रहों का स्थान लेने लगी। फिर, जब कोई जड़ूत शिक्षित हो जाता था और उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती थी तो उसके प्रति ऊँची जाति के लोगों की भावना बदल जाती थी।

अस्पृश्यता के जादूरे जायिक थे। अछूतों की पेशागत एकरूपता समाप्त हो जान पर और उनकी भौतिक और सांस्कृतिक स्थिति में सुधार होने पर, व आधुनिक जायिक मरचना के विभिन्न अवयवों के रूप में परिणत हुए होंगे। इससे अस्पृश्यता की नींव काफी कमजोर होगी।

### राष्ट्रीय आंदोलन के प्रभाव

अस्पृश्यता निवारण आंदोलन के पक्ष में एक और शक्ति काम कर रही थी। बढ़त हुए राष्ट्रीय आंदोलन ने राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए हर जाति या समुदाय के लोगों का एकजुट करने का प्रयास किया। स्वराज्य आंदोलन की सफलता उन सारी जातियों एवं समुदायों के प्रजातांत्रिक सहयोग पर निर्भर थी, जिनके हितों की रक्षा भारत की राजनीतिक आजादी से होने वाली थी। यह एकता मूलतः आजादी की लड़ाई के दरम्यान और उस सिलसिले में बनी थी। इस तरह राष्ट्रीय आंदोलन ने धीरे-धीरे ही मही लेकिन पुराने विभेद समाप्त होने लगे। दूसरी ओर अस्पृश्यता जमी सामाजिक अनीतियों की समाप्ति को अपना लक्ष्य बनाने वाले समाज सुधार आंदोलनों ने भी प्रजातांत्रिक आधार पर भारतीय जनता को एकजुट करने में मदद दी। इन तरह शुद्ध सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध मध्य करने बकने भी समाज सुधारक मानवीय एवं राष्ट्रीय दाना प्रकार के उद्देश्यों से अनुप्रेरित थे।

अछूत लोग भारतीय आजादी के सर्वांगिक निधन जग थे। बरतन मादूरी करत ने निम्नतम पेशा में लगने जयवा जद्व दास की स्थिति में थे। व जायिक और सामाजिक दाना तरह की बुराइयाँ में पीलिये और ये दाना प्रकार की बुराइयाँ परस्पर मधुद्ध थी। उनकी निम्न सामाजिक स्थिति के कारण उनकी निम्न सामाजिक स्थिति में दुहता आइ।

### अस्पृश्यता निवारण के लिए आवश्यक शर्तें

राष्ट्रीय जयतन की समृद्धि, जायिक एवं सामाजिक तयवा में एम परिवर्तन आ अछूतों के साथ ही माय सबमा-करण की स्थिति में भी सुधार कर तय शिक्षा का प्रचार, नए कानून जो पुरानी दृष्टियाँ का उपालयिण बिना अछूतों की सारी सामाजिक अशक्तताओं का समाप्त कर दे अस्पृश्यता निवारण का प्रयास इन तयवा जाता से जुड़ा हुआ था। जयन जाय में शुद्ध समाज के कुछ विशेष प्रभाव तय तयवा लाल थे। यह साधारणतः सामाजिक बुराइयों की जायिक जयन तयवा पढ़न पाता

या ! इसीसे इसके परिणाम प्रायः जाशिक्र जोर अस्वाइं ये ।

अस्पृश्यता निवारण आदोलन को धीरे धीरे काफी बल मिला, लेकिन यह भारतीय मानस में बहत्तर राष्ट्रीय एव मानवीय चेतना के उदभव का ही एरु रूप था । यह भारतीय जनता के राष्ट्रीय एव प्रजातान्त्रिक आदोलन का अनियाय अग था ।

## सदम

- 1 घयें प० 142 ।
- 2 रामश्वरी नेहरू प० 4 ।
- 3 वही प० 3 ।
- 4 वही प० 2 ।
- 5 दयें अम्बदकर (2) और (3) ।
- 6 दयें रिपोट आफ द सर्वे ऑ क्नीशस आफ हरिजन इन इन्डिया रिपाट जान हरिजन सर्वे कमटी 1933 34 कानपुर रिपाट जान ऑ कडाशम आफ हरिजन रिन्नी ।
- 7 रिपोट आफ द बलिगशन सेंट टु इडिया वाइ व इडिया लाग इन 1932 प० 136 में उद्धत ।
- 8 वही प० 137 ।
- 9 ब्रत्मपाड प० 17 18 ।

## स्त्री स्वातंत्र्य का आंदोलन

### प्राक् ब्रिटिश भारत में नारी की स्थिति

नए आर्थिक परिवारण व उदभव नई राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना, आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा पद्धति और चिंतन शक्तियों के प्रसार आदि के फलस्वरूप भारत में जो साधारण राष्ट्रीय और प्रजातांत्रिक जागरण हुआ उसी की एक अभिव्यक्ति यह भी थी कि जिस मध्ययुगीन सामाजिक अधीनस्थता और प्रपीडन से भारतीय नारी सदियों से ग्रस्त थी उससे उसकी मुक्ति के आंदोलन शुरू हुए।

प्राक् ब्रिटिश भारत में जबतक वैदिक युग व शुरु के काल को छोड़कर, ह्रदय नारी पुरुष की अधीनता में रहती जाइ थी। धर्म और विधि में पुरुष और स्त्रियों और उनके अधिकारों का समान नहीं माना गया था। समाज में पुरुष का कुछ ऐसे अधिकार थे, उनकी कुछ ऐसी स्वतंत्रता थी, जिनसे स्त्रियां वंचित थी। स्त्री और पुरुष के निजी और सामाजिक आचरण की अच्छाई बुराई का मानदंड भिन्न था।

प्रागतिहासिक कबीलाई समाज का छोड़कर सभी प्राचीन और मध्ययुगीन समाजों की तरह भारत में भी अंग्रेजों की भारत विजय के पूर्व, स्त्री पुरुष का अधीन थी। अंग्रेजों के आगमन पर जब भारत में नए अर्थ और नई विधि व्यवस्था की स्थापना हुई और जब भारत पश्चिम की दशा की आधुनिक प्रजातांत्रिक विचार शक्तियों का मफल म जाया, तो स्थिति अवश्य कुछ बदली।

अतीत में भी बौद्ध धर्म जैसे मुद्धार व आंदोलनों ने स्त्री की स्थिति में मुद्धार लाने के कुछ प्रयास किए थे। लेकिन स्त्री के प्रति महिला से जा सामाजिक और कानूनी अत्याय हात रहे थे उनका निवारण के लिए आवश्यक आंदोलन अंग्रेजी शासन काल में ही चल सके।

यह सही है कि भारतीय इतिहास में गार्गी बाद वाली नूरजहां, रजिया मगम, शाही की रानी, मीराबाई और जहल्लाबाई जंगी औरत हा चुकी हैं जिहां साहित्य, कला, दर्शन, प्रशासन और यहाँ तक कि रणनीति व धर्म में भी उच्च महत्त्व दिए। लेकिन ये औरत समाज की शासन अधिकार प्राप्त शक्तियों की

उपज थी, और इसलिए सामाजिक अधीनस्थता की उस स्थिति से मुक्त थी जिसमें अधिकांश भारतीय औरतें रहती थी और जहाँ उन्हें आत्माभिव्यक्ति के लिए न तो स्वतंत्रता थी और न उपयुक्त अवसर।

### नारी की स्थिति पर नई आर्थिक शक्तियाँ का प्रभाव

अंग्रेजों की भारत विजय ने भारत का संपूर्ण सामाजिक परिवेश बदल दिया। इससे ऐसे वस्तुनिष्ठ एवं भावनिष्ठ तथ्यों का जन्म हुआ जिन्होंने लोगों में प्रजातांत्रिक भावनाओं का उदय कराया। सामाजिक अस्तित्व की स्थिति में जो समाज सुधार आंदोलन उदभूत हुए उनका एक लक्ष्य यह भी था कि भारतीय नारी जिन सामाजिक और धार्मिक विषमताओं एवं अन्यायों की शिकार है, उन्हें दूर किया जाए।

प्राकृतिक भारतीय नारी की दासता उन दिनों की सामाजिक आर्थिक संरचना में निहित थी। उस वक्त समाज में व्यक्ति की स्थिति उसके जन्म द्वारा निर्धारित होती थी और नारी की नारी असक्तता का मूल यह था कि उसका जन्म ही नारी के रूप में हुआ था। धार्मिक विधान स्त्रियों की निरंकुश स्थिति का पवित्र भी बना जाता रहने से।

भारत में अंग्रेजों ने पूजापादी अधिव्यवस्था और नई सामाजिक धार्मिक संरचना कायम की, वह व्यक्ति की समानता और स्वतंत्रता पर आधारित थी। इनमें जन्म, यानि जाति संप्रदाय मूलक विषमताओं के लिए जगह नहीं थी।

जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में इन सिद्धांतों की मायना के लिए मध्यम करने पड़े। अंग्रेजी सरकार की शक्ति और समाज के पागलपणियों के प्रति क्रियात्मक प्रतिरोध का कुछ हद तक प्रयत्न करने के बाद ही नागरिक अधिकारों के क्षेत्र में स्त्री पुरुष का अधिकाधिक बराबरी का दर्जा दे सकने वाले कानून बन सके।

### स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए किए गए आंदोलन

स्त्रियों को बराबर रखने वाले कानूनों और रीति रिवाजों का प्रयत्न करने का प्रारम्भिक प्रयास पुरुष जाति के ही प्रयुक्त समस्या के लिए। तब तक इन अन्यायों की शिकार थी, ये भी कालक्रम से स्वयं उद्भूत हुए और उन्होंने अपने स्वयं के नास्त्य में अपनी मुक्ति का आन्दोलन चलाए। उन्होंने अपने मंगल बनाए और अपनी असक्तताओं के विरुद्ध मध्यम के लिए मार्गदर्शनी की। उनमें सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक उत्थान के लिए काम करने वाले मंगलनाम 1926 में स्थापित जाल इंडिया वीमन काँग्रेस बनने जागे थे।

भारतीय औरतों की असक्तता का उन्मूलन का विभिन्न प्रांतों में उत्थान के मुक्ति की प्रक्रिया कायापत्ती थी। पुराणों में भारत और पुराना सामाजिक और न्यायव्यवस्था विचारधाराएँ इन सिद्ध थीं। फिर भी, इन

दिशा में लगातार प्रगति होती रही और अनेक विशिष्ट सफलताएँ भी प्राप्त हुई।

एक जमाने में भारतीय नारी सती और बालहत्या जैसी बुराई, क्रूर प्रथाओं की शिकार थी। पति के मरने पर विधवा को पति की लाश के साथ चिता पर जल मरना होता था। गरीबों में दूध पीने के लिए लड़की की गादी काफी महंगी थी, इसलिए मानव प्रायः नवजात बच्चियाँ की हत्या कर देते थे। सती प्रथा के उन्मूलन के बाद भी विधवाओं का पुनर्विवाह की सुविधा नहीं मिली।

पदा प्रथा और मदिरा में वेश्यावृत्ति जैसी बुराईयाँ भी प्रचलित थीं। मुसलमानों में ही नहीं हिंदुओं के कुछ वर्गों में भी पर्दा जैसी घातक और हानिकारक प्रथा प्रचलित थी। औरतें मानो जिदभी भर के लिए कद में डाल दी गईं हैं। उसकी स्वभावतः तीव्र ज्ञानेन्द्रियाँ निष्क्रियता के कारण सुस्त पड़ जाती हैं, उन तक ज्ञान का प्रकाश नहीं पहुँच पाता और वे अज्ञान एवं पूर्वाग्रह में पड़ी रहती हैं, जधे में रास्ता टटोलती समाज के रीति रिवाज के नाम पर उत्सग।<sup>11</sup>

प्रचारात्मक काय द्वारा राजा राममोहन राय जैसे समाज सुधारकों ने सती प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया और जतन में लॉर्ड वेस्टमिंघम ने इस समाप्त कर दिया। बाद में बालहत्या का भी अपराध करार दिया गया।

लोगों में शिक्षा एवं उदारवादी और बुद्धिवादी विचारों के प्रसरण से पर्दा प्रथा भी मिटने लगी। भोपाल की रंगमा जैसी उच्चकुलीन औरतों ने इस दिशा में मार्ग प्रदर्शन किया। औरतों के जादोलना में इस बात पर जोर दिया गया कि पर्दा का सामाजिक प्रगति एवं शरीर और मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। 'सामाजिक जीवन के उत्थान में अगर औरतों का अपनी भूमिका जदा करनी है अगर उनके लिए यह जानना जरूरी है कि किन कतब्याँ एवं उत्तरदायित्वों के लिए उनके लड़कों को प्रशिक्षित होना है तो पर्दा प्रथा को खतम होना चाहिए।'

बाल विवाह भी हिंदू समाज की एक प्रमुख बुराई थी और इससे पुम्पा की अपक्षा स्त्रियों का अधिक नुकसान था। ईश्वरचन्द्र विद्यासागर के प्रयत्नों के फलस्वरूप 1960 का एक्ट पारित हुआ जिसके अनुसार विवाहित और अविवाहित लड़कियों के लिए महामति की उम्र बढ़ाकर दस वर्ष कर दी गई। इसी समाज सुधारक के प्रयत्नों के फलस्वरूप 1850 में विधवा विवाह कानून में मान्य हुआ।

बाल विवाह के इस हानिकारक रिवाज के विरुद्ध निर्गमिण भदम 1929 में उठाया गया। इस साल पारित किए गए 'साइलेंट मरिज रिस्ट्रेंट एक्ट' में विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाकर लड़कियों के लिए चौदह वर्ष और लड़कों के लिए अठारह वर्ष कर दी गई।

बंगाल में ईश्वरचन्द्र विद्यासागर तथा पश्चिम में श्रीमान्नावरी, कनिनमण्डल जस्टिस रानाड और क० नटराजन जैसे समाज सुधारकों ने विधवा विवाह के अधिकार का जमाने समर्थन किया। समाज सुधारकों ने भी पाठना में अपना

वायक्रम में विधवा विवाह का प्रमुख स्थान दिया, लेकिन यह आंदोलन बहुत प्रगति नहीं कर सका क्योंकि जनमत दुरी तरह विधवा विवाह के विरुद्ध था। वानुनी स्वावटो के समाप्त हो जाने पर भी, पुरानी चिंतन शली में अंतर नहीं आया।

मदिरा में वश्यावृत्ति की प्रथा नए भारत का अतीत से विरासत में मिली थी, यद्यपि इस तरह की प्रथा प्राचीन यूनान में भी प्रचलित थी। दबदासिया की वशागत जाति ही थी और यद्यपि वे ही मंदिर की सेवा में समर्पित हो जाती थीं। 'हाल में मद्रास में उनकी संख्या लगभग दो लाख रही होगी, और यद्यपि इनकी सर्गीत और नृत्य कुशलता का कारण यह बलाएँ जीवित बनी रहीं, फिर भी इस तथ्य का कारण कि ये दबदासिया वेश्याएँ थीं, सम्माननीय कुलीन औरतों के लिए ये बलाएँ निवृष्ट और अप्रिय अरुचिकर थीं।<sup>3</sup>

डा० मुतुलक्ष्मी रेडडी और अन्य सुधारकों के सतत प्रयत्न के फलस्वरूप, 1925 में एक एक्ट पारित हुआ और दंड संहिता की कुछ धाराएँ जिनके अनुसार नाबालिग लड़कियाँ का अवध जनतिक व्यापार दंडनीय हैं, दबदासिया पर भी लागू हुईं।

### शिक्षा के अधिकार के लिए संघर्ष

कुछ अपवादों का छोड़कर प्रायः ब्रिटिश भारत में स्त्रियों को प्रायः शिक्षा नहीं मिलती थी। मध्ययुगीन विचार प्रणाली में स्त्रियों का केवल गृहस्थ की जिम्मेवारी दी गई थी। लड़कों के लिए गाँवों और शहरों में स्कूल होते थे लेकिन स्त्रियों के लिए कहीं शिक्षा का प्रबंध नहीं था।

पुराने समाज के विनाश और नए समाज के उदय के साथ ही भारत में एक नए जीवन दान का जन्म हुआ। इच्छा स्वतन्त्र्यवादी मित्रता ने तभी से सत्तावादी सिद्धांतों का स्थान ग्रहण किया। इन सिद्धांतों के अनुसार लिंग, जाति, प्रजाति, धर्म आदि विभेदों का धारण न कर हर व्यक्ति के समान अधिकार और सबका एक ही स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए। ब्रिटिश शासन के डढ़ मोड़ों में भारतीय जनता के प्रतिरोध के लगातार राजनीति, धर्म, शिक्षा और समाज के क्षेत्र में नए प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के व्यावहारिक परिणामों के प्रयास करने लगे हैं। इन्होंने सिद्धांतों के नाम पर स्वराज्य की मांग की गई। जातिगत विभेद और विषमता के उन्मूलन की रात की गई। वर्मानुगत पुंगहिता के एकाधिकार पर आपात किए गए और जातिगत, राजनीतिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक क्षेत्रों में स्त्री पुंग के समानाधिकार की घोषणा की गई।

सामाजिक अस्तित्व के प्रत्यक्ष क्षेत्र में प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के कार्यान्वयन के आगमन के साथ ही सत्ता पर हाँ नहीं, बल्कि प्रायः ब्रिटिश भारत का नए प्रजातांत्रिक विरासत पर हाँ पड़ेगी। उद्देश्य जातिगत विभेद निवृत्त निवृत्त न अधीन अधीन का आचार निर्दिष्ट, और पुरुषों के प्रायः

स्त्री को वंचित रखने की प्रथा का विरोध किया।

यह प्रायः सबने स्वीकार किया कि स्त्री को शिक्षा और संस्कृति के समान अधिकार हैं। स्त्रियाँ म तेजी से शिक्षा का प्रसार हुआ। लड़कियाँ की शिक्षा के प्रति जा रुझित विरोध या वह खतम होना लगा। 'एक समय था जब भारत में स्त्री शिक्षा के समर्थक तो नहीं थे, जलवत्ता उसके विराधी और शत्रु थे। जब तक स्त्री जाति कई मजिला से गुजर चुकी है पूरी उदासीनता, उपहास, आलोचना और स्वीकृति। अब यह आमानी से कहा जा सकता है कि भारत में सबत्र स्त्रियाँ की शिक्षा को भी उतना ही आवश्यक समझा जा रहा है जितना लड़कों की शिक्षा को, इस राष्ट्रीय प्रगति की आवश्यक शत माना जा रहा है।'<sup>4</sup>

ब्रह्म समाज, आय समाज रामकृष्ण मिशन आदि सुधार मगठना, डनिश, अमरीकी, जमन और ब्रिटिश मिशनरी संस्थायाँ और अल्पसंख्यक परतु प्रगतिशील पारसी मप्रदाय न स्त्री शिक्षा की दिशा में पथ प्रदर्शन का काम किया। प्रो० कर्वे द्वारा 1916 में स्थापित इंडियन वीमस यूनिवर्सिटी न स्त्रियाँ का शिक्षा प्रदान करने में सिलसिले में बड़ा काम किया।

मुसलमानों में स्त्री शिक्षा का प्रसार काफी मुस्त था यद्यपि पिछली ही सदी के अंत में सर सैयद अहमद खाँ और जय नताओन इसकी खुलकर हिमायत करनी शुरू कर दी थी। फिर भी इस दिशा में लगातार तरक्की हाती रही। स्त्री शिक्षा में लगातार हानी हुई प्रगति का इसी बात से श्रदाज हा जाता है कि 1917 में स्कूल जातवाली लड़कियाँ की संख्या 1,230,000 थी और 1837 में यह संख्या बढ़कर 2,890,000 हो गई।

भारतीय जावादी के अधिकांश बहुत गरीब थे और स्त्री शिक्षा के तंत्र विकास के रास्ते में यह तथ्य एक बहुत बड़ा अवरोध था। गरीबी के कारण, भारतीय जनता के कमकर बग किसान और मजदूर, स्त्री शिक्षा की जो भी सुविधाएँ प्राप्त थी उनका फायदा नहीं उठा सक। वे इसका खर्च नहीं उठा सकते थे इसलिए शिक्षा उन तक नहीं पहुँच सकी। भारतीय राष्ट्रवादियों के अनुसार भारतीय जनता की गरीबी का कारण यह था कि जिस तरह की आर्थिक प्रगति से उनका आर्थिक स्तर ऊँचा हाता, उस तरह की प्रगति के रास्ते में विदेशी शासन बाधक था। भारतीय जनता में शिक्षा के सामंजस्य विवास का प्रश्न उनकी राजनीतिक स्वतंत्रता और तज्जय आर्थिक प्रगति के प्रश्न से जुड़ा हुआ था।

### राजनीति में स्त्रियों का सहयोग

राजनीति में स्त्रियाँ का तीव्र प्रवेश, घामकर 1919 के वाक, भारतीय इतिहास की अत्यंत जाश्चयजनक घटना है। प्रायः ब्रिटिश भारत में मुलताना रजिया जगम, चाद बीबी नूरजहा अहल्याबाइ हालकर जसी कुछ अनिजातर्गीय स्त्रियाँ के अतिरिक्त अन्य स्त्रियाँ न राजनीति में भाग नहीं लिया। ब्रिटिश शासन का न



स्थिति बदली। उन्हें जो मताधिकार मिला था, सीमित ही नहीं, उसका उन्होंने जोशोखराश के साथ इस्तमाल किया, साथ ही उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाए गए जन आंदोलनों में भी भाग लिया। महात्मा गांधी और कांग्रेस राष्ट्रीय प्रयास के लिए उनका आह्वान कर रहे थे, और उन्होंने देखा कि इस अविष्य द्रष्टा गांधी और ब्रिटिश सरकार की सर्वोपरि सत्ता न उनके हाथों में एक कारगर हथियार दे रखा है। एक हाथ से उन्होंने निष्क्रिय विरोध (सत्याग्रह) का हथियार और दूसरे हाथ से मतदान का अधिकार ग्रहण किया।

बड़ी तादाद में राजनीतिक जन आंदोलनों में भाग लेती हुई, गराय की हड़तालों पर धरना देती हुई प्रदर्शनों में भाग लेती हुई, जेल जाती हुई लाठी और गोलीबाजी का सामना करती हुई स्त्रियों का दृश्य भारतीय इतिहास में अभूतपूर्व था। एक ही वार में भारतीय जीरते अपनी सदिया पुरानी सीमाओं का अतिक्रमण कर जाग बंद गई। पहले वे जाज्ञाकारी, घरलू नौकरा जसी थी, लेकिन जब वे नागरिकों के रूप में उठ खड़ी हुई, और उन्होंने राजनीतिक कार्यक्रम पर अपना मत देना और बड़े राजनीतिक आंदोलनों में भाग लेना शुरू किया। सरोजनी नायडू, कमलादेवी चट्टोपाध्याय विजय लक्ष्मी पंडित जमी कुछ औरतें तो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति लब्ध नेता मिड हुई।

जब 1936 में कांग्रेस की सरकारें बनीं तो कुछ औरतों ने मंत्री, जवर सचिव और प्रांतीय विधायिका सभाओं के उपाध्यक्ष के रूप में काम किया। भारतीय जीरते लोकल बोर्डों और म्युनिसिपैलिटी की सदस्यता भी हुई। इस तरह भारतीय महिलाओं में जागरण की एक नई लहर आई। सही है कि अतिशय त्रिद्विता के कारण नागरिक जीवन में प्रवेश और शिक्षा के अवसर उच्च और मध्यमवर्गीय महिलाओं को ही मिले थे। फिर भी, ऐसा व्यापक स्त्री जागरण प्रायः ब्रिटिश भारत में देखने में नहीं आता।

### युग संघर्ष में स्त्रियों का सहयोग

निश्चल तबका की स्त्रियाँ भी अशिक्षा और त्रिद्विता के बावजूद अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही थीं। हजारों की संख्या में किसान और मजदूर जीरतों में हड़तालें प्रदर्शनों और कांग्रेसों में भाग लिया। उनमें राजनीतिक चेतना का भी विकास हो रहा था और वे राष्ट्रीय राजनीतिक गठनों में शामिल हुईं। वे मजदूर संगठनों और किसान सभाओं में भी शामिल हुईं जिनका लक्ष्य था न केवल स्वतंत्र भारत बनने स्वतंत्र समाजवादी भारत। भारतीय जीरतों का यह जागरण उनमें राष्ट्रीय और व्यक्तिगत स्वतंत्र्य के लिए राष्ट्रीय भावना और प्रजासत्ताक उद्देश्यों के विकास का परिचायक था।

स्त्री को वचित रखन की प्रथा का विरोध किया।

यह प्रायः सत्रन स्वीकार किया कि स्त्री का शिक्षा और सञ्चति के समान अधिकार हैं। स्त्रियां म तेजी से शिक्षा का प्रसार हुआ। लडकियां की शिक्षा के प्रति जो रुद्धिगत विरोध था, वह खतम होने लगा। एक समय था जब भारत में स्त्री शिक्षा के समर्थक तो नहीं थे जलवत्ता उसका विरोधी और शत्रु थे। अब तक स्त्री जाति कई मजिला से गुजर चुकी है पूरी उदासीनता उपहास, आलोचना और स्वीकृति। अब यह आसानी से कहा जा सकता है कि भारत में सबन स्त्रियों की शिक्षा का भी उतना ही आवश्यक समझा जा रहा है जितना लडका की शिक्षा को, इसे राष्ट्रीय प्रगति की आवश्यक शत माना जा रहा है।<sup>14</sup>

ब्रह्म समाज आय समाज रामकृष्ण मिशन जादि सुधार मगठना, डैनिश, जमरीकी, जमन और ब्रिटिश मिशनरी सस्थाआ और जल्पमर्यक परतु प्रगति शील पारसी मप्रदाय ने स्त्री शिक्षा की दिशा में पय प्रदशन का काम किया। प्रा० कर्वे द्वारा 1916 में स्थापित इंडियन वीमस यूनिवर्सिटी ने स्त्रियां को शिक्षा प्रदान करने के सिलसिले में बडा काम किया।

मुसलमानों में स्त्री शिक्षा का प्रसार काफी सुस्त था, यद्यपि पिछली ही सती के जत में मर मयद अहमद खा और जय नताओ न इसकी खुलकर हिमायत करनी शुरू कर दी थी। फिर भी इस दिशा में लगातार तरक्की हाती रही। स्त्री शिक्षा में लगातार हानी हुई प्रगति का इसी बात से श्रदाज हा जाता है कि 1917 में स्कूल जानवाली लडकियां की मर्यादा 1,230,000 थी और 1837 में यह मर्यादा बढ़कर 2,890,000 हो गई।

भारतीय जावादी के अधिकांश बहुत गरीब थे और स्त्री शिक्षा की तीव्र विकास के रास्ते में यह तथ्य एक बहुत बडा अवरोध था। गरीबी के कारण, भारतीय जनता के कमकर बग किसान और मजदूर स्त्री शिक्षा की जो भी सुविधाएं प्राप्त थी उनका फायदा नहीं उठा सका। वे इसका खर्च नहीं उठा सकते थे, इसलिए शिक्षा उन तक नहीं पहुंच सकी। भारतीय राष्ट्रवादियों के अनुसार भारतीय जनता की गरीबी का कारण यह था कि जिस तरह की जायिक प्रगति से उनका जायिक स्तर ऊंचा हाता, उस तरह का प्रगति के रास्ते में विदेशी सामन बाधक था। भारतीय जनता में शिक्षा के सावजनीन विकास का प्रश्न उनकी राजनीतिक स्वतंत्रता और तज्जय जायिक प्रगति के प्रश्न से जुडा हुआ था।

### राजनीति में स्त्रियों का सहयोग

राजनीति में स्त्रियां का तीव्र प्रवेश घासकर 1919 के बाद, भारतीय इतिहास की अत्यंत जाश्चमजनक घटना है। प्रायः ब्रिटिश भारत में मुलताना रजिया राम, चान् वीपी, नूरजहा, जहलियागड हातरर जसी कुछ अभिजातशर्गीय स्त्रियां के अतिरिक्त अन्य स्त्रियां न राजनीति में भाग नहीं लिया। ब्रिटिश सामन काल में

स्थिति बदली। उन्हें जो मताधिकार मिला था, सीमित ही मही, उसका उंहोन जोशोखरोश के साथ इस्तमाल किया, माय ही उंहोन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाए गए जन जादोलनो म भी भाग लिया। महात्मा गांधी और कांग्रेस राष्ट्रीय प्रयास के लिए उनका जाह्वान कर रहे व, और उंहान देखा कि इस भविष्य द्रष्टा गांधी और ब्रिटिश सरकार की सर्वोपरि सत्ता न उनके हाथ म एक कारगर हथियार द रखा है। एक हाथ से उंहान निष्क्रिय विरोध (सत्याग्रह) का हथियार और दूसर हाथ स मतदान का अधिकार ग्रहण किया।'

बड़ी तादाद म राजनीतिक जन आदालनो म भाग लती हुई, शराव की दूकाना पर धरना देती हुई, प्रदर्शनो मे माच करती हुई, जेल जाती हुई, लाठी और गोलिया का सामना करती हुई स्त्रिया का दृश्य भारतीय इतिहास म अभूतपूर्व था। एक ही वार म भारतीय औरते अपनी सदिया पुरानी सीमाजा का अतिक्रमण कर आग बढ गई। पहल व आज्ञाकारी घरेलू नौकरो जैसी थी, लकिन अब व नागरिको के रूप म उठ खडी हुई, और उंहाने राजनीतिक कार्यक्रम पर अपना मत देना और बडे राजनीतिक आदोलनो म भाग लेना शुरू किया। सरोजनी नायडू, कमलादेवी चट्टोपाध्याय विजय लक्ष्मी पंडित जमी कुछ औरते ता अंतर्राष्ट्रीय व्यापति लब्ध नेता सिद्ध हुई।

जय 1936 म कांग्रेस की सरकार बनी तो कुछ औरतो न मंत्री जवर सचिव और प्रातीय विधायिका सभाओ के उपाध्यक्ष के रूप मे काम किया। भारतीय औरते लोकल बोर्डो और म्युनिसिपैलिटी की सदस्या भी हुई। इस तरह भारतीय महिलाओ मे जागरण की एक नई लहर आई। सही है कि अतिशय दरिद्रता के कारण नागरिक जीवन म प्रवेश और शिक्षा क अवसर उच्च और मध्यमवर्गीय महिलाओ का ही सुलभ थ। फिर भी, एसा व्यापक स्त्री जागरण प्राक ब्रिटिश भारत म देखने म नही आता।

### वग सघष मे स्त्रियो का सहयोग

निचले तबवा की स्त्रिया भी, अशिक्षा और दारिद्र्य के बावजूद अपने अधिकारा क प्रति जागरूक हो रही थी। हजारो की सदस्या म किसान और मजदूर औरता न हडताल प्रदर्शन और काफ़सो म भाग लिया। उनम राजनीतिक चेतना का भी विकास हा रहा था और व राष्ट्रीय राजनीतिक संगठना मे शामिल हुई। वे मजदूर संगठना और किसान सभाओ म भी भर्ती हुई जिनका लक्ष्य था न केवल स्वतंत्र भारत वरन स्वतंत्र समाजवादी भारत। भारतीय औरतो का यह जागरण उनम राष्ट्रीय और व्यक्तिगत स्वातंत्र्य के लिए राष्ट्रीय भावना और प्रजातान्त्रिक उद्वेगा के विकास का परिचायक था।

आधारित सामाजिक विभेद को मायता प्राप्त थी और व्यक्ति जाति और सयुक्त परिवार के अधीन था। नए समाज के अस्तित्व के लिए आवश्यक था कि जम और सेक्स पर आधारित विशेषाधिकार का समाप्त कर दिया जाए।

शुरू के दम सुधारका न व्यक्ति स्वातंत्र्य के सिद्धान्त को धर्म के क्षेत्र में भी प्रचारित किया। वस्तुतः, ब्रह्म समाज, प्राथना समाज, आय समाज और अयान्य सस्थाएँ पुराने धर्म का नए समाज की आवश्यकताओं के कमोवेश अनुकूल बनाने की ही काशिश कर रही थी। यह सच है कि उनके कुछ लोग (विशेषतः आय समाज वाले) यह नमन रहे थे कि वे वैदिक युग के आर्या की शुद्ध सामाजिक संरचना का ही पुनरुज्जीवित कर रहे थे कि वे स्वर्ण युग (सतयुग) की ओर वापस जा रहे थे। लेकिन वस्तुतः वे हिंदू धर्म का नवीन भारतीय राष्ट्र की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने में लगे थे। इतिहास में उनके उदाहरण मिलेंगे जब नए समाज के निर्माताओं ने यह समझा कि वे अतीत की ओर वापस जा रहे हैं और पुराने जमाने के सर्वाच्च सामाजिक रूपा का पुनरुज्जीवित कर रहे हैं। भारत के प्रारंभिक धर्म सुधार आंदोलनों ने ऐसे धार्मिक दृष्टिकोण का विकसित करने की कोशिश की जो हिंदू, मुसलमान, पारसी आदि सभी मजहबों की एकता कायम कर सकें, और इस तरह भारत के नवीन आर्थिक विकास, जनता के विकास के रास्ते के बाधा विघ्ना की समाप्ति स्त्री पुरुष की समता के सिद्धांत की स्थापना जाति व्यवस्था का उन्मूलन पुरातन संस्कृति के एकाधिकारी रूप एवं व्यक्ति और ईश्वर के पारस्परिक संबंध के एकमात्र माध्यम के रूप में ब्राह्मणों की हैसियत का आत्मा, आदि सम्मिलित राष्ट्रीय उद्देश्य और लक्ष्य की पूर्ति में सहायक हो सकें। यूरोप के प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन की तरह ही भारत के धर्म सुधार आंदोलन भी समाज के किसी अतीतकालीन युग का पुनः स्थापित नहीं कर रहे थे बरन नवोदित समाज की स्थापनाओं और उपलब्धियों को दृढ़तर बना रहे थे।

उदारवाद उदीयमान पूँजीवाद का जीवन दर्शन है।<sup>1</sup> राष्ट्रवाद और प्रजातंत्र इसके दो मूलभूत सिद्धांत हैं। दम सुधार आंदोलनों ने धर्म क्षेत्र में उदारवादी दृष्टिकोण का प्रवेश कराया।

**अतीत का आग्रह, इसका विशिष्ट तात्पर्य**

आय समाज वाले, और लागू की ही तरह, अतीत में अनजान नए समाज का निर्माण कर रहे थे बरन उन्हें ऐसा कुछ प्रम था कि वे अतीत के शुद्ध जाति कालीन समाज की ओर वापस जा रहे थे। इस तरह के प्रमपूर्ण चिंतन के गंभीर दार्शनिक एवं मनाचार्तिक कारण हैं। यह चिंतन सामाजिक अस्तित्व के नए रूपा प्राप्त और पुरातन चिंतन के दृढ़ता से परिणाम हैं।

व्यक्ति भी समाज की ही तरह अनजान के अस्तित्व एवं युगा से उत्तराधिकार में प्राप्त अतीतकालीन विचार पद्धति के मयाग में बना है

इसलिए वह अपने अतस्तल म अस्तित्व एव चिंतन, नए जीवन और पुरानी विचारधारा के तनाव का अनुभव करता है असपूण भविष्य उस पर अपनी जोर आजमाइश कर रहा है त्रेकिन च्कि मानस के महजजोधिक मौलिक तत्व प्राचीनतम ह, इसलिए उसे लगता है कि उसका अतीत ही उस पर हावी हो रहा है। इमीलिए हम प्राय यह विराधाभास देघन को मिलता है कि जननायक अतीत का जाग्रह करता है और इसे वापस लाने के लिए जन मानस को उद्वेलित करता है लकिन ऐसा करने की चंष्टा म वह भविष्य का निर्माण करता है। (मूराप के) पूजीवादी नव जागरण म क्लासिकल गौरव ग्रथा और मान्यताजा का बोलवाला रहा। नेपालियन और फ्रांस की राज्य श्राति पर रोम की प्राचीन सभ्यता का काफी प्रभाव था। अठारहवीं सदी के क्रातिकारियो का आदश था प्राकृतिक और अभ्रष्ट, जबिकृत आदिम मानव की जोर प्रत्यावतन। फिर भी, ऐसे मौका पर लोग प्राय अपने मन मस्तिष्क म नए का ही तनाव महमूस करते ह

व्यक्ति विशेष के लिए यह मोचना मभव है कि वह अतीत की रक्षा या उस पुन स्थापित करन के लिए ही पैदा हुआ है और जब उसके किए का परिणाम दृष्टिगत हाता है तभी यह स्पष्ट होता है कि भविष्य का निर्माण हुआ। आदिम ईमाइत्व की जार अभिमुख सुधारक बुजुआ प्रोटस्टेटवाद को ज म देता है।

इसी तरह गाधी ने साचा कि वे हिंदुओ के स्वण युग अथात रामराज्य की स्थापना कर रह ह जब वस्तुत वे भारत के लिए जाधुनिक प्रजातांत्रिक, पूजीवादी, राष्ट्रवादी राज्यत्व लाने का प्रयास कर रह थ।

भारतीय जनता की दासता क कारण अतीत का जाग्रह और अधिक बलशील हुआ। विदेशी शासन से मुक्ति की स्वस्थ आकाक्षा के साथ ही पुनरज्जीवित हिंदुत्व के जरिए विश्व के आध्यात्मिक विजय' के अर्थ और उग्र राष्ट्रीयता मूलक स्वप्न भी देखे गए, जैसे रामकृष्ण मिशन आदालन के महान नेता विवेकानंद द्वारा। भारत की विशिष्ट आध्यात्मिक प्रतिभा' के दावे सारे ससार म घापित किए गए।

फिर भी भारत के प्रारंभिक धम सुधार जादोलन प्रगतिशील थे। वे भारतीय जनता के प्राथमिक राष्ट्रीय जागरण के परिणाम थे। मध्ययुग से जाधुनिक पूजीवाद की जार नरमण के काल म प्राय प्रत्येक राष्ट्र न धम सुधार जादोलना के माध्यम से, नए सामाजिक लक्ष्या क अनुसार पुरान धम को नए साच म ढालने क प्रयास किए है।

### मध्ययुगीनता वनाम उदारवादी दृष्टिकोण

मध्ययुगीनता का अर्थ हे जाभिजात्य द्वारा शासन। उदारवाद जो पूजीवाद का जीवन दशन है जनतन और जनसाधारण द्वारा शासन का हिमायती है।

मध्ययुगीनता एवं मध्ययुगीन धर्म जन्म पर आधारित विशेषाधिकार के पोषक हैं। उदारवाद ने इन नारे विशेषाधिकारों का अत्यायुक्त वताया और उन पर चोट की, और उसने व्यक्ति स्वातंत्र्य समानाधिकार मुक्त प्रतिद्वंद्विता के सिद्धांत घोषित किए। मध्ययुगीन विचारधारा के अनुसार राजत्व के ईश्वरीय उद्भव, सामाजिक संरचना की पवित्रता और जो कुछ है उसकी देवमन्मत प्रकृति में लोगों का विश्वास अनिवार्य था। उदारवाद ने आस्था निष्ठा की जगह आलोचनात्मक बुद्धिवाद को प्रतिष्ठापित किया जिसके अनुसार प्रत्येक संस्था और सिद्धांत की बुद्धिवादी गवेषणा आवश्यक है।

मध्ययुगीनता ने अपकथ के सिद्धांत का प्रचार किया, जिसके अनुसार आदमी आदिवासी स्वयंयुग से आज के ब्रह्मकलियुग में आ पड़ा है। उदारवाद ने इतिहास के वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर यह स्थापना प्रस्तुत की कि आदमी विकासशील रहा है समाज आदिम अवस्था से दास युग फिर दासता से सामंत युग और अभी पूंजीवादी युग के रास्ते लगातार प्रगति करता रहा है। मध्ययुगीन विचार शैली ने मूलतः आदमी को जीवन का नराश्रयपूर्ण दशन अपनाया और अपनी दृष्टि परलाक पर केंद्रित करने को बाध्य किया है। उदारवाद ने जीवन की चाह उसकी भूख को बढ़ाया है और इस तरह आधुनिक मनीषा और विज्ञान की मदद से जानद बढान वाले भौतिक पदार्थों के उत्पादन का व्यापक क्षेत्र उजागर किया है।<sup>3</sup>

पुराने समाज का निम्न आर्थिक और सांस्कृतिक विकास पुराने धर्म का आधार था। नए समाज की जड़ें नए और राष्ट्रवाद प्रधान जीवन के प्रति शाखावादी और नकारात्मक दृष्टिकोण और बुद्धिवादी दशन आदि के नदम में पुराने धर्म का पुनरीक्षण और नए निरूपण आवश्यक था।

कल मित्राकर, इन पुनर्निर्मित धर्मों का मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रीय प्रगति। जिन लोगों ने धर्म का परिवर्तन या सुधार नहीं किया उनके लिए धर्म और राष्ट्र संसम और अनिश्चय। उदाहरण के रूप में वी० सी० पात्र जर्जिंद घाव और कुछ अन्य लोगों द्वारा प्रतिपादित राष्ट्र धर्म का उल्लेख किया जा सकता है।

कभी-कभी लोगों ने राष्ट्रीय भावनाओं और आशाओं का जगत करने के लिए पुराने देव-देवियों की नई व्याख्या की प्रस्तुत की जाती। 'देवता और स्त्रियों की मूर्तियों की इस नई व्याख्या के कारण देश के प्रचलित धार्मिक उत्सवों में तथा सारंगभण्डुजा, हजारा नखा लोग गणतथात्री या कान्ही या दुर्गा की सभ्यता उपासना करते समय 'प्रद मानस' का उल्लास न्यत्र उच्चरित करते हैं। ये देवियाँ भारतीय सिद्धांतों की उत्पत्ति हैं। इस प्रतीकात्मक परिवर्तन से आशा की गतराई और मानस का कारण भी है और प्रमाण भी है। पुराने देव-देवियों का यह चामत्कारिक रूप परिवर्तन नए राष्ट्रवाद का नदम और जन माधारण के बीच पट्टा रहा है।<sup>4</sup> इस तरह धर्म पुनर आदालत का तरह धर्म

के पुनर्जीवन के जादोलन भी राष्ट्रीय आदश द्वारा अनुप्रेरित थे ।

### धम सुधार आदोलनो का व्यापक प्रभाव

धम सुधार आदोलनो की एक यह भी विशिष्टता थी कि उनका कार्यक्रम धम सुधार तक ही सीमित नहीं था, उन्होंने सामाजिक मस्याआ और सबधो के नवनिर्माण का भी वाय किया । इसकी वजह थी कि भारत म धम और समाज परस्पर जैविक रूप से अनुलग्न थे । जातिगत श्रेणी शृखला स्त्री-पुरुष की विषमता, अस्पृश्यता और सामाजिक वजना इसलिए फल-फूल रहे थे कि उन्हें कम वा प्रशय प्राप्त था । इसलिए समाज सुधार सभी धम सुधार आदोलनो का अनिवाय लक्ष्य था । इन आदोलनो ने कमोवेश मात्रा म न केवल धम को वरन सामाजिक मस्याआ और सबधो का भी बौद्धिक आधार पर प्रतिष्ठापित करने की चेष्टा की । कही भी धम व्यक्ति के जीवन को वसे प्रभावित और निर्णीत नहीं कर रहा था जैसे भारत म । यहा व्यक्ति का जायिक क्रियाकलाप, उसका सामाजिक जीवन, उसका जन्म, व्याह और देहात, उमका एक जगह से दूसरी जगह आना जाना, इन सब पर पूरी तरह धम का नियन्त्रण था । धम सुधार के आदोलनो के लिए धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक सुधार के लिए सबव्यापी आदोलन करना आवश्यक था । उहान बहुदेववाद आर मूर्ति पूजा के गिलाफ तो मघप किया ही साथ ही जाति प्रथा और विदेश यात्रा सबधी निषेध पर भी चोट की । धम के क्षेत्र म ब्राह्मणो के एकाधिकार और जातिगत विषेणाधिकार पर भी इन आदोलनो ने आघात किया । और इन सबके पीछे मूल उद्भावना यह थी कि जिन पुरानी मस्थाजा, प्रथाजा को खतम करने की कोशिश की गई, वे राष्ट्रीय प्रगति म बाधक थी और राष्ट्रीय प्रगति के लिए सभी दलो और व्यक्तियो की समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांत पर जाधारित राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता थी ।

इन जादोलना की मूल अनुप्रेरणा थी देश का विकास । भारतीय जनता के प्रथम राष्ट्रीय जागरण का स्वरूप प्रधानत धार्मिक था । बाद के दशकाम जागरण की यह भावना गहरी और व्यापक हाती गई और उसका स्वरूप धमनिरपेक्ष हाता गया ।

### यूरोप मे वैसे ही आदोलन

यूरोप म भी ऐसी ही बात हुई थी । राष्ट्रीय राज्यतंत्र एव समाज की स्थापना को लक्ष्य बनाकर जा आदोलन हुए, उनके पहले नवोदित राष्ट्रीयता प्रोस्टेस्टवाद और धम सुधार जैसे धार्मिक रूपो म ही लक्षित हुई । इसकी वजह थी कि मध्ययुगीन धम, जो नया समाज बन रहा था उसके अनुकूल नहीं था । यूरोप का मध्ययुगीन धम, रोमन कैथलिक धम, समूचे इसाई ससार की सास्कृतिक एकता का मूल था, लेकिन यह सामतशाही का पोषक था और सामतशाही बढ़ते हुए पूजीवादी अथतंत्र के बढ़ते हुए राष्ट्रीय विनिमय सबधो के जाधार पर राष्ट्रा के आर्थिक

समन्वय के रास्ते में बाधक थी। यह भी द्रष्टव्य है कि सामंती राज्य व्यवस्था को समर्थन प्रदान कर रोमन चर्च राष्ट्रीय राज्या की स्थापना में जड़चन छोड़ कर रहा था और नए पूंजीवादी जयतंत्र की स्वतंत्र और क्षिप्र प्रगति के लिए राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था अत्यावश्यक है।

इसलिए यूरोप के देशों में जनता के राष्ट्रीय जागरण ने सामंती धर्मतंत्र के विरुद्ध धार्मिक मघप का रूप लिया। फ्रांस में सामंती जयतंत्र और राज्य व्यवस्था के जाध्यात्मिक ममथक रोमन चर्च का विरोध सभसे पहले वाल्टयर, रूसो, हलवमियस हलवाय आदि ने किया। यह धर्म विरोधी विद्रोह सामंतशाही के विरुद्ध किए गए धर्म निरपेक्ष राष्ट्रीय राजनीतिक विद्रोह के पहल हुआ।<sup>5</sup>

भारत में भी राष्ट्रीय जागरण ने गुरु के दिनों में धर्म सुधार आंदोलन का रूप लिया। इनमें से कुछ ने सनातन धर्म को उदारवाद के सिद्धांतों की रोशनी में फिर से देखने की काशिश की। कुछ दूसरे लोगों ने इसे उनके प्राचीनतम रूप में ही फिर से प्रस्तुत करने की चेष्टा की।

जैसे मालहवी नदी में यूरोप, वैसे ही उनीमवी नदी में हिंदुत्व के विभिन्न जवयव जाध्यात्मिक प्राति की चपेट में जाकर सुगवुगा उठे (यूरोप के) धर्म सुधार की ही तरह यहाँ भी लोग परंपरा के जादिम स्वरूप की आर कुके और प्राद के दिना के जवविश्वाम और विकृति की मत्सना की।<sup>6</sup>

भारत में मध्ययुगीन धर्म के विरोध में धर्म सुधार आंदोलन का ज में हुआ क्योंकि मध्ययुगीन धर्म जानि जसा मस्थाजा का पोषण करत थे जो दंग में नग अयतंत्र न विकास और भारतीय जनता की राष्ट्रीय एतता न राम्म में जवदस्न रवावटे पैना करती थी। बहुदववाद जात्मा का हनन करन सने निरान धार्मिक ममसाड धार्मिक रुद्धिग जादि न विरुद्ध भी मघप हुग स्वाभि म जनता की जालोचनात्मक वौद्धिक गक्ति न। कमजार करती थी। ये धर्म सुधार आंदोलन तथ्यत राष्ट्रीय थे तन्मिन रूपत धार्मिक। हमार राष्ट्रीय जस्मिन्त के बाद के दिना में राष्ट्रीयता मपूणत धर्मनिरपेक्ष हो सती।

इन धर्म सुधार आंदोलनों में से कुछ ने हमें तथप में विवरण दग। अनस हम जान सकेंगे कि कस से धर्म सुधार आंदोलन राष्ट्रीयता व उद्भव ती गति मजोए थे और उनके एम तावधम में ता धर्म के क्षेत्र में उदारवाद का प्रथम दत हैं और उनमें सिद्धांतों का तार्किकित करत है।

## ग्रह समाज आंदोलन

जिम प्रकार के धर्म सुधार आंदोलन ही हम था कर रहे हैं उनमें मयम पट्ट न ग्रह समाज आंदोलन हुआ ग। इससे पहले 1828 में राजा राममाहन राय (1772-1833) ने, जो गहा जवों में भारताय राष्ट्रवाद न तनन बहु जा गत। ट, गुरु किया। राजा राममाहन राय म्मुन प्रकृतप्रवासी और मानवतावादी न। अपन धार्मिक, गतिन और सामाजिक दृष्टिगण में न स्नाम न परंपरा



और मूर्ति पूजा विरोध, सूफीमत के रहस्यवाद, ईसाई धर्म की जाचारशास्त्रीय नीतिपरक शिक्षा और पश्चिम के आधुनिक देशों के उदारवादी बुद्धिवादी सिद्धांतों से काफी प्रभावित थे। 'उन्होंने अपने ही व्यक्तित्व में इस्लाम ईसाई धर्म और आधुनिक मानवतावाद या बुद्धिवाद के सर्वोत्तम तत्वों को परिभाषित और जमीन करने की चेष्टा की और उन्हें एक मूल धर्म में रूपायित किया, जिसके तत्व उन्हें उनके अपने समुदाय के उपनिषद दर्शन में मिले।'<sup>7</sup>

उन्होंने प्राचीन हिंदू एकेश्वरवाद की जगह आजात बाली बहुदेववादी विकृति की जालोचना की। उन्होंने हिंदुओं की मूर्ति उपासना का अमानवाचित और गलत कहा और मंत्र धर्मों और मारी मानवता के एक अकेले ईश्वर के सिद्धांत को प्रतिपादित किया।

बहुदेववाद और मूर्ति पूजा के विरुद्ध उनके सघर्ष की अनुप्रेरणा दार्शनिक आस्था के अतिरिक्त राष्ट्रीय और सामाजिक जाचारशास्त्रीय विचारों में भी निहित थी। 'हिंदू मूर्तिपूजा की विचित्र प्रथा किसी भी अर्थ में इमाई उपासना पद्धति की अपेक्षा समाज की संरचना के लिए अधिक हानिकारक है। तज्जय कमकाड़ पर लगातार सोचते रहने से और अपने दशवासियों के प्रति करुणा की भावना के कारण मैं उन सब तरीकों का उपयोग करने के लिए बाध्य हूँ जिनसे वे प्रकृति के ईश्वर की एकता और सबव्याप्ति का मनन कर सकें।'<sup>8</sup>

राजा राममोहन राय धर्म के प्रति बुद्धिवादी दृष्टिकोण अपनाने के पक्ष में थे। उनका विचार था कि व्यक्ति का पुरोहित के माध्यम के बिना स्वयं धर्मशास्त्रों का पाठ करना चाहिए और स्वयं किसी सिद्धांत को समझना पहचानना चाहिए। उसे स्वयं अपनी आचारपरक विचार बुद्धि की कसीटी पर धार्मिक सिद्धांतों को परखना चाहिए और उन सिद्धांतों को अस्वीकार कर देना चाहिए जो इस कसीटी पर सरे नहीं उतरे।

चूँकि हिंदू समाज पर हिंदू धर्म की धार्मिक स्थापनाओं का शासन और नियंत्रण था, इसलिए किसी भी धर्म सुधार आंदोलन के लिए समाज सुधार का भी अपने कार्यक्रम में रखना आवश्यक था। राजा राममोहन राय और शुरू के धर्म सुधारकों के अनुसार समाज के कल्याण के लिए धर्म के रूप परिवर्तन की आवश्यकता थी। इसलिए धर्म सुधार के आन्दोलनों के संपूर्ण कार्यक्रम का अन्विष्टा जगत् या समाज सुधार।

राजा राममोहन राय के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने जाति प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाया और इसे अप्रजातंत्रिक, अमानुषिक और राष्ट्र विरोधी बतलाया। इसमें सती और बान विवाह के विरुद्ध सघर्ष किया और विधवाओं के पुनर्विवाह और स्त्रियों पुण्य के समानाधिकार का समर्थन किया।

ब्रह्म समाज ने आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के महत्त्व का समर्थन और लोगों में इसके प्रसार के लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की। राजा राय पाश्चात्य उदारवादी प्रजातंत्रिक संस्कृति के समर्थक थे।

राजा राममोहन राय के अनुसार भारत में अंग्रेजी शासन एक अच्छी बात थी। मती प्रथा और बाल हत्या का उन्मूलन जैसे समाज सुधार और स्वतंत्र पत्र-कारिता तथा आधुनिक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना आदि प्रगतिशील कार्यों के लिए उन्होंने ब्रिटिश शासन की तारीफ की। यह स्वाभाविक ही था, क्योंकि उनोसवीं सदी के प्रारंभ में भारत में ब्रिटिश शासन के ऐतिहासिक दृष्टि से प्रगतिशील पहलू भी थे।

ब्रिटिश शासन के प्रारंभिक दिनों में जैसे उनोसवीं सदी के गुरु में, औद्योगिक महार के बावजूद ब्रिटिश शासकगण प्रगतिशील भूमिका अदा कर रहे थे। वे कई क्षेत्रों में भारतीय समाज की रूढ़िवादी और सामंती शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे। ये साहसिक सुधार के दिन थे, जैसे मती प्रथा का उन्मूलन (जो भारतीय समाज के प्रगतिशील तत्वों का संपूर्ण सन्निय सहयोग का साथ किया गया था), दासता का उन्मूलन (यवहार में बहुत दूर तक महज औपचारिक) ठीकी और बाल हत्या के खिलाफ लड़ाई, पश्चात्य शिक्षा का प्रारंभ और जयवारा की आजादी। शुरू के दिनों के ब्रिटिश शासकों का दृष्टिकोण सकीण था जो वे भारतीय परंपरा में जो कुछ पिछड़ा था उसके प्रति असहिष्णु थे। उनका यह विश्वास था कि उनोसवीं सदी की बुजुर्ग और क्रिश्चियन धारणाएँ मनुष्य जाति के लिए आदर्श तुल्य हैं। फिर भी उन्होंने उन दिनों की आगामी उच्चमुखी बुजुर्गों के प्रतिनिधियों के रूप में नवाचार और नवीनता की दिशा में बहुत सारा काम किया। इन शासकों में जो सबसे प्रमुख थे जैसे सर हनरी लारेस व उन लांग का प्रेम और आदर भाव जीवन में सफर हुए जिनके साथ उन्हें काम करना पड़ा। अंग्रेजों व सभसे बड़े दुश्मन प्रतिक्रियावादी शासक थे जिन्होंने यह दवा कि अंग्रेज उन्हें हटा सकते हैं। उन दिनों के भारतीय समाज का सबसे अधिक प्रगतिशील तत्व नराम राममोहन राय और ब्रह्म समाज के सुधार आंदोलन व प्रगति का पथदर्शक रूप में अंग्रेजों की भूरि भूरि प्रशंसा की। उनके द्वारा लाए गए सुधारों को पूरा समर्थन प्रदान किया और उन्हें एक नई मर्मता के हरावन दस्त दे दिए।<sup>9</sup>

लेकिन अंग्रेजों का प्रति प्रशासकों का बावजूद राजा राममोहन राय न प्रगतिशीलता को सीमित करने की सरकारी नीति का खिलाफ संघर्ष का संगठन किया। उन्होंने ऊँच जोहदा से भारतीयों का बर्तन रखने का सरकारी नीति का भी आलोचना की। ब्रह्म समाज बनने एवं धार्मिक आन्दोलन भर नहीं था बरन सामाजिक और राजनीतिक सुधार भी उसका कार्यक्रम का अंग थे। इस तरह यह आन्दोलन इत्यादि द्वारा परंपरों के बाल में गुंथ लिए गए समाज सुधार आन्दोलन और उच्चमन नगनल संघर्ष का प्रारंभिक दिनों का राजनीतिक आन्दोलन का अग्रदूत था। इस तरह धर्म सुधार आंदोलन ने समाज में गुंथे हुए धर्म निरपेक्षता का मार्गदर्शक और राजनीतिक सुधार आन्दोलन का निर्माण, जमानत तयार की। यही रास्ता

राममोहन राय और उनके द्वारा चलाए गए ब्रह्म समाज का ऐतिहासिक महत्व है। 'राजा राममोहन राय ने भारत में आधुनिक युग की शुरुआत की।'<sup>10</sup>

राजा राममोहन राय के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेन्द्र नाथ टैगोर (1817-1905) ने किया। उन्होंने धर्मशास्त्रों को भ्रमातीत नहीं माना और उन्हें पूणत अस्वीकार कर दिया। उन्होंने धर्मशास्त्रों की जगह अतदृष्टि अतर्वोध को प्रतिष्ठापित किया। उन्होंने उपनिषद के कुछ प्रकरण खोज निकाले, जो ब्रह्म समाज के सिद्धांतों और कार्यक्रम के धार्मिक वैचारिक आधार बने।

केशवचंद्र सेन (1838-84) ब्रह्म समाज के दूसरे नेता थे। उनके नेतृत्व में ब्रह्म समाज का सिद्धांत शुद्ध ईसाइयत के अधिकाधिक नजदीक आया। बाद के युग में, उन्होंने 'अदेश' का सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसके अनुसार ईश्वर कुछ व्यक्तियों में ज्ञान की प्रेरणा देता है जिनके शब्द को सत्य और भ्रमातीत माना जाना चाहिए। ब्रह्म समाज के कुछ लोगों ने यह सिद्धांत स्वीकार नहीं किया, समाज को छोड़ दिया और साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की।

ब्रह्म समाज राष्ट्रवादी आंदोलन का अग्रणी था, राष्ट्रीय आंदोलन जो धर्म सुधार आंदोलन के तौर पर शुरू हुआ और जिसका उद्देश्य था सत्तावादी धर्म के विशद बोझ से व्यक्ति को मुक्त करना, सत्तावादी धर्म जो व्यक्ति की पहल शक्ति का गला घाट देता था, और व्यक्ति एवं जनमानस को जड़वत बना देना था।

ब्रह्म समाज ने व्यक्ति स्वातंत्र्य, राष्ट्रीय ऐक्य और महकमण, एवं सामाजिक समस्याओं और संवधा के प्रजातन्त्रीकरण के सिद्धांतों को घोषित कर भारतीय जनता के लिए नए युग का नृजन किया। भारतीय जनता के राष्ट्रीय जागरण की यह पहली मगठित अभिव्यक्ति थी।

### प्राथना समाज

प्राथना समाज का बंबई में एम० जी० रानाडे ने 1867 में स्थापित किया। इसके धार्मिक और सामाजिक सुधार के कार्यक्रम बसे ही थे जैसे ब्रह्म समाज के। इसके नेता रानाडे इंडियन नेशनल काँग्रेस और इंडियन साइल काफरेंस के भी नेता थे जिनकी पहली सभाएं क्रमशः 1885 और 1880 में हुई।

### आर्य समाज

आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में बंबई में की। यह भी भारतीय राष्ट्रवाद के पहले उफान का परिचायक था लेकिन यह बिलकुल भिन्न प्रकार का आंदोलन था। इसमें पुरानी प्रवृत्तियों का पुनरुज्जीवित करने की बात पर विशेष ज़ोर दिया गया। इसके अनुसार वेद भ्रमातीत और जमाघ हैं और भूत, वतमान, भविष्य के सारे ज्ञान के जविरल स्रोत हैं। हम वेदों को ठीक तरह से समझना और उनकी उचित व्याख्या करनी है, क्योंकि उनमें दार्शनिक, तकनीकी, वैज्ञानिक सब तरह का सारा ज्ञान है। पर्याप्त धर्म से हम वेदों में सारा

आधुनिक रसायन अभियंत्रण, सैनिक और गैर सैनिक शास्त्र पा सकते हैं।<sup>11</sup>

चूँकि वेद अमाध और भ्रमातीत थे, इसलिए वेद सूत्र ही न कि व्यक्तिगत निणय ज्ञान की चरम कमीटी थे। वेदा के अमाधत्व का सिद्धांत प्रतिपादित कर आज समाज ईश्वरीय वाक्य सूत्र के ममक्ष व्यक्तिगत निणय का कोई महत्व नहीं प्रदान कर सकता था। इन तरह ब्राह्मणा के अधिकार और जयाय से व्यक्ति का मुक्त करते हुए भी आज समाज वेदा में संपूर्ण आस्था की मांग करना था। आज समाज ने व्यक्तिगत निणय की स्वतंत्रता के बदल वेदा की प्रामाणिकता स्वीकृत स्थापित की।

ब्राह्मणा की सत्ता का खंडन, जीर जिन निरर्थक कमकांडों की असख्यता और विभिन्न देवी-देवताओं की मूर्तियाँ की जिस उपासना के कारण समाज परस्पर विरोधी पथों में बंटा था उनकी निंदा, जिस धार्मिक अधविश्वास के कारण सदियाँ में हिंदू जन मानस जाध्यात्मिक पतन के कुहावद्ध गत में पड़ा था उसके विरुद्ध संघर्ष, आज समाज के कायक्रम के ये प्रगतिशील तत्व थे। वेदा की ओर चलो, ऐसा उनका जो नारा था उसके पिछे राष्ट्रीय तेज्य गौरव और चेतना की प्रेरणा काम कर रही थी। लेकिन, चूँकि इसका आधार मनीषा था इसलिए जिस राष्ट्रीय एकता की यह घोषणा करता था वह मुसलमाना और ईसाइया जैसे गैर हिंदू जातियों का नहीं समेट सका। यह हिंदू धर्म का ही अध बौद्धिक रूप था।

आज समाज का समाज मुधार रा भी अपना कायक्रम था। यह वशानुगत जाति प्रथा के निरन्ध रा लेकिन जन्म नहीं बर द्वारा विवेचित समाज की चतुर्व्यवस्था में इसका विश्वास था। चूँकि वेदों में इस तरह की व्यवस्था थी और चूँकि वेद गलत नहीं हैं सवतें इसलिए आज समाज जाति व्यवस्था का परित्याग नहीं कर सकता था। आज समाज सामाजिक और शिक्षा मामला में स्त्री पुत्र्य व समानाधिकार का समर्थक था। यह तो स्पष्टतः प्रजातान्त्रिक धारणा थी। लेकिन चूँकि वेदा में महेशिक्षा नहीं थी, इसलिए आज समाज सहशिक्षा का विरोधी था।

लडकू लडकियाँ व निण आज समाज ने दश में बहुत सार स्कूल-मालजा रा स्थापना की। इन स्कूलों में शिक्षा मानृभाषा के माध्यम में ली जाती थी। दयानंद एंग्लो वेदिक कालज 1886 में स्थापित हुआ। आज समाज के पुराणपथियों ने कहा कि इस कालज में दी ज्ञान प्राप्ति नि सा पूर्ण तरह बदिन नहीं थी। इसलिए इन लोगों ने मुशीराम व तनूत्र में हरिद्वार में गुरुकुल स्थापना कहा शिक्षा की विषय वस्तु और उसकी प्रणाली दोनों का चर्चिच रचित था।

अपने सारे शिक्षासत्ता में आज समाज राष्ट्रवादता और प्रजातंत्र की भावना से अनुप्ररिण था। इनमें उप-जातियों का समापन तर हिंदुजा व समर्थक रा गठना थी। इनमें ज्ञान में शिक्षा का प्रसार किया, ज्ञानि जन्म, प्रप्रचार निण जाति विभेदा व बायजूर मानव मात्र का एतता व शिक्षा का उद्घाष किया। उनमें

देश की प्रजा हान के नात उनम अनिवायत जो हीन भावना धर कर गई थी, उसे समाप्त करने की भी आय समाज न काफी काशिश की।

उसके सकीण हिंदू आधार के बावजूद और उसके इस तकहीन विश्वास के बावजूद कि सारा ज्ञान वेदा म सचित है, अनेक राष्ट्रीय हिंदू इसके प्रभाव म आए। एक जमाने म तो आय समाज सरकार की दमन नीति का मुख्य लक्ष्य था। इसम शायद ही कोई जाश्चय की बात है कि जब 1907 के वाद की उथलपुथल की जाच करन, 'लदन टाइम्स' की ओर स सर वलटाइन शिरल भारत आया तो उसने आय समाज का इग्लट और राज्य सत्ता के लिए बहुत ही खतरनाक बतलाया।<sup>1</sup>

आय समाज एक प्रकार से भारतीय जनता के राष्ट्रीय जागरण का ही एक रूप था। चूकि इसका आधार सकीण था, और इस्नाम के प्रति इसका दृष्टिकोण नकागात्मक, इसलिए कालक्रम से इसकी वजह स मुसलमाना ने भी अपन का साप्रदायिक आधार पर सगठित किया। शुरू के दिना म जब राष्ट्रीय जागरण का अभी उद्भव ही हो रहा था उस वक्त आर्य समाज की भूमिका प्रगतिशील थी। इसके प्रगतिशील और प्रतिगामी दोनो तरह के पहलू थे। धार्मिक जधविश्वास और ब्राह्मणो के पुरोहिती एकाधिपत्य के विरुद्ध मघप, बहुदेवाद का विरोध एव जन शिक्षा का समथन, उपजातिया का उमूलन, स्त्री पुरुष की एकता, आदि कायनम के कारण इसने समाज को जागे की ओर ही बढ़ाया। लेकिन वेदो को जमोघ और ब्रह्माड कं भूत, बतमान भविष्य के सारे ज्ञान का आगार कहना और गुण पर ही जाधारित सही लेकिन चतुवण का समथन करना जाय समाज की प्रतिगामी भूमिका के परिचायक थ। काइ भी ज्ञान इस जनत और जविरल तीर पर विकासशील सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया म अतिम नहीं हो सकता। इसलिए वेद किसी भी तरह सारे ज्ञान के आगार नहीं हो सकत। फिर, मारा ज्ञान इतिहास द्वारा अर्थात जिस युग म वह ज्ञान सामन आया है उस युग के सामाजिक और आर्थिक विकास द्वारा सीमित और निर्णीत है। इसलिए परिवर्ती पीढिया को परपरागत ज्ञान को आलाचनात्मक दृष्टि स आगे ढढाना होता है और उस बुद्धि एव सामाजिक उपयोगिता के तराजू पर तौना होता है। यही व्यक्तिगत निणय का प्रश्न आता है। वेदा को जमोघ मान लेने पर, व्यक्ति विशेष ही नहीं उमकी मारी पीढी भी अपना स्वतंत्र निणय देने और धमशास्त्रो पर सम्मति अभिव्यक्त करने से बचित रह जाती है। इसका अथ है व्यक्ति विनेप और उसकी सारी पीढी की मानसिक दासता। यह दृष्टिकोण उदारवादी भावधारा का विरोधी था।

वेदो के जमोघत्व और उनकी सवज्जता के सिद्धात के कारण आय समाज कभी भी पूरी तरह से राष्ट्रीय और सावजनीन नहीं हो सकता था।

फिर भी, जैसा ऊपर कहा गया है, भारतीय राष्ट्रवाद के गुरु के दिनो म जाय समाज की भूमिका प्रगतिशील थी। जब राष्ट्रीय जागरण व्यापक हुआ और गहराया, जब राष्ट्रीय जादोलन वम निरपेक्षता की ऊचाइयो पर पहुचा, तब जाय समाज भारतीय राष्ट्रवाद के विकास म खावट क रूप म जाया, क्याकि अनजान

आधुनिक रसायन अभियंत्रण सैन्य और गैर सैन्य शास्त्र का स्रोत है।<sup>11</sup>

चूँकि वेद समाज और भ्रमातीत न इसलिए वेद मूल ही न कि व्यक्तिगत निणय, ज्ञान की चरम कसौटी न। वेद के अमाधत्व का सिद्धांत प्रतिपादित कर जाय समाज ईश्वरीय वाक्य मूल के उमल व्यक्तिगत निणय का कोई महत्व नहीं प्रदान कर सकता था। इन तरह ब्राह्मण के अधिकार आर अत्याय से व्यक्ति का मुक्त करते हुए भी जाय समाज वेदा में संपूर्ण आस्था की भांग करता था। जाय समाज न व्यक्तिगत निणय की स्वतंत्रता के उदले वेदा की प्रामाणिकता स्वीकृत स्थापित की।

ब्राह्मणों की सत्ता का घड़न, और जिन निरथक कमकांडा की अनख्यता और विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियाँ तीजिम उपासना के कारण समाज परस्पर विरोधी पथा में पड़ा या उनकी निंदा जिम धार्मिक अंधविश्वास के कारण सदियाँ में हिंदू जन मानस जाध्याँ भर पनन के तुहायद्ध गत में पड़ा था, उसके विरुद्ध मधय, जाय समाज के वायजम के ये प्रगतिशील तत्त्व न। वेदा की ओर 'उला' एमा उनका जा नारा था उनके विरुद्ध राष्ट्रीय ऐयय गौरव और चतना की प्ररणा काम कर रही था। तर्जि चकि इसका जाचार मकीण था इसलिए जिम राष्ट्रीय एनता की यह घोषणा करता था यह मुसलमानों और ईसाइयों जैम गर हिंदू जातियाँ का नहा नमट मका। यह हिंदू धम का ही अध बीडिक रूप था।

जाय समाज का समाज मुधार ता ती जाना वायजम का। यह यानुगत जाति प्रथा के विरुद्ध या तर्जिन जम रही कम द्वाग विचरित समाज ती चतु-वण व्यवसाय में इसका विरगग था। तूनि यना में इन तरह की व्यवस्था की और तूनि वेद गतत रहा हा गतत तर्जिन जाय समाज जाति व्यवस्था का परिहाराग नहा कर सकता था। जाय समाज सामाजिक और शक्ति सामना में स्त्रा पुग्ग र समानाधिकार का समरक था। यह ती स्पष्टत प्रजातांत्रिक प्ररणा ती। तर्जिन तूनि वेदा में ग विधा था ता इगर्जिन जाय समाज महजिधा का विरोधी था।

तुहुँ तर्जिन र विण जाय समाज त दज में तूनु तार मूल-नाजों का स्थापना ती। इन स्त्रुता में ति ता तातृणा र माध्यम ती जाता ती। त्शान्त एनता रदिक कातत 1556 में स्थापित हुआ। जाय समाज र पुराणविद्या न रहा ति इन सारजम ती जात्र सता विधा पूरा कर रदिक तुहुँ ती। इगर्जिन इन साना र मु गीगम र तुहुँ न रदिकार में पुग्गुन ग्याता, जता विधा ता विपय र तुहुँ और ताती प्रजातांत्रिकता ती तर्जिन ती र ता।

जना गार विरासता में जाय समाज राष्ट्रवाद और प्रजातन्त्र का भागता ती जात्रगि था। इगर् उप-जातिना ती समाज र हिंदुता र मम रत ती ग्याता ती। इन साना र ति ता र प्रजातन्त्र विधा ताति, जन तर्जिन विर नाँ विरगग न सानुद मानर मात्र का एरता र गिद्धा र हा उद्गारणा रत। तुहुँ न

देश की प्रजा होने के नाते उनमें अनिवायत जो हीन भावना घर कर गई थी, उस समाप्त करने की भी आय समाज ने काफी कोशिश की।

उसके सकीर्ण हिंदू आधार के बावजूद और उसके इन तकहीन विश्वास के बावजूद कि सारा ज्ञान वेदा में संचित है, अनेक राष्ट्रीय हिंदू इसके प्रभाव में आए। एक जमाने में तो आय समाज सरकार की दमन नीति का मुख्य लक्ष्य था। इसमें शायद ही कोई आश्चर्य की बात है कि जब 1907 के बाद की उथलपुथल की जांच करने, 'लदन टाइम्स' की ओर से सर वैंलेटाइन शिरल भारत आया तो उसने आय समाज का इंग्लैंड और राज्य सत्ता के लिए बहुत ही खतरनाक बतलाया।<sup>1</sup>

आय समाज एक प्रकार से भारतीय जनता के राष्ट्रीय जागरण का ही एक रूप था। चूंकि इसका आधार सकीर्ण था, और इसनाम के प्रति इसका दृष्टिकोण नकारात्मक, इसलिए कालक्रम से इसकी वजह से मुसलमानों ने भी अपने का सांप्रदायिक आधार पर संगठित किया। गुरु के दिना में जब राष्ट्रीय जागरण का अभी उद्भव ही हो रहा था, उस वक़्त आय समाज की भूमिका प्रगतिशील थी। इसके प्रगतिशील और प्रतिगामी दोनों तरह के पहलू थे। धार्मिक अधविश्वास और ब्राह्मणों के पुरोहिती एकाधिपत्य के विरुद्ध मधुप, बहुदमाद का विरोध एवं जन शिक्षा का समर्थन, उपजातियों का उन्मूलन, स्त्री पुत्र्य की एकता, आदि कार्यक्रम के कारण इसने समाज का जाग की ओर ही बढ़ाया। लेकिन वेदों को अमोघ और ब्रह्मांड के भूत बतमान, भविष्य के सार ज्ञान का आगार कहना और गुण पर ही आधारित सही लेकिन चतुर्वर्ण का समर्थन करना आय समाज की प्रतिगामी भूमिका के परिचायक थे। कोई भी ज्ञान इस अनंत और अविरल तौर पर विकासशील सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया में अंतिम नहीं हो सकता। इसलिए वेद किसी भी तरह सारे ज्ञान के आगार नहीं हो सकते। फिर, सारा ज्ञान इतिहास द्वारा अर्थात् जिस युग में वह ज्ञान सामने आया है, उस युग के सामाजिक और आर्थिक विकास द्वारा सीमित और निर्णीत है। इसलिए परिवर्ती पीढ़ियां को परंपरागत ज्ञान को आलोचनात्मक दृष्टि से आगे बढ़ाना होता है और उस बुद्धि एवं सामाजिक उपयोगिता के तराजू पर तौटना होता है। यही व्यक्तिगत निणय का प्रश्न आता है। वेदों को अमोघ मान लेने पर, व्यक्ति विशेष ही नहीं उसकी सारी पीढ़ी भी अपना स्वतंत्र निणय देने और धर्मशास्त्रों पर सम्मति अभिव्यक्त करने से वंचित रह जाती है। इसका अर्थ है व्यक्ति विशेष और उसकी सारी पीढ़ी की मानसिक दासता। यह दृष्टिकोण उत्तरवादी भावधारा का विरोधी था।

वेदों के अमोघत्व और उनकी सचनता के सिद्धांत के कारण आय समाज कभी भी पूरी तरह से राष्ट्रीय और सावजनीन नहीं हो सकता था।

फिर भी, जसा ऊपर कहा गया है भारतीय राष्ट्रवाद के गुरु के दिनों में आय समाज की भूमिका प्रगतिशील थी। जब राष्ट्रीय जागरण व्यापक हुआ और गहराया, जब राष्ट्रीय जादोलन धर्म निरपेक्षता की ऊंचाइयों पर पहुंचा, तब आय समाज भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में रूकावट के रूप में आया, क्योंकि जनजाने

ही सही इसी युद्धपरक धार्मिक सांप्रदायिक मनोवृत्ति को जन्म दिया और तदनुरूप वातावरण की सृष्टि की।

### रामकृष्ण मिशन आंदोलन

भारतीय जनता का राष्ट्रीय जागरण रामकृष्ण द्वारा अनुप्रेरित आंदोलन में भी परिलक्षित होता है। रामकृष्ण चंडीदास और चतुर्थ की परंपरा में एक महान हिंदू सत थे। भक्ति का सिद्धांत उनके आंदोलन का आधार था। इस सिद्धांत के सबसे बड़े प्रचारक स्वामी विवेकानंद थे, जो रामकृष्ण के शिष्य थे और महान विद्वान। उन्होंने रामकृष्ण की शिक्षाओं के प्रचार के लिए अपने गुरु की मृत्यु के बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना की।

पश्चिम के भौतिकवादी प्रभाव से भारत का बचाए रखना रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य था। इसने मूर्तिपूजा एवं बहुदेववाद समेत हिंदू धर्म को आदर्श, गौरवमंडित रूप में प्रस्तुत किया। पुनरुज्जीवित हिंदू धर्म के लिए विश्व की सांस्कृतिक विजय को इसने अपना साध्य माना।<sup>13</sup>

भारत पर विदेशी शासन का एक हानिकारक परिणाम यह हुआ कि बहुत सारे भारतीय आधुनिक पश्चात्य सभ्यता से विमुख हो गए यद्यपि यह सभ्यता हिंदुस्तान की प्राकृतिक पूजावादी संस्कृति से जिस पर सामंजस्य भारतीय की चेतना आधारित थी, ऐतिहासिक दृष्टि से उच्चतर थी।

धर्म सुधार के कुछ छोटे मोटे आंदोलन भी ये जिन्होंने नई चेतना को स्वर दिया। पुनरुज्जीवित या सुधारवादी रूपों में हिंदू धर्म राष्ट्रीय पैमाने पर संगठित होने लगा। उदाहरणार्थ, भारत धर्म महामंडल समाज 1902 में स्थापित हुआ। हिंदू धर्म का सुधार और हिंदुओं के बीच धार्मिक और गैर धार्मिक शिक्षा का प्रचार इस संगठन का ध्येय था। 1890 में श्री नारायण नृतिया लागा का आंदोलन शुरू किया। नृतिया संप्रदाय दानवा की पूजा करता था और हिंदू समाज की निम्नतम जातियों के लिए इसके संस्कार थे। इनके लिए मदिरा और पाठशाला की स्थापना श्रीनारायण के आंदोलन का कार्यक्रम था।<sup>14</sup>

### थियासफी (ब्रह्मवाद)

नए देशी और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव के कारण भारत में जो धर्म सुधार आंदोलन उदित हुए, उनमें एक थियासफी भी था। भारत में इसे मंडम बनावट्सकी और हनरी स्टील आलकाटन 1879 में शुरू किया और श्रीमती एनी बेसंट ने इसका प्रचार किया। यह आंदोलन इस अर्थ में बजोड़ था कि यह हिंदू धर्म के महान प्रशंसक एक गैर भारतीय द्वारा शुरू किया गया था। थियासफी ने पुरातन हिंदू धर्म के आध्यात्मिक दशन और उनके पुनर्जागरण का स्वीकार किया। इसने जाति, धर्म, प्रजाति और यौन भेद के परे विश्व बंधुत्व के सिद्धांत का प्रचार किया। इसने भारतीयों में राष्ट्रीय भावना के विकास का प्रयत्न किए। श्रीमती बेसंट ने, 1905



में लिखा 'और वाता के अतिरिक्त, भारतीय जादृशों पर अधारित और पश्चिम की विचारधारा और संस्कृति के सम्मिश्रण से संभव (उनके द्वारा शासित या नियंत्रित नहीं) शिक्षा पद्धति और राष्ट्रीय भावना का विकास भारत के लिए आवश्यक है।'<sup>10</sup>

थियासफी ने पूरव के देशों के सार धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन पर जोर दिया। लेकिन इसने प्राचीन हिंदू धर्म को दुनिया का सर्वाधिक आध्यात्मिक धर्म माना। फिर भी थियासफी हिंदुस्तान में जड़ नहीं जमा सकी।

दरमम और राधा स्वामी सरसग जैसे कुछ छोटे-माटे धर्म सुधार आंदोलन भी हुए, जिन्होंने हिंदू धर्म का समसामयिक भारत की सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप बदलने की कोशिश की। अधिक व्यापक आंदोलन की ही तरह इन आंदोलनों में भी हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों के इतने गिद हिंदुओं के समक्ष, उनके सामाजिक संघर्षों के प्रजातंत्रीकरण और उनमें राष्ट्रीय भावनाओं के प्रसार का प्रयत्न किया। वे भी धार्मिक रूप में हिंदुओं के नए राष्ट्रीय जागरण के परिचायक थे।

### समाज सुधार की दिशा में प्रमुख राजनीतिक नेताओं का कार्य

इस तरह धर्म सुधार या धार्मिक पुनर्जागरण के संगठित राष्ट्रीय आंदोलन तो हुए ही लेकिन साथ ही विपिनचंद्र पाल, अरविंद घोष, तिलक और गांधी जैसे महान राजनीतिक नेताओं ने भी धर्म सुधार के कार्य किए। यद्यपि उन्होंने इसके लिए कोई आंदोलन विशेष संगठित नहीं किया। बंगाल में राष्ट्रवाद की भावना अद्विधात्मक धर्म निरपेक्ष हो रही थी। लेकिन शुरू में कुछ दिनों तक इसका रूप धार्मिक था और स्वामी विवेकानंद के नव वेदांतवाद का इस पर बड़ा गहरा प्रभाव था। 'इसीलिए बंगाल के राष्ट्रवादियों ने उपनिषद के पुरातन आदर्श का अपने स्वराज्य आंदोलन का आधार बनाया, जिसके अनुसार मनुष्य को आध्यात्मिक परम तत्व को अपने अंतरतम में खोजना पड़ता है। इसीलिए मा की उपासना शुरू हुई। मा अर्थात् काली के रूप में प्रतिष्ठापित मातृभूमि।'<sup>16</sup>

तिलक ने गीता की फिर से व्याख्या की और बतलाया कि कम इसकी मूल शिक्षा है। उन्होंने कहा कि गीता के दर्शन का मूल तत्व ही भारतीय नहीं समझ पाए हैं, और इसलिए वे निष्क्रियता और भाग्यवाद के शिकार हैं। अगर भारतीय यह समझ लें तो भारत देश सक्रिय प्रयोग से आगे बढ़ सकता है। तिलक ने पुरातन भारतीय धर्म की नवीन व्याख्या द्वारा राष्ट्रवाद का जागरूक जीवन दर्शन प्रदान करने की चेष्टा की।

इस तरह राष्ट्रीय आंदोलन कई अर्थों में सर्वव्यापक धार्मिक आंदोलन का प्रतिफलन भी था। ये राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य था आधुनिक अर्थतंत्र और प्रजातंत्र पर आधारित भारतीय समाज और राष्ट्र की स्थापना और ब्रिटिश शासन से देश की स्वतंत्रता। राष्ट्रवाद धार्मिक शब्दावली में निरूपित हुआ और

धार्मिक रहस्यवाद से परिवेष्टित था। लेकिन जैसे जैसे राष्ट्रवाद की भावना विकसित होती गई, वैसे वैसे वह धार्मिक तत्वों से मुक्त अधिकाधिक धर्म निरपेक्ष होती गई।

### भारत में भौतिकवादी दशन का अभाव

भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की यह खासियत थी कि इसके शुरू के या बाद के भी नेताओं ने न तो कोई भौतिकवादी दशन विकसित करने की कोशिश की और न कोई भौतिकवादी दशन अपनाने की ही। दशन, राजनीति या मस्कृति के क्षेत्र में काम करने वाले राजा राममोहन राय, गाँखले, निलक, बनर्जी वी० सी० पाल, अरविंद घोष लाला लाजपत राय, रवींद्रनाथ टगोर, गांधी, अजुल कलाम आजाद इकबाल, जगदीशचंद्र बाम और अन्य लोगों जैसे भारतीय राष्ट्रवाद के सभी नेताओं ने अपने अलग अलग तौर से, पुरातन धर्मों के नवीकरण का प्रयास किया और उसे समर्थन दिया। लेकिन इनमें किसी ने भी धर्म या ईश्वरत्व की भावना और सत्ता की चुनौती नहीं दी, उसे नकारा नहीं। उनमें से किसी ने भी भौतिकवादी दशन नहीं अपनाया।

नवोदित राष्ट्रवाद के युग में यूरोप में स्थिति इसके विपरीत थी। यह सच है कि यूरोपीय राष्ट्रवाद का सद्घातिक नेतृत्व जिन लोगों के हाथ में था उनमें से अधिकांश जादशवादी (दशनशास्त्र वाले अर्थ में) थे और उन्हें ईश्वर में विश्वास था। ईसाईमत का बास्तेयर जसा धार विरोधी भी देववादी था। लेकिन उस युग की दार्शनिक भावधारों में भौतिकवाद का भी अपना स्थान था। फ्रांसीसी विश्वकोपवादियों में कुछेक जैसे हालबाय और दिदरो भौतिकवादी थे। साथ ही जब यूरोप के विभिन्न देशों में राष्ट्रीय राज्यों और समाजों की स्थापना हो गई, तब उन देशों में बहुत सारे दार्शनिकों का उदय हुआ जिन्होंने भौतिकवादी सिद्धांत को प्रतिष्ठापित किया। हैकल, फ्यूरेबाय, मार्क्स, इनमें प्रमुख हैं। राष्ट्रवाद के युग में, यूरोप ने इन कट्टर भौतिकवादियों के अलावा कट और हबट स्पेसर जैसे अनेयवादी और ह्यूम जैसे मग्यवादी दार्शनिकों का भी जन्म दिया।<sup>17</sup> लेकिन भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में किसी भी विशिष्ट भौतिकवादी, अनेयवादी या सशयवादी दार्शनिक का नाम नहीं जाता।

इसकी वजह संभवतः यह है कि भारतीय राष्ट्रवाद विभिन्न रूप में विकसित हुआ। आधुनिक भौतिकवादी समस्त यूरोपीय मस्कृति का छोटा ही सही लेकिन जगभूत अंश था। चूंकि यह दशन अंग्रेजों का दशन था जिन्होंने भारत पर प्रियय हासिल की थी और उस पर राज्य कर रहे थे, इसलिए राष्ट्रवादी नेता जान अनजाने उससे विमुख सं थे, उससे निच हुए से। दशन के क्षेत्र में भारत का स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होना था, और उसे अपनी परंपरागत दार्शनिक समृद्धि का सहारा लेना था। यह परंपरा मूलतः धार्मिक आध्यात्मिक थी। संभवतः यही वह प्रमुख कारण था जिसके चलते इन नेताओं ने आधुनिक भौतिकवाद ही नहीं मगने

बुद्धिवाद मे भी विशेष रचि नही ली । अ पने बुद्धिवादी दृष्टिकोण के बावजूद राजा राममोहन राय वेदो की नैसर्गिकता म विश्वास करते रहे । उनके उत्तराधिकारी देवेन्द्रनाथ टैगोर ने तक और आदमी की सहज बुद्धि का समन्वय करना चाहा । केशवचन्द्र सेन ने भगवान के पगवर होने का दावा किया और कहा कि उह मानवताको ईश्वर का मदेश देना था । पाल और अरविंद का आध्यात्मिक रहस्यवाद मे विश्वास था । आय समाज के लाजपतराय न वेदा को नसर्गिक माना । भारतीय राष्ट्रवाद के सभसे महान नेता गाधी न, जब कभी उनके सामभ कोई विकट राजनीतिक या सामाजिक समस्या आई, अतरत्मा की वाणी का सहारा लिया ।

विदेशी शासन के कारण, सुधरे हुए मस्तिष्क के राष्ट्रवादिया ने भी, जाने अनजान विदेशी शासन का ही नही बरन विदेशी शासका की संस्कृति का भी, विराध किया । गलत ही सही, लकिन इन दोनो म तादात्म्य दखा गया । चूकि राष्ट्रीय चेतना ही विदेशी सत्ता की स्थिति मे उत्पन हुई थी और यह विदेशी सत्ता इस चेतना के विकास म बाधक थी, इसलिए राष्ट्रवादिया ने प्राय देश की पुरातन संस्कृति के पुराणपथी और रहस्यवादी पहलुओ का सहारा लिया और उह ही अर्वाचीन प्रगतिशील और प्रजातांत्रिक आदोलन का आधार बनाने की कोशिश की । इसके कारण राष्ट्रीय आदोलन मे उलझनें आई, भटकाव आए और विभिन्न सामाजिक धार्मिक दलो की राष्ट्रीय एकता के रास्त मे रुकावटे पदा हुइ । राज नीति धम द्वारा दूषित हा गई और रहस्यवाद के प्रभाव से उसम विकृति आ गई ।

### प्रारंभिक धम सुधार आदोलना की प्रगतिशील भूमिका

शुरू के दिनो म जब भारतीय राष्ट्रवाद अपरिपक्व था, जब अभी उसमे अकुर ही फूट रहे थे, जब वह ब्रह्म समाज जैसे उदारवादी धम सुधार आदोलनो के रूप मे प्रकट हुआ, राष्ट्रीय आदोलन की अपरिपक्वता के ही कारण राष्ट्रवाद ने धार्मिक रूप ग्रहण किया । इसलिए अपनी कमजोरियों के बावजूद इन धम सुधार आदोलनो की अपनी प्रगतिशील भूमिका रही । मध्ययुगीन संस्थाओ के विशाल दुर्भेद्य दुग म इन आदोलनो ने मानो पहली दरार बनाई, पहली बार मानो, धम और ममाज सुधार की भाषा म ही सही, यह घोषणा हुई कि आधुनिक भारतीय राष्ट्र जन्म ले चुका है और सयाना हा रहा है । बाद मे, जब राष्ट्रीय चेतना बढी और राष्ट्रीय आदोलन मजबूत और लडाकू हुआ तब भी पाल और अरविंद जैसे कुछ वामपथी राष्ट्रवादिया द्वारा इस बात के लिए प्रयास किए गए कि पुरातन हिंदू धम के धार्मिक रहस्यवादी दशन को इस आदोलन का आधार बनाया जाए इसके चलत राष्ट्रीय आदोलन का विकास रुका । इन नेताओ ने कुछ लोगो की राष्ट्रीय चेतना को गहराई दी और उसे लडाकू भी बनाया, लेकिन राष्ट्रवाद को हिंदू रहस्यवाद से जोडकर और उस पर आधारित कर इन लोगो न इसके सामाजिक आधार को विस्तृत व्यापक हाने से रोका । राष्ट्रीय आदोलन म मुसलमान बहुत बढी तात्वाद म नही जाए उसके बहुत सारे कारणो मे एक यह भी

गांधी के नेतृत्व में भी राष्ट्रवाद में धम का पुट मिला रहा। यही निर्णायक कारण नहीं था, लेकिन इस कारण की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यह सच है कि गांधी द्वारा संचालित इंडियन नेशनल कांग्रेस के नस्ल में चल रहे राष्ट्रीय आन्दोलन का लक्ष्य था भारत का राष्ट्रीय जनतांत्रिक रूपांतरण, न कि हिंदू राज की स्थापना। यह भी सच है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस राष्ट्रीय संगठन में, सारे जागरूक राष्ट्रीय तत्वों का जमाव था। लेकिन गांधी के इस कथन से कि राजनीति का आध्यात्मिकरण होना चाहिए, चाहे यह धार्मिक नैतिक सिद्धांतों के अनुकूल ही क्यों न हो, वे सारे लोग विमुख हो गए जो राष्ट्रीय आंदोलन को धम निरपेक्ष रखना चाहते थे। साथ ही, इसके राजनीतिक परिकल्पन में रहस्यवादी तत्व का समावेश हुआ और आंदोलन की युद्ध नीति विकृत हुई।

### बुद्धिवाद और भौतिकवाद का विकास

1930 के बाद धीरे-धीरे भारत में बुद्धिवादी और भौतिकवादी दार्शनिक विचार फलने लगे। इसके अनेक कारण थे, जैसे 1914-18 के युद्ध के बाद पश्चिम के राजनीतिक, समाजशास्त्रीय और दार्शनिक साहित्य में भारतीय बुद्धिजीवियों की बढ़ती हुई रुचि। विश्व पूंजीवाद के संकट और समाजवाद के इस दावे के कारण कि यह पूंजीवादी का उत्तराधिकारी है, राजनीतिक रुचि रखने वाले भारतीय युवक पश्चिम के समाजवादी साहित्य और द्वैतात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत पर आधारित मार्क्सवाद का अध्ययन करने लगे। अधिकाधिक भारतीय बुद्धिजीवी मार्क्सवाद का अपनात भी लगे। सावियत यूनियन की सफलताओं के कारण भी बढ़ती हुई संख्या में भारतीय मार्क्सवादी भौतिकवाद की ओर आकृष्ट हुए। कांग्रेस समाजवादियों, साम्यवादियों, रायवादियों टैंगोरवादियों और ट्राट्स्कीवादियों जैसे राजनीतिक दलों ने मार्क्सवाद को अपने जीवन दर्शन के रूप में अपनाया। मार्क्सवादी भौतिकवादी विचारधारा के अलावा एक अन्य विचारधारा भी भारत में जोर पकड़ रही थी। भारत में बुद्धिवादियों की संख्या बढ़ रही थी।

शिक्षित और बुजुर्ग वर्ग ही राष्ट्रवाद के अग्रणी और पथ प्रदर्शक थे। नए पूंजीवादी समाज को उन्होंने अपनी भावभूमि बनाया। यह पूंजीवादी समाज ऐतिहासिक दृष्टि से आगे बढ़ा हुआ समाज था। धीरे-धीरे मध्ययुगीन समाज व्यवस्था की जगह नई समाज व्यवस्था कायम हुई। राष्ट्रवादियों ने पूंजीवाद के आर्थिक आधार की परिकल्पना स्वीकार कर ली। वे समाज का मुक्त विकास चाहते थे। उदारवाद उदीयमान पूंजीवाद का दर्शन था। इसमें ऐसे सिद्धांतों का समावेश था जिनसे पूंजीवाद का विकास की गारंटी होती थी। जैसे प्राक् पूंजीवादी व्यवस्था की अपेक्षा पूंजीवाद उच्चतर सामाजिक तंत्र था वैसे ही राष्ट्रीय समकन, व्यक्ति स्वातंत्र्य, प्रजातंत्र, मानव, मानव के समानाधिकार, प्रतिनिधि मन्त्राण बुद्धिवाद, जाति सिद्धांतों से बना उदारवाद प्राक् पूंजीवादी दर्शन की अपेक्षा उच्चतर दर्शन था। पुराने दर्शन अधिकांशतः धार्मिक पुराणपर्य पर निर्भर थे

और जन्म पर आधारित ओहदा और विशेषाधिकार के रक्षक थे।

युक्तिसंगत तो यह था कि भारतीय बुद्धिजीवी, जो भारतीय राष्ट्रवाद के अगुआ थे, उदारवादी दर्शन को पूणत अपनाते। लेकिन, चूँकि उदारवाद पश्चिम में पैदा हुआ था और चूँकि भारतीय जनता पर पश्चिमी शक्ति का शासन था, इसलिए उन लोगों ने पुराने हिंदू धर्म को ही सक्रिय बनाया, और या तो उसे अपने शुद्ध सनातन रूप में पुनर्ज्जीवित किया या उदारवादी दृष्टिकोण और आधुनिक भारतीय समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल उसमें कुछ परिवर्तन किए।

### मुसलमानों में राष्ट्रीय जागरण

#### उनमें राष्ट्रीय भावना के अक्षिप्र विकास के कारण

मुसलमानों में राष्ट्रीय जागरण हिंदुओं की अपेक्षा धीरे-धीरे आया। इसके ऐतिहासिक और धार्मिक कारण थे। औरंगजेब के परवर्ती काल में जब मुगल साम्राज्य का विघटन हुआ, उस वक्त उनके हिंदू राज्य कायम हुए। फिर भी मुसलमान हरदम यह समझते रहे कि वे भारत के शासक हैं। वे खासकर अंग्रेजों के खिलाफ थे, जिन्होंने राजनीतिक सत्ता उनसे छान ली थी। अंग्रेजों ने सिपाही विद्रोह के समय बहादुरशाह को तख्त से हटा दिया और वह उस वक्त तथ्यत नहीं तो विधानतः सारे भारत का सम्राट था। सिपाही विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने जो मुसलमान विरोधी नीति अपनाई, उससे मुसलमानों में अंग्रेज विरोधी भावनाएँ आईं। इसके कारण मुसलमान भारत में अंग्रेजों द्वारा लाई गई नई संस्कृति और शिक्षा के संपर्क से वंचित रहे। वे उस शिक्षा के प्रभाव में आने से बचे और पुराने पथी इस्लाम के साथ और जमकर सट रहे।

अंग्रेजों की भारत विजय की प्रक्रिया में मुसलमान बड़ी तेजी से गरीब हुए। 'भारत के बारीक और नपुण्यमूलक उद्योगों में से बहूतेरे मुसलमानों के हाथ में थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की वित्तीय नीति के कारण ये लोग बर्बाद हुए। प्राकृतिक भारत में बड़े-बड़े ओहदों पर सनातन शासन में पढाई लिखाई के पक्ष में, मुसलमान लोग ही जमे हुए थे। लेकिन उच्च और मध्यमवर्ग के बहूत सारे लोग अब भिखमगी की हालत में आ गए। इसमें कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं कि उन्नीसवीं सदी के प्रारंभ में मुसलमानों में अंग्रेजों के प्रति घोर अविश्वास था, क्योंकि इन लोगों ने उनकी शक्ति क्षीण की थी। उन्हें पाश्चात्य संस्कृति पर भी अविश्वास था, क्योंकि यह अंग्रेजों से जुड़ी हुई थी।'<sup>48</sup>

हिंदुओं ने नई शिक्षा का फायदा उठाया। उनके यहाँ शिक्षित वर्ग का उदय हुआ, और उनमें से कुछ लोगों ने उदारवाद के सिद्धांत अपनाए, दूसरे धर्मों का अध्ययन किया और सुधार आंदोलन संगठित किए। दूसरी तरफ मुसलमान नई शिक्षा से विमुख होते गए।

हर देश में सदा आधुनिक बुद्धिजीवी वर्ग और बुजुर्गों ने ही राष्ट्रवाद नतुत्व किया है। उदीयमान पूँजीवाद के युग में बुद्धिजीवी और पूँजीपति

जो बुजुआजी समाज के समर्थक पोषक थे, राष्ट्रीय आंदोलनों का संगठन किया। भारत में नए बुद्धिजीवी और पूँजीपति वर्ग के लोग मुख्यतः हिंदू समाज से आए और वे भारतीय राष्ट्रवाद के नेता और प्रदर्शक रहे।

उन्नीसवीं सदी के अंत में मुसलमान आधुनिक शिक्षा की ओर मुड़े। धीरे-धीरे उनके बीच भी शिक्षित आधुनिक बुद्धिजीवी वर्ग का उदय हुआ। इस बुद्धिजीवी वर्ग के कुछ लोगों ने धीरे-धीरे राष्ट्रीय दृष्टिकोण भी अपनाया। साथ ही मुसलमानों में भी व्यापारिक और औद्योगिक बुजुआजी का जन्म हुआ, और उनके बीच भी राष्ट्रवाद की भावना फली।

इस्लाम का आधारभूत चरित्र भी भारतीय मुसलमानों में देर से राष्ट्रवाद के उदय का एक कारण था। किसी भी अन्य धर्म की अपेक्षा इस्लाम अधिक कट्टरता से अपने अनुयायियों की एकता पर जोर देता है। यह अपने अनुयायियों को विश्व बहुत्व की शिक्षा देता है। यह सारे विश्व के मुसलमानों का सावजनीन संगठन है। इस तरह यह राष्ट्रीयता के विकास के रास्ते में अवरोध प्रस्तुत करता है क्योंकि राष्ट्रीयता का सीमित भूखंडीय आधार है और इस्लाम या तो अखिल इस्लामवाद या मानवतावाद को प्रथम देता है।

अगर किसी दश विशेष में, जैसे अरब या तुर्की में, मुख्यतः मुसलमान ही रहते हैं और वहाँ आर्थिक पूँजीवादी विकास हो चुका हो, तो वहाँ के मुसलमानों में राष्ट्रीय चेतना का प्रादुर्भाव हो सकता है। या, किसी मध्ययुगीन धर्म की अपेक्षा इस्लाम राष्ट्रीयता के उदय में अधिक रुकावट डालता है, लेकिन समाजवाद जैसे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम को मुसलिम आवादी के निम्न बुजुआ और गरीब तबकों में बड़ी जल्दी और तेजी से मायता मिली।

इस लेखिका को अपनी बातचीत के दौरान मालूम हुआ कि मुसलमान नवयुवक समाजवादी नेता जवाहर लाल नेहरू की ओर किसी भी राजनीतिक नेता की अपेक्षा अधिक भुके हुए थे। यह स्पष्ट है कि छात्रों और नौजवानों के संगठनों में समाजवाद का प्रसार हुआ है। पंजाब की सोशलिस्ट पार्टी में अधिकतर मुसलमान हैं, और फिर, फ्रंटियर सोशलिस्ट पार्टी में भी अधिकांश मुसलमान हैं और भारत में फ्रंटियर सोशलिस्ट पार्टी की सदस्यता सबसे अधिक है।<sup>19</sup> मेरा ध्यान है कि मुसलिम जन साधारण की प्रवृत्तियों अंतर्गत शक्ति बहुत अधिक है और शायद इसका यह कारण है कि हिंदुओं की अपेक्षा उनमें पारस्परिक साहचर्य की स्वतंत्रता अधिक है। चलना शुरू कर दें तो वे समाजवाद की दिशा में बड़ी तेजी से बढ़ेंगे।<sup>20</sup>

इस्लाम का उदय ही विशेषाधिकार प्राप्त सामाजिक श्रेणियों के विरुद्ध अरबों की साधारण जनता के प्रजातान्त्रिक उद्वेलन का परिणाम था। इसलिए इसका स्वर स्वभावतः जनतांत्रिक है। इस्लाम सामाजिक साम्य की शिक्षा देता है इसलिए मुसलिम आवाज के बीच अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद का प्रचार अधिक आसानी से होता है।

राष्ट्रीयता के रास्ते पर प्रगति की दृष्टि से मुसलमानों की अपेक्षाकृत निष्क्रियता के बावजूद, उनके बीच भी कालक्रम से कई धार्मिक पुनरुज्जीवन और धर्म सुधार के आंदोलनों का जन्म हुआ। लेकिन ये आंदोलन हिंदुओं के बीच हुए ऐसे ही आंदोलनों जितने शक्ति संपन्न नहीं हो सके। साथ ही, इनमें अधिकांश में राष्ट्रीयता का अभाव था। इस तरह के चार प्रमुख आंदोलन हुए। दिल्ली के शाह अब्दुल अजीज, बरेली के सैयद अहमद, जौनपुर के शेख करामत अली और फरीदपुर के हाजी शरियत उल्ला इन आंदोलनों के जनक थे।<sup>21</sup>

मूलतः इन चार आंदोलनों का उद्देश्य पुराने धर्म का पुनरुज्जीवन ही था।

### अहमदिया आंदोलन

1889 में मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा स्थापित अहमदिया आंदोलन कमोवेश उदारवादी सिद्धांतों पर आधारित था। इसने अपने को मुसलिम पुनर्जागरण का ध्वजधारी कहा। ब्रह्म समाज की तरह इसे भी समस्त मानवता के विश्वधर्म के सिद्धांत में विश्वास था। इस धर्म के संस्थापक पाश्चात्य उदारवाद वियासफी और हिंदुओं के धर्म सुधार आंदोलन से काफी प्रभावित थे।

अहमदिया आंदोलन ने जेहाद अर्थात् गैर मुसलमानों के खिलाफ धर्म युद्ध के सिद्धांत का विरोध किया। इसे सभी राष्ट्रों संप्रदायों के पारस्परिक भ्रातृत्व के सिद्धांत में आस्था थी। इस आंदोलन ने भारतीय मुसलमानों में पाश्चात्य उदारवादी शिक्षा का प्रचार किया। इसके लिए अहमदिया लोगों ने कई स्कूल-कालेज खोले और अंग्रेजी तथा देशी भाषाओं में किताबें और पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित कीं। अपने उदारवादी दृष्टिकोण के बावजूद, वहाँई आंदोलन की ही तरह जो पश्चिम एशिया के देशों में पल्लवित हुआ, अहमदिया आंदोलन भी रहस्यवाद से दूषित था। फिर भी इसने इस्लाम की ओर से पाश्चात्य उदारवादी भावनाओं को आत्मसात करने की चेष्टा की।

जसा पहल कहा जा चुका है ऐतिहासिक कारणों से मुसलिम संप्रदाय राष्ट्रीय प्रजातान्त्रिक प्रगति के पथ पर हिंदुओं के बाद आया। 1857-58 के विद्रोह की दुखद असफलता से पुरानी सभ्यता का अंत होता है और भारतीय मुसलमानों के लिए राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक भंग का काल शुरू होता है। इसके कारण नई व्यवस्था के प्रति उनका रोप उनका विलगाव उनकी दमित घृणा भावना और भी अधिक तीव्र हुई। इस स्थिति का हल यह था कि अपने को नई स्थिति के अनुकूल बनाया जाए जा नई शक्तिपदा हो गई थी उनका इस्तमाल किया जाए और अंग्रेजी शिक्षा के फलस्वरूप प्रगति के जो नए जस्त रचे गए थे उन्हें अपनाया जाए।<sup>22</sup>

इस नई वास्तविकता से दीर्घकालीन पसायन संभव नहीं था। शीघ्र ही, मुसलमानों में भी नई शिक्षा का प्रचार हुआ और उनके बीच भी नए बुद्धिजीवी वर्ग का उदय हुआ। वे व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में भी आए-जाए। इन नए

शिक्षित मुसलमानों और मुसलमान व्यापारियों और उद्योगपतियों में जो प्रगतिशील तत्व थे, उनमें राष्ट्रीय दृष्टिकोण आता गया और वे राजनीति में राष्ट्रीयता और सामाजिक मामलों में प्रजातांत्रिक सुधार के रास्ते पर अग्रसर हुए।

### अलीगढ़ आंदोलन

मुसलमानों के प्रथम राष्ट्रीय नवजागरण की अभिव्यक्ति जिस आंदोलन में हुई, उसने मुसलमानों को राजनीतिक तौर पर जागरूक बनाने और उनके बीच आधुनिक शिक्षा का प्रचार करने का प्रयास किया। सैयद अहमद खाँ इस आंदोलन के अगुआ थे। उनको शायर उवाजा अल्ताफ हुसैन हाली मौलवी नजीर अहमद और मौलवी शिवली नुमानी जैसे योग्य सहयोगी भी मिल गए।

सर सैयद अहमद खाँ ने जिम् उदारवादी समाज सुधारक और सांस्कृतिक आंदोलन की शुरुआत की उसे अलीगढ़ आंदोलन के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस आंदोलन ने 1875 में अलीगढ़ में महामदन एंग्लो आरियटल कालेज की स्थापना की। इसी कालेज में 1890 में अलीगढ़ विश्वविद्यालय का रूप लिया। इसके साथ एक आन इंडिया मुसलिम एजुकेशन काफ़ेस भी गठित हुआ।

अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य था धार्मिक जात्या को स्थिर रखते हुए मुसलमानों में पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार करना। इसने जिन शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की उनमें धर्म निरपेक्ष शिक्षा के साथ ही धार्मिक शिक्षा भी दी जाती थी। इसने मुसलिम संप्रदाय में समाज सुधार का भी काम किया। अलीगढ़ आंदोलन ने कमोन्स जाधुनिक ढंग पर भारतीय मुसलमानों के विशिष्ट सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का प्रयत्न किया। इसने बहु विवाहवाद की और विधवा विवाह पर लगे सामाजिक प्रतिबंधों की तीव्र भ्रमना की इस्लाम में विधवा विवाह की अनुमति है लेकिन जो लोग हिंदू धर्म छोड़कर मुसलमान हुए वे वैसे कुछ लोगों में विधवा विवाह व्यवहारत निषिद्ध था। अलीगढ़ आंदोलन कुरान की उदारवादी व्याख्या पर आधारित था। इसने आधुनिक उदारवादी संस्कृति और इस्लाम में तालमेल बैठाने की कोशिश की। अलीगढ़ आंदोलन के गुरु होने पर, बंबई पंजाब, हैदराबाद और अन्य जगहों में भी स्वतंत्र कमावश प्रगतिशील आंदोलन शुरू हुए।

### सर मुहम्मद इकबाल

विश्वविद्यालय शायर सर मुहम्मद इकबाल ने भारतीय मुसलमानों की इतिहास में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। उन्होंने उदारवादी आंदोलन का समर्थन किया, लेकिन साथ ही उदारवादी मुसलमानों से यह आग्रह भी किया कि वे जाति और राष्ट्र के नाम पर इस्लाम के व्यापक मानवतावादी मित्रता का बहिष्कार न करें।<sup>4</sup>

इकबाल ने यूरोपीय सभ्यता को जमानुषिक, हिंस्र, परभक्षी लुब्ध और



ह्लासो मुख कहा । यूरोपीय सभ्यता की भत्सना के लिए उहोने नीरशे, शापनहावर, स्पेग्लर, काल माकम जस परस्पर विरोधी विचारवाल लेखवा की उक्तियो को उद्धत किया । अपनी कविताआ मे, जो फारसी और उदू साहित्य की उत्कृष्ट रचनाए हैं, उहोने बडी भावपूण शली मे यूरोपीय सभ्यता पर चोट की है । वे मूलत मानवतावादी थे और इस्लाम का व्यापक मानवतावादी धर्म मानत थे ।<sup>25</sup>

लेकिन उनके जीवन के परवर्ती काल मे इकबाल मे प्रतिक्रियात्मक प्रवृत्ति भी देखन मे आती है । उहोने व्यवस्था के रूप मे प्रजातन्त्र का विरोध किया और वे भारतीय राष्ट्रीय आदालन के विरोधी हो गए ।<sup>6</sup> माडन इस्लाम इन इडिया नामक अपनी पुस्तक मे डब्ल्यू० सी० स्मिथ ने लिखा है पूजीवाद के बढ़ने 'पाश्चात्यवाद' के विरोध का यह परिणाम था कि वे उदारवाद विरोधी प्रतिक्रियावादिया के शिकार हो गए । इस तरह कल के 'यायसगत और विश्व व्यापक भ्रातृत्व का सबसे नेक स्वप्नद्रष्टा सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी संप्रदायवादिया का हिमायती होकर रह गया ।'

### अन्य मुसलिम सुधार आदोलन

कालक्रम से मुसलिम औरता की मुक्ति और पर्दा प्रथा के उमूलन के आदोलन भी हुए । बंबई मे इस आदोलन का अगुआ थे तयबजी जो प्रबुद्ध और प्रगतिशील मुसलमान थे । मयुक्त प्रांत मे शेख अब्दुल हलील शरार (1860-96) ने, जो बड़े अच्छे लेखक और पत्रकार थे, पर्दा प्रथा के खिलाफ जोरदार सघष किया ।

मुसलमाना मे उदारवादी विचारों भावनाओं के प्रसार से, मुसलिम औरतों की सामाजिक स्थिति का सुधारने वाले और उनके लिए हानिकर रीति रिवाज का खतम करने वाले जादोलना को काफी बल मिला । बाल विवाह के साथ-साथ बहु विवाह प्रथा भी खतम होन लगी । आल इडिया मुसलिम काफरेस मुसलिम औरता की शिक्षा के लिए नियमित और विशिष्ट जायिक अनुदान देता रहा । सारे देश मे मुसलमान औरता के लिए मुसलमाना न व्यक्तिगत और संगठित तौर पर अधिकाधिक शिक्षण नस्थाए स्थापित की । धीरे धीरे मुसलिम औरता मे शिक्षा का प्रसार बढा ।

इस तरह धर्म और समाज सुधार के आदोलन मुसलमाना मे भी तेजी से बढे । तुर्की और अरब की राष्ट्रीयता के उदय के कारण, और तुर्की मे राष्ट्रीय धर्म निरपेक्ष राज्य सत्ता के उद्भव के कारण हिंदुस्तानी मुसलमाना का दृष्टिकोण भी व्यापक हुआ । तुर्की के जाधुनिकीकरण का यह प्रभाव पडा कि अधिकाधिक भारतीय मुसलमानों को भी चिंतन शली आधुनिक हुई । भारत मे राष्ट्रीय जादोलन के उदय और विकास के कारण भी अधिकाधिक मुसलमान भारतीय राष्ट्रीयता का प्रभाव मे आए । बाद मे साम्यवादियो, समाजवादियो या जवाहरलाल नहरू जैसे वामपंथी राष्ट्रवादियो के नतृत्व मे जो स्वतंत्र मजदूर और किसान जादोलन उभरे, उनके चलते भी मुसलमान जनता मे राष्ट्रीय और वर्गीय चेतना का प्रादुर्भाव

हुआ। इन आंदोलनों से दोनों संप्रदायों के लोगों का स्वस्थ प्रशिक्षण हुआ और राष्ट्रीय और वर्गीय हित में सहयोग का क्षेत्र तैयार हुए। आर्थिक संरचना और विदेशी शासन के चलते वे साथ आए और उन्होंने सारे राष्ट्र की मुक्ति के लिए सहयोग का रास्ता अपनाया।

**परवर्ती काल में धर्म सुधार आंदोलनों की प्रतिक्रियावादी भूमिका**

हमें यह भी खयाल रखना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रवाद का शुरुआत के दिनों में, जब यह अभी उभर रहा था तथा कुछ ही लोगों तक सीमित था राष्ट्रीयता ने धर्म सुधार आंदोलनों का रूप लिया। इसी रूप में राष्ट्रीय जागरण शुरू शुरू में परिलक्षित हुआ। लेकिन बाद के दिनों में जब नए वर्ग और संप्रदाय आए और उनमें राष्ट्रीय वर्ग या दल चेतना विकसित हुई, और फिर जब राष्ट्रीय आंदोलन का आधार बहुवर्गीय बहुसंप्रदायिक हो गया तब इसी धर्म सुधार आंदोलनों में जविकाश राष्ट्रीय चेतना के विकास के रूप में होकर इसके विकास में अवरोध का काम करने लगे। इनमें से कुछ राष्ट्र विरोधी विघटन और स्वतंत्रता के संयुक्त राष्ट्रीय आंदोलन के विरोधी सिद्ध हुए। उनकी भूमिका में यह परिवर्तन इसलिए आया कि वे राष्ट्रीय धर्म सुधार आंदोलन न रह कर धार्मिक संप्रदायिक आंदोलनों में परिणत हो गए। यह बात खासकर 1918 के बाद परिलक्षित होती है। इस तिथि के बाद देश में प्रगतिशील राष्ट्रीय और वर्गजन्य आंदोलनों में तीव्रता आई। ऐसी परिस्थिति में कुछ पुराने और कुछ नए धार्मिक संप्रदायिक आंदोलनों में निहित स्वार्थों के छिपे हुए हथियार का काम किया। उन्होंने भारतीय जनता की लगातार बढ़ती हुई राष्ट्रीय एकता को कमजोर किया और साथ ही विभिन्न संप्रदायों के गरीबों की आर्थिक और राजनीतिक एकता का भी। ये गरीब लोग मजदूर मगठन किसान सभा और ऐसे अन्य संगठनों के माध्यम से निहित स्वार्थों के विरुद्ध खड़े हो रहे थे।

साथ ही, धार्मिक संप्रदायिक आंदोलनों में ब्रिटिश हितों की भी सेवा का। संप्रदायिक प्रतिनिधित्व और संप्रदायिक चुनाव क्षेत्रों के जागमग से वस्तुतः राष्ट्रीय एकता का नक्सान हो रहा था क्योंकि इनके चलते संप्रदायिक विरोध भावना को प्रश्रय मिल रहा था।

सभी अध्यात्मज्ञानी और राजनीतिविद यह मानते हैं कि यह काल पूजावाद के साधारण ह्रास का काल था और सब जगह प्रगतिशील राष्ट्रीय और वर्गशक्तियाँ लगातार बढ़ती जा रही थी। ऐसे वक्त देशों और विदेशी निहित स्वार्थों को धार्मिक रहस्यवाद और संप्रदायवाद से राष्ट्रीय हित के आंदोलनों को कमजोर करने में काफी सफल सहयोग प्राप्त हुआ।

सदभ

- 1 देखें लास्की और वीजबाड ।
- 2 काडवल प० 27 28 ।
- 3 देखें लास्की ।
- 4 बी० सी० पाल बख (2) द्वारा उद्धृत 184 ।
- 5 देखें टोनी लास्की हान्स काहन वीजबोड ।
- 6 काहन प० 55 56 ।
- 7 बख प० 6 ।
- 8 राजा राममाहन राय प० 5 ।
- 9 आर० पी० दत्त प० 273 75 ।
- 10 रवाद्रनाथ टगोर ब्रजद्रनाथ सील द्वारा उद्धृत पृ० 95 ।
- 11 दख मक्समूलर प० 64 ।
- 12 काहन पृ० 67 68 ।
- 13 देखें विवेकानंद पृ० 193 95 ।
- 14 देखें काहन प० 73 ।
- 15 एनी बेसट बख (2) द्वारा उद्धृत प० 174 ।
- 16 बख (2) प० 142 ।
- 17 देखें लास्की टोनी लान एगल्स वीजबोड ।
- 18 ओ मेली प० 392 93 ।
- 19 एडिव प० 339 340 ।
- 20 जवाहरलाल नेहरू प० 577 ।
- 21 देखें आ मेली ।
- 22 देखें काहन प० 36 ।
- 23 ओ मेली प० 398 ।
- 24 देखें सर एम० इकवान प० 227 ।
- 25 देखें ओ मेली प० 406 ।
- 26 एम० आर० स्मिथ पृ० 156 ।

## भारतीय राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति के रूप में राजनीतिक आंदोलनों का उद्भव

### राजनीतिक राष्ट्रवाद, विदेशी शासन परिणाम

अंग्रेजों की भारत विजय और भारत पर अंग्रेजी शासन के पीछे ब्रिटिश हितों की रक्षा की भावना काम कर रही थी। इसलिए भारत में अंग्रेजी सत्ता का उपयोग मूलतः ब्रिटिश हितों की रक्षा और विकास के लिए हुआ। चूंकि भारतीय और ब्रिटिश हितों में विरोध था, इसलिए ब्रिटेन और भारतीय जनता के विभिन्न वर्गों और दलों में, विभिन्न जगहों में पारम्परिक द्वन्द्व का जन्म हुआ। राजनीतिक राष्ट्रवाद हितों के इस संघर्ष का परिणाम था और इसके कारण देश में कई राजनीतिक आंदोलनों का उद्भव हुआ। इन आंदोलनों के लक्ष्य थे ? राजनीतिक सत्ता में अधिकाधिक सहभागिता और फिर क्रमशः डोमिनियन स्टेट्स, होमरूल और पूर्ण स्वराज्य। अपने विभिन्न सामाजिक, जातिक और जातीय हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक सत्ता हस्तगत करने के भारतीय जनता और उसके विभिन्न वर्गों के प्रयास राजनीतिक आंदोलनों में मूर्तिमान हैं।

भारत पर ब्रिटेन के निरंकुश शासन के कारण औद्योगिक पुर्जुआजीयों भारत का अनियंत्रित औद्योगिक विकास करने में दिक्कत हो रही थी। राज्य व्यवस्था के प्रमुख पदों पर अंग्रेजों के एकाधिकार के कारण शिक्षित वर्ग के लोगों का नौकरियां प्राप्त करने की अपनी यासगत जाकाक्षा की पूर्ति में दिक्कत हो रही थी। धरती के बेटे, किसान यह देखते थे कि अंग्रेजों द्वारा लाई गई नई भूराजस्व व्यवस्था उनकी बढ़ती हुई गरीबी का कारण थी। महाराज मजदूर वर्ग के लोग देखते थे कि यह विदेशी अप्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था उन्हें अपनी हालत सुधारने और जिस मजदूरी तंत्र में उनका गोपण हो रहा था उसे बदलने के लिए आवश्यक वर्ग संघर्ष को विकसित करने से रोक रही थी।

फिर समस्त भारतीय जनता ने यह भी देखा कि इस विदेशी शासन के कारण उनका अपना साधारण सामाजिक, जातिक और सांस्कृतिक विकास नहीं हो पा रहा था। राजनीतिक सत्ता से उनकी यह भी अपेक्षा थी कि दक्षिण अफ्रीका, चेना, मलाया, लका जादि उपनिवेशों या अर्द्ध उपनिवेशों में प्रचलित जाति विभेद

और भारतीय हिता की जवहेलना आदि कुरीतिया समाप्त की जाए। चूकि विदेशी शासन गुलाम देश का स्वतंत्र विकास जवरुद्ध करता है, इसलिए साधारण जनता में राष्ट्रीय भावनाएँ स्वतः उभरती है।<sup>1</sup>

### राजनैतिक आदोलन के प्रथम अकुर

सगठित आदोलन के रूप में भारतीय राष्ट्रवाद का उद्भव, उनीसवीं सदी के अंतिम कुछेक दशका में हुआ। लेकिन इसके प्रथम अकुर उनीसवीं सदी के प्रारंभ में भी दृष्टिगोचर होते हैं। प्रबुद्ध हिंदू बुद्धिजीवी वर्ग ने अंग्रेजों द्वारा लाई गई आधुनिक शिक्षा पाई थी और इस शिक्षा के माध्यम से इस वर्ग के लोग आधुनिक पाश्चात्य, प्रजातांत्रिक विचारधाराओं के संपर्क में आए थे। इस वर्ग की उदीयमान राष्ट्रीय चेतना का 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के रूप में धार्मिक प्रस्फुटन हुआ। इसी प्रारंभिक काल में 1843 में स्थापित ब्रिटिश इंडिया सोसायटी और 1851 में स्थापित ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो उन दिनों के राजनीतिक दलों के एकीकरण से बना था, जैसे धर्म निरपेक्ष राजनीतिक संगठनों का भी जन्म हुआ।

शुरू के राजनीतिक दल भारतीय राजनीतिक राष्ट्रवाद के उद्भव के परिचायक हैं। लेकिन ये दल महज कुछेक व्यक्तियों से बने थे और इनका कोई सामूहिक आधार नहीं था। इनका अखिल भारतीय आधार संभव भी नहीं था, क्योंकि सारा भारत इन संस्थाओं की स्थापना के बहुत बाद अंग्रेजों के अधिकार में आया। सगठित अखिल भारतीय आदोलन के रूप में (यद्यपि अभी भी संकुचित सीमित सामाजिक बुनियाद पर) भारतीय राष्ट्रवाद का उनीसवीं सदी के अंतिम दशका में जन्म हुआ जब इसके लिए स्थिति परिपक्व हो गई थी।

लेकिन इस सगठित राष्ट्रीय आदोलन के उदय का सर्वेक्षण करने के पहले हम 1857 के विद्रोह की चर्चा करेंगे। पुराने भारतीय समाज के कुछ वर्गों की सत्ता और शक्ति का अंग्रेजों के भारत आगमन से अपहरण हुआ था। 1857 का विद्रोह उनकी ओर से भारत से अंग्रेजों को निकाल भगान और प्राक् ब्रिटिश भारत की सामाजिक राजनीतिक स्थिति की ओर प्रत्यावर्तन का अंतिम संशक्त प्रयास था।

### 1857 के विद्रोह के कारण

भारत पर अंग्रेजों की राजनीतिक विजय इस विजय द्वारा उदभूत आर्थिक तत्त्वा और कायवाहियों एवं नए शासन द्वारा प्रवर्तित नवाचार से भारतीय समाज के जो हिस्से आक्रांत हुए, उनका मंचित अनतोष 1857 के विद्रोह का कारण हुआ। यह कहना गलत होगा कि 1857 का विद्रोह महज सिपाहियों का विद्रोह था। इसका सामाजिक आधार अधिक व्यापक था। डा० डफ ने कहा है

‘अगर यह कौड़ी बनना भर होना, और जनता की इसके प्रति सहानुभूति नहीं होती और इस जनता की मदद नहीं मिली होती तो जिम तरह की कुछ

निर्णायक जीतें हमें मिली, वे इसे खतम कर देने के लिए काफी थी और सच यह है कि यह फौजी बलवा भर नहीं था, वरन् था जन विद्रोह, जन-क्रांति

प्रारंभ से ही यह धीरे-धीरे जन विद्रोह का रूप लेता गया है, सिपाहिया की फौज के बाहर हजारों लाखों के जनसमुदाय का ब्रिटिश प्रभुत्व और सत्ता के विरुद्ध विद्रोह।'

अंग्रेजों ने देशी राज्या को अपने अधिकार में कर लेने की नीति अपनाई, खासकर लाड डलहौजी के शासन काल में, जिसके फलस्वरूप अनेक देशी सामंती राज्यों का विघटन हुआ। अंग्रेजों की गई राजस्व व्यवस्था के कारण भारतीय किसानों की स्थिति दिन पर दिन बुरी होती गई थी। ब्रिटिश उद्योगों के मशीन निर्मित सामान बड़ी तेजी से भारतीय बाजार में आए जिसके फलस्वरूप हजारों लाखों की तादाद में भारतीय कारीगर और हस्त शिल्पकार बर्बाद हुए। ये सब 1857 के विद्रोह के मुख्य कारण थे और इन सभी सामाजिक वर्गों का गंभीर असंतोष इस विद्रोह में परिलक्षित है।

अपहृत सामंती सरदारों ने विद्रोह की जगुआई की, और वे अपने खोए हुए भूभाग वापस लेना चाहते थे। अनपहृत रजवाड़ों में भी इस बात का डर बना हुआ था कि कभी उनके राज्य का अपहरण हो सकता है, इसलिए उन लोगों में भी कुछेक विद्रोह में शामिल हुए।

अंग्रेज मालिकों के नीचे के और अग्रयण वागानों के मजदूरों में भी असंतोष था क्योंकि विदेशी मालिकों के अधीन उनके जीवन और श्रम की स्थिति काफी दयनीय थी। उन लोगों में भी ब्रिटेन विरोधी भाव जगे।

कुछ और कारणों से भी लोगों के बीच अंग्रेज विरोधी भावना बढ़ी। यूरोप के ईसाई मिशनरियों के धर्म परिवर्तन सवधी उत्साह के कारण लोगों को यह संदेह हुआ कि अंग्रेज भारतीयों को ईसाई बनाना चाहते हैं। पंडितों और मौलवियों ने तो जानबूझ कर इस भावना को प्रश्रय दिया, क्योंकि विधि व्यवस्था को धर्म निरपेक्ष बनाना, सती जसी प्रथा का उन्मूलन आधुनिक शिक्षा की स्थापना जिसने साधारणतः विश्व और सामाजिक सवधों के बारे में धार्मिक विचारों को चुनौती दी, आदि अंग्रेजी शासन के कार्यों से पंडितों और मौलवियों की शक्ति क्षीण हुई और उनका प्रभाव घटा।

कुछ और कारण भी थे। बल प्रयोग द्वारा देश के गुलाम बनाए जाने और लोगों के जीवन पर नई आर्थिक शक्तियों के हानिकारक प्रभाव के फलस्वरूप अविश्वास और शत्रुता का जो वातावरण तैयार हुआ था, उसके कारण रेलवे और तार व्यवस्था की स्थापना जैसे प्रगतिशील काम के बारे में यह समझा गया कि इस जादू टोने के जरिए यं गोर जादूगर सार देश को लाह की जंजीरों में बांध देना चाहत है। इस तरह ब्रिटिश सरकार के प्रति लोगों की शत्रुता की भावना बढ़ी। यह मूलतः पुराने भारतीय समाज के उन हिस्सों का विद्रोह था जिनका

भारत पर अंग्रेजों की राजनीतिक विजय और उनके द्वारा देश में लाए गए आर्थिक तत्वों के परिणामस्वरूप विनाश अवश्यभावी था।

अंग्रेजों ने बड़ी क्रूरता से इस आंदोलन का दमन किया।<sup>3</sup> इसकी असफलता के बहुत सारे कारण थे। विद्रोहियों में एकता का अभाव था। उनके पास एक जसी सैनिक रणनीति नहीं थी। उनमें परस्पर समन्वय का भी प्रभाव था। विद्रोह सावजनीन भी नहीं था और नेतृत्व कारगर नहीं था। विद्रोही दला में परस्पर वग स्वार्थों का संघर्ष भी था, जैसे एक तरफ जमींदारों और देशी रजवाड़ा एवं दूसरी ओर खेती करने वाले किसानों के बीच संघर्ष।

अपने विरुद्ध एकता के अभाव का अंग्रेजों ने पूरा फायदा उठाया। देशी सरदारों ने जल्दी ही यह जान लिया कि अगर वे किसानों और कारीगरों के बहुत नजदीक आएंगे तो नेतृत्व धीरे-धीरे उनके हाथ से निकल जाएगा।<sup>4</sup> इसके अलावा अंग्रेजों ने खास तरीकों से वर्गों के इस संयुक्त मोर्चे में फूट डाली।

देशी रजवाड़ा को ब्रिटिश इंडिया में पूरी तरह आत्मसात करने की नीति छान्द दी गई। किसानों पर जमींदारों की पकड़ और अधिक मजबूत कर दी गई, अंग्रेजों ने बेगार के सवाल पर जमींदारों का साथ दिया बड़े-बड़े किसानों को कुछ विशेषाधिकार देकर और किसानों की जमीन की खरीद-विक्री के लिए कायदे बनाकर अंग्रेजों ने किसानों की भी एकता खत्म करने की कोशिश की।<sup>5</sup>

## विद्रोह का स्वरूप और उसका महत्व

1857 के विद्रोह को आधुनिक जय में राष्ट्रीय नहीं माना जा सकता। इसके पीछे जो भावनाएँ थीं वे विदेशियों के खिलाफ थीं, लेकिन इस विद्रोह का कोई निश्चित राष्ट्रीय स्वरूप नहीं था। इस विद्रोह में जिन विभिन्न तत्वों ने भाग लिया उन्हें कभी यह बोध नहीं हुआ कि वे एक ऐसे राष्ट्र के जग हैं जिसका सम्मिलित आर्थिक और राजनीतिक अस्तित्व हो सकता है। विद्रोह के सामंती नेताओं के राजनीतिक कार्यक्रम का बस एक ही नकारात्मक उद्देश्य था, विदेशियों को निकाल बाहर करना। उन्होंने सारे देश के लिए राष्ट्रीय राज्यतंत्र की स्थापना की न तो कोई योजना बनाई और न वे ऐसा कर ही सकते थे। वैसे ही, भारतीय समाज के निर्माण के लिए उन्होंने न तो कोई कार्यक्रम तैयार किया और न वे ऐसा कर ही सकते थे। उनमें राष्ट्रीय चेतना का अभाव था। वस्तुतः, उनमें केवल विदेशियों को निकाल बाहर करने के सवाल पर ही एकता थी। इसका बदले व फिर पुराना प्राक ब्रिटिश खंडित सामंती भारत वापस लाना चाहते थे, या संभवतः दिल्ली के सम्राट के अधीनस्थ सामंती राज्यों का राज्य संघ बनाना चाहते थे।

अपने मूल चरित्र और प्रमुख नेतृत्व की दृष्टि से 1857 का विद्रोह पुरानी रूढ़िवादी और सामंती शक्तियों और गद्दी से हटाए गए रजवाड़ा का, अपने

अधिकारों के लिए विद्रोह था, क्योंकि उन्हाने नई व्यवस्था में अपने अधिकारों के विनाश की प्रक्रिया देखी। इस विद्रोह के प्रतिक्रियात्मक रूप के कारण इस व्यापक जन समर्थन नहीं मिल सका और इसकी असफलता लगभग अवश्यभावी थी।<sup>6</sup>

विद्रोहियों में बड़े अच्छे यादवा थे। उन्हाने अपने जादश के लिए प्राणों की बलि दे दी। लेकिन उनका जादश ऐतिहासिक दृष्टि से प्रतिगामी था, ऐसे राजनीतिक भारत का जादश जा विदेशी शासन से मुक्त होत हुए भी ऐसी विभिन्न देशी रियासतों में विभक्त हो जिनका सामाजिक जादर और अतन्त सामती हो।

1857 का विद्रोह जनताधिक जाधार पर बने देश के राष्ट्रीय सयुक्तिकरण की ऐतिहासिक रूप से प्रगतिशील भावना द्वारा अनुप्रेरित नहीं था। फिर भी ब्रिटिश शासन को दसन जो चुनौती दी थी उसने बाद के युग में बहुत सार भारतीयों के लिए देशभक्ति मूलक प्रेरणा का काम किया। यह विदेशी शासन को उठा फेंकने की लागे की इच्छा का प्रतीक बना। इस विद्रोह के शासी की रानी जस नताआ की महापुरपा की काटि में गिनती हाने लगी। कुछ राजनीतिक दला, आतकवादियों और जतिवादी वामपक्षी राष्ट्रवादियों ने इस स्वतन्त्रता की भावी सफल लडाई का पूर्वाभ्यास माना। दूसरे राजनीतिक दला ने यह तो माना कि पराधीन और शोषित देश के लोगे का विदेशी शासन के साथ यह अवश्यभावी और शायदपूर्ण सघष था, लेकिन उन्होने यह भी बतलाया कि इस विद्रोह का खास कर इसक सामती नताओ का, उद्देश्य ऐतिहासिक दष्टि से प्रतिगामी था।<sup>7</sup>

1857 में भारतीय इतिहास में पहली बार, कायत, यह सिद्ध हुआ कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हिंदुआ और मुसलमानों की व्यापक एकता संभव है।<sup>8</sup> इससे भारतीय जनता के सयुक्त राष्ट्रीय आंदोलन की परंपरा बनी।

### ब्रिटिश शासन की युद्ध नीति

विद्रोह के बाद भारत और ब्रिटेन के मबधे के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। ब्रिटेन की सर्वोच्च सत्ता पर अपना सीधा राजनीतिक आधिपत्य स्थापित किया और सरकारी नीति में भी परिवर्तन हुए।

1857 तक अंग्रेजों का उद्देश्य था देशी रियासतों का विलयन और सार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रत्यक्ष शासन की स्थापना। 1857 के अनुभव के जाधार पर इस उद्देश्य का परित्याग किया गया और इसके बदले यह नीति अपनाई गई कि जिन देशी रियासतों पर अभी तक कब्जा नहीं हुआ था, उन्हें ज्यों का त्यों छोड़ दिया जाए। ब्रिटेन की नई नीति अब यह थी कि इन रियासतों के राजाओं को दोस्त और अंग्रेजी शासन का देशभक्त समर्थक बना लिया जाए।

यह ब्रिटेन की राजनीतिक योजना में परिवर्तन का बिंदु था। 1857 तक अंग्रेज विभिन्न भागों में बँडित भारत में अनेकानेक सामती राज्यों के अस्तित्व के



कारण जो अनेकता थी उसे खतम करने में लगे हुए थे। यह सच है कि जो तरीके अपनाए गए वे हिंस्र और क्रूर थे और भारत को गुलाम बनाकर रखने की नीयत अजनतातिक थी। फिर भी भारत का राजनीतिक इकाई के रूप में संपृक्त कर ब्रिटेन ऐतिहासिक दृष्टि से प्रगतिशील भूमिका अदा कर रहा था।

1857 के बाद, अपने शासन की रक्षा के लिए, ब्रिटेन ने देशी राज्यों के विलयन की नीति छोड़ दी। इसने इस प्रतिक्रियावादी, रूढ़िवादी राज्यों को बनाए रखा और उन्हें बाहर और भीतर के सभी हमलों से बचाने का भी जिम्मा लिया। इस तरह ब्रिटेन भारतीय सामंतवाद का दुश्मन न होकर उसका दोस्त बना, और केवल बाहर के ही खतरों से नहीं बरन रियासतों के भीतर के उदीयमान प्रगतिशील तत्वा से भी उनका रक्षक सिद्ध हुआ।

इस तरह यद्यपि ब्रिटिश पूंजीवाद ने अपने देश में सामंतवाद को खतम कर दिया, फिर भी वह भारत में इसे बनाए रखा। बनावटी अवलंबन पर आधारित ये सामंती राज्य, कुछेक को छोड़कर राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रतिक्रियावाद के गढ़ थे।<sup>9</sup>

काल माक्स न कहा है

जिम स्थिति में इन देशी रियासतों की सतही स्वतंत्रता बरकरार रहने दी गई वह शाश्वत ह्रास की स्थिति है और ऐसी स्थिति में प्रगति कदापि संभव नहीं। अपभ्रान्त अधिक प्रभुताशील सत्ता की मौन सहमति पर जीन वाली प्रत्येक व्यवस्था की तरह यहाँ भी जैविक दुबलता जीवन का अटूट नियम है

देशी रजवाड़े घण्टे ब्रिटिश शासन व्यवस्था के सबसे बड़े परिपोषक हैं और भारतीय प्रगति की राह में सबसे बड़े अवरोध।<sup>10</sup>

चूँकि ब्रिटेन ने प्रतिक्रियावादी सामंतवाद को अपने शासन का आधार बनाया, इसलिए अंग्रेजों की भारत विजय की जो भी सीमित प्रगतिशील भूमिका हो सकी थी, वह समानुपातिक तौर पर और घटी ही।

### ब्रिटिश शासन की नई नीति के परिणाम

देश में इस नई नीति का महत्वपूर्ण परिणाम निकला। जब कालक्रम से देशी रियासतों के लोग अपनी दमनात्मक राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक स्थिति के प्रति जागरूक हुए और रजवाड़ा के निरंकुश शासन के विरुद्ध प्रतिनिधि सरकार और जनतात्मिक मांगों के लिए संगठित होने लगे तब उन्हें अनिवायत ब्रिटिश शासन से भी सघप करना पड़ा क्योंकि ब्रिटिश सरकार इन रजवाड़ों की रक्षा के लिए बचनबद्ध थी। इस तरह रियासतों की जनता का सघप ब्रिटिश भारत की जनता के स्वतंत्रता संग्राम के साथ एक स्रोत में मिल गया और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध समस्त भारतीय जनता के मयुक्त जखिल भारतीय आंदोलन का जन्म हुआ। ब्रिटिश शासन का रजवाड़ा का समर्थन प्राप्त था और उसी तरह

रजवाड़े को भी (बहुत बुरे शासन वाली कुछ रियासतों को छोड़कर) ब्रिटिश सरकार का समर्थन प्राप्त था।

1857 के बाद ब्रिटिश सरकार ने राजनीतिक युद्धनीतिक कारणों से पुराने प्रतिक्रियावादी और अशक्त सामंती रियासतों को जिंदा तो रखा ही, उसने देश के गैर प्रगतिशील तत्वों के साथ दोस्ती की और उन्हें समर्थन प्रदान करने की नीति भी अपनाई। 1876 में लार्ड लिटन ने घोषणा की कि भविष्य में इंग्लैंड का राजा हर तरह से देशों आभिजात्य का साथ देगा। टेम्पल को अपने काल (1848-80) के अंत में ऐसा भान होने लगा था कि देशों शासन की प्राचीनता और परंपरा पर आधारित देशों आभिजात्य ब्रिटिश शासन के अधीन संगठित और विकसित हो सकेगा।<sup>11</sup> उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध में अपक्षायित स्वतंत्र पत्रकारिता और प्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार का एक प्रगतिशील काम था। 1857 के विद्रोह के बाद सरकार ने मूलतः प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित करने की नीति अपनाई।

1857 के पहले ब्रिटेन ने जमकर भारतीयों के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप किया और सती जैसी क्रूर सामाजिक प्रथाओं के खिलाफ आंदोलन किए और कानून बनाए। लेकिन 1857 के बाद इसने सामाजिक मामलों में निष्पक्षता की नीति अपनाई। राजा राममोहन राय और अन्य लोगों द्वारा चलाए गए समाज सुधार आंदोलनों और रुढ़िग्रस्त सामाजिक संस्थाओं और प्रथाओं के विरुद्ध उनके सघर्ष को सरकार का समर्थन मिला था। 1857 के बाद ऐसे लोगों का अपने प्रगतिशील लक्ष्य की पूर्ति में, सामाजिक प्रतिक्रियावादियों के साथ ही साथ सरकार की उदासीनता का भी सामना करना पड़ा। सरकार के इस रुख के कारण परंपरागत, रूढ़िवादी तत्वों की बल मिला।

इस तरह 1857 के बाद अंग्रेजों की भारतीय नीति लगभग पूर्णतः बदल गई। शुरू में अंग्रेजी शासन ने प्रगतिशील तत्वों की तरफ झुका था, उसने उन्हें समर्थन भी दिया, लेकिन जब इसके विपरीत रूढ़िवादी शक्तियों के प्रथम की नीति अपनाई गई।

### 1857 और 1885 के बीच की प्रमुख घटनाएँ

1885 में उदारवादी भारतीय बुद्धिजीवियों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। इसे व्यापारिक बुरुजुआजी के भी एक जश का समर्थन प्राप्त था और यह अखिल भारतीय आधार पर भारतीय राष्ट्रीयता के आंदोलन के पहले वास्तविक उदय का प्रतीक था। लेकिन इसके विकास का इतिहास चित्रित करने के पहले हम 1857 और 1885 के बीच की कुछ प्रमुख घटनाओं का उल्लेख करेंगे।

1857 में अपनी पुरानी शक्ति और मर्यादा को फिर से स्थापित करने का पुराने समाज की सामाजिक शक्तियों का अंतिम प्रयास पूर्णतः असफल हो गया। भविष्य में इस तरह का कोई नया प्रयास कर सकने की स्थिति में अब वे नहीं थे।

संगठित राष्ट्रीय आंदोलन की अगुआई करने वाली नई सामाजिक शक्तियाँ,

था बुद्धिजीवी वर्ग और व्यापारिक बुजुर्गों, अभी अपने ऐतिहासिक कार्य को पूरा करने के लिए पूरी तरह परिपक्व नहीं हो पाई थी। 1870 के बाद, कई कारणों के संयोग से देश में फिर राजनीतिक उथार जाया और नई सामाजिक शक्तियों को राजनीतिक चेतना और आर्थिक शक्ति मिली, और उनकी राजनीति पुनरुत्थान शुरू होने लगी। इस नई स्थिति में, 1885 में, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई।

लेकिन 1857 और 1870 के बीच दो ब्रिटेन विरोधी आंदोलन हुए, जिनका प्रमुख लक्ष्य था ब्रिटिश सरकार को सशस्त्र विद्रोह द्वारा उखाड़ फेंकना। इनमें एक तो बहावी लोगों का विद्रोह था। मुसलमानों के इस लड़ाकू संप्रदाय के अनुयायियों ने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था और इसके दमन के बाद भी कुछ दिनों तक अपनी कायबाही जारी रखी थी। दूसरा विद्रोह मराठों के एक दल का था। 1857 की हार के बाद भी वे निरुत्साह नहीं हुए थे और अंग्रेजों को हटाने के लिए प्रयत्न करते रहे। 1871 तक बहावी आंदोलन कुछ सशस्त्र मुठभेड़ों के बाद सरकार द्वारा पूरी तरह दबा दिया गया। ब्रिटिश विरोधी मराठा प्रयत्नकारियों के पुना स्थित केंद्र का 1863 में पता चल गया और इस तरह उनका प्रयास विफल हो गया। ये दोनों आंदोलन 1857 के विद्रोह के ही अवशिष्ट थे।

### अनधिकारी दुर्भिक्ष और किसान विद्रोह

1870 के बाद राजनीतिक और आर्थिक असंतोष व्यापक रूप लेने लगा जिसकी चरम परिणति के रूप में 1885 में भारतीय राष्ट्र के प्रमुख राजनीतिक संगठन इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। 1857 के विद्रोह के परवर्ती काल में किसानों का असंतोष लगातार बढ़ता गया क्योंकि ब्रिटिश शासन में वे अधिकाधिक विपन्न होते गए थे। भूराजस्व और लगान के बढ़ते हुए बोझ का उन पर बढ़ा बुरा असर पड़ा था। 1870 तक हस्तशिल्प और कारीगर उद्योग पूरी तरह खत्म हो गए थे जिसके चलते कृषि मजदूरी बढ़ी। 1870 के कृषि मजदूरी के फलस्वरूप किसानों की स्थिति और भी बुरी हुई और उनमें कृषकता बढ़ी। 1867 और 1880 के बीच कई अनधिकारी दुर्भिक्ष पड़े। 1887 का जकाल विशेषतः विनाशकारी था। बर्मा, मद्रास और देश के दूसरे हिस्सों के 200 000 वर्गमील और 3 करोड़ 60 लाख लोग इसकी चपेट में आए।<sup>12</sup>

1865 और 1880 के बीच हुए दुर्भिक्ष केवल इसीलिए ही महत्वपूर्ण नहीं हैं कि उनके चलते काफी क्षति और काफी तबाही हुई, बरन इसलिए भी कि वे ऐसे संक्रमण काल में हुए थे जब भारत धीरे-धीरे मुद्रातन्त्र की ओर बढ़ रहा था अधिकांश रैयता को सूदखोर महाजनों के यहाँ जाना पड़ा, और आर्थिक मजदूरी के बाद दुर्भिक्ष का यह परिणाम हुआ कि उत्पादक निधन हो गए और दासता की जड़ों में जकड़ गए।<sup>13</sup>

आर्थिक विपत्ति के कारण किसानों में जो असंतोष आया, उसके का

कई दगे हुए, जिनमे 1875 का डक्कन किसान विद्रोह सर्वाधिक गभीर था। सरकार ने स्थिति की गभीरता को समझा और सारी कृषक समस्या की गवेषणा के लिए उसी साल उसने डेक्कन रैंजर्स कमीशन, और बार बार होने वाले दुर्भिक्ष से हुई विपत्ति के कारण 1878 में फेमिन कमीशन बहाल हुआ।

दूसरे अफगान युद्ध के वित्तीय बोझ और 1877 के असयत, अतिव्यापी, भव्य और चामत्कारिक दिल्ली दरवार, जिसमें ब्रिटोरिया को भारत साम्राज्य घोषित किया गया, के कारण लागा का असतोष और रोष बढ़ा ही, खासकर इसलिए कि यह दुर्भिक्ष और भुखमरी का जमाना था। फिर 1878 के बर्नार्डुलर प्रेस ऐक्ट, जो भारतीय प्रेस की स्वतन्त्रता पर रोक लगाने के निमित्त पारित किया गया था, और 1879 के इंडियन प्रेस और आम्स ऐक्ट के कारण लोगों के असतोष की ज्वाला प्रज्वलित हुई। ये दोनों ऐक्ट लाड लिटन के शासनकाल में पारित हुए थे। स्थिति लगभग विस्फोटक हो गई थी।

### इलवर्ट बिल

कुछ और ऐसे कारक थे जिनके चलते ब्रिटिश सरकार और भारतीय जनता के बीच की खाई और अधिक चौड़ी होती गई। श्वेत शासक वर्ग के सदस्य हान का एहसास कुछ ऐसा था कि अधिकांश सरकारी और गैर सरकारी जग्गें न भारतीयों के प्रति जहकार ज बड़प्पन का भाव अपनाया।<sup>14</sup> इसके कारण भारतीयों में तीव्र ब्रिटिश विरोधी भावनाओं का जागरण हुआ।

जब लाड रिपन ने इलवर्ट बिल आगे बढ़ाया, जिसमें अपराध और 'वाय क क्षेत्र में भारतीयों और यूरोपियनों की समानता की बात थी, तो सारे यूरोपीय समाज ने इसके खिलाफ जोरदार सघष संगठित किया। 'वायसराय को चढ़पट घाट पर स्टीमर में बठाकर केप के रास्ते वापस इंग्लैंड भेज दें' की भी साजिश तयार की गई।<sup>15</sup>

यूरोपियन लोगों में 'मजात श्रेष्ठता की भावना के ही कारण हम भारत जीत सके हैं। इस देश का वाशिदा कितना ही शिक्षित और चतुर क्या न हो, उसने अपने का कितना ही बहादुर क्यों न सिद्ध कर लिया है, और हम उस चाह किसी भी पद पर क्यों न आसीन कर दें मरा विश्वास है कि कोई भी ब्रिटिश अफसर उसे अपना समकक्ष नहीं मान सकता।'<sup>16</sup>

यूरोपीय समाज के कट्टर विरोध के कारण यह बिल पास नहीं हो सका। इसके चलते दोनों जातियों की पारस्परिक कटुता की भावना और अधिक तीव्र हुई। ब्रिटिश शासन की निष्पक्षता के बारे में भारतीयों की गलतफहमी खतम हुई। जातिगत विभेद की झलक इस बात में भी मिलती है कि प्रशासन में सारे ऊंचे पदों पर यूरोपियन लोग ही आसीन थे। भारतीय जनता का शिक्षित समुदाय इस बात पर विशेष रूप से रष्ट था।

जब 1877 में इंग्लैंड में होने वाले सिविल सर्विस इन्वैस्टिगेशन के लिए

अल्पतम आयु सीमा 21 से घटाकर 19 कर दी गई, तो सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने इसके विरोध में आंदोलन संगठित किया। उनके अनुसार सरकार ने यह काम जानबूझकर इसलिए किया था कि प्रशासन में ऊँचे ओहदा पर भारतीय नहीं आ सकें।

फिर, सरकार ने 1882 में लका शायर के सूती उद्योग को मदद पहुँचाने के लिए सूती सामान पर से आयात कर उठा लिया। भारत को घाटे में डालकर ब्रिटिश आर्थिक हितों की रक्षा के इस पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण सरकार की अलोकप्रियता बढ़ी। भारतीय जनता के हर वर्ग यथा किसानों कारीगरों और बुद्धिजीवियों में असंतोष फैलता गया।

### बढ़ता हुआ असंतोष और नया नेतृत्व

राष्ट्रीय आंदोलन को संगठित करने और आगे बढ़ाने में शिक्षित मध्यम वर्ग का एक अन्य स्रोत से भी प्रेरणा मिली। अंग्रेजों द्वारा स्थापित स्कूल और कालेजों में उन्हें जो शिक्षा मिली, उससे उन्हें यूरोप के प्रजातांत्रिक विचारों और विभिन्न देशों में स्वतंत्रता के लिए हुए राष्ट्रीय संघर्ष की जानकारी प्राप्त हुई। शिक्षित भारतीयों ने अमेरिकी जनता के स्वतंत्रता संग्राम, आस्ट्रिया के प्रभुत्व से मुक्ति के लिए इटली के संघर्ष और आइरिश जनता की स्वतंत्रता की लड़ाई की कहानी पढ़ी। उन्होंने टॉम पेन, स्पेंसर बक मिल, वाल्टेयर, मैजिनी जस लेखकों की रचनाएँ पढ़ी, जिन्होंने व्यक्तिगत और राष्ट्रीय स्वातंत्र्य के सिद्धांत का प्रचार किया था। ये शिक्षित भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के वार्त्तिक और राजनीतिक नेता बने।

उदीयमान भारतीय राष्ट्रवाद की शक्तियों को नए बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा दिया गया नेतृत्व 1857 के विद्रोह के सामंती नेतृत्व की तुलना में ऐतिहासिक दृष्टि से प्रगतिशील था। यह नया बुद्धिजीवी वर्ग आधुनिक राष्ट्रवाद और प्रजातंत्र की भावनाओं से ओत प्रोत था। शुरू के दिनों में यह ब्रिटिश प्रजातंत्र की मदद से ही स्वतंत्र और प्रगतिशील सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से मयुक्त भारतीय राष्ट्र का निर्माण करना चाहता था। इसके विपरीत 1857 के विद्रोह के अगुआ विदेशी शासन हटाकर फिर से सामंती अनेकता पर आधारित पुराने भारत को वापस लाना चाहते थे। अधिक से अधिक वे स्वतंत्र निरंकुश सामंती रियासतों का महासंघ बनाना चाहते थे।

1870 और 1885 के बीच राष्ट्रीय पत्रकारिता और साहित्य का लगातार विकास हुआ जिससे लोगों के बढ़ते हुए असंतोष का पूरा परिचय मिलता है। 'समाचार पत्र रंगमंच, गुप्त श्रांतिकारी दल, खास तौर पर बंगाल में सक्रिय थे। गरिबालडी और मैजिनी के जीवन चरित का अनुवाद किया गया और 'हिस्ट्री आफ इंडिया गॅड इन अ ड्रीम' जसी कृतियों में राष्ट्रीय मुक्ति का आदर्श घोषित हुआ।' बंगाल में लिखे गए नाटक 'नील दर्पण' में यूरोपियन मालिकों व नील बागानों में काम करने वाले मजदूरों की मुसीबतों और जदोजेहद का चित्रण था।

भारतीय जनता का राजनीतिक और आर्थिक असतोप बढ़ता गया, खासकर 1870 के बाद, और 1883 के लगभग तो वह विस्फोटक स्थिति में पहुँच चुका था। लार्ड लिटन की सरकार के जन विरोधी कार्यों से यह असतोप बढ़ा। 'प्रतिक्रियावादी काय और पुलिस जुल्म के रूसी तरीके के कारण लार्ड लिटन के शासन काल का भारत त्रातिकारी विस्फोट की स्थिति के बहुत करीब पहुँच गया था, लेकिन ह्यूम और उसके भारतीय सलाहकारों ने बड़े मौके से इस स्थिति में हस्तक्षेप किया।'<sup>18</sup>

### सुरक्षा कपाट (बचाव के रास्ते)

की आवश्यकता के बारे में ह्यूम के विचार

ह्यूम ने, जिसने आग चलकर उदारवादी भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग के सहयोग से इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की, यह समझा कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जन असतोप विद्रोह के रूप में फूट पड़ने वाला था। वह 1882 तक सरकारी नौकरी में था और उसे गुप्त पुलिस रिपोर्टों को देखने का मौका मिला था, जिनसे यह पता चलता था कि किस तेजी से जन असतोप बढ़ रहा था और छिपे हुए पड़ोसकारियों के संगठन फल रहे थे।<sup>19</sup>

देश में बड़े गंभीर विद्रोह की संभावना के कारण ह्यूम ने भारत के तत्कालीन वायसराय लार्ड डफरिन से भेंट करने की आवश्यकता महसूस की। इसके तुरंत बाद 1885 में, कुछ महान उदारवादी भारतीय विद्वानों के सहयोग से उसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। कांग्रेस राष्ट्रीय असतोप खासकर शिक्षित वर्गों के असतोप के केंद्रबिंदु का काम कर सकती थी, और भारत की राजनीतिक प्रगति के लिए इस असतोप को जनतांत्रिक, वैधानिक आंदोलन का रास्ता ले चल सकती थी। यह सरकार के बारे में शिक्षित वर्गों की राय से भी उत अलग कर सकता था।

ह्यूम की बातों से ही स्पष्ट है कि कांग्रेस की स्थापना की बात सुरक्षा कपाट के रूप में की जा रही थी। हमारे ही कार्यों के फलस्वरूप पैदा हुई, बढ़ती हुई महान शक्तियों के विकास के लिए सुरक्षा कपाट की आवश्यकता थी, और हमारे कांग्रेस आंदोलन से अधिक अच्छा कारण सुरक्षा कपाट मभव नहीं था।<sup>20</sup> सर आकलेड कालविन को लिखे गए अपने पत्र में ह्यूम ने कहा

जिन लोगों ने इस आंदोलन को प्रारंभिक प्रेरणा दी, उनके सामने कोई रास्ता, कोई उपाय नहीं रह गया था। पश्चात्त विचारों, शिक्षा, आविष्कार और औजार की सृष्टि के कारण जो उद्वेलन आया, वह बड़ी तेजी से, बढ़ती हुई तीव्रता से काम कर रहा था, और यह अत्यंत आवश्यक था कि इसके परिणामों के विकास के लिए खुली हुई वैधानिक बाहिका तयार की जाए, सतह के नीचे मड़ने के लिए छोड़ देने के बदले सड़ाई शुरू हो गई थी।<sup>21</sup>

हमारे इतिहासकारों ने भी इस तरह की बात की है

कांग्रेस की शुरुआत के शीघ्र पहले के साल 1857 के बाद सबसे अधिक खतरनाक थे। अंग्रेज अफसरों में ह्यूम ने ही आने वाला खतरा देखा और उसे रोकने की कोशिश की वह शिमला गया अफसरों को यह बतलाने के लिए कि हालत कितनी नैराश्यपूर्ण हो चुकी थी यह संभव है कि उसकी बातचीत से नए वायसरॉय न जो काफी प्रच्छन्न बुद्धि का था स्थिति की गंभीरता समझी और ह्यूम को कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्साहित किया। इस अखिल भारतीय आंदोलन के लिए समय एकदम परिपक्व था। शिक्षित लोगों की सहानुभूति और समयन प्राप्त सभावित कृपक आंदोलन के बदले जब कांग्रेस के रूप में उदीयमान वर्गों को नए भारत के निर्माण के लिए राजनीतिक रंगमंच मिला।<sup>2</sup>

इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के पहले भी देश के विभिन्न भागों में कुछ राजनीतिक संगठन थे जैसे एस० एन० बनर्जी द्वारा बंगाल में स्थापित इंडियन एसोसिएशन, बर्बई में दादाभाई नौरोजी और जगन्नाथ शंकर सेठ द्वारा स्थापित वावे एसोसिएशन पूना में त्रिपलकर द्वारा स्थापित सांख्यिक सभा इत्यादि। लेकिन कांग्रेस की स्थापना के पहले कोई अखिल भारतीय संगठन नहीं था।

### इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना

भारतीय जनता के सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन बर्बई में 1885 में हुआ। भारतीय राष्ट्रवाद के लगभग सभी प्रमुख नेताओं ने इस अधिवेशन में भाग लिया।

1885 से 1905 तक कांग्रेस में जिन उदारवादी बुद्धिजीवियों का प्रभुत्व था वे भारतीय राष्ट्रवाद के प्रथम चरण के नेता थे। उनमें बंगाल के डब्ल्यू० सी० बनर्जी, आनंदमोहन बोस, लालमोहन घोष, ए० सी० मजुमदार, रासबिहारी घोष, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आर० सी० दत्त बर्बई के दादाभाई नौरोजी फिरोजशाह महता, बदरुद्दीन तयबजी आष्टे जगरकर, तेलंग, रानाडे गोपालकृष्ण गोखले डी० ई० वाचा, मालाबारी और चदावरकर, मद्रास के पी० आर० नायडू, सुब्रमण्य अय्यर, आनंद चालू, वीरराघवचार्य और केशव पिल्ल पंडित भालवीय और पंडित धर जस लोग थे। कांग्रेस और इसके क्रियाकलाप के विकास में ह्यूम, वेडरबन, और हेनरी काटन जैसे उदारवादी लोगों ने भी कांग्रेस संगठन और उसके क्रियाकलापों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।<sup>23</sup>

कांग्रेस के पहले अधिवेशन के सभापति डब्ल्यू० सी० बनर्जी के अनुसार कांग्रेस के प्रमुख उद्देश्य थे (1) राष्ट्रीय कायवर्तियों में पारस्परिक मवघ का विकास, (2) सारे देशप्रेमियों के बीच प्रजाति, धर्म और प्रातीयता जन्य विभेद का उन्मूलन और उनके बीच राष्ट्रीय एकता की भावना का अधिकाधिक विकास, (3) मूलभूत भारतीय समस्याओं पर पूरी बहस के बाद उनके बारे में शिक्षित भारतीयों के निणय अंकित करना, और (4) अगले साल का कार्यक्रम निश्चित करना

कांग्रेस ने ही पहली बार राष्ट्रीय मांग के समर्थन में प्रस्ताव पारित किए। इनमें से कुछ मांगें थीं इंडियन काउंसिल का उन्मूलन, आई० सी० एस० का एक साथ ही इस्तफान लेना और उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु को ऊंचा करना, विधायिका सभाओं के लिए सदस्य चुनना, और नाथ वेस्टन फ्रिटियर प्राविस, अवध और पंजाब में ऐसी विधायिका सभाएं बनाना।<sup>4</sup>

इस तरह उदारवादी राजनीतियों द्वारा स्थापित और संचालित कांग्रेस के पहले अधिवेशन की मांगें काफी मनुलित थीं और प्रशासनिक सुधार और विधायिका सभाओं में चुनाव के सिद्धांत की स्वीकृति तक ही सीमित थीं। कांग्रेस की तरफ से ह्यूम ने, अधिवेशन के अंत में महारानी साम्राज्ञी विक्टोरिया के लिए जयनाद भी किया और इस तरह कांग्रेस की राजभक्ति पर जोर दिया।

### उदारवादी नेतृत्व की विचार पद्धति और काय प्रणाली

जब हम उदारवादी राष्ट्रियता के मध्य में सिद्धांत और तरीका पर प्रकाश डालेंगे। भारत के उदारपथियों को ब्रिटिश जनतंत्र में निस्सीम आस्था थी। वे साचते थे कि बड़े दब मयोंग से भारत में अंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ है और यह देश को स्वतंत्र, प्रगतिशील, प्रजातांत्रिक राष्ट्रीय अस्तित्व प्रदान करेगा। जस्टिस रानाडे ने कहा कि भारत में अंग्रेजी शासन की साथकता यह है कि बड़े पमाने पर, नागरिक और साम्रज्यनिक त्रियाकलाप के क्षेत्र में, राजनीतिक शिक्षा देना इसका दैवी लक्ष्य और विधान है और यह इसके लिए सुयोग्य भी है।<sup>5</sup>

भारतीय उदारवादियों को ब्रिटेन से यह उम्मीद थी कि सामाजिक और सांस्कृतिक पिछड़ेपन को दूर करने में और भारतीयों को प्रतिनिधि सरकार का काय में प्रशिक्षित करने में वह भारतीय जनता का पथ प्रदर्शन करेगा। 1895 में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने कहा 'इंग्लैंड से हम प्रेरणा और पथ प्रदर्शन की जाशा है इंग्लैंड से वह महान आदेश आएगा जिससे हमारी जनता का मताधिकार मिलेगा। इंग्लैंड हमारा राजनीतिक नेता है राजनीतिक कृतव्य के उच्च क्षेत्र में।'<sup>6</sup> जगें उ हान यह भी कहा हम अंग्रेजी जनता की काय भावना और उसकी उदारता का भरोसा है हम पार्लियामेंट की जननी, ब्रिटिश हाउस आफ कामंस, जो विश्व की सबसे बड़ी प्रतिनिधि सभा है के स्वतंत्रता प्रेमी अतर्नान में अतीव आस्था है इसमें उन द्वीपों का जनतंत्र आसीन है जहां कहीं अंग्रेजों ने अपना झंडा फहराया है या अपनी सरकार बनाई है वहां उन्होंने उसी को अपना आदेश बनाया है।<sup>7</sup>

भारतीय उदारवादियों ने भारत और ब्रिटेन के हितों का विराधी न बदल सहयोगी माना। इसलिए वे राजभक्त न और उहान ब्रिटेन से मयध बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। एम० बनर्जी ने कहा हम पावक्य नहीं वरन एकता, मयुक्तीकरण और उस महान साम्राज्य का अभिन अग के रूप में समेकन चाहते हैं जिसने सारी दुनिया के समक्ष म्बनत मय्थाओं का आदेश



प्रस्तुत किया है।' <sup>8</sup> दादाभाई नौरोजी ने भी इसी उदारवादी भावना का अभिव्यक्ति दी जब उन्होंने कहा, 'हम मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हम अंग्रेजी राज्य से हुए फायदों का ज्ञान हैं।' <sup>9</sup>

इन उदारवादियों ने यह भी माना कि कांग्रेस जनसाधारण का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही थी, केवल उनकी शिकायतों की व्याख्या कर रही थी। कांग्रेस वस्तुतः जनसाधारण की आवाज नहीं बुलंद कर रही थी, लेकिन शिक्षित देशवासियों का यह कतव्य अवश्य था कि वह साधारण जनता की तकलीफों की व्याख्या करे और उनको खतम करने की राय दें। <sup>30</sup>

उदारवादियों की नियमबद्ध प्रगति में आस्था थी, वे विकास की धीमी प्रक्रिया में विश्वास करते थे और क्रांतिकारी परिवर्तन के विरुद्ध थे। 'भारत के लोगों को आकस्मिक परिवर्तन और त्राति से प्रेम नहीं। वे ऐसे नए विधान नहीं मांगते जो विधायिका सभाओं की रूपी जुपीटर के सिर से सशस्त्र मिनर्वा की तरह निकले हों वे वर्तमान सरकार को मजबूत करना चाहते हैं और उसे जनजीवन के अधिक समीप लाना चाहते हैं। वे सेक्रेटरी आफ स्टेट की काउंसिल में भारतीय कृषि और उद्योग के प्रतिनिधियों के रूप में कुछ भारतीयों को देखना चाहते हैं वे प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रश्न पर विचार विनिमय के लिए भारतीय जनता के हितों का प्रतिनिधित्व चाहते हैं।' <sup>31</sup>

ब्रिटिश राष्ट्र के सहयोग और साहाय्य से भारत के क्रमिक विकास में विश्वास करने वाले इन उदारवादियों ने क्रांतिकारी आकस्मिक परिवर्तन और उसकी कार्यप्रणाली को स्वीकार नहीं किया। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने वैधानिक आंदोलन का रास्ता अपनाया। उनका खयाल था कि इसके जरिए वे एक तरफ तो जनजागरण और जनशिक्षा का विकास कर सकेंगे और दूसरी तरफ अंग्रेजों को यह समझा सकेंगे कि भारतीय जनता की मांगें 'यायसगत' हैं और उनकी पूर्ति प्रशासन का जनतांत्रिक कतव्य है। साविधानिक सत्ता जिनके हाथों में है उनके क्राय और सहयोग द्वारा वांछित परिवर्तन लाने के लिए वैधानिक संधय का उन्हें अधिकार था। केवल तीन बातें बर्जित थीं विद्रोह विदेशी आक्रमण की सहायता या उसे प्रथय, अपराध का रास्ता। मोटे तौर पर इन तीन बातों को छोड़कर बाकी सब कुछ साविधानिक था। जो कुछ साविधानिक था वह सब आवश्यक या युक्तिसंगत नहीं था, लेकिन यह अलग बात थी। इस कार्यप्रणाली के एक छोर पर 'याय' के लिए प्रार्थना और जपिल की व्यवस्था थी दूसरे छोर पर निष्क्रिय विरोध (सत्याग्रह) की, जिसका अंतिम रूप यह भी था कि जब तक मांगें पूरी नहीं हो जाती, तब तक कर का भुगतान नहीं किया जाएगा। <sup>32</sup>

### उदारवादी नेतृत्व की प्रगतिशील भूमिका

राजनीति विषयक अपनी अनेकानेक गलत धारणाओं के बावजूद भारतीय उदार-

वादी भारत में आधुनिक बुजुर्ग समाज के हितों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और इस तरह उनकी भूमिका प्रगतिशील थी। वे प्रथम अखिल भारतीय, राजनीतिक, राष्ट्रीय संगठन के संस्थापक थे। उन्होंने भारतीय जनता के कुछ भागों में राष्ट्रीय चेतना का प्रादुर्भाव कराया उनके बीच प्रजातांत्रिक विचारों का प्रचार किया और प्रतिनिधि संस्थाओं के विचारों को लोकप्रिय बनाया। उन्होंने भारतीयों को भारतीयों जैसा अनुभव करने के लिए कहा, चाहे उनमें प्राचीन या सांप्रदायिक विभेद ही क्या न हो। वे आधुनिक यूरोप की संपन्न प्रजातांत्रिक और वैज्ञानिक संस्कृति के भारत में प्रचार और प्रसार के घोर समर्थक थे, और उन्होंने प्राकृतिक ब्रिटिश काल की मध्ययुगीन, पुराणपथी एवं निरकुश सामाजिक संरचना के खिलाफ जमकर सघप किया। वे उद्योगीकरण और सामाजिक संघर्ष के प्रजातन्त्रीकरण द्वारा भारत की आर्थिक प्रगति के पक्षधर थे।

इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के समय इसका मूल सामाजिक आधार बुद्धिजीवी वर्ग, शिक्षित समाज के ऊपरी तबके और वाणिज्यिक बुर्जुआजी से (1885 में औद्योगिक बुर्जुआजी अभी कुछ खास तौर पर विकसित नहीं हो सकी थी) से निर्मित था। इसके कार्यक्रम में मूलतः वे बातें थीं, सरकारी नौकरियों का भारतीयकरण, व्यापार संबंधी विभेद और प्रश्रय का अंत, आदि, और इस कार्य से उपयुक्त वर्गों के हितों का परिचय मिलता है।

उदारवादियों की बहुत सारी गलत राजनीतिक धारणाओं की वजह यह थी कि वे ब्रिटेन और भारत के संघर्षों की वास्तविक प्रकृति को ठीक तरह से नहीं समझ सके। वे यह नहीं समझ सके कि भारत ब्रिटिश पूंजीवाद का उपनिवेश था और इसलिए ब्रिटेन इस देश का मुक्त आर्थिक विकास नहीं होने देगा और भारत के आर्थिक विकास को ब्रिटिश पूंजी की आवश्यकताओं पर निर्भर रहना पड़ेगा। ब्रिटिश और भारतीय स्वार्थों के बीच इस वास्तविक संघर्ष को उदारवादी लोग नहीं समझ पाए। फिर चूंकि भारत पर ब्रिटेन की राजनीतिक सत्ता ब्रिटिश स्वार्थों की रक्षा कर रही थी इसलिए ब्रिटेन से यह उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी कि वह भारत का सत्ता हस्तांतरित कर देगा या यहाँ मूलभूत प्रशासनिक सुधार लाएगा।

1885 से 1905 तक भारतीय उदारवादियों के नतत्त्व में कांग्रेस ने प्रशासनिक सुधार के लिए सघप किए, जैसे, कार्याकारिणी और वार्षिक व्यवस्था का पथक, जन सेवाओं में वरावरी की शर्तों पर भारतीयों की नियुक्ति और बाद में, इन सेवाओं का भारतीयकरण, आम्स एक्ट का हटाना, भारत से बाहर घन जल की प्रक्रिया पर रोक लगाना, क्योंकि इससे लोग बड़ी तादाद में मरीज हो रहे थे, सेना संबंधी खर्च में कमी इत्यादि। 1892 में कांग्रेस ने पंडित मालवीय का प्रस्ताव पारित किया, जिसमें सरकार से कहा गया था कि क्षीणप्राय ह्रासोमुख हस्तशिल्प उद्योग को पुनरुज्जीवित किया जाए। उदारवादी नतत्त्व ने भारत में औद्योगिक विकास का तीव्र करने की प्रक्रिया के रूप में स्वदेशी का भी प्रश्न

उठाया, और 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसके समर्थन में प्रस्ताव रखा गया। 1895 में इस उदारवादी नेतृत्व ने ट्रांसवाल फ्री स्टेट और केप कालनी के भारतीयों के विरुद्ध बने कानूनों के खिलाफ भी जावाज उठाई।

यह उदारवादी नस्ल प्रतिनिधि नस्लाओं और चुनाव के सिद्धान्त का समर्थक था। इसने जनता द्वारा निर्धारित विधायिका सभाओं और कार्यकारिणी पर विधायिका सभा के नियंत्रण की मांग की।

### मांगे जो पूरी नहीं हुईं

उदारवादियों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के माध्यम से और सांविधानिक आंदोलन के तरीकों से, जिन्हें ब्रिटिश जनता की प्रजातांत्रिक विवेक, बुद्धि और परंपरा से काफी बल मिला, इस बात की काशिश की कि सरकार प्रशासनिक सुधार प्रतिनिधि संस्थाएँ, आर्थिक बहिष्गमन पर रोक नोकप्रिय और तकनीकी शिक्षा भारतीय उद्योगों के लिए संरक्षण दमनात्मक कानूनों का खाता आदि मांगों की पूर्ति करे।

फिर भी 1918 तक, कांग्रेस के विभिन्न अधिवेशनों में प्रस्तावों द्वारा पारित अधिकांश मांगों की पूर्ति नहीं हुई। 1918 तक भी जा मांगे नहीं मानी गईं थीं वे य थी इंडियन काउंसिल का उन्मूलन और जाइ० सी० एस० के लिए एक साथ ही परीक्षा की व्यवस्था (1885 के कांग्रेस अधिवेशन में पारित प्रस्ताव), कार्यकारिणी और आर्थिक व्यवस्था का पाठ्यक्रम (1886), ब्रॉम्स एक्ट्स और रूल्स का संशोधन (1877), तकनीकी और औद्योगिक विकास (1888) भूराजस्व नीति का सुधार (1889) करों का सुधार (1892), बेगार का उन्मूलन (1893), काटन पर उत्पादन शुल्क खतम करना (1893), उपनिवेशों में गए हुए भारतीयों की हालत में सुधार (1894), क्रमशः 1818, 1819 और 1827 के बंगाल मद्रास और बांग्लादेश में सेडिशन (राजद्रोह) एक्ट की समाप्ति (1897), इंडियन युनिवर्सिटीज एक्ट आफ शीयल सिन्ड्रेट्स एक्ट की समाप्ति (1903) स्थानीय स्वायत्त शासन की दिशा में प्रगति (1905) ट्रिनिटील लॉ जोमंडमट एंड यूजफेस एक्ट्स की समाप्ति (1908) निशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा (1908) सेडिशन मीटिंग्स एक्ट और इंडियन प्रेम एक्ट का निरसन (1910) और गोत्रले के बिल में प्रस्तावित निशुल्क अनिवार्य शिक्षा (1910)।<sup>33</sup>

राजभक्ति के बावजूद अपनी स्थापना के तुरंत बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस को सरकार के प्राध का भागो हाना पडा। एनी कमट न बतलाया है कि कस अपने जिला अधिकारी की जाना के विरुद्ध 1887 में कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हान के लिए एक व्यक्ति को शांति बनाए रखने के लिए 20 000 रु० की जमानत देन का कहा गया।<sup>34</sup>

एक मकतूर में कहा गया कि इन सभाओं में दशक के रूप में भी सरकार।

अफसरों का शामिल होना उचित नहीं है, और इन समाजों की कायवाही में उनका भाग लेना भी मना था।<sup>35</sup> इस तरह प्रशासनिक सुधार, प्रेस की स्वतंत्रता, संपत्ति के बहिष्मन पर रोक, जादि जसी सयमित मागा के लिए कांग्रेस द्वारा किए गए वैधानिक आंदोलन भी सरकार का नापसंद थे।

1897 में सरकार ने कांग्रेस की कारवाइयां पर रोक के लिए सक्शन 124 (ए) और 153 (ए) का विधान किया। 1898 में प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए गुप्त प्रेस समितियां स्थापित की गईं। 1900 में लाड कजन ने सेनेटरी आफ स्टेट को लिखा 'कांग्रेस धीरे धीरे लडखडा कर गिर रही है और भारत में रहते हुए यह मेरी बहुत बड़ी आकांक्षा है कि इसमें शांतिपूर्ण अवसान में सहायक बनूँ।'<sup>36</sup>

बीसवीं सदी के प्रथम दशक में सरकार ने अपने अस्त्रागार में बहुत से हथियार एकत्र किए जैसे क्रिमिनल ला ओमडमेट ऐक्ट (1904), द यूज पेस ऐक्ट (1908) दि इंडियन प्रेस ऐक्ट (1910) द सडीशस मीटिंग्स ऐक्ट (1910)। इस तरह सरकार ने प्रेस मंच और समाज की स्वतंत्रता जैसी नागरिक स्वतंत्रताओं पर काफी रोक लगाई।

### बढता हुआ मोहभंग

ब्रिटिश शासन व्यवस्था की सीमा में ही रहकर जिन मागा की पूर्ति की आशा की गई थी, उनकी पूर्ति न होने से और फिर सरकारी दमन के कारण भारतीय उदारवादियों का धीरे धीरे मोहभंग होने लगा। उनकी यह उम्मीद कि भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं की स्थापना और भारतीय जनता की सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक प्रगति के लिए ब्रिटिश प्रजातंत्र का सहयोग मिलगा धीरे धीरे खतम होने लगी। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने कहा 'नागरिक सेवाओं का इतिहास वचनभंग का ज्विरल त्रिवरण है।'<sup>37</sup> पंडित धरम 1911 में कांग्रेस के सभापति पद से कहा 'हमारी मुसीबतों का अगर निदान नहीं मिला, तो भविष्य में इसके बड़े हानिकार दुष्परिणाम होंगे, और हमारी मुसीबतों का असली कारण यह है कि भारतीय जनता की नवजात आशाओं आदर्शों के प्रति अफसरशाही का रुख असहृदय और अनुदार हाता जा रहा है।'<sup>38</sup> 1914 में कांग्रेस के सभापति भूपेन्द्रनाथ वसु ने कहा 'देश का शासन अब भी विदेशी नागरिक सेवाओं के हाथ में है राज्य के सार विभाग उन्हीं के संरक्षण में हैं। उनके लिए यह सोचना कि वे जैसे हैं उससे भिन्न हो जाए अतिमानवीय होगा।'<sup>39</sup>

ब्रिटिश सरकार में भारतीय उदारवादियों की आस्था लगातार खतम होती गई खासकर लाड कजन के शासनकाल के अनुभवा के बाद। उन पर उन लडाकू राष्ट्रीय तत्वों का भी दबाव बढ रहा था जो उन्नीसवीं सदी के अंत में उदभूत हुए और जो बीसवीं सदी के गुरुव दिनों में अधिकधिक संशक्त होत जा रहे थे। इन कारणों से उदारवादियों ने अब अपने कार्यक्रम में गुड प्रशासनिक सुधार

की जगह स्वराज्य की मांग को भी स्थान दिया। 1906 के कलकत्ता कांग्रेस में दादाभाई नौरोजी के सभापतित्व में स्वराज्य (स्वशासी ब्रिटिश उपनिवेशों में चलन वाली शांति व्यवस्था) का नया कार्यक्रम स्वीकृत हुआ। कलकत्ता कांग्रेस ने विदेशी बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा आदि कार्यक्रम भी अपनाए और उदारवादियों ने उनका समर्थन किया।

ये इन उदारवादियों ने प्रशासनिक सुधार के बदले स्वराज्य को अपना राजनीतिक लक्ष्य तो अवश्य बना लिया, लेकिन इन्होंने सधप का गैर ससदीय रास्ता नहीं अपनाया। इसका कारण था वैधानिक आंदोलन की प्रभावोत्पादकता में निस्सीम, जड़ विश्वास। 1905 में भी दादाभाई नौरोजी को इसमें पूरा विश्वास था। हमारे लिए जरूरी है कि हम जंगलों से ही, जमकर, खुलकर दरखास्ता, प्रदर्शनी सभाओं के जरिए शांतिपूर्वक उत्साहपूर्ण तरीके से आंदोलन करने का सबक सीखें।<sup>40</sup>

कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ही कुछ लोगों का धीरे-धीरे उदारवादियों के सिद्धांतों और तरीकों से राजनीतिक माहौल हुआ, फिर भिन्न राजनीतिक विचारधारा और कार्यनीति वाले लड़ाकू राष्ट्रवादियों के नए दल का कांग्रेस के अंदर ही उद्भव और विकास हुआ। कई कारणों से 20वीं सदी के अंत में यह दल, जिसे गरमदल के नाम से जाना जाता है बड़ी तेजी से बढ़ रहा था।

20वीं सदी के अंत में देश में सांघातिक दुर्भिक्ष और उसके फलस्वरूप बढ़ा गंभीर आर्थिक संकट आया। प्लेग के भीषण प्रकोप में काफी लोग मरे भी। इन कारणों से लोगों की नजर में ब्रिटिश शासन का महत्व घटा।

वायसरॉय की हैसियत से लार्ड कर्जन ने जो दमनात्मक कार्य किए उनसे भी लोगों में राजनीतिक असंतोष फला। कलकत्ता नगर निगम के अधिकारों में उसके द्वारा की गई कटौती, उसका आफिशियल सिन्डेट्स एक्ट विश्वविद्यालयों का उसने द्वारा अफसरीकरण जिससे शिक्षा अधिक महंगी हुई तद्व्यतिरिक्त उसके द्वारा भेजा गया सैनिक अभियान फिर उसके द्वारा बंगाल का विभाजन, इन सबके कारण देशभक्त राजभक्त भारत की रीढ़ टूट सी गई और देश में एक नई भावना का जन्म हुआ। कलकत्ता के अपने भाषण में उन्होंने हम पर असह्य भाषण का जो आरोप लगाया उससे जारम सम्मान की हमारी भावना को ठेस लगती ही है, लेकिन उससे भी अधिक बटु यह अतिरिक्त कथ्य है कि हम भारतीय अपने परिवेश, अपनी परंपरा और अपनी शिक्षा दीक्षा के कारण ब्रिटिश शासन के अधीन ऊंचे जोहदों के लिए, नितांत अयोग्य हैं।<sup>41</sup>

20वीं सदी के प्रारंभ में खासकर बंगाल में शिक्षित लोगों के बीच बकारी काफी बढ़ गई थी। यह अनुभव सिद्ध था कि ब्रिटिश सरकार की महायत्ना से लाए गए मज्जिम, प्रथमिक विकास का सिद्धांत और महज अजिया और भाषणा का तरीका असफल रहे, इसलिए ये बकारी शिक्षित नौजवान नरम दम से विमुख होकर नए दल की ओर चले, जिनके प्रमुख नेता थे तिनक, विपिनचंद्र

पाल, अरविंद, वारींद्र घोष, और लाला लाजपत राय। नए राष्ट्रवाद को मध्यम वर्ग से सामाजिक समर्थन मिला। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन पहले उच्च वर्गीय शिक्षित समाज और व्यापारिक बुजुर्गों के कुछ हिस्सा तक ही सीमित था। लेकिन 1905 के बाद इस आंदोलन का सामाजिक आधार अधिक व्यापक हुआ और उसमें निम्न मध्य वर्गीय लोग भी आए।

कुछ और कारणों से भी भारत में लड़ाकू राष्ट्रवाद की प्रगति हुई। 1905 में जारिस्ट रूस की जापान के हाथों हार और अडोवा में इटली की हार से यूरोपियन लोगों की अविजयता के सिद्धांत को बहुत बड़ा धक्का लगा। भारतीय अपनी हीन भावना का परित्याग करने लगे और उन्हें विश्वास होने लगा कि वे ब्रिटिश शासन का हटा सकते हैं।

### लड़ाकू राष्ट्रवादी नेतृत्व का उद्भव

आर्थिक और राजनीतिक मांगों को मानने से सरकार ने इकार कर दिया। साथ ही उसने बढ़ते हुए राष्ट्रीय आंदोलन के विरुद्ध दमनात्मक करवाई भी की। फलस्वरूप उदारवादी राष्ट्रवाद की विचारधारा और कार्य पद्धति में अधिकाधिक लोगों की आस्था समाप्त होने लगी। वे लड़ाकू राष्ट्रवादियों के दल के इतने गिरे हुए इकट्ठा होने लगे। अब हम मक्षेप में इनकी विचारधारा और कार्य शैली का संक्षिप्त विवरण देंगे।

इन लड़ाकू राष्ट्रवादियों ने भारत के अतीत से प्रेरणा लेकर इतिहास की महान उपलब्धियों के विवरण द्वारा लोगों को जगाने और उनमें राष्ट्र गौरव और जात्म सम्मान की भावना भरने का प्रयास किया। उदारवादियों ने पाश्चात्य विरोधक ब्रिटिश संस्कृति का लगातार गौरवमय रूप में प्रस्तुत किया था। नए राष्ट्रवादियों ने इसके लिए उनकी जालोचना की और कहा कि यह सांस्कृतिक आत्म समर्पण का रास्ता है। इन लोगों ने कहा कि इससे भारतीयों में हीन भावना का जन्म होगा और स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए जो राष्ट्रीय गौरव और जात्म विश्वास अत्यंत आवश्यक है वह दमित होगा।

इस तरह इन लड़ाकू राष्ट्रवादियों ने हिंदुओं के वेदकालीन अतीत, जशाक और चंद्रगुप्त के महान शासन काल, राणा प्रताप और शिवाजी की बहादुरी, यासी की रानी और 1857 के राष्ट्रीय विद्रोह का नतत्व करने वाली लक्ष्मीबाई की महान दशभक्ति की याद जगाई।

इस लड़ाकू राष्ट्रवाद के दार्शनिकों का भारत की विशिष्ट प्रतिभा में विश्वास था। उन्होंने यह स्थापना प्रस्तुत की कि भारतीय जनता की अपनी विशिष्ट भावनात्मक आध्यात्मिक चेतना है। हिंदू सभ्यता विशिष्ट है। आध्यात्मिक और शाश्वत जीवन के बारे में उनकी सहज, अतर्जान चेतना न उनके चरित्र का सजाया मवारा है और उनमें समस्त इतिहास का रूप और रंग प्रदान किया है।<sup>4</sup>

पाल और अरविंद घोष के नेतृत्व में वगाल ने लड़ाकू राष्ट्रवादी स्वामी

विश्वेकानंद के नव वेदातिक आंदोलन से प्रभावित थे। 'नव वेदातवाद नव हिंदू धर्म का सारस्वतत्व है, यह जीवन के ठोस पदार्थों और वास्तविक सबंधों के गौरवान्वयन और आध्यात्मिककरण के द्वारा पुराने आध्यात्मिक आदर्शों को रूपायित करने का प्रयास है। इसलिए यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक नव निर्माण की मांग करता है। वर्तमान राष्ट्रवादी आंदोलन का आध्यात्मिक स्वर पूरी तरह से वेदातिक विचारधारा से लिया गया है।'<sup>43</sup>

इस तरह राष्ट्रवादी आंदोलन, जिसका लक्ष्य था ब्रिटिश शासन से मुक्ति और प्रजातान्त्रिक और नए पूजावादी जनतान्त्रिक आधार पर भारतीय समाज और राज्य की स्थापना, सर्वव्यापी धार्मिक आंदोलन का ही त्रियात्मक जग होकर रह गया। राष्ट्रवाद को धार्मिक शब्दों में अभिव्यक्ति मिली और इसकी रूप सज्जा भी धार्मिक रहस्यवादी थी।

तिलक के नेतृत्व में महाराष्ट्र में भी नए राष्ट्रवाद में भारत के सांस्कृतिक अतीत की स्मृति को पुनर्जागृत करने की चेष्टा की और इसने भी पाश्चात्य मस्कृति के सम्मुख उदारवादियों के सांस्कृतिक आत्म समर्पण की भूमना की। लेकिन इन्होंने स्वराज के आंदोलन को धार्मिक रहस्यवादी पोशाक नहीं पहनाई। महाराष्ट्र के लोगो को वीरता और आत्मोत्सर्ग के लिए अनुप्रेरित करने के लिए तिलक ने महाराष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए मुगल साम्राज्य के विरुद्ध किए गए शिवजी के संघर्ष की याद दिलाई। उन्होंने राजनीतिक प्रचार के लिए गणपति पूजा की प्रथा फिर से शुरू की और उसका पूरा उपयोग किया। लोगो की निष्क्रियता और जडत्व को समाप्त करने के लिए उन्होंने भगवद्गीता की नई टीका प्रस्तुत की और कहा कि कम ही उसका सार भाव है। फिर भी महाराष्ट्र में यह नया राष्ट्रवाद बगल की तरह रहस्यवादी धार्मिक दशन में आविष्टित नहीं हुआ।

गरमदल अर्थात् इन लड़ाकू राष्ट्रवादियों ने उदारवादियों की इसलिए आलोचना की कि वे भारत की राजनीतिक मुक्ति के लिए ब्रिटेन से जाशा वाधे हुए थे। गरमदल वाला न रहा कि राजनीतिक व्यवहार वास्तविक हिता, न कि अमृत सिद्धांतों से निर्णीत होता है। उनका कहना था कि ब्रिटेन भारतीय उद्योग का मुक्त, अनियंत्रित विकास नहीं होने देगा, और ऐसा विकास भारत की समृद्धि के लिए आवश्यक और ब्रिटिश उद्योगों के हित के विरुद्ध है। अगर ब्रिटिश सरकार सेवाओं का भारतीयकरण कर देती है तो मकड़ा जग्गो को सीधा नुकसान होगा। राष्ट्रवादी आंदोलन ही ब्रिटेन और भारत के स्वार्थों के संघर्ष का परिणाम था। ब्रिटेन के प्रजातान्त्रिक विचार विवेक और परंपरा का नाम लन से या बहस मुवाहसे से स्वार्थों के विरोध की वास्तविकता समाप्त नहीं हो जाती। लाला लाजपत राय ने कहा 'सबशक्तिमान प्रभु की प्राथना से शायद राजनीतिक स्वातंत्र्य और राजनीतिक अधिकारों की आपकी इच्छा शक्ति अधि-  
है। लेकिन शासक राष्ट्र से प्राथना की कंबल यही साधकता है कि  
राष्ट्र के हिता में मरण की स्थिति में राजनीतिक प्रश्नों पर जादमी

भावनाओं से आग्रह अनुरोध की निरथकता सिद्ध होती है।<sup>144</sup> तिलक न दानो दला के अन्तर को बड़े स्पष्ट शब्दों में प्रस्तुत किया 'राजनीतिक अधिकारों के लिए मध्य करना होगा। नरम दल वाले सोचते हैं कि अनुनय से ये जीते जा सकते हैं हम सोचते हैं कि ये अधिकार सरकार पर अधिकाधिक दबाव डालकर ही हासिल किए जा सकते हैं।'<sup>145</sup>

लडाकू राष्ट्रवादियों ने भारतीय जनता में राष्ट्रीय चेतना का स्वर फूँका। उन्होंने कहा कि तक और प्रायना की जमीन ऊसर है और उन्होंने विदेशी के बहिष्कार जसा कार्यक्रम अपनाया जिसमें जनसाधारण भाग ले सकें और जिससे ब्रिटिश शासक वर्ग को नुकसान हो सके। ब्रिटिश माल के बहिष्कार की उपयोगिता और उसकी प्रभावोत्पादकता के बारे में लाला लाजपत राय ने कहा 'दुकान दारा के इस राष्ट्र पर अपने व्यापार के नुकसान का तक व्यापार की जांच सहिता पर आधारित किसी भी तक की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होगा।'<sup>146</sup>

चूँकि लडाकू राष्ट्रवादी ब्रिटन और भारत के स्वार्थों को परस्पर विरोधी मानते थे, न कि सहयोगी, इसलिए महज प्रशासनिक सुधार या नौकरियाँ का भारतीयकरण उनका उद्देश्य नहीं था, उनका कहना था कि स्वराज्य या राजनीतिक मत्ता ही मूलभूत सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति ला सकती है। दूसरे शब्दों में व व्यवस्था का विनाश, न कि उसका सुधार, चाहते थे। ब्रिटिश सरकार से अपनी जाशाआ की पूर्ति न हान की वजह से 1906 में उदारवादियों ने भी स्वराज्य की मांग का समर्थन किया।

सांविधानिक आन्दोलन के द्वारा नरम दल वाला ने कहा कि जिस देश में निरंकुश विदेशी शासन चल रहा हो वहाँ इसकी कोई उपयोगिता नहीं। भारतीय संविधान का भारतीय जनता न रहा, वरन ब्रिटिश पार्लियामेंट न बनाया था, और ब्रिटिश पार्लियामेंट ब्रिटिश जनता की तावभौम इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए, इस संविधान पर आधारित भारतीय सरकार ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति जिम्मेदार थी, भारतीय जनता के प्रति नहीं। केवल इंग्लैंड जैसे देश में सांविधानिक आन्दोलन की उपयोगिता हो सकती है जहाँ लोग अपने प्रतिनिधि और अपनी पार्लियामेंट चुनते हैं और इसके जरिए सरकार पर अपना नियंत्रण रखते हैं।

### स्वदेशी और बहिष्कार

इन लडाकू राष्ट्रवादियों की स्वदेशी में बड़ी गाड़ी जासवा थी और उन लोगों ने बड़े उत्साह के साथ लागू में इसका प्रचार किया। स्वदेशी के बारे में लाजपत राय ने कहा 'मैं इसी में जपन देश की मुक्ति निहित मानता हूँ। स्वदेशी आन्दोलन से हम आत्मसम्मान आत्मविश्वास आत्मनिर्भरता और पुरस्चित गुण (इसका अर्थ में उल्लेख किया जा रहा है लेकिन यह कम महत्वपूर्ण नहीं है) मिलेंगे। इस आन्दोलन से हम धर्म, वण, जाति का विचार किए बिना समस्त भारतीयों के



अत्यंत कल्याण के लिए अपनी पूजा, अपने साधन, अपने श्रम, अपनी शक्तिया, अपनी प्रतिभा का सुचारु सदुपयोग करना सीखेंगे। सारे धार्मिक और सांप्रदायिक मतभेद के बावजूद हम स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से एकताबद्ध हो सकेंगे। मरे ख्याल से, स्वदेशी को सारे संयुक्त भारत का सम्मिलित धर्म होना चाहिए।<sup>47</sup>

इन नए राष्ट्रवादियों के मतानुसार, स्वदेशी दश के औद्योगिक और साधारण आर्थिक पुनर्जन्म और विकास के लिए आवश्यक था। इसका कार्यान्वयन के लिए बड़े वलिदान की आवश्यकता थी, खासकर, जैसा तिलक ने कहा मध्य वर्गीय लोगों की ओर से क्योंकि वे ही विदेशी माल का सर्वाधिक इस्तमाल करते थे। तिलक ने कहा कि स्वदेशी की सफलता के लिए 'आत्म सहायता, दृढ़ता और उत्सर्ग की आवश्यकता है।'

दूसरी तरफ, बहिष्कार आंदोलन जिसे उग्र राष्ट्रवादियों ने वचारिक और मागठनिक रूप दिया, पूरी तरह, कट्टर ब्रिटेन विरोधी था। इसका कार्यक्रम बड़ा व्यापक था। इसने केवल ब्रिटिश माल के परित्याग की ही बात नहीं की, बरन उपाधिया सरकारी ओहदा और काउंसिलों के बहिष्कार का भी नारा दिया। बहिष्कार आंदोलन के नेताओं ने दम विभाजन वापस लेने और दमनात्मक कारवाई बंद करने के लिए सरकार का वाध्य करने के लिए इस अस्त्र का इस्तमाल किया।

लाला लाजपत राय ने बहिष्कार आंदोलन के महत्व की निम्नांकित व्याख्या की सरकार के लिए उसकी प्रतिष्ठा भावना का प्राथमिक महत्व है और बहिष्कार आंदोलन इस प्रतिष्ठा भावना की जड़ पर कुठाराघात करता है। वह भ्रातिजन्य भावना जिसे प्रतिष्ठा कहते हैं, वास्तविक अधिकार से कही अधिक सशक्त और समर्थ है और 'वायकाट' के द्वारा हम इस प्रतिष्ठा भावना को समाप्त करना चाहते हैं हम गवर्नमेंट हाउस से विमुख होकर लोगों की ज्ञाप-दियों की ओर जाना चाहते हैं। जहां तक सरकार से आग्रह अनुरोध का सवाल है हम उससे कुछ लेना-देना नहीं, हमारा आग्रह अनुरोध तो जनसाधारण को निव-दित है। यही वायकाट आंदोलन का मनाविधान है। यही उसका आचारशास्त्र और यही उसका आध्यात्मिक महत्व है।<sup>48</sup> इस तरह वायकाट आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य था स्वराज्य प्राप्त करने के लोगों के लडाकू दृढ़ सक्त्प को जागृत करना।

### लडाकू राष्ट्रवाद के बारे में जवाहरलाल नेहरू के विचार

हिंदू धर्म और हिंदू इतिहास की परंपराओं को स्वराज आंदोलन का आधार बनाने के लिए नए राष्ट्रवाद के प्रणेतारों की वाद में बड़ी कड़ी आलोचना हुई। जाला-चका का विचार था कि इसके कारण राजनीति में रम्यवाद और धार्मिक रुढ़ि-वादिता का प्रवेश ता हुआ ही साथ ही मुसलमान, जो आवाजों के लगभग तिहाई भाग थे, राष्ट्रीय आंदोलन से विमुख हो गए। इन मनानुक्ति के

राजनीतिक आंदोलन के दम निरपेक्ष तत्त्व भी कमजोर हुए।

राष्ट्रीय आंदोलन की आत्मा के रूप में सनातन धर्म के आग्रह और जाधुनिक 'पाश्चात्य' सभ्यता की तुलना में पुरातन हिंदू सभ्यता की कल्पित आध्यात्मिक श्रेष्ठता की घोषणा से (इसे जाधुनिक मनावैज्ञानिक अवश्य अनुपूरक विभ्रम का नाम देगे) अनिवायतन राष्ट्रीय आंदोलन और राजनीतिक चेतना की प्रगति अवरुद्ध एवं क्षीण हुई। साथ ही, राष्ट्रीय आंदोलन में मुसलिम आवादी के बहुत बड़े जश के अलग रहने का एक कारण यह भी था ही कि हिंदू धर्म पर बहुत अधिक जार दिया गया।<sup>49</sup>

बी० सी० पाल और अरविंद घोष के नेतृत्व में वगल का वामपंथी राष्ट्रवाद हिंदू धर्म के धार्मिक रहस्यवाद पर आधारित था। इसके कारण अनेक राष्ट्रवादी जो अन्यथा इसका समर्थन करते, इससे विमुख होकर उदारवादियों के साथ रह गए। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार इसी कारण पंडित मातीलाल नेहरू 1907 में राष्ट्रवादी आंदोलन में अलग रहे। 'इन जादालनों की पृष्ठभूमि धार्मिक राष्ट्रवाद की थी जो उनकी प्रवृत्ति के प्रतिकूल थी। वे भारत के अतीत के पुनरुज्जीवन के पक्ष में नहीं थे। सामाजिक दृष्टि से 1907 में भारतीय राष्ट्रवाद का पुनर्जन्म निश्चय ही प्रतिक्रियावादी था।'<sup>50</sup>

राष्ट्रवादी आंदोलन लोगों के दम निरपेक्ष हिता के कार्यक्रम पर आधारित होता चाहिए। तभी सारा देश जाति और संप्रदाय से ऊपर उठकर एक ही कक्षा में जा पाता है। 'राष्ट्रीय आंदोलन का राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रम, धार्मिक सद्भाव और लगावों से अलग और ऊपर हटकर भी, भारत की जनता के विभिन्न जगहों को मूवबद्ध कर सकता है और उसे ऐसा करना चाहिए। इस वक्त ऐसा संशकत, धर्म निरपेक्ष, जाधुनिक, संयुक्त प्रजातांत्रिक आंदोलन सांप्रदायिकता को रोकने में सर्वाधिक समय हो सकता है।'<sup>51</sup>

1905 और उसके तुरंत बाद के युग में मुसलमान राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल नहीं हुए। इसकी यह भी वजह थी कि भारतीय राष्ट्रवाद के नेताओं ने खुल शब्दों में हिंदू विचारतंत्र का इसका आधार बनाया। पाल अरविंद और दूसरे नेताओं ने अपने आंदोलन का हिंदू धर्म की बुनियाद पर लड़ा करने की कांशिश की और राष्ट्रीय जागरण और हिंदू धर्म के पुनर्जन्म को एक माना। उनमें इस काम में मुसलिम जनता राष्ट्रीय आंदोलन से विमुख हुई और 1906 में मुसलिम लीग की स्थापना की मरफारी, धूर्ततापूर्ण चाल के लिए रास्ता साफ हुआ।'

लडाकू राष्ट्रवादियों में स्वतंत्रता के लिए अतीव आत्मात्मक और कष्टमूलन की जमीन शक्ति थी। वे राष्ट्रीय आंदोलन के पहले शहीद थे। उनका कार्यक्रम ही ऐसा था कि उहान सरकार के साथ सीधी टक्कर ली। वे जल गए, उह देश निकाला मिला और उहान बड़ी तकलीफ में ली। अपना जादशों और कायनम में प्रति अपनी लगन और आभक्ति के कारण वे जनता के पूज्य रहे और घर घर में

उत्कृष्टता का अर्थ है। हमें नैतिकता को अपने अंदर लेना। देशवाद को नष्ट करने के लिए हमें अपने देश को छोड़ना होगा, वरना नए राष्ट्रवाद के प्रमुख मंत्रों में और हमें अपने देश को छोड़ने के लिए अपना जीवन त्याग कर दिया। तब हमें अपने सबसे अधिक उत्कृष्ट मंत्रों, प्रवृत्तियों के लिए राजनीतिक भावना को छोड़ देना।

नए राष्ट्रवाद ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को लड़ाकू और स्वदेशी बना दिया। नए भारतीय राष्ट्रवाद का लक्ष्य यह ही बनना निश्चय है कि हमें आत्मनिर्भर बनना। इस भारतीय आंदोलन से हमें कि बहुत कुछ बिना स्वयं नहीं मिल सकता। पहला राष्ट्रवाद ने हमें नए और कुछ हद तक जान बूझ कर ही हमें परिष्कार में लगे रहा। 1918 में बंबई के टिफिन मंडल ने तिलक की विस्तारों के विरोध में राम स्वामी की ओर यह भारतीय नवदूरवा का पहला राजनीतिक कार्य था। तब से नए राष्ट्रवाद का अभिनय किया।

### लडाकू राष्ट्रवादियों के प्रमुख कार्य

अब हम नए राष्ट्रवादी इन के क्रियाकलाप का नभित सिद्धान्तों को लेंगे। तीक्ष्ण बुद्धि सबल राजनीतिक यथासंभव दुर्लभ इच्छाशक्ति और आत्मोत्साहक कारण तिलक इस दल के सबसे बड़े नेता माने गए हैं। अपने पुरुष के दिना में य चिन्तक और चारकर जने महान राष्ट्रवादियों से काफी प्रभावित थे। 1882 में राजनीतिक यात्रा में उनका प्रथम उत्साह हुआ। आपत्तिजनक लेख प्रकाशित करने के लिए उन्हें आरकर के साथ चार महीने जेल की सजा भुगतनी पड़ी।

तिलक न्यू इंग्लिश स्कूल और फायुन कालेज से संबंधित थे। इन दोनों विषय नम्याओं के नदम्य प्रगाड देशभक्ति और आत्मोत्साह की भावना से अनुप्राणित थे। 1880 में तिलक ने कस्तुरी (मराठी साप्ताहिक) और मराठा (अंग्रेजी साप्ताहिक) की स्थापना की। इनके माध्यम से नए राष्ट्रवाद के सिद्धांतों और नीतियों का प्रचार प्रचार किया गया।

तिलक ने 1893 में आपत्ति प्रजासत्तय फिर शुरू कराया। इन उत्सवों की आड में व्यापक राष्ट्रीय आंदोलन गठित हुआ। 'व्याख्यान, जुनून, गीत पाठिकाँ इस उत्सव के आवश्यक भाग हैं। इनसे लोगों की धार्मिक भावना की ही अभिव्यक्ति नहीं होती राष्ट्रीय भावना का भी पापन होता है, और रोजमर्रा के प्रमुख सवाल में रुचि पैदा होती है।'<sup>53</sup>

तिलक ने 1895 में शिवाजी उत्सव का भी फिर से शुरू कराया। इस पुनर्जागरण का राजनीतिक लक्ष्य था, मुगला के प्रभुत्व से महाराष्ट्र को मुक्त कर देना, शिवाजी की स्मृति का पुनर्जीवित करना, और इस तरह लोगों को आत्मनिर्भरता से मुक्ति के पीछे मकल्प को प्राप्त करना।

उन्नीसवीं सदी के अंत में महान दुर्भिक्ष का समय तिलक और ७

ने जमकर सहायता काय किए। तिलक न परोक्षत ही सही, लोगो को यह राय भी दी कि उह सरकारी बकाया तभी चुकाना चाहिए जब उनके लिए यह आर्थिक दृष्टि से सभव हा। 'रानी विक्टारिया किसी की मृत्यु नही चाहती, लाट साहब कहत है सब जिंदा रह, वैसी हालत मे क्या आप स्वय भय और मुखमरी के द्वारा आत्महत्या करना चाहंगे ? यदि आपके पास सरकारी बकाया चुकाने के लिए पैसा है तब तो आप बकाया चुका दें, लेकिन अगर आपके पास सरकारी बकाया देने के लिए पसा नही है तो क्या आप कुछ अवर अधिकारियो के कल्पित क्रोध से बचने क लिए अपना मालमत्ता बेच देग ? मौत के मुह म भी पहुच कर क्या आप हिम्मत से काम नही लेग ?'<sup>54</sup>

उही दिनो भारत म प्लेग की महामारी भी फैली। इससे भिडन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम से लोगो म काफी रोप आया। तिलक ने केसरी म सरकारी उपायो की तीव्र आलाचना की। कुछ ही दिना बाद जातकवादियो ने लेफिटेनेट थायस्ट और स्वास्थ्य अधिकारी रड को गाली मार दी। इस सिलसिले म चफेकर बधुजा को गिरफतार किया गया और उह वाद म मौत की सजा मिली। सरकार का खयाल था कि तिलक के प्रचार काय स जातकवादी कायवाही के लिए वातावरण तयार हा रहा है। 1895 मे दशद्राह के आरोप पर तिलक को गिरफतार कर लिया गया और उह अठठारह महीन की कैद की सजा मिली। जिन दिना तिलक जेल म ये सरकार ने इंडियन पीनल काड (भारतीय दड सहिता) म सेक्शस 124 (ए) और 153 (ए) जोडे।

वीसवी मदी के शुरू के वप तूफानी थे। प्लेग और दुर्भिक्ष के समय पर्याप्त सहायता दे सकन मे सरकारी असफलता क कारण लोगो मे तेजी से राजनीतिक असतोप बढा था। कांग्रेस की मांगे लगातार ठुकराई जा रही थी जिससे उदार वादियो की कायपद्धति और उनके कायक्रम के प्रति, राजनीतिक तौर पर सचेत बुद्धिजीवियो म लगातार सशय और अनास्था का जम हो रहा था। शिक्षित भारतीय बहुत बडे पैमाने पर यूरोपियन इतिहास का अध्ययन कर रहे थे, जिसम फ्रांस की राज्यशाति अमरीका क स्वतन्त्रता संग्राम जास्टियन प्रभुत्व के विरुद्ध इटालियन जनता क राष्ट्रीय नातिकारी मघप, जाइरिश लोगो की स्वतन्त्रता की लडाइ आदि का भी इतिहास था। वे लाग टाम पेन, मैजिनी वात्तेयर रुसी इत्यादि की रचनाए भी पढ रहे थ। उनम जो नई राजनीतिक दृष्टि विकसित हा रही थी उसरु परिणामस्वरूप वे एक तरफ ता नए राष्ट्रवादी विचार की ओर मुड रहे थे और दूसरी जार पड्यनकारी आतकवाद की ओर। लाड वजन क शासनकाल की सरकारी नीति क कारण जनता के जमताप की जाग और भडकी। वग विभाजन न ता इस ज्वाला का बृहद जग्निवाड म परिणत कर दिया।

विविध विचारधारा क भारतीय राजनीतिन इस वात पर सहमत थ कि बलबत्ता वारपारेसन ऐक्ट द्वारा लाड वजन स्थानीय स्वायत्त शासन पर बुठारा-घात कर रहे थ, इंडियन युनिवर्सिटीज ऐक्ट द्वारा उच्च शिक्षा को सीमित करने

का प्रयास कर रहे थे, और बंग विभाजन द्वारा बंगाली जनता की राजनीतिक एकता को खतम करना चाहते थे। माननीय श्री चौधरी ने कहा कि बंग विभाजन हिंदुओं और मुसलमानों में विभेद लाएगा। लाड बजन के अनुसार लगता है भारत जातिगत शत्रुता के जादू पर ही संयुक्त रह सकता है बंग विभाजन का यही कारण था ढाका में मुसलिम शासन केंद्र और कलकत्ता में हिंदू शासन केंद्र, एक दूसरे के प्रतिस्पर्द्धी।<sup>56</sup> बंग विभाजन का सबसे विरोध किया। सारे राजनीतिक दला ने इसके खिलाफ संयुक्त सघष किया। कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर, 'यायाधीश सर गुरुदास बनर्जी, और मेमनसिंह एव वासिम बाजार के महाराजाओं ने भी विरोध में साथ दिया।

बंग विभाजन विरोध के आंदोलन के सिलसिले में स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के नारे सामने आए। तिलक ने इस कार्यक्रम के लिए घनघोर प्रचार किया और कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन से सिफारिश की कि यह कार्यक्रम स्वीकार हो। दादाभाई नौरोजी और दूसरे उदारपंथी नेताओं ने भी इसका समर्थन किया और यह मजूर भी हो गया। इसके बाद तिलक राष्ट्रीय आंदोलन के अखिल भारतीय नेताओं में प्रमुख और अग्रणी हो गए।

तिलक, पाल, अरविंद चारींद्र लाजपत राय आदि सारे राष्ट्रवादी नेताओं ने समाचारपत्रों और भाषणों के माध्यम से 'वायकाट' का जनप्रिय बताने के लिए देशव्यापी प्रयास किए। आंदोलन सफल रहा और इससे ब्रिटिश माल की खपत बेतरह घटी और भारतीय उद्योगों को बल मिला। दि इंगलिश मैन नामक कलकत्ता के अग्रणी भारतीय पत्र ने लिखा

'यह विलकुल सही है कि कलकत्ता के गोदामों में कपड़े भरे हैं जिनकी बिक्री नहीं हो पाती। कई प्रसिद्ध मारवाड़ी फर्म विलकुल बर्बाद हो गए हैं, और कई बहुत बड़े बड़े यूरोपियन आयात गहों (कपड़ियों) को या तो अपनी कुछ शाखाओं को बंद कर देना पड़ा है या उनमें व्यापार को बहुत सीमित कर देना पड़ा है। वायकाट राज्य के दुश्मनों के हाथ में बड़ा संशय है हथियार है देश के ब्रिटिश हिता को नुकसान पहुंचाने का'<sup>56</sup>

आंदोलन बड़ी तेजी से बढ़ा। ब्रिटिश व्यापार काफी घटा। जनसभाओं, प्रदर्शनों और हड़तालों का सिलसिला लग गया। बंबई में तिलक के केसरी और 'मराठा' में एव बंगाल में 'सध्या', 'बदमातरम', और 'जुगातर' ने लोगों को नई दृष्टि और नए कार्यक्रमों की दीक्षा दी।

सरकार ने अधिकाधिक तेजी से बढ़ते हुए दमन का रास्ता अपनाया। वायवाही आदेश द्वारा बंगाल प्रांतिशियल काँग्रेस को भंग कर दिया गया। नेताओं और आंदोलन के प्रचारकों और संगठनकर्ताओं का गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया।

शामकर बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब में जातिवादियों दला का उदय हुआ जिन्होंने काफी काम किया। राजनीति में अकृतिमा और अफगरी की हत्या की की

गई। इन दिनों के नातिकारी और आतंकवादी आंदोलनों का संक्षिप्त इतिहास जागे दिया जाएगा।

### कांग्रेस में फूट, 1907

1907 में कांग्रेस में उदारवादियों और वामपंथी राष्ट्रवादियों में फूट हा गई। यह विभाजन अवश्यभावों था क्योंकि उदारवादियों ने नए राष्ट्रवादियों की विचारधारा और कार्यक्रमों को स्वीकार नहीं किया, यद्यपि सरकार की कार्यवाही से उनका भी लगातार माहभंग होता रहा था।

1907 में कांग्रेस का दो दिनों का लुफानी मूरत अधिवेशन हो हल्ला के साथ समाप्त हा गया। उदारवादियों ने शीघ्र ही सम्मेलन बुलाया जिसमें पारित प्रस्ताव में कहा गया

जसा स्वायत्त शासन ब्रिटिश साम्राज्य के जय देशों में है वसा ही भारत में स्थापित करना इंडियन नेशनल कांग्रेस का अंतिम लक्ष्य है। यह इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कटुतर साविधानिय तरीकों से ही वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था में क्रमिक, समयित सुधार के रास्ते जागे बडेगा।

उग्रवादियों का कहना था कि उह कांग्रेस से अलग रखने के लिए उदारवादियों ने इस आशय का संविधान अपनाया था।

1907 के बाद सरकार की दमनात्मक कार्यवाही में तेजी आई। 1907 में इमने सेडीशंस मीटिंगमें (राजद्रोहात्मक सभा) एकट और 1910 में इंडियन प्रेंस ऐक्ट पारित किया। बंगाल में बदमातरमें 'जुगातर' आदि कई अपवार सरकार द्वारा बंद कर दिए गए। मिना, ए० क० दत्त, एस० चक्रवर्ती और पी० बी० दास जैसे कई प्रख्यात नेताओं को दस निकाला मिला। एक नातिकारी पंडित से सबद्ध हान के आरोप पर 1908 में जरबिद धाप का गिरफ्तार कर लिया गया लेकिन सबूत के अभाव में उह छोड दिया गया। फिर किसी नए आरोप पर उह गिरफ्तार किया जा सके इसक पहले ही ब्रिटिश भारत छोडकर पांडिचरी में जा बसे।

नए राष्ट्रवाद के दुर्दम्य नेता थे और जो स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इस लकर रहगे नार के ज मदाता तिलक का अपन पत्र में प्रकाशित एक लेख के लिए 1908 में छ वर्ष की सजा मिली और उह मडाल भेज दिया गया। यायालय में अपन भाषण के क्रम में तिलक ने रहा 'नियति की निष्पायक कुछ जय उच्चतर शक्तिया हू और विधि का यही विधान होगा कि जिस लक्ष्य के लिए मैं मघपशील हू वह मेरी मुक्ति की अपथा मेरी यातनाओं के जरिए ही अधिक जामानी में उपलब्ध हा।'<sup>57</sup> मडाल व्रत में तिनक ने दि जाकटिक हाम जाफ द बदाज और गीता रहस्य नामक पुस्तकें लिखीं। इन पुस्तकों में उनका प्रमाण नाशनिक् और एतिहासिक तान और अतनुद्धि का परिचय मिलता है।

पंजाब में लाहौर, लायलपुर और रावलपिंडी में कनाल बालनी विल और अन्य कारणों से किसानों के दंगे हुए और लाला लाजपत राय एवं अजीतसिंह को प्रात के बाहर भेज दिया गया।

### मालि मिटो रिफार्म्स और उसके बाद

चूँकि दमन नीति के बावजूद आंदोलन बढ़ता ही जा रहा था इसलिए राजनीतिक समझदारी इसी में थी कि कुछ सुधारों के द्वारा राष्ट्रवादियों का मन जीतने की कोशिश की जाए। मालि मिटो सुधारों के जरिए सरकार ने केंद्रीय और प्रांतीय विधायिका परिषदों में कुछ निर्वाचित सदस्यों का विधान किया, यद्यपि ये परिषदें केवल राय दे सकती थीं इनके पास कोई निर्णायक शक्ति नहीं थी।

उग्रवादियों ने इन सुधारों को असंतोषजनक कहा, लेकिन नरम दल वालों ने इनका अभिनंदन किया। इन सुधारों से कुछ हद तक ब्रिटिश सरकार की नीयत और प्रतिनाओं में नरम दल की जास्था वापस आई जो ब्रिटिश सरकार की हाल की कारवाइयों से खतम हो रही थी। 1911 में वंग विभाजन को रद्द कर देने से यह आस्था कुछ और मजबूत हुई।

1914 में पहला विश्वयुद्ध शुरू हुआ। हाउस ऑफ कामंस में सन्नेटरी आफ स्टेट ने घोषणा की कि ब्रिटिश नीति का लक्ष्य है भारत में क्रमशः जिम्मेदार सरकार की स्थापना।

युद्ध में भारतीय वृजुजाजी से और अधिक मदद लेने के लिए सरकार ने 1916 में सूती वस्त्रों पर 3½% आयात शुल्क लगाया, जिससे भारत में कपड़ा उद्योग के विकास को काफी बल मिला।

लेकिन इन सब कार्यों से वामपंथी राष्ट्रवादी तत्व सन्तुष्ट नहीं हुए और लडाइ के दरम्यान वे स्वराज का अपना सघष चलाते रहे। 1914 में जेल से निकलने पर तिनक न भारत में होमरूल के लिए आंदोलन शुरू किए और 1916 में पूना में होमरूल लीग की स्थापना की। 6 महीने बाद एनी बमोंट ने भद्रास में जाल इंडिया होमरूल लीग की शुरुआत की।

1916 के लखनऊ कांग्रेस में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल वाले फिर से एक हो गए। लेकिन यह एकता कुछ ही दिन चली। इस काल की एक अन्य महत्वपूर्ण घटना है 1916 में कांग्रेस और मुसलिम लीग का सहयोग, जिस लखनऊ पैक्ट या कांग्रेस लीग योजना के नाम से जाना जाता है। ब्रिटन तुर्की के खिलाफ युद्ध में लगा था और तुर्की में मुसलिम राज्य का इसलिए ब्रिटन के खिलाफ मुसलमानों में काफी रोष था। लीग और कांग्रेस की संयुक्त योजना के अनुसार काउंसिल में चुने हुए सदस्यों को यहूमत काउंसिलों का और अधिक अधिकार, वायसरॉय की वायकारिणी में आधी मदम्यता व भारतीयकरण, जादि मुंधारा की मांग की गई। मुसलिम लीग और कांग्रेस की राजनीतिक एकता का महत्व है। मुहम्मदावाद के राजा मजहूरुलहक, ए० रमूल और जिन्ना तीनों का नेता था।

होमरूल आंदोलन सरकार की दमन नीति का लक्ष्य बना हुआ था। वेसेंट के 'यू इंडिया' से जमानत की बहुत बड़ी रकम मांगी गई और वह जमानत कर ली गई। 1917 में एनी वेसेंट का उटकमंड मंजूर कर लिया गया। उनकी जीर वाडिया एव अरुडले जैसे अन्य नेताओं की नजरबंदी से होमरूल लीग काफी जनप्रिय हुआ और कुछ दिनों बाद जिन्ना भी इसमें शामिल हो गए। 1917 में तिलक और पाल को पंजाब और दिल्ली से बाहर चले जाने का आदेश दिया गया।

1918 में उदारवादियों ने कांग्रेस में संघर्ष विच्छेद कर लिया और लिबरल फेडरेशन की स्थापना की। हाल ही में घोषित मोटेग्यु चेम्सफोर्ड रिफॉर्म स के बारे में मतभेद के कारण ही यह फूट पड़ी थी। उदारवादी नए सुधारों के अनुसार विधान के कार्यान्वयन के पक्ष में थे, लेकिन 1918 के कांग्रेस अधिवेशन ने इन सुधारों के बहिष्कार का प्रस्ताव लिया।

### आतंकवादी और क्रांतिकारी आंदोलन का उदय

राष्ट्रीय आंदोलन के अगले चरण की प्रमुख घटनाओं के अवलोकन के पहले, बीसवीं सदी के प्रथम दशक में जो क्रांतिकारी और आतंकवादी आंदोलन हुए थे, उनका संक्षिप्त विवरण आवश्यक है। उदारवादियों के कार्यक्रम और कार्य रीति की असफलता से हुए मोहभंग यूरोप के देशों के क्रांतिकारी आंदोलनों तथा रूसी शून्वादियों एवं अन्य यूरोपियन गुप्त दलों द्वारा अपनाए गए पडयत्नकारी आतंकवादी तरीकों के अध्ययन ने कुछ भारतीयों को हिंदुस्तान में भी आतंकवादी संगठन और कार्यप्रणाली की प्रेरणा दी।

राज्य के शासनकाल में सरकार द्वारा उठाए गए कदम और राष्ट्रीय आंदोलन के विरुद्ध की गई दमनकारी शरणाइ के कारण उदारवादी लोग भी लडाकू बहिष्कार आंदोलन का समर्थन करने लग गये। वे भी विधान सभा के उद्घाटन राजनीतिक आतंकवाद का रास्ता अपनाया। इनके कार्यक्रम में राजनीतिक हत्या भी शामिल थी। धामकर नाम का फसला भी। ऐसी उम्मीद की जाती थी कि अफसरशाही में आतंक फैलगा और उनका मनावल कमजोर होगा। इन आतंकवादियों का यह भी खयाल था कि अगर राजनीतिक हत्या का कार्यक्रम बड़े पैमाने पर अपनाया जाए तो उससे सशस्त्र क्रांति के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार होगा। धनी भारतीयों और सरकार से पना लन की नीयत से सशस्त्र डकैती भी इनके कार्यक्रम में शामिल थी। गुप्त महाराजा वम बनान की प्रयोगशालाओं हथियार बनान के लिए कारखाना जादि भी स्थापना और गचातन के लिए इन्हें भय की जम्मत था। कुछ ऐसे क्रांतिकारी दलों का भी जन्म हुआ जिनका कार्यक्रम अहिंसक व्यापक था। ये लोग में विद्रोह और विमानों की बगावत कराना चाहते थे।

बंगाल पंजाब और महाराष्ट्र इन क्रांतिकारों और आतंकवादी कार्यवाहियों



के मुख्य केंद्र थे। बंगाल जातकवाद का तूफानी केंद्र बिदु या सभवतः इसलिए कि बंगाल में शिक्षित नौजवान बहुत बड़ी तादाद में वेकार थे और सभवतः इसलिए भी कि बंगाली चरित्र विशेष रूप से भाव प्रवण है। नातिकारियों और जातकवादियों ने भारत के बाहर लंदन, पेरिस और यूनाइटेड में भी अपने केंद्र स्थापित किए थे। अब हम संक्षेप में इन आंदोलनों से संबंधित प्रमुख आघातों और घटनाओं की चर्चा करेंगे।<sup>58</sup> 1897 में पूना में रड और आयस्ट की हत्या की पहली ही चर्चा की जा चुकी है।

श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में इंडियन हामरूल सोसायटी की और कुछ ही दिनों बाद हाइगेट में इंडिया हाउस की स्थापना की। दोनों नातिकारी केंद्र थे। यहाँ नातिकारी साहित्य और हथियार तैयार किए गए जो जबैध तरीके से भारत भेजे गए। भारत में नाजायज रूप से भेजे गए ऐसे एक पफलेट का नाम था 'बंदे मातरम्' जिसमें कजन वाइली की हत्या की प्रशंसा की गई थी। वाइली इंडिया आफिस का अधिकारी था और 1909 में इंडिया हाउस के सदस्य डीगरान उसकी हत्या की। इस पुस्तिका में राजनीतिक जातकवाद की भूमिका के बारे में कहा गया 'हिंदुस्तानी और अंग्रेज हर तरह के सरकारी अधिकारी को जातकृत किए रहो और तब अत्याचार के समूच यंत्र का विनाश समीप होगा अलग अलग हत्याओं का तरीका अफसरशाही को क्रियाहीन बनाने और लोगों को जगान का सभसे अधिक कारगर सभव तरीका है।'<sup>59</sup>

वी० डी० सावरकर इंग्लैंड में कृष्ण वर्मा के बहुत बड़े सहयोगी थे। वी० डी० सावरकर के भाई जी० डी० सावरकर हिंदुस्तान में थे। उन्हें नातिकारी कार्य के लिए ज़िदगी भर के लिए दश निकासे की सजा मिली। उसी साल नासिक में जैक्सन पर, जिसने सावरकर को सजा दी थी गोली चलाई गई। इस सिलसिले में चलाए गए नासिक पडयंत्र केस में वा हर को मृत्यु की और सत्ताइस जय जादमिया को जेल की सजा मिली। 1909 में तत्कालीन वायसराय लार्ड मिंटो की हत्या का प्रयास हुआ।

बंगाल में यह आंदोलन काफी लोकप्रिय हुआ। रीनेट रिपाट के अनुसार अनुशीलन समिति जातकवादियों का प्रमुख संगठन थी। बलकत्ता और ढाका में इनके मुख्य केंद्र थे, यों सारे प्रांत में इनके और भी कई छांट पाट केंद्र थे। अनुशीलन समिति ने नातिकारी साहित्य का प्रचार और गुप्त दलों का संगठन किया।

बंग विभाजन के बाद के दिनों बंगाल में जातकवादी काफी सक्रिय रहे। बम और पिस्तौल जातकवादियों का प्रमुख हथियार थे और उनकी बजह में बहुत सारे पुलिस अफसरों, मजिस्ट्रेटों, मुखविरा और सरकारी बकीला को भी जान में हाथ धोना पड़ा। अलीपुर पडयंत्र केस के मुखविरा गासाइ और इस मुकदमे में पुलिस, बरील तथा जार ती अधीशक बाद में जातकवादियों द्वारा मार गए। इस प्रांत में इन तरह के कई पडयंत्र केस हुए, जिनसे पता चलता

क्रांतिकारी दलों की कायवाही कितनी व्यापक थी।

अरविंद और वारींद्र घोष जैसे कुछ राष्ट्रवादी नेताओं के बारे में संदेह था कि वे आत्मकवादी और क्रांतिकारी आंदोलनों के बड़े करीब थे। 1908 में पंडित के आरोप पर अरविंद को गिरफ्तार किया गया, लेकिन सबूत की कमी के कारण उन्हें रिहा कर दिया गया। बाद में वे ब्रिटिश भूक्षेत्र छोड़कर पाकिस्तान में रहने लगे। मार्शल मिटो रिफॉर्म से और 1911 में बंग विभाजन के समाप्त हो जाने के बाद भी बंगाल में आत्मकवाद जीवित रहा।

पंजाब में क्रांतिकारी दल 1907 में बने। इनमें बहुत सारे क्रांतिकारी जाय समाजी थे। 1912 के बाद कुछ मुसलमान भी इस आंदोलन में शरीक हुए। हरदयाल 1910 में यूरोप से भारत लौटे और उन्होंने पंजाब में क्रांतिकारी दल संगठित किए। इस कार्य में उन्हें खासकर रासबिहारी और अमीनचंद से मदद मिली। 1911 में लाहौर में, एक बम विस्फोट के सिलसिले में अमीनचंद और अन्य लोग गिरफ्तार हुए उन पर मुकदमा चला और उन्हें फांसी की सजा मिली। दिल्ली में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या की चेष्टा हुई।

1911 में अमरीका पहुंचने के बाद हरदयाल ने वहां क्रांतिकारी संगठन बनाए और 1914 में सनफ्रान्सिस्को से 'गदर' (विद्रोह) नामक पत्र निकालना शुरू किया। अमरीका सरकार ने उन्हें 1914 में गिरफ्तार कर लिया। उन्हें जमानत पर छोड़ा गया और तब बरकतुल्ला के साथ वे स्ट्रिटजरलैंड भाग गए। उनके जाने के बाद रामचंद्र गलर आंदोलन के नेता हुए।

गदर पार्टी के लोग अमरीका में रहने वाले भारतीयों के बीच आप्रवास कानूनों के विरुद्ध आंदोलन संगठित कर रहे थे। 1914 में, कई भारतीय यात्रियों, खासकर सिक्खा और मुसलमानों को लेकर, 'बामागाटा मार्ब' नामक जहाज हांगकांग से वैनकुवर के लिए रवाना हुआ। जब जहाज बनपुर पहुंचा तो कनाडा की सरकार ने यात्रियों को उतरने नहीं दिया। सरकार का कहना था कि उसके आप्रवास मवधी कानून इन यात्रियों का कनाडा जान से अनुमति नहीं देते। जहाज जयदस्ती बंदरगाह से बाहर भेज दिया गया। हांगकांग के बंदर जहाज बलकत्ता लाया गया जहां सरकार ने उन्हें सीधे पंजाब पहुंचा देने के लिए पहल सही गाड़ी ठीक कर रखी थी। करीब तीन सौ सिक्खों ने पंजाब जान से इंकार कर दिया। फलस्वरूप जा गोली चली उसमें अठारह आदमी मार गए। बाद में कुछ सिक्खों, गिरफ्तार कर लिए गए। जा पंजाब वापस गए वे भी काफी क्रुद्ध थे। उन्होंने क्रांतिकारी केंद्र बनाए और लोगों में क्रांतिकारी आंदोलन संगठित किए।

इन क्रांतिकारी दलों ने 1914-15 में पंजाब और अन्य प्रांतों में भी कई प्रचार के कार्य किए, जिनमें सशस्त्र डकैती, पुलिस अफसरों की हत्या, पंजाब की मनिव टुकड़ियों और मरठ तथा बानपुर जस पत्रिका बंदों में क्रांतिकारी प्रचार आदि।

सरकार ने 1915 में डिफेंस आफ इंडिया एक्ट पारित किया, जिसमें

अधिकारिया को नजरबंदी का अधिकार मिला। सरकार ने विशेष ट्राइब्यूनल्स भी बहाल किए जिन्होंने वाद में बीस आदमियों को मीत की, अट्ठावन को आजीवन कारावास की और अट्ठावन को थोड़े दिनों के लिए कैद की सजा दी।<sup>60</sup> इसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन क्षीणप्राय हो गया।

गदर के नेताओं ने यूनाइटेड और शघाई के जमान कौंसिल से राजनीतिक संपर्क स्थापित किया। 1915 में रगून के एक बलूच रेजिमेंट और सिंगापुर की पाचवीं लाइट इनफैंट्री में विद्रोह के बीज बोने में भी उन्हें सफलता मिली, लेकिन विद्रोह दबा दिए गए।

### मीटिंग्स-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट्स

मीटिंग्स चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1918 में प्रकाशित हुई। इस प्रतिवेदन पर आधारित रिपोर्ट्स स एक्ट जगले साल पारित हुआ। इस रिपोर्ट ने द्वैतप्रथा शुरू की, जिसके अनुसार प्रांतीय सरकार के अधीनस्थ विषय दो भागों में बांट दिए गए, 'हस्तांतरित' और 'सुरक्षित'। हस्तांतरित विषय मंत्रियों के जिम्मे दिए गए जो निर्वाचित विधायिका सभा के प्रति जिम्मेदार थे। इनमें स्थानीय शासन, जन स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे विषय थे। वित्त, भू राजस्व, पुलिस इत्यादि सुरक्षित विषय थे, जो मंत्रियों के नियंत्रण में नहीं थे।

इन सुधारों की आलोचना का प्रमुख यह आधार था कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषय सुरक्षित रखे गए थे और 'हस्तांतरित' विषयों में भी वास्तविक प्रगति के लिए वित्त की आवश्यकता थी जो मंत्रियों के नियंत्रण के बाहर था। इस प्रतिवेदन में कांग्रेस और लीग की उन मांगों की कोई सुनवाई नहीं थी, जो कांग्रेस और लीग की सम्मिलित योजना में प्रस्तुत की गई थी। इस योजना में भारत के लिए आत्मनिर्धारण के सिद्धांत और आत्मशासन की भी मांग की गई थी।

मुस्लिम लीग ने मीटिंग्स-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट को जस्वीकार कर दिया और 1918 में कांग्रेस लीग योजना दुहराई। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1918 के जत में अपना अधिवेशन किया, और इसमें यह प्रस्ताव पारित किया गया कि भारत का प्रगतिशील राष्ट्र माना जाए और उस आत्मनिर्धारण का अधिकार दिया जाए।' दिल्ली कांग्रेस ने भी भारत के लिए पूर्ण उत्तरदायी सरकार की मांग का प्रस्ताव पारित किया। इसने भी कांग्रेस लीग योजना की बातें दुहराई।

युद्ध और युद्ध के बाद भारतीय जनता में अमतोष फैला। युद्ध का वित्तीय भार, मूल्यों में वृद्धि, मुनाफाखोरी आदि से जननाधारण की जायिक तकलीफें काफी तजी से बढ़ीं। युद्ध के बाद बड़े अर्थकर रूप में इनपलुएजा की महामारी आई जिसमें बहुत सारे लोग मरे।

लड़ाई के बाद जर्मनी, जास्ट्रिया और रूस में प्रांतिया हुई, जिनके फलस्वरूप हाइनब्रालन, हैम्बर्ग और रामानाव राजवंश राजच्युत हो गए। इन प्रांतियों का एशिया के लागा के दिमाग पर काफी असर पड़ा। एशिया के देशों में व्यापक

राजनीतिक उद्वेग का जन्म हुआ। इधर तिलक और जय लोगो के होमरूल आंदोलन ने भी लोगो की राजनीतिक चेतना बढ़ाई और इस तरह जनसाधारण को आधार बनाकर राष्ट्रीय आंदोलन के संगठन के लिए वातावरण तैयार हुआ।

चूँकि डिफेंस ऑफ इंडिया ऐक्ट लड़ाई के बाद समाप्त हो जाने वाला था, इसलिए 1919 में भारत सरकार ने रीलेट बिल के जरिए कार्याकारिणी (प्रशासन) को व्यापक अधिकार देना चाहा, जैसे मुकदमा चलाए बिना लोगो का गिरफ्तार कराने का अधिकार। लोगो के हर तबके ने बिल का विरोध किया। गांधी ने धमकी दी कि बिल कानून हो जाएगा तो वे सत्याग्रह करेंगे। लोगो के विरोध के बावजूद मार्च में रीलेट बिल पारित हो गया। नेताजी ने 6 अप्रैल को नए कानून के प्रति विरोध प्रदर्शन का फैसला लिया और इस दिन सार देश में हड़ताल, प्रदर्शन आदि हुए।

हिंदुओं और मुसलमानों में अभूतपूर्व भ्रातृत्व इस साधारण उत्तेजना का एक द्रष्टव्य तत्व था। राष्ट्रीय मंच पर उनके नेताओं की एकता काफी दिनों से स्थापित हो चुकी थी। जनता के इस उभार के दिनों में साधारण लोग भी अपने विभेद भूल गए। मेल-मिलाप के असाधारण दृश्य देखने के लिए हिंदुओं ने मुसलमानों के हाथ से पानी पिया और मुसलमानों ने हिंदुओं के हाथ से। इन जुलूसों की पताकाओं पर हिंदू-मुसलिम ऐक्य का ही नारा सर्वप्रमुख था और प्रायः यही नारा लगाया भी जाता था। एक मसजिद के मंच से हिंदू नेताओं को भाषण भी देने दिया गया था। (इंडिया, 1919)

अमृतसर के अधिकारियों ने पंजाब कांग्रेस के दो नेताओं सत्यपाल और डा० बिचलू को किसी अनात जगह भेज दिया। इससे जनता का उद्वेग बढ़ा और अमृतसर, गुजरात वाला और कुमूर में हिंसात्मक कार्य हुए। दिल्ली, कलकत्ता, बंबई, अहमदाबाद और भारत के अन्य भागों में भी उपद्रव हुए। गोलीबाद और कारावास के रूप में सरकारी दमन कार्य भी बढ़ा। इन सारे उत्पातों का कारण गांधी ने सत्याग्रह वापस ले लिया।

### जालियावाला बाग की दुःखद घटना

13 अप्रैल को अमृतसर में जालियावाला बाग की दुःखद घटना घटी। जनरल डायर के आदेशानुसार शांतिपूर्ण सभा में हाजिर तिहत्तों लोगों पर सैनिकों द्वारा किए गए गोलीबाद में 400 आदमी मरे और 1200 घायल हुए। जब लोगो ने उस घटना की खबर पढ़ी तो क्रोध और आतंक की एक लहर फैल गई।

15 अप्रैल को लाहौर अमृतसर और पंजाब के कई जिलों में फौजों को कानून लागू कर दिया गया। खास कचहरिया घाली गई जिनमें सरकारी तौर पर ब्यापक हाता था। बहुत बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी हुई और लोगो का सारा सारा और मृत्यु की सजा दी गई। बांड की मार की भी सजा दी जान लगी और अमृतसर की एक खास गली में जा लाग पुजस्त वे उह पट के बन चलन का बाध्य किया

जाता था।<sup>61</sup> फौजी कानून 11 जून तक चला। उस अवधि में पंजाब को सेमरशिप के जरिए देश के और भागों से पूरी तरह अलग रखा गया। जलियावाला बाग की घटना आठ महीने बाद विलायत पहुंची।

लोगों की जोरदार मांग के फलस्वरूप जलियावाला बाग की घटना की जांच करने के लिए हटर कमेटी बहाल हुई। कमेटी ने मार्च, 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। रिपोर्ट में केवल इतना कहा गया कि डायर का कार्य गंभीर आनुमानिक त्रुटि का परिणाम था जो हालत की युक्तिमगत आवश्यकताओं और हृदा से आगे बढ़ गया। सेक्रेटरी आफ स्टेट माटेग्यु ने इस विचार की पुष्टि की और कहा कि डायर उद्देश्य की ईमानदारी और कर्तव्य की निर्भीक भावना से अनुप्रेरित था। अमंगत कारावास गोलीकांड कशाघात जैसे तरीकों से पंजाब में आंदोलन का दमन करनेवाला और डायर के लिए जिन लोगों ने सजा की मांग की थी उन्हें इस रिपोर्ट से सतोष नहीं हुआ। कांग्रेस ने अपनी अलग समिति बनाई जिसकी मांग में प्रकाशित रिपोर्ट में सरकार द्वारा किए गए विभिन्न दमन कार्यों की गिनती भी थी।

1919 में जन आंदोलन का तेजी से विकास हुआ। राजनीतिक आंदोलन, हड़ताल आदि बढ़ रहे थे। राष्ट्रीय आंदोलन को पहली बार जन आधार मिल रहा था और लोगों में राजनीतिक उद्वेग बढ़ रहा था।

1919 के अंत में अमृतसर में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तिलक प्रतिस्वेदी सहयोग की नीति के समर्थक थे। सी० जार० दास का कहना था कि रिफॉर्म को अस्वीकार कर देना चाहिए। गांधी ने अपना दृष्टिकोण इन शब्दों में प्रस्तुत किया रिफॉर्म एक्ट और तत्संबंधी बकबक ब्रिटिश जनता के इस अभिप्राय के परिचायक है कि वह भारत के साथ धाय करना चाहती है और जब इस संबंध में कोई सदेह नहीं रहना चाहिए इसलिए हमारा कर्तव्य है कि रिफॉर्म को कटु आलोचना न कर हम उसका हृदय बनाने के प्रयास करें।<sup>62</sup>

अमृतसर कांग्रेस के समझौतावादी प्रस्ताव में कहा गया रिफॉर्म एक्ट अपर्याप्त असतोषप्रद और निराशाजनक है इस कांग्रेस का यह भी मत है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट आत्म निर्धारण के सिद्धांत के अनुसार भारत में पूर्ण उत्तरदाई सरकार बनाने के लिए कदम उठाए। लेकिन इस कांग्रेस का विश्वास है कि ऐसा हान तक लागू यथामभव रिफॉर्म को इस तरह कार्यान्वित करेंगे कि पूर्ण उत्तरदाई सरकार की शीघ्र स्थापना हो सके।'

असतोषप्रद रिफॉर्म एक्ट, रोलेट एक्ट, पंजाब में फौजी शासन और सरकार की आम दमनारम्भ नीति के कारण जो राजनीतिक तनाव बाधक हुआ था वह खिलाफत के सवाल के कारण 1920 में और अधिक बढ़ा। भारतीय मुसलमान सत्रों की संधि की शर्तों से क्रुद्ध थे। उनके अनुसार मुसलिम राज्य तुर्की को सारिया, फिजीस्तीन, अरब और तुर्की साम्राज्य के अन्य एशियाई इलाकों से वंचित कर दिया गया। मुसलमानों का कहना था कि उनका पवित्र स्थान इही

भूखोना में स्थित है, इसलिए यह क्षेत्र हरदम तुर्की के मुलतान के अधीन होने चाहिए, क्योंकि वह सारी दुनिया के मुसलमानों का खलीफा अर्थात् धार्मिक नेता है। गांधी और दूसरे कांग्रेसी नेता खिलाफत के पक्ष में थे और उन्होंने मुहम्मद अली और शौकत अली के साथ देश में शक्तिशाली खिलाफत आंदोलन चलाया। सेव्रेज की संधि की शर्तों में, 1920 में प्रकाशित हुई। जून में इलाहाबाद में सभी दलों के संयुक्त सम्मेलन में कार्यक्रम तैयार करने के लिए, गांधी और प्रमुख मुसलिम नेताओं की कमेटी बनी।

खिलाफत आंदोलन के कारण मुसलमान राष्ट्रीय आंदोलन के करीब आए। खिलाफत, पंजाब के दमन काय और ताकाफी सुधारों का अदृश्य प्रवाह, इस त्रिवेणी में राष्ट्रीय आंदोलन की धारा को आयतन एवं परिमाण दोनों दृष्टियों से समृद्ध बनाया। स्थिति सब तरह से असहयोग के लिए परिपक्व थी।<sup>63</sup> तिलक में अहिंसक असहयोग के आंदोलन के लिए बहुत उत्साह नहीं था। लेकिन उन्होंने इसका विरोध नहीं किया और न इसमें उन्होंने बाधा ही डाली।<sup>64</sup> अगस्त 1920 को तिलक का देहावसान हो गया।

### गांधी और गांधीवाद का दौर

असहयोग आंदोलन से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नए दौर की शुरुआत होती है। इस दौर में आंदोलन के सर्वप्रमुख नेता गांधी थे और गांधीवाद इसका दर्शन था। गांधी भीमकाय पुरुष की तरह समूचे दृश्यपट पर छा गए। राष्ट्रीय आंदोलन का उनका अनुदान अनन्य और अद्वितीय है। राष्ट्रीय मुक्ति के सपने में जनसाधारण और जन आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका का समर्थन वाले वे पहले राष्ट्रीय नेता थे। पहले के नेताओं इस सपने को कारगर बनाने में जनता के निर्णायक महत्व का नहीं समझ रहे थे।

गांधी ने सपने का ऐसा कार्यक्रम बनाया जिसमें जनसाधारण राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति जागरूक हो सकें और मजदूर किसान, पूजापति विद्यार्थी बगीचे दूसरे पेशेवर लोग, जोरों-जोरों से सब तरह के लिए इस आंदोलन में भाग ले सकें। अपने विचारों की सीमा-जा, चामिया कमजोरियों के बावजूद, पहली बार गांधी ने ही राष्ट्रीय आंदोलन का जनसाधारण का बहुबर्गीय आधार प्रदान किया। उनके नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय स्वातंत्र्य संग्राम का बीर, दशमकत, निर्भीक योद्धा मित्र हुए। बड़ी ता'द में लोग जेल गए और बहादुरी से साम्राज्य की पुलिस और मना की गलियाँ और लाठियों का सामना किया। अपनी समझौता परस्त नीति के बावजूद गांधी ने लोपा में शतान्तरित स्वयं चिट्ठी सरकार के प्रति जबरजस्त घृणा और स्वराज्य का अदमनीय विषाक्त भर दो।

किसानों के लिए उनका कार्यक्रम था कि वे सरकार को नाराज न रहें। इसमें सरकार के आर्थिक आधार के कमजोर होने का ध्यान रखा गया। उन्होंने छात्रों से शिक्षण-अभ्यास छाड़ने का अनुरोध किया क्योंकि शिक्षण-अभ्यास ही

सरकारी अफसर और कमचारी निकलते थे। उन्होंने बकीला से कचहरिया छाडन को, कहा, जिससे सरकार की कानून व्यवस्था ठप्प हो जाए। उन्होंने औरतो का आह्वान किया शराब और विदेशी कपडों की दुकानों की पिकेटिंग करने के लिए, और औरतो ने हजारों की तादाद में यह काम किया और जेल गई। उन्होंने लोगो से कहा कि वे सरकार द्वारा बनाए गए अनुचित कानूनों का उल्लंघन करें। उनके आह्वान पर करोड़ों की तादाद में लोग गोली और लाठी की बौछार के बीच जुलूस और गैर कानूनी सभाओं में सम्मिलित हुए।

यह बड़ा उत्साहवर्द्धक दृश्य था कि हजारों लाखों की तादाद में औरतो, जो सदियों से मकीण घरेलू जीवन की शृंखला में आबद्ध थी और जिन्हें सत्तावादी सामाजिक व्यवस्था ने घर में गुलामों की तरह रखा था, सड़कों पर आ निकली और उन्होंने अपने पुरुष साथी देशभक्ता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर गैर कानूनी प्रदर्शनों में भाग लिया।

गांधी ने अपने पूर्ववर्ती काल से वायकाट' और स्वदेशी जैसे तरीके अपनाए और उनका इस्तेमाल किया, लेकिन उन्होंने ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालने के और भी अधिक कारगर नए तरीके भी अपनाए सत्याग्रह असहयोग, नागरिक अहिंसा (व्यक्तिगत एवं सामूहिक) करना देना कानूनों का खुला उल्लंघन जान-बूझकर जेल जाना सांजनिक प्रदर्शन और जुलूस, भूख हड़ताल, राष्ट्रीय सघष को उन्होंने प्रमुख नए अस्त्र दिए।

गांधी राजनीतिक क्षेत्र में तो महान व्यक्तित्व थे ही, वे बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे। वे मानवता की भावना से जातप्रोत थे, और उन्होंने सामाजिक संघर्षों के हर क्षेत्र में अत्याय के विरुद्ध जेहाद किया। सबसे अधिक प्रपीडित वर्ग के विरुद्ध हिंदू समाज के चिरकालीन जघन्य अपराध के प्रतीक अस्पृश्यता की क्रूर, बुरा प्रथा की उन्होंने नतिक आक्रांश के आगम्य शब्दों में भर्त्सना की। इस अति शय अमानुषिक प्रथा का निवारण, उन्मूलन के लिए उन्होंने सघष किए और इसे अपने राजनीतिक कार्यक्रम का आवश्यक अंग बनाया। उन्होंने उच्च वर्ग के हिंदुओं के नतिक भाव का जारदार शब्दों में आह्वान किया और युगों के अत्याय के विरुद्ध उनकी विवक बुद्धि को जागत करने की चेष्टा की।

गांधी क्लासिकल किस्म के राष्ट्रवादी नता थे और इसलिए पूरी तरह सांप्रदायिकता विरोधी। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों की सांप्रदायिकता का राष्ट्र विरोधी और मानवता विरोधी कहा और अपनी समस्त अर्थव्यवस्था अहित के साथ उनके खिलाफ युद्ध किया। अतः में उन्होंने 'भारतीय जन के सामाजिक संघर्षों से सांप्रदायिकता का उन्मूलन के लिए जीवित अघ्य के रूप में अपने जीवन रक्त का दान दिया।'

गांधी की रुचियां संघर्षों में और मनव्यापक या जिनकी परिधि भारतीय राष्ट्र जीवन का हर पहलू उजागर है। भाषा और साहित्य में भी रुचि थी। उन्होंने गुजराती का समृद्ध किया हिंदी का जनप्रिय बनाया था।

की विभिन्न भाषाओं के साहित्य पर भी अपनी अमिट छाप छोड़ी है।

इस बहुमुखी कार्यक्रम के कार्यायन के लिए महात्मा गांधी ने स्वयं आत्म-त्यागी पेनेवर कायकर्त्ताओं के जत्थे तयार करने के लिए कई केंद्र स्थापित किए और जय लोगा को भी ऐसे केंद्र खोलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सामाजिक राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षिक संस्थाओं का जाल बिछा दिया। इनमें प्रशिक्षित कायकर्त्ताओं ने उन सिद्धांतों के आधार पर जिन्हें गांधीवाद की सज्ञा दी गई है, गांधी द्वारा चलाए गए कार्यक्रम की सफलता के लिए काम किए।

### असहयोग आंदोलन

सितंबर, 1920 के कलकत्ता कांग्रेस में अहिंसक असहयोग का कार्यक्रम स्वीकार करते हुए एक प्रस्ताव पारित हुआ। ऐसे संघर्ष के पिछले अनुभव के कारण गांधी का इस आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया। यह आंदोलन तब तक चलाया जानेवाला था जब तक शिनाफ्त और पंजाब सबकी गलतियां सुधार नहीं ली जाती और स्वराज्य स्थापित नहीं हो जाता।

गांधी नैतिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों को राजनीति में सत्याग्रह आंदोलन का आधार बनाया। इस तरह उन्होंने राजनीति में धर्म का पुट मिलाया और इस तरह राजनीति का रहस्यवादी स्वरूप प्रदान किया। राजनीतिक आंदोलन के सिद्धांतों और कार्यक्रमों को निश्चित करने का उनका मानदंड यह था कि उनसे भारतीय जनता की नैतिक शक्ति कितनी मजबूत होती है। उन्होंने प्रायः 'आरंभिक बल' अमृत सत्य' (सत्य का परिभाषित किए बिना), और राजनीतिक विरोधी के नैतिक हृदय परिवर्तन की चर्चा की। जब वस्तुनिष्ठ शक्तियों के बानािक विश्लेषण के बदले अमृत और जस्पष्ट धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर राजनीतिक कार्यक्रम का निरूपण होता है, तब उसके उद्देश्य और लक्ष्य की स्पष्टता और कार्यक्रम की ताकिकता समाप्त हो जाती है।

लोगों ने कांग्रेस के आह्वान पर आंदोलन में जमकर भाग लिया। विद्यार्थियों द्वारा शिक्षण संस्थाओं के स्वच्छापूर्ण परित्याग का शिक्षण संस्थाओं पर बड़ा बुरा असर पड़ा। लेकिन कचहरियों का बहिष्कार कुछ खास सफल नहीं हुआ।

इसी काल में कई स्वाधीन राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाएँ स्थापित हुईं जिनमें नेशनल मुसलिम युनिवर्सिटी अलीगढ़, गुजरात विद्यापीठ तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, बंगाल नेशनल युनिवर्सिटी, वाशी विद्यापीठ और बिहार विद्यापीठ।

दिसंबर, 1920 में कांग्रेस का साधारण अधिवेशन नागपुर में हुआ। कार्यक्रम व्यवस्थापित से पारित हुआ। कांग्रेस के पुराने लक्ष्य 'साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन' के बदले नया लक्ष्य निर्धारित हुआ, शांतिपूर्ण एवं बानािक तरीकों से स्वराज्य का स्थापना। यह तय हुआ कि अमृत सत्य आंदोलन बरकरार नहीं हान पर नागरिक जनता का कार्यक्रम अपनाया जाए। लेकिन इनके बारे में कोई स्पष्ट योजना नहीं थी और न कोई निश्चित लक्ष्य।



लेकिन सावजनीन अबना आंदोलन पर सबका मन लगा हुआ था। यह क्या था, यह क्या होगा? गांधी ने स्वयं कभी इसे परिभाषित नहीं किया कभी इसकी व्याख्या नहीं की, कभी इसे स्पष्ट तौर पर देखा या रूपायित नहीं किया, खुद अपने लिए भी नहीं। स्पष्ट, द्रष्टा और शुद्ध मानस को यह स्वयं पग पग पर स्पष्ट हो जाएगा <sup>65</sup>

कांग्रेस द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन के अलावा दूसरे तरह के भी आंदोलन इस काल में हुए, जस आसाम बंगाल रेलवे मजदूरों की हड़ताल, मिदनापुर जिले के किसानों का टक्स नहीं देना का आंदोलन मालावार का मापला विद्रोह और पंजाब में महतो के खिलाफ ज्वालियों का विद्रोह।

5 नवंबर 1921 को दिल्ली में कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति की सभा हुई और उसने तय किया कि नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाए। इसने प्रत्येक प्रांतीय कमेटी को अपने में क्षेत्र नागरिक अवज्ञा के कार्यावयन का पूरा अधिकार और उत्तरदायित्व सौंपा। भूराजस्व का भुगतान नहीं करना भी कार्यक्रम में शामिल था। प्रांतीय कमेटियों को यह अधिकार था कि वे इसके लिए जो भी तरीका उचित समझें उसके अनुसार काम करें। लेकिन नागरिक अवज्ञा आंदोलन के लिए चुने जाने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए कुछ आवश्यक शर्तें निश्चित कर दी गईं।

इसी अवधि में सरकार ने भारत में प्रिंस आफ वेल्स के आगमन का प्रवर्धन किया और कांग्रेस ने इसके बहिष्कार का नारा दिया। जब 17 नवंबर को प्रिंस आफ वेल्स भारत पहुंचे तो देश भर में हड़ताल और प्रदर्शन हुए। कई जगह दंगे हो गए। बंबई में चार दिन तक उपद्रव होत रहे। पुलिस ने कई जगहों पर गोली चलाई और कुल मिलाकर 53 आदमी मारे गए और 500 घायल हुए।

व्यापक जनहिंसा के कारण गांधी का काफी विक्षोभ हुआ और उन्होंने कहा कि उनकी नाक में स्वराज को बड़ी बुरी गंध आ रही है।

इस मौके पर देश में स्वयंसेवक आंदोलन में भी तर्जो आईं। कांग्रेस और खिलाफत के स्वयंसेवकों ने विदेशी कपड़ों की दुकानों पर पिकेटिंग की और हड़तालों संगठित की। उनकी सघ्ना गैर कानूनी करार दी गईं, फिर भी वे अपना काम करते रहें और बड़ी तादाद में गिरफ्तार होत रहें। सरकार ने आंदोलन के सभी प्रमुख नेताओं का साल छतम हान व पहले गिरफ्तार कर लिया था और उन्हें जेल भेज दिया, उनमें श्री० आर० दास, पंडित मातीलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, अली बखु आदि प्रमुख थे। केवल गांधी जेल में बाहर रहे।

बुजुआ नतत्व में भारतीय जनता का जन आंदोलन उस वक्त अपनी पराकाष्ठा पर था, जब साल के अंत में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अहमदाबाद में अपना अधिवेशन किया। इस अधिवेशन के निर्वाचित सभापति श्री० आर० दास जेल में थे, इसलिए उनकी जगह पर हरीम अजमल खां ने इसी अध्यक्षता की। इस

अधिवेशन का सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव था

यह कांग्रेस बाध्य होकर अपना यह निश्चय दज करती है कि जब तक पंजाब और खिलाफत के सिलसिले में की गई गलतियाँ सुधारी नहीं जाती, स्वराज की स्थापना नहीं होती, भारत सरकार का नियंत्रण गर जिम्मेवार कारपोरेशन के बदले देश की जनता के हाथों में नहीं चला जाता, तब तक पहले से भी अधिक उत्साह से जर्हिसक जसहयोग का कार्यक्रम चलता रहेगा।

इस अधिवेशन का विश्वास है कि 18 वरस या अधिक की आयु का प्रत्येक व्यक्ति तुरत स्वयंसेवक संगठन में शामिल होगा।

इस अधिवेशन का विचार है कि आवश्यक सुरक्षाओं के साथ व्यक्तिगत और सामूहिक नागरिक अबना पर ध्यान कद्रित करने के लिए जहा कहीं और जब तक आवश्यक ही अन्य सारे कांग्रेस कार्यक्रम रोक दिए जाए।

यह अधिवेशन महात्मा गांधी को कांग्रेस का एकरुमात्र कार्यक्रम अधिकारी नियुक्त करता है।

अधिवेशन में कांग्रेस के एक प्रमुख मुसलिम नेता मालाना हसरत मोहाना ने चेष्टा की कि स्वराज के राजनीतिक तत्व को स्पष्ट और निश्चित किया जाए। उन्होंने स्वराज की व्याख्या प्रस्तुत करनी चाही, सारे विदेशी नियंत्रण से मुक्त पूर्ण स्वतंत्रता। गांधी ने इस राय का विरोध किया। उन्होंने कहा, जिस हलकेपन के साथ इस प्रस्ताव पर आप में कुछ लोग विचार कर रहे हैं, उससे मुझे दुःख हुआ है। इससे मुझे तकलीफ हुई है क्योंकि इसमें उत्तरदायित्व का अभाव दिखाई पड़ता है।<sup>66</sup>

अहमदाबाद के कांग्रेस अधिवेशन में कर भुगतान नहीं करने की कोई चर्चा नहीं की गई। लाड रीडिंग ने इसे शुभ माना।

निममस बाल सप्ताह में कांग्रेस ने अपनी सालाना मीटिंग अहमदाबाद में की। वहाँ के दंग फसाद का गांधी पर काफी असर पड़ा और दंग के चलते वे सावजनिक नागरिक अबना के खतरा से अवगत हो गए, कांग्रेस के प्रस्तावों में इन बातों का सूत्र मिलता है, इन प्रस्तावों में नागरिक अबना के संगठन का आह्वान तो अवश्य किया गया, लेकिन टक्स नहीं देने की कोई बात नहीं हुई।<sup>67</sup>

जनवरी, 1922 के मध्य में एक सबदतीय सम्मेलन बुलाया गया, जिसकी अध्यक्षता सर एम० विश्वेश्वरैया ने की और जिसमें जिन्ना जयकर और अन्य लोग शामिल हुए। गांधी भी इस सम्मेलन में मौजूद थे और उन्होंने कांग्रेस की बातें रचीं। सम्मेलन ने सरकार की दमनात्मक नीति की निंदा की। इसने वाय मराय के साथ गंधि बाता के दरम्यान नागरिक अमहयोग आपस में लेने की राय कांग्रेस को दी। इसने खिलाफत पंजाब और स्वराज की समस्याओं के समाधान के लिए अधिष्ठान गानमय सम्मेलन का प्रस्ताव रखा। 17 जनवरी का कार्यक्रम की

कायकारिणी समिति ने कहा कि महीने के अंत तक नागरिक अवज्ञा का कार्यक्रम स्थगित रहेगा। लेकिन वायसराय ने सर्वदलीय सम्मेलन की राय नहीं स्वीकार की। फरवरी के अंत में वायसराय का 1 फरवरी को सूचित किया कि उन्होंने गुजरात के वारदोली जिले में नागरिक अवज्ञा की शुरुआत करने का फैसला ले लिया है।

5 फरवरी को युक्त प्रांत के चोरीचौरा नामक जगह में हिंसक कारवाही हुई। प्रमुख किसानों की एक भीड़ ने एक धान पर हमला कर दिया और उसमें आग लगा दी, जिससे 22 सिपाही मर गए। गांधी ने नागरिक अवज्ञा के कार्यक्रम को रोक देने का फैसला दिया। उन्होंने 12 फरवरी को वारदोली में कायकारिणी समिति की सभा बुलाई और यह प्रस्ताव पारित हुआ कि 'चोरीचौरा में भीड़ के अमानुषिक व्यवहार के कारण नागरिक अवज्ञा का कार्यक्रम रोक दिया जा रहा है। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि कायकारिणी समिति कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और मजदूरों को यह सलाह देती है कि वे किसानों को सूचित कर दें कि जमींदारों को मालगुजारी नहीं देना कांग्रेस का प्रस्ताव के प्रतिकूल है और देश हित के लिए हानिकारक।' इसमें जमींदारों को यह आश्वासन भी दिया कि कांग्रेस आंदोलन उनके कानूनी हक पर कोई हमला नहीं करना चाहता और जहा रयता का शिकायत भी है कायकारिणी की राय है कि उन शिकायतों को पारस्परिक राय मशविरे और पंच की मदद से हल कर लिया जाए।' इससे यह पता चलता है कि गांधी और दूसरे कांग्रेसी नेता जमींदार वर्ग के मूलभूत अधिकारों की रक्षा करना चाहते थे। कायकारिणी समिति ने चर्खे का प्रचार नशाबंदी, राष्ट्रीय शिक्षण मन्थाओं की स्थापना आदि रचनात्मक कार्यक्रम अपनाए।

कुछ कांग्रेसी नेताओं को, जो जेल में थे, वारदोली का फैसला बतारह नापसंद आया। 'जनता का उत्साह उबाल पर आ रहा था कि उसी वक्त पीछे हटने की आग जारी हो गई और यह घटना किसी घोर राष्ट्रीय विपत्ति से कुछ कम नहीं थी। देशबंधु दास, पंडित मातीलाल नेहरू और लाला लाजपत राय (जो उन दिनों जेल में थे) जैसे महात्मा के प्रमुख अनुयायियों में भी जनसाधारण के जसा आक्रोश था। मैं उस वक्त देशबंधु के साथ था और मैंने देखा कि वे थोड़े और दुःख से आप के बाहर थे।'<sup>68</sup>

पंडित मातीलाल और लाला लाजपत राय ने जेल से कायकारिणी के फैसले के विरुद्ध गांधी को पत्र लिखा। एक स्वयं विरोध के दुष्कर्म के लिए मारे देश का सजा देने के लिए इन लोगों ने गांधी की आलोचना की। पंडित जी ने पूछा कि क्या कमोरिन के पास कोई गांव अगर अहिंसक नहीं रहे पाया तो हिंसा के तरीके में किसी शहर को क्या सजा दी जाए।<sup>69</sup>

13 मार्च को राजद्रोह के आरोप में छुद गांधी का गिरफ्तार कर लिया मुसद्मा चन्दा और उह छ सात की जेल की सजा हुई। उक्ति दा माल ग हान के पहने ही वे छोड़ दिए गए। आंदोलन वापस ले लिए जान पर

जो हालत थी उसके बारे में सरकार की राय का वायसरॉय द्वारा सेक्रेटरी आफ स्टेट को भेजे गए विवरण से पता चलता है

शहरो के निम्न वर्गों पर असहयोग आंदोलन का बड़ा गहरा असर पड़ा। कुछ इलाकों में किसानों पर भी इसका असर पड़ा है, खासकर युक्त प्रांत, बिहार और उड़ीसा, बंगाल और जासाम के कुछ हिस्सों में। पंजाब में अकाली आंदोलन देहातों के सिक्खों में भी फैल गया है। सारे देश में मुसलिम आवादी का बहुत बड़ा हिस्सा गुस्से और कटुता से भरा था। पहले कभी जितने व्यापक रूप से शानि और व्यवस्था भंग हुई है, कहीं उससे अधिक व्यापक अशांति के लिए सरकार तैयार है, और वह इन तथ्यों को जरा भी नजरअंदाज नहीं करती कि स्थिति चिंताजनक है। (टेलीग्राफिक कार्स पाडेस, रिगाडिंग द सिचुएशन इन इंडिया, 7 फरवरी, सी एम डी० 1586, 1922)।

### असहयोग आंदोलन को वापस लेना और इसके परिणाम

वारदोली के फैलने के साथ ही असहयोग आंदोलन समाप्त हो जाता है। यह आंदोलन पहले के सारे आंदोलनों से इस जगह में भिन्न था कि यह मुख्यतः जन-आंदोलन था। इसमें किसानों, मजदूरों के भी कुछ वर्गों ने भाग लिया। इस तरह का राष्ट्रीय आंदोलन 1917 तक उच्च और मध्य वर्गों में ही सीमित था उसे पहली बार असहयोग के दिनों में जनसाधारण का आधार और समर्थन मिला। लेकिन किसानों और मजदूरों में अभी विशिष्ट वर्गीय या दलीय चेतना इस हद तक नहीं आ सकी थी कि वे स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति हो सकें, अपना वग नवृत्त्व, कायम, झुंडा आदि विकसित कर सकें और उनके साथ राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो सकें। असहयोग आंदोलन के दिनों में वे बुजुर्ग नेतृत्व के अनुयायी रहें। वारदोली प्रस्ताव से स्पष्ट था कि यह नेतृत्व जमींदारों जैसे निहित स्वार्थी से गबद था और वस किसी भी जन आंदोलन का उसे भय था जिससे निहित स्वार्थों पर खतरा पहुंचे।

हम ऊपर देख चुके हैं कि लाजपत राय और पंडित मातिलाल नहरू जैसे नेताओं के अनुसार आंदोलन गांधी की गलत राजनीति के कारण असफल हुआ।

कवल भूराजस्व का छोड़कर और किसी भी विषय पर आंदोलन के कार्यक्रम में जनसाधारण की कोई विशिष्ट जायिक मांग नहीं थी, मजदूरों में वृद्धि और मजदूरों के लिए सामाजिक न्याय प्रदान करने वाले विधान और रातों में लगी हुई आवादी के लिए वर और ऋण की कमी ऐसी कोई भी मांग सरकार के सम्मुख नहीं रखी गई। नवृत्त्व ने यह नहीं समझा कि जनसाधारण के राजनीतिक अमर्ताप की जड़ें उनकी जायिक स्थिति में हैं राष्ट्रवाद संबंधी किसी जर्मन भावना में नहीं।

जो जायिक बुजुर्गों का तत्त्व के दिनों में जो जायिक प्रकार के कारण रातों

आर्थिक ताकत हासिल कर ली थी। उन लोगों ने प्रायः असहयोग आंदोलन का समर्थन किया। इसके बाद औद्योगिक बुजुर्गों ने कांग्रेस द्वारा संचालित राष्ट्रीय आंदोलन की नीतियों और कार्यक्रमों पर पर्याप्त निर्णायक प्रभाव डाला। बारदोली के फसल के बाद राष्ट्रीय आंदोलन का हास हुआ। मुसलिम लीग और कांग्रेस का सहयोग समाप्त हो गया और आंदोलन के दरम्यान जो हिंदू मुसलिम एकता बनी थी वह खतम होने लगी।

### स्वराज पार्टी की स्थापना

कांग्रेस में प्रवेश के कार्यक्रम को लेकर 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। देशबंधु दास, पंडित मोतीलाल नेहरू, विट्ठलभाई पटेल जेल से रिहा हो चुके थे। वे इस दल के प्रमुख नेता थे। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत डोमोनियन स्टेट्स प्राप्त करना स्वराज पार्टी का लक्ष्य था। पार्टी कार्यक्रम में पूंजीवाद और जमींदारी की रक्षा की गारंटी दी। कार्यक्रम में कहा गया कि 'व्यक्तिगत और निजी संपत्ति को मायता प्राप्त रहगी और उसकी रक्षा होगी। यह भी घोषणा की गई कि यह पार्टी पूंजी के शोषण से धर्म की रक्षा करेगी और धर्म की अनुचित मांगों से पूंजी की रक्षा करेगी। एक तरफ तो हम ऐसे संगठन का रास्ता निकालना चाहेगा जिसके जरिए पूंजीपतियों या जमींदारों द्वारा धर्म का शोषण रोका जा सके, लेकिन दूसरी तरफ हम इस बात का भी खयाल रखना पड़ेगा कि ये संगठन मनमानी और असंगत मांगों के जरिए शोषण के माध्यम में बन जाए, धर्म को सुरक्षा प्रदान करने की जरूरत है लेकिन वस ही औद्योगिक कारखानों की रक्षा भी आवश्यक है।<sup>०</sup> स्वराजवादियों का निजी संपत्ति, वगैरह समर्थन और पूंजी एवं धर्म में हिता क तादात्म्य के सिद्धांत में विश्वास था।

स्वराज पार्टी ने कांग्रेस को राजनीतिक क्रियाकलाप का केंद्र बनाया। कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम से यह पार्टी मनुष्य नहीं थी। इस पार्टी में पहले तो यह कहा कि कांग्रेस में जाने का उनका मकसद था विधायिका सभाओं का भीतर से कमजोर करना। लेकिन, धीरे धीरे यह नीति बदल गई। स्वराज पार्टी के लोगों में 1924 में सरकार की स्टील प्रोटेक्शन कमेटी में काम किया और 1925 में स्त्री कमेटी में। विधायिका सभाओं को भीतर से कमजोर करने की प्रारंभिक नीति के बदले धीरे धीरे विधायिका सभाओं में भाग लेने और उनके इन्तमाल और सरकार के साथ सहयोग की नीति अपनाई गई।<sup>11</sup>

स्वराज पार्टी ने 1924 में केंद्रीय सभा में स्टील प्रोटेक्शन बिल का समर्थन किया। इस बिल के अनुसार टाटा स्टील कंपनी का सरकार की आरंभिक आर्थिक सहायता दी गई हालांकि इस उद्योग में लग हुए मजदूरों के हितों की रक्षा का कोई प्रबंध नहीं हो सका।

स्वराज पार्टी अपनी शक्ति की पराकाष्ठा पर 1925 में थी, जब कांग्रेस ने अपना मार्ग राजनीतिक कार्य स्वराज पार्टी का हस्तांतरित कर दिया था। स्वराज

पार्टी भारतीय बुजुर्गों का विधानवादी दल था। राष्ट्रवादी जनतादोलन का ज्वार जब उतर गया तब भारतीय बुजुर्गों ने अपने वर्गीय हितों और कार्यक्रम के प्रथम के लिए विधायिका सभा का इस्तेमाल करना चाहा। इस वृत्ति की मार्गें थी, औद्योगिक प्रसार, बड़े बड़े उद्योगों का विकास आदि।

### सांप्रदायिक तनाव में वृद्धि

आगे बढ़ने के पहले, असहयोग आंदोलन के बाद के वर्षों में सांप्रदायिक तनाव सघन में जो बढ़ि हुई, उसकी थोड़ी सी चर्चा आवश्यक है। आंदोलन के दिनों में हिंदुओं और मुसलमानों की एकता बनी थी और उन्होंने संयुक्त सघन भी किए थे। लेकिन आंदोलन के बाद विरोधी प्रक्रिया शुरू हुई। दोनों संप्रदायों के प्रति क्रियावादीयों ने मौके से फायदा उठाया और दुश्मनी के बीज बाने शुरू किए। मुसलिम लीग और हिंदू महासभा दोनों ने युद्धकारी सांप्रदायिक प्रचार शुरू किए। इससे राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय चेतना कमजोर हुई।

इन दोनों सांप्रदायिक दलों पर इन संप्रदायों के जमींदारों और अन्य रूढ़िवादी निहित स्वार्थों का कब्जा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार 'हिंदू और मुसलिम' सांप्रदायिकता सही जहाँ में सांप्रदायिकता भी नहीं, वस्तुतः सामाजिक रूढ़िवादी प्रतिक्रियात्मक शक्तियों ने सांप्रदायिकता के मुखौटे में अपना चेहरा छिपा रखा है।<sup>2</sup>

असहयोग आंदोलन के बाद वाले काल में कई सांप्रदायिक झगड़े हुए। 1924 में दिल्ली, गुलबर्गा, नागपुर लखनऊ शाहजहापुर, इलाहाबाद, जबलपुर, कोहट में और 1925 में दिल्ली, कलकत्ता, इलाहाबाद और दूसरी जगहों में सांप्रदायिक दंगे हुए। बाद के वर्षों में भी दश के विभिन्न भागों में ऐसे दंगे हुए।

### समाजवादी और साम्यवादी विचारों का विकास

असहयोग के बाद वाले काल में समाजवादी और साम्यवादी तंत्रों में मजदूर वर्ग के अपने स्वतंत्र आर्थिक और राजनीतिक वर्ग संगठन का भी उदय और विकास हुआ। राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में यह लगातार अधिकाधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। रूस में समाजवादी क्रांति की सफलता और समाजवादी राज्य की स्थापना के कारण आमूल परिवर्तन के इच्छुक राष्ट्रवादी लोग समाजवादी और साम्यवादी सिद्धांतों की ओर जाहृष्ट हुए। जो लोग गांधीवादी विचारधारा और गांधी की रचनात्मक कार्य और स्वराज पार्टी की प्रधानिकता में अंतर्मुख थे उन्होंने समाजवादी जीवन दर्शन का अध्ययन और अनुसरण किया। इस नए दर्शन की रोगनी में उन्होंने स्वतंत्र भारत के बारे में अलग कार्यक्रम बनाए। 1923 में एम० ए० डांग ने बर्मा में 'द सांगनिस्ट नामक पहला समाजवादी साप्ताहिक निकला। 1924 में सरकार ने डांग, मुजफ्फर अहमद और कुछ और लोगों का पंडितों के आगे पर गिरफ्तार किया और इन पत्रिकों में जो सांगपुर

कासपिरसी बंस चला, उसमें अभियुक्तों को चार चार साल की कठोर कारावास की सजा मिली। समाजवादी विचारा का यह स्वल्प विकास भी देश के लिए नई बात थी।

वाद के वरसा में मूलभूत सुधार के इच्छुक नौजवानों में समाजवादी विचार फैलने लगे। बंबई बंगाल और पंजाब में बकम एंड पीजटस पार्टिया बनी। उन दलों ने राष्ट्रीय स्वातंत्र्य के कार्यक्रम का प्रचार किया। उन्होंने मजदूरों और किसानों की आर्थिक और राजनीतिक मांगों का समर्थन किया और उन्हें वगजन्म मांगों की पूर्ति के लिए बग आधार पर संगठित किया। स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए उन्हें मजदूरों और किसानों के संघों का सीधा तरीका पसंद था।

बकम एंड पीजटस पार्टिया ने मजदूर संघ बनाए और कई हड़तालों का संगठन और पथ प्रदर्शन किया। 1928 में बंबई की पार्टी ने गिरनी कामगार यूनियन की स्थापना की, जिसकी सदस्य संख्या 65,000 (पसठ हजार) थी। बंबई के सूती कारखानों के मजदूरों की हड़ताल बंगाल, नागपुर रेलवे के मजदूरों की हड़ताल, साउथ इंडियन रेलवे की हड़ताल और कई अन्य हड़तालों में जो 1928 में हुई, उन्हीं पार्टियों के सदस्यों द्वारा संगठित और संचालित थी।

इन्हीं दिनों इंग्लैंड के अत्यंत विकसित मजदूर संगठनों और समाजवादी एवं साम्यवादी पार्टिया ने फेडरल कांफे, स्ट्रेट, वेन ब्रेडली और अन्य कई प्रतिनिधियों को उदीयमान मजदूर वर्गों और राष्ट्रीय आंदोलनों की मदद के लिए भारत भेजा। मरठ कासपिरसी बंस में स्ट्रेट और ब्रेडली गिरफ्तार भी हुए उन पर मुकदमा चला और उन्हें सजा भी मिली।

### साइमन कमीशन के बहिष्कार से लाहौर कांग्रेस तक

1926 के बाद राष्ट्रवादियों में लगातार अमत्तोंप बढ़ता गया। गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम और स्वराज पार्टी की प्रधानिकता दोनों की निरर्थकता का एहसास बढ़ रहा था। स्पष्ट की विनिमय दर को 1 पि० 6 पै० पर निश्चित करना, ब्रिटिश इस्पात के लिए अधिमानिक दर लागू करना, आदि आर्थिक कारवाइया के कारण भारतीय बुजुर्गों में सरकार के प्रति गहरे विश्वास के भाव पैदा हुए।

1927 में गैर हिंदुस्तानिया से बने साइमन कमीशन की स्थापना से राजनीतिक दलों और पार्टियों में असंतोष और गहराया। कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन (1927) बंद होकर राजनीतिक अमत्तोंप के वातावरण में हुआ। कांग्रेस में काम पेश का उद्देश्य हा गया था जो डामिनियन स्टेट्स में लक्ष्य से मनुष्य नहीं था और पूरा स्वराज का अपना लक्ष्य जानना चाहता था। इन उद्देश्यों के कार्यक्रम पर भी जोर दिया।

मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस के इतिहास में एक नया मोड़ पड़ा। पहली बार यही कांग्रेस ने पूरा स्वराज का अपना लक्ष्य घोषित किया। इनमें साइमन कमीशन के बहिष्कार का और इंटरनेशनल लीग ऑफ़ नेशंस इन्फ्लुएंसिज (1927)

वाद विरोधी अंतर्राष्ट्रीय सस्था) से सबद्ध होने का फैसला किया। कांग्रेस ने जापानिया एव अय साम्राज्यी ताकतो के विरुद्ध चीन की जनता की लड़ाई का समर्थन किया। गांधी ने मद्रास के स्वतंत्रता मन्धी प्रस्ताव का अनुचित माना। उनका कहना था कि प्रस्ताव पर ठीक से, पूरी तरह विचार नहीं किया गया था और उस बिना साचे-समझे पास कर दिया गया था।

स्वतंत्रता को कांग्रेस का लक्ष्य मान लिया गया, इसलिए स्वराज पार्टी को भी दुख हुआ। वे तो साम्राज्य के मातहत डोमिनियन स्टेट्स भर चाहते थे। मद्रास अधिवेशन के ठीक पहले मोतीलाल नेहरू न कहा, 'सरकार की हाल की कायवाहिया के फलस्वरूप केवल उन सारे लोग के हाथ मजबूत हांग जो पूण स्वराज चाहते है और जिनकी मख्या लगातार बढ़ती रही है। जो साम्राज्य क अधीन पूण जिम्मेदार सरकार चाहते है व निस्संदेह जब भी बहुमत म ह, लेकिन मरा खयाल है कि यह बहुमत बनाए रखना बड़ा मुश्किल है।' <sup>3</sup>

1928-29 म दश म खामकर बंबई और बंगाल म, बड़ी तेजी से छात्रा और नौजवाना क आदोलन बडे। इसी के साथ जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता म जाल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना हुई जिसकी कई जगह गावाए बनी। इन संगठना न स्वतंत्रता की मांग का समर्थन किया और आमूल परिवर्तन का कार्यक्रम अपनाया। इनकी सहानुभूति जनसाधारण के आदोलनो और मांगो से थी और उहान उनका समर्थन किया। वे साधारणत स्वतंत्रता, देशी रियासती और जमींदारिया क उन्मूलन और जनता की हालत सुधार सकन वाले राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक कार्यक्रम क पक्ष म थे। इंडिपेंडेस लीग एकम एंड पीजट्स पार्टिया और छात्रो और नौजवाना क संगठना न माइमन कमीशन के बहिष्कार म महत्वपूर्ण भूमिका जदा थी।

स्टैंड्युटरी कमीशन 3 फरवरी, 1928 का भारत पहुंचा। उस दिन विरोध म जगिल भारतीय हड़ताल संगठित की गई। दंग क कई भागा मे समाए हुए प्रदर्शन हुए। दिल्ली, लखनऊ, मद्रास, कलकत्ता पटना और जयपुर म बडे बडे जुनूम निकल कई जगहा म पुत्रिम और प्रदर्शनकारिया म मुठभेड हुए। लाहौर म जय पुलिस भेड का तिनर बितर कर रही थी तो वाला लाजपत राय को लाठी स चाट लगी। बटुता का कहना था कि कुछ महीना बाद उनकी मौत उसी वक्त लगी चोट क कारण हुई थी।

फरवरी म एक सबदनीय सम्मेलन हुआ, जिसम पंडित मनीलाल नेहरू जस कांग्रेस क दक्षिणपथी नेता और सर तज म्हादुर सग्रू और जली इमाम जम उदारवादी नेता भी शामिल हुए। अगस्त म सम्मेलन न अपनी रिपाट प्रकाशित की गिस नेहरू रिपाट क नाम स जाना जाता है। उसम भारत क मविधान का एन एपररा प्रस्तुत का गई। इन याजना न स्वायत्तशाही डोमिनियन पर जाधा रित मविधान का मांग का। रिपाट न एग्जिनगन श्रीर निजा मपत्ति क अग्रसार का भी स्वीकार किया।



समाजवादिया और वामपंथी राष्ट्रवादियों ने इस योजना की आलोचना की। उनका कहना था कि इसमें स्वतंत्रता के लक्ष्य को तिलाजलि दे दी थी और जमींदारी एवं अर्थ प्रतिक्रियावादी सांपत्तिक स्वार्थों को संरक्षण प्रदान किया था।

1928-29 में सारे देश में कई हड़तालें हुईं। बम्बई की सूती मिला की ग्राम हड़ताल में 15 लाख मजदूर शामिल हुए। हड़ताल का नेतृत्व गिरनी कामगार यूनियन और वाव टक्स्टाइल लेबर यूनियन ने किया। हड़ताल का क्रम 1929 में पणजाणा पर था। 1927 में कुल 1,31,655 मजदूर ही हड़तालों में शामिल हुए थे लेकिन 1929 में 531,059।

हड़तालों से भारतीय मजदूर वर्ग की बढ़ती हुई वर्ग चेतना और लड़ाकूपन का पता चलता है। यह भी जातव्य है कि इन हड़तालों का नेतृत्व प्रायः (जिस वर्ग में) कर्मक एव पीजटस पार्टी के लोग ने किया। मजदूर वर्ग स्वतंत्र सामाजिक शक्ति के रूप में विकसित हो रहा था। मजदूरों ने राजनीतिक जुलूसों में भी अपने झंडे के साथ भाग लिया। इससे भी उनकी बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना का पता चलता है। वे साइमन कमीशन के बहिष्कार में भी बहुत बड़ी तादाद में शामिल थे।

कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन दिसम्बर, 1928 में हुआ। यह डोमिनियन स्टेट्स (नेहरू रिपोर्ट में प्रस्तावित) और शीघ्र स्वतंत्रता की मांग के समर्थकों के बीच राजनीतिक युद्ध का रणक्षेत्र था। सुभाष बोस और जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता के पक्षधर थे। गांधी अधिवेशन में उपस्थित थे और उन्होंने समझौतावादी प्रस्ताव स्वीकृत कराने के लिए सारी शक्ति लगा दी और सब तरह से प्रतिनिधियों पर अपना प्रभाव का उपयोग किया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि अगर साल भर के अंदर डोमिनियन स्टेट्स मिल जायें तो उसे स्वीकार कर लिया जाएगा, अन्यथा अहिंसक असहयोग आंदोलन शुरू करना पड़ेगा।

बोस और जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया समझौता अस्वीकार हो गया। संशोधन में कहा गया था कांग्रेस मद्रास अधिवेशन के फैसले के साथ है जिसमें पूर्ण स्वराज को भारतीय जनता का लक्ष्य माना गया था। इसका यह भी विचार है कि सच्ची स्वतंत्रता तब तक नहीं आ सकती जब तक ब्रिटिश सवध समाप्त नहीं हो जाता।<sup>74</sup> कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन से आमूल परिवर्तन के समर्थकों की बढ़ती हुई शक्ति का परिचय मिलता है।

मजदूर वर्ग की बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना का इस बात से पता चलता है कि कलकत्ता की मिला के 50,000 मजदूर जुलूस बनाकर पंडाल में आए दो घंटे तक बहा रहे और राष्ट्रीय स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया। इन्हीं दिनों कलकत्ता में कर्मक एव पीजटस पार्टी ने अपना पहला जर्मिन भारतीय सम्मेलन किया। इन पूर्ण स्वतंत्रता, दली रियासत और जमींदारी के उन्मूलन, मूल उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, आठ घंटे का कार्यकारी दिन, जाति भांग का कार्यक्रम अपनाया।

मार्च 1929 में सरकार ने मजदूर वर्ग और राष्ट्रीय आंदोलन के कई नेताओं को पड़पत्र के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। मेरे कामपिरसी के चार वर्ष तक चला जिसने जतन में कुछ अभियुक्तों को छाड़ दिया गया और कुछ का बड़ी लंबी सजाएँ मिली, जिनकी अवधि जपान के बाद काफी घटा दी गई। अभियुक्तों में कम्युनिस्ट और गर कम्युनिस्ट और स्प्रेट, ब्रडली और हॉचसन, तीन अग्रज भी थे। अभियुक्तों में तीन जाल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य थे।

1929 के मध्य में, वायसरॉय ने पब्लिक सेफ्टी आर्डिनंस जारी किया, जिसमें गवर्नर जनरल इन काउंसिल को यह अधिकार दिया कि वे भारत से ब्रिटिश और विदेशी कम्युनिस्टों को निकाल बाहर कर दें।<sup>75</sup> उसी माहट्रेड डिस्प्युट एक्ट भी पास हुआ। जिसके अनुसार सहानुभूति में या सरकार पर दबाव डालने के लिए, या आवश्यक जनसेवाओं में की गई हड़तालें गर कानूनी घोषित कर दी गईं।

1929 में सरकार ने बढ़ते हुए आंदोलनों के खिलाफ कड़े कदम उठाए। 'द माइन रिव्यू' के मपादक रामानंद चटर्जी इंडिया इन 'आडेज' को प्रकाशित करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिए गए। भगतसिंह और दत्त का आजम देश निकाला की सजा दी गई क्योंकि उन्होंने सेटल लॉन्गस्टेडिव अमेवली के अधिवेशन में वम और प्रचारार्थक पर्चे फेंके थे। कलकत्ता में सुभाष बोस और कुछ अन्य प्रमुख कांग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिए गए और उन पर राजनीतिक आरोपों पर मुकदमा चलाया गया।

भगतसिंह और दत्त लाहौर जेल में थे और उन्हें आजम देश निकाला की सजा मिल चुकी थी लेकिन जब य जेल में थे तभी उन पर लाहौर के सुपरिंटेंडेंट आफ पुलिस, मि० माडम की हत्या का भी आरोप लगाया गया। उस मुकदमे का लाहौर कासपिरसी कंस के नाम से जानत है और इसमें दत्त तो छूट गए लेकिन भगतसिंह, सुखदेव और राजगुरु को फाँसी की सजा मिली।

कई राजनीतिक रक्षियों में जिनमें लाहौर कासपिरसी के कंस के बंदों और जतीनदास भी थे राजनीतिक रक्षियों के लिए विधेय मुविधाजा की मांग पर भूख हड़ताल की। 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद जतीनदास की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु से लोग काफी उत्तेजित हुए। बर्मा में रॉबर्ट विराय ने, जो दण्डाह्वय के आरोप में जेल में थे, साधारण मुविधाजा की प्राप्ति के लिए भूख हड़ताल की। 164 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी मौत हो गई। दश में राजनीतिक वातावरण काफी तनावपूर्ण हो रहा था।

वायसरॉय लार्ड इविन ने 31 अक्टूबर को एक वक्तव्य पढ़ा 'हिज मजस्टी की सरकार को जोर से मुझे यह कहने का अधिकार है कि 1917 का घोषणा में यह निहित है कि 'मिनियन स्टैटम का प्राप्ति भारत की नावधानिय प्रगति का उचित परिणाम होगा।

वायसरॉय ने वक्तव्य में जोर से जोर से नानाओं में राजनीतिक मनमिलाप की कुछ उम्मांग बना। ये दिनांक में मिन और उनकी जायग एन

घोषणापत्र (दिल्ली मैनिफेस्टो) प्रकाशित हुआ जिसमें आशा व्यक्त की गई कि भारत की आवश्यकताओं के उपयुक्त डोमिनियन स्टेट्स की योजना बनाने के हिज मैजेस्टी की सरकार के प्रवास में हम सहयोग दे सकेंगे।' यह भी कहा गया कि प्रस्तावित गोलमेज सम्मेलन की सफलता के लिए उपयुक्त वातावरण बनाने के निमित्त राजनीतिक बदिया को क्षमादान होना चाहिए और सम्मेलन में भारतीय राजनीतिक दलों को साधक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इस घोषणापत्र पर गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती बेमट सर टी० बी० सप्रू आदि के हस्ताक्षर थे। इस घोषणापत्र पर जवाहरलाल का हस्ताक्षर बड़ा असंगत माना गया, क्योंकि वे पूर्ण स्वतंत्रता व समथक व और समझौता नहीं चाहते थे। बाद में उन्होंने कहा कि यह घोषणापत्र राजनीतिक दृष्टि से गलत था।

23 दिसंबर, 1929 को कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी और मोतीलाल नेहरू तथा अन्य दलों के प्रतिनिधि के रूप में जिन्ना और सप्रू दिल्ली में वायसरॉय से मिले। गांधी ने इस बात का आश्वासन मांगा कि गोलमेज सम्मेलन भारत के लिए पूर्ण डोमिनियन की मांग की पूर्ति को आधार मानकर अपनी वायसाही शुरू करे। ऐसा आश्वासन दे सकने में वायसरॉय ने अपनी असमर्थता जाहिर की फलस्वरूप समझौता वार्ता विफल हो गई।

### पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित

कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन तनावपूर्ण राजनीतिक वातावरण में हुआ। लाहौर कांग्रेस कमेटी के अनुसार स्वराज का अर्थ था पूर्ण स्वतंत्रता। इसमें आल इंडिया कांग्रेस कमेटी को यह अधिकार दिया कि वह जब उचित समझे जवाब आंदोलन शुरू कर दे। इस आंदोलन के अनुसार कर का भुगतान भी रोक दिया जाना वाला था।

अपने अध्यक्षीय भाषण में जवाहरलाल नेहरू ने अपने वा जनतंत्रवादी और समाजवादी कहा। हमारे लिए स्वाधीनता का अर्थ है ब्रिटिश साम्राज्य से पूर्ण मुक्ति।' उन्होंने यह भी कहा, 'भूल सत्य है अधिकार ग्रहण, चाहे आप इस जा ताम दें। मैं नहीं मानता कि भारत के लिए उपयुक्त किसी भी तरह का डोमिनियन स्टेट्स हम वास्तविक अधिकार दे सकेंगे।' लाहौर कांग्रेस से एन और राष्ट्रीय जनआंदोलन की शुरुआत हुई। कांग्रेस ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया। का निश्चय किया। इसमें 26 जनवरी, 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया। सारे देश में व्यापक प्रश्न हुए, सभाएं हुई।

30 जनवरी को गांधी ने 'मंग इंडिया' में ग्यारह सूत्री मांग रखी। पूर्ण माल निषेध, रपए व विनिमय दर का घटाकर। नि० 4 पें० करना, भूराजस्व का न कम 50 प्रतिशत कम करना, नमक कर का उन्मूलन विदेशी रपड पर रक्षात्मक कर हटाना, वास्तव टारिफ रिजॉर्गन विन का पारित करना,

मागे इस कार्यक्रम में थी। उन्होंने लिखा, 'भारत के लिए आवश्यक लेकिन इन अत्यंत सी.पी. सादी मागा पर वायसराय हम सतुष्ट करे। तब नागरिक अवज्ञा की गई चर्चा नहीं होगी और कांग्रेस किसी भी सम्मेलन में मुशी से शरीक होगी।

वामपंथी राष्ट्रवादियान इस ग्यारह मूनी कार्यक्रम की आलाचना की। उनका कहना था कि इस कार्यक्रम में स्पष्टता की माग का घटा कर और नशाधित कर उसके प्रदल केवल कुछ सुधारों की माग की गई है। लेकिन सरकार ने भी इन मागा पर कोई ध्यान नहीं दिया।

### नागरिक अवज्ञा आंदोलन

फरवरी में सावरमती में कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई और इसने गांधी और उनके सहयोगियों का नागरिक अवज्ञा आंदोलन के नेतृत्व और संचालन का सारा अधिकार सौंप दिया। आंदोलन शुरू करने के पहले गांधी पूर्णतः जाश्वन्त होना चाहते थे कि इसमें प्रत्यक्ष या पराक्षत किसी भी तरह थोड़ी सी भी हिंसा नहीं होगी। फिर भी उनकी राय थी कि अगर अहिंसक आंदोलन नहीं शुरू किया गया तो स्वातंत्र्य के लिए लोगों को अतीर व्याकुलता के कारण देश भर में हिंसक आंदोलन शुरू हो जाएगा। 2 मार्च 1930 को वायसराय को लिख गए अपने पत्र में उन्होंने यह राय जाहिर की थी हिंसा में विश्वास करने वाले दल ताकतवर हो रहे हैं और उनका असर महसूस होना होगा है ब्रिटिश सरकार की संगठित हिंसा के साथ ही हिंसा में प्रतिकार करने वाले दल की संगठित हिंसा में विरुद्ध भी मैं अहिंसा की नीति का क्रियाशील बनाना चाहता हूँ। चुपचाप बैठने का मतलब है उपयुक्त नाना प्रकार की गतिविधियों की लगाम ढीली छोड़ देना।' तत्कालीन स्थिति के कारण गांधी का यही भाव्य था।

अंत में गांधी ने सघन शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने घोषणा की कि प्रथम चरण में यह आंदोलन का जपान जाय तक एव सावधानी में चुन गए अपने उत्तम अनुयायियों तक ही सीमित रखे और यह मार्च 7 अप्रैल को डंडा में सरकार ने नमक बालूना का उत्खनन करेगा। गांधी और जिन अन्य लोगों ने नमक बालूना का गैर-मिष्णन नहीं किया गया। फिर भी इसके चलते देश में उद्वेग उत्पन्न हो गए और अंतर्ध्वंस आंदोलन शुरू हो गए।

9 अप्रैल को गांधी ने आंदोलन के लिए यह कार्यक्रम निश्चित किया है कि गांधी और बालूना तार पर नमक बनाया जाए या चाया जाए, उहान पराश्र की तुलना अक्षीय। अंग्रेजों और विदेशी कंपनियों के दुश्मनों पर विरक्ति कर। शुरू और नान चर्या दात विदेशी कपड़े बना लिए जाए। शुरू शुरू हुए छाने विदेशी मशीनों के रूल का दंड जोड़ें और सरकारी नागरिकों के नागरिकों के रूनाता में हमें हमें शक्ति प्राप्त कराने के लिए प्रयास करना चाहिए।

विदेशी कंपनियों और नागरिकों के प्रतिद्वंद्वी विरक्ति कर और नमक का उत्खनन कर। विदेशी कंपनियों के नागरिकों के रूनाता में हमें हमें शक्ति प्राप्त कराने के लिए प्रयास करना चाहिए।

प्रतिव्यक्ति के बावजूद कांग्रेस कमेटियों ने समाए की आर इन गर रानूनी समाजो को ताउन के त्रिए सरकार ने गाली जार लाठी का महारा त्रिया ।

देश म दूमेरे तरह के भी जादीवन शुरू हुए । अपत्र म कुछ क्रान्तिकारिया न चटगाव न पुलिम शस्त्रागार का नूट त्रिया । मइ म शालापुर म जन प्रश्नना म मिलसिले म गीड जौर पुलिम क बीच मघप हुए । कइ सरकारी महान जार गराव की दुकान नष्ट कर दी गइ । काफी लाग पुलिस की गानिया के जिनार हुए । फौजी कानून लागू कर दिया गया जौर जादालन को दवान क लिए फौज बुलाई गई ।

लेकिन सबसे गभीर घटनाए अप्रैल म पगावर म हुइ । गहर म कई जन प्रदशन हुए जिनम पुलिस जौर लोगो की भीड म मघप हुए । एन इतिवार-वद गाडी को प्रदशनकारिया न जला दिया जौर इमर पारण पुनिम न गानो चलाई तो कई लोग मार गए जौर घायन हुए । इस काल की एक महत्वपूर्ण घटना यह थी कि जब अठारहवीं रायन गडवानी राइफल्स क कुछ हिंदुस्तानी भनिरा को भीड पर गोली चलाने को कहा गया तो उन्होंने इसने द्धार कर दिया । बाप म उनपर फौजी कचहरी म मुकदमा चला और उह लखी जबकि क त्रिए कागजान की सजा मित्री । बडी तादाद म फौजे बुलाई गइ जौर तब जतन गहर पर बाप पाया जा सका ।

5 मइ का अधिकारिया ने गांधी को गिरफ्तार कर लिया । उनही गिरफ्तारी पर सार दंग म हड़ताल जौर प्रदशन जाइ हुए । वद गह पर उपद्रव हुए । शोनापुर की जिन घटनाओ की ऊपर चर्चा की जा चुकी है व गांधी की गिरफ्तारी के बाद हइ सी । सरकार ने भी कल्प म्य इतिवार किया । मइ जार्जिनम जारी किए गए । जून म इसने कांग्रेस जार इसकी गणवाजा का अध घापित कर दिया । जुनाइ घतम हान क पहले प्रम जार्जिनस के अतगत 67 जयजारा जौर 51 छापा छाना का वद कर दिया गया । दमन काय तग हा रहा था । कांग्रेस न इतिगम-सार पट्टाभि मोनारम्भया न अनुमान के अनुसार इस जबकि म गान्धीनिय प्रतियो की संख्या 90 000 तक पट्टे गइ थी । जनवरी 1931 म सरकार न गांधी जौर कांग्रेस की कायकारिणी समिति क जय नताजा का रिहा कर दिया ।

### गांधी इविन समझौता

काफी बातचीत क बाद, माच म गांधी इविन समझौता हुआ । इस सन्ध्या की गती क अनुगार सरकार दमन की कारवाइ रोकन जौर क्तिर काय क त्रिए जिम्मेदार भाग क अतिरिक्त गप रातनीतिर त्रिया का रिहा करन का नकार हा गई । अपनी जार स गांधी गानात्र सम्मेलन म नग वत का इवार म गए । तब दुभा कि गोलमज सम्मेलन भारत क गविधान का वाताता वाताग्या जार मधीय सरकार का निडात द्वा गविधान का अतिवाय जग हाया । जन 1 । पुर ता, विदग नीति जल्प गदवना सी त्रियि, भारत का रिताय गांधी, जार

दायित्व एवं अनुबंध के निर्वाह चादि मामला में भारतीय हितों के संरक्षण और भारतीय उत्तरदायित्व की भी गारंटी होगी।

वामपंथी राष्ट्रवादियों ने इस राजीनामे की जांच की और इसे समर्थतावादी कहा। उनका कहना था कि जिस लक्ष्य के लिए सघन गुरु हुआ था, यह राजीनामा उससे व्यक्तिगत रूप से परिचायक है। 1931 के कराची अधिवेशन ने राजीनामे का अनुमोदन किया। बोस और जवाहरलाल इससे सहमत नहीं थे लेकिन राष्ट्रीय हित में दोनों ने इसका पक्ष में मत दिया।

इस अधिवेशन में कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों पर भी एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया, जिसमें सभी नागरिकों को नागरिक अधिकारों की सुरक्षा प्रदान की गई। यह अधिवेशन यातायात के साधनों और प्रमुख उद्योगों के राष्ट्रीयकरण, मजदूरों के लिए जीवन और थम की अच्छी शर्तों, दूरगामी कृषि सुधार, अनिर्वाह और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा सबके लिए वयस्क अधिकारों की पक्ष में था।

कुछ ही दिनों बाद गांधी इंग्लैंड के लिए रवाना हुए जहाँ वे गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने मतीय योजना, अल्पसंख्यकों की स्थिति, सेना आदि पर कई वक्तव्य दिए और कांग्रेस के दृष्टिकोण को परिभाषित किया। उन्होंने सार्वभौमिक निर्वाचन इकाइयों का विरोध किया और इस प्रश्न पर विचार विभेद के कारण सम्मेलन विसर्जित हो गया और शिष्टमंडल के सदस्य वापस भारत लौट आए।

जिन कुछ महीनों गांधी बाहर रहने के व्यापक किसान असंतोष के महीने थे। कृषि मकट के कारण खेती की उपज की कीमतों में जो भारी कमी हुई उससे कारण भारतीय किसानों की आर्थिक स्थिति बड़ी बुरी थी। यहाँ का कृषि मकट उस विश्वव्यापी आर्थिक मकट का ही भाग था जो 1929 में शुरू हुआ, और अभी चल ही रहा था। 1931 के उत्तरार्द्ध में, युक्त प्रांत गुजरात और बर्मा में कुछ इलाकों में कुछ किसानों ने लगान और मालगुजारी देने से इंकार कर दिया था। सरकार का आरोप था कि कांग्रेस किसानों को उबसा रही है और इस तरह गांधी इंग्लैंड इव रारनाम का गर्तों में ताड़ रही थी। दूसरी ओर कांग्रेस का कहना था कि इकरारनाम में वावजूद सरकार ने दमन की नीति का परित्याग नहीं किया था।

### नागरिक अवज्ञा आंदोलन का पुनर्जन्म

दिसंबर में भारत लौटने के तुरंत बाद गांधी ने नए वायसराय लॉर्ड बिर्लिंगटन से मिलना चाहा लेकिन लॉर्ड बिर्लिंगटन इंग्लैंड में तयार नहीं हुए। जब कांग्रेस और सरकार के बीच धारणागत अंत में गहरी त्रुटि उत्पन्न हुई तो नागरिक अवज्ञा आंदोलन का पुनर्जन्म करने का निर्णय लिया। 4 जनवरी, 1932 को गांधी निरवधारण कर लिए गए। सरकार ने तुरंत बंद आंदोलन, जारी किए, जैसे दमनकारी पायलट आर्जेंटिन, जनताकुन इन्डिगेशन आर्जेंटिन प्रियजन आफ मान स्टेशन एंड रायफाटिंग आर्जेंटिन जनताकुन एमामिणन आर्जेंटिन। कांग्रेस

के संगठन अवधि करार दिए गए। लगभग सारे कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, और बहुत सारे नागरिक अवनता के स्वयंसेवकों का भी जेल में डाल दिया गया। आर्द्धिनैसी द्वारा मिल हुए अधिकार के बल पर सरकार ने कई संगठनों की संपत्ति जब्त कर ली और इस संधि के समर्थक अलवारों के खिलाफ कारवाही की। अप्रैल 1933 में कांग्रेस के अनुमान के अनुसार गिरफ्तार लोगों की संख्या 120 000 थी।

नागरिक अवनता के अतिरिक्त, 1932 में दो और आंदोलन हुए, एक काश्मीर में, दूसरा अलवर में। दोनों देशी रियासतें थीं, जिनमें सत्तावादी रजवाड़ों का शासन था। अलवर के किसानों के विद्रोह का आधार आर्थिक था। किसानों से लगान की बहुत ऊंची दर की वसूली के कारण ही यह आंदोलन हुआ था। यह विद्रोह काफी व्यापक था और अंत में ब्रिटिश सना की मदद से दबाया जा सका।

प्रधान मंत्री मैकडानल्ड ने जुलाई में कम्युनल जवाब (सांप्रदायिक निषेध) की घोषणा की, जिसने अनुसार दलित जातियाँ एवं अन्य अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचक इकाइयों की व्यवस्था हुई। गांधी दलित जातियों के किसी भी पृथक निर्वाचन के विरुद्ध थे और उन्होंने प्रधान मंत्री के निषेध के विरुद्ध आमरण अनशन शुरू किया। इसके फलस्वरूप पूना पैक्ट का जन्म हुआ जिसमें सम्मिलित हिंदू निर्वाचन क्षेत्रों की बात बरकरार रही, लेकिन दलित जातियों के लिए स्थान सुरक्षित कर दिए गए। सुरक्षित स्थानों की संख्या वायसरॉय के फैसले में निश्चित किए गए स्थानों की संख्या से अधिक थी।

मई 1933 में गांधी ने फिर अनशन शुरू किया। इन अनशन द्वारा वे अपने और अपने सहयोगियों का आध्यात्मिक नैतिक शक्ति प्रदान करना चाहते थे, जिससे वे अपने का अधिक अच्छी तरह से हरिजनों के उद्धार में लग सकें। इस उपवास का व्यवहार यह परिणाम निकला कि लोगों का ध्यान राजनीतिक संधि से विमुख हो दूसरी ओर चला गया। सरकार ने गीध ही गांधी का जल से रिहा कर दिया। अनशन के सप्ताह में गांधी की राय से ही कांग्रेस अध्यक्ष ने फिलहाल नागरिक अवनता आंदोलन को स्थगित कर दिया।

### नागरिक अवनता आंदोलन से सवक

सुभाष बोस और बिट्टनभाई पटेल उन दिनों यूरोप में थे और उन्होंने एक अनुसूचक यक्तव्य में नागरिक अवनता आंदोलन के स्थान के बारे में कहा, नागरिक अवनता आंदोलन के स्थान में गांधी का इन काय में स्पष्ट है कि उन्होंने अपनी असफलता कबूल कर ली है। हम लोगों का स्पष्ट विचार है कि राजनीतिक नेता के रूप में गांधी असफल हो गए हैं। नए विद्रोह और नई काय पद्धति का आधार पर राष्ट्र के आम जन पुनर्गठन का वक्त आ गया है और इनके लिए नए नेता ही आवश्यक हैं।

गांधी की राय पर कांग्रेस ने जनता युवाओं में मासिक नागरिक आंदोलन को गंभीरता से काफला किया। जन इतिया राष्ट्रीय समिती ने

1934 में व्यक्तिगत और सामाजिक नागरिक जवना जादोलन को पूरी तरह वापस ले लिया। केवल गांधी को इसके लिए स्वतंत्र छोड़ दिया गया कि वह चाहता इस पर जमन कर सकत है। जून 1934 में सरकार ने सार कांग्रेस संगठना को फिर वैध मान लिया। फिर भी, कई नौजवान संगठन और अन्य संस्थाएँ अवध हो रही।

कुछ कांग्रेसियों से बढ़ते हुए मतभेद के कारण गांधी ने कुछ ही दिनों बाद कांग्रेस की सदस्यता में इन्हींका दखलिया। कांग्रेस संगठन से अलग होने के पक्ष गांधी ने कांग्रेस की सामाजिक संरचना और उच्च संविधान में परिवर्तन के लिए उमनयार कर लिया। ऐसा उ होने कांग्रेस में वामपंथी राष्ट्रवादियों और समाजवादी शक्तियों की बढ़ती हुई ताकत के कारण किया। कांग्रेस की प्रांतीय समितियाँ न सदस्यता की संख्या घटा दी गईं और ऊपर की समितियों में चुनाव के तरीके बरत दिए गए जिसमें अल्पसंख्यक दलों को नुकसान हुआ। वामपंथियों ने इन संस्थाओं का अप्रजातान्त्रिक कहा और उनकी आलोचना जारी की। 1935 में पार्लियामेंट में संघीय संविधान पारित हुआ लेकिन दो साल बाद 1937 में प्रांतीय स्वायत्तता की योजना लागू हो सकी।

नागरिक जवना जादोलन भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास में दूसरा सामाजिक राष्ट्रीय संघर्ष था जो 1934 में समाप्त हो गया। इसका जन आधार 1920-21 के जादोलन से अधिक प्राथमिक था। इसमें भारतीय जनता में बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना का सूत्र मिलता है। माध्यम लागू जिनमें किसान भी थे बड़ी तादाद में राष्ट्रीय जादोलन में शामिल हुए। पहली बार उनके अपने व्यापक, स्वतंत्र, राजनैतिक और आर्थिक संगठन भी बन गए। फिर भी, जादोलन का संचालन कांग्रेस ने चुनना नताजा न हाथ में रहा।

जुजुआ संसद के जगुआ व गांधी, और गांधीवादी राजनीतिक विचारधारा और नदनुन्द वगैरे के अनुसूत इस संतत्व में राष्ट्रीय जादोलन का ध्येय, पटुचित और सीमित रखा। मजदूरों और किसानों की स्वतंत्र संरचना का, जो हड़ताल करवाया लगान नहा नना, इन संतत्व में नियमित विराट दिया। किसानों और मजदूरों ने इन आंदोलनों का अपने ही वगैरे नताजा ही अनुसूत में पाठिका किया और उनके अपने अनन्य राजनीतिक नार थे, जिनमें उनके तादातन तादात और प्रभावों का उल्लेख हुआ। जुजुआ नतागण में इस भाव में नय भावों का विद्यमान संघर्ष अनियंत्रित हानर जमाकर जस-जस विहित संस्थाओं का नारा देते पटुजाएंगे। इन संघर्षों में ही इन आंदोलनों का प्रति उनका प्रतिष्ठापण विराट रखा। गांधी की ग्यारह सूत्री मांगों से स्पष्ट है कि वे नय समन्वित और

\* गांधी ने कांग्रेस और जुजुआ के बीच अलग-अलग समिति पर जोर देकर भारतीय संसद का जादोलन करवाया था। मजदूरों और किसानों के बीच अलग-अलग संस्थाओं का उभार पक्ष विचार न था। गांधी ने नय सामाजिक संरचना में न तादात विराट दे और न नय माना था कि नतागण का उभार नय गांधी के जादोलन का विराट का नियमित करवा





और विदेशी वित्तीय पूँजी पर आश्रित ष्ट्री और इसका अत्यन्त जमींदारों के हित से सलग्न और सबद्ध था, इसलिए यह साम्राज्यवाद और सामतवाद से समझौता करन का वाध्य था। फिर यह खतरा भी हरदम मौजूद था ही कि जन आंदोलन तगड़ा हाकर देशी पूँजीवाद को भी चुनौती देने लगेगा। इसके चलत राष्ट्रीय बुजुआजी ने नाति विरोधी होत हुए भी, विरोध पक्ष से, सुधारवादी सामाजिक शक्ति की भूमिका अदा की।

गाधीवाद ने राष्ट्रीय बुजुआजी की दोनों जरूरतों को पूरा किया। जन आंदोलन के जरिए इसने साम्राज्य पर दवाव डाला और साथ ही मध्य को सीमित भी रखा और ऐस रास्ता से मध्य चलाया कि भारत के संपत्तिशील वर्गों का इससे नुकसान नहीं हा।

अपने जीवन दशन की वगजय सीमाओं के कारण गाधी का विश्वास था कि पूँजीवादी सामाजिक व्यवस्था को आधार बनाकर सुखी, सपन्न राष्ट्रीय अस्तित्व का निर्माण किया जा सकता है। भारतीय पूँजीवाद अपने शशव म नहीं था और उसका कोई उज्जवल समृद्ध भविष्य नहीं था। यह ह्मासो मुख विश्व पूँजीवाद की एक कमजोर कड़ी था। इसे विशद लाभ के अजस्र स्रोत के रूप म मड़ी और उपनिवेश उपलब्ध नहीं थ। अमरीका, ब्रिटेन और अन्य देशों के विशालकाय पूँजीवादों के साथ प्रतिद्वन्दात्मक मध्य म इसकी सफलता की आशा करना धेकार था। इसका अस्तित्व अनिश्चित था और इसके लाभ सीमित थ, इसलिए यह मज दूरों के जीवन का स्तर थोड़ा भी ऊचा नहीं कर सकता था।

नकिन वगगत सीमाओं के कारण गाधी इस वस्तुनिष्ठ ऐतिहासिक तथ्य को समथ मवने म असमथ थ। उहाने यह नहीं समथा कि प्रतिवागिता पर आधारित पूँजीवादी अत्यन्त के अपने वस्तुनिष्ठ नियम है, पूँजीपतियों की अपनी कोई स्वतंत्र इच्छाशक्ति नहीं। जायिक क्षेत्र म उनका व्यवहार प्रतियोगी जायिक संरचना की आवश्यकताओं द्वारा निर्णीत हाता है। पूँजीवादी सामाजिक भूमि म वग मध्य स्वत उत्पन्न होता है।

अपन वग की सीमाओं के कारण गाधी बुजुआ दृष्टिकोण का अतिभ्रमण नहीं कर सके और मुद्ध, शापण और दमन के सामाजिक कारणों को नहीं ममझ सके। फलत उहाने आंदोलन की आचरण मध्यी कमजारी का इन मवका कारण धत दाय्या। सामाजिक संरचना के आमूल परिवर्तन को दुनिया की बुराईया के समाधान के लिए आवश्यक मानने के बदल उहाने हृदय परिवर्तन के सिद्धांत को सारी बुराईया के समाधान इलाज के रूप म देया।

सामाजिक व्यवस्था का बदलने की जरूरत नहीं, बरन आंदोलन के हृदय का आमूल नतिक परिवर्तन हांना चाहिए। पूँजीवादी सामाजिक मवधा की जगह समाजवाद सामाजिक मवधा के प्रतिष्ठापन के बदल उहाने पूँजीवादी सामाजिक मवधा के माननीकरण का पटा ही। नकिन पूँजीवाद के अपने गारतरन म विनिष्ठ शापणारमण गुण है और दमनिक उमता मान्यकरण म मर नहीं। गाधी

ने समाज के वग चरित्र में सामाजिक बुराइयों की जड़ नहीं देखी, वरन् पूजोवादी व्यवस्था नहीं आदमी के जिस नतिक जाचारमूलक पतन का जन्म दिया था उसी को उठोने सारी बुराइयों का कारण माना।

लेकिन जब गांधी की बुजुआ चेतना की बात की जाती है तो इसका यह अर्थ नहीं कि यह चेतना किसी साधारण पूजोपति की स्वाथपरक धिनौनी चेतना का पर्याय है। ऐसा सोचना गलत होगा। गांधी इस अर्थ में बुजुआ थे कि पूजोवादी सापत्निक व्यवस्था पर जाधारित समाज के औचित्य में उनकी आस्था थी और वे मानते थे कि सामाजिक अराजकता के अतिरिक्त इस व्यवस्था का कोई विकल्प नहीं। गांधी ने पूजोवादी शोषण की बात मानी और जबलत शब्दा में उसकी बररता की निंदा की, लेकिन वे अपने मूलभूत बुजुआ दृष्टिकोण की परिधि का अतिक्रमण नहीं कर सके। गांधी का जनसाधारण में विश्वास था, लेकिन साथ ही वे बुजुआ सामाजिक व्यवस्था में भी विश्वास करते थे। उस समाज की सीमाओं में रहकर जनसाधारण की हालत सुधारी नहीं जा सकती थी, क्योंकि विश्व की पूजोवादी व्यवस्था के ह्रास के काल में खासकर भारत जैसे देश में जहाँ सपन पूजोवाद का विकास असभव था, मानवतावादी सुधारक कार्यक्रम को लागू करने के लिए जिस आर्थिक आधार की आवश्यकता हाती है वह बन नहीं सकता।

विकास के ऐसे चरण में हमें प्रायः ऐसे उदात्त मानवतावादी मिलते हैं, जिन्हें देखकर कष्ट होता है, क्योंकि वे जनसाधारण की तकलीफें दूर करने की नाकामयाब कोशिश करते रहते हैं और साथ ही समाज को बदलने के जनसाधारण के सारे प्रयत्नों का अनवरत विरोध भी करते हैं। सामाजिक व्यवस्था की उपयुक्तता और अपरिवर्तनशीलता में अटूट विश्वास के कारण वे परिवर्तन का विरोध करने को बाध्य हैं। वह उदात्त मानवतावादी जो ह्रासोमुख सामाजिक व्यवस्था की प्रतिक्रियात्मक प्रवृत्ति को नहीं पहचान पाता, ऐतिहासिक दृष्टि में आवश्यक सामाजिक परिवर्तन का विरोधी हो जाता है।

यद्यपि जमा कहा जा चुका है, गांधी जनन्य रूप से सांप्रदायिकता विरोधी थे और हिंदू-मुसलिम एकता के लिए मध्य करते रहे, दुर्भाग्यवश यह है कि राष्ट्रीय आंदोलन के हर चरण में हिंदू-मुसलिम विरोध घटने के बदले बढ़ता ही गया। इसकी वजह थी कि वे इस विरोध के सामाजिक ऐतिहासिक कारणों का उद्घाटन नहीं कर सके। उनके अनुसार 'भारतीय समाज की भौतिक जीवनप्रक्रियाएँ नहीं, वरन् लोगो की आचरण संबंधी बमजारी' इन विरोधों का कारण थी। 'ऐतिहासिक दृष्टि से तो मुसलमानों का संप्रदायवाद वस्तुतः पूजोपतिवादी, जमादारो, मूदघोर महाजना और व्यापारियों द्वारा प्रचलित व्यापक जायिक जाताओं की बुरूप विवृत अभिव्यक्ति थी। भारत में ये लोग मुख्यतः हिंदू थे। जायिक जातों पर अधममुत्तम उच्चवर्गों ने अपने सधम हिंदू प्रतिस्पर्धियों के साथ उष्य में मुत्तम जाता रूप का जाताओं को जाप्रगणित माना और उष्य

इस्तेमान किया। मुसलिम मप्रदायवाद का यही जनक था।'

जब मुसलिम सप्रदायवाद या जमा, तो इसे खतम करने का एक ही कारगर तरीका था, यह कि भारतीय जनता हिंदू और मुसलमान दोनों को, उनके मयुक्त आर्थिक हिता के आधार पर एकताबद्ध किया जाए और उन्हें हिंदू मुसलमान दोनों तरह के निहित स्वार्थों के खिलाफ लड़ाई में उतारा जाए। इसी प्रकार मुसलिम सप्रदायवादियों को मुसलिम जनता से अलग किया जा सकता था। 'गांधी ने तीस वर्षों तक भावपूर्ण दशमंति का उभारकर जादमी की मानवीय गहराइयों की याह नकर और जहर उपवास के द्वारा सप्रदायवाद के उमूतन के लिए वीरचित प्रयास किए। फिर भी सप्रदायवाद बढता गया।

गांधी और गांधीवादी विचारधारा द्वारा शामिलित संचालित राष्ट्रीय आंदोलन जजीव मयाग या शौचपूर्ण प्रगति और जावस्मिक एव मनमाजी ठहराव का, चुनौती और उमर वाद जावाचित समलौत का और इमर परिणाम थ अनिश्चय उन्नतन और जनसाधारण के परिप्रेक्ष्य का दुरला हाता। फन्स्वरूप वे प्रतिक्रिया वादी प्रयत्तिया मजत हुं जिह गांधी खतम करना चाहत थ।

उग्रवादी (मूलभूत परिवर्तन चाहने वाले) संगठनों का उदय

1936 के बाद राष्ट्रीय आंदोलन उ वमुत्ती हुआ। तखनऊ काग्रेस के अध्यक्ष पं स जब हरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता या समवन देन वाली सभी पक्षियों के मयुक्त मोर्चे के कायम के लिए प्रतिनिधियों का आह्वान किया। —होए मजदूर गंधा और किसान संगठना (देश में अब तक किसान समाजा का उदून हा चुना था) की सखदता की सिफारिश की, जिससे कांग्रेस द्वारा गंलित राष्ट्रीय आंलन या तन जागर व्यापक हा सने। इन तरह के संगठना का मखद करना या प्रस्नाव ता कांग्रेस का स्वोत्न नहीं हा मरा, तनि एव जन मपक ममिति या निमाण हुआ।

अननर कइ उग्रवादी संगठना या उदून हा चुवा था। कांग्रेस के भीतर ही अखिन भारतीय आधार पर सांगठिक पार्टी की स्थापना हुई। कांग्रेस के आर जमाशरी के उमूतन और भूमिखर, खण खगान जादि म तभी की तारतारि मागा के जागर पर स्वामी महजानत प्रा० रया आर इतुतान यातित के तदून म रिमान संगठन स्थापित हा चुा थ। तखनऊ कांग्रेस के फन्स पर इन शक्तिया के उदून का प्रभाव दज या मरता है।

अप्रै, 1936 के तखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस ने फन्स रिखा कि यह तण मरि गां के तात 1937 में हांन यां वुसय में तण तण। उता माल कि तार म रिख तखन या अधिवेशन हुआ। दतम पारित प्रस्नाय तण याता या स्वध इच्छा के सिद्ध साण मरि यां आर 193७ के तखन के जाण इतिहासक या पूणत स्वीकार कर दिया गया। प्रस्नाय में यह या तण तया कि तखन सिपुद्ध याता तयाति याता तया त। इन तरह, तयाय वर के

मताधिकार के सिद्धांत पर चुनी गई ऐसी विधान सभा द्वारा ही लाया जा सकता है जिसे अंततः देश का सविधान निश्चित करने का अधिकार हो। कांग्रेस इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम कर रही है और जनसाधारण का संगठित करती है। विधायिका सभाओं में कांग्रेस के प्रतिनिधियों का सन्तान यह उद्देश्य अपनाने सामने रखना होगा।

कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र में नागरिक स्वतंत्रता और नागरिकों के समानाधिकार की भांग की गई थी। इसमें यह भी कहा गया था कि कांग्रेस काश्तकारी ताना और कर विषयक सुधारों की जमीन पर बहुत हुए धान का सम्यक् वितरण कर और लगानों की राशि में पर्याप्त कमी के द्वारा निम्न किमानों की मदद और अनाधिक काश्त पर स लगान और कर को हटा लेना आदि मांगों का समर्थन करती है। घोषणा पत्र में किसानों का ऋण का सवाल की जाच पड़ताल की और उस काफ़ा कम करने की भी बात की गई।

औद्योगिक मजदूरों के लिए घोषणा पत्र में कहा गया कि उनके लिए ममुचित जीवन स्तर एवं काम की स्थिति और घट तथा उनके सामाजिक रल्याण मंत्री कानून आदि की व्यवस्था होगी। घोषणा पत्र में यूनियन बनाने और अपने हिता के लिए हड़ताल करने का मजदूरों के अधिकार का भी समर्थन किया गया। घोषणा पत्र में यह भी कहा गया कि कांग्रेस सामाजिक जायिक जाय जाय क्षेत्रों में मकम सबधी असमानता का उन्मूलन का पक्ष में है। इनमें अस्पृश्यता निवारण और पिछड़ी जातियों का उद्धार का पक्ष लिया। घोषणा पत्र में गान्धी और ग्रामाद्योग को महायता और इनके हिता को नुकसान पहुंचाए बिना बने हुए उद्योगों को सुरक्षा प्रदान करने की भी बात थी।

इस कार्यक्रम और कांग्रेस की प्रतिष्ठा के कारण चूंकि इन अतीत में जनक महान राष्ट्रीय आंदोलन गुरु किए और चलाए थे, चुनाव घोषणा पत्र का बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा और कांग्रेस में चुनावों में बहुत बनी जीत हासिल की। बरद, मद्रास, मयूर प्रान्त, मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में कांग्रेस का विनायर बहुमत प्राप्त हुआ और बंगाल तथा आसाम में यह सबसे अधिक प्रतिपाती पार्टी सिद्ध हुई।

### प्रारंभ में कांग्रेस के मंत्रिमंडल

मार्च, 1937 में आल इंडिया कांग्रेस कमिटी ने फैसला किया कि जिस प्रान्त का विधायिका सभाओं में कांग्रेस का बहुमत है वहां यह सरकार बना लेगी। लेकिन तब तक ऐसा नहीं किया जा सकता जब तक कि विधायिका सभाओं में कांग्रेस के नेता इस बारे में आशय नहीं हों और स्पष्टतः यह नही है कि वे प्रति गवर्नर हस्तक्षेप का आग्रह विधायिका का प्रयोग नहीं करेंगे और यदि विधायिका विधायिका में मंत्रिमंडल का गठन राष्ट्रिय का रूप में नहीं होगा। तब मात्र भी तब तक वरत घोल प्रस्ताव में कुछ अलापरत भागों में उन उपाय विधायिका

और कुछ वामपंथी राष्ट्रवादियों, को विरोध था।

जहाँ विधायिका सभाओं में कांग्रेस का बहुमत था, उन प्रांतों में कुछ दिनों तक, दूसरे दलों के सदस्यों से प्रतीति हुई अंतरिम सरकार ने काम किया। 22 जून को वायसराय ने घोषणा की कि प्रांतों के गवर्नर साधारणतः इस तौर पर काम करेंगे कि मंत्रियों से सघन नहीं हों, चाहे वे मंत्री किसी भी दल के हों। इस तरह के टकराव से बचने के लिए और उसके समाधान के लिए, वे हर संभव प्रयत्न करेंगे। इस संदर्भ में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाने का फैसला किया।

इस फैसले के तुरंत बाद बंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, उड़ीसा और मध्यप्रदेश में कांग्रेस के मंत्रिमंडल बने। बाद में नाथ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में भी कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना, क्योंकि कुछ गैर कांग्रेसी सदस्यों की मदद से, जो कांग्रेस का अनुशासन मानने को राजी थे कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हो गया।

सत्ताधारण के बाद कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने तुरंत राजनीतिक कदमों को रिहा कर दिया। ऐसी संधियाँ जो अवैध करार दी गई थीं अब फिर बंध मान ली गईं। राजनीतिक कदमों के दृष्टिकोण से और नजरबंदी के हुकम को रद्द कर दिया गया। कई अखबारों की जमानतें वापस कर दी गईं।

फिर भी कुछ ही दिनों में वामपंथी राष्ट्रवादियों, समाजवादियों और मजदूर तथा किसान संगठनों के नेताओं ने नागरिक अधिकारों का सीमित करन और दमनात्मक कार्रवाई के लिए कांग्रेसी सरकारों की आलोचना शुरू कर दी। फ्रिंमिन्स ला जमंडमट ऐक्ट को कांग्रेस ने हरदम से दमनात्मक कानून माना था। आलोचकों का कहना था कि राजगोपालाचारी की मदद से मद्रास का कांग्रेसी मंत्रिमंडल हिंदू विरोधी जादालन के विरुद्ध इस ऐक्ट का उपयोग कर रहा था। आलोचकों का और अधिक विश्वास हुआ जब गांधी ने भी इसके इस्तमाल का समर्थन किया। उन्होंने हरिजन भेदभाव, भी कहा कि यह ऐक्ट नहीं पढ़ा है लेकिन राजाजी की स्पष्ट घोषणा से पता चलता है कि इसमें कुछ अच्छे प्रकरण भी हैं जो कांग्रेस जिम्मेदार स्थिति का सामना कर रही है उसमें उपयुक्त हैं। अगर ऐसी बात है तो इनका इस्तमाल न कर राजाजी बचूफ्री करेंगे।'

घाटलीवाला नामक एक प्रमुख समाजवादी को मद्रास से निकाल बाहर कर दिया गया। 1938 में बंबई में वायसराय डिम्ब्युटम एक्ट बना। इस ऐक्ट ने हस्तगत की स्वतंत्रता सीमित कर दी और मजदूर संगठनों के रजिस्ट्रेशन के नियमों को अधिकृत कर दिया। मजदूर नेताओं के अनुसार यह वायसराय के लिए वायसराय के 4 जिन्हें मिल मालिकों ने मुद्रा गड़ा किया था। वायसराय प्रोविंसियल ट्रेड यूनियन वायसराय के विरोध में हड़ताल में गठित की। इस मिलमिल में पुलिस की गोला भी एक जादमी मरा और बहुत से घायल हुए।

पुनः घोषणा पत्र में हस्तगत के अधिकारों का सुरक्षा प्रश्न भी गढ़ा था। जब वायसराय सरकार ने इस अधिकारों का सीमित करन कहा तो प्रति 15 अगस्त के लिए उम्मीदें जागरूक हुईं। पुलिस गठानों का भी निर्णय हुआ।

अहमदाबाद में मजदूरों ने हड़ताल की तो कांग्रेस सरकार में दफा 144 लागू किया। जब राजनीतिक बंदियों की रिहाई दिवस के अवसर पर शोलापुर के मजदूरों ने प्रदर्शन संगठित किए तो उनके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। उनमें से कुछ पर मुकदमा चला और उन्हें सजा भी मिली। जब किसानों ने तारु के राजा के खिलाफ मघप शुरू किया तो नाथ वेस्ट फ्रटियर प्रांत की कांग्रेसी सरकार ने भी क्रिमिनल ला अमंडमट ऐक्ट का इस्तेमाल किया जिसके लिए उसकी आलोचना हुई।

अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष स्वामी सहजानंद ने बाबू राजेंद्र प्रसाद के जवाब में 'दि अदर साइड जाफ द शील्ड' नामक पुस्तिका लिखी। उसमें उन्होंने बड़े बड़े शब्दों में चुनाव के पहले दिए गए वचनों को भंग करने के लिए और किसान आंदोलन के खिलाफ दमनात्मक कार्य के लिए कांग्रेस की आलोचना की। इंडियन सिविल लिबरटोज यूनियन के सचिव डा० मनन ने सिविल लिबरटोज अंडर प्रॉविसियल एटानमी में लिखा

यह तो मानना ही पड़ेगा कि प्रमुख दमनात्मक कानून ज्यों के त्यों हैं।

क्रिमिनल ला अमंडमट ऐक्ट भी इन्हीं में है।

इस ऐक्ट के इस्तेमाल के सिलसिले में पंजाब की सरकार ने सत्रस अधिक जघन्य अपराध किए हैं। 1937 में पंजाब में इस कानून के अंतर्गत 24 मुकदमों चले। इसका वाद बंगाल का स्थान आता है।

जहाँ तक तादाद का सवाल है इस ऐक्ट के इस्तेमाल में मद्रास की कांग्रेस सरकार इन दोनों से भी आगे बढ़ी हुई है।

बंबई की सरकार ने अहमदाबाद के सूती कारखानों के मजदूरों की हड़ताल के सिलसिले में इस ऐक्ट का लागू किया और शोलापुर में भी इस ऐक्ट का इस्तेमाल हुआ।

पर्याप्त वित्त के अभाव में मंत्रिमंडल समाज कल्याण के विधेयक को पारित कर सके और न लागू कर सका। किसानों के बारे में कांग्रेस सरकार ने कुछ काम किए, लेकिन वे अपर्याप्त थे। कांग्रेस सरकार की वाद टर्नेसी बिल से जता कि बिल की प्रस्तावना के रूप में दिए गए वक्तव्य में कहा गया है, 'केवल चार प्रतिशत किसानों को फायदा हुआ। सेतिहर मजदूरों के लिए लगभग कुछ नहीं किया गया।

किसान संगठनों की बढ़ती हुई ताकत तथा कांग्रेस की बाएँ खिलाफियों का इन संगठनों द्वारा की गई आलोचना से किसानों के अंतर्गत का परिचय मिलता है।

कांग्रेस सरकारों की यह भी आलोचना की गई कि चुनाव घोषणा पत्र के विरुद्ध प्रांतों में व्याप्तता सिद्धान्तों को लागू किया जा रहा है। यह आलोचना कांग्रेस के ही कामपदियों ने की।

1935 के बाद रा एन महत्वपूर्ण घटना यह भी थी कि भारत के दली रियासतों के लोगों की राजनीतिक चेतना लगातार बढ़ती रही। तब उन्हीं रियासतों में प्रजा मंडल या जनताघन स्थापित हुए। आज उत्तर रियासतों के इन





दे दिया और उनकी जगह राजद्रप्रसाद चुने गए। वाम नवाद में फारवर्ड ब्लाक की स्थापना की।

मई में जाल इंडिया कांग्रेस समिती की बैठक हुई और इसमें जो प्रस्ताव पारित किए उससे कांग्रेस का मविधान अधिक सुनम्य हो गया। कांग्रेस मन्त्रिमंडल पर नियंत्रण रखने के प्रांतीय कांग्रेस कमिटियों के अधिकार को कम कर दिया गया और कांग्रेस समिती की महामति के बिना कांग्रेस सदस्यों के आंदोलन शुरू करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसमें चलते कांग्रेस के पदासीन नतृत्व की इच्छा के विरुद्ध कोई आंदोलन संगठित करना असंभव हो गया।

दक्षिणपंथी नतृत्व के प्रभाव के कारण काय की स्वतंत्रता खत्म करने का जा निषेध लिया गया उसका सामपंथी दत्ता ने विरोध किया। इसलिए वीम पर जारप लगाया गया कि वे कांग्रेस का अनुशासन भंग कर रहे हैं। इसलिए उन्हें प्रगत प्रांतीय कांग्रेस समिती की अध्यक्षता में भी इस्तीफा देना पड़ा।

कांग्रेस ने मधीय राजना अस्वीकार कर दी थी और यह फमला भी लिया जा चुका था कि अगर यह लागू किया गया तो इसके खिलाफ राजाशासन शुरू किया जाएगा। कांग्रेस के भीतर और बाहर उग्रवादी शक्तियां बढ़ रही थी। उन्नी तरह किसानों और मजदूरों के आंदोलन भी बढ़ रहे थे और रियायतों की जनता के प्रजातांत्रिक और सामंत विराधी लघप भी अधिक व्यापक हो रहे थे। जब दंग में ये सारी घटनाएँ हो रही थी, तभी द्वितीय महायुद्ध शुरू हो गया।

जगह की तमी की बाहसे और चूनि राजनीतिक राष्ट्रवाद का गवाह रनिहाय लिखना नहीं परा भारतीय राष्ट्रवाद के उद्भव की सामाजिक पृष्ठभूमि और उसकी उत्पत्ति के सामाजिक कारणों का विवेचन करना हमारा उद्देश्य है इसलिए भी अब हम यह अध्ययन समाप्त करते हैं।

## संदर्भ

- 1 अग्र दृश्य० राय सिमर ।
- 2 अग्र (2) अग्र उद्धृत पृ० 14-15 ।
- 3 अग्र राय एड भवन ।
- 4 जाल जून प 35 ।
- 5 पृ० प० 35 ।
- 6 अग्र पृ० प० 274 ।
- 7 अग्र राय एड भवन सिद्धिपत्र दत्त और शूच ।
- 8 अग्र राय प 59 ।
- 9 अग्र राय एड भवन अग्र और शूचर ।
- 10 अग्र राय पृ० 55 ।
- 11 अग्र पृ० 75 ।

- 12 देखें टामसन एंड गरेट प० 492 ।
- 13 वही प० 493 ।
- 14 देखें जान स्टुवर्ट मिन हास वाहन ।
- 15 वध प० 151 ।
- 16 सर जी० आथर प० 177 ।
- 17 हास वाहन प० 360 ।
- 18 सर विलियम बडरवन, प० 10 ।
- 19 आर० पी० दत्त प० 279 ।
- 20 सर विलियम बडरवन द्वारा उद्धृत प० 77 ।
- 21 वध द्वारा उद्धृत प० 170 ।
- 22 एड्ज एंड मुखर्जी, प० 128 29 ।
- 23 देखें पट्टाभि सातारमया पृ 26-27 ।
- 24 एनी बमट प० 7 ।
- 25 वेलाक द्वारा उद्धृत प० 120 ।
- 26 सुरदनाथ बनर्जी प० 94-95 ।
- 27 वही, प० 315 16 ।
- 28 काग्रन प्रमिडमियल एड्सोज फ्ल्ट सिराज प० 254 55 ।
- 29 वही प० 78 ।
- 30 फिरोजशाह महता आर० पी० दत्त द्वारा उद्धृत प० 288 ।
- 31 आर० सी० दत्त प० XVIII ।
- 32 गोखले प० 1005 6 ।
- 33 वध पट्टाभि सातारमया प० 94 95 ।
- 34 वही पृ० 109 ।
- 35 वही ।
- 36 रानाल्डस जिल् II प० 151 ।
- 37 पट्टाभि सातारमया द्वारा उद्धृत पृ० 112 13 ।
- 38 काग्रन प्रमिडमियल एड्सोज, सरुड गिरीज प० 12 ।
- 39 वही प० 167 ।
- 40 काग्रन प्रमिडमियल एड्सोज फ्ल्ट गिरीज प० 738 39 ।
- 41 पट्टाभि सातारमया प० 11 ।
- 42 सा० सा० पाल वध (2) द्वारा उद्धृत प० 103 ।
- 43 बी० मा० पाल प० 36 ।
- 44 वध (2) द्वारा उद्धृत प० 144 ।
- 45 वही प० 45 ।
- 46 वही प० 145 46 ।
- 47 वही, प० 127 28 ।
- 48 वही प० 146 ।
- 49 आर० पी० दत्त प० 292 ।
- 50 ब्रह्मरान नरु प० 23 24 ।
- 51 आर० पी० दत्त पृ० 418 ।
- 52 वध, पृ० 416 ।
- 53 वध वध (2) द्वारा उद्धृत पृ० 28 ।

- 54 वहाँ पृ० 29 ।
- 55 वही, पृ० 34-35 ।
- 56 वही, पृ० 49 ।
- 57 पट्टाभि सीतारमया द्वारा उद्धृत पृ० 164-65 ।
- 58 यह सारी सूचना मुख्यतः रीलेट कमटी रिपोर्ट पर आधारित है ।
- 59 डब्ल्यू० राय स्मिथ पृ० 80 ।
- 60 देखें डब्ल्यू० राय स्मिथ पृ० 80 ।
- 61 देखें पट्टाभि सीतारमया पृ० 280 ।
- 62 यंग इंडिया, 31 दिसंबर 1919 ।
- 63 पट्टाभि सीतारमया पृ० 235 ।
- 64 वहाँ पृ० 33 ।
- 65 वही ।
- 66 पट्टाभि सीतारमया द्वारा उद्धृत पृ० 383 ।
- 67 लाड रीडिंग टेलिग्राफिकल कारेसपाइस रिमाइंडिंग द सिचुएशन इन इंडिया [सी एम डी० 1586 1922 ।
- 68 सुभाष बोस पृ० 90 ।
- 69 पट्टाभि सीतारमया पृ० 399-400 ।
- 70 स्वराजवाणी बक्तव्य, पट्टाभि सीतारमया द्वारा उद्धृत पृ० 462 ।
- 71 देखें पट्टाभि सीतारमया ।
- 72 जवाहरलाल नेहरू पृ० 459 ।
- 73 जॉन ब्यूक्चर द्वारा उद्धृत पृ० 185 ।
- 74 पट्टाभि सीतारमया द्वारा उद्धृत पृ० 560 ।
- 75 गवर्नमेन्ट आफ इंडिया रिपोर्ट, इंडिया 1928-29 ।
- 76 माधो जार० पी० दत्त द्वारा उद्धृत पृ० 33 ।
- 77 आर० पी० दत्त द्वारा उद्धृत पृ० 342 ।

## राष्ट्रिक इकाइयों और अल्पसंख्यकों की समस्या

### भारत में राष्ट्रिक इकाइयों और अल्पसंख्यकों की समस्या

राष्ट्रिक इकाइयों और अल्पसंख्यकों की समस्या भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की अत्यंत समस्या थी। जाधवासिया, मलयालियों, कर्नाटकवासियों, महाराष्ट्रियों, बलूचियों इत्यादि राष्ट्रिक इकाइयों एवं मुसलमानों, सिक्खों, दलित जातियों आदि अल्पसंख्यकों में जैसे-जैसे राजनीतिक जागरण जाया, वैसे वैसे राजनीतिक स्वातंत्र्य के लिए किए गए संयुक्त राष्ट्रीय आंदोलन और स्वातंत्र्योत्तर भारत की भावी राज्यव्यवस्था की दृष्टि से यह प्रश्न विविध और विनाशकारी महत्व का होता गया। राष्ट्रिक इकाइयों और अल्पसंख्यकों की समस्या भारत की ही तरह आस्ट्रेलिया, हंगरी, रूस आदि देशों के भी आधुनिक इतिहास में उदित हुई है और उन देशों में भी इसके समाधान की आवश्यकता पड़ी है।

ऐसा नहीं है कि अपने ऐतिहासिक विकास के आधुनिक चरण में हर देश को राष्ट्रिक इकाइयों के प्रश्नों का सामना करना पड़ा हो। उदाहरणार्थ, अंग्रेजों और फ्रांसिसियों का अपने राष्ट्रगत समकालीन और फिर परस्पर युग के अपने संपूर्ण विजयशील अस्तित्व के दिनों में भी इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। इसके विपरीत पूर्वी यूरोप के देशों, जैसे आस्ट्रो-हंगेरियन साम्राज्य और बाल्कन क्षेत्र में इस संकाल से निपटना पड़ा।<sup>1</sup> इस अंतर के पास ऐतिहासिक कारण हैं।

### राष्ट्रिक इकाइयों की उत्पत्ति के कारण

आधुनिक राष्ट्रों की ऐतिहासिक प्रगति का सर्वोत्तम स्रोत इस विविध तथ्य का पता चलता है कि वे समाज के पूंजीवादी विकास के परिणाम हैं। पूंजीवादी आर्थिक विकास के विस्तार की प्रक्रिया किसी भी राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जनयत्ना का अतिप्रमाण है और यह राजनीतिक और व्यवस्था के अंतर्गत समाजिक जीवन राष्ट्र के रूप में एकतायुक्त कर देता है।

आधुनिक पूंजीवाद के आगमन पर जासूसी के विभिन्न युगों और इनके विभिन्न भागों में पारस्परिक संबंध बढ़ता है। आधुनिक पूंजीवाद के

शक्तिशाली समाकलनात्मक तत्व है। यह सामतवाद द्वारा लगाए गए व्यवधानों, अवरोधों को खतम कर बहुत बड़ी तादाद में लोगों को औद्योगिक केंद्रों में एकत्र करता है। यह शहरों और देहातों को जोड़ना है और मध्य वर्ग का निर्माण करता है, जो शुरू में राष्ट्रीयता की नई विचारधारा का एकमात्र प्रतिनिधि है। आधुनिक राष्ट्रों का उदभव मध्यवर्गीय प्रजातांत्रिक क्रान्तियों से जुड़ा हुआ है, इन क्रान्तियों ने सामंती जलगाव और विखराव को खतम किया और पहली बार समान विचारों के आधार पर बड़ी-बड़ी आवादियाँ का समुक्त संघर्ष में एकताबद्ध किया। इस तरह सत्रहवीं सदी की क्रान्ति के फलस्वरूप ब्रिटिश राष्ट्र का उदय हुआ और 1789 की महान् क्रान्ति के फलस्वरूप फ्रांसीसी राष्ट्र का।

कुछ देशों में केंद्रीभूत राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना के पहले ही आर्थिक एवं भाषागत और सांस्कृतिक समेकन की प्रक्रिया ने राष्ट्रिक इकाइयों को सुगुण राष्ट्रों के रूप में गठित कर लिया था, और वहाँ राष्ट्रिक इकाइयाँ और अल्पमध्यको की कोई विशेष समस्या नहीं थी। इसके विपरीत कुछ दशकों में पूँजीवादी आर्थिक विकास की प्रक्रिया में लोगों को एकीकृत कर सकने की जो शक्ति है उसका फलस्वरूप विभिन्न जातियों के लोग सम्मिलित आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के भागी की हैसियत से राष्ट्र के रूप में परिवर्तित हो सकें इसके पहले ही ऐतिहासिक कारणों से केंद्रीभूत राज्य सत्ता स्थापित हो गई, और वहाँ ऐतिहासिक विकास के क्रम में राष्ट्रिक इकाइयाँ और अल्पमध्यको की समस्या का जन्म हुआ। स्टालिन ने इस ऐतिहासिक तथ्य की सारगर्भित विवेचना की है

आधुनिक राष्ट्र का निश्चित युग, उदीयमान पूँजीवाद युग की देन है। सामतवाद के उन्मूलन और पूँजीवाद के विकास की प्रक्रिया जनता के राष्ट्र रूप में परिवर्तन की भी प्रक्रिया थी। पूँजीवाद की विजयशील प्रगति और सामंती जनकता पर उसकी जीत के युग में ब्रिटिश फ्रेंच, जर्मन और इटालियन राष्ट्रों का उदय हुआ।

जहाँ राष्ट्रों का निर्माण केंद्रीभूत राज्य सत्ता के उदय के साथ-साथ हुआ, वहाँ राष्ट्रों का अनिवाद्यत राज्य सत्ता का परिवर्तन मिला और वे स्पष्टतः बुर्जुआ पूँजीवादी राष्ट्रीय राज्यों के रूप में परिणत हुए। ग्रेट ब्रिटेन (आयरलैंड को छोड़कर) फ्रांस और इटली में यही स्थिति थी। इसके विपरीत, पूर्वी यूरोप के देशों में, केंद्रीभूत राज्यों का स्थापना (तुर्क, मंगोल, इत्यादि लोगों के हमला से) आत्मरक्षा की आवश्यकताओं के कारण जल्दी हुई, सामतवाद के विघटन और इस तरह राष्ट्रों के निर्माण के पहले। फलस्वरूप, इन देशों में, राष्ट्र राष्ट्रों के रूप में विद्यमान नहीं हो सके और नहीं हुए, और वे मिश्रित बहुराष्ट्रिक बुर्जुआ पूँजीवादी परिणत हुए आस्ट्रिया, हंगरी और रूस में यही स्थिति थी।<sup>2</sup> आर्थिक तथा अन्य प्रसार के विकास एवं अधिन गतिमान

के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दमन के इन बहुराष्ट्रिक राज्यों की विभिन्न राष्ट्रिक इकाइयाँ म राष्ट्रिक इकाई की चेतना का विकास हुआ।<sup>4</sup> दमित लेकिन आर्थिक तौर पर समेकित और चैतन्य राष्ट्रिक इकाइयों ने, जिनके अपने विभिन्न भू-भागीय क्षेत्र थे, राजनीतिक स्वतंत्रता और सावभौम राज्य सत्ता के लिए जादोलन शुरू किए। इसी तौर पर धार्मिक (जैसे यहूदी) या प्रजातीय अल्पसंख्यका न जा देश के समस्त भू-भाग में बिखरे हुए थे, चैतन्य होने पर धार्मिक स्वतंत्रता, और अपनी भाषा और संस्कृति के विकास की उचित सुरक्षा के लिए जादोलन किए।

### राष्ट्र और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक, उनके अंतर

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक जनसमुदाय से राष्ट्र इस तरह भिन्न है कि राष्ट्र के लोग निश्चित भू-भाग में रहते हैं, प्रायः एक ही भाषा बोलते हैं, और उनका सम्मिलित आर्थिक जीवन होता है, और उनकी सम्मिलित मनोवैज्ञानिक संरचना होती है जो उनकी संस्कृति द्वारा उदभासित है।

राष्ट्र ऐतिहासिक तौर पर विकसित होता है, यह भाषा, भूक्षेत्र, आर्थिक जीवन और सांस्कृतिक ऐक्य में परिलक्षित मनोवैज्ञानिक अस्तित्व का स्थिर, निश्चित संयोग है।<sup>5</sup>

किसी राष्ट्र के लोग विभिन्न धर्मों के अनुयायी हो सकते हैं, लेकिन इससे उनके राष्ट्रत्व पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि धर्म स्वार्थी तत्व नहीं है। 'असमी मूल धार्मिक कमबन्ड और अस्त्रियमाण मनोवैज्ञानिक अवस्था' उनके चतुर्दिक 'गीबत सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्ष' लगातार परिशासित होते रहते हैं।<sup>6</sup> इस तरह ब्रिटेन के लोग में से कुछ प्रोटेस्टेंट हैं, कुछ कैथोलिक तौर उनका बीच नौतिकवादिया अनेकवादिया और विवासफिस्टा के भी दक्कान-बुवका छोटे-माटे दल हैं, फिर भी वे एक राष्ट्र का सदस्य हैं।

भारत के मुसलमानों और दलित जातियों जैसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक राज्य का मार भूक्षेत्र में फैल हुए होते हैं। ये लोग प्रायः धर्म के मूल में परस्पर उधे रहते हैं और अप्रजातान्त्रिक समाज व्यवस्था के कारण किसी विशिष्ट सामाजिक अंश के भागी होते हैं। लेकिन ये भिन्न, पृथक् राष्ट्र नहीं होते, क्योंकि एस किसी दल के सार सदस्य किसी पूंज्य विद्या के वासी नहीं होते और उनका सम्मिलित आर्थिक जीवन नहीं होता। यस्तुतः इनके अलग-अलग हिस्से विभिन्न नूतनों में रहने वाले विभिन्न राष्ट्रिक इकाइयाँ के अंग होते हैं। इन राष्ट्रिक इकाइयों की अपना अलग-अलग भाषाएँ होती हैं और इनका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन परस्पर भिन्न होता है।

### भारतीय राष्ट्रवादी जादोलन को विशिष्टता

प्रायः ब्रिटेन काव का नीति, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक

तोर पर असंपृक्त भारतीय जनता का कमोवेश संयुक्त आधुनिक राष्ट्र के रूप में परिवर्तन का रास्ता अंग्रेज और फ्रांसीसी जनता के राष्ट्रीय संवेदन के रास्ते से भिन्न था। ब्रिटिश पूँजीवाद ने आर्थिक और राजनीतिक साधना के जरिए भारतीय सामंतवाद का जपग किया, पूँजीवादी आर्थिक रूपों और प्रक्रियाओं के जरिए भारत का आर्थिक एकीकरण किया, जावागमन और संचार के आधुनिक साधना की स्थापना की जो मध्ययुगीन जलम जनजीवन के बहुमुखी विकास और संगठन के लिए अत्यंत आवश्यक है, और भारत में केंद्रीभूत राज्य व्यवस्था का जनक था।<sup>7</sup>

फिर भी, चूंकि भारतीय समाज का यह रूपांतर विदेशी पूँजीवाद के हितों द्वारा अनुप्रेरित था और चूंकि इस रूपांतर की प्रकृति, व्यापकता और गहराई इन विदेशी हितों द्वारा अनुकूलित थी, इसलिए यह रूपांतर अधूरा और विवृत रहा। इस रूपांतर ने अव्यवस्थित मध्य युगीन जनसमुदाय से भारतीय राष्ट्र के उद्भव के लिए वस्तुनिष्ठ जावार तैयार किया और इस रूपांतर के अधूरेपन के कारण हिंदुस्तान राष्ट्र के रूप में ब्रिटेन या फ्रांस के समान समर्थित नहीं हो सका।

इन यूरोपीय देशों में सामंतवाद पर विजय के फलस्वरूप जो राष्ट्रीय राज्य बन, उन्होंने उन राष्ट्रों के सामाजिक और आर्थिक जीवन से सारे सामंती अवशेष निकाल फेंके, तथा मुक्त और तीव्र आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास को जमकर मदद पहुंचाई। लेकिन हम देख चुके हैं कि भारत में अंग्रेजी शासन ने सामंती अवशेषों को जीवित रहने दिया और प्रायः भारतीय समाज के प्रतिक्रियावादी तत्त्वों को, शासन के सामाजिक स्तंभ के रूप में समर्थन प्रदान किया और साथ ही सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों, विधायिका सभा में हितों के प्रतिनिधित्व और अन्य तरीकों से राजनीतिक संतुलन की नीति अपनाई। इन कारणों से पुराने विभेद बने रहे और भारतीय जनता के राष्ट्रीय संगठन की प्रक्रिया अवरुद्ध हुई। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय अर्थतंत्र को साधारणतः ब्रिटेन के अर्थतंत्र के अधीन रखा, जिसके फलस्वरूप इसका तीव्र और उच्च विकास नहीं हो सका यद्यपि देश के राष्ट्रीय संगठन के लिए यह अत्यंत आवश्यक था। जावागमन के साधना और वाणिज्य का विकास, शहरों की प्रगति और उनका उच्चाधिकरण और तंत्रण सामाजिक एक्य और सांस्कृतिक उत्थान, जीवन के ये सारे नए तथ्य संकुचित और विवृत होते गए। संतुलन और विनिष्ट सांप्रदायिक एवं दूसरे प्रकार के हितों की रक्षा के नाम पर देश के सांप्रदायिक और दूसरे प्रकार के रुढ़िवादियों का समर्थन प्रदान करने की अंग्रेजी शासन की जा नीति थी, उसने राष्ट्र विरोधी विभाजन की प्रवृत्ति या ही प्रथम दिया। इन्हीं प्रमुख कारणों से भारतीय जनता का राष्ट्रीय संवेदन उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सका जहां उन्नीसवीं सदी में अंग्रेज और फ्रांसीसी जा था।

<sup>7</sup>म अशांत परिपक्वता में प्रदायवादियों और अन्य की प्रतिक्रियाओं से देश की नींवता का भी साधन रहा। यह विच्छेदपूर्ण उन्नियोगी साधारण और

आर्थिक और सांस्कृतिक विकास की अवरुद्ध स्थिति में फले फूले थे। जो प्रगतिशील तत्व नए भारतीय समाज में ब्रिटिश काल में उत्पन्न हुए थे उनकी तथा समस्त भारतीय समाज की भी मुक्त आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रगति पर रजवाड़ा, जमींदारों, मप्रदायवादियों और अन्य देशी प्रतिनियामकों की मदद से अंग्रेजी सरकार ने जो प्रतिबंध लगाए थे, उनके खिलाफ प्रगतिशील तत्वों के अधिकाधिक समवेत और सतक संघर्ष के परिणामस्वरूप भारतीय राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इस तरह भारतीय सामंती अवस्था तथा अन्य प्रतिनियामकों की तत्वा द्वारा समर्थित ब्रिटिश पूंजीवादी शासन से भारतीय राष्ट्रवाद को टक्कर लेनी पड़ी। इसके विपरीत, अंग्रेजी और फ्रांसीसी जनता की राष्ट्रीयता को, राष्ट्रीय जनतान्त्रिक विकास के काल में देशी सामंती वर्गों के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ा। भारतीय राष्ट्रवाद की यह एक मूलभूत विशेषता थी।

भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन की यह भी खासियत थी कि विद्वानी पूंजीवादी राष्ट्र की गुलामी में रहते हुए उपनिवेशी जनता के आंदोलन के रूप में, इस जन आधार 1920 के बाद प्राप्त हुआ, उस वक्त जब विश्व पूंजीवादी व्यवस्था का ह्रास शुरू हो गया था और शक्तिशाली समाजवादी दुनिया का उदय हो चुका था। भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन उस साम्राज्यवादी व्यवस्था के खिलाफ था जिसका विरोध समाजवादी आंदोलन द्वारा भी हो रहा था।

भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन की तीसरी विशेषता यह थी कि बुजुर्गों, जिसने बाद के चरण में इस आंदोलन को जनता का आंदोलन बनाया, समझौते की प्रवृत्ति से ग्रस्त रही और शासन साम्राज्यवादी से मेल मिलाप चाहती रही। इसकी यह वजह थी कि भारतीय बुजुर्गों देश के प्रतिनियामकों जमींदार और मूदधार महाजन तबका से पूर्णतः मरुद्ध थी अपनी आर्थिक कमजोरी के कारण ब्रिटिश वित्तीय पूंजी पर आश्रित थी और साथ ही जन आंदोलन के विस्तृत होत हुए जायमान से डरी हुई थी, क्योंकि इन वह अपने वर्ग हितों के लिए अतर्नाक मानती थी। बुजुर्गों के वर्ग हितों की दृष्टि से यह तबक संगत भी था। जन आंदोलन की बढ़ती हुई ताकत में यह संभावना निहित थी कि देश का घर पूंजीवादी राष्ट्रीय शक्तियों की पूर्ण विजय होगी और स्वातंत्र्योत्तर काल में समाजवादी व्यवस्था स्थापित होगी।

इस तरह, पूंजीवाद के उदय के काल में सामंतवाद के विरुद्ध अंग्रेजों और फ्रांसिसी लोगों के जो राष्ट्रीय जनतान्त्रिक आंदोलन हुए, उनका परिणाम बुजुर्गों की विजय और इन देशों में आधुनिक पूंजीवादी समाज का स्थापना में और इन विजय पूंजीवादी विज्ञान का काल शुरू हुआ। इस विपरीत, ब्रिटिश पूंजीवाद के अस्तित्व के युग में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध चलाने गए भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में यह संभावना परिनिर्मित थी कि अंतर्गत परिणामों पर पूंजीवादी विजय नहीं होगी और इसलिए दुनिया के दूसरे भागों के साथ यह भारतीय जनता के राष्ट्रीय अन्तिम समाजवादी चरण में प्रवेश करेगा।



## सुपुप्त राष्ट्रिक इकाइयो का जागरण

ऊपर कहा जा चुका है कि राष्ट्रिक इकाइयो एव अल्पसंख्यका की समस्या भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन की एक प्रमुख समस्या थी। अब हम यह विचार करें कि इस समस्या का जन्म कैसे हुआ और कैसे भारतीय राष्ट्रवादी राजनीति में यह समस्या इतनी महत्वपूर्ण हुई।

विभिन्न संप्रदायो और प्रांता में राष्ट्रवाद का विकास समय और स्थानानुसार अलग-अलग प्रक्रिया थी। हम देख चुके हैं कि अंग्रेजों की भारत विजय और भारत पर उनके शासन और उसकी सहयोगी शक्तियों की क्रियाओं द्वारा सृजित स्थिति के फलस्वरूप भारत में राष्ट्रवाद का जन्म हुआ।

अंग्रेजों की प्रभुता और तत्संबन्धी शक्तियों का विस्तार सारे देश में एक साथ नहीं हुआ था, इसलिए जिस स्थिति में राजनीतिक और राष्ट्रीय चेतना को जन्म दिया, वह विभिन्न भागों और संप्रदायों में असमान तौर पर परिपुष्ट हुई। कुछ प्रांतों और संप्रदायों में राजनीतिक चेतना पहले आई। फलस्वरूप, भारतीय जनता के राष्ट्रीय आंदोलन में समानांतर रूप से, मुसलमानों, दलित जातियों, सिक्खों और गैर ब्राह्मणों जैसी सामाजिक धार्मिक श्रेणियों के और आंध्रप्रदेश, बंगाल, कर्नाटक, तमिल नाडु, कन्नड़, और मराठियों, उड़ीसा, गुजरातियों, पंजाबियों, सिंधियों, उड़ीसियों, बिहारियों आदि प्रांतीय सामाजिक दलों के जिनकी एक भाषा और संस्कृति थी स्वतंत्र राजनीतिक आंदोलन शुरू हुए।

इन प्रांतीय सामाजिक समुदायों में निहित जो सुपुप्त राष्ट्रिक इकाइया थी, उनका वर्तमान सदी के चौथे दशक में इस हद तक राजनीतिक जागरण हो गया था कि ये लोग अपने-अपने विभिन्न इकाइयों, अपने-अपने राष्ट्रिक इकाइयों मानने लगे। इसके कई कारण थे, जैसे इन प्रांतों की आर्थिक प्रगति, जिससे औद्योगिक और वाणिज्यिक वर्गों का काफी विकास हुआ, शिक्षित वर्गों की संख्या में वृद्धि, 1930-34 का नागरिक अवकाश आंदोलन जो पहली बार इन राष्ट्रिक इकाइयों की जनता में कुछ लोगो को राष्ट्रीय आंदोलन की परिधि में लाया और जिससे उनमें राष्ट्रीय चेतना की ज्योति जली। संपन्न प्रांतीय साहित्य का भी इन वर्गों में उदय हुआ। इनमें इन प्रांतों में बुद्धिजीवी वर्ग की राष्ट्र चेतना का अभिव्यक्ति मिली। विविध राष्ट्रिक इकाइयों के रूप में स्वतंत्र जीवन की इन राष्ट्रिक इकाइयों की इच्छा आकांक्षा को भी इन साहित्यिक रचनाओं में बाणी दी। इस तरह आवाजों से अधिकाधिक लोगो में राष्ट्र चेतना का प्रसार हुआ। इन राष्ट्रिक इकाइयों के आंदोलन आत्मनिर्णय की भावना और विविध राष्ट्रिक इकाइयों के रूप में स्वतंत्र जीवन के विचारों की आकांक्षा से अनुप्रेरित थे। ये आंदोलन उनके द्वारा अनुभूत विविध नामों से विविध दवावों के परिणाम थे।

जैसे-जैसे इन प्रांतों में दल चेतना बढ़ी, वैसे-वैसे उनमें यह भावना भी

आई कि वे मुक्त सामूहिक जीवन व्यतीत करे, ऐसा जीवन जो बलमान प्रातीय सीमाओं और विभाजनों द्वारा अवरुद्ध नहीं हो। ये प्रात भाषागत आधार पर नहीं, वरन अंग्रेजों के बढ़ते हुए प्रभाव के युग में प्रशासनिक सुविधा के लिए बन थे। इनमें से कुछ राष्ट्रिक इकाइयों ने, जैसे बिहारिया, आंध्रवासिया, कर्नाटकवासिया, जिनकी अपनी पृथक भाषा और मस्कृति थी, प्रातों के पुनर्गठन की मांग की, जिससे वे भूक्षेत्रों की दृष्टि से भी एकीकृत हो जाएं। उदाहरणार्थ, आंध्र वाले मद्रास से अलग होना चाहते थे और कर्नाटक वाले महाराष्ट्र से अलग संयुक्त कर्नाटक चाहते थे। बिहार और उड़ीसा आदि के लोगों ने भी ऐसी ही मांगें प्रस्तुत कीं।

इन नवजागत राष्ट्रिक इकाइयों ने अपनी-अपनी भाषाओं और अपने-अपने साहित्य का समृद्ध बनाया, अपने विश्वविद्यालय स्थापित किए, अपने 'राष्ट्रीय रंगमंच' की स्थापना की, सब तरह से अपनी मस्कृति को पुनरुज्जीवित किया, और उस सुमपन बनाया। आंध्र, महाराष्ट्र और कर्नाटक के अपने व्यापार मंडल भी स्थापित हुए। इनसे इन जातियों में जाति चेतना के उद्भव और एकीकरण की उनकी इच्छा का परिचय मिलता है। इन लोगों की यह इच्छा कि उनके अपने अलग प्रात बनें जहां लागू एक ही भाषा बोलें जहां उनकी एक मस्कृति हो, एक भारतीय राज्य की धारणा के विरुद्ध नहीं थी। प्रातों के पुनर्विभाजन की मांग केवल इसलिए की गई कि इनका निर्माण ब्रिटिश शासन की जख्मतों की दृष्टि से किया गया था। इन जागृत जातियों ने पृथक सावभौम राज्य सत्ता की या भारत के राजनीतिक विभाजन की मांग नहीं की।

इंडियन नेशनल कांग्रेस ने स्थिति को पहचाना और उसमें भाषागत आधार पर प्रातों के पुनर्गठन की योजना अपनाई। स्वतंत्र भारत के लिए जिस संघीय राज्य की कल्पना उसने की उसके अनुसार सुरक्षा, संचार, विदेशी संबंध आदि कुछ मामलों में केंद्र का अधिकार और नियंत्रण के अतिरिक्त अन्य मामलों में प्रातों को व्यापक स्वायत्ता मिलनी वाली थी। उसमें यह भी कहा कि कोई भी भूभागीय इकाई भारतीय संघ में रहने को बाध्य नहीं होगी और अगर वह चाहे तो उस अलग हो जाना चाहेगा।

## दो विरोधी प्रवृत्तियाँ

लेकिन इन जागृत राष्ट्रिक इकाइयों के बढ़ते हुए आंदोलन में दो विरोधी प्रवृत्तियाँ काम कर रही थीं—पहली प्रगतिशील और दूसरी राष्ट्र विरोधी, विघटनवादी और प्रतिश्रियावादी।

जब इन राष्ट्रिक इकाइयों ने भूभागीय एकीकरण एवं अपनी भाषा और मस्कृति के मुक्त विकास आदि की मांग की तो उन्होंने पूरे आत्मनिर्भरता और आत्मनिर्भरता की अपनी राष्ट्रीय प्रजातंत्रिक इच्छा का प्रदर्शन भी किया। उनका एक इच्छा एक दूसरी राष्ट्रिक इकाइयों और समस्त भारत के साथ राष्ट्रीय स्वायत्तता का स्थापना राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होना था जो उनकी इच्छा के साथ ही आगे बढ़ेगा।

नहीं था। वस्तुतः इस नवजागरण से राष्ट्रीय एकता की उनकी इच्छा और अधिक बलवती ही हुई, क्योंकि स्वतन्त्रता प्राप्ति पर वे अन्य लोगों के साथ, सध में विशिष्ट राष्ट्रिक इकाइयों के तौर पर, अपना भी मुक्त विकास कर सकेंगे। इस प्रवृत्ति से आशा की जा सकती थी कि स्वतन्त्र भारत विभिन्न राष्ट्रिक इकाइयों के सपन्न जटिल बहुमुखी सामाजिक और सांस्कृतिक अस्तित्व का सम्मिश्रण होगा। यह निश्चय ही प्रगतिशील प्रवृत्ति थी।

लेकिन इसके साथ एक दूसरे तरह की प्रवृत्ति भी काम कर रही थी। इन नवजागृत राष्ट्रिक इकाइयों के वाणिज्यिक और औद्योगिक तत्वों ने इन राष्ट्रिक इकाइयों के साधारण लोगों की जातीय चेतना का दुरुपयोग किया। उन्होंने दूसरी राष्ट्रिक इकाइया एवं प्रांत के व्यापारिक और औद्योगिक प्रतियोगियों के खिलाफ घबूँटा की भावना जगाकर निजी स्वार्थों का राष्ट्रीय पहनावा देने की चेष्टा की। इसी तरह राष्ट्रिक इकाइयों के पेशेवर वर्गों के लोगों ने भी अपनी राष्ट्रिक इकाई के जनसाधारण के बीच दूसरी इकाई या दूसरे प्रांत के पेशेवर लोगों के खिलाफ घृणा के प्रचार द्वारा अपने निजी स्वार्थों को राष्ट्रीयता का वातावरण पहनाया। इस तरह ये पेशेवर और वाणिज्यिक एवं औद्योगिक तत्वों के वस्तुतः भारतीय जनता के व्यापक राष्ट्रीय ऐक्य के विघटन में लग हुए थे। यह एकता संपूर्ण भारतीय जन की स्वतन्त्रता और प्रगति के लिए और विभिन्न राष्ट्रिक इकाइयों के विशिष्ट राष्ट्रीय, स्वतन्त्र विकास के लिए अत्यंत आवश्यक थी। लेकिन अतर्प्रांतीय घट्टता की भावना से राष्ट्रीय ऐक्य और समुक्त राष्ट्रीय आंदोलन की इच्छा कमजोर हुई एवं प्रगतिशील सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यों के लिए विभिन्न सामाजिक दलों के बीच सहयोग की भावना मजबूत हो रही थी उसे नुकसान पहुंचा।

### भारतीय मुस्लिम, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक

भारतीय राष्ट्रवाद आंदोलन के ढांचे में ही नवजागृत राष्ट्रिक इकाइयों के अतिरिक्त मुसलमानों दलित जातियाँ, सिक्खा और अन्य अल्पसंख्यकों के भी आंदोलनो हुए। ऊपर जिस मद्दातिक मानदंड का निरूपण ही चुका है, उसके अनुसार ये सामाजिक दल राष्ट्रिक इकाइया नहीं थे, क्योंकि इनकी एक भाषा नहीं थी, इनका अपना निरिक्त भूभाग नहीं था और इनका अपना सम्मिलित आर्थिक जीवन भी नहीं था। ये वस्तुतः सामाजिक धार्मिक श्रेणियों के लोग थे।

इनमें पहला स्वान मुसलमानों और दलित जातियों का था और ये सारे देश में बिखरे हुए थे। वे उन प्रांतों की भाषा बोलते थे जहाँ वे रहते थे। वे विभिन्न प्रांतों, सामाजिक समुदायों के एकावित अंग थे, और उनके आर्थिक जीवन के नाश थे। मालाबार में मुसलमान (मापला) उही पाशक भी पहनते थे जा हिंदू ब्राह्मण और कुछ और प्रांतों में भी यही बात थी। प्रायः उनका खान पान भी प्रायः उही का था। बंगाली मुसलमान और मापला प्रायः चारल खान थे, जा



है वह खंडित नहीं होता। भारत पर अंग्रेजी शासन और भारतीय समाज के यह चरित्र स भारतीय जनता की जो राष्ट्रीय और निम्न तत्त्वा की जो वर्गीय एकता कायम हुई थी, उसे सांप्रदायिकता के विकास से नुकसान हुआ।

लेकिन यह मानना पड़ेगा कि मिथ, बलूचिस्तान और नाथ वेस्ट फ्रंटियर प्रांतों की जनता में जो मुख्यतः मुसलमान थे, बहुत हद तक विभिन्न राष्ट्र-इकाइयाँ के गुण मौजूद थे। उनके अपने-अपने नृनाभय धर्म थे, अपनी भाषा और संस्कृति थी अपना आर्थिक जीवन था। वे आंध्र प्रदेशवासियों, मलयालियों आदि की तरह राष्ट्रिक इकाइयों की श्रेणी में आते थे, जतन बस इतना था कि वे मुख्यतः एक ही धर्म के लोग थे। लेकिन उह राष्ट्रिक इकाई माना जाता है, तो धर्म साम्य की वजह से नहीं, वरन् इसलिए कि उनका अपना विशिष्ट नृनाभय धर्म था अपनी जलज भाषा और संस्कृति थी, और उनका अपना समुक्त आर्थिक जीवन था। वे किसी कल्पित भारतीय मुस्लिम राष्ट्र के अंग नहीं थे, वरन् विशिष्ट राष्ट्रिक इकाइयाँ के लोग थे, जिनमें अधिकांश एक ही धर्म के अनुयाई थे।

### मुसलमानों में सांप्रदायिकता के उद्भव के कारण

मुस्लिम जनता के राजनीतिक जागरण का गलत, सांप्रदायिक तरीका से इस्तेमाल किया जा सका, इनके कई कारण हैं। मुस्लिम संप्रदाय में पंजाब और गुजरात वर्गों का विकास हिंदू संप्रदाय की अपेक्षा घाट में हुआ। मुसलमानों ने देखा कि हिंदू उनसे पहले से ही सरकारी नौकरियाँ और व्यापार, उद्योग और वित्त में प्रमुख स्थानों पर आसीन हैं। नौकरियाँ और ओद्योगिक एवं वाणिज्यिक हिताओं का लडाईं में अपने हिंदू प्रतियोगियों के विरुद्ध उह अपने संप्रदाय के जनसाधारण की मदद को जरूरत थी। एक ही वर्ग के विभिन्न भागों के पारस्परिक विरोध का उन्होंने सांप्रदायिकता का नाम दिया और कहा कि यह बस हिंदू और मुस्लिम संप्रदायों का पारस्परिक विरोध है। उह राजनीतिक तौर पर जागृत मुस्लिम जनसाधारण का समर्थन भी मिला। चलमान स्थिति में उनकी व्यापक परिदृष्टि और प्रबल हुए राष्ट्रीय आंदोलन के फलस्वरूप उनमें राष्ट्रीय चेतना अधिकाधिक विकसित हो रही थी। मुस्लिम संप्रदाय के ऊँच तत्त्वा जमातिया, गुजराती और पंजाबी वर्गों ने मुस्लिम जनता की बढ़ती हुई राष्ट्रीय और वर्ग-चेतना का विरुद्ध सांप्रदायिक रूप देना चाहा, जिनमें वे अपने स्वार्थों की पूर्ति और विहित स्वार्थों के विरुद्ध सभी संप्रदायों के गरीब भागों के समुक्त जनसाधारण का समर्थन के लिए इन लोगों का समर्थन प्राप्त कर सके।

संप्रदायवाद के प्रचार में अंग्रेजों का भी हाथ था। उन्होंने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, सांप्रदायिक निराचन क्षत्रा और साम्राज्य हिंसा में राजा के पुनर्जाति आदि तरीकों से जनता में अंध-धर्म कायम रखने के लिए राजनीतिक समुक्त का समर्थन भी अनाद था। राजनीतिक समुक्त कायम और साम्राज्य के लिए जनता के समुक्त राष्ट्रीय आंदोलन का विनाश आरम्भ हुआ। उह आंध्र प्रदेश

कि वय ब्रिटिश राजनताआ न भी यह समझा कि ब्रिटिश प्रभुसत्ता को सबल बनाने के लिए ही सतुलन की नीति अपनाई गई थी। सप्रदायवाद मूलतः ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय सामाजिक अर्थतंत्र के विशिष्ट विकास, विभिन्न सप्रदायों के असम आर्थिक और सांस्कृतिक विकास और ब्रिटिश सरकार और इन सप्रदायों के निहित स्वार्थों की रणनीति का परिणाम था।

### मुसलमानों के राष्ट्रीय जागरण में विलय के कारण

चालीस करोड़ की जावादी में मुसलमानों की संख्या नौ करोड़ थी। यह हिंदुस्तान के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक थे। इनकी राजनीतिक प्रगति और इनके राजनीतिक जादालना का सर्वेक्षण आवश्यक है।

भारतीय मुसलमानों का पहला संगठित आंदोलन बहावी जादालन था। यह घम सुधार जादालन के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन बाद में इनमें राजनीति, सामाजिक और आर्थिक तत्व भी शामिल हुए। राजनीति वाले अध्याय में बतलाया जा चुका है कि यह ब्रिटिश विरोधी आंदोलन के रूप में शुरू हुआ और अंततः वे कुछ मुसलमानों को मिले, जिसके फलस्वरूप अमान विद्रोह हुआ। यद्यपि यह दबा दिया गया। यह आंदोलन 1857 के विद्रोह के कुछ दिनों बाद खतम हो गया।

1857 का परवर्ती काल भारतीय मुसलमानों के इतिहास में राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अंधकारमय युग था। चूंकि 1857 के विद्रोह में मुसलमानों ने हिंदुओं की अपेक्षा अधिक प्रमुख भूमिका ली थी इसलिए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय मुसलमानों का भरोसा नहीं किया और उनका अपना स्वतंत्र नीति अपनाई।<sup>10</sup> अपना प्रभुत्व कायम रखने के लिए ब्रिटिश ने भारत पर अपने संपूर्ण शासनकाल में राजनीतिक सतुलन की नीति अपनाई। विद्रोह के पहले भी, 1843 में लार्ड एलनबरो ने कहा था, 'मैं इन तथ्यों से नजरअंदाज नहीं कर सकता कि मुसलमान मूलतः हमारे शत्रु हैं और हम हिंदुओं को शासन रखने की नीति अपनानी चाहिए।'<sup>11</sup> विद्रोह के दबाए जाने के कुछ ही दिनों बाद लार्ड एल्फिंस्टन ने कहा, 'लागा में फूट पला और इस तरह का प्रशासन होगा, जो पुराने शासन लागा का शासन था और यहाँ हमारा भी शासन है।'<sup>12</sup> फोर्ब्स ने ऊँच जाहदा से मुसलमानों का अंतर्गत किया गया।<sup>13</sup> इसका उच्चतम श्रेणी में मुसलमानों की आर्थिक स्थिति पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा क्योंकि वे अपना अपना धर्म तो ही अपना पना बनाते रहे।

प्रशासनिक एवं अन्य प्रकार के कार्यों के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को शुरू कराया। इससे अरबों और फारसी भाषीयों का महत्व घटा और मुस्लिम बुद्धिजीवियों की आर्थिक स्थिति पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश सरकार की उद्देश्यपूर्ण विच्छेद करने वाले जादालन के कारण अंग्रेजी शिक्षा में विमुख रहे यद्यपि अंग्रेजी शिक्षा में सहायता में शामिल थे और उनका धर्म और अर्थतंत्र बुद्धिजीवियों का ही अंतर्गत किया था। मुसलमानों

के सांस्कृतिक पिछड़ेपन का कारण तो था ही इसके चलते वे 'प्रगामनि' अहंदा और कानून, डाक्टरी आदि पेशाओं से वंचित रह गए। नई शिक्षा के माध्यम से हिंदू बुद्धिजीवियों ने प्रजातंत्र और स्वतंत्रता के परिचयों विचारों को हृदयगम किया और वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेता और अगुजा हुए।

एक अन्य कारण से भी मुस्लिम संप्रदाय में राजनीतिक चेतना का विकास हिंदुओं के बाद हुआ। मुस्लिम संप्रदाय का आर्थिक राजनीतिक और साम्प्रतिक दृष्टि से प्रभावशाली बहुत बड़ा हिस्सा उत्तरी भारत में केंद्रित था, जो मुद्रत हिंदू आबादी वाले इलाकों से अपेक्षाकृत बाद में ब्रिटेन की राजनीतिक प्रभुता और साम्प्रतिक प्रभाव में आया। 'बंगाल, बंबई मद्रास, इन तीन बंदरगाह वाले इलाकों में, जहाँ से अंग्रेजी मस्त्रुति और व्यापार का सारे देश में प्रसार हुआ, बुरुआजी का पहला उदय हुआ। इसलिए ये अपेक्षाकृत पहले स्वाधीनता की स्थिति में पहुँच गए। इन इलाकों के लोग खासकर मध्यम वर्ग के लोग मुख्यतः हिंदू थे। बंगाल में मुसलमानों की संख्या काफी है लेकिन वे प्रायः शिक्षित हैं और इसलिए परिवर्तनों से अप्रभावित रहें।'<sup>14</sup>

उही प्रमुखतः हिंदू इलाकों में पहले नई अव्यवस्था की स्थापना हुई, जाया गमन के आधुनिक साधनों का प्रसार हुआ औद्योगिक नगर बने, नई शिक्षण संस्थाएँ बनीं। हिंदू प्रायः ब्रिटिश काल में भी व्यापार पर अधिकार जमाएँ हुए थे और राजस्व विभागों में जन्म हुए थे। उन्होंने बड़ी जल्दी अपने को नए शासन तंत्र की आवश्यकताओं के अनुकूल ढाल लिया और नई स्थिति का फायदा उठाया। इसलिए पहले उही ने बीच राष्ट्रवादी और प्रगतिशील बुद्धिजीवियों का विकास हुआ।

### सर सैयद अहमद और मुस्लिम नवजागरण

सर सैयद अहमद सा (1817-98) मुसलमानों के पहला नेता था जिन्होंने मुसलमानों का एकता का सूत्र में बाधन के प्रयास किए और उन्हें पारंपारिक शिक्षा और मस्त्रुति के प्रति आकृष्ट किया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार और भारतीय मुसलमानों के बीच अच्छे संबंधों की स्थापना की चप्पा ली। 1860 में प्रकाशित अपनी किताब 'द लायल महमूदम आफ इंडिया' में उन्होंने यह समझाने की कोशिश की कि मुसलमान मूलतः राजभक्त हैं ब्रिटिश सरकार का मुसलमानों के प्रति राजनीतिक दायित्व का भाव छोड़ देना चाहिए और मुसलमानों का प्रगमन में भाग लेना चाहिए तथा भारत में अंग्रेजों द्वारा नई नई प्रगतिशील शिक्षा का हस्तांतरण करना चाहिए।

सर सैयद ने भारतीय मुसलमानों के लिए पारंपारिक शिक्षा का मार्ग उभारा दिया। इस योजना में आधुनिक शिक्षा और इस्लाम की कलाओं को बौद्धिक आधार पर परिभाषित करने का काम किया गया। सरकार के समर्थन और पुश्तक मध्य वर्ग की आर्थिक सहायता से सर सैयद ने अपनी योजना में महत्वपूर्ण कार्य किया।





लाजपत राय और घोष वधुआ जैसे उग्रवादियों के अधिकाधिक प्रभाव में आया। पाल, घोष और अन्य नेताओं में राष्ट्रीयता की भावना का सनातन हिंदू विचारों का बाना पहनाया और यह बात मुस्लिम मध्य वर्गों की राजनीतिक चेतना को पमद नही आई। तबिन 1905 या उसके बाद के वर्षों में राष्ट्रीय आंदोलन में मुसलमानों के भाग नही लेने का और भी कारण था। कांग्रेस का असल हथियार था ब्रिटिश माल का बहिष्कार। बहिष्कार जादालन की सफलता में ब्रिटिश पूंजीवाद को काफी नुकसान और भारतीय उद्योगपतियों का फायदा हुआ, तबिन भारतीय उद्योगपतियों में अधिकांश हिंदू थे। '1905 में भारत का उद्योगीकरण अब अपेक्षणीय नही रह गया था। फिर भी अधिकांश मध्यवर्गीय मुसलमान या तो किराने थे, या विभिन्न पेशा में लग थे, वे मिल मालिक नही थे। विदेशी माल के बदले देशी माल के इस्तमाल से उन्हें कोई लाभ नही था। बहिष्कार के चलते तो जलजता उन चीजों की कीमत बढ़ गई। जिन्हें वे खरीदते थे।<sup>10</sup> मुसलमानों का खयाल था कि स्वदेशी के उपयोग द्वारा वे केवल हिंदू मिल मालिकों को ही लाभ पहुंचाएंगे। लाइ कंजन न बग विभाजन को प्रशासकीय सुविधा की दृष्टि से उचित माना। तबिन भारतीय राष्ट्रीय जादालन के उत्पन्न-वादी नेताओं के अनुसार यह कदम भारतीय राष्ट्रवाद का समझार करने के लिए उठाया गया था। उनका कहना था कि इस तरह बंगाल की राजनीतिक तौर पर जाग बढी हुई जावादी में फूट डाली जा रही थी। मुख्यतः मुस्लिम जावादी पाल पूर्वी बंगाल और आसाम को मुख्यतः हिंदू जावादी बान पश्चिम बंगाल से अलग कर सांप्रदायिक मतुलन या प्रतिताल का मिद्दान सामू किया जा रहा था। भारतीय राष्ट्रवादियों के अनुसार सांप्रदायिक जाधार पर बंगाल का बटवारा राजनीतिक तौर पर जरूरी हिंदुओं के विरुद्ध पिछड़े हुए मुस्लिम प्रदाय को मदद पहुंचाने के लिए किया जा रहा था। फिर भी उनीयवी सत्ता के अंत में शिक्षित मुस्लिम मध्य वर्ग में तजों से राजनीतिक चेतना का उभार हुआ रहा था। प्रशासनिक म उह आत्ममात करने में सरकारी जासमधना के कारण तबिन भी सरकार की जालाचना की भावना धीरे धीरे ही सही, घर करने लगी।

### मुस्लिम लोग और उसका सांप्रदायिक और उच्चवर्गीय स्वरूप

मुसलमानों के पहला राजनीतिक संगठन मुस्लिम लोग का स्थापना 1906 में हुई। इसमें मुख्यतः मुस्लिम प्रदाय के उच्चवर्गीय और पेशेवर वर्गों का भाग था। मुस्लिम लोग का स्थापना के ठीक पहले 1905-1906 में ही मुसलमानों का एक गिण्ट मंडल उन दिनों के वायसरॉय लॉर्ड मिंटो ने जा किया। इन गिण्ट मंडल में विवाचन की शक्ति भी स्वीकृत करने में गृधक प्रतिनिधित्व की मांग थी। वायसरॉय ने यह मांग मान ली और कहा

आपने मानने का तार इसमें निहित है कि स्तुतिनिधित्व का इच्छुक था  
या तबिन तबिन का उचित म नियारन का उनी साइनी साइनी

जाए, जिसके अनुसार निर्वाचित प्रतिनिधित्व लागू किया जाए या बढ़ाया जाए, तो मुस्लिम संप्रदाय का संप्रदाय की हैमियत से अलग प्रतिनिधित्व मित्रता चाहिए। आपका कहना है कि अभी निर्वाचक इकाइया जिस तरह की ह उनसे अधिकांश में मुस्लिम उम्मीदवारों के जीतने की कोई संभावना नहीं है। अगर संयोगवश कोई मुस्लिम उम्मीदवार जीत भी जाए तो ऐसा तभी संभव है जब वह उम्मीदवार अपने संप्रदाय के विरोधी बहुसंख्यक लोगों के विचारों के हित में अपने संप्रदायगत विचारों का परित्याग करे। ऐसी हालत में वह किसी भी तरह अपने संप्रदाय का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। आप ठीक ही कहते हैं कि आपकी बात का मूल्यांकन आपकी सांख्यिक शक्ति के आधार पर नहीं बरन आपके संप्रदाय के राजनीतिक महत्व और साम्राज्य के हित में की गई आपकी सेवाओं के आधार पर होना चाहिए। मैं पूरी तरह आपसे सहमत हूँ।<sup>1</sup>

लाड मॉलि का पत्राल या कि पृथक् निर्वाचन के दाव का लाड मिटो से मिल समझने के कारण ही मुसलमानों ने अपने सांप्रदायिक राजनीतिक संगठन की बात सोची और उसे रूप दिया। उसने लाड मिटो को लिखा, 'मैं मुसलमानों के सवाल पर आपसे द्वारा बहस नहीं करना चाहता। लेकिन मैं एक बार फिर यह नम्र निवेदन करूंगा कि उनके अतिरिक्त दावे के समझने में आपने जो पहली बकवृत्ता दी उसी से मुस्लिम परमाणु की यात्रा शुरू हुई।'<sup>2</sup>

मुस्लिम लीग की स्थापना भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक विकास में मील का पत्थर है। यह उनका पहला राजनीतिक संगठन था। लीग ने निम्नांकित लक्ष्य प्रस्तावित किए— '(1) भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा को भांगना करना (2) भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक एवं दूसरे प्रकार के अधिकारों की रक्षा करना और स्वतंत्र भाषा में सरकार के सामने उनकी आवश्यकताएं और जाता जाए प्रस्तुत करना, (3) जहां तक संभव हो, और ऊपर (1) और (2) में उल्लिखित उद्देश्यों का अनुमान पहचान कर, मुसलमानों और भारत के अन्य संप्रदायों में समझौते की भावना को प्रचार करना।'<sup>3</sup>

लीग ने 1908 में अजमेर अधिवेशन में जो मार्ग रखे गए उस दिशा में प्राथमिक एवं उच्च और मध्यमार्गीय चरित्र का परिचय मिलता है। अधिवेशन में पारित प्रस्तावों द्वारा लाहौर प्रांतीय और प्रीवी काउंसिल में मुस्लिम प्रतिनिधित्व और संसदे में प्रतिनिधित्व आरंभ की मांग की गई। इस तरह लीग ने मुस्लिम पंथ के वर्गों को नोकरियां बनने से बचाया और भांगना से अभिव्यक्ति दी।

**'संप्रदायों, वर्गों और हिता' की ब्रिटिश राजनीति**

1909 में लॉर्ड रिफॉर्म ने भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक् चुनाव क्षेत्रों और प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की और इस तरह भारतीय राजनीति में सांप्रदायिक विभाजन का प्रभाव हुआ। यह विभाजन बाद में गिरा, लेकिन जातिवाद और वर्ग के

अन्य अल्पमध्यक दला पर भी लागू हुआ। 1935 के गवर्नमेंट आफ इंडिया एक्ट में कई संप्रदायों के लिए अलग निर्वाचन का विधान था।

ब्रिटिश सरकार ने समीक्षकों, यूरोपियनों, व्यापारियों और उद्योगपतियों जैसे गैर सांप्रदायिक दलों के लिए भी अलग चुनाव क्षेत्रों का प्रबंध किया। साधारण चुनाव इकाइयों के साथ ही 'संप्रदायों, वर्गों और हिंदुओं' के लिए विभिन्न निर्वाचक गणों की भी व्यवस्था की गई।

भारतीय राष्ट्रवादियों ने अलग चुनाव क्षेत्रों और प्रतिनिधित्व की प्रथा को बड़ी आलोचना की। उनका कहना था इनके चलते राष्ट्रीय एकता का विकास अवरोध हो रहा था और सांप्रदायिक विभेद बढ़ रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि ब्रिटिश न भारतीय जनता की राष्ट्रीय एकता का समर्थन करने के लिए जान बूझकर यह राजनीतिक हथकण्डा इस्तेमाल किया था।

बड़े ब्रिटिश राजनेताओं का यह विचार था कि प्रतिद्वंद्वी नीति अर्थात् वर्गों या संप्रदायों के बीच परस्पर मतभेद बनाए रखने की नीति भारत पर अंग्रेजों का प्रभुत्व बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक थी। इस प्रश्न पर हमने पहले ही लार्ड एलेनबरो और माउंटबेट्टन एलफिंस्टन के विचार उद्धृत किए हैं। 1926 में लार्ड आर्चबिशप ने लिखा, 'भारतीय मामलों की जिस भी अच्छी जानकारी है उसमें यह मानना सही नहीं होगा कि, कुल मिलाकर भारत की अंग्रेज-शाही मुस्लिम संप्रदाय का पक्ष लेती है, कुछ तो गहरी महानुभावता के कारण, लेकिन मुख्यतः हिंदू राष्ट्रवाद के विरुद्ध प्रतिद्वंद्वी आवश्यकता के कारण।' <sup>4</sup>

हमें यह चुनने है कि 1906 में मुस्लिम लीग के विच्छेद मसल को दिए गए अपने जवाब में लार्ड मिंटो ने स्पष्ट कर दिया कि मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की स्वीकृति साम्राज्य के लिए उत्तर द्वारा की गई संधियों का पुरस्कार है। लॉर्ड मिंटो का उक्ति था 'यदि हमें अपने नापण में उतारने पर हमें नहीं बहना, भारतीय हिंदुओं के लिए और अधिक प्रतिनिधित्व में ब्रिटिश प्रशासन के समर्थन हानि के बदन और मजबूत होगा।' <sup>5</sup>

ब्रिटिश प्रभुत्व का अनुरोध 'संघर्ष भारत में अंग्रेजों का प्रमुख लक्ष्य था। उनके शासन के विभिन्न चरणों में इसी बात ने उनकी राजनीति का स्थापित किया। उपरोक्त ब्रिटिश विचारकों और राजनेताओं ने भी भारत में अंग्रेजों के शासन का ही सफाया दिया, न कि स्वायत्तता का। स्वतंत्र सरकार का निर्माण संप्रदायों के अछिष्ट प्रशासन प्रणाली के द्वारा किया गया है, साम्राज्यवाद के अंतर्गत स्वतंत्र शासन का समर्थन नहीं। साम्राज्यवाद ने अंग्रेजों को यह भी स्पष्ट कर दिया था कि 'साम्राज्यवाद का पुरस्कार ही उत्तरी है। 16 दिसंबर 1907 का मिंटो ने भारत का विचार, हमें जो उपरोक्त सरकार का विचार न बतलाया है। यह बड़े अंतर्गत और ही शासन में हमें जो कुछ करके यह जानना जाना जाना की महत्त्व है न अंग्रेजों और कुछ नहीं है।' <sup>6</sup>

स्पष्ट है, प्रतिद्वंद्वी नीति आवश्यकताओं और भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का

जाए, जिसके अनुसार निर्वाचित प्रतिनिधित्व लागू किया जाए या बढ़ाया जाए, तो मुस्लिम संप्रदाय का संप्रदाय की हैमियत से अलग प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। आपका कहना है कि अभी निर्वाचित इकाइया जिस तरह की हं उनसे अधिकांश मुस्लिम उम्मीदवारों की जीतन की कोई मभावना नहीं है। अगर मयोगवश कोई मुस्लिम उम्मीदवार जीत भी जाए तो ऐसा तभी संभव है जब वह उम्मीदवार अपने संप्रदाय के विरोधी बहुमूल्यक लोगों के विचारों के हित में अपने संप्रदायगत विचारों का परित्याग कर दे। ऐसी हालत में वह किसी भी तरह अपने संप्रदाय का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। आप ठीक ही कहते हैं कि आपकी बात का मूल्यांकन आपकी सांख्यिक शक्ति के आधार पर नहीं बरन आपका संप्रदाय के राजनीतिक महत्व और साम्राज्य के हित में की गई आपकी सेवाओं के आधार पर होना चाहिए। मैं पूरी तरह आपसे सहमत हूँ।<sup>1</sup>

लाड मॉलि का खयाल था कि पृथक निर्वाचन के दावे का लाड मिटो से मिल समर्थन के कारण ही मुसलमानों ने अपने सांप्रदायिक राजनीतिक संगठन की बात सोची और उसे रूप दिया। उसने लाड मिटो को लिखा, 'मैं मुसलमानों के खयाल पर आपसे द्वारा बहस नहीं करना चाहता। लेकिन मैं एक बार फिर यह नम्र निवेदन करूंगा कि उनके अतिरिक्त दावे के समर्थन में आपने जो पहली बकतूता दी, उसी से मुस्लिम खरगोश की यात्रा शुरू हुई।'<sup>2</sup>

मुस्लिम लीग की स्थापना भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक विकास में मील का पत्थर है। यह उनका पहला राजनीतिक संगठन था। लीग ने निम्नांकित लक्ष्य प्रस्तावित किए '(1) भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा की भावना भरना (2) भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक एवं दूसरे प्रकार के अधिकारों की रक्षा करना और मजबूत नापा में सरकार के सामने उनकी आवश्यकताएं और आकांक्षाएं प्रस्तुत करना, (3) जहां तक संभव हो, और ऊपर (1) और (2) में उल्लिखित उद्देश्यों को नुकसान पहुंचाए बगर, मुसलमानों और भारत के अन्य संप्रदायों में मजबूती की भावना का प्रचार करना।'<sup>3</sup>

लीग के 1908 के अमत्सर अधिवेशन में जो माने रखी गई उनसे इसके सांप्रदायिक एवं उच्च और मध्यवर्गीय चरित्र का परिचय मिलता है। अधिवेशन में पारित प्रस्तावों द्वारा लोकल बोर्डों और प्रीवी काउंसिल में मुस्लिम प्रतिनिधित्व और सेवाओं में प्रतिशत आरक्षण की मांग की गई। इस तरह लीग ने मुस्लिम पेशेवर वर्गों के नौकरियां मजबूती हितों और भावनाओं को अभिव्यक्त की।

### 'संप्रदायों, वर्गों और हितों' की ब्रिटिश रणनीति

1909 के मॉलि मिटो रिफॉर्म से ने भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक चुनाव क्षेत्रों और प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की और इस तरह भारतीय संविधान में सांप्रदायिक सिद्धांत का प्रवेश हुआ। यह सिद्धांत बाद में मिक्खा, दलित जातियां और देश के

अन्य अल्पमध्यक दला पर भी लागू हुआ। 1935 के गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट में कई संप्रदाया के लिए अलग निर्वाचन का विधान था।

ब्रिटिश सरकार ने समीक्षार्थी यूरॉपियन व्यापारियों और उद्योगपतियों के नाम पर संप्रदायिक दला के लिए भी अलग चुनाव क्षेत्रों का प्रबंध किया। साधारण चुनाव इकाइया के साथ ही 'संप्रदाया, वगैरह और हिता के लिए विशिष्ट निर्वाचक गणा की भी व्यवस्था की गई।

भारतीय राष्ट्रवादियों ने अलग चुनाव क्षेत्रों और प्रतिनिधित्व की प्रथा की कड़ी आलोचना की। उनका कहना था इनके चलते राष्ट्रीय एकता का विकास अव्यक्त हो रहा था और 'संप्रदायिक विभेद बढ़ रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि ब्रिटिश ने भारतीय जनता की राष्ट्रीय एकता को कमजोर करने के लिए जान बूझकर यह राजनीतिक हथकण्डा इस्तेमाल किया था।

कई ब्रिटिश राजनेताओं का यह विश्वास था कि प्रतिनिधित्व की नीति अर्थात् वर्गों या संप्रदाया के बीच परस्पर समुलन बनाए रखने की नीति भारत पर अंग्रेजों का प्रभुत्व बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक थी। इस प्रश्न पर हमने पहले ही लार्ड एलेनबरो और माउंटबेट्टन एट एल्फिंस्टन के विचार उद्धृत किए हैं। 1926 में लार्ड जान्स्विकर ने लिखा, 'भारतीय मामला की जिस भाँति जल्दी जानकारी है उस यह मानने में दिक्कत नहीं होगी कि, कुल मिलाकर भारत की अफसर-शाही मुस्लिम संप्रदाय का पक्ष लेती है, कुछ तो गहरी गहानुभूति के कारण, लेकिन मुख्यतः हिंदू राष्ट्रवाद के विरुद्ध प्रतिनिधित्व की आवश्यकता के कारण।'

हम देख चुके हैं कि 1906 में मुस्लिम लीग के गिष्ट मंडल का दिए गए अपने उदाहरण में लार्ड मिंटो ने स्पष्ट कर दिया कि मुसलमानों के लिए संप्रदायिक प्रतिनिधित्व की स्वीकृति साम्राज्य के लिए उनका द्वारा की गई सजाया का पुरस्कार है। लजिस्लेटिव काउंसिल के सामने अपने भाषण में उसने यह भी कहा, 'भारतीय हिन्दो एक संप्रदाया के लिए और अंग्रेज प्रतिनिधित्व स ब्रिटिश प्रशासन के कमजोर होने के बल और मजबूत होगा।'

ब्रिटिश प्रभुत्व का अनुरक्षण गवापन भारत में अंग्रेजों का प्रमुख उद्देश्य था। उनके पास के विभिन्न कारण में इसी बात में उनकी राजनीति का स्पष्टीकरण दिया। उदारवादी ब्रिटिश विचारकों और राजनेताओं ने भी भारत में अंग्रेजों के शासन का ही उपाय देखा, न कि स्वायत्तता का। स्वयं सरकार की नीति अंग्रेजों के अच्छे प्रशासन प्रणाली पर मरती है। अंग्रेजों के लिए यह सिद्ध है, साम्राज्यवाद के अभाव में स्वयं शासन का मसाला नहीं। साम्राज्यवाद अंग्रेजों के लिए ही स्वयं सरकार की सुरक्षा का उपाय है। 16 दिसंबर 1967 का मिंटो ने मार्किट का विचार, हमें तीन प्रकार के विचारों के बड़े अंग्रेजों की नहीं बड़े मरती और इन विचारों हमें जो कुछ करेंगे वह अंग्रेजों का शासन को मजबूत करने के अभाव और कुछ नहीं है।'

स्पष्ट है, प्रतिनिधित्व की नीति अंग्रेजों के लिए भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का

बनाए रखने के लिए अपनाई गई। 1857 के विद्रोह के बाद रजवाडे और जमींदारों ने प्रतिभूल का काम किया। लाड लिटन भारतीय जाभिजात्य के दल पर ब्रिटिश शासन चलाना चाहते थे। लाड डफरिन ने जन विद्रोह की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए उदारवादी बुद्धिजीवियों का इस्तेमाल किया और साविधानिक आदोलन के मच के रूप में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना में उह मदद दी। लेकिन कुछ ही दिनों में यह एहसास होने लगा कि कांग्रेस विद्रोहात्मक रूप अपनाते लगी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के उग्रवादी राष्ट्रवादियों में अधिकांश हिंदू पेशेवर और मध्य वर्गों के लोग थे और उनके विरुद्ध प्रतिभूल के रूप में लाड मिंटो ने बढ़ते हुए मुस्लिम पेशेवर वर्गों का इस्तेमाल किया।

### इस नीति की आलोचना

वाद में दलित जातियों, सिक्खा, अल्पसंख्यक दलों में राजनीतिक चेतना का उदय और विकास हुआ, और सुधार की जो योजनाएँ तैयार हुईं उनमें विशेष निर्वाचक समुदाय एवं विशेष प्रतिनिधित्व और अर्थ अधिकार दिए गए। इस तरह नवजागत राजनीतिक इकाइयों को खुश किया और बढ़त हुए राजनीतिक आदोलन का प्रतिभूल तैयार हुआ। के० बी० कृष्ण ने इस तथ्य की चर्चा की है

अंग्रेजों ने कई कृतिम वर्गों की रचना की। जैसे ही इन वर्गों की मण्टि हुई, उनमें मधुप शुरू हुआ। अंग्रेजों ने इन मधुपों को प्रेरणा प्रदान की और उह कानून की मदद से तीव्र किया। वकील, स्कूलों के अध्यापक, विद्यार्थियों और अर्थ मध्य वर्गीय लोगों के अधिकारों और मागों के विराध में रजवाडे, इलाकेदारों, उद्योगपतियों और मुसलमानों को खडा किया गया। लाड लिटन और कजन न वाबुजा की मख्या कांग्रेस 'और उनकी मागों' के उचित प्रतिभूल के रूप में लब्धप्रतिष्ठ व्यक्तियों की परिपद की चर्चा की। अपन पत्रों और गश्ती चिट्ठियों में मिंटो और मालि दोनों के प्रतिभूल के विचार का खुलकर उपयोग किया। आज भारत का नया मविधान पूरी तरह से प्रतिभूलित नीतियों के पूण पारस्परिक सतुलन पर आधारित है।<sup>7</sup>

इसी लेखक ने यह भी लिखा है

भारतीय विद्रोह न नए प्रकार के साम्राज्यवाद की नींव डाली। इससे भरा तात्पर्य यह है कि विद्रोह के बाद के काल की नीति उदारवादी और साम्राज्यवादी नीतियों का सम्मिश्रण है। इस नए साम्राज्यवाद का एक पहलू है प्रतिभूल की नीति। यह उदारवादी भी है और साम्राज्यवादी भी उदारवादी इस अर्थ में कि यह नीति जैसे जस वर्गों का उदय हुआ, वैसे वैसे उह मायता देती और उनके दावों स्वीकार करती, साम्राज्यवादी इस अर्थ में कि जो दावों स्वीकार किए जाते थे वे सदा साम्राज्यवादी हितों द्वारा सीमित और परिधिबद्ध रहे और इसमें सरकार ने हरदम विभिन्न वर्गों और स्वार्थों की पारस्परिक होड का इस्तेमान किया।<sup>8</sup>

इस लेखक ने आगे यह भी कहा है कि 'इस नीति का मूल अचारिक आधार है 'मप्रदाया, वर्गों और स्वार्थों का सिद्धांत।' इस सिद्धांत का प्रजातन्त्र से कभी कोई मराकार नहीं रहा है। यह एवमात्र स्वार्थों वर्गों, कुछ धार्मिक मप्रदाया से सन्तुलन से संबंधित है क्योंकि इनमें से प्रत्येक ने सत्ता और शक्ति के लिए शार करना शुरू किया।<sup>9</sup> आगे यह भी कहा गया है

- 1 भारत सरकार द्वारा अपनाया गया वर्गीकरण अवनानिक है मिल जुले विभाजना से भरा हुआ, वास्तविक राष्ट्रिक इकाइया, या एतिहासिक मप्रदाया की उपक्षा पर आधारित
- 2 इस सिद्धांत ने भारतीय नरम दल की राजनीति को जन्म दिया।
- 3 इस धार्मिक आधार पर कृत्रिम साहचर्य और सगठन स्वार्थों और वर्गों की फसल उग आई। मुसलमानों के बाद, सिखों, भारतीय ईसाइ, एंगो इंडियन अछूत और अन्य लोग सामने आए

सांप्रदायिक निर्वाचक इकाइया की स्थापना का अमल उद्देश्य था या प्रतिनिधित्व के लिए जमीन व्यापार और वाणिज्य पर आधारित सीमित चुनाव क्षेत्रों की स्थापना के बाद, मुसलिम पेशेवर वर्ग का हिंदू पेशेवर वर्ग से प्रतिस्पर्धा के रूप में तयार करना। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का मूल इंगी में निहित है।<sup>30</sup>

लेखक ने भारत में अंग्रेजों की आधारभूत नीति का साम्राज्यिक सत्ता का मानक बनाना बल प्रयोग, प्रतिस्पर्धा, रियायत आदि का 'मम्मिषण' माना है।<sup>31</sup>

जो छूट और रियायत दी गई प्रायः उनका भी उद्देश्य था भारत में ब्रिटिश सत्ता का बनाए रखना। 'जो रियायतें दी गई हैं या भविष्य में दी जाएंगी, अतिनी ही उदार क्या न हों। भारत पर जिन अधिपत्य का छोड़ने का हमारा जरा भी इरादा नहीं है और इसकी भी कोई उभापना नहीं दी जा सकती है जो जान वाली पीढ़ियों का एका काई इरादा होगा।<sup>32</sup> जिन्हीं की दंग की जनता के विभिन्न, विविष्ट सामाजिक दलों को जो रियायतों का लिए गए मुद्दों की प्रवृत्ति हानी है वहां ही जनता का विभक्त करना और अनुसूचित जातों के विचारों का अखण्ड करना। मार्च मिटा रिफॉर्म्स, माटंगु चम्पपाइ रिफॉर्म, 1935 के मसनमट आफ इंडिया ऐक्ट द्वारा लाया गया अधिधान बिजन दंग में अधिराष्ट्रिक जल्पसभ्यका दल और हिता का रिफॉर्म प्रतिनिधित्व प्रदान किया, इन उपायों इनमें से कई दंगों के बीच विरोध और फूट का पूजन किया, वास्तव में इनके लिए भारतीय समाज के निम्न वर्गों के राजनीतिक जागरण के कारण राष्ट्रिय जागतिक प्रतिनिधित्व मजबूत हुआ जा रहा था।

1912 के बाद मुसलमानों में बढ़ता हुआ लटारूप

भारतीय मुसलमानों में राजनीतिक उठाव जागार बढ़ती गई। 1912 के बाद इनमें तीव्र उठाव रूप में आया। प्रथम विश्व युद्ध के टाठपट्टे के

मुस्लिम मध्य वग राजनीतिक दृष्टि से अधिकाधिक परिपक्व हुआ। जनवरी पाशा के राष्ट्रीय प्रजातान्त्रिक यग टक जादोलन के कारण भी भारतीय मुसलमान भारत के लिए स्वशासन का कार्यक्रम लेकर आगे उढ़े। 1913 में लीग ने यह कार्यक्रम अपनाया। मुसलमान अब अधिकाधिक राष्ट्रीय आदोलन की परिधि में आन लगे थे।

प्रथम विश्व युद्ध के पहले के वर्षों में मुसलमानों का नया मध्य वग, शिक्षित और बाचाल साम्राज्यी व्यवस्था में अपनी अधीनस्थ स्थिति से बाहर निकल आया और अपना अमतीप अभिव्यक्त करन लगा।<sup>33</sup>

मुसलमानों की राजनीतिक चेतना के नए और उच्चतर चरण में डा० असारी, अबुल कलाम आजाद मौलाना मुहम्मद अली और हकीम अजमल खा उनके प्रमुख नेता थे। 1912 में आजाद ने 'अल हिलाल' का प्रकाशन शुरू किया और मुहम्मद अली ने अंग्रेजी पत्र 'कामरेड' और उदू पत्र 'हमदद' की स्थापना की और उन्हें संपादित किया। इन पत्रों ने मुसलमानों की राजनीतिक चेतना को गहरा किया और मुसलमानों में राष्ट्रीय भावना का प्रसार किया। 1913 में लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश राज के मातहत भारत के उपयुक्त स्वशासन की प्राप्ति को अपना उद्देश्य बनाया।

1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत के बाद, ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों को उन राजनीतिक नेताओं और दलों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाही की जिनके कार्यों को उन्होंने युद्ध संचालन की सफलता के लिए घातक माना। उसने 'अल हिलाल' 'कामरेड' और 'हमदद' का प्रकाशन बंद कर दिया, और मुहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना आजाद और हजरत माहानी जैसे मुस्लिम नेताओं को नजरबंद कर दिया।

लीग और कांग्रेस दोनों के अपने अलग अलग अधिवेशन लखनऊ में हुए। लीग के अधिवेशन में कांग्रेस के भी प्रमुख नेता उपस्थित थे, जैसे पंडित मालवीय, गांधी और अय लीग। हिज हाइनेस जागा खा ने लीग के नए राष्ट्रीय दृष्टिकोण का अनुमोदन नहीं किया और कुछ ही दिनों बाद उन्होंने लीग के स्वाई सभापतित्व से त्याग पत्र दे दिया। यह इस बात का परिचायक था कि लीग राजनीतिक तौर पर उग्रवादी हो रहा था।

अठारहवें अध्याय में हमने लीग और कांग्रेस के बीच 1916 में लखनऊ पक्क की चर्चा की है। दोनों संगठनों में पारस्परिक सहयोग का यह पहला दृष्टांत था। जिन क्षेत्रों में मुसलमान अल्पसंख्यक थे उन क्षेत्रों के लिए इस पक्क में उनके लिए पृथक निर्वाचक इकाइयों और अधिक प्रतिनिधित्व की बात थी और अंग्रेजी सरकार से मांग की गई कि योजना में निहित सुधारों को लागू कर स्वशासन की दिशा में निश्चित कदम उठाए जाएं और यह भी कि 'साम्राज्य के पुनर्गठन में, भारत अधीनस्थता की स्थिति से हटाकर आत्मशासी क्षेत्रों के साथ बराबर का साझेदार की हैमियत में लाया जाए।



मुस्लिम मध्य वग लीग का प्रमुख सामाजिक आधार था और यह लगातार राष्ट्रीय धारणाओं और उद्देश्यों की ओर रुख रहा था, यद्यपि अब भी सांप्रदायिकता ही इसका आधार थी। 1918 के दिल्ली अधिवेशन में लीग ने मांग की कि भारत में स्वतंत्रता और जात्मनिर्णय का मिश्रित लागू किया जाए।

### खिलाफत और हिजरत आंदोलन

राजनीति वाले अध्याय में खिलाफत आंदोलन के उदय और इतिहास की चर्चा की जा चुकी है। गांधी और अन्य कांग्रेसी नेताओं के सक्रिय सहयोग से मुस्लिम नेताओं ने खिलाफत काफ़ेम की स्थापना की। काफ़ेम ने खिलाफत पक्षों को कांग्रेस के विरुद्ध संघर्ष का फसला लिया और ब्रिटिश माल के बहिष्कार और सरकार के साथ असहयोग का कार्यक्रम अपनाया।

तुर्की का पवित्र भूमि जाटमन, धर्म और स्मृति लौटा दिया जाए, खिलाफत काफ़ेम और लीग की इस मांग का गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बड़े उत्साह के साथ समर्थन दिया।

1919 में उल्मा अर्थात् मुसलमान धर्माधिकारियों ने अपना संगठन जमायत उल उल्मा बनाया। इसने खिलाफत काफ़ेम की मांग का समर्थन किया। इसने असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए भारतीय मुसलमानों का जादूना किया। असहयोग आंदोलन भारत का पहला राष्ट्रीय जन आंदोलन था, जिस का प्रारंभ ने खिलाफत काफ़ेम की मदद से शुरू किया था। संग्रहीत अधि द्वारा लिए गए कांग्रेस का मार्जिन, पत्रों और दल के अन्य भागों में की गई सरकार की दमनात्मक कार्रवाई का निराकरण, स्वराज की स्थापना आदि आह्वानों का प्रसारण के उद्देश्य थे।

असहयोग आंदोलन के इतिहास के विभिन्न चरणों की चर्चा अठारहवें अध्याय में की जा चुकी है। अपने नेताओं के जादूना पर मुसलमानों ने बड़ी तादाद में इस आंदोलन में भाग लिया। इस साधारण आंदोलन का एक विशेष पक्ष था हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अभूतपूर्व भ्रातृत्व।<sup>24</sup> इस आंदोलन के क्रम में गृह-मंद अला, गोपनीय अला और कई अन्य मुसलमान नेता गिरफ्तार हुए। इन संगठनों पर सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के उल्लंघन के लिए उनका मुसलमान राज्य गठन जल गए। इस आंदोलन के हर चरण में मुसलमानों ने धुनार भाग लिया।

विधि और नायक बस्ट फटियर प्रताप के कुछ मुसलमानों ने हिजरत का प्रस्ताव का संगठन किया। उनकी विधि के प्रति विरोध प्रस्ताव के रूप में इलाहाबाद छात्रों के अध्यायिकाओं में का बचन का पत्रिका दिया। लेकिन अला और सरकार ने उन्हें दाना अनुमति नहीं दी। आंदोलन कमजोर रहा। 1921 में भारत विद्रोह शुरू हुआ। सरकार का यथार्थ था कि यह विद्रोह का प्रसार काय हो परो। परिणाम का बर्नामि इस बातों में आह्वानों को गठन। नायक का विद्रोह का प्रस्ताव का जादूना किया था।

मोपला विद्रोह से यह देखने में आता है कि कैसे किसानों और जमींदारों का आर्थिक विरोध सांप्रदायिक रूप ले लेता है, अगर इन वर्गों के लोग विभिन्न धर्मों के अनुयाई हैं। 'मोपला विद्रोह मुख्यतः हिंदू महाजना (सूदखोरा) और जमींदारों और सरकार के विरुद्ध मोपला किसानों का आंदोलन था। मद्रास के प्रचार विभाग द्वारा प्रसारित विज्ञप्ति में इस समस्या का यह विश्लेषण किया गया, 'मोपला लोगों को विद्रोह पर उतारू करने वाले दो कारण हैं। इनमें धार्मिक अभिप्रेरणा अधिक शक्तिशाली है, लेकिन मोपला लोगों के बंठे जीवन और नम्बूदिरी जमींदारों के राजसी भवना के बीच आर्थिक विरोध भी कम महत्वपूर्ण नहीं है' <sup>135</sup>

1921 में जहमदाबाद में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ। इसके सभापति पद से अपने अध्यक्षीय भाषण में मोलाना हजरत मोहानी ने कहा 'मुसलमानों का समझना चाहिए कि भारतीय गणतंत्र की स्थापना से उन्हें दुहरा लाभ होगा, प्रथमतः, प्रजातान्त्रिक गणतंत्र में नागरिकों की हैसियत से उन्हें औरों की ही तरह समान अधिकार और फायदे मिलेंगे, और फिर, अंग्रेजों के प्रभाव क्षेत्रों का मकुचित कर वे मुस्लिम सत्ता को राहत की सांस लेने का मौका देंगे, जो रचनात्मक कार्यों के विकास के लिए आवश्यक है।' <sup>136</sup>

उसी वक्त जहमदाबाद में ही हुए कांग्रेस के अधिवेशन में मोहानी ने यह प्रस्ताव भी रखा कि स्वशासन के बदले भारतीय गणतंत्र की स्थापना कांग्रेस का लक्ष्य हो। गांधी का इस विचार से घोर मतभेद था और उन्होंने (मानसिक) हल्केपन' के लिए मोहानी की भत्सना भी की। मोहानी का प्रस्ताव कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। चोरी चोरा कांड के बाद गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की कार्यकारिणी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया।

भारतीय मुसलमानों की राजनीतिक चेतना के विकास की दृष्टि से असहयोग आंदोलन का बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। इससे यह तथ्य प्रकाश में आया कि जो राजनीतिक चेतना पहले उच्च एवं मध्य वर्गीय मुसलमानों तक ही सीमित थी वह अब मुस्लिम संप्रदाय के निम्नवर्गीय जनसाधारण के भी कुछ भागों में प्रविष्ट हो चुकी थी। यह सही है कि खिलाफत धार्मिक प्रश्न था, लेकिन यह स्वराज्य के संघर्ष से जुड़ा हुआ था और इसमें मुसलमानों की राष्ट्रीय चेतना को आगे बढ़ाया। इस मौके पर पहली बार बहुत सारे हिंदुओं और मुसलमानों ने भारत के लिए स्वशासन जैसे राष्ट्रीय लक्ष्य के लिए परस्पर सहयोग किया। कांग्रेस और मुसलमानों के राजनीतिक मगठनों के संयुक्त नेतृत्व द्वारा निर्णित प्रत्यक्ष कार्यवाही के विभिन्न मुद्दों पर उन्होंने साथ काम किया। जब उनके बीच का संघर्ष इस बात पर मुनहसिर नहीं था कि जनसेवाओं में पदों और विधायिका सभाओं में स्थानों का विभाजन कैसे हो।

गांधी और कांग्रेस की कार्यकारिणी द्वारा आंदोलन के वापस ले लिए जान से लोगों में नराशय की भावना का जन्म हुआ। मुलतान और खलीफा के रूप में छोटे मुहम्मद के पदच्युत किए जाने और उसकी जगह पर केवल तुर्कों के लोग

द्वारा अन्न जल मजदूर के खलीफा बनाए जाने से भारतीय मुसलमानों में निराशा की यह भावना और बढ़ी। इतिहास ने भारतीय मुसलमानों के साथ निम्न मजाक किया। उन्होंने जो मघर्ष शुरू किया था उसका एक प्रमुख लक्ष्य था कि उनके पवित्र तीर्थ स्थान तुर्कों के मुसलमानों को लौटा दिए जाए, क्योंकि वह सारी दुनिया के मुसलमानों का धर्म प्रमुख था, लेकिन उधर तुर्कों के लोगों ने स्वयं अपने राज्य को धर्म निर्वेध बना दिया और धर्म और राजनीति को पृथक् कर दिया।

असहयोग आंदोलन के उत्तम होने पर हिंदू मुस्लिम एकता भी जा इस काल में काफी बढ़ी थी उत्तम होने लगी। राष्ट्रीय एकता के बदले सांप्रदायिक गद्दता और विभाजन की भावना बढ़ने लगी। असहयोग आंदोलन के बाद वाले युग में कई सांप्रदायिक दंगे हुए जिनमें कोहाट का दंगा सबसे अधिक गंभीर था।

1922 के बाद जो राजनीतिक उत्साह भंग हुआ, उसके बारे में जवाहरलाल ने लिखा है, 'यह मभव है कि इस महान आंदोलन का सहसा रोक देने से (नेहरू असहयोग आंदोलन को वापस ले लेने के फैसले की चर्चा कर रहे हैं) दंगों में बड़े दुःख स्थिति आ गई। राजनीतिक मघर्ष में अनियमित और निरन्तर हिंसा को प्रवृत्ति तो उत्तम हो गई लेकिन इस अवस्था, दमित हिंसा भावना का कोई राह तो मिलनी थी, और जान वाले वर्षों में शायद इसी के कारण सांप्रदायिक अशांति बढ़ी।' 27

शायद यह सही नहीं कि 'दमित हिंसा भावना' के कारण 'सांप्रदायिक अशांति' बढ़ी। सांप्रदायिकता के प्रभाव का शायद यह दुहरा कारण था कि जबल तो राजनीतिक चेतना की जड़ें ठीक तरह से नहीं जमी थीं। धार्मिक विच्छेद हुए मुसलमानों में, और दोषम कि असहयोग आंदोलन के बाद राष्ट्रीय नेताओं ने बाद समुचित कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं किया। गांधी ने दंगों का गैर राजनीतिक, राजनैतिक कार्यक्रम तो दिया, जिसमें मदिरा निषेध, पूत कातना और अल्पसख्यता निवारण आदि मुद्दे थे, लेकिन मुस्लिम जन माधारण में यह कार्यक्रम बहुत लोकप्रिय नहीं हो सके थे। राष्ट्रीय आंदोलन का नवोत्पन्न कार्यक्रम न थाया म था और भारतीय जनता के लिए उचित राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक कार्यक्रम बना सके म यह असफल रही। कांग्रेस की इस असफलता के कारण भी सांप्रदायिक प्रचार बहुत हद तक बरकरार हुआ।

एक अन्य कारण से भी मुसलमान राष्ट्रीयता की भावना से अधिकाधिक विलग हुए जा और सांप्रदायिक दृष्टिकोण अपनाते गए। इतिहास ने सांप्रदायिक धर्म निर्वेध राष्ट्रीय समस्या थी और भाग्यीय जनता का राष्ट्रीय मुक्ति दायका लक्ष्य था। फिर भी, गांधी जंग दंगों प्रमुख नेताओं ने कभी-कभी राष्ट्रीय आंदोलन में हिंदू धार्मिक भावनाओं का जालन की धृष्टता की। उदाहरणार्थ, गांधी ने स्वराज का ध्याना रामराज्य के रूप में की, लेकिन यह इतिहासिक सृष्टि मुसलमानों का अनाहिता नहीं कर उठी। राजनीतिक समाधान के धर्म निर्वेध आधारित पर हिंदू धार्मिक भावनाओं के कारणों से मुसलमानों का उत्पन्न हुआ

कि कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय आंदोलन हिंदू आंदोलन था। जार० पी० दत्त ने कहा है, 'राष्ट्रीय आंदोलन का राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रम, धर्म की भावना के परे, भारतीय जनता को एकजुट कर सकता है और उसे ऐसा करना चाहिए। इस तरह सशक्त, धर्म निरपेक्ष, आधुनिक, एकतावादी, प्रगतिवादी आंदोलन ही इस चरण में सांप्रदायिक उद्वेग के विरुद्ध सबसे बड़ी ताकत सिद्ध हो सकता है।'<sup>38</sup>

### सांप्रदायिकता के मूल तत्व

सांप्रदायिकता विभिन्न धर्मों के निहित स्वार्थों के पारस्परिक संघर्ष की ही छत्र अन्वित थी। इन निहित स्वार्थों ने अपने इस संघर्ष को सांप्रदायिक जामा पहना रखा था। विभिन्न संप्रदायों के पेशेवर वर्गों की पदा और स्थानों की लड़ाई भी इसी छत्र रूप में लड़ी जाती रही। सांप्रदायिकता के विरुद्ध संघर्ष का एक सर्वाधिक कारगर तरीका यह था कि विभिन्न संप्रदायों के निम्न वर्गों को उनके सम्मिलित आर्थिक और अन्य हितों की बड़ाई में एकतावादी किया जाए।

हिंदू और मुस्लिम साधारण लोगों के सम्मिलित आर्थिक और राजनीतिक स्वार्थ थे। विधायिका परिषद (लेजिस्लेटिव काउंसिल) में स्थानों या जन सेवाओं में पदों के विभाजन से उनका कोई हित साधन संभव नहीं था। उनके सम्मिलित राजनीतिक और आर्थिक स्वार्थों पर आधारित कार्यक्रम ही उन्हें उत्साहित और एकतावादी कर सकता था। सम्मिलित स्वार्थों की प्राप्ति से संबंधित आंदोलनों में उन्होंने जितना ही भाग लिया, उतना ही उसके लिए सांप्रदायिकता का मूल्य घटा और राष्ट्रीय एकता बनी।

सांप्रदायिक प्रश्न का धार्मिक समस्याओं से कोई संबंध नहीं, उसका संबंध है लाभ और लूट एवं प्रतिशत से अनुग्रह एवं पदों से। सांप्रदायिक प्रश्न साधारणतः विभिन्न मतों के पेशेवर वर्गों के विभिन्न तंत्रों की आपसी लड़ाई का प्रश्न है।

इंडियन स्ट्यूडेंट्स एसोसिएशन को बंबई की सरकार द्वारा दिए गए स्मारक पत्र में इस विषय पर कहा गया है, 'मुसलमानों में शिक्षा का प्रसार भी इसका कारण है मुसलमानों एवं अन्य पिछड़े हुए वर्गों में राजनीतिक चेतना के विकास से उनमें अपनी कमजोरी का भी एहसास हुआ अन्य बातों के साथ ही इस कारण ने भी कि आगे बढ़े हुए वर्गों को जन सेवाओं में काफी अधिक स्थान प्राप्त था, और इसके साथ ही उन्हें ओहदा और प्रभाव भी प्राप्त था।' यहाँ बंबई का सरकार ने यह बात मानी है कि सांप्रदायिक प्रश्न पिछड़े और आगे बढ़े हुए वर्गों में जोहदा और पारिधमिक का झगडा था।<sup>39</sup>

कुछ दूसरे प्रकार के भी संघर्ष थे जिन्होंने मूलतः आर्थिक होने पर भी सांप्रदायिक रूप लिया। बंगाल जैसे प्रांतों में ऐतिहासिक कारणों से, किसान प्रधानतः मुसलमानों और जमींदार मुसलमानों हिंदू। किसानों के सांस्कृतिक पिछड़ेपन व



कि कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय आंदोलन हिंदू आंदोलन था। आर० पी० दत्त ने कहा है, 'राष्ट्रीय आंदोलन का राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रम, धर्म की भावना के परे, भारतीय जनता को एकजुट कर सकता है और उसे ऐसा करना चाहिए। इस तरह सशक्त, धर्म निरपेक्ष, आधुनिक, एकतावादी, प्रजातान्त्रिक आंदोलन ही इस चरण में सांप्रदायिक उद्वेग के विरुद्ध सबसे बड़ी ताकत सिद्ध हो सकता है।'<sup>38</sup>

### सांप्रदायिकता के मूल तत्व

सांप्रदायिकता विभिन्न वर्गों के निहित स्वार्थों के पारस्परिक संघर्ष की ही छत्र अन्वित थी। इन निहित स्वार्थों ने अपने इस संघर्ष को सांप्रदायिक जामा पहना रखा था। विभिन्न संप्रदायों के पेशेवर वर्गों की पदा और स्थानों की लड़ाई भी इसी छत्र रूप में लड़ी जाती रही। सांप्रदायिकता के विरुद्ध संघर्ष का एक सर्वाधिक कारगर तरीका यह था कि विभिन्न संप्रदायों के निम्न वर्गों को उनके सम्मिलित आर्थिक और अन्य हितों की बड़ाई में एकतावादी किया जाए।

हिंदू और मुस्लिम साधारण लोगों के सम्मिलित आर्थिक और राजनीतिक स्वार्थ थे। विधायिका परिषद (लेजिस्लेटिव काउंसिल) में स्थानों या जन सेवाओं में पदों के विभाजन से उनका कोई हित साधन संभव नहीं था। उनके सम्मिलित राजनीतिक और आर्थिक स्वार्थों पर आधारित कार्यक्रम ही उन्हें उत्साहित और एकतावादी कर सकता था। सम्मिलित स्वार्थों की प्राप्ति से संबंधित आंदोलनों में उन्होंने जितना ही भाग लिया उतना ही उसके लिए सांप्रदायिकता का मूल्य घटा और राष्ट्रीय एकता बनी।

सांप्रदायिक प्रश्न का धार्मिक समस्याओं से कोई संबंध नहीं उसका संबंध है लाभ और लूट एवं प्रतिशत से अनुग्रह एवं पदों से। सांप्रदायिक प्रश्न साधारणतः विभिन्न वर्गों के पेशेवर वर्गों के विभिन्न तत्वों की आपसी लड़ाई का प्रश्न है।

इंडियन स्टैंडर्डिंग कमीशन को बंबई की सरकार द्वारा दिए गए स्मार्क पर म इस विषय पर कहा गया है, 'मुसलमानों में शिक्षा का प्रसार भी इसका कारण है मुसलमानों एवं अन्य पिछड़े हुए वर्गों में राजनीतिक चेतना का विकास से उनमें अपनी कमजारी का भी एहसास हुआ, अन्य वर्गों के साथ ही इस कारण से भी कि आगे बढ़े हुए वर्गों को जन सेवाओं में काफी अधिक स्थान प्राप्त था, और इसके साथ ही उन्हें ओहदा और प्रभाव भी प्राप्त था।' यहाँ बंबई की सरकार ने यह बात मानी है कि सांप्रदायिक प्रश्न पिछड़े और आगे बढ़े हुए वर्गों में ओहदा और पारिश्रमिक का बगड़ा था।<sup>39</sup>

कुछ दूसरे प्रकार के भी संघर्ष थे जिन्होंने मूलतः आर्थिक हानि पर भी सांप्रदायिक रूप लिया। बंगाल जमीनदातों में ऐतिहासिक कारणों से, किसान प्रधानतः मुसलमान थे और जमींदार मुख्यतः हिंदू। किसानों के सांस्कृतिक पिछड़ेपन का

कारण संप्रदायवादियों के लिए मुसलमान बटाईदारों और हिंदू जमींदारों के बीच के वास्तविक आर्थिक सघप का सांप्रदायिक सघप के रूप में प्रस्तुत और परिणत करना जासान था। इसी कारण हिंदू महाजनो और मुस्लिम कजदारो के द्वंद्व कभी-कभी इस तौर पर परिभाषित किए जाते थे मानी वे हिंदुओ द्वारा मुसलमानो के शोषण के प्रतिफलन थे और इस तरह इन्हें भी संप्रदायवादियों ने सांप्रदायिक रूप दिया। जमींदार बटाईदार का या सूदखोर कजदार का सघप गलत तौर पर सांप्रदायिक सघप के रूप में वर्णित हुआ। इस तरह संप्रदायवादियों ने विभिन्न संप्रदायों के विभिन्न वर्गों के सघपों को सांप्रदायिक रूप प्रदान किया। अपनी पुस्तक 'द प्रॉब्लम आफ् मिनारिटिज' में के० वी० कृष्ण ने ऐसे सारे सघपों का निम्नांकित वर्गीकरण प्रस्तुत किया है।

- 1 विभिन्न मता और संप्रदायों के पेशेवर वर्गों में सघप है। हिंदू पेशेवर वर्गों की तुलना में मुस्लिम, सिक्ख, भारतीय इसाई, एंग्लो इंडियन और अछूत पेशेवर वर्ग शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से पीछे थे। सुधारों एवं राजनीतिक आकांक्षाओं ने इन वर्गों में प्रतियोगिता की भावना और बढ़ाई ही। इस सघप ने अल्पमण्डको या निर्वाचक इकाइयों की समस्या का नाम इतितयार कर लिया है।
- 2 यह सघप विभिन्न मता और संप्रदायों के वाणिज्यिक औद्योगिक और वनिया-व्यापारी वर्गों में भी फला हुआ है। हिंदू और मुसलमान वनियों की प्रतियोगिता उनकी छुट्टियाँ के समय और नागकिक अवज्ञा आंदोलन के समय खास तौर पर देखने में आती है। हिंदू सूदखोर और मुसलमान कज खोर, हिंदू जमींदार और मुसलमान किसान, हिंदू और मुसलमान सूदखोर, हिंदू और मुसलमान जमींदार इनके सघप भी इसी श्रेणी में जाते हैं।
- 3 अतत, पिछड़ेपन, अशिक्षा, कभी कभी विरोधी राजनीतिज्ञा के पडयत्ता, भीड के पागलपन और हुल्लडबाजी और समाज के अन्य विरोधों द्वारा सजित विभिन्न मतों के प्रतिगामी वर्गों का पारस्परिक सघप है। ये सघप देश के सामाजिक अथतन के कारण उत्पन्न हुए। लेकिन सामंती स्थिति में भारतीय पूजोवाद के उदय के काल में ब्रिटिश साम्राज्यवाद और प्रतिलोल की उसकी नीति ने इन सघपों को तीव्र किया।<sup>40</sup>

असहयोग आंदोलन के बाद मुस्लिम संप्रदाय के राजनीतिक आंदोलन का ह्रास होने लगा। मुस्लिम लीग फिर से मुस्लिम पागपधियों का संगठन बन गई। यह उस संप्रदाय का प्रगतिशील राजनीतिक नेतृत्व नहीं प्रदान कर सकी। लीग में राष्ट्रीय मुसलमानों का बस एक छोटा सा दल रह गया।

साइमन कमिशन की नियुक्ति से जिसमें केवल गर भारतीय ही थे, भारतीय जनता में व्यापक विक्षोभ का जन्म हुआ। सभी राजनीतिक दलों ने इसने वहिष्कार का फसला किया। मुस्लिम लीग भी, जिसमें मुदत केवल मुस्लिम राजिवादी ही थे, इसके साथ सहयोग के प्रश्न पर एकमत नहीं हो सकी। फनस्वरूप

लीग में फूट पड़ गई। सर मुहम्मद सफी, मलिक फिराज खा नून, सर मुहम्मद इकबाल के नेतृत्व में एक दल लाहौर में मिला। सर मुहम्मद सफी ने इस सभा की सदारत की। इसने कमीशन का स्वागत करते हुए एक प्रस्ताव पास किया। लीग के दूसरे दल ने जिन्ना के सभापतित्व में कलकत्ता में अपना सम्मेलन किया। इसने कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव लिया।

इंडियन नेशनल कांग्रेस ने नहरू कमेटी रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें भारत के संविधान के आधारभूत तत्त्वों का निरूपण किया गया था (देखें अध्याय अठारह)। कमेटी ने सुरक्षित स्थानों के साथ संयुक्त निर्वाचक इकाइयों, सिंध के पृथक्करण और बलूचिस्तान और नाथ वस्त फ्रंटियर प्रांत को दूसरे प्रांतों के समकक्ष बनाने की अनुशंसा की। इसने पथक चुनाव क्षेत्रों की योजना की भूमना की। फिर, इसका यह भी फसला था कि केंद्रीय एवं प्रांतीय विधायिका सभाओं में स्थानों का आरक्षण सारी जावादी में मुसलमानों के अनुपात के आधार पर निर्धारित हो।<sup>41</sup> अपने नेता जिन्ना के जरिए लीग ने कांग्रेस से नहरू संविधान में कई संशोधन लाने का कहा। इन संशोधनों में एक यह था कि केंद्रीय विधायिका में एक तिहाई स्थान मुसलमानों के लिए आरक्षित रहे। कांग्रेस ने प्रस्तावित संशोधनों का स्वीकार नहीं किया और संयुक्त मध्य के लिए कांग्रेस और लीग के बीच समझौते की संभावना समाप्त हो गई।

### जिन्ना की चौदह सूत्री योजना

तत्पश्चात् 1929 में जिन्ना ने अपनी मशहूर चौदह सूत्री योजना प्रकाशित की जो बाद में लीग के प्रचार आंदोलन का आधार हुई। ये चौदह सूत्र नहरू कमेटी की रिपोर्ट के सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझावों के विरोधी थे। इस योजना की कुछ मुख्य बातें ये थीं, कुछ विषयों पर प्रांतीय स्वायत्तता का साथ मध्य मधीय राज्य की स्थापना केंद्रीय विधायिका सभा में कम से कम एक तिहाई मुस्लिम प्रतिनिधित्व, प्रथक निर्वाचक इकाइयां, किसी भी केंद्रीय या प्रांतीय मंत्रिमंडल में एक तिहाई मुस्लिम मंत्रियों की व्यवस्था।

कुछ ही दिनों बाद लीग के राष्ट्रीय मुसलमानों और रूढ़िवादी तत्वों में फूट हो गई। राष्ट्रीय मुसलमान कुछ छोटे-मोटे संशोधनों के साथ नहरू रिपोर्ट का समर्थन करना चाहते थे। उन्होंने नेशनलिस्ट मुस्लिम पार्टी की स्थापना की। 1930-34 के नागरिक जवानों के आंदोलन का इतिहास अध्याय अठारह में दिया जा चुका है। राष्ट्रीय मुसलमानों ने इसमें जोश के साथ भाग लिया। गोलमज कांग्रेस में सरकारी तौर पर आगा खां लीग का नेतृत्व लिया। कांग्रेस के भारतीय दलों में सांप्रदायिक प्रश्न पर असहमति के बावजूद ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामजे मैकडानल्ड ने कम्युनल अवाइ की घोषणा कर दी।

1933 के बाद जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने फिर से अपना को सगठित और एजेंट करना शुरू किया। जिन्ना अध्यक्ष चुन गए और तत्पश्चात् राजनीति में



क्रियाकलाप का कार्यक्रम अपनाया गया। 1935 के ववई अधिवेशन में लीग ने 1935 के गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट की सघीय योजना की मत्सना की और उसे इसलिए अस्वीकार कर दिया कि इससे जनता की स्वशासन की मांग पूरी नहीं हो रही थी।

1937 के चुनावों में अपनी महान सफलता के फलस्वरूप कांग्रेस कई प्रांतों में सरकार बना सकी। जिन्ना और अन्य मुस्लिम नेताओं ने कांग्रेस की सरकारों से अपना असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने यह दोषारोपण किया कि ये सरकारें मुस्लिम हितों के विरुद्ध थीं और इन्होंने हिंदुओं के प्रति पक्षपात का रुख अपनाया।

### कांग्रेसी सरकारों की जिन्ना द्वारा की गई आलोचना

1937 में लीग के लखनऊ अधिवेशन के अपने अध्यक्षीय भाषण में जिन्ना ने कहा कांग्रेस के वर्तमान नतामण, खासकर पिछले दस वर्षों में, भारत के मुसलमानों का अपने से अधिकाधिक विलग और विमुख करने के लिए जिम्मेदार रहे हैं। इन्होंने ऐसी नीति का अनुसरण किया है जो केवल हिंदुओं के हित में है। जिन छ प्रांतों में उन्हें बहुमत प्राप्त है उनमें सरकार बनाने के बाद उन्होंने अपने कार्यों, शब्दों और कार्यक्रम द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि मुसलमान उनसे धार और औचित्य की उम्मीद नहीं कर सकते। जो थोड़े बहुत अधिकार और उत्तरदायित्व उन्हें मिले हैं, उनमें मिलते ही बहुसंख्यक संप्रदाय ने यह स्पष्टतः प्रदर्शित कर दिया है कि हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए है।<sup>41</sup>

संभवतः यह कांग्रेस की गलती थी कि उसने प्रांतों में कांग्रेस और लीग की सम्मिलित संयुक्त सरकारें नहीं बनाई और इस तरह यह खयाल बना कि वे सत्ता पर एकाधिकार चाहते थे। विद्या मंदिर की योजना में हिंदू धर्म की गंध भी थी। कुछ कांग्रेस मंत्रियों ने जाने अनजाने कुछ हिंदुओं के प्रति पक्षपात भी किया होगा। कांग्रेसी सरकारों के सामाजिक और जायिक कार्यक्रम भी भारतीय जनसाधारण की आशाओं-उम्मीदों की पूर्ति नहीं कर सके होंगे, और उन्होंने किया भी नहीं। चुनाव पूर्व की अपनी घोषणा के बावजूद, कांग्रेसी सरकारों ने मिमिनल ला जमडमट ऐक्ट जैसे कानून का उपयोग किया, हड़तालियां पर गोलीकांड का अनुमोदन किया, और बाव ट्रेड डिस्प्युटस ऐक्ट जैसे कानून बनाए जिसके जरिए हड़ताल करने के मजदूरों के प्रजातांत्रिक अधिकार का हनन हुआ। लेकिन लीग का यह दावा कि कांग्रेसी सरकारों ने जान-बूझकर मुस्लिम संप्रदाय के दमन और उस पर हिंदुओं के प्रभुत्व की स्थापना की सुविचारित नीति अपनाई, सत्य की विडम्बना मात्र है, संपूर्णतः असत्य।

कांग्रेसी सरकारों मूलतः भारतीय युजुआजों के हितों को आग बढ़ा रही थी, और इसलिए कुछ छोट मोट सुधारों के बावजूद वे भारतीय समाज के गरीब तबकों की जायिक एवं जन्याय मांगों की पूर्ति करने में असफल रही। इनने

वारण संप्रदायवादी लीग न नेतागण मुस्लिम जनता को कुछ हिस्सा को कांग्रेस के विरुद्ध कर सके और उन्हें अपनी तरफ माड़ मके। चूँकि अधिकांश जमींदार और पूँजीपति हिंदू थे इसलिए लीग के नेता गरीब मुसलमानों का बरगलान में सफल रहे और ये गरीब मुसलमान ऐसा सोचने लगे कि हिंदू जमींदारों और उद्योगपतियों के जिस शोषण के व शिकार वे उसे कांग्रेसी नेता, जो अधिकांश हिंदू थे, जान बूझकर, सांप्रदायिकता की भावना के कारण, स्याई बना रहे थे। इस तरह सांप्रदायिक प्रचार के जरिए मुसलमानों का बगजय जायिक जनतोष और विक्षोभ सांप्रदायिक रास्तों पर लाया जा सका और सांप्रदायिक विरोध के रूप में परिणत किया जा सका।

बाद के अपने मारे अधिवेशनों में लीग ने कांग्रेस विरोधी प्रचार को और तीव्र ही किया। इसने कांग्रेस के उस प्रस्ताव को विरुद्ध भी प्रचार किया जिसके अनुसार त्रिष्वजनीन वालिग मताधिकार और मुसलमानों के लिए पथक निर्वाचक इकाइयों के आधार पर चुनी गई सविधान सभा की मांग की गई थी। लीग का कहना था कि प्रमुखतः हिंदू जावादी के इस दण में इस तरह की सविधान सभा पर बहुमध्यक हिंदुओं का ही जाधिपत्य होगा।

### मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग

पथक निर्वाचक इकाइयों और विशिष्ट अधिकार की अपनी पुरानी मांग से हटकर लीग अब पाकिस्तान अर्थात् सावभौम हिंदू और सावभौम मुस्लिम राष्ट्र में दश के विभाजन की मांग की और अग्रसर हो रही थी। 1940 के लाहौर अधिवेशन में लीग ने पाकिस्तान की मांग की घोषणा की। दो राष्ट्रों का सिद्धांत इस मांग का राजनीतिक व चारिक आधार था। इस सिद्धांत के अनुसार मुसलमान एक विशिष्ट राष्ट्र थे यद्यपि वस्तुतः वे एक सामाजिक धार्मिक प्रकार के लोग थे जो सारे देश में बिखरे हुए थे। राष्ट्र की यह धारणा राष्ट्र की जय धारणाओं से अलग थी, जैसे उस धारणा से जिसके अनुसार राष्ट्र ऐतिहासिक तौर पर विकसित ऐसा जन समुदाय है जो एक भाषा का व्यवहार करता है जिसका एकसम अयुक्त जायिक जीवन है, जिसका अपना अलग निश्चित भूभाग है और जिसकी अपनी सम्मिलित मनोवैज्ञानिक संरचना और संस्कृति है।

1939 में युद्ध हान पर भारत की राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन आया। इंडियन नेशनल कांग्रेस को यह बात नागवार लगी कि ब्रिटेन ने भारतीय जनता की राय के बिना भारत को लड़ाई में झोक दिया था, फलस्वरूप, कांग्रेस के निर्देश पर प्रांतों के कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने इन्तीफा दे दिया। कांग्रेसी मंत्रिमंडल के त्यागपत्र पर मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाकर खुशी का इजहार किया। जाल इंडिया मुस्लिम लीग ने 1940 के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान अर्थात् दो राष्ट्रों के सिद्धांत पर आधारित मुसलमानों का सावभौम राष्ट्र ही स्थापना की मांग का प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में कहा गया

तय हुआ कि आल इंडिया मुस्लिम लीग की यह सुविचारित राय है कि इस देश में कोई भी सांविधानिक योजना कार्यान्वित नहीं हो सकेगी और न मुसलमानों का मजूर ही होगी, अगर उसे यह आधारभूत सिद्धांत स्वीकार्य नहीं कि भौगोलिक दृष्टि से समीपस्थ इलाकों जैसे क्षेत्रों में बटे हों और आवश्यक क्षेत्रीय समायाजन के आधार पर इस तरह बने हों कि जिन इलाकों में मुसलमान बहुसंख्यक हैं जैसे पश्चिमी और पूर्वी इलाका में वे स्वतंत्र राज्य हों और उनकी विभिन्न इकाइयाँ स्वायत्तशासी और सावधान हों। इन इकाइयों और क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों के लिए संविधान में पर्याप्त, कारगर और अधिदेशात्मक सुरक्षा मिलनी चाहिए, जिससे उनके धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और जातीय अधिकारों तथा हितों की, उनके साथ सलाह मशविरों के आधार पर रक्षा की जा सके, इसी तरह भारत के उन भागों में जहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक हैं वहाँ संविधान में खास तौर पर उनके लिए और अन्य अल्पसंख्यकों के लिए पर्याप्त कारगर और अधिदेशात्मक सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे उनके धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रशासनिक और जातीय अधिकारों और हितों की उनके साथ सलाह मशविरों के आधार पर रक्षा की जा सके।

यह अधिवेशन कार्यकारिणी समिति को यह अधिकार भी प्रदान करता है कि वह इस आधारभूत सिद्धांतों की रीढ़नी में ऐसा संविधान बनाए, जिसमें इस बात की व्यवस्था हो कि अतएव इन विभिन्न क्षेत्रों को सुरक्षा, विदेशी मामलों, मंचार कस्टम्स आदि बातों में भी पूरा अधिकार मिल सकें।

लीग ने 1941 में अपना जगला अधिवेशन मद्रास में किया। जिन्ना ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा 'हम किसी भी हालत में अखिल भारतीय संविधान और केंद्र में एक सरकार नहीं चाहते हम इस उपमहाद्वीप में स्वाधीन राष्ट्र और स्वाधीन राज्य की स्थापना के लिए कृतमकल्प हैं।

## दूसरे मुस्लिम संगठन

लीग की पाकिस्तान योजना के बारे में कांग्रेस उदारवादियों, दलित जातियों आदि राजनीतिक दलों और संगठनों के चिंतन की चर्चा करने के पहले हम संक्षेप में कुछ अन्य मुस्लिम राजनीतिक संगठनों का उल्लेख करेंगे जो 1928 के बाद स्थापित हुए और जिनसे भारतीय मुसलमानों की बढ़ती हुई राजनीतिक और राष्ट्रीय चेतना का परिचय मिलता है।

1930 में अब्दुल गफ्फार खां ने खुदाई खिदमतगार नामक संस्था की स्थापना की। नाथ वेस्ट फ्रंटियर प्रांत के राजनीतिक तौर पर जागत मुसलमानों की संस्था कांग्रेस समर्थक थी। नागरिक अवज्ञा आंदोलन के काल में इस संगठन ने प्रांत के कुछ भागों में किसानों के बीच कर नहीं देना का आंदोलन चलाया। इस संगठन का विचार था कि गांधीवादी मध्य के तरीके से राष्ट्रीय स्वतंत्रता

प्राप्त करने की आवश्यकता है। बलूचिस्तान में राष्ट्रीय मुसलमान कांग्रेस समझक बतन पार्टी में संगठित थे। भारतीय मुसलमानों का एक अन्य राजनीतिक संगठन भी था आल इंडिया मोमिन कांग्रेस जो मुख्यतः मुस्लिम जुलाहों का संगठन था। इसने साधारणतः इंडियन नेशनल कांग्रेस का समर्थन किया और लीग एवं पाकिस्तान का विरोध।<sup>43</sup>

कुछ राष्ट्रवादी मुस्लिम नेताओं ने 1930 में पंजाब में अहमदगढ़ पार्टी की स्थापना की। कुछ दिनों तक इस पार्टी की मुस्लिम जनता पर इस पार्टी का बहुत अधिक राजनीतिक प्रभाव रहा। कांग्रेस द्वारा चलाए गए 1930-34 के नागरिक अवज्ञा आंदोलन में और 1940 के सत्याग्रह में भी अहमदगढ़ पार्टी के लोग ने भाग लिया। आल इंडिया शिया पोलिटिकल कांग्रेस भारतीय शिया लोग का संगठन था। कांग्रेस ने साधारणतः इंडियन नेशनल कांग्रेस का समर्थन किया।

बंगाल की कृषक प्रजा पार्टी के नेता फजलुल हक प्रभावशाली वक्ता और तर्जुमे से बदलने वाले राजनीतिक फनकार थे। इस पार्टी का कार्यक्रम था ससदीय और सांविधानिक तरीके से कृषि शक्ति और मुस्लिम किसानों में इस पार्टी का आधार बड़ा व्यापक था। हक के नेतृत्व में इस दल का रुझान कभी सांप्रदायिक रहा और कभी राष्ट्रवादी। 1931 में अल्लामा मशरीफी द्वारा स्थापित खासकर पार्टी का भी भारतीय मुसलमानों के बीच महत्वपूर्ण स्थान था।

खासकर आंदोलन प्रारंभिक इस्लाम के धार्मिक विचारों पर आधारित था। खासकर लोग आधुनिक इस्लाम को भ्रष्ट मानते थे और उन्होंने इसके पुनर्जागरण में और मुस्लिम समाज के नतिक उत्थान का व्रत लिया था। इस आंदोलन का दावा था कि यह समाज के गरीब तबकों का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें शुद्ध, पवित्र जीवन और समाज सेवा में जीवनापण के लिए अपने सदस्यों का जाह्वान किया।

खासकर पार्टी जट्ट मनिक अनुशासन पर आधारित थी। यह अपने सदस्यों से नेता के प्रति पूरा आस्था और आज्ञानुवर्तितता की अपेक्षा करती थी। यह पार्टी कभी कभी विश्व विजय का भी सपना देखती थी। फिर भी राजा, शासक, विश्व विजय और धरती का सर्वोपरि स्वामी होना हमारा लक्ष्य है।<sup>44</sup> खासकर आंदोलन में फासिज्म की तीव्र गंध है। पंजाब, संयुक्त प्रांत और सिंध में यह आंदोलन सबसे अधिक तगड़ा हुआ। दक्षिण भारत के भी कुछ इलाकों में यह फैला।

1940 में जल्लाबद्ध के सभापतित्व में आजाद मुस्लिम कांग्रेस की स्थापना हुई। इंडियन नेशनल कांग्रेस जमायतुन उल्मा, अहमदगढ़ पार्टी और अन्य राष्ट्रवादी मुस्लिम संगठनों में जो राष्ट्रवादी मुसलमान थे यह उन सबका मिला जुला दल था। यह दल मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग के विरोध था और इसने कांग्रेस की इस मांग का समर्थन किया कि प्रांतों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन हो और इन नए प्रांतों का आत्मनिर्धारण का हक मिले, यहाँ तक कि वे चाहें तो अलग भी हो सकें, लेकिन यह सब भारत की स्वतंत्रता के प्रयोग में हो।<sup>45</sup>

## पाकिस्तान के सिद्धांत का इतिहास

देश के प्रमुख मुस्लिम गणना की चर्चा करने के बाद अब हम मुस्लिम लीग की पाकिस्तान योजना और उसके सिद्धांतिक आधार के बारे में विभिन्न लोगों के विचार प्रस्तुत करेंगे। जिस सिद्धांत पर यह योजना आधारित थी वह धर्म की समानता से बना था और उसके अनुसार मुसलमान अलग राष्ट्र थे। जिन्ना के अनुसार महान मुस्लिम कवि इकबाल ने पाकिस्तान के सिद्धांत का निरूपण किया था।

यह सब विदित है कि पाकिस्तान का सिद्धांत हजरत अल्लामा इकबाल के मस्तिष्क की देन है। वे अपनी जनता की श्रेष्ठतम आकांक्षाओं के प्रवक्ता थे।<sup>46</sup>

1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्षीय भाषण में इकबाल ने कहा था, मैं पंजाब नाथ वेस्ट फ्रंटियर प्रांत, सिंध और बलूचिस्तान को एक राज्य के रूप में संयुक्त देखना चाहता हूँ। स्वायत्त शासन ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत मिले या उससे बाहर, उत्तर पश्चिम भारत के मुसलमानों की नियति मुझे यही मालूम पड़ती है कि अंततः उनका एक संयुक्त उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य बनेगा।<sup>47</sup>

लेकिन नए संविधान के लागू होने और कई पाता में कांग्रेसी सरकारों की स्थापना के बाद ही वही पाकिस्तान की धारणा मुस्लिम राजनीतिक दलों के ध्यान में खास तौर पर आई। 1940 में लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षीय पद से जिन्ना ने यह घोषणा की कि भारतीय मुसलमान महज एक धार्मिक संप्रदाय भर नहीं हैं, बरन् पृथक राष्ट्र भी हैं। भारत की समस्या महज अंतःसाम्राज्यिक नहीं, बरन् स्पष्टतः अंतर्राष्ट्रीय है और इस पर इसी रूप में विचार होना चाहिए। जब तक यह आधारभूत सत्य स्वीकार नहीं किया जाता, तब तक कोई भी संविधान बने उससे अनर्थ ही होगा। अगर ब्रिटिश सरकार सचमुच चाहती है कि इस उपमहाद्वीप में लीग शांति और सुखपूर्वक रहे तो हम सबके लिए एक ही रास्ता है और वह यह कि भारत को 'स्वायत्तशासी राष्ट्रीय राज्यों' में विभक्त कर प्रमुख राष्ट्रों के लिए अलग दशा की व्यवस्था की जाए।<sup>48</sup> जिन्ना ने यह भी कहा कि हिंदू और मुसलमान एक भारतीय राष्ट्र के रूप में मगन नहीं हो सकते। उनका तर्क था

यह समझना बड़ा मुश्किल है कि हमारे हिंदू दोस्त इस्लाम और हिंदू धर्म की वास्तविक प्रकृति को समझ पाने में कैसे असफल रह जाते हैं। वे शब्दों के सही अर्थ में धर्म हैं ही नहीं, बरन् विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाएँ हैं और यह सोचना महज सपना है कि वे कभी भी सम्मिलित राष्ट्र के रूप में विकसित हो सकेंगे। हिंदुओं और मुसलमानों के अलग-अलग धर्म दर्शन सामाजिक प्रथाएँ और साहित्य हैं। न तो वे आपस में शादी-व्याह करत हैं

आर न एक साथ खान-पान, वस्तुतः वे दो ऐसी भिन्न समस्याओं के लोग हैं जो विरोधी विचारों और धारणाओं पर आधारित हैं स्पष्ट है कि उन्हें विभिन्न इतिहास स्रोतों से प्रेरणा मिलती है। उनके महाकाव्य भिन्न हैं, उनके विरोचित काव्य नायक भिन्न हैं प्रायः एक का नायक दूसरे का शत्रु है और इसी तरह उनकी हार और जीत जलग जलग है। ऐसे दो राष्ट्रों को, बहुमध्यक और अल्पमध्यक के रूप में एक राज्य में नाथ देने से लगातार असंतोष और विक्षोभ बढ़ेगा ही, और ऐसे राज्य की सरकार के लिए जो ताना-बाना बनेगा वह नाट होकर रहेगा

मुस्लिम भारत ऐसा कोई सविधान स्वीकार नहीं कर सकता जिससे जिन वायत हिंदू बहुसंख्यक राज्य बनें। अल्पसंख्यकों पर लादे गए किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर हिंदू और मुसलमान एक साथ रहें तो वह वस्तुतः हिंदू राज्य व्यवस्था ही होगी। कांग्रेस जाला कमान जिस तरह के लोकतंत्र के पक्ष में है वह इस्लाम में जो सबसे अधिक मूल्यवान है उसका पूर्ण विनाश करके रहेगा

राष्ट्र की किसी भी परिभाषा के अनुसार मुसलमान जन्य राष्ट्र ही और उनका अपना जलग दश, अपना असलग भूभाग, अपना जलग राज्य होना ही चाहिए हम चाहते हैं कि हमारे लोग पूरी तरह अपने जाध्यात्मिक सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन का सर्वोत्तम विकास कर सकें और उनका जीवन जिसे हम सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और जो हमारे अपने आदर्श और हमारे जन जीवन की प्रतिभा के समरूप है उसके अनुरूप हो।<sup>49</sup>

पाकिस्तान के मसूदा ने भारत में सघीय राज्य की योजना को अस्वीकार कर दिया जिसके अनुसार केंद्रीय विधायिका के प्रति जिम्मेदार केंद्रीय मंत्रिमंडल सुरक्षा, संचार, विदेशी मामलों आदि पर नियंत्रण रखता। उनका कहना था कि केंद्रीय विधायिका पर हिंदू बहुसंख्यकों का आधिपत्य होगा क्योंकि देश में उन्हीं का बहुमत था।

मुस्लिम लीग ने अधिकारी तौर पर कोई ऐसी योजना प्रकाशित नहीं की थी जिसमें स्वायत्तशासी सावभौम मुस्लिम राज्यों के स्वरूप और उनकी प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था की विस्तृत और ठोस व्यवस्था हो, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने अपनी योजनाएँ बनाई थीं। पंजाबी जलीगढ़ के प्राफसरान डा० लतीफ सर सिकंदर हयात खां, रहमत जली और सर जदुला हारून कमटी आदि की योजनाएँ इनमें प्रमुख थीं। ये योजनाएँ एक दूसरे से भिन्न थीं, लेकिन वे सब इस प्रश्न पर सहमत थीं कि भारत में हिंदू और मुसलमान दो पृथक् राष्ट्र हैं। जसा ऊपर कहा जा चुका है, इनमें ने वार्ड भी योजना लीग द्वारा नहीं अपनाई गई थी और लीग ने पाकिस्तान की खुद अपनी काइ व्यापक और ठोस योजना नहीं प्रस्तुत की थी।

राष्ट्रिक इकाइयों और जल्पमध्यवर्ती समस्या

पाकिस्तान के बारे में विभिन्न राजनीतिक दलों और नेताओं के विचार

अब हम देखेंगे कि देश के प्रमुख राजनीतिक दलों के विचार उस सिद्धांत के प्रारंभ में क्या थे जिसके अनुसार भारतीय मुसलमान पृथक् राष्ट्र थे और जिसके अनुसार उनके बहुमत वाले इलाकों में उनके अलग राज्य बनने चाहिए।

(क) इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेताओं के एतद्विषयक विचार

उदारवादियों की ही तरह तिलक, पाल, और घाष आदि उग्रवाद्याओं के मतों में भी इंडियन नेशनल कांग्रेस की हृदय में यही राय थी कि भारतीय समशील राष्ट्र है उह इस राष्ट्र भावना का एहसास दिलाना और प्रशासनिक सुधार एवं जाति शासन के लिए एतद्विषयक मध्यम के रास्ते पर उह चलाना कांग्रेस के प्रचार का एक महान लक्ष्य था। पहले के नेताओं के बाद गांधी आदि जातीय नेता आए उनका भी ऐसा ही खयाल था, हालांकि उहने यह भी माना कि मुसलमानों और दलित जातियों जैसे जल्पमध्यक जन समुदायों के हितों की पूरी रक्षा हानी चाहिए। उनका विचार था कि मही ज्यों में लोचतांत्रिक मंत्रिपरिषद इन हितों का सब तरह की सुरक्षा प्रदान कर सकेगा।

कांग्रेस के नेतागण सांप्रदायिक सुविधाओं और पृथक् निर्वाचक इकाइयों के सिद्धांत के विरुद्ध थे। उनका खयाल था कि इनसे सांप्रदायिकता की भावना गहरी और स्थायी होगी। लेकिन वे हिंदू मुस्लिम एकरता का देश की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक मानते थे और इसलिए उन्होंने पृथक् निर्वाचक इकाइयों, विशेष सुविधाओं, या स्थानों के आरक्षण संबंधी दलित जातियों और मुसलमानों की मांगों को मान लिया। 1916 का कांग्रेस लीग पैक्ट और 1933 में विधायिका सभाओं में स्थानों के प्रश्न पर दलित जातियों का गांधी द्वारा दी गई रियायत (पूना पैक्ट) इसके उदाहरण हैं। फिर भी, कांग्रेस ने मुसलमानों या भारत की किसी अन्य जल्पमध्यक जाति को कभी पृथक् राष्ट्र नहीं माना।

कांग्रेस की राय थी कि भारतीय जनता अपनी समष्टि में भारतीय राष्ट्र है। लेकिन उसने ब्रिटिश सरकार द्वारा विभिन्न प्रांतों में देश के विभाजन की आलाचना की। उसका कहना था कि यह विभाजन भारतीय राष्ट्र के विभिन्न भाषा भाषी दलों के अनुकूल नहीं है। कांग्रेस ने भाषा के आधार पर देश के प्रांतों के पुनर्गठन की योजना बनाई।

कांग्रेस ने भारतीय राष्ट्र के भाषायुक्त और प्रांतीय सांस्कृतिक विविधता का स्वीकार किया, लेकिन वह देश के लिए मध्यम राजतंत्र के पक्ष में थी। इसके अनुसार सम्मिलित और जीवित हितों पर सघन नियंत्रण और जाकी मामलों में भाषा के सिद्धांत पर कभी मध्यम इकाइयों का अधिकार होना चाहिए, साथ ही प्रांतों को अत्यंत प्रांतीय स्वायत्तता उपलब्ध होनी चाहिए। 1947 के दिल्ली

अधिवेशन मे काग्रेस की वायकारिणी द्वारा पारित प्रस्ताव मे कहा गया कि किसी भी क्षेत्रीय इकाई को अपनी इच्छा के विरुद्ध भारतीय राष्ट्र मे शामिल हान के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा ।

लेकिन गांधी जीर अ य काग्रेसी नेताआ न लीग के दम सिद्धात का त्रि मुसलमान अलग राष्ट्र है, कभी स्वीकार नहीं किया, वरन उसका विराध ही किया । उहोन धम को राष्ट्रत्व का निर्णायक लक्षण नहीं माना यद्यपि उहान यह स्वीकार किया कि किसी वम विशेष का मानन वाला की सांस्कृतिक जीर सांप्रदायिक अल्पसंख्यक इकाई के रूप मे गणना हो सकती है । लीग के नेताओ के द्विराष्ट्रीय सिद्धात के विरुद्ध तक देते हुए गांधी न कहा

द्विराष्ट्रीय सिद्धात असत्य है । भारत के अधिमख्यक मुसलमानो न वम परिवतन से इस्लाम स्वीकार किया है । जैसे ही उनका धम परिवतन हुआ वे एक जलग राष्ट्र नहीं हो गए । बगाली मुसलमान वही भापा वालत हं जो भापा बगाली हिंदू वालत है । वे एक ही भोजन करते हं, उनके मनोरजन भी एक है । वे एक ही प्रकार के कपडे पहनत हं

यही बात दक्षिण मे भी गरीया मे दखन मे जाती हं जो भारत की जनता हं बहुत सारे मुस्लिम समुदाया मे उत्तराधिकार का वही कानून लागू है जो हिंदुओ मे प्रचलित है । भारत मे हिंदू और मुसलमान दो राष्ट्र नहीं है । जिहू भगवान न एक बनाया है, उहू आदमी कभी जलग नहीं कर सकता ।<sup>०</sup> प्रख्यात अमरीकी पत्रकार लुई फिगर मे भी गांधी न ऐसे ही विचार व्यक्त किए थ । उहाने कहा

हम लोग दो राष्ट्र नहीं है । भारत मे हमारी सम्मिलित संस्कृति है । उत्तर मे हिंदी जीर उदू को हिंदू जीर मुसलमान दाना समझत हं । मद्रास मे हिंदू और मुसलमान दाना तमिल बोलत है बगाल मे दाना बगाली बोलते है और कोई हिंदी या उदू नहीं । सांप्रदायिक दग हरदम गाय या धार्मिक जुलूस सवधी घटनाओ का लेकर हात हं । दमका अय हं कि हमार अध-विश्वासा के कारण उपद्रव हात हं और इसलिए नहीं कि हम विभिन्न राष्ट्रिक इवाइया हं ।<sup>१</sup>

हिंदू मुस्लिम फूट के लिए गांधी न बहुत हद तक त्रिटिंग सरकार का दापो ठहराया । लुई फिगर स ही गांधी ने यह भी कहा था, जब तक यह तीमरी शक्ति इग्लंड यहा है तब तक हमार सांप्रदायिक विभद हम परशान करत रहंग । बहुत पहले उन दिनो के वायसराय लाड मिटा न कहा था कि भारत पर जातिपत्य बनाए रखने के लिए मुसलमानो जीर हिंदुओ को जलग रखना हांगा

लेकिन गांधी का यह भी विश्वास था कि अगर भारतीय मुसलमान जलग होने को त्त सकल्प है ता कोई भी शक्ति उहू जलग हान स रोड नहीं सवती । उहान कहा, मुझे ऐसा जहिंसक तरीका मालूम नहीं जिमके जरिए नौ बराड मुसलमाना का भारत के रूप लागा की इच्छा मानन का माध्य किया जा सके,



चाहें जय लाग बहुत बड़ी तादाद में ही क्यों न हो। मुसलमानों को जात्मनिर्णय का वही अधिकार मिलना चाहिए जो शेष भारत को। इस देश का कोई भी भाग देश से अलग होने की मांग कर सकता है।<sup>3</sup>

आगे उन्होंने यह भी कहा अगर भारत में मुसलमान सचमुच इस बात पर जड़ जाते हैं तो अहिंसा में विश्वास करने वाले आदमियों की हैसियत से मैं इस प्रस्तावित विभाजन का मजल प्रतिरोध नहीं कर सकता। लेकिन मैं मन से इस विभाजन या जीवच्छेदन का समर्थक नहीं हो सकता। इसे रोकने के लिए मैं सारी मंथन अहिंसक कार्यवाही करूंगा विभाजन एक सफेद झूठ है। मेरी आत्मा किसी भी हालत में यह मानने का तयार नहीं कि हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों पूणत विराधी संस्कृतियाँ और सिद्धांत हैं। लेकिन जब मुसलमान यह साक्ष्य दे कि वे अलग राष्ट्र हैं तो मैं अपना विश्वास खतरन उन पर नहीं लाद सकता।<sup>4</sup>

मुस्लिम नेताओं का यह कहना था कि हिंदू मुसलमानों का आर्थिक शोषण कर रहे हैं। एक प्रमुख कांग्रेसी नेता सत्यभूति ने इस तर्क को गलत बतलाया। उनका कहना था कि ये संप्रदाय आर्थिक तौर पर समरूप नहीं हैं। हिंदू संप्रदाय में एक तरफ पूजापतियों, जमींदारों और जय मयन लोगों का वर्ग है और दूसरी ओर मजदूरों, किसानों और जय गरीब लोगों का। मुस्लिम संप्रदाय की भी बनावट ऐसी ही थी। जय गरीब और जमीर मुसलमानों का आर्थिक हित समान नहीं था। वैसे ही गरीब और अमीर हिंदुओं के भी आर्थिक हित एक जय नहीं थे। सत्यभूति का कहना था कि इस तरह यह कहना गलत है कि हिंदू संप्रदाय मुस्लिम संप्रदाय का आर्थिक शोषण कर रहा है।<sup>5</sup>

एक जय प्रमुख कांग्रेसी नेता राजेंद्र प्रसाद के अनुसार भारत में सामंशिकता पृथक चुनाव इकाइयों और विशेष सुविधाओं के कारण पड़ी। यह भी उतना ही स्पष्ट है कि पृथक निर्वाचन इकाइयों में सामंशिकता की भावना का किसी भी जय तथ्य की अपेक्षा अधिक जागत किया और बढ़ावा दिया है। यह भावना उन्हीं संप्रदायों तक सीमित नहीं रही है जिन्हें पृथक निर्वाचक इकाइयाँ मिली हैं लेकिन उन संप्रदायों में भी फैली है जो इसके शिकार हुए हैं। यह भावना विभिन्न संप्रदायों और जातियों में भी फैली है। यह भावना हम जतीत से जभी हान में प्राप्त हुई है।<sup>6</sup>

राजेंद्र प्रसाद ने यह भी कहा कि पाकिस्तान का मांग आधुनिक संसार की 'राष्ट्रों के अनुकूलकरण की प्रवृत्ति का विरुद्ध है। आज की दुनिया में छोटों राष्ट्रों के लिए बचा रहना और स्वतंत्र बन रहना बड़ा कठिन है। चूंकि आधुनिक संश्रुति में राजनायक अत्यंत ही नायक से ही राष्ट्र में प्रगति या ममद्वि जा ममती है और चूंकि छोटों राज्य अपन सीमित साधनों के आधार पर राजनायक बनना नहीं अपना सकते, इसलिए भारत का कइ राज्यों में बांटने जमी पाकिस्तान का योजना भारत के हिंदुओं और मुसलमानों के बीच आर्थिक भिन्नता का उत्तर में डाल रही है। राजेंद्र प्रसाद ने यह भी बताया कि भारत के बाहर के मुस्लिम

राज्या के लोग 'अपन देश की राजनीति और जननीति को अधिकाधिक धर्मोत्तर तथ्या पर आधारित करने लगे ह। मुस्लिम लीग और पाकिस्तान के सिद्धांत के प्रणेता चाहें जो कहें, इस बात में कहीं कोई शक नहीं कि युरोप के इमाई राज्या की ही तरह दुनिया के मुस्लिम राज्य भी आज धर्म निरपेक्ष हो रहे ह। संकल यह है कि क्या भारतीय मुसलमान घटनाओं के ज्वार की दिशा मोड़ सकेंगे और भारत में किसी अन्य आधार पर कोई राज्य स्थापित और गंचालित कर सकेंगे।' उन्होंने यह भी कहा कि अगर भारत हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बंट जाएगा तो अल्पमध्यको की समस्या और भी उलझ जाएगी।<sup>7</sup>

1942 में डा० एम० ए० जतीफ को लिखे गए अपने पत्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान योजना पर अपने विचार अभिव्यक्त किए। उन्होंने इस आधार पर इस योजना का विरोध किया कि यह भारत की आर्थिक एकता को भंग कर देगी, और ऐसी आर्थिक एकता भारतीय राष्ट्र के भौतिक कल्याण और उसकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है, क्योंकि किसी देश की सैनिक शक्ति उसकी आर्थिक शक्ति पर निर्भर है। अगर यह योजना लागू होती है तो देश के लिए मुनियोजित अद्यतन का कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो सकेगा और ऐसा कार्यक्रम देश की उत्पात्क शक्ति को बढ़ाने, उसके जरिए भारतीय जनता की गरीबी को खतम करने और उनके भौतिक और सांस्कृतिक अस्तित्व को उचा उठाने के लिए आवश्यक है। आज देश के लिए मुनियोजित अद्यतन की और इसके लिए, और साथ ही देश की सुरक्षा के लिए सक्षम केंद्रीय सत्ता की बड़ी जरूरत है।<sup>8</sup> उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि पाकिस्तान के पास पर्याप्त प्राकृतिक साधन नहीं हैं, इसलिए अगर राजनीतिक विभाजन के कारण देश कई आर्थिक इकाइयों में बंट जाए, तो सबसे अधिक नुकसान खुद पाकिस्तान का होगा।

पंडित नेहरू ने यह भी कहा कि आज दुनिया में बड़े बड़े मघा के निर्माण की प्रवृत्ति बढ़ रही है। पाकिस्तान की योजना इस प्रवृत्ति के विरुद्ध है। अगर भारत कई राज्या में बंट गया, तो ये राज्य छोटे-छोटे और अपेक्षाकृत कमजोर होंगे, और बड़े बड़े राष्ट्रा के उपग्रह जैसे होकर रह जाएंगे। इसीलिए जवाहरलाल भारत के विभाजन के विरुद्ध थे। उन्होंने कांग्रेस के विचार का या प्रस्तुत किया

इस तरह कांग्रेस दृष्टि के साथ भारत की एकता और गंभीर पद्धति के पक्ष में है। ऐसा संधि जिसे इकाइयों का स्वायत्तता होगी फिर भी दिल्ली में इसने स्पष्ट कर दिया कि अगर कोई भूभागीय इकाइया साफ साफ इस राय की है कि वह भारतीय मध्य से अलग हो जाए तो उस अपनी इच्छा के विरुद्ध काम करने को बाध्य नहीं किया जा सकता। यह स्वाभाविक है कि हम ऐसी बात का स्वागत नहीं करेंगे और यह कुछ भौगोलिक और अन्य तथ्या पर निर्भर होगा।<sup>9</sup>

### (ख) कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी

इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक प्रशाखा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने भी लीग के द्विराष्ट्रीयता के सिद्धांत का स्वीकार नहीं किया और जपन प्रस्तावा के द्वारा पाकिस्तान की मांग का विरोध किया। पार्टी के दो प्रमुख नेताओं, ए० मेहता और ए० पटवर्धन ने लिखा 'पाकिस्तान की अत्य मांग गणनातीत अनिष्ट की मभावना से परिपूर्ण है विभाजन हिंदू मुस्लिम समस्या का समाधान करने के बदले उसे और अधिक उलझाएगा, और उसके कारण भारत की मुक्ति का दिन और दूर चला जाएगा। यह देश के राजनीति रूपी शरीर के घावा के लिए मलहम का काम करने के बदले उन पर विघटन का अम्ल डालता है।'<sup>60</sup>

इन सोशलिस्ट नेताओं का विचार था कि मुस्लिम और हिंदू क्षेत्रों को समरूप बनाने के लिए आबादी के हेर फेर की तकनीक अव्यावहारिक है। डा० लतीफ की योजना की जालोचना करते हुए उन्होंने कहा, 'इस तरह के हेर फेर का भारत की समूची आबादी के दो तिहाई भाग पर असर पड़ेगा। इसका अर्थ होगा जभूत-पूर्व पमाने पर मानवता का उमूलन। इसका बड़ा व्यापक जन विरोध होगा और लोगों का भयकर दुःशा का सामना करना पड़ेगा।'<sup>61</sup> इन नेताओं की यह भी राय थी कि चूंकि भारतीय जनतंत्र मिश्रित है, इसलिए भारत में कई सावभौम राज्या की स्थापना से यह जनतंत्र भंग होगा और यह पाकिस्तान और हिंदुस्तान दाना के आर्थिक हिता के लिए घातक होगा।

पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों देशों में कुछ 'विदेशी' अल्पसंख्यक रह जाएंगे। मेहता और पटवर्धन का कहना था कि इस तरह अल्पसंख्यकों की समस्या और जटिल होगी। उन्होंने लिखा, विभाजन के बाद भी हिंदू और मुस्लिम दानों राज्यों में दूसरे संप्रदाय के विदेशी जन क्षत्र रह जाएंगे और विदेशी सत्ता या आधिपत्य से भूभाग वापस लाने के सिद्धांत से इन जन क्षेत्रों की शांति और सुरक्षा पर हरदम खतरा बना रहेगा यह भूक्षेत्र वापस लानेवाली बात तो बनी ही रहेगी क्योंकि विभाजन के बाद भी लोग का उम्मीद है कि वह हिंदुस्तान में रह गए मुसलमानों का संगठित करेंगे और उनका नेतृत्व करेंगे। हिंदू लोग भी ऐसा ही दावा करेंगे। इस तरह दाना राज्या में सुमधुनत अल्पसंख्यकों के रूप में एक महान अभिशाप विद्यमान रहेगा और इनकी निष्ठा पर शंका बनी रहेगी'<sup>62</sup>

### (ग) भारतीय उदारवादी

भारतीय उदारवादियों ने पहले ही मान रखा था कि भारत कई प्रजातंत्रों से बना हुआ राष्ट्र है। फलस्वरूप उदारवादी नेताओं ने द्विराष्ट्रीयता के सिद्धांत और उन पर आधारित पाकिस्तान की मांग का विरोध किया। डा० आर० पा० पण्डित ने कहा, 'इस तरह यह समझ लेना चाहिए (आवश्यक है) कि आज का भारत न तो हिंदू भारत है और न मुस्लिम भारत, बरन मात्र भाग्य है, और इस विषय पर

वह शक्ति जो भारत को एकता बढ़ाती है उस प्रोत्साहन मिलना चाहिए और जो भी इस एकता को खंडित करती है उस शक्ति का तिरस्कार होना चाहिए।<sup>63</sup>

सर चिमनलाल एच० सटलवाड ने जिना के तका का यह जवाब दिया, मि० जिना कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान एक राष्ट्र नहीं हो सकते, क्योंकि वे एक साथ खाते पीते नहीं, आपस में शादी-ब्याह नहीं करते और उनके दो भिन्न धर्म दर्शन हैं। लेकिन हिंदुओं में भी तो विभिन्न जातियों के लोग हैं जो एक साथ खाते पीते नहीं और जो आपस में शादी-ब्याह नहीं करते जैन, बौद्ध, लिगायत, तमिल, तेलगु आदि के अपने विभिन्न धर्म हैं और वे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। शिया और सुन्नी लोगों में तीव्र धार्मिक मतभेद है जिनके कारण उनके बीच खून खराबी से भर हुए दंगे होते रहते हैं। क्या इन सबका विभिन्न राष्ट्रों के रूप में वर्गीकृत करना होगा और उन्हें विभिन्न राष्ट्र मानना होगा?<sup>64</sup>

### (घ) हिंदू महासभा

हिंदू महासभा ने पाकिस्तान की मांग का जमकर जनम्य, अटल विरोध किया। हिंदू महासभा के अध्यक्ष बी० डी० सावरकर ने लिखा हम हिंदुओं के लिए भारत माता एक और अनिर्भाज्य है। बरिदक युग से आने तक भारत की एकता एक स्थापित तथ्य है। इसलिए विभिन्न क्षेत्रों में भारत के बंटवारे की मांग हिंदू कभी वर्दीष्ट नहीं कर सकते।<sup>65</sup>

सावरकर ने यह घोषणा की कि हिंदू लोग स्वतः एक राष्ट्र हैं और संपूर्ण भारत उनकी पवित्र राष्ट्रभूमि है। हमारी एक सम्मिलित पितृभूमि और तज्जय क्षेत्रीय एकाग्रता तो है ही, हमारा एक सम्मिलित पवित्र क्षेत्र भी है जो हमारी सम्मिलित पितृभूमि का समरूप है, उससे अभिन्न है। यह तथ्य मसाल में और कहीं द्रष्टव्य नहीं है। यह हिंदुस्तान यह भारत भूमि हमारी पितृभूमि भी है और पुण्य भूमि भी हमारा कुछ ऐसे सजातीय संवर्ध भी है, सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक माया भाषी और जातीय, जिन्होंने जनगिनत सदियों के पारस्परिक संपर्क और स्वांगीकरण की प्रक्रिया के जरिए हमें समरूप और जविक राष्ट्र के रूप में ढाल लिया है।<sup>66</sup>

तात्पर्यत इम सिद्धांत के अनुसार भारतीय मुसलमान भी अलग राष्ट्र हैं। सावरकर ने इस माना भी। सावरकर ने भारतीय मुसलमानों का अलग राष्ट्र ता आवश्यक माना, लेकिन उन्होंने मुस्लिम गृहभूमि की उनकी मांग को भायता प्रदान करने से इंकार कर दिया। उन्होंने जायावत या भारत को मात्र हिंदुओं का गृहभूमि माना और हिंदू राज का सपना देखा यह तक मगत नहीं था।

### (च) डा० अम्बेदकर

'घाटस जान पाकिस्तान' नामक अपनी पुस्तक में अम्बेदकर ने पाकिस्तान पर अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने रमन द्वारा निरूपित राष्ट्रों के जादशशास सिद्धांत

को माना। रेनन के अनुसार, 'राष्ट्र एक जीवित आत्मा है, एक आध्यात्मिक सिद्धांत। दा तथ्य जा वस्तुतः एक ही है, इस जीवित आत्मा इस आध्यात्मिक सिद्धांत का निर्माण करत हैं। इनमें एक अतीत में और एक वर्तमान में निहित है। एक स्मृतियों के मपन उत्तराधिकार का स्वत्व भोग है तो दूसरा साथ रहने की इच्छा या वास्तविक स्वीकार भाव है परंपरा से मिले हुए अविभाजित उत्तराधिकार के सुयोग्य संरक्षण की इच्छा है।'<sup>67</sup>

डा० अम्बेदकर ने कहा कि इस मानदंड से देखने पर हिंदू और मुसलमान एक राष्ट्र नहीं हैं। वे दा हथियारबंद फौजे हैं जो एक दूसरे के खिलाफ मघप कर रही हैं। उनका अतीत एक दूसरे के विनाश का अतीत है राजनीति और धर्म दोनों क्षेत्रों में जापसी शत्रुता का अतीत है हिंदुजा और मुसलमानों का जो तथा कथित समान दाते एक साथ बाधती है, उनसे अधिक गहराई से राजनीतिक और धार्मिक शत्रुता उन्हें विभाजित करती है।<sup>68</sup>

डा० अम्बेदकर ने यह भी कहा कि मुसलमान केवल एक संप्रदाय भर नहीं, वरन् राष्ट्र है इसलिए भारतीय राज्य का कोई ऐसा संविधान जो अल्पसंख्यक संप्रदायों के हितों की गारंटी करता है इस समस्या का हल नहीं कर सकता। उन्होंने संप्रदाय और राष्ट्र के विभेद का निम्नांकित विवेचन किया

यह अंतर मूलतः यह है संप्रदाय का सुरक्षा का अधिकार है, राष्ट्र को पृथक्करण की मांग का अधिकार है मर विचार से अंतिम नियति के सवाल में इस अंतर का कारण निहित है जिस राज्य में कई संप्रदाय हैं, उसमें एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय के खिलाफ हो सकता है लेकिन अपनी अंतिम नियति के बारे में उनकी भावना यह होती है कि वह एक है। लेकिन जा राज्य कई राष्ट्रों से बना है उसमें अगर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के खिलाफ उठ पड़ा जाता है तो उनका अंतर उनकी अंतिम नियति के अंतर से जुड़ा हुआ है संप्रदाय केवल सरकार का रूप और उसकी पद्धति में परिवर्तन चाहता है लेकिन राष्ट्र का विसर्जन का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि यह सरकार का रूप में परिवर्तन मात्र से संतुष्ट नहीं होगा। इसका अर्थ अंतिम नियति के प्रश्न से जुड़ा है।'<sup>69</sup>

लोगों के मुसलमानों ने बहुत दूर से यह जाना था कि भारतीय मुसलमान राष्ट्र हैं और डा० अम्बेदकर ने इसकी यह व्याख्या की, कि संसदीय अपने को गलती से संप्रदाय मान ले सकता है यद्यपि इसमें राष्ट्र के तत्त्व मौजूद हो सकते हैं।'<sup>70</sup>

डा० अम्बेदकर का सवाल था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में एकता संभव नहीं है। वास्तविक एवं अविभाज्य होने के लिए एकता का सादृश्य और बहुत्व की भावना पर आधारित होना पड़ेगा। इस एकता को आध्यात्मिक होना पड़ेगा। चूंकि मुसलमान स्वार्थी आध्यात्मिक ईसाई हैं यद्यपि हिंदुजा और मुसलमानों की एकता संभव नहीं। अम्बेदकर ने कहा कि पाकिस्तान का मर तत्त्व भाग्य में

सावभौम केंद्रीय सत्ता की स्थापना के प्रति विरोध में निहित है। पाकिस्तान का अर्थ है मुस्लिम इलाको में मुसलमानों के पृथक सावभौम राज्य की स्थापना।

डा० अम्बेदकर का विचार था कि जिन इलाको में मुसलमान अधिक संख्या में हैं वहां स्वाधीन मुस्लिम राज्यों का निर्माण होना चाहिए। जावादी के हेर फेर से इन इलाकों को समरूप बनाया जा सकता है। जाधुनिक सावना और प्रक्रियाओं के कारण इस तरह का हेर फेर बहुत कठिन भी नहीं होगा। डा० अम्बेदकर ने यह भी कहा कि इसमें जितनी परेशानी होगी और जो खर्च लगेगा उससे अधिक हम लाभ होगा, क्योंकि इस अत्यंत जटिल और विशद समस्या का स्थाई हल मिल जाएगा।

### (छ) कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया

जिन इलाकों में मुसलमान अधिक तादाद में थे, वहां उनके स्वायत्तशासी राज्य और भारत से पृथक हो सकने के अधिकार को कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया ने स्वीकार किया। पार्टी के एक प्रमुख नेता डा० जी० अधिकारी ने लिखा, 'अगर हम पाकिस्तान की मांग के सारभूत तत्त्व पर ध्यान दें तो असल में यह मांग पंजाब सिंध, बलूचिस्तान और बंगाल के पूर्वी क्षेत्रों आदि की मुस्लिम राष्ट्रिक इकाइयों के आत्मनिर्णय और अलग हो सकने के अधिकार की मांग है।'<sup>71</sup> 1943 के पार्टी अधिवेशन के प्रस्ताव के निम्नांकित खंड में राष्ट्र जातियाँ और स्वतंत्र भारत के सम्भावित राज्यतंत्र के प्रश्न पर पार्टी के विचार दिए गए हैं

(अ) भारतीय जनता के जिन किसी अंश का अपना सलग्न भूभाग है, सम्मिलित ऐतिहासिक परंपरा, सम्मिलित भाषा, संस्कृति, मानसिक संरचना और आर्थिक अस्तित्व है उसे पञ्च राष्ट्रिक इकाई की मान्यता मिलेगी, स्वतंत्र भारतीय संघ स्वायत्तशासी राज्य के रूप में रहने का उसे हक होगा, और इच्छा हो तो उसके अलग होने का भी उसे अधिकार होगा। इसका आशय यह है जो भूभाग इन राष्ट्रिक इकाइयों के गृहक्षेत्र है जो आज के ब्रिटिश प्रांतों और तथाकथित 'भारतीय राज्यों' की कृत्रिम सीमाओं द्वारा विभिन्न भागों में विभक्त है, उन्हें स्वतंत्र भारत में फिर से एक कर दिया जाएगा और उन राष्ट्रिक इकाइयों को वापस कर दिया जाएगा। इस तरह मध्य प्रदेश का स्वतंत्र भारत पठान, पश्चिमी पंजाबी (मुख्यतः मुस्लिम), सिंध, सिंधी हिंदुस्तानी राजस्थानी गुजराती, बंगाली, जासामी बिहारी, उड़ीसा और आंध्र तमिल, कर्नाटक महाराष्ट्र, केरल के रहने वाले जादि विभिन्न राष्ट्रिक इकाइयों के स्वायत्तशासी राज्यों का मध्य होगा।

(ब) अगर इन नए राज्यों में अल्पसंख्यक विचर रहे हों तो संस्कृति, भाषा शिक्षा आदि क्षेत्रों में उनके अधिकार कानून द्वारा सुरक्षित होंगे

(स) अधिकारों की ऐसी घोषणा ऊपर बतलाई गई प्रत्येक राष्ट्रिक इकाई का और इसलिए मुस्लिम धर्म का मानने वालों राष्ट्रिक इकाई को भी

स्वायत्तशासी राज्यगत अस्तित्व और सबंध विच्छेद का अधिकार प्रदान करती है। इसलिए ऐसी घोषणा नेशनल कांग्रेस और लीग के बीच एकता का आधार हो सकती है। इससे जहाँ कहीं मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में हैं और जहाँ उनका अपना सलग्न गृहक्षेत्र है, वहाँ उन्हें अपना स्वायत्त शासी राज्य बनाने और चाह तो अलग होने का भी अधिकार होगा। ऐसी घोषणा पाकिस्तान की मांग के सार तत्त्व को स्वीकार करती है।

- (द) लेकिन इस रूप में सबंध विच्छेद के अधिकार की स्वीकृति का अर्थ यह नहीं है कि इससे सचमुच सबंध विच्छेद होगा ही। इसके विपरित, पारस्परिक सशय को दूर कर, इस तरह की घोषणा आज की स्थिति में कायगत एकता लाती है और कल के स्वतंत्र भारत में उच्चतर एकता का आधार बनती है। ऐसी घोषणा के फलस्वरूप जो राष्ट्रीय एकता बननी और मातृभूमि की रक्षा के संयुक्त संघ में मजबूत होगी, इससे सारी भारतीय राष्ट्रिक एक माथ रहने और स्वतंत्र भारतीय संघ की स्थापना की आवश्यकता को समझ सकेंगी, क्योंकि हर राष्ट्रिक इकाई का राज्य ऐसे संघ का स्वतंत्र और समानाधिकारी सदस्य होगा और उसे अलग हो सकने का अधिकार होगा। इस तरह ये राष्ट्रिक इकाइयाँ यह समझ सकेंगी कि देश में भावी स्वतंत्रता लोकतंत्र का बचाने का यही रास्ता है।

डा० अधिकारी के अनुसार राष्ट्रीयता की भावना के विकास और भारतीय जनता में राष्ट्रीय आंदोलन के प्रसार के कारण भारत में राष्ट्रिक इकाइयाँ का आंदोलन विकसित हुआ। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 'भारत के कोन-काने में फल रहा है और सबसे अधिक पिछड़ी हुई राष्ट्रिक इकाइयाँ और संप्रदायों की किसान जनता भी इसके भवर-प्रभाव में आ रही है। देश की मुक्ति का अखिल भारतीय आंदोलन बहुराष्ट्रिक और बहुजातीय आंदोलन के रूप में विकसित हो रहा है। भारत की राजनीतिक और आर्थिक मुक्ति का सम्मिलित लक्ष्य व्यक्तिगत चेतना की जागती हुई आत्मा में परिलक्षित हो रहा है।'<sup>73</sup>

सांप्रदायिक निवाचक इकाइयों विशिष्ट प्रतिनिधित्व और भारतीय मुसलमान अलग राष्ट्र है इस सिद्धांत पर आधारित मुस्लिम लीग की मांग के परिप्रक्ष्य में, देश के सबसे महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक संप्रदाय मुसलमानों की समस्याओं पर विभिन्न राजनीतिक मगठनों और दलों के दृष्टिकोण और विचार का हम उल्लेख कर चुके।

1930 के बाद भारत की राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रिक इकाइयाँ और अल्पसंख्यकों की समस्या केंद्रीय महत्व की है। इस संवाल पर घनघार विवाद हुए और विभिन्न दलों की ओर से तीव्र राजनीतिक प्रतिक्रिया हुई।

अगर हम भारतीय समाज के प्रस्तुतिष्ठ ऐतिहासिक विकास समस्या और इसकी प्रवृत्तियाँ को समझने का प्रयास करें, तो

सामाजिक ऐतिहासिक स्थिति को समझ सकें जिसमें इस समस्या का सही समाधान नभव है।

### राष्ट्रिक इकाइयों की समस्या, इसकी आवश्यक शर्तें और इसका प्रगतिशील समाधान

किसी सामाजिक स्थिति से ही काइ सामाजिक समस्या उभरती है। उस समस्या का समाधान उन सामाजिक शक्तियों का निराकरण पर ही संभव है जिनसे उस समस्या का जन्म हुआ। भारत में जो सुप्त राष्ट्रिक इकाई वाल दल थे उनका सम्मिलित जायिक जीवन था, उनकी समान भाषा और संस्कृति थी। इनके राजनीतिक जागरण का फलस्वरूप राष्ट्रिक इकाइयों की समस्या का उदभव हुआ था। इन राष्ट्रिक इकाइयों का जादोलन पचासत भूभागीय एकावयन और जायिक जीवन, भाषा एवं संस्कृति के मुक्त विकास की उनकी इच्छा को अभिव्यक्त करते थे और यह विनास ब्रिटिश शासन के कारण अवरोध था।

इस समस्या के समाधान की पहली शर्त यह थी कि इन राष्ट्रिक इकाइयों के विकास के पथ में ब्रिटिश शासन के रूप में जो अवरोध था उस खतम किया जाए और यह भी कि इन राष्ट्रिक इकाइयों का आत्मनिर्णय, यहाँ तक कि नवव्यवस्था का भी अधिकार दिया जाए। हम फिर भी यह विचार करना है कि क्या ब्रिटिश शासन में मुक्ति और आत्मनिर्णय के अधिकार की प्राप्ति राष्ट्रिक इकाइयों की समस्या के प्रगतिशील समाधान के लिए पचासत है।

पिछले दो सौ वर्षों के विश्व इतिहास का सर्वेक्षण से पता चलता है कि राष्ट्रिक इकाइयों की समस्या के साथ-साथ समाधान के लिए मात्र राष्ट्रीय स्वातंत्र्य ही काफी नहीं है। जास्ट्रिया, हंगरी और बाल्कन प्रायद्वीप में राष्ट्र जातियों की समस्या उन देशों की स्वतंत्रता का बावजूद ज्यों की त्यों बनी रही। इसका कारण यह था कि समाज की पूजावादी जायिक संरचना के ढाँचे में राष्ट्रिक इकाइयों की समस्या का पूरा समाधान नभव नहीं था।

पूजावादी समाज राष्ट्रों के बीच और एक ही देश की राष्ट्रिक इकाइयों के बीच भी प्रतियोगी संघर्ष पर आधारित है। फिर, चूंकि पूजावाद में व्यक्तियों राष्ट्रिक इकाइयों और राष्ट्रों के विकास की प्रवृत्ति और गति असमान होती हैं इसलिए पूजावादी जायिक आधार पर विकसित हान वाले राष्ट्रों और राष्ट्रिक इकाइयों की जायिक शक्ति और संपन्नता एक जैसी नहीं होती। राष्ट्रों और विश्व के अन्य तंत्र के पूजावादी संगठन के कारण, ये राष्ट्र और राष्ट्रिक इकाइयों बाजार, कच्चे माल और पूजा निवेश के क्षेत्रों के लिए अनवरत संघर्ष करती रहती हैं। फलस्वरूप, युद्ध और शत्रुता एवं लोगों का गोपण और उनकी परतंत्रता का जन्म होता है।

बाजार और कच्चे माल की खोज में शक्तिशाली पूजावादी राष्ट्र औपनिवेशिक साम्राज्यों का निर्माण करते हैं और अन्य राष्ट्रों का परतंत्र बनाते हैं। अतः ही राष्ट्रों की राष्ट्रिक इकाइयों जो पूजावादी जायिक आधार पर विकसित हाता हैं उन



दूसरे से और बाकी दुनिया से भी पूँजीवादी आर्थिक लक्ष्यो की पूर्ति के लिए मघप करती है। साम्राज्यवाद अर्थात् पूँजीवाद के ह्रास क युग म य मघप खास तीर पर तेज होत ह। इससे दुनिया के राष्ट्रों क बीच एकता की भावना नही बढ़ती है वरन राष्ट्रीय शत्रुता, साम्राज्यवादी युद्ध और गुलाम देशो की राष्ट्रीय स्वाधीनता क मघप बढ़ते हैं।

राष्ट्रो और राष्ट्रिक इकाइया के बीच मघप समाज के पूँजीवादी सगठन म निहित है। यह मघप तभी खतम होगा जब समाज प्रतियोगिता के बदल सहयोग और सहकारिता अर्थात् समाजवादी जयतन पर आधारित हा।

पूँजीवाद का आधार है लाभाय उत्पादन और प्रतियोगिता का सिद्धांत। इसलिए यह मानवता का शत्रु राष्ट्रों के रूप मे खडित विभाजित करता है और गण्टा को मघपशील, युद्धरत युद्धेच्छु, राष्ट्रिक इकाइया वाल दला और वर्गों म विभक्त करता है। समाजवाद उपभोगमूलक उत्पादन और सहयाग के सिद्धांत पर आधारित है। इसलिए यह मानवता को सहयोगी समुदाय के रूप म एकताबद्ध करने म सहायक है और राष्ट्रों एव राष्ट्रजातियों क बीच बहुत्व के मवध स्थापित करता है। समाजवाद म, राष्ट्रों या राष्ट्रिक इकाइया म कोई पूँजीवादी दल नही हाता, जो प्रतियोगिता क कट्टर विधान और आर्थिक आवश्यकता के द्वारा अनु प्रेरित होकर लागू के बीच अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रिक इकाइया के बीच शत्रुता का मूजन करे जिससे बाजार का विस्तार और बच्चे माल के स्रोता की प्राप्ति जस उनके वर्गीय स्वार्थों की पूर्ति हो सके। समाजवादी आर्थिक आधार पर मगठित राष्ट्रिक इकाई स्वतंत्र समुदाय भाईचारे और सहयाग के लिए स्वच्छिक मघ क सदस्य होते हैं। इस तरह समाजवाद राष्ट्रों या राष्ट्रिक इकाइया म एक वग का दूसरे वग पर शासन नो समाप्त करता ही है साथ ही राष्ट्रों और राष्ट्रिक इकाइयो के बीच सहयाग का माग तयार करता है।

समाजवादी राष्ट्रीय अस्तित्व की स्थिति म ही अल्पमध्यको की समस्या का सपूर्ण हल मभव है। स्वतंत्र भारत म लोकतान्त्रिक संविधान अल्पमध्यका के नागरिक एव अन्य अधिकारों की सुरक्षा कर सकता है। लेकिन पिछडे हुए समाजों के पूँजीवादी आर्थिक विकास की स्थिति म उन देशों की युजुजाजी और पशेवर वग व्यापारिक एव औद्योगिक हिता और नौकरियों तथा पदा की अपनी लडाई म अपन संप्रदायों की जनता क जागरण का इस्तमाल करने का लोभ सवरण नही कर सकग। इससे देश म संप्रदायवाद एव सांप्रदायिक वितृष्णा और मघप का उदभव होना अवश्यभावी ह।

समाजवाद समाज के वग चरित्र का अंत कर युजुजाजी क अनुभागीय मघर्षों के उन्मूलन म भी सफल हाता है। यह राष्ट्रों और राष्ट्रिक इकाइया की ही तरह संप्रदायों के बीच भी गतिपूर्ण और सहयोगी संबंधों के लिए पथ प्रशस्त करता है।

राष्ट्रीय स्वतंत्रता राष्ट्रिक इकाइया के लिए आत्मनिर्णय का अधिकार समाजवादी आर्थिक व्यवस्था की स्थापना राष्ट्रिक इकाइया और

की समस्या के पूर्ण समाधान के लिए गर्ते आवश्यक थी ।

साम्राज्यवाद के विनाश के बाद भी, उन सामाजिक तत्वा पर विजय पान का सवाल रह जाएगा जो स्वाथ जीवन और सप्रदायवाद का जन्म देते ह । और यही समाजवाद समस्या के समाधान के रूप म सामने आता है । प्रजातन्त्र समाजवाद स जविच्छेद्य है । यही भारतीय पूजीवादियो और सामन्तवादियो से सघष का प्रारभ होता है । राष्ट्रजाति का प्रश्न हमारे सामाजिक अस्तित्व क प्रश्न स अलग नही । यह सामाजिक क्रांति की पूरक समस्या है । पूजी के आधिपत्य के प्रश्न से अलग कर इस पर विचार नही किया जा सकता ।<sup>74</sup>

## संदर्भ

- 1 देखें कार और मकाटनी ।
- 2 विटरनिज प० 6 ।
- 3 स्टालिन प० 8 ।
- 4 देखें मकाटनी जीर कार ।
- 5 स्तालिन प० 7 ।
- 6 कृष्ण प० 18 ।
- 7 देखें कार ।
- 8 देखें कृष्ण ।
- 9 देखें डब्ल्यू० सी० स्मिथ प० 1 ।
- 10 ग्रहम प० 58 ।
- 11 पदलेकर द पयचर आफ इस्नाम इन इडिया एशिया जिल 28 स० 11 (नवबर 1928) प० 874 म उद्धृत ।
- 12 आर पी० दत्त प 389 म उद्धृत ।
- 13 हटर प० 156 ।
- 14 डब्ल्यू० सी० स्मिथ प० 22 ।
- 15 विल्सन प० 188 ।
- 16 ग्रहम प० 178 ।
- 17 वही प० 273 मे उद्धृत ।
- 18 कृष्ण प० 97 म उद्धृत ।
- 19 देखें डब्ल्यू० सी० स्मिथ ।
- 20 वही प० 201 ।
- 21 बकन प० 244 ।
- 22 मालि प० 325 ।
- 23 देखें ए० भट्टा एड ए० पटवधन प० 82 ।
- 24 नान् आरिबियर न् टाइम्स को पत्र 10 जुलाई 1926 ।
- 25 कृष्ण द्वारा उद्धृत प० 90 ।

- 26 वही पृ० 314 ।
- 27 वहाँ प० 85 ।
- 28 वही प० 132 ।
- 29 वही प० 133 ।
- 30 वही प० 131 ।
- 31 वही प० 72 ।
- 32 साह भोमर प० 126 127 ।
- 33 डब्ल्यू० मी० स्मिथ प० 225 ।
- 34 इंडिया इन 1919 ।
- 35 कृष्ण प० 266 ।
- 36 ए० मेहता एड ए० पटवर्धन द्वारा उद्धृत प० 38 ।
- 37 पंडित जवाहर लाल नेहरू प० 86 ।
- 38 आर पी० दत्त प० 418 ।
- 39 कृष्ण प० 278 ।
- 40 वही प० 296 ।
- 41 दध पट्टाभि सीतारमया ।
- 42 ए० मेहता एड ए० पटवर्धन द्वारा उद्धृत प० 43 ।
- 43 लख अझारी टिब्यून 21 मार्च 1942 ।
- 44 मशरौकी डब्ल्यू० मी० स्मिथ द्वारा उद्धृत प० 278 ।
- 45 अलनाबकश टिब्यून 10 अक्टूबर 1942 ।
- 46 इन्डियाज प्रान्सम आफ हूर फ्यूचर नास्टिब्यूशन प० 103 ।
- 47 बकवान प० 10 ।
- 48 जिना प० 12 ।
- 49 वहाँ प० 13 14 ।
- 50 लखें अजरफ प० 78 79 ।
- 51 दखें फिशर प० 36 37 ।
- 52 वही प० 34-35 ।
- 53 लखें अजरफ प० 75 ।
- 54 वहाँ प० 92 83 ।
- 55 वही पृ० 93 ।
- 56 राजेंद्र प्रसाद पृ० 6-7 ।
- 57 दध राजेंद्र प्रसाद पृ० (2) प० 319 21 ।
- 58 दखें डा० नजीर शार जय पृ० 211 ।
- 59 वही पृ० 119 ।
- 60 लखें ए० मेहता एड ए० पटवर्धन प० 211 ।
- 61 वहाँ प० 213 ।
- 62 वही प० 219 ।
- 63 डा० आर० पा० पराज्ये डा० अजरफ द्वारा उद्धृत प० 64 65 ।
- 64 मर मी० मदनवाड डा० अजरफ द्वारा उद्धृत पृ० 6 ।
- 65 बा० डी० मावरकर डा० अजरफ द्वारा उद्धृत पृ० 40-41 ।
- 66 बी० डी० मावरकर डा० अम्बरकर द्वारा उद्धृत प० 135 ।
- 67 डा० अम्बरकर द्वारा उद्धृत प० 29 ।

- 68 डा० जम्बदकर प० 3० ।
- 69 वही प० 329 30 ।
- 70 वहा प० 337 38 ।
- 71 डा० जी० जधिकारी प० 36 ।
- 72 वहा प० 15 16 ।
- 73 वही प 4 ।
- 74 कृष्ण प० 346 47 ।

### भारत में राष्ट्रवाद के विकास के प्रमुख चरण

अपने इस अध्ययन में हमने देखा कि ब्रिटिश शक्ति का पारम्परिक क्रिया प्रक्रिया के फलस्वरूप भारतीय राष्ट्रवाद का उदय और विकास हुआ। हमने यहाँ इस बात की भी व्याख्या प्रस्तुत की है कि क्या प्राकृतिक ब्रिटिश भारत के आर्थिक और सामाजिक वातावरण में राष्ट्रीयता का उदय संभव नहीं था और नहीं हुआ। ब्रिटिश शासन काल के भारतीय समाज के आधारभूत आर्थिक रूपांतरण का भी हमने अभिचित्रित किया है, क्योंकि अमयुक्त भारतीय जनसमुदाय की राष्ट्र के रूप में एकाविति के लिए यह आर्थिक रूपांतरण अत्यंत आवश्यक था। भारतीय जनता के मयुक्तीकरण और उसके बीच राष्ट्रीय चेतना के प्रस्फुरण में जावागमन के आधुनिक साधना नई शिक्षा समाचारपत्रा आदि नए तथा क विशिष्ट अनुदान को भी हमने आका है।

भारतीय राष्ट्रवाद के विकास के कई चरण थे। जैसे जैसे यह एक चरण से दूसरे चरण की तरफ बढ़ा इसका सामाजिक आधार भी अधिक व्यापक होता गया, इसके लक्ष्य अधिकाधिक माहसिक हुए और अधि र स्पष्टता से परिभाषित हुए और यह विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त हुआ। भारत और सारे विश्व में विभिन्न शक्तियों के विकास के फलस्वरूप भारतीयों में अधिकाधिक तादाद में राष्ट्रीय चेतना और दृष्टि अपनाई और राष्ट्रीय आंदोलन की वृद्धि में आए। राष्ट्रीय जीवन के सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक, हर क्षेत्र में यह राष्ट्रीय जागरण परिलक्षित हुआ।

हम यह भी देख चुके हैं कि नए वर्गों ने जो नए अवसर के फलस्वरूप पदा हुए थे और एक ही राज्य सत्ता के अधीन रहे रहे थे, अपने युग की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में अपना मुक्त और पूर्ण विकास अवरोध पाया और इसलिए अपने विकास के रास्तों के अवरोधों का हटाने के लिए उन्होंने अपने अंगित भारतीय संगठन बनाए और आंदोलन किए। इस दरम्यान इन बातों के फलस्वरूप भी भारतीय जादानन विकसित होता रहा और उसमें अधिकाधिक शक्ति आती गई।

### प्रथम चरण

भारतीय राष्ट्रवाद के विकास के प्रथम चरण में इसका सामाजिक आधार अत्यंत मकीन था। उन्नीसवीं सदी के प्रथम दशकों में जंग्रेजा द्वारा भारत में स्थापित शिक्षण संस्थाओं में जिन्हें शिक्षा मिली और जिन्होंने पाश्चात्य संस्कृति के प्रजातान्त्रिक और राष्ट्रवादी विचारों को आत्मसात किया उन बुद्धिजीवियों में राष्ट्रीय चेतना और महत्वाकांक्षा का सबसे पहला विकास हुआ। राजा राममोहन राय और उनके साथी प्रबुद्ध भारतीयों ने भारतीय राष्ट्रवाद के हरावत दस्ते का काम किया। वे भारतीय राष्ट्र की धारणा के प्रतिपादक थे और उन्होंने जनसाधारणों को बीच इस धारणा का प्रचार किया। उन्होंने समाज और धर्म सुधार के जादालन चलाए जो प्रजातंत्र बुद्धिवाद और राष्ट्रीयता जादिए नए सिद्धांतों के आधार पर भारतीय समाज और धर्म के पुनर्निर्माण के प्रयास थे। वस्तुतः ये जादोलन भारतीय जनता के ही एक भाग की उदीयमान राष्ट्रीय प्रजातान्त्रिक चेतना के प्रतीक थे। भारतीय राष्ट्रवाद के इन प्रथम योद्धाओं ने प्रेस की स्वतंत्रता जैसे प्रजातान्त्रिक अधिकारों का समर्थन किया और माग की कि देश के प्रशासन में देश के लोगों का भी हाथ रहे।

### दूसरा चरण

भारतीय राष्ट्रवाद के विकास का प्रथम चरण 1885 तक रहा और उस माल इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना में इसकी चरम परिणति हुई। दूसरे चरण की अवधि थोड़ा मोटी तौर पर 1885 में 1905 तक रही। इस अवधि में कांग्रेस और राष्ट्रीय जादोलन का नतृत्व उदारवादी बुद्धिजीवियों के हाथ में था। उनकी चिंतन पद्धति और कार्यक्रमों में ही इस जादोलन के कार्यक्रम और स्वरूप का निर्माण हुआ और इनमें भारत के विकासमान, पूँजीवादी समाज के हितों का प्रतिफलन हुआ। इस काल में व्यापारी वर्ग के कुछ भाग और शिक्षित मध्यम वर्ग के लोग राष्ट्रवादी जादालन की परिधि में आए। उन्नीसवीं सदी के अन्त तक दशों और विदेशी व्यापार के विस्तार के परिणामस्वरूप व्यापारी वर्ग और उसी तरह आधुनिक शिक्षा के प्रसार के फलस्वरूप शिक्षित मध्य वर्ग काफी विकसित हो चुका था। आधुनिक उद्योग धंधों के उदभव और विकास के कारण उद्योग पतियों का वर्ग पैदा हुआ और उसकी ताकत भी बढ़ती गई। ये कांग्रेस की तरफ जाने लगे और कांग्रेस ने देश के उद्योगीकरण का कार्यक्रम अपनाया और 1905 में स्वदेशी आदालन चलाया।

उदारवादियों के नतृत्व में कांग्रेस ने मुख्यतः शिक्षित वर्गों और व्यापारी वर्ग की मागों को आग बढ़ाया जैसे नौकरियों के भारतीयकरण की माग, राज में प्रशासन तंत्र में भारतीयों की महभागिता की माग, पूँजी के बहिर्गमन पर रोकथाम की माग, इत्यादि। इनमें प्रतिनिधि मन्धयंत्रों की स्थापना और नागरिक

स्वातन्त्र्य जैसे सवाल भी उठाए। सघप के जो तरीके अपनाए गए उन पर भी उदारवादी धारणाओं का प्रभाव स्पष्ट था। उन्हें सांविधानिक जादोलन, कारगर बहस, ब्रिटिश जनता की प्रजातांत्रिक विवेक वृद्धि और परंपराओं पर भरोसा था।

अंग्रेजी सरकार ने भारत के राष्ट्रीय जादोलन की महत्वपूर्ण मागा का आदर नहीं किया। फलस्वरूप उदारवादियों की विचारधारा और कायपद्धति में राष्ट्रवादियों के कुछ अंशों की जास्था समाप्त हो गई, और कांग्रेस के भीतर ही नए जीवन दशन, नई राजनीतिक विचारधारा और सघप के नए तरीकों के आधार पर नए दल का सजन हुआ।

ब्रिटिश शासन काल की सामाजिक प्रशासनिक स्थिति में सबको रोजगार मिलना जनभव था, अस्तु शिक्षित मध्य वर्ग में नौजवानों में वरोजगार की तादाद बढ़ती गई। उन्नीसवीं सदी के अंत में विनाशकारी दुर्भिक्ष और महामारी के कारण लोगों की तकलीफें बतरह बढ़ी। इस तरह कांग्रेस में जन्मे इन नए अतिवादी दल के प्रचार प्रसार के लिए जमीन तैयार हुई। लाड कजन के शासन काल में सरकार द्वारा किए गए अप्रिय कार्यों जैसे, वर्ग विभाजन और इंडियन युनिवर्सिटीज एक्ट, के कारण लोग सरकार से और अधिक विमुख हुए। राजनीतिक दृष्टि से चतुर्थ मध्य वर्ग के लोग अतिवादी, गरम दल के लोगों के इद गिद आन लगे। तिलक, अरविंद घोष वी० सी० पाल और लाजपत राय इस दल के नेता थे। 1905 तक कुछ उदारवादी लोग भी ब्रिटिश सरकार में अपनी जास्था खोने लगे थे। लेकिन न ता उन्होंने अपने जीवन दशन का ही परित्याग किया और न सघप मरघी अपनी कायनीति का ही। अतिवादियों की विचारधारा मूलतः उदारवादियों की विचारधारा से उलटी थी। उदारवादियों का यह घोर विश्वास था कि भारत का प्रगतिशील सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक उत्थान ही ब्रिटेन का लक्ष्य था अतिवादियों के अनुसार ब्रिटेन भारत का गुलाम बनाए रखने और उसके आर्थिक शापण का इच्छुक था। फिर, उदारवादियों ने पाश्चात्य ससृति का गुणगान किया लेकिन अतिवादियों ने भारत के अतीत और उसकी पुरातन ससृति की गौरव गाथा गाई और उन्हें पुनर्जीवित करना चाहा।

ब्रिटिश प्रजातंत्र से अनुराध और आग्रह के द्वारा राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने की उदारवादी काय पद्धति से भी अतिवादियों की कोई जास्था नहीं थी। इसके विपरीत उनका घ्याल था कि मागा की पूर्ति के लिए बाधकाट आगे नन जस गैर ससदीय आदालन के जरिए सरकार पर दबाव डालन की जरूरत थी। ये प्रशासकीय सुधार स ही मतुष्ट हाने वाले नहीं थे। उन्होंने स्वशासन की माग की जिसका 1906 में उदारवादियों ने भी समचन किया।

राष्ट्रीय जादोलन के दूसरे चरण में राजनीतिक अमताप आतंकवादी जादालन के रूप में प्रस्फुटित हुआ। कुछ राष्ट्रवादी नययुवक आतंकवादी दलों में नाश्रिज हुए और उन्होंने राजनीतिक म्वतघता के लिए अपमरा का हत्या और यदा यदा सना में छोटी-मोटी बागत के तरीके का सहारा लिया।

### तीसरा चरण

राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण 1905 से 1918 तक चला। आंदोलन के इस चरण में उदारवादियों की जगह जतिवादी नेतृत्व में आए। सरकार की दमनात्मक कारवायों के बावजूद, राष्ट्रीय आंदोलन विकासशील रहा। जतिवादियों के राजनीतिक प्रचार के फलस्वरूप लोगों में राष्ट्रीय आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की भावना जगी। उदारवादियों के कथनानुसार राजनीतिक स्वातंत्र्य के लिए अंग्रेजों पर निर्भर रहने के बदले अब लोग स्वयं अपनी शक्ति पर भरोसा करने लगे। लेकिन आंदोलन की यह एक बहुत बड़ी कमजोरी थी कि इसके नेताओं ने इसे पुनर्जाँवित हिंदू दशन पर आधारित करने की कोशिश की। इससे चलते कुछ हद तक आंदोलन में रहस्यवादी रूप इच्छित्यार कर लिया और इसका गर धार्मिक स्वरूप कमजोर हुआ। फलस्वरूप मुसलमानों पर इसका बहुत प्रभाव नहीं पड़ सका।

तीसरे चरण में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने जुझारू और चुनौतीपूर्ण रूप लिया और निम्न मध्य वर्ग में इसमें बढ़त हुए प्रभाव के कारण इसका सामाजिक आधार पहले से अधिक व्यापक हुआ। युद्ध के दिनों में होमरूल आंदोलन के कारण लोगों में राजनीतिक चेतना और सबल हुई। इसी काल में उच्चवर्गीय मुसलमानों में राजनीतिक चेतना आई और उन्होंने 1906 में अपने राजनीतिक मगठन, मुस्लिम लीग की स्थापना की। कई कारणों से उच्च और मध्य वर्गीय मुसलमानों की उदीयमान राजनीतिक चेतना का स्वरूप सांप्रदायिक या जिनके फलस्वरूप उनके मगठन का आधार सांप्रदायिक था।

### चौथा चरण

भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के विकास का चौथा चरण 1918 में शुरू हुआ और माटा मोटी तौर पर 1930-34 के नागरिक अंग्रेजों के आंदोलन तक रहा। इस काल का एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि राष्ट्रीय आंदोलन को व्यापक जन आधार मिला और इसमें प्रत्यक्ष जन आंदोलन के हथियार का इस्तेमाल करना शुरू किया। अभी तक राष्ट्रीय आंदोलन मुख्यतः उच्च और मध्य वर्ग तक ही सीमित था, अब यह तब तक से भारतीय जनता के बीच फैला।

प्रथम विश्वयुद्ध के ठीक बाद के वर्षों में कई कारणों से भारतीय जन आंदोलन में राष्ट्रीय चेतना का आविर्भाव हुआ। युद्धोत्तर जायिक मकट सरकारी वादा खिलाफी के कारण हुए मोहभंग और बलती हुई दमनात्मक कारवायों आदि का किसानों, मजदूरों पर भी गहरा असर पड़ा और वे काफी आंदोलित थे।

यूरोप में कई दशकों में हुई प्रजातान्त्रिक आतिया और रुत में हुई ममाजवादी नाति जैमी महान अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के कारण भारतीय जनता की राजनीतिक चेतना में स्पष्ट विकास हुआ था। प्रथम विश्वयुद्ध के दिनों में होमरूल आंदोलन



के कारण भी लोगो में राजनीतिक चेतना का विस्तार हुआ था और उसमें तीव्रता आई थी। सेत्र की मधि के कारण भारतीय मुसलमानों में बड़ा क्षोभ था और इस तरह मयुक्त राष्ट्रीय जन आंदोलन के लिए पृष्ठभूमि तैयार थी।

लड़ाई के दिनों के औद्योगिक विकास के फलस्वरूप भारतीय पूँजीपति आर्थिक दृष्टि से सशक्त हो चुके थे। उन्होंने भी पहले की अपेक्षा अधिक तत्परता से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन का समर्थन किया। कांग्रेस द्वारा दिए गए स्वदेशी और बायकाट के नारा से तथ्यत उद्योगपतियों की स्वाथ सिद्धि हो रही थी और उन्होंने स्पष्ट-पैसे में उनकी मदद की। वग सामाजिक और सामाजिक शांति के गांधीवाणी सिद्धांत और 1919 के कलकत्ता कांग्रेस में स्वदेशी के प्रस्ताव के गांधी द्वारा समर्थन के फलस्वरूप अब भारतीय बुजुर्गों के कुछ जगो ने कांग्रेस और गांधी के नतृत्व में मगठित राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन करना शुरू कर दिया। 1918 के बाद भारतीय औद्योगिक बुजुर्गों कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कार्यक्रम बायनीति युद्ध और रण नीति आदि से निर्धारण में सशक्त भूमिका अदा करने लगी।

इस युग में देश में समाजवादी और साम्यवादी दलों का भी उदय शुरू हुआ। 1928 के आसपास ये दल मग सघष के सिद्धांत पर आधारित स्वतंत्र राजनीतिक और ट्रेड यूनियन आंदोलन शुरू करने में मफल हो चुके थे। व देश में समाजवादी राज्ज की स्थापना के पक्ष में थे और उन्होंने ही राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य माना। असहयोग आंदोलन में जिन राजनीतिक चेतना मपन मजदूरों में भाग लिया था, उनका अपना कोई स्वतंत्र मगज्जय कार्यक्रम नहीं था। तबिन 1926 के बाद तिन मजदूरों ने साइमन कमिशन के बायकाट जन आंदोलन में भाग लिया था उनके अपने तारे थे उनका अपना जलग बड़ा था और अकार उनके अपने नेतामण थे। इस तरह मजदूर मग न राष्ट्रीय आंदोलन में स्वतंत्र राजनीतिक इकाई के रूप में प्रवेश किया। राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में यह एक नई बात थी।

इसी काल में कांग्रेस ने अपरिभाषित स्वराज के बदन म्मतव्रता का अपना लक्ष्य बनाया। बहुत सारे यूव और इन्डिपेंडेस लीगा का जन्म हुआ और उन्होंने भी स्वतंत्रता को ही अपना लक्ष्य माना। तबिन इन घटनाओं के तार ताय प्रति क्रियावादी, सांप्रदायिक शक्तियां न भी अपने मगठन बनाने शुरू किए और इन कान में नई सांप्रदायिक दगे हुए। राष्ट्रीय आंदोलन के इस चरण की चरम परिणति हुई 1930-34 के नागरिक अवना आंदोलन में जिन तायम न गांधी ने नतृत्व में मगठित किया था। भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास में यह दूबरा जन-आंदोलन था।

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इस चरण में म्गत तीर पर ये पायल हुए, इन आंदोलन का आचार अधिष्ठ व्यापक हुआ, स्वतंत्रता का म्मतव्रता बनाया, स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति के रूप में मजदूरों का आंदोलन मग

और इन्डिपेंडेंस लीगो का ज म हुआ और किसानो ने बडी तादाद म जादालन म भाग लेना शुरू किया। जादोलन म निम्नांकित वाता ने ज्वरोधक का काम किया गांधी न धर्म और राजनीति का जो समन्वय करना चाहा, उसके कारण राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रीय आंदोलन म ध्रुवलापन और उलझाव आए, कांग्रेस संगठन पर पूजापतिया का जोर बढा और इसके फलस्वरूप कांग्रेस के कार्यक्रम और कायनीति म ऐसे मशोधन हुए जिनसे राष्ट्रीय प्रगति के बदले उनके वर्गीय स्वार्थों की सिद्धि अधिक होती थी, सांप्रदायिक भावना म तजी आई।

### पाचवा चरण

राष्ट्रीय आंदोलन के अगल चरण की अवधि थी 1934 से 1939 तक, अर्थात् द्वितीय विश्वयुद्ध की शुरुआत तक। इस काल म कुछ नई बातें हुई। गांधीवादी विचारधारा कार्यक्रम और कायनीति म कुछ कांग्रेसियो की आस्था खतम हो गई और उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। यह पार्टी वग क आधार पर किसान और मजदूरा के संगठन के पक्ष म थी, जार इमने उह ही राष्ट्रीय आंदोलन की अभिप्रेरक शक्ति बनाना चाहा। लेकिन यह पार्टी विपमवर्णी थी और इसम ऐसे लोग थे जो विभिन्न कारणों से गांधीवाद से अलग हुए थे और जिनका सामाजिक आधार निम्न बुजुआ था। गांधीवाद से भिन्न, उससे अलग कुछ अन्य प्रवृत्तिया का भी ज म हुआ जस सुभाष बोस के नेतृत्व म फारवर्ड ब्लाक। इस काल म दलित जातिया का आंदोलन लगातार बढता रहा। मुस्लिम लीग भी इस दौर म संगठनात्मक और राजनीतिक दृष्टि से पहल की अपेक्षा सुदृढ हुई। फिर राष्ट्रीय और सांप्रदायिक किस्म के कई अन्य मुस्लिम संगठना का भी इस काल म उदय हुआ।

इस दौर म कम्युनिस्ट पार्टी का तजी से विकास हुआ और छात्रा, मजदूरा और किसानो म लगातार इसका प्रभाव बढता रहा। साथ ही इस काल म किसानो के आंदोलन भी तजी से बढे। अधिकाधिक किसानो म राष्ट्रीय और वर्गीय चेतना का उद्भव और विकास हुआ। उनके अपने संगठन बने, उनके अपने नेता सामने आए, उनके अपने कार्यक्रम और नारे थे और उनका अपना झण्डा था। अतएव राजनीतिक तौर पर जागरूक किसान कार्यक्रम के नेतृत्व म थे, जत्र इनकी बहुत बडी तादाद ने अपने वग की मांगो को सामने रखना शुरू किया। इन लोगो ने जमींदारी और ऋणग्रस्तता के उन्मूलन की मांग की। आल इंडिया किसान सभा ने जागरूक किसानो को एकजुट किया और इसने भारत म ममाजवानी राज्य की स्थापना का लक्ष्य सामने रखा। इमने किसानो के स्वतंत्र संघर्षों का संगठन किया और राष्ट्रीय आंदोलन म स्वतंत्र इकाई के रूप म भाग लिया।

इस काल म भारतीय रियासतो की जनता के प्रजातान्त्रिक आंदोलन का भी विकास हुआ। इन रियासतो की जनता ने राज्य के एकाधिकार के उन्मूलन, प्रतिनिधि मस्थापना, नागरिक अधिकार आदि की मांग की। इन रियासतो के

आंदोलनो पर मूलतः वहाँ के व्यापारियों का कब्जा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इन आंदोलनों का समर्थन किया और उन्हें मदद की।

इस दौर में भारत की विभिन्न राष्ट्रिक इकाइयों में भी राजनीतिक चेतना का उद्भव और विकास हुआ। उन्होंने भाषा के आधार पर प्रांतीय पुनर्गठन की मांग की। आंध्र, उड़ीसा, कर्नाटक आदि प्रदेशों के लोगों में नए जीवन का संचार हो चुका था और वे भाषा के आधार पर स्पष्ट राजनीतिक और प्रशासनिक इकाइयों के रूप में एकांकित होना चाहते थे।

स्वतंत्र किसान आंदोलन का उदय, समाजवादी गतिविधियों का विकास, नवजागत राष्ट्रनीतियों के आदान-आदान और ऐसी-वैसी बातें अभी भी राष्ट्रीय आंदोलन में संभव, निर्णायक स्थिति नहीं प्राप्त कर सकी थी। राष्ट्रीय आंदोलन पर अब भी गांधीवादी जीवन दर्शन और गांधी के नेतृत्व का बोलबाला था। अभी भी वह मूलतः पूँजीपतियों और अन्य उच्चवर्गीय लोगों के हितों की ही रक्षा कर रहा था।

फिर भी नए आंदोलनों का इंडियन नेशनल कांग्रेस पर असर पड़ने लगा था। इसके फलस्वरूप इसमें मौलिक अधिकारों का कार्यक्रम बनाया जिसमें नागरिक अधिकारों की सुरक्षा प्रदान की गई और मजदूरों और किसानों के हितों की पूर्ति का आश्वासन दिया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो देश की सबसे महत्वपूर्ण समस्या थी और जिसके हल में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व था, जागत राष्ट्रजातियों की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जागरूकताओं को मायता दी। यह सांस्कृतिक स्वायत्तता और भाषाधार प्रांतों के निर्माण के पक्ष में थी। उसने यह भी माना कि भाषा के आधार पर संगठित प्रांतों के लोगों का अगर वे चाहें भारतीय मध्य से अलग होने का भी हक होगा।

लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले विभिन्न सामाजिक वर्गों में परस्पर इस बात की होड़ लगी रही कि इस आंदोलन का नेतृत्व किसके हाथों में हो। मजदूर, किसान मध्य वर्ग के वामपंथी लोग जैसे-जैसे राजनीतिक तौर पर जागरूक और सचेत एवं संगठनात्मक तौर पर संभव हुए वैसे-वैसे उन्होंने कांग्रेस पर अपना प्रभाव डालना शुरू किया, जो अब तक पूँजीपति वर्ग के नियंत्रण में थी। जागत राष्ट्रजातियों भी अधिकाधिक ताकत से यह मांग कर रही थी कि उनके स्वतंत्र और पूर्ण विकास के रास्ते में जो अवरोध है उन्हें समाप्त किया जाए।

### परिप्रेक्ष्य

बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना के साथ नई सामाजिक गतिविधियों ने राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश किया और उन्होंने नेतृत्व पर हर तरह के दावों को डाला लेकिन इससे यह आंदोलन दुर्बल नहीं हुआ। बल्कि इससे चलते-चलते राष्ट्रीय आंदोलन में और अधिक गतिशीलता आई। जान-बूझकर भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व मूलतः पूँजीवादी वर्ग के हाथों में रहना या नए सामाजिक वर्गों के हाथों में

म चला जाएगा और इस तरह इन वर्गों के स्वार्थी और हितो और अल्पमध्यका और राष्ट्रिक इकाइया की सांस्कृतिक और जया य आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेंगा, यह बहुत कुछ भारत और विदेश में होने वाली घटनाओं पर निर्भर करेगा और निर्भर करेगा इस बात पर कि इन वर्गों और दलों का सामाजिक सतुलन कैसा है, उनका भाव वाद और उनकी संगठनात्मक शक्ति कैसी है।

इस प्रसंग में हम युद्ध के दिनों में प्रकाशित इस पुस्तक के प्रथम संस्करण में दिए गए पूर्वानुमान का उद्धृत करना चाहेंगे

भारत के पूँजीपति वर्ग न द्वितीय विश्वयुद्ध के काल में अपनी शक्ति में काफी वृद्धि कर ली है। इनका नेतृत्व ऐसे अनुभवी और कुशल राजनीतिज्ञों के हाथ में है जिनमें अतीव राजनीतिक और रणनीतिक योग्यता है। इनके विपरीत भारत के नवजागत निम्न तबकों के लिए सांस्कृतिक तौर पर पिछड़े हुए हैं। उनमें संगठनात्मक शक्ति और राजनीतिक चतना का अभाव है। उनका नेतृत्व जिन लोगों के हाथ में है वे राजनीतिक दृष्टि से उतने महान और अनुभवी नहीं हैं। इस वजह से इस बात की बहुत अधिक सम्भावना है कि ठीक इसका वाद वाल चरण में भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन पर पूँजीपति वर्ग का दबाव रहेगा और यह उसी वर्ग का हित साधन करेगा।

भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन के विकास की यह दिशा मोटा मोटी तौर पर अंकित की जा सकती है।

इस विकास का एक प्रमुख लक्षण यह होगा कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद इस बदली हुई परिस्थिति में और अधिक व्यापक पैमाने पर रियासतों और प्रतिभोतों की नीति का अनुकरण करेगा जिसमें निहित स्वार्थों के अधिकाधिक लोग उसका समर्थन करें और उनमें अधिक से अधिक प्रतियोगिता बढ़े जिसका उसे फायदा मिल सके। इसके चलते इन वर्गों में लड़ाई और अधिक तीव्र होगी और संप्रदायवादी एवं अंतर्प्रतीय शक्तियाँ बढ़ेंगी।

इस विकास का एक अन्य लक्षण यह होगा कि निहित स्वार्थों के नेता आवादी के निम्न तबकों के जन आंदोलनों का विरोध करेंगे या ब्रिटिश साम्राज्यवाद एवं अपने देशों विदेशी प्रतियोगिता से रियासतों के लिए इन आंदोलनों का उपयोग करेगा, या फिर उनका विघ्न करने का भी प्रयास करेगा।

संविधानवाद घनघोर साम्प्रदायिकता, बड़ी हुई अंतर्प्रतीय हाड़ बढ़ते हुए जन आंदोलनों का विरोध या उनका रूप भंग, भारतीय इतिहास के अगले चरण के प्रमुख तथ्य होंगे।

## प्रथ सूची

### सामान्य

- अधिकारी, जी० पाकिस्तान एंड यूनिटी (1944)  
आगा खा, इंडिया इन ट्राजिशन (1918)  
अहमद, जेड० ए०, दि अग्रेरियन प्राब्लम इन इंडिया (1936)  
अय्यर, सर पी० एस० एस०, इंडियन कास्टिट्यूशन प्राब्लम (1928)  
अल्टेवर ए० एस० हिस्ट्री आफ विलेज कम्युनिटीज इन इंडिया (1926)  
अम्बेदकर वी० जार० 1 थाटस आन पाकिस्तान (1941)  
2 कास्टम इन इंडिया (1917)  
3 अनाहिलेशन आफ कास्ट (1936)  
एडूज एंड मुखर्जी दा राइज एंड ग्रोथ आफ द कांग्रेस (1938)  
ऐस्टी, बेरा दि इकनामिकल डेवलपमट आफ इंडिया (1937)  
जाथर, सर जी० लाइफ आफ लाड विचनर (1920)  
जशरफ क० एम० (सपा०), पाकिस्तान (1940)  
जायगर एस० क०, एशियट इंडिया एंड द साउथ इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर (1941)  
बडन पावेल, लड सिस्टम आफ ब्रिटिश इंडिया (1882)  
बनर्जी, डी० एन० अर्ली लड रेवन्यू सिस्टम इन बेंगाल एंड विहार (1936)  
बनर्जी सर सुरेन्द्रनाथ स्पीचेज एंड राइटिंग्स  
बरकतुल्ला मुहम्मद दि विलाफन (1922)  
बाकर सर जर्नेस्ट, 1 नेशनल करेक्टर (1927)  
2 आइडिआज एंड आइडियल्स आफ द ब्रिटिश एम्पायर (1941)  
3 रिफरन्स जान गवर्नमट (1942)  
वान्स एच० ई०, 1 सासायटी इन ट्राजिशन (1940)  
2 मानिआनजी एंड पोलिटिकन थियरी (1925)

- वानेस, लेनाड, 1 एम्पायर जाग डेमानेसी (1939)  
2 सोवियट लाइट आन द कालनीज (1944)
- वास, मारगरिटा 1 दि इंडियन प्रेस (1940)  
2 इंडिया टुडे एंड टुमारो (1937)
- वसु, मेजर वी० डी० 1 द रुइन आफ इंडियन ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज (1935)  
2 द राइज आफ क्रिश्चियन पावर इन इंडिया (1931)  
3 इंडिया अंडर द ब्रिटिश क्राउन (1933)
- व्यूकप, जोन, ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म इन इंडिया (1935)
- वेन ए० डब्ल्यू०, अ हिस्ट्री आफ माडन फिलासफी (1933)
- वेमेट, एनी हाउ इंडिया राट फार फ्रीडम (1915)
- ववन, एडविन, इंडियन नेशनलिज्म (1913)
- वाल्टस, विलियम कसिडरेशस जान इंडियन अफेयस (1772)
- वास मुभाप चद्र, दि इंडियन स्ट्रगल (1934)
- व्रेल्सफोड, एच० एन०, सञ्जक्ट इंडिया (1943)
- व्रिफाल्ट, रायट द डिक्लाइन एंड द फाल आफ द ब्रिटिश एम्पायर (1938)
- वृजनारायण, इंडिया इन द क्राइसिस (1935)
- ब्रुकस, ऐडम्स द ला जाफ भिविलाइजेशन एंड डिफे  
त्राइस, जेम्स माडन डेमानेसीज (1921)
- ववन, जे० लाड मिटो
- वक, एम० ए०, 1 राइज एंड ग्रोथ जाफ इंडियन लिबरलिज्म (1938)  
2 राइज एंड ग्रोथ आफ इंडियन मिलिटेंट नेशनलिज्म  
(1940)  
3 राइज एंड ग्रोथ आफ इंडियन नेशनलिज्म (1939)
- व्युकैनन डी० एच०, द डेवलपमंट आफ कपिटलिस्ट इटरप्राइज इन इंडिया  
(1934)
- वर्जेस, जेम्स द क्रोनोलजी जाफ माडन इंडिया (1913)
- कैलवटन वी० एफ०, दि अवेर्निंग आफ अमेरिका (1939)
- कार, इ० एच०, (चेयरमन, स्टीट ग्रुप) नेशनलिज्म (1939)
- काडवेल, सी०, स्टडीज इन अ डाइग कल्चर (1938)
- चौधरी, एन० सी०, डिफेंस जाफ इंडिया (1935)
- चितामणि, सी० वाई०, इंडियन पालिटिक्स सिन द म्युटिनी (1937)
- चिरोल, वी०, 1 इंडियन अनरस्ट (1910)  
2 इंडिया (1926)
- चुदगर, पी० एल०, इंडियन प्रिसेज अंडर ब्रिटिश प्रोटक्शन (1929)
- कांग्रेस प्रेमिडेशियल एड्रेसज (1935)
- काटन, सर हनरी, न्यू इंडिया आर इंडिया इन ट्रांजिशन (1904)

- कूपलड, रेजिनाल्ड, द वास्टिटयूशनल प्राब्लम इन इंडिया (1944)
- कनिंगम, डब्ल्यू०, ग्रोथ आफ इगलिस कामम एंड इडस्ट्राज इन माडन टाइम्स (1882)
- डालिग, एम० एल० 1 द पजाब पेजेट इन प्रास्पेरिटी एंड डेब्ट (1925)  
2 रस्टिक्स लोकिटर (1930)
- दास, सी० आर० 1 स्पीचेज  
2 इंडिया फार इंडियस (1921)
- दास, आर० के०, द लेबर मूवमेण्ट इन इंडिया (1923)
- दत्त, डी०, लडलार्डिज्म इन इंडिया, (1931)
- डिग्वी, डब्ल्यू०, प्रास्परस ब्रिटिश इंडिया (1902)
- डाव एम०, एन आउटलाइन आफ यूरोपियन हिस्ट्री, (1925)
- डाना, डब्ल्यू० आर, द हिस्ट्री एंड ला आफ सेडीशन
- दत्त, आर० सी०, इकनामिक हिस्ट्री आफ ब्रिटिश इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल (1901)
- दत्त, आर० पी०, इंडिया टु डे (1940)
- दत्त, सुकुमार, द प्राब्लम आफ इंडिया नशनलिटी (1926)
- एडिब, हैलिड, इनसाइड इंडिया (1937)
- एडवड स एंड मेरिवेल, लाइफ आफ सर हनरी लारेंस (1872)
- एगोल्स, एफ०, पेजट वार इन जमनी
- एजेकेल, आइ० ए०, स्वराज आर सरडर (1931)
- फेदरस्टन, एच० एल० अ सेंचुरी आफ नेशनलिज्म (1939)
- फिशर, लुई, अ वीक विद गांधी (1943)
- फाक्स, रेलफ, कलोनियल पालिसी आफ ब्रिटिश इपीरियलिज्म (1933)
- गाडगिल, डी० आर०, दि इंडस्ट्रियल इवोल्युशन आफ इंडिया इन रीगॅट टाइम्स (1933)
- गांधी, देवदास, (मपा०) इंडिया जनरिकसाइलड (1943)
- गांधी, एम० के० 1 आटोबाजाग्रफी (1940)  
2 स्पीचेज एंड राइटिंग्स  
3 सत्याग्रह (1935)
- गरेट, जी० टो०, ऐन इंडियन कामट्री (1930)
- घोष ए० के०, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया (1930)
- घोष, अरविंद, बाल गंगाधर तिलक (1919)
- घोष, एन० एन०, त्रिस्टोदास पाल (1887)
- घुर्गे, जी० एस०, कास्ट एंड रस इन इंडिया (1932)
- गिलफ्राइस्ट, आर० एन०, इंडियन नेशनलिटी (1930)
- गान्धे, जी० के०, स्पीचेज (1920)

## 3 वावे प्लैन, अ क्रिटिसिज्म (1945)

- मेहता, ए० एड पटवधन, ए०, द कम्युनल ट्रेगल इन इंडिया (1942)  
 मेहता, जे० एम०, अ स्टडी आफ रूरल इकानमी आफ गुजरात  
 मेनन, लक्ष्मी एन०, द पोजीशन आफ वीमन (1944)  
 मिल, जेम्स, हिस्ट्री आफ ब्रिटिश इंडिया (1848)  
 मिशेल केट, इंडिस्ट्रियलाइजेशन आफ द वेस्टन पैसिफिक (1942)  
 मिना एन० एन० (सपा०), इंडियन ऐनुअल रजिस्ट्रम  
 मुहम्मद नामान, मुस्लिम इंडिया (1942)  
 मोटेग्यु इ० एस० ऐन इंडियन डायरी (1930)  
 मुखर्जी राधा कुमुद, फडामटल यूनिटी आफ इंडिया (1926)  
 मोरलड, डब्ल्यू० एच०, अग्रेरियन मिस्टम आफ मुस्लिम इंडिया (1929)  
 मार्शल, जान, रिकलेक्शन, जिल्द II (1918)  
 मारिसन, थियोडार दि इकनामिक ट्राजिशन इन इंडिया (1914)  
 मुखर्जी, राधा कमल लड प्रान्स् इन इंडिया (1933)  
 मुखर्जी, डी० पी०, माडन इंडियन कल्चर (1942)  
 मुलर, मैकम, बिजोर्ग्रेफिकल एसज (1884)  
 मुस्तफा, खा, ऐन अपालजी फार द यू लाइट (1891)  
 नीरोजी, दादाभाई 1 स्पीचेज एंड राईटिंस् (1910)

## 2 पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया (1876)

- नैश वी, द ग्रेट फेमिन (1900)  
 नटराजन, एम० एस०, फेमिन (1944)  
 नटराजन, एस०, सोशल प्रान्स् (1942)  
 नजीर, यार जग (सपा०), द पाकिस्तान ईमू (1943)  
 नेहरू, जवाहरलाल, ऐन आटोबाओग्रफी (1936)  
 नेहरू, मोतीलाल, (अध्यक्ष), नेहरू कमेटी रिपोट (1928)  
 नेहरू रामेश्वरी द हरिजन मूवमट (1940)  
 नेहरू श्यामकुमार, (सपा०) अवर काज  
 नेहरू, एस० एस०, कास्ट एंड क्रेडिट इन अ रूरल एरिया (1942)  
 नरुल्ला, सयद एंड नायक, जे० पी०, हिस्ट्री आफ एजुकेशन इन इंडिया  
 (1943)  
 ओक्शाट, एम०, द सोशल एंड पोलिटिकल डिकट्रस आफ वटेम्पररी  
 यूरोप (1939)  
 ओ' मली (सपा०,) माडन इंडिया एंड द वस्ट (1941)  
 पालवी० सी० 1 द न्यू स्पिरिट (1907)

## 2 मेमरिज आफ माइ लाइफ एंड टाइम्स (1932)

- पलेयर एम० ए० ट्रेड आफ इंडिया (1943)



- पराजपे, एम० आर० अ मोस बुक आफ माडन इंडियन एजुकेशन (1938)  
 पराजपे, आर० पी० द रुक्स आफ दि इंडियन प्रब्लम (1931)  
 परूलेकर, आर० वी०, लिटरेरी इन इंडिया (1940)  
 पजावी', द कानफेडरेसी आफ इंडिया  
 पर्सेल एंड ह्याल्सवथ रिपोर्ट आन लेबर कंडिशन इन इंडिया (1928)  
 पर्डी, एम० जी०, द साउथ अफ्रिकन इंडियन प्रब्लम (1943)  
 राजेंद्र प्रसाद, 1 पाकिस्तान (1940)  
 2 इंडिया डिवाइडेड (1946)  
 रामचंद्र राव, पी० आर०, डिकू आफ इंडियन इंडस्ट्रीज (1935)  
 रानाडे एम० जी० एसेज आन इंडियन इकनामिक्स (1898)  
 रगायर, सी० एस०, इंडिया इन द फुसिब्ल (1928)  
 रगा, एन० जी० 1 किसान स्पीक्स (1937)  
 2 द माडन इंडियन पजट (1936)  
 3 पेजेंटम एंड काग्रेस (1938)  
 4 किसान हडबुक (1938)  
 5 हिस्ट्री आफ किसान मूवमट (1939)  
 राय, पी० सी० लाइफ एंड टाइम्स आफ सी० आर० दास (1937)  
 रिची ज० ए० सन्वैशम फ्राम दि एजुकेशनल रेकार्ड स, खड I जीर II  
 (1923)  
 रिजली, सर एच० एच०, दी पीपल आफ इंडिया (1915)  
 राकर आर०, नेशनलिज्म एंड कल्चर (1937)  
 रोनाल्डशे, लाड, लाइफ आफ लाड कजन जिल्द II (1928)  
 राय एम० एन०, 1 इंडिया इन ट्रांजिशन (1922)  
 2 हिस्टोरिकल रोल आफ इस्लाम (1938)  
 3 मेटरियलिज्म (1940)  
 राजा राममोहन राय, इंगलिश वक्म (1906)  
 रशनुक, विलियम्स, ह्याट अवाउट इंडिया ?  
 मतानम, के० द नाड आफ डिस्ट्रेस (1943)  
 साजेंट, जे०, प्राग्रस आफ एजुकेशन इन इंडिया (1940)  
 शिफ, लेनाड, द प्रजट कंडिशन आफ इंडिया (1939)  
 सील ब्रजेंद्र नाथ, राजा राममोहन राय  
 सीली, जे० आर०, एक्मर्पसन आफ इग्नड (1883)  
 सेनाट, एम० वास्ट इन इंडिया (1950)  
 सहजानंद स्वामी, दि अदर साइड आफ द गाल्ड (1938)  
 शाह, क० टी०, ह्याड पाकिस्तान ? ह्याड नाट ? (1940)  
 शलचकर व० एस० प्रान्तम आफ इंडिया (1940)

- शिवा राव, दि इंडस्ट्रियल वर्कर इन इंडिया (1939)
- सीतारमया पी० द हिस्ट्री आफ दि इंडियन नेशनल कांग्रेस (1935)
- स्मिथ, डब्ल्यू० सी०, माडन इस्लाम इन इंडिया (1943)
- स्मिथ, डब्ल्यू० राय, नेशनलिज्म एंड रिफॉर्म इन इंडिया (1938)
- सोनी, एच० आर०, इंडियन ट्रांसपोर्ट (1935)
- स्प्रेट, फिलिप, गांधीज्म (1939)
- स्टालिन, जाजफ माक्सिज्म एंड द नेशनल एंड कलानियल क्वेश्चन
- स्ट्रैची मर जान, इंडिया, इट्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राग्रस (1903)
- सनयात सन सान भिनचुआइ (1929)
- टैगोर, रवीद्रनाथ, नेशनलिज्म (1917)
- टगार, सोमद्रनाथ 1 गांधीज्म एंड द लेबर पेजेट पाब्लिश (1940)
- 2 बुजुआ डमाक्रैटिक रिवोल्यूशन एंड इंडिया (1939)
- टानी, आर० एच०, रेलिज्म एंड द राइज आफ कपिटलिज्म (1929)
- टपल सर आर०, मेन एंड इवटम आफ माइ टाइम इन इंडिया (1882)
- टामस एफ० डब्ल्यू०, हिस्ट्री एंड प्रोस्पेक्टस आफ ब्रिटिश एजुकेशन इन इंडिया (1891)
- टामसन, इ० एंड गैरट जी०, राइज एंड फुलफिलमेंट आफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया (1935)
- टामसन, इ० रिक्स्ट्रक्शन आफ इंडिया (1930)
- टैनीलियन, मी० ई०, दि एजुकेशन आफ द पीपल आफ इंडिया (1838)
- वार्ग ई० द ग्रेट फ्राइमि (1934)
- विजयाराघवाचारी, सर टी० लड एंड द टम प्रोब्लम (1944)
- विश्वेश्वरया, मर एम० प्लड इकानमा फार इंडिया (1954)
- विवेकानंद स्वामी, फ्राम कालम्बा टु जलमोना सर्वेटीन लेक्चर (1897)
- वाडिया पी० ए० एंड जाशी जा० एन०, वेल्थ आफ इंडिया (1925)
- वाडिया, पी० ए० एंड मचेंट, क० टी० 1 जवर इकनामिक प्रोब्लम (1943)
- 2 माडन टाट्स (1882)
- वालचंद हीराचंद, ह्वाइ इंडियन रिपिड टुज नाट था (1940)
- वाल्टर एच० ए०, रि जहमदिया मूवमेंट (1918)
- वेव, ब्रिटिश, माइ अप्रेंटिसशिप (1938)
- वडरवन, विलियम, एलन जास्टवियन ह्यूम (1913)
- वीजवाड, ए०, द काक्वम्ट आफ पावर (1938)
- व्हाइटहड विशप, इंडियन प्रोब्लम (1924)
- विन्सन एस० सी० माडन मूवमेंट जमन मुन्निम (1916)
- विटररिडज ज०, नेशनलिटीज इन यूरोप (1945)

विटिंगम, टी०, म्युटिनी (1936)  
 यागिनक, जाइ० के०, पेजेटस रिवोल्टम (1939)  
 जकारिआम, एच० सी० ई० रिन्मेट इडिया (1933)  
 जिमन ए० ई०, नज्ञानलिटी एड गवतमट (1919)

सरकारी प्रकाशन

इपीरियल गजेटियस आफ इडिया जिल्द I IV  
 इडियन स्टटिस्टिकन अब्मट्रेक्ट (वार्षिक)  
 माटग्यु चम्तफाड रिपाट (1918)  
 रिपोट आफ दि इडियन इंडस्ट्रियल कमीशन 1916-18  
 रिपाट आफ द मडलर कमीशन 1917 19  
 रिपाट आफ द रायल कमीशन आन द पब्लिक सर्विस (इजलिग्न कमीशन)  
 (1917)  
 रिपाट आफ द रौलट (सेडीशन) कमेटी (1918)  
 रिपाट आफ द रायल कमीशन आन द मुपिरियर सिविल सर्विस इन  
 इडिया (ली कमीशन) (1924)  
 रिपोट आफ द वाव रायटन इनक्वायरी कमेटी (1925)  
 रिपोट आफ द इडियन इकनामिक इनक्वायरी कमेटी (1925)  
 रिपोट आफ द रायल कमीशन आन एग्रीकल्चर (1928)  
 रिपाट आफ द बटलर कमेटी (1929)  
 रिपाट आफ द हार्टोग कमीशन (1929)  
 रिपाट आफ दि इडियन स्टच्युटरी कमीशन (गादमन कमीशन) (1930)  
 रिपाट आफ द फ्रेंचाइज कमेटी (1931)  
 रिपोट आफ द रायल कमीशन आन लबर (1931)  
 रिपाट आफ दि मेट्रल ब्रकिंग इनक्वायरी कमेटी (19 1)  
 रिपाट आफ द ज्वायट कमेटी (1914)  
 रिपाट आफ द फुडरेंन पात्रिमी कमेटी (शहरी कमेटी) (1943)  
 रिपोट आफ द लंड रनेजू कमीशन (पलाउडस कमीशन)  
 रिपाट आफ द फेमिन कमीशन (फाइनल रिपाट) (1945)  
 द मारन एड मटरियल प्राग्रस इन इडिया (एनुअल 1)



